

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj )

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

# प्रारम्भिक अर्थशास्त्र

अमरनाथ अग्रवाल, एम० ए०

अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग,  
रामजस कालेज, देहली

पाचवा संशोधित संस्करण

फ्रैंक ब्रादर्स एण्ड कम्पनी -

चाँदनी चौक, देहली

प्रकाशक -

श्रीकृष्ण ब्रादर्स एण्ड कम्पनी,

बादनी चौक, देहली

### सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रथम संस्करण	१९४६
दूसरा संशोधित संस्करण	१९४८
तीसरा संशोधित संस्करण	१९५१
चौथा संशोधित संस्करण	१९५३
पाँचवा संशोधित संस्करण	१९५५

मूल्य ५० रु०

मुद्रक  
क्रान्ति प्रेस  
मोरीचेट, दिल्ली

## प्राक्थन

इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रत्येक विषय, विदेशी भाषा की अपेक्षा, अपनी भाषा में अधिक सुगमता के साथ और अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अपनी भाषा में अनेक विषयों पर विशेषरूप से अर्थशास्त्र जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर पुस्तकें लिखी जायें। इसकी आवश्यकता इस कारण और बढ़ती जा रही है कि धीरे-धीरे कुछ स्थानों पर हिन्दी शिक्षा का माध्यम बन गई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यह प्रवृत्ति निश्चय ही जोर पकड़ेगी और वह समय बहुत दूर नहीं जबकि हिन्दी राष्ट्र भाषा बन जायगी और स्कूलों में ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों में भी उच्च शिक्षा की पढाई हिन्दी में होने लगेगी। अस्तु, इस आर उचित ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य को लेकर अर्थशास्त्र विषय पर यह छोटी-सी पुस्तक लिखने का प्रयास किया गया है।

यह पुस्तक विशेषतः हायर सेकण्डरी विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर लिखी गई है। इसमें अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों और समस्याओं को सरल ढंग से सुबोध बनाने का पूरा प्रयत्न किया गया है जिससे प्रारम्भिक कक्षाओं के विद्यार्थियों इस महत्त्वपूर्ण किन्तु गम्भीर विषय को सहज में समझ सकें। जहाँ तक सम्भव हो सका है भाषा सरल और आम बोल-चाल की रखी गई है तथा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कोष्ठ में अंग्रेजी शब्द दे दिये गये हैं, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि विषय का वैज्ञानिक महत्त्व नष्ट न हो।

इस पुस्तक को लिखते समय मैंने इन विषयों को अनेक अंग्रेजी



पुस्तक की सहायता ली है। मैं उन मत्र पुस्तक के लेखक और प्रकाशकों का बहुत श्रणी और आभारी हूँ।

इस पुस्तक की रचना पद्धति पारिभाषिक शब्द शैली आदि क सम्बन्ध में जो भी सुधार के लिए सुझाव रख जायें मैं उनका मध्य-वाद स्वागत करूँगा।

रामजम कालेज दिल्ली  
जुलाई १९४६

अमरनाथ अग्रवाल

### चतुर्थ संशोधित संस्करण

इस पुस्तक का प्रथम संस्करण १९४६ में प्रकाशित हुआ था। इस बीच इसके दो संस्करण और प्रकाशित हुए और अब इसका चौथा संशोधित संस्करण निकाला जा रहा है। हर नए संस्करण में मैं इस पुस्तक को अधिकाधिक उपयोगी बनाने का भरमक प्रयत्न किया है और अबकी बार तो यह बिल्कुल नए सिरे में लिखी गई है। लगभग प्रत्येक अध्याय द्वारा लिखा गया है और एक-दो नए अध्याय भी जोड़ दिये गये हैं। मुझे आशा है कि प्रस्तुत पुस्तक अपने इस नए रूप में और भी अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। यदि ऐसा हुआ तो मैं अपने परिश्रम को सफल समझूँगा।

अन्त में मैं श्री गुरेशचन्द्र गोविल को धन्यवाद देना नहीं भूल सकता क्योंकि उन्होंने प्रथम संशोधन कर पुस्तक को अन्तिम रूप देने में बड़ी सहायता की है। कानिकल प्रस के श्री एम० आर० बी० राव का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने बड़ धैर्य के साथ काम किया है।

दिल्ली,  
अप्रैल, १९५३

अमरनाथ अग्रवाल

## पाँचवाँ मंशोधित मंस्त्रण

१९५३ में इस पुस्तक का चतुर्थ मंशोधित मंस्त्रण प्रकाशित हुआ था। उस मंस्त्रण का तैयार करत समय यह पुस्तक एक तरह से फिर से लिखी गई थी और मन यह जाणा प्रकट की थी कि पुस्तक पढ़ने में अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। इसी वजह से अपना इस आशा का पूरा होना देख कर मुझे अत्यंत हर्ष है और निम्नलिखित आशाएँ स्वभाविक ही हैं। पुस्तक की इस प्रकार प्राप्तिता में बड़ी देर पर मुझे इसमें उम्मीद है। पुस्तक में अनेक आवश्यक मंशोधन किए हैं। वास्तव में अंतिम अध्याय का बदल कर नया टुकड़ा मिला गया है और कुछ अध्यायों को पहले से बहुत बढ़ा दिया गया है। मेरा अपना यह विचार है कि तब इस विषय में अध्ययन और अध्यापन-कार्य में बहुत सुविधा होगी और पुस्तक की लोकप्रियता में पहले से अधिक वृद्धि होगी। इस प्रकार मोचन में मैं कह सकता हूँ यह तो अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के लिए बड़ा फायदा है।

अनेक महानुभावों ने मुझे इस कार्य में समय-समय पर सहायता और प्रोत्साहन मिला है। मैं उन सबका विशेष रूप में ऋणी और आभारी हूँ। अंत में मैं इस पुस्तक के प्रकाशक श्री किशोरीलाल गोविंद के प्रति जिन्होंने बड़ी तत्परता सहृदयता एवं रुचि के साथ पाँचवाँ मंशोधित मंस्त्रण निकालने में कार्य किया है अपनी कृतज्ञता प्रकट किए बिना नहीं रह सकता।

दिल्ली

मार्च १९५५

अमरनाथ अग्रवाल

# विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठ

पहला भाग विषय प्रवेश

१—अर्थशास्त्र का विषय १

आर्थिक समस्या — आर्थिक समस्या और समाज — आर्थिक  
समस्या और द्रव्य — अर्थशास्त्र और सम्पत्ति — अर्थशास्त्र  
और आर्थिक प्रयत्न ।

२—अर्थशास्त्र का क्षेत्र १४

अर्थशास्त्र का विषय — अर्थशास्त्र विज्ञान या कला — अर्थ-  
शास्त्र और विज्ञान — अर्थशास्त्र और कला — अर्थशास्त्र  
का अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध ।

३—अर्थशास्त्र के नियम २४

राज्य नियम — नैतिक नियम — व्यावहारिक नियम — वैज्ञानिक  
नियम — अर्थशास्त्र के नियमों की विशेषताएँ ।

४—अर्थशास्त्र का महत्त्व ३१

गैदार्निव लाभ — व्यावहारिक लाभ ।

५—आर्थिक जीवन का विकास ३७

शाम्बेटावस्था — पशु पालनावस्था — कृषि अवस्था — हस्त-  
कला अवस्था — यत्नमान औद्योगिक काल ।

६—कुछ पारिभाषिक शब्द ५०

उपयोगिता — मूल्य — कीमत — वस्तु — धन या सम्पत्ति —  
सम्पत्ति का वर्गीकरण ।

७—अर्थशास्त्र के विभाग ६३

उपभोग — उत्पत्ति — वित्तिय — वितरण — राजकीय अर्थ-  
व्यवस्था — विभागों का पारस्परिक सम्बन्ध ।

अध्याय

गृ०

द्वितीय भाग उपभोग

८—उपभोग और उसका महत्त्व

७५

अन्तिम और उत्पादन उपभोग — उपभोग का महत्त्व ।

९—आवश्यकताएँ

८२

आवश्यकता का अर्थ — आवश्यकता और उपयोग — आवश्यकताओं की विविधताएँ — आवश्यकताओं का वर्गीकरण — वर्गीकरण का आधार ।

१०—सीमान्त उपयोगिता हानि नियम

९३

उपयोगिता की माप — सीमान्त और समस्त उपयोगिता — सीमान्त उपयोगिता हानि नियम — अन्य सब बातें पचवन् रह — इस नियम के अपवाद ।

११—मांग

१११

मांग का अर्थ — मांग पृथक् — मांग रेखा — मांग का नियम — मांग में परिवर्तन — मांग की लोच — लोच का निर्धारित होना — लोच की माप — मांग की लोच का महत्त्व ।

१२—उपभोग सम्बन्धी कुछ नियम

- १२१

उपभोगिता की वृद्धि का नियम — उपभोगिता की वृद्धि का महत्त्व — समसीमान्त उपयोगिता नियम — पारिवारिक आय व्यय ।

१३—व्यय और वृद्धि की समस्या

१४८

व्यय — व्यय का सामाजिक पहलू — वृद्धि — व्यय और वृद्धि का सम्बन्ध — विलासिता की समस्या ।

१४—जीवन स्तर

१६०

जीवन-स्तर का अर्थ — भारतवासियों का जीवन-स्तर ।

तीसरा भाग उत्पत्ति

- १५—उत्पत्ति और उसके साधन १७१  
उत्पत्ति का अर्थ—उपपत्ति का वृद्धि के रूप—उत्पत्ति के साधन—  
उत्पत्ति पर प्रभाव—उत्पत्ति का महत्त्व ।
- १६—भूमि १८३  
भूमि की विशेषता—भूमि का महत्त्व—भूमि की उत्पादन  
शक्ति पर प्रभाव—चिन्तन और गहरी खेती ।
- १७—धर्म और उसके लक्षण १९०  
धर्म के भेद—धर्म के लक्षण—धर्म का महत्त्व ।
- १८—धर्म की पुति १९६  
जन्म-दर—मृत्यु दर—आवास प्रवास—साधन का जनसंख्या  
न वृद्धि—मिथ्याज्ञा—साधन के मिथ्याज्ञा की समीक्षा ।
- १९—धर्म की क्षमता २०६  
क्षमता पर प्रभाव—भारतीय धर्म की कार्य-क्षमता—धर्म  
की गतिशीलता ।
- २०—धर्म-विभाजन २२०  
धर्म-विभाजन के रूप—धर्म-विभाजन में लाभ—धर्म-  
विभाजन से हानि—धर्म-विभाजन की सीमा ।
- २१—पूजा २३६  
पूजा का अर्थ और विशेषता—पूजा और सम्पत्ति—पूजा और  
भूमि—पूजा और मृदा—पूजा के रूप—पूजा का महत्त्व  
और उसका फायदा—पूजा की वृद्धि—भारत में पूजा का  
संक्रम ।
- २२—मशीन का उपयोग २५०  
मशीन से लाभ—मशीन से हानि ।

अध्याय	पृष्ठ
२३—प्रबन्ध और साहस	२५९
संगठनकर्त्ता के कार्य ।	
२४—व्यवसाय-व्यवस्था के रूप	२६५
धैर्यवित्तक साहस प्रणाली — साशेदारी — मिश्रित पूँजी वाली कम्पनी — महकारी उद्योग — सरकारी उद्योग ।	
२५—उद्योग-मन्थों का स्थानीयकरण	२८१
स्थानीयकरण के कारण — स्थानीयकरण में लाभ — स्थानीय- करण में हानियाँ — विकेन्द्रीकरण ।	
२६—उत्पादन की मात्रा	२९०
बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के लाभ — बड़ी मात्रा की उत्पत्ति की सीमा — बड़ी मात्रा की उत्पत्ति से हानियाँ — छोटी मात्रा की उत्पत्ति से लाभ ।	
२७—उत्पत्ति के नियम	३०३
आदर्श मिश्रण — त्रमागत उत्पत्ति हानि नियम — कृषि और उत्पत्ति हानि नियम — नियम की परिमितताये — त्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम — त्रमागत उत्पत्ति समता नियम ।	
चौथा भाग विनिमय	
२८—विनिमय	३१९
विनिमय के भेद — विनिमय का महत्त्व ।	
२९—मर्दी	३२६
गली का वर्गीकरण — मर्दी का विस्तार ।	
३०—पूति	३३३
पूति का अर्थ — पूति-सूची और रखा — पूति की लोन — उत्पादन व्यय — प्रमुख और पूरक लागत — सीमान्त और औसत उत्पादन व्यय ।	

- अभ्यास १८४
- ३१—मूल्य निर्धारण की समस्या ३४४  
 माग (मीमान्त उपयोगिता) - पूर्ति ( मीमान्त उत्पादन  
 व्यय) - माग और पूर्ति की समता - बाजार तथा सामान्य मूल्य ।
- ३२—प्रतियोगिता और मूल्य ३५६  
 प्रतियोगिता की बिम्बपताएँ और मूल्य निर्धारण - प्रतियोगिता  
 से लाभ और हानियाँ ।
- ३३—एकाधिकार और मूल्य ✓ ३६३  
 एकाधिकार के भेद - एकाधिकार मूल्य - एकाधिकार मूल्य  
 कम या अधिक - एकाधिकारी की शक्ति की सीमा - एका-  
 धिकार से लाभ तथा हानियाँ ।
- ३४—मुद्रा = मूल्य ३७५  
 मुद्रा की परिभाषा - मुद्रा के कार्य - अच्छी मुद्रा के गुण -  
 धातुवत्त्व मुद्रा - मिश्रता बढ़ाई - पत्र-मुद्रा के लाभ और  
 हानियाँ - मुद्रा का वर्गीकरण - पत्रम का मुद्रा सम्बन्धी  
 सिद्धान्त - मुद्रा का महत्त्व ।
- ३५—मुद्रा का मूल्य ३९५  
 मूल्य अब - मुद्रा का मूल्य निर्धारण - मुद्रा परिणाम  
 सिद्धान्त - मुद्रा के मूल्य परिवर्तनों के परिणाम ।
- ३६—साख और बैंक ✓ ४०८  
 साख पत्र - साख का महत्त्व - बैंक - बैंक के कार्य - बैंक की  
 महत्ता ।

### पाचवों भाग वितरण

- ३७—वितरण और उसकी समस्या ४२१  
 वितरण की समस्याएँ ।

अध्याय

पृष्ठ

३८—मज्झिमा

४३२

ममयानुसार मज्झिमा - बार्मानुसार मज्झिमा - नवमी तथा  
वाम्नाविक मज्झिमा - मज्झिमा निर्धारण - धम्म की माता -  
धम्म की पुत्री मरण और पुनर्जन्म का परम्पर प्रभाव -  
मज्झिमा अन्तर - मज्झिमा की मज्झिमा - मज्झिमा और बार्मानु-  
सार ।

३९—व्याज

४४९

दुष्ट और कुल व्याज - व्याज की आवश्यकता और औचित्य -  
व्याज क्या मागा और दिया जाता है - व्याज दर का  
निर्धारण व्याज की दृष्टि में विभिन्नता - उत्पत्ति का व्याज  
पर प्रभाव ।

४०—लगाव

४६५

लगाव के वाम्नाविक अर्थ का स्पष्टीकरण - लगाव निर्धारण  
और गेहवारों का मिश्रण लगाव और माय लगान पर  
कुछ बातों का प्रभाव ।

४१—लाभ

४७९

कुल लाभ का विवेचन - लाभ का निर्धारण - लाभ तथा  
उत्पादन व्यय - लाभ तथा मज्झिमा ।

परीक्षापत्र

४८९



विषय-प्रवेश

## अध्याय १

# अर्थशास्त्र का विषय

(Subject-matter of Economics)

अर्थशास्त्र मानव-जीवन का अध्ययन है। इसमें मनुष्य की आवश्यकताओं और उनकी तृप्ति का अध्ययन किया जाता है। किन्तु केवल इतना कहने से ही अर्थशास्त्र का विषय स्पष्ट नहीं हो सकता। कारण, अर्थशास्त्र के अतिरिक्त और कई विज्ञान हैं जिनमें मानव-जीवन सम्बन्धी बातों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राजनीतिशास्त्र, न्यायशास्त्र, मनो-विज्ञान, धर्मशास्त्र, आचारनीति, आदि। इन सब में मानव-जीवन के भिन्न-भिन्न पहलुओं तथा अंगों का विवेचन होता है। अस्तु, ये सभी मानव-विज्ञान की शाखाएँ हैं। अर्थशास्त्र भी मानव-विज्ञान की एक शाखा है। इसलिए अर्थशास्त्र के विषय को भली भाँति समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि इसमें मानव-जीवन के किस अंग, रूप अथवा पहलू का, किस प्रकार की समस्या का अध्ययन होता है। हमें यह मालूम करना होगा कि आर्थिक समस्या है क्या और इसकी क्या विशेषताएँ हैं। तभी अर्थशास्त्र के विषय का पुरा-पूरा ज्ञान हो सकेगा।

## आर्थिक समस्या

(Economic Problem)

यदि हम मानव-जीवन पर दृष्टि डालें तो कुछ बातें हमें विशेष रूप से दिखाई देंगी। एक तो यह कि मनुष्य की आवश्यकताओं की कोई गिनती नहीं; वे असंख्य हैं। उनकी पूर्ति और तृप्ति के लिए मनुष्य तरह-तरह के उद्योग करता है। संसार में जितने भी काम दिखाई देते हैं, उन

सबका मूल कारण आवश्यकता है। आवश्यकता उद्योग की जननी है, उसी के लिए सब काम किये जाते हैं। यदि आवश्यकताएँ न हो तो किसी भी प्रकार का काम न किया जायगा। चूँकि आवश्यकताओं का कोई अन्त नहीं, इसलिए मनुष्य जीवन भर किसी न किसी कार्य में लगा ही रहता है।

दूसरे, वैसे तो मनुष्य की आवश्यकताएँ अनेक हैं, पर वे सब एक समान तीव्र नहीं होती। उनकी तीव्रता (intensity) में अन्तर होता है। कोई अधिक तीव्र होती है, और कोई कम। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को, तीव्रता के आधार पर, एक क्रम में मान-सा लेता है और फिर उसी क्रम के अनुसार उनकी पूर्ति करता है। पहले वह उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करता है जो औरों से अधिक जल्दी होती है, अर्थात् जिनमें अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता होती है। इनके बाद वह उन आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर ध्यान देता है जो उनसे कम जल्दी होती हैं। इस प्रकार वह अपनी आवश्यकताओं को, उनकी तीव्रता के अनुसार, तृप्त करने का उद्योग करता रहता है।

तीसरी बात यह है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन साधनों अथवा वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, वे अधिकतर सीमित (scarce) होती हैं। आवश्यकता की अपेक्षाकृत उनका परिमाण परिमित होता है, कम होता है। अर्थात् वे इतनी मात्रा या परिमाण में नहीं होती जितनी कि उनकी मांग होती है। इसलिए साधारणतः वे मनुष्य को मुफ्त नहीं मिलती। उनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को उद्योग करना पड़ता है; उनके बदले में उसे कुछ त्याग करना पड़ता है।

मनुष्य अपने जीवन-काल में अनेक प्रकार के उद्योग, व्यापार-धर्मसम्य करता है जिससे उसे आवश्यकता पूर्ति के सीमित साधन प्राप्त हो सकें। यदि आवश्यकता-पूर्ति के साधन असीमित होते, अथवा मनुष्य के पास जादू की कोई ऐसी अगूँठी होती जिसके केवल पिराने से ही सारी इच्छित वस्तुएँ जब और जहाँ वह चाहता मिल सकती, तो निश्चय ही जीवन की सब समस्याएँ अपने आप ही हल हो जाती। तब तो मनुष्य को

अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कोई भी एटिनाई न होती । उसे किसी प्रकार का उद्योग करने की आवश्यकता न होती । विन्तु, वास्तविक जीवन में न तो आवश्यकता-पूर्ति के सभी मा अधिकतर साधन असंसीमित हैं, और न ही साधारण व्यक्ति के पास ऐसा कोई जातू है जिससे उसे सब इच्छित वस्तुएं बिना किसी परिश्रम के मिल सकें । अतएव साधारणतया आवश्यकता-पूर्ति के साधनों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को उद्योग करना पड़ता है, उससे बढ़ते में कुछ-न-कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है, चाहे वह स्वयं दे या उसके लिए कोई और मूल्य चुकाये, या उद्योग करे ।

एक और विशेषता जो ध्यान देनी योग्य है, वह यह है कि आवश्यकता-पूर्ति के सीमित साधनों के अनेक सम्भव प्रयोग अथवा व्यवहार हैं । उन्हें भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है, पर सब स्थानों में एक साथ नहीं । अब किसी सीमित साधन को एक आवश्यकता की पूर्ति में लगाया जायगा, तो अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में उसका प्रयोग सम्भव न होगा । फलस्वरूप उन आवश्यकताओं को, अर्थात् साधन के अन्य प्रयोगों को, छोड़ना पड़ेगा । जैसे भूमि के एक टुकड़े को कई प्रकार से काम में ला सकते हैं, उससे कई आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं । उस पर खेती कर सकते हैं, बाग लगा सकते हैं, भण्डार, दूकान या स्कूल बना सकते हैं । किन्तु जब हम इनमें से किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस भूमि का प्रयोग कर लेंगे तो उसके अन्य प्रयोगों को छोड़ना पड़ेगा । अर्थात् अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका प्रयोग न हो सकेगा । व्यवहार में आने वाले लगभग सभी साधनों के साथ यह बात लागू होती है । दुध को हम पी सकते हैं, या उससे और कोई चीज तैयार कर सकते हैं, पर दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते । इसी प्रकार लोहा, कौयला, अन्न, समय, मनुष्य की शक्ति आदि सभी सीमित वस्तुओं और साधनों के विभिन्न व्यवहार या प्रयोग होते हैं । जब हम इनमें किसी एक आवश्यकता की पूर्ति करने में उपयोग करेंगे, तो अन्य आवश्यकताओं को, जो इनके प्रयोग द्वारा पूरी हो सकती हैं, छोड़ना पड़ेगा ।

उपर्युक्त विशेषताओं के कारण मनुष्य के नामने चुनाव (choice) की अवस्था निर्णय करने की समस्या आ खड़ी होती है। उसे यह तय करना पड़ता है कि सीमित साधनों को बब, किंग प्रकार और किन आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोग किया जाय। वह यह भली-भाँति जानता है कि साधनों के सीमित होने के कारण सभी आवश्यकताओं की तृप्ति सम्भव नहीं है। अतः वह अपनी कुल आवश्यकताओं में से, तृप्ति करने के लिए, कुछ को चुन लेता है और बाकी मक्कों, कुछ समय के लिए, अतृप्त ही छोड़ देता है। मनुष्य के दैनिक जीवन में इस प्रकार चुनने की अनेक समस्याएँ बराबर आती रहती हैं और इन्हीं पर उनकी उपरति, सुल-समझि बहुत कुछ निर्भर करती है।

जीवन में इस प्रकार की चुनने और निर्णय की समस्या तभी उपस्थित होती है जबकि उपर्युक्त चारों बात या विशेषताएँ एक साथ होती हैं। इनमें से किसी एक के न होने पर चुनने की समस्या पैदा न होगी। जैसे यदि आवश्यकताएँ असीमित न हों, तो मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं में से कुछ को चुनने और कुछ को छोड़ने की समस्या न होगी। उस दशा में तो वह अपनी सभी आवश्यकताओं को तृप्त कर लेगा। साथ ही यदि आवश्यकताओं की तीव्रता में अन्तर न हो, अर्थात् वे एक समान तीव्र हों, तो उस दशा में मनुष्य भला किम प्रकार कोई निर्णय कर सकेगा। ऐसा होने पर तो वह कोई भी काम न कर सकेगा। इसी प्रकार यदि साधन सीमित न हों, या उनके विभिन्न व्यवहार न हों, तो भी निर्णय की कोई समस्या उत्पन्न न होगी। साधनों के असीमित होने पर आवश्यकताओं की तृप्ति करने में कोई कठिनाई न होगी, और न फिर यह निर्णय करने की ही जरूरत रहेगी कि किन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाय, और किन की नहीं। इसी तरह यदि साधनों के विभिन्न प्रयोग नहीं हैं, उनके एक-एक ही प्रयोग हैं, तो भी चुनने और निर्णय की कोई समस्या न उठेगी। जब कोई साधन केवल एक ही तरह से उपयोग हो सकता है, तो इस बात का कोई प्रश्न ही न उठेगा कि उसे किम तरह, कौन-सी

आवश्यकता की पूर्ति में उपयोग किया जाय।

अस्तु, जीवन की इन विशेषताओं के एक माध्य होने के कारण मनुष्य को चुनने और निर्णय करने की आवश्यकता पड़ती है। चुनने की यह आवश्यकता उसे सदा घेरे रहती है। यह इन बातों के निर्णय में बराबर लगा रहता है कि किन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाय, किस प्रकार सीमित साधनों को, जिनके अनेक प्रयोग हैं, उपयोग में लाया जाय, जिसमें अधिक में अधिक तृप्ति और सन्तोष उसे प्राप्त हो सके। यही आर्थिक समस्या है, चाहे इसका सम्बन्ध व्यक्ति से हो या समाज में, और इसी का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। सीमित साधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग के सम्बन्ध में जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जो कार्य व निर्णय किये जाते हैं, उन सबका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है।

मनुष्य अपने दैनिक जीवन में आवश्यकता-पूर्ति के सीमित साधनों के उपयोग के सम्बन्ध में अनेक निर्णय करता है और उनके कार्यान्वित के लिए विभिन्न उद्योग, व्यापार-व्यवसाय करता है। उदाहरणार्थ उसे यह निर्णय करना पड़ता है कि अपना समय, शक्ति और पैसे अमुक कार्य में लगाने या दूसरे में, अपनी आय को वर्तमान और भावी आवश्यकताओं की तृप्ति में किस तरह बाँटे, आय को किस रूप में रखे, अमुक वस्तु खरीदे या दूसरी, एक विशेष कीमत पर किसी वस्तु को कम बेचे या अधिक? इस प्रकार के अनेक निर्णय-कार्य उसे करने पड़ते हैं। समाज के सामने भी इसी तरह के अनेक प्रश्न उठते हैं। ये सब आर्थिक प्रश्न अथवा समस्याएँ हैं। अर्थशास्त्र में इनही बातों का विवेचन किया जाता है।

हम ऊपर कह चुके हैं कि चुनने और निर्णय की आवश्यकता इन बातों के कारण होती है : ( १ ) मनुष्य की आवश्यकताएँ असंख्य हैं, ( २ ) आवश्यकताएँ एक समान सीढ़ी नहीं हैं, ( ३ ) आवश्यकता-पूर्ति के साधन सीमित हैं, और ( ४ ) सीमित साधनों के विभिन्न प्रयोग हैं। चूँकि निर्णय करने की आवश्यकता के फलस्वरूप ही आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए उपर्युक्त बातें आर्थिक समस्या के आधार हैं।

इन्हीं के कारण आर्थिक समस्या का जन्म होता है। अस्तु, जब तक ये बातें बनी रहेंगी, तब तब आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न होती रहेंगी और फलस्वरूप उस समय तक अर्थशास्त्र का अध्ययन चलता रहेगा।

### आर्थिक समस्या और समाज

(Economic Problem and Society)

थव स्पष्ट है कि आर्थिक समस्या क्या है तथा किन परिस्थितियों अथवा दशाओं में यह पैदा होती है। ये परिस्थितियाँ समाज अथवा उसके किसी विशेष रूप पर निर्भर नहीं हैं। ये हर स्थान और समय पर हो सकती हैं। चूँकि इन परिस्थितियों के कारण ही आर्थिक समस्या का जन्म होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्थिक समस्या के लिए समाज का होना आवश्यक नहीं है। चाहे समाज हो या नहीं, चाहे उसकी व्यवस्था का कोई भी रूप हो, यदि मनुष्य की आवश्यकताएँ अनन्त हैं और उनकी अपेक्षावृत्त आवश्यकता-पूर्ति के साधन सीमित हैं तथा सीमित साधनों के विभिन्न प्रयोग हैं, तो अवश्य ही आर्थिक समस्याएँ होंगी। थोड़ी देर के लिए मान लो कि समाज में एक ही व्यक्ति है। उसके सामने भी यह समस्या होगी कि विभिन्न कार्यों में जैसे पूजा-पाठ, भोजन, मनन आदि में जपाने सीमित शक्ति और समय को किस प्रकार बाँटे जिससे उसको अधिकतम सुख प्राप्त हो सके। उसे यह निर्णय करना पड़ेगा कि एक समय में अग्रे कार्य करे या दूसरा। यह निश्चय ही आर्थिक समस्या है। अस्तु, आर्थिक समस्या समाज या किसी साम सामाजिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न नहीं होती। हाँ, यह बात अवश्य है कि समाज की उपस्थिति में, उसका एक विशेष रूप होने पर आर्थिक समस्याओं में भिन्नता आ जाती है। उनकी सख्या और रूप में परिवर्तन आ जाता है।

### आर्थिक समस्या और द्रव्य

(Economic Problem and Money)

आमतौर से आजकल द्रव्य (money) या रुपये-पैसे की समस्या को ही आर्थिक समस्या समझा जाता है। वर्तमान समय में द्रव्य का प्रयोग बहुत

बढ़ गया है। हर क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। इसी के रूप में लोगों को बेतन दिया जाता है, वस्तुओं का विनिमय होता है, और उनका मूल्य मापा जाता है। सी के आधार पर लेन-देन का कार्य होता है और हिसाब-खाता रखा जाता है। कहने का आराख़ यह है कि द्रव्य हमारे जीवन का आज एक विशेष अंग बन गया है। फिर भी इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि द्रव्य ने कारण आर्थिक समस्या पैदा होती है और द्रव्य के न होने पर आर्थिक समस्या न रहेगी। द्रव्य के प्रयोग को बन्द कर देने से निश्चय ही हमें अनेक अनुविधाओं या सामना करना पड़ेगा, विशेष कर व्ययताम और व्यापार क्षेत्र में। यहाँ तक कि हमें जीवन की अनेक अच्छाइयों से हाथ धोना पड़ेगा और हमारी उत्पत्ति बहुत कुछ एक जायगी। तो भी द्रव्य के निकल जाने से उन परिस्थितियों में कोई हेर-फेर न होगा जिनके कारण आर्थिक समस्या पैदा होती है। उन परिस्थितियों के होने पर, चाहे द्रव्य का प्रयोग चलता रहे या बन्द कर दिया जाय, आर्थिक समस्याएँ बनीं रहेंगी। अतः, आर्थिक समस्या के लिए द्रव्य या मुद्रा अपना रूप-पैसा का प्रयोग आवश्यक नहीं है।

संक्षेप में, जब हम अर्थशास्त्र के विषय को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। अर्थशास्त्र मानव विशाल की एक शाखा है। इसमें मानव-प्रयत्न के उस अंग अथवा पहलू का विवेचन होता है जिसका सम्बन्ध आवश्यकताओं और विभिन्न प्रयोग वाले सीमित साधनों के साथ होता है, चाहे वह प्रयत्न समाज में रहकर किया गया हो या उसके बाहर।

प्रो० रॉबिन्स ने भी इसी प्रकार अर्थशास्त्र की परिभाषा की है। उनके मतानुसार “अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य के कार्य-कलापों का अध्ययन इस दृष्टि से करता है कि वे उनके उद्देश्यों और विभिन्न प्रयोग रखने वाले सीमित साधनों के बीच से क्या सम्बन्ध स्थापित करते हैं।” \*

---

\* “Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses”—Robbins.



इस परिभाषा के मूल में वही चारों चीजें हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। मनुष्य की आवश्यकताएँ अनन्त हैं लेकिन उनकी पूर्ति के साधन सीमित हैं और साथ ही इन सीमित साधनों के कई उपयोग होते हैं। इसलिए मनुष्य के सामन चुनने का प्रश्न उठता है। उसे इस बात का निर्णय करना पड़ता है कि अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करे और बिना छोड़ दे। अर्थात् अपनी सीमित साधनों को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में किस प्रकार उपयोग करे। अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का इस दृष्टि में अध्ययन करता है। अतः, यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र की समस्या चुनना अथवा किफायत की समस्या है।

अर्थशास्त्र की इस प्रकार की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि इसमें केवल कुछ खास मनुष्यों का या मनुष्य के कुछ विशेष प्रयत्नों का अध्ययन नहीं होता, बल्कि मनुष्य के प्रत्येक प्रयत्न के एक विशेष पहलू का अध्ययन किया जाता है। इस पहलू से अभिप्राय आवश्यकता-पूर्ति के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। इसे आर्थिक पहलू (economic aspect) कह सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में मानव-प्रयत्न के आर्थिक पहलू का विवेचन होता है।

समय-समय पर अर्थशास्त्र की अनेक प्रकार से परिभाषाएँ की गई हैं। उनमें से एक-दो पर विचार करने से अर्थशास्त्र का विषय, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, और भी स्पष्ट हो जायगा। साथ ही यह भी मालूम हो जायगा कि वे कितनी ठीक हैं।

### अर्थशास्त्र और सम्पत्ति

(Economics and Wealth)

कई अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को एक सम्पत्ति शास्त्र (science of wealth) मानते हैं। उनके कथनानुसार अर्थशास्त्र मनुष्य का सम्पत्ति के सम्बन्ध में अध्ययन करता है। इसमें इस बात की छाया-बीज की जाती है कि मनुष्य किस प्रकार धनोपार्जन करता है और किस प्रकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे उपयोग में लाता है।

साधारणतः मनुष्य का अधिकांश समय जीविका के उपायार्जन करने में व्यतीत होता है। वह धन की, अर्थात् आवश्यकता पूर्ति की सीमित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अनेक कार्य, व्यापार-व्यवसाय करता है और फिर उस धन को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में इस प्रकार उपयोग में लाने का प्रयत्न करता है जिससे उसे अधिकतम तृप्ति और सुखोप प्राप्त हो। अर्थशास्त्र में इन सब कार्यों, व्यवहारों आदि का अध्ययन होता है जो मनुष्य अपने प्रतिदिन के जीवन में धन के उपायार्जन और उसके उपयोग में लाने के लिए करता है। अर्थात् अर्थशास्त्र में मनुष्य और सम्पत्ति दोनों का ही अध्ययन एक साथ चलता है।

प्रो० मार्शल की प्रतिष्ठित परिभाषा का यही आधार है। उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार की है "अर्थशास्त्र मनुष्य के प्रतिदिन के साधारण जीवन के कार्यों का अध्ययन है। इसमें इस बात की खान-चीन की जाती है कि मनुष्य किस तरह धन कमाता है और किस तरह से उसे उपयोग में लाता है। इसलिए एक ओर तो यह सम्पत्ति का अध्ययन है और दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है, यह मानव जीवन के अध्ययन का एक भाग है\*।"

अर्थशास्त्र की इस प्रकार से की गई परिभाषा को भलीभाँति समझने के लिए एक-दो बातों को स्पष्ट कर देना जरूरी जान पड़ता है, वही तो श्रम में पड़ने की सम्भावना बनी रहती। एक तो यह कि इस परिभाषा में 'सम्पत्ति' शब्द का उपयोग रुपये-पैसे के अर्थ में नहीं बरन उन तमाम सीमित साधनों के लिए किया गया है जिनसे मनुष्य अपनी आवश्यकताएँ

---

\* "Economics is the study of man's actions in the ordinary business of life; it enquires how he gets his income and how he uses it. Thus it is on one side a study of wealth, and on the other and more important side, a part of the study of man"—Marshall.

पूरी करता है। सम्पत्ति में वे सभी वस्तुएँ शामिल हैं जो मनुष्य की किसी-न किसी आवश्यकता की पूर्ति कर सकने वाली हैं और साथ ही मात्र सीमित\* भी हो। यदि सम्पत्ति को इस व्यापक और सही अर्थ में समझ लिया जाए तो अर्थशास्त्र के विषय को इस परिभाषा द्वारा स्पष्ट करने में कोई दोष न होगा।

दूसरी बात यह है कि जब इस परिभाषा के अनुसार यह कहा जाता है कि अर्थशास्त्र एक सम्पत्ति-शास्त्र है, तो यह न समझ लेना चाहिए कि अर्थशास्त्र में मनुष्य को छोड़कर केवल सम्पत्ति का ही विचार किया जाता है, अथवा अर्थशास्त्र में मनुष्य की अपेक्षा सम्पत्ति का स्थान अधिक महत्वपूर्ण या ऊँचा है। क्योंकि ऐसा सम्भव ही नहीं है। सम्पत्ति में तो केवल वही वस्तुएँ सम्मिलित की जा सकेंगी जिनमें मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की शक्ति हो। अस्तु, जब सम्पत्ति पर विचार किया जायगा, तब मनुष्य और उसकी आवश्यकताओं पर विचार करना अनिवार्य हो जायगा। मनुष्य पर विचार किये बिना सम्पत्ति के विषय में विचार किया ही नहीं जा सकता। वास्तव में सम्पत्ति का स्वतः कोई महत्व नहीं। इसका अस्तित्व और महत्व मनुष्य की आवश्यकताओं पर निर्भर है। फिर भला किस प्रकार इसका स्थान अधिक ऊँचा हो सकता है, अथवा किस प्रकार मनुष्य को छोड़कर केवल इसी पर विचार किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में हम सम्पत्ति पर ध्यान इसलिए केन्द्रित करते हैं कि हमें

---

\* यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि "सीमित" शब्द को एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है। सीमित वस्तु कहलाने के लिए केवल यही जरूरी नहीं है कि उस वस्तु की मात्रा सीमित हो। सड़े-गले अने मात्रा में कम होते हैं, किन्तु आर्थिक दृष्टि से वे सीमित नहीं हैं। आर्थिक दृष्टि से वह वस्तु सीमित मानी जाती है, जिसकी मात्रा या पूर्ति (supply) माँग से कम होती है। यदि किसी वस्तु की मात्रा माँग से कम है, तो उसे सीमित कहेंगे, अन्यथा नहीं।

मनुष्यों के उन काम-कलाओं का अध्ययन करना है जिनका सम्बन्ध आवश्यकता-पूर्ति के सीमित माधनों अथवा सम्पत्ति से है।

अर्थशास्त्र को सम्पत्ति-शास्त्र मानने में कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि 'सम्पत्ति' शब्द को सही और व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाय। लेकिन गुरु-गुरु में जब अर्थशास्त्र को यह कह कर व्याख्या की जाती थी कि यह सम्पत्ति का विज्ञान है तो सम्पत्ति को एक बहुत ही सीमित और सुष्ठुपूर्ण अर्थ में प्रयोग किया जाता था। इसका आशय भौतिक पदार्थों से था जैसे अनाज, कपड़ा, मेज-कुर्सी, आदि। फलस्वरूप इस परिभाषा से तरह-तरह के ग्रन्थपूर्ण विचारों का प्रचार होने लगा। लोग अर्थशास्त्र को रपया-पैसा जोड़ने का अर्थात् कजूसों का विज्ञान समझने लगे। अब सम्पत्ति को व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग रुपये के अर्थ में नहीं बरन उन तमाम सीमित पदार्थों के लिए किया जाता है जिनसे मनुष्य अपनी आवश्यकताएँ पूरी करता है, चाहे वे भौतिक हों या अजीतिक। यदि सम्पत्ति को इस भाव में प्रयोग किया जाय तो अर्थ-शास्त्र को सम्पत्ति-शास्त्र कहना गलत न होगा।

### अर्थशास्त्र और आर्थिक प्रयत्न

(Economics and Economic Activities)

कई अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के विषय को यह कह कर स्पष्ट करते हैं कि यह मनुष्य के आर्थिक प्रयत्नों (economic activities) का अध्ययन है। आर्थिक प्रयत्नों से उनका अभिप्राय मनुष्य के उन कार्यों और व्यवहारों से है जिनका सम्बन्ध सम्पत्ति से होता है। जब कोई कार्य मनुष्य धन के उद्देश्य से नहीं अपितु दया, भक्ति, मनोरंजन, प्रेम, आदि के उद्देश्यों से करता है, तो उनको वे आर्थिकेतर प्रयत्न (non-economic activities) कहते हैं। इनके कथनानुसार अर्थशास्त्र के अन्तर्गत आर्थिक प्रयत्नों का विवेचन होता है, आर्थिकेतर प्रयत्नों का नहीं।

अर्थशास्त्र की परिभाषा जब इस प्रकार की जाती है तो इसका

## अर्थशास्त्र का क्षेत्र (Scope of Economics)

अर्थशास्त्र का क्या-कितना क्षेत्र अथवा विस्तार है, इसे पूर्ण रूप से समझने के लिए हम निम्नलिखित दो बातों पर विचार करना होगा —

(क) एक तो यह कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या विषय है ? अर्थात् मानव-जीवन के किस अंग या पहलू का हम विवेचन होता है ।

(ख) दूसरे, यह किस प्रकार का अध्ययन है—विज्ञान है या कला अथवा दोनों ? और यदि विज्ञान है तो क्या यह केवल एक मथार्थ-मूलक विज्ञान ( positive science ) है, या यह आदर्शमूलक विज्ञान ( normative science ) भी है ? इन प्रश्नों के उत्तर द्वारा अर्थशास्त्र का क्षेत्र जाना जा सकता है ।

### अर्थशास्त्र का विषय

(Subject matter of Economics)

अर्थशास्त्र का क्या विषय है, इसके अन्तर्गत किस बात का अध्ययन होता है, इसका विवेचन पहले अध्याय में दिया जा चुका है । फिर से उसको यहाँ दोहराना अनावश्यक होगा । यहाँ बस इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि अर्थशास्त्र मनुष्य का अध्ययन उसके सीमित साधनों अथवा सम्पत्ति के सम्बन्ध में किया जाता है । मनुष्य अपने प्रतिदिन के जीवन में आवश्यकतापूर्ति के सीमित साधनों की प्राप्ति तथा उनको काम में लाने के लिए जो विभिन्न निर्णय-कार्य, व्यापार-व्यवसाय करता है, उन सबका अध्ययन अर्थशास्त्र में होता है ।

अर्थशास्त्र के विषय के सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने योग्य है। अर्थशास्त्र केवल एक समाजशास्त्र ( social science ) ही नहीं है, बल्कि एक मानव-विज्ञान ( human science ) भी है। हममें मनुष्य का अध्ययन व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों रूपों में किया जाता है। अर्थशास्त्र के कई सिद्धान्त ऐसे हैं जिनके लागू होने के लिए समाज की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य चाहे समाज में रहे या उसके बाहर, वे नियम लागू होंगे। समाजशास्त्र में मनुष्य का अध्ययन व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि समाज के एक सदस्य के रूप में किया जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र का क्षेत्र समाजशास्त्र के क्षेत्र से नहीं अधिक विस्तृत और व्यापक है।

### अर्थशास्त्र—विज्ञान या कला

(Economics—Science or Art)

इसके पहिले कि यह निश्चय किया जा सके कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, या कला या दोनों, यह देखना आवश्यक है कि विज्ञान और कला कितने कहते हैं।

साधारणतः ज्ञान के दो भाग किये जाते हैं—विज्ञान और कला।

**विज्ञान**—विज्ञान प्रकृति के किसी विभाग के विषय में सम्बद्ध ज्ञान के संग्रह को कहते हैं। प्रकृति के किसी विभाग में जो एकता दिखाई देती है, उसका विज्ञान सम्बद्ध अध्ययन करता है और उसके आधार पर वह कुछ तथ्य प्राप्त करने का प्रयत्न करता है जिन्हे नियम अथवा सिद्धान्त कहा जाता है।

किसी चीज का अध्ययन दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो वस्तु का अध्ययन उसके प्रस्तुत रूप में, और दूसरे उसका अध्ययन उसके आवर्तन के रूप में। पहले प्रकार के अध्ययन को यथार्थ-मूलक विज्ञान और दूसरे प्रकार के अध्ययन को आदर्श-मूलक विज्ञान कहते हैं।

**यथार्थ-मूलक विज्ञान**—यह वस्तु का यथातथ्य अध्ययन करता है, वस्तु को उसी रूप में ग्रहण करता है जिस रूप में वह है। यह उसके

कारण और परिणाम के सम्बन्ध का विदलेपन तथा स्पष्टीकरण करता है। इसका क्षेत्र "क्या है" तक सीमित है। इसका एक मूल कार्य किसी वस्तु के कारण और परिणाम को मालूम करना है। अन्य किसी बात में इसका कोई सम्बन्ध नहीं। अमुक वस्तु घुरी है अथवा अच्छी, अमुक कार्य मरुप्य को करना चाहिए या नहीं, इन सब बातों में यथार्थ-मूलक विज्ञान का कोई सम्बन्ध नहीं होता। किसी प्रकार की शिक्षा या राय देना, अथवा आदर्श रखना इसका कार्य नहीं।

**आदर्श-मूलक विज्ञान**—यह वस्तु का उसके आदर्श रूप में अध्ययन करता है, और वस्तु के कल्याणकारी रूप की ओर संकेत करता है। इसका सम्बन्ध "क्या होना चाहिए" में है। हम यह बताता है कि अमुक कार्य उचित है या अनुचित, क्या हम करना चाहिए और क्या नहीं, अथवा किन-किन वस्तुओं से हमें बचना चाहिए और किनको अपनाना चाहिए। आचार-नीति और धर्मशास्त्र आदर्श-मूलक विज्ञान है।

**कला**—यह हमें अपने लक्ष्य या आदर्श तक पहुँचने का मार्ग तथा साधन बताती है। इससे हम उन व्यावहारिक बातों और तरीकों का बोध होता है जिनके द्वारा हम अपने इच्छित स्थानों तथा आदर्शों तक पहुँच सकते हैं, बुराइयों से बच सकते हैं और अच्छाइयों को पा सकते हैं।

कला को इस प्रकार और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। यह ज्ञान का व्यावहारिक रूप है। प्रत्येक विज्ञान का एक व्यावहारिक रूप होता है जिसे कला कह सकते हैं और प्रत्येक कला के पीछे उस का एक विज्ञान होता है।

अब ज्ञान के उपर्युक्त तीनों विभागों का परस्पर भेद बिल्कुल स्पष्ट है। यथार्थ-मूलक विज्ञान वस्तुओं के प्रस्तुत रूप का विवेचन करता है। आदर्श-मूलक विज्ञान वस्तुओं का आदर्श रूप निर्धारित करता है और कला इन आदर्शों तक पहुँचने का साधन या मार्ग बताती है।

अब हमें यह देखना है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, या कला अथवा दोनों ? और यदि विज्ञान है, तो क्या यह यथार्थ-मूलक विज्ञान है, या आदर्श-मूलक विज्ञान अथवा दोनों ?

### अर्थशास्त्र और विज्ञान (Economics and Science)

अर्थशास्त्र मनुष्य और सम्पत्ति के सम्बन्धों का शृङ्खलाबद्ध अध्ययन है। यह मनुष्य की उन एक-रूपताओं का अध्ययन करता है जो उसने दैनिक जीवन के साधारण कार्य-कलापों में देखने में आती हैं। इसलिए यह एक विज्ञान है। पर कुछ लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। वे यह कहते हैं कि अर्थशास्त्र में उतनी अनिश्चितता और अस्थिरता है कि विज्ञान का निर्माण सम्भव नहीं हो सकता। अर्थशास्त्र परिवर्तनशील स्वभाव वाले मनुष्य का अध्ययन है। इससे प्रयोजन, उसकी परिस्थितियाँ तथा सम्बन्ध आदि सभी समय-समय पर बदलते रहते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र के सिद्धान्त सभी स्थानों, समयों और कार्यों पर एक समान लागू नहीं हो सकते, और न ही अर्थशास्त्र के लिए यह सम्भव है कि वह भविष्य के बारे में ठीक-ठीक बातें बता सके। फिर भला किस प्रकार अर्थशास्त्र विज्ञान माना जा सकता है।

किन्तु यह विचारभारा ठीक नहीं है। विज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह ठीक-ठीक भविष्यवाणी कर सके। आधुनिक मत के अनुसार चिन्ता विषय के सम्बद्ध अध्ययन को, जिससे सिद्धान्तों की स्थापना होती है, विज्ञान कहते हैं। अर्थशास्त्र मनुष्य और सम्पत्ति के सम्बन्धों का शृङ्खलाबद्ध अध्ययन है। इस अध्ययन से कई सिद्धान्तों की स्थापना हो चुकी है जो निरोगी परिस्थितियों तथा बाधाओं के न रहने पर पूरी तरह से लागू होते हैं। अस्तु, अर्थशास्त्र निश्चय ही एक विज्ञान है।

अब प्रश्न यह है कि अर्थशास्त्र यथार्थ-मूलक विज्ञान है, या आदर्श-मूलक या दोनों ? अर्थशास्त्र सम्पत्ति के सम्बन्ध रखने वाले मानव-जीवन



और समाज के तथ्यों का विचार करता है । यह भाषिक कार्यों और स्थितियों की छानबीन करके उनके कारणों और परिणामों का निर्देश करता है । इसके द्वारा हमें यह मालूम होता है कि अमुक कारण की उपस्थिति में अमुक परिणाम होने की सम्भावना है । जैसे अर्थशास्त्र मांस और कीमत के सम्बन्ध में हमें बतलाता है कि अन्य चीजों के यथास्थिति रहते हुए, कीमत के गिरने से मांस बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने से मांस घट जाती है । इसी तरह, दूसरे स्थान पर अर्थशास्त्र द्वारा हमें यह मालूम होता है कि यदि एक समय में किसी एक वस्तु का अधिक उपभोग होता है तो परिणामस्वरूप उस वस्तु की आगे मिलने वाली इकाइयों (units) की उपयोगिता पिछली इकाइयों की उपयोगिता की अपेक्षा कम होती जायगी । अर्थशास्त्र में इस प्रकार के कारण और परिणाम का परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया जाता है । यह कार्य यथार्थ-मूलक विज्ञान का है । अतएव अर्थशास्त्र एक यथार्थ-मूलक विज्ञान है ।

पर क्या अर्थशास्त्र आदर्श-मूलक विज्ञान भी है ? इस विषय पर थोड़ा मतभेद है । कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थशास्त्र केवल एक यथार्थ-मूलक विज्ञान है । यह वस्तुओं का यथातथ्य अध्ययन करता है, वस्तुओं को उनके प्रस्तुत रूप में ग्रहण करता है । अर्थशास्त्र का आदर्शों से कोई सम्बन्ध नहीं, और न ही किसी प्रकार की राय देना इसका काम है । किन्तु अर्थशास्त्र को यह रूप देना ठीक नहीं है । अर्थशास्त्र मनुष्य के प्रतिदिन के साधारण कार्यों का अध्ययन है । यह अध्ययन उसी समय लाभप्रद सिद्ध हो सकेगा जबकि अर्थशास्त्र व्यावहारिक आदर्शों पर यथोचित प्रकाश डाल सके । लेकिन यह तभी सम्भव हो सकेगा जबकि अर्थशास्त्र को आदर्श-मूलक विज्ञान का भी रूप दिया जावे । इस रूप के बिना अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्त्व बहुत कम रहेगा । इसलिए अर्थशास्त्र को यथार्थ-मूलक विज्ञान ही नहीं बल्कि साथ-साथ आदर्श-मूलक विज्ञान भी मानना चाहिए ।

## अर्थशास्त्र और कला (Economics and Art)

अर्थशास्त्र कला माना जाय या नहीं, इस विषय पर विभिन्न मत हैं। कई अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि इसका क्षेत्र केवल विज्ञान तक ही सीमित रहना चाहिए। उनका कहना है कि यदि इस पर कला का बोझ लाद दिया जायगा, तो अवश्य ही अर्थशास्त्र की वैज्ञानिक उन्नति रुक जायगी। ऐसा होने पर अर्थशास्त्र कला का कार्य भी ठीक दूर में न कर सकेगा। परिणामस्वरूप विज्ञान और कला दोनों ही क्षेत्रों में अर्थशास्त्र पिछड़ा रहेगा। अस्तु, इसे कला मानना ठीक नहीं।

किन्तु दूसरी ओर बहुत से अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों ही है। मनुष्य तथा समाज के प्रतिदिन के व्यावसायिक जीवन में समय-समय पर अनेक आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न होती रहती हैं। अर्थशास्त्र इन समस्याओं के कारणों और परिणामों पर ही विचार नहीं करता, बल्कि उनके सुलझाने का मार्ग तथा साधन भी बताता है। यह हमें उन व्यावहारिक साधनों और उपायों से परिचित कराना है जिनके द्वारा आर्थिक कष्टों को दूर कर अधिक से अधिक सुख और समृद्धि बढ़ाई जा सकती है। कला का यही कार्य होता है। इसलिए अर्थशास्त्र एक कला भी है।

वास्तव में जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, प्रत्येक विज्ञान का एक अपना व्यावहारिक अथवा क्रियात्मक रूप होता है। वही कला कहलाता है। अर्थशास्त्र में भी अपना यह अर्थ व्यवहार रूप है। अर्थशास्त्र के कला का आशय किसी दिये हुए लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आर्थिक विद्वानों के व्यावहारिक प्रयोग में है।

उपरोक्त बातों से अर्थशास्त्र का क्षेत्र स्पष्ट है। इसका विषय मनुष्य और सम्पत्ति है। यह एक विज्ञान है। परार्थ और आदर्श-मूलक दोनों रूप इसमें हैं। और इसका एक व्यावहारिक अथवा क्रियात्मक रूप भी है जिसे कला कहा जा सकता है।

## अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों में सम्बन्ध (Relation of Economics to other Sciences,

अर्थशास्त्र के विषय और उसके क्षेत्र के सम्बन्ध में अगर कहा जा चुका है कि अर्थशास्त्र में मानव जीवन में आर्थिक पहलू का अध्ययन होता है और इस अध्ययन के वैज्ञानिक और जलात्मक दोनों रूप हो सकते हैं। यहाँ एक बात को स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। वह यह है कि आर्थिक पहलू अन्य पहलुओं में स्वतन्त्र नहीं है। यह दूसरों पर अपना प्रभाव डालता है और वगैरह दूसरों में प्रभावित होता है। आर्थिक सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक व अन्य पहलुओं एक दूसरे से इतने मिले हुए होते हैं कि एक को भली प्रकार समझने के लिए दूसरों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। अतएव अर्थशास्त्र का विषय स्वतः सीमित व पूर्ण नहीं है। यह अन्य शास्त्रों से बहुत घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। यहाँ तक कि इसके और कुछ शास्त्रों की बीच सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती। कभी-कभी यह कहना कठिन हो जाता है कि मानव जीवन से सम्बन्ध रखने वाली अधिक बात एक विज्ञान के अन्तर्गत आती है अथवा दूसरे विज्ञान के।

संक्षेप में, हम यहाँ विवेचन करेंगे कि अर्थशास्त्र तथा कुछ अन्य शास्त्रों में क्या-कैसा सम्बन्ध है।

**अर्थशास्त्र और राजनीति (Economics and Politics)—** अर्थशास्त्र में मनुष्य और सम्पत्ति के सम्बन्धों का अध्ययन होता है और राजनीति में मनुष्य और राज्य के सम्बन्धों का। दोनों मानव-वित्तन की शाखाएँ हैं और परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। वर्तमान समय में ये एक-दूसरे पर अधिक प्रभाव डालने लगी हैं और समय के साथ इनका परस्पर सम्बन्ध और अधिक घनिष्ठ होता जा रहा है। किसी देश की आर्थिक स्थिति और प्रगति बहुत कुछ उस देश की शासन प्रणाली पर निर्भर करती है। राज्य-शासन की नीति-नीति, नियम-कानून, आदि

जाता है सम्पत्ति के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, व्यापार-व्यवसाय आदि सभी आर्थिक कार्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि इनके द्वारा देश की सारी अर्थ-व्यवस्था बदली जा सकती है। यदि राज्य-शासन की रीति-नीति व नियम-कानून देश की अर्थ-व्यवस्था के पक्ष में हितकर हूँ तो अर्थ-व्यवस्था मजबूत होगी, तजी और सतृलित ढग से उसमें उत्तति होगी जिसके फलस्वरूप जन साधारण का जीवन-स्तर ऊपर उठेगा। किन्तु यदि नियम कानून विरुद्ध पड़ें तो अर्थ-व्यवस्था को भारी क्षति पहुँचेगी। उसको प्रगति रक जायगी और सम्भव है उससे विभिन्न अंगों के बीच का तालमेल भी जाना रहे। विदेशी राज्य के समय में भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर राजनीतिव कारणों का ऐसा ही बुरा प्रभाव पड़ा था। मजदूरी, बकारी, पूँजीपतियों और मजदूरों के झगड़े, धन वितरण की विषमता आदि जैसी आर्थिक समस्याएँ समुचित राज्य-व्यवस्था और नियन्त्रण के बिना सफलतापूर्वक सुलझाये नहीं जा सकने। इस प्रकार राजनीति का अर्थशास्त्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अर्थशास्त्री को आर्थिक बातों पर विचार करते समय राज्य-शासन की रीति नीति को ध्यान में रखना पड़ता है। उसे यह देखना होता है कि राज्य-व्यवस्था का आर्थिक स्थिति पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ता है।

दूसरी ओर राजनीतिज्ञ को भी आर्थिक पहलू पर ध्यान-पूर्व विचार करना पड़ता है। राज्य सम्बन्धी नीतियों के निर्धारण में आर्थिक बातों का विशेष स्थान होता है। किसी रीति-नीति के अपनाते व कानून बनाने के पहले आर्थिक परिस्थितियों और मन्शाओं पर विचार कर लेना बहुत जरूरी होता है। अनेक राजनीतिक उल्लान और समस्याएँ आर्थिक प्रश्नों के कारण पैदा होती हैं। यही नहीं, बहुत-कुछ अर्थ तक राज्य की शक्ति और उसके कार्य अर्थ-व्यवस्था के स्वरूप और जनकी तरफ पर निर्भर है। अस्तु स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र और राजनीति एक दूसरे को बहुत प्रभावित करते हैं। दोनों के बीच कोई सीमा-रेखा खींचना सम्भव

नहीं है। बहुत-सी समस्याएँ ऐसी हैं जो दोनों के अन्तर्गत अध्ययन की जाती हैं जैसे जेल-मुधार, धर्म सम्बन्धी कानून, एकाधिकार-नियंत्रण आदि।

**अर्थशास्त्र और आचारनीति शास्त्र (Economics and Ethics)**—यद्यपि इन दोनों के अध्ययन के क्षेत्र अलग-अलग और विशिष्ट हैं, फिर भी इन दोनों में घनिष्ट सम्बन्ध है। आचारनीति शास्त्र में मनुष्य के आचार-व्यवहार व रीति-नीति का विचार किया जाता है। आचार-व्यवहार पर आर्थिक बातों का बहुत असर पड़ता है। बहुत अर्थ में मनुष्य व समाज की आचारनीति जीविका के उद्देशन तथा उपभोग के द्वारा निर्धारित होती है। जिन तरीकों से मनुष्य अपनी जीविका चलाता है, जिस वातावरण में उसे रहता और काम करना पड़ता है, जिस ढंग से वह अपनी आमदनी को खर्च करके आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इन सब बातों का उसके चरित्र, और आचारनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर आचारनीति का मनुष्य की आर्थिक स्थिति पर बहुत असर पड़ता है। आर्थिक क्रियाओं को करने समय नैतिक पक्ष को ध्यान में रखना होता है। अनेक व्यवसाय आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होने पर भी इस कारण छोड़ दिये जाते हैं कि वे नैतिक दृष्टि से उचित नहीं होते। सच्चा आर्थिक कार्य अन्त में नैतिक कार्य होता है। इन प्रकार अर्थशास्त्र और आचारनीति शास्त्र में निकट सम्बन्ध है।

**अर्थशास्त्र और इतिहास (Economics and History)**—इन दोनों विषयों में भी बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है। इतिहास अर्थशास्त्री के लिए अध्ययन-सागरी जुटाता है। इसके द्वारा पुराने काल की आर्थिक स्थितियों और सिद्धान्तों की जानकारी होती है जिससे वर्तमान स्थिति के समझने और वैज्ञानिक सिद्धान्तों के स्थापन और निरूपण में बड़ी सहायता मिलती है। किसी भी आर्थिक समस्या को बिना उसके पूर्व इति-

हास की जानकारी के हल नहीं किया जा सकता। आज को अधिकांश आर्थिक समस्याओं का अपना एक इतिहास है। उसे पूरी तरह समझे बिना इन समस्याओं को सफलतापूर्वक मुलझाया नहीं जा सकता। अस्तु अर्थशास्त्र इतिहास का बहुत ऋणी है। किन्तु दूसरी ओर इतिहास भी अर्थशास्त्र का ऋणी है। आर्थिक सिद्धान्तों का ज्ञान इतिहास लेखक के लिए अत्यन्त आवश्यक है। आर्थिक स्थितियों के विश्लेषण के बिना इतिहास का कोई विशेष महत्त्व नहीं। यह ठीक ही कहा गया है कि इतिहास के बिना अर्थशास्त्र अधूरा है और अर्थशास्त्र के बिना इतिहास का कोई रस नहीं।

### QUESTIONS

1. Which things would you include in describing the scope of Economics? Explain them fully.
- (2) What do you mean by the terms 'science' and 'art'? Do you think that Economics is both a science and an art?
3. What is meant by positive and normative science? Is Economics only a positive science or has it a normative aspect as well?
4. Define Economics and briefly show its relation with Politics and Ethics

## अध्याय ३

### अर्थशास्त्र के नियम

(Laws of Economics)

‘नियम’ शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ तथा व्यवहार हैं। मुख्यतः नियमों के चार विभाग किये जा सकते हैं —राज्य-नियम, नैतिक-नियम, व्यावहारिक नियम तथा वैज्ञानिक नियम। इन चार प्रकार के नियमों का उल्लेख करने से हमें यह समझने में आसानी होगी कि अर्थशास्त्र के नियम क्या हैं और वे किस तरह अन्य नियमों में भिन्न हैं।

**राज्य-नियम (Statutory Laws)**—प्रत्येक देश में कुछ नियम वहां के राष्ट्र अथवा पार्लियामेंट द्वारा बनाये जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनका पालन करना अनिवार्य होता है। वे यह बताते हैं कि अमुक कार्य वहां के निवासी कर सकते हैं और अमुक कार्य नहीं। इन नियमों के उल्लंघन करने वालों को राज्य की ओर से उचित दण्ड दिया जाता है। ऐसे नियमों या कानूनों को ‘राज्य नियम’ कहा जाता है। ये नियम सदा एक-मे नहीं बने रहते। सरकार इनमें समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन लाती रहती है और नये नियम भी बनाये जाते हैं। जिस देश के वे नियम होते हैं, वही के लिए वे लागू होते हैं, बाहरी देशों के लिए नहीं।

**नैतिक-नियम (Moral Laws)**—इनका सम्बन्ध नीति, आदर्श तथा धर्म से है। ये बताते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जैसे मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, आदि। इन्हें ‘नैतिक नियम’ कहते हैं। इनके उल्लंघन करने वालों को राज्य की ओर से दण्ड तो नहीं दिया जा सकता, पर ऐसे लोग नैतिक दृष्टि में नीचे गिर जाते हैं।

**आमहारिक नियम (Customary Laws)**—आमहारिक नियम का अभाव उन नियमों से है जो किसी आदि की सामाजिक रीतियाँ अथवा परम्परागत रिवाजों में स्थापित नियमों से होते हैं। जैसे हिन्दू समाज में कई ऐसे रिवाज प्रचलित हैं जिन्हें लोग जन्म, विवाह, मृत्यु आदि अवसरों पर पालन करते हैं। जो ऐसा नहीं करते वे उस समाज की दृष्टि से नीचे गिर जाते हैं।

**वैज्ञानिक नियम (Scientific Laws)**—ये कारण और उनके परिणाम का परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने हैं। इनके द्वारा यह पता लगता है कि अमुक कारण का क्या परिणाम होगा। जो नियम इस तरह का बतलाते हैं अर्थात् कारण और परिणाम का सम्बन्ध बताते हैं उन्हें वैज्ञानिक नियम कहा जाता है, जैसे आकर्षण-बलित या नियम। यह नियम इस बात को बताता है कि प्रत्येक वस्तु, जो हवा में भारी है, आकाश के न गिरने पर पृथ्वी पर गिर पड़ेगी। इसलिए यह एक वैज्ञानिक नियम है।

### अर्थशास्त्र के नियमों की विशेषताएँ

(Nature of Economic Laws)

अर्थशास्त्र के अन्तर्गत कई नियमों का उल्लेख किया जाता है जैसे भाग का नियम, उपभोगिता द्वारा नियम, समसमानता उपभोगिता नियम, न्यायन उत्पत्ति-वृद्धि या द्वारा नियम आदि। यह पूछा जा सकता है कि ये नियम किस प्रकार के हैं? क्या ये सरकार की ओर से बनाए जाते हैं? अथवा क्या इनका सम्बन्ध धर्म या रीति रिवाजों में है? या क्या ये वैज्ञानिक नियम हैं?

अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अतएव इसके सब नियम वैज्ञानिक नियम अर्थात् सिद्धान्त हैं। अब वैज्ञानिक नियमों की तरह अर्थशास्त्र के नियम भी कारण और परिणाम का परस्पर सम्बन्ध स्थापित करते हैं। वे बताते हैं कि अमुक आर्थिक स्थिति में अमुक कारणों का अमुक परिणाम होगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अर्थशास्त्र मुख्यतः मनुष्य के प्रतिदिन



के व्यावसायिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले कार्यों का अध्ययन है। यह उन कार्यों के कारण और परिणाम के परस्पर सम्बन्ध के विषय में प्रकाश डालता है। यह इस बात की छानबीन करता है कि मनुष्य विशेष दशाओं में किस तरह से बर्ताव करते हैं। यदि किसी विशेष आर्थिक स्थिति में एक ही प्रकार का बर्ताव या सम्बन्ध देखने में आता है, तो उसे एक निश्चित रूप लेकर अर्थशास्त्र का नियम कहने लगते हैं। उदाहरण द्वारा इसे और स्पष्ट किया जा सकता है। हम यह प्रतिदिन देखते हैं कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, तो मांगारत उस वस्तु की माग घट जाती है, और मूल्य के गिर जाने से माग में वृद्धि होती है। इस तरह का सम्बन्ध करीब-करीब हर जगह और हरेक वस्तु के साथ देखने में आता है। अर्थशास्त्रज्ञ इस बात को नियमित रूप से कहते हैं कि मूल्य के घटने और बढ़ने से, यदि अन्य सभी बातें वैसे ही रहें, तो माग में वृद्धि और कमी की प्रवृत्ति होती है। यह अर्थशास्त्र का एक नियम है जिसे माग का नियम कहते हैं। यह नियम वस्तु की कीमत और उसकी माग के बीच का परस्पर सम्बन्ध स्थापित करता है। यह बताता है कि मूल्य के उतार-चढ़ाव का माग पर क्या परिणाम होता है। इस तरह का सम्बन्ध स्थापित करना वैज्ञानिक नियम का कार्य है। इसलिए माग का यह नियम वैज्ञानिक नियम है। अर्थशास्त्र के अन्य नियम भी इसी प्रकार के हैं। अस्तु, वे सभी वैज्ञानिक नियम हैं।

उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र के नियम अन्य प्रकार के नियमों से बिलकुल विभिन्न हैं। आर्थिक नियम किसी राष्ट्र या सरकार द्वारा नहीं बनाये जाते। ये किसी एक देश में ही लागू नहीं होते, और न इनके उल्लंघन करने वाले को किसी प्रकार का सरकारी दण्ड ही दिया जा सकता है। ये किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा अथवा भावों हमारे सामने नहीं रखते। इनका तो केवल एक कार्य है—वह है कारण और परिणाम का परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना।

अर्थशास्त्र के नियमों के सम्बन्ध में एक-दो बातें ध्यान देने योग्य हैं । एक तो यह कि ये एक विरोध परिस्थिति में ही लागू हो सकते हैं । प्रत्येक नियम के साथ यह शर्त लगी हुई होती है कि अन्य सब बातें पूर्ववत् ही रहें, स्थिति में कोई परिवर्तन न हो । परिस्थिति के बदल जाने से सिद्धान्तों में हेर-फेर आ जाता है, ये ठीक नहीं उगलते । पर इसका यह अर्थ नहीं कि अर्थशास्त्र के नियम गलत या व्यर्थ हैं । प्रत्येक शास्त्र तथा विज्ञान के सम्बन्ध में यह धर्म लागू होती है । उसके नियम उसी दशा में पूरी तरह लागू होते हैं जब यह मान लिया जाता है कि अन्य सब बातों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । परिस्थितियों के बदल जाने पर कोई भी सिद्धान्त लागू नहीं हो सकता । उदाहरण के लिए आकर्षण-शक्ति के सिद्धान्त को ही ले लीजिए । इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु को, जो हवा से भारी हो, आधार के न रोकने पर जमीन पर गिर पड़ना चाहिए । लेकिन यह बात कई जगहों पर लागू नहीं होती । हवाई जहाज व गुब्बारे नीचे न गिरकर ऊपर उठ जाते हैं । इसका कारण यह है कि विरोधी परिस्थितियाँ तथा बाधाएँ बीच में आकर उन चीजों को नीचे गिरने से बचाती रहती हैं । लेकिन इसके आधार पर कौन कह सकता है कि आकर्षण शक्ति का सिद्धान्त गलत है । अस्तु, यदि परिस्थितियों में अन्तर आ जाने से अर्थ-शास्त्र के नियम किसी समय या स्थान पर लागू न हो सके, तो हमने यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वे नियम ठीक नहीं हैं । उनकी सच्चाई में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ।

दूसरी बात यह है कि अर्थशास्त्र के नियम अपेक्षाकृत कम निश्चित और स्थिर हैं । ये पूर्ण रूप से नहीं कहते कि अमुक कारण का अमुक परिणाम अवश्य होगा । नियमों के कम निश्चिन अथवा स्थिर होने के अनेक कारण हैं । सर्वप्रथम, अर्थशास्त्र परिवर्तनशील स्वभाव वाले मनुष्यों की इच्छाओं तथा कार्यों का अध्ययन है । मनुष्य स्वेच्छाचारी है । उसके स्वभाव को नियमबद्ध नहीं किया जा सकता, और न यह आशा ही की जा सकती है कि वह सदैव उसी तरह बर्ताव करता रहेगा । उसकी इच्छाएँ

बराबर बदलती रहती हैं। वे अत्यन्त अनिश्चित हैं। चूंकि इन्हीं के आधार पर अर्थशास्त्र के नियम बनाये जाने हैं, इस कारण वे मदा इतने ठीक नहीं बैठते जितना कि उन्हें बैठना चाहिए। दूसरे, आर्थिक जीवन पर तरह-तरह के प्रभाव पड़ने रहते हैं। राजनैतिक, धार्मिक, आदि मनीषियों का प्रभाव मनुष्य की आर्थिक प्रवृत्तियों पर पड़ता है। कारणवश अर्थशास्त्र के नियम, जिनका सम्बन्ध केवल आर्थिक प्रवृत्तियों से ही है, पूर्ण रूप से निश्चित नहीं हो पाते। तीसरे, अर्थशास्त्र में प्रत्यक्ष प्रयोग सम्भव नहीं है क्योंकि इसका सम्बन्ध मनुष्य से है जो एक जीवित तथा स्वतन्त्र प्राणी है। इसरी इच्छाएं रोकी नहीं जा सकती। इन सब कारणों से अर्थशास्त्र के नियम कम निश्चित होते हैं।

इसके विपरीत भौतिक विज्ञान के नियम पूर्ण रूप से निश्चित सम्बन्ध स्थापित करते हैं और वे सर्वत्र लागू होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि भौतिक नियमों का सम्बन्ध मनुष्य की अनस्थिर इच्छाओं से नहीं, बल्कि भौतिक वस्तुओं से है जो निश्चित और अपरिवर्तनशील हैं। इसके अनिश्चित भौतिक विज्ञानों में प्रत्यक्ष प्रयोग का अवलम्बन पूर्णरूप में इच्छानुसार किया जा सकता है। प्रयोगशाला में विरोधी परिस्थितियों को दूर रखकर उस बात की, प्रयोग द्वारा परीक्षा की जा सकती है कि अमुक कारण होने पर अमुक परिणाम होगा। यही कारण है कि भौतिक नियम बड़े निश्चित होने हैं। आकर्षण बल का नियम एक भौतिक नियम है। यह बताता है कि किस तरह एक वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होगी है। चाहे वह चरतु कोई भी वस्तु न हो, पृथ्वी उसे अपनी ओर अवश्य खींचेगी। इसमें अका का लेशमात्र भी स्थान नहीं है। अर्थशास्त्र के नियम इतने निश्चित नहीं हैं। इसलिए उनकी तुलना भौतिक नियमों से नहीं की जा सकती।

आर्थिक नियम ज्वार-भाटा के नियमों (laws of tides) के समान हैं। ज्वार-भाटा के नियम यह बताते हैं कि किस तरह सूर्य और

चन्द्रमा के प्रभाव में एक दिन में दो बार ज्वार-भाटा उठता और गिरता है, किन्तु तरह नवीन तथा पूर्ण चन्द्रमा के दिन प्रबल ज्वार-भाटा उठता है, आदि । पर ये निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि अमुक स्थान पर किम समय ज्वार-भाटा तेंजी से आयेगा । कारण, मौसम व हवा आदि के प्रभाव में ज्वार-भाटा की गति में काफी अन्तर पड़ जाता है । ज्वार-भाटा के नियम केवल यह कह सकते हैं कि अमुक स्थान अथवा समय पर इस प्रकार के ज्वार-भाटा की सम्भावना है । हो सकता है, तेज हवा या वर्षा के कारण अनुमान ठीक न सिद्ध हो । यही दशा अर्थशास्त्र के नियमों की भी है । ये मनुष्य की प्रवृत्तियों की ओर संकेत करने हैं जिनसे प्राय और अकस्मात् परिवर्तन होता रहता है । फलतः आर्थिक नियम निश्चित रूप से सम्बन्ध नहीं स्थापित कर पाते । ये ज्वार-भाटा के नियमों की तरह यह बताते हैं कि अमुक आर्थिक परिस्थिति में अमुक परिणाम होने की संभावना है ।

यद्यपि आर्थिक नियम भौतिक नियमों की तुलना में कम निश्चित हैं, फिर भी वे अन्य समाज शास्त्रों के नियमों से बड़ी अधिक निश्चित हैं । अर्थशास्त्र का सम्बन्ध मनुष्य की उन इच्छाओं तथा कार्यों में है जिनका माप द्रव्य अथवा मुद्रा द्वारा किया जा सकता है । इस कारण अर्थशास्त्र के नियमों में अधिक यथार्थता आ जाती है और विचार, छान-बीन तथा निर्णय करने में श्रुति होती है । अन्य सामाजिक विज्ञानों को द्रव्य ऐसा कोई माप दण्ड प्राप्त नहीं है । अतएव उनके नियम आर्थिक नियमों की अपेक्षा बहुत ही अनिश्चित होते हैं ।

### QUESTIONS

1. What are the different meanings attached to the term 'Law'? How do they differ from the economic sense of this term ?
2. Explain the distinction between an economic law and a statutory law. Show how all economic laws are mere statements of tendencies.

- 3 'The laws of Economics are to be compared with the laws of tides rather than with the simple and exact law of gravitation' Comment
- 4 Are economic laws less exact? If so, what are the causes?
- 5 Compare and contrast economic laws with the laws of physical sciences
- 6 'Economic laws are the most exact of all the social laws' Do you agree? Give reasons

## अध्याय ४

### अर्थशास्त्र का महत्त्व

#### (Importance of Economics)

विभी भी विषय का अध्ययन मुख्यतः दो उद्देश्यों से किया जाता है । एक तो ज्ञान के लिए और दूसरे उम विषय से प्रतिदिन के जीवन में होने वाले लाभ व कल्याण के लिए । प्रत्येक विषय के अध्ययन में ये दोनों बातें मॉडी-बहुत मात्रा में पाई जाती हैं । विभी अध्ययन में ज्ञान की मात्रा अधिक होती है, और विभी में व्यावहारिक लाभ उठाने की । उदाहरणार्थ भूषम विज्ञान अथवा मनोविज्ञान में, ज्ञान-उद्देश्य का स्थान बहुत ऊँचा है । इन विषयों का अध्ययन मुख्यतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है । दूसरी ओर कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें व्यावहारिक लाभ का असा अत्यधिक होता है, जैसे वैद्यक, न्यायशास्त्र, आदि ।

अर्थशास्त्र के अध्ययन में हमें यह दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं : सैद्धान्तिक (theoretical) और व्यावहारिक (practical) । इससे हमारे ज्ञान-कोष में वृद्धि होती है और साथ ही व्यावहारिक क्षेत्र में अनेक सुविधाएँ भी मिलती हैं । इन्हीं दोनों दृष्टिकोणों से अर्थशास्त्र के अध्ययन के महत्त्व का हम यहाँ निरूपण करेंगे ।

#### सैद्धान्तिक लाभ

##### (Theoretical Importance)

ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से अर्थशास्त्र का अध्ययन काफी महत्त्वपूर्ण है । यह सत्यानुसन्धान का एक साधन है जिसमें हम सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाले मानव-जीवन और समाज के यथायं तथ्यों का पूरा ज्ञान

प्राप्त होता है। साथ ही, यह हमें सत्यानुसन्धान के लिए सभी आवश्यक शक्तियों से सुसज्जित करता है। इनके द्वारा सतर्क निरोधण, धैर्यपूर्ण विश्लेषण, उचित तर्क तथा ठीक निर्णय करने का अभ्यास होता है।

हमारा दृष्टिकोण भी इसके द्वारा विस्तृत हो जाता है। यह अर्थशास्त्र का ही अध्ययन है जो हमें बताता है कि धन की उत्पत्ति कैसे होती है, क्यों और कैसे धन का विनिमय और वितरण होता है, कैसे वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है, किस तरह धन के उपभोग से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस ज्ञान के बिना हम अपने सामाजिक तथा आर्थिक जीवन को मली-भाति नहीं समझ सकते। अर्थशास्त्र हमें राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान दिलाता है और इसके द्वारा हमें यह पता लगता है कि इसके बीच हमारा क्या स्थान है। आधुनिक समाज की अनेक जटिल आर्थिक समस्याओं को समझने और सुलझाने के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। समाज की उन्नति तभी हो सकती है जब कि मनुष्य का पेट भरा हो। इस आर्थिक पहलू का ज्ञान हमें अर्थशास्त्र द्वारा होता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र हमें मानव-समाज के आर्थिक प्रयत्नों से मली-भाति परिचित कराता है। अस्तु, हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का स्थान केवल ज्ञान के लिए अथवा मानवीय शक्तियों के शिक्षण और अभ्युन्नति की दृष्टि से भी बहुत ऊँचा है। यह एक सर्व रक्षिक, महत्व और रसपूर्ण विषय है।

### व्यावहारिक लाभ

#### (Practical Importance)

अर्थशास्त्र के अध्ययन का व्यावहारिक अथवा वित्तीय महत्त्व बहुत अधिक है। बहुत-से अर्थशास्त्रवेत्ताओं का तो कहना है कि अर्थशास्त्र का प्रमुख महत्त्व व्यावहारिक क्षेत्र में ही है। इसके ज्ञान द्वारा जीवन की अनेक सुस्थितियाँ सरलतापूर्वक सुलझायी जा सकती हैं। चाहे जिस दृष्टिकोण से हम देखें, अर्थशास्त्र का ज्ञान व्यावहारिक जीवन के

लिए अत्यन्त उपयोगी है । नशेष में, हम यहां यह विचार करेंगे कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यावहारिक जीवन में कितना लाभदायक है ।

सर्वप्रथम, उपभोक्ता अथवा घर के मुखिया को ही ले लीजिए । प्रत्येक गृहस्वामी को यह इच्छा होती है कि वह परिवार को मोमित आय को इस प्रकार से व्यय करे जिसमें कुटुम्ब वालों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके । अर्थशास्त्र द्वारा उन नियमों का बंध होता है जिनके पालन से अधिकतम कृति प्राप्त हो सकती है, जैसे सम-सीमान्त-उपयोगिता का नियम, पारिवारिक-आय-व्यय-तालिका आदि । जिस घर के मुखिया ने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है, वह अपनी जिम्मे-वारी को दूसरों की अपेक्षा अधिक सफलतापूर्वक पूरा कर लेगा । अस्तु, अर्थशास्त्र के अध्ययन से उपभोक्ता को अपनी मोमित आय से अधिकतम कृति प्राप्त करने अथवा पारिवारिक सुख और सतोष बढ़ाने में बड़ी सहायता मिलती है ।

अर्थशास्त्र का ज्ञान व्यापारी अथवा व्यवसायी के लिए भी बहुत उपयोगी है । आधुनिक उत्पत्ति तथा व्यापार प्रणाली बहुत ही जटिल है । मंदैव बड़ी-बड़ी समस्याएँ उत्पन्न होतीं रहती हैं । इनकी समझने और मूल्यज्ञान के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है । अर्थ-शास्त्र उत्पात्ति और व्यापार सम्बन्धी सभी बातों पर उचित प्रकाश डालता है । यह बतलाता है कि उत्पत्ति के कौन-कौन से साधन हैं, किन्-विन्-इन्हें उत्पत्ति की जा सकती है तथा किस क्षेत्र में कौन सी मुख्य कठिनाईयाँ आती रहती हैं और कैसे उनका सामना किया जा सकता है । इसके द्वारा व्यापारियों अथवा उत्पात्तिकर्त्ताओं को विशिष्टीकरण, वैज्ञा-निक व्यवस्था, बेकिंग कारोबार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आदि महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्राप्त होती है । इन बातों को समझें बिना उत्पत्ति अथवा व्यापार क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना असम्भव है । अतएव अर्थ-



शास्त्र का ज्ञान उत्पत्तिकर्ता, व्यापारी तथा व्यवसायी के लिए बहुत ही लाभप्रद है ।

अर्थशास्त्र की जानकारी मजदूरों के लिए भी बहुत लाभदायक है । उनके अध्ययन में उन्हें यह अच्छी तरह में मालूम हो जाता है कि धनोत्पत्ति में उनका क्या स्थान है । इसके द्वारा उनको इस बात का पूरा ज्ञान हो जाता है कि उन्हें एक विशेष मजदूरी क्यों मिलती है, वह किस-किस दातों पर निर्भर करती है और वह किस प्रकार बढ़ सकती है ? उन्हें अपने अधिकारों के समझन और उनके निर्माण उचित सस्त्र या उपायों में काम लेने की शिक्षा भी मिलती है । संक्षेप में, उन्हें इस बात का पूरा बोध हो जाता है कि अपने हितों की रक्षा और उत्पत्ति के लिए सहयोग और संगठन विदना आवश्यक है ।

इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र का ज्ञान राजनैतिक नेताओं के लिए भी बहुत महत्त्व रखता है । अर्थशास्त्र राजनीतिज्ञ को वर्तमान आर्थिक समस्याओं तथा उनके दूर करने के विभिन्न तरीकों का बोध कराता है जिसके बिना वह अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता । अर्थशास्त्र के राजस्व विभाग में राजकीय आय तथा व्यय सम्बन्धी बातों का विवेकान किया जाता है जिसके ज्ञान में राजनीतिज्ञ राज्य और समाज को आर्थिक समस्याओं को गली भाँति समझ सकता है और उनके हल करने में सफल हो सकता है ।

सामाजिक समृद्धि को बढ़ाना समाज-सुधारक का प्रमुख लक्ष्य है । वह सदैव सामाजिक मुल्य-समृद्धि के बढ़ाने के लिए उपाय खोजता रहता है । उसे इस काम में अर्थशास्त्र से बहुत अधिक सहायता मिलती है । अर्थशास्त्र मुख्यतः एक समाज शास्त्र है । यह समाज की आर्थिक समृद्धि का अध्ययन करता है । सम्पत्ति और सामाजिक समृद्धि में क्या, कैसा और कितना सम्बन्ध है, इसका बोध हमें अर्थशास्त्र द्वारा पूर्ण रूप में होता है । यह हमें बताता है कि भौतिक साधनों का प्रभाव हमारी समृद्धि के ऊपर

जितना पड़ता है । अस्तु, अर्थशास्त्र ज्ञान-सम्पन्न समाज-मुधारक अपने मुधार के कार्य में पर्याप्त सफलता प्राप्त कर सकता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र का अध्ययन उपभोक्ता, व्यापारी, उत्पत्तिकर्ता, मजदूर, राजनीतिज्ञ, समाज-मुधारक आदि सभी के लिए आवश्यक और उपयोगी है ।

अर्थशास्त्र का ज्ञान व्यक्तिगत दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी आवश्यक है । जैसा कि हम पहले कह चुके हैं अर्थशास्त्र मुख्यतः एक सामाजिक विषय है । इसका मुख्य उद्देश्य समाज की आर्थिक उन्नति करना है जिसमें जनसाधारण की आर्थिक दशा सुधरे और उनका जीवन सुलभ हो सके । समाज की अधिकतर कठिनाइयाँ या समस्याएँ आर्थिक कारणों से ही उत्पन्न होती हैं । अतएव सामाजिक उन्नति इन्हीं समस्याओं के सुलझाने के ऊपर निर्भर है । पर इन समस्याओं का हल सभी सम्भव हो सकता है जब कि हम इनके आर्थिक कारणों को बिबिध रूप से जान लें । इसके लिए हमें अर्थशास्त्र की शरण लेनी पड़ेगी । अर्थशास्त्र द्वारा हमें इन बातों का पूरा ज्ञान होता है और साथ ही साथ यह भी पता चलता है कि इन कारणों के दूर करने के क्या-क्या उपाय हो सकते हैं । उदाहरणार्थ वर्तमान समाज की कुछ समस्याएँ ही ले लीजिए । बेरोजगारी और निर्धनता की समस्याएँ आधुनिक समाज की घुरी तख्त से जकड़े हुई हैं । समाज में जात्र जो असान्निध्य की आग फैली हुई है, अधिकतर इन्हीं के कारण है । सामाजिक उन्नति तथा सुख के लिए इनमें दृढ़ता से लड़ना आवश्यक है । अर्थशास्त्र हमें जोर पर्याप्त सहायता देता है । यह इन समस्याओं के कारण तथा उनको दूर करने के उपायों में हमें परिचित कराता है । अतः अर्थशास्त्र का अध्ययन सामाजिक उन्नति तथा कल्याण के दृष्टिकोण से भी अत्यन्त उपयोगी है ।

### QUESTIONS

1. What is Economics ? How far is its study helpful in practical life ?

- 2 Examine the theoretical importance of Economics
- 3 Discuss fully the value of Economics for a businessman, a labourer and a statesman

## आर्थिक जीवन का विकास

(Evolution of Economic Life)

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हमारे चारों ओर सभी कुछ परिवर्तनशील है। परिवर्तन का नियम केवल प्राकृतिक घटनाओं पर ही नहीं, बल्कि सभी बातों पर लागू है। आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक सभी दिशाओं में परिवर्तन होता है। यदि हम मनुष्य के आर्थिक जीवन पर दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि समय-समय पर उसमें बिताने ही परिवर्तन होने रहे हैं। आदिम मनुष्य की आवश्यकताएँ बहुत थोड़ी थी। उनकी पूर्ति का ढंग सीधा और सरल था। मांस, मछली और फल-फूल खाकर वे अपना जीवन निर्वाह करते थे। पर अब वर्तमान युग में आर्थिक जीवन का सारा ढाँचा ही बदल गया है। पुरानी अर्थ-व्यवस्था बदल चुकी है और उसका स्थान नई व्यवस्था ने ले लिया है। हमारी आवश्यकताएँ अब पहले से बहुत बढ़ गई हैं। उनकी पूर्ति के लिए किये गये उद्योग भी पहले की अपेक्षा बिल्कुल विभिन्न हैं। आज-कल बड़े-बड़े कारखाने स्थापित किये गये हैं जिनमें हजारों मजदूर एक साथ काम करते हैं। उत्पादित वस्तुओं के पैमाने पर होने लगी है। व्यापार, मशीन, यातायात के साधनों आदि में भी बड़े परिवर्तन हुए हैं। इन सब कारणों से आज के आर्थिक जगत का रूप बिल्कुल बदल गया है। इसमें अनेक नई-नई विशेषताएँ आ गई हैं। वर्तमान आर्थिक जगत और उसकी विशेषताओं को पूर्ण रूप से समझने के लिए यह ज्ञान लेना आवश्यक होना कि समय-समय पर इसमें क्या-क्या परिवर्तन होते रहे हैं और किस तरह मनुष्य इस तक पहुँचा है।

मनुष्य के आर्थिक जीवन के विकास का क्रमचर ने निम्नलिखित पाँच अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है — आखेटावस्था (Hunting Stage), पशु-पालावस्था (Pastoral Stage), कृषि-अवस्था (Agricultural Stage), हस्त-कला-अवस्था (Hand-craft Stage), और औद्योगिक काल (Industrial Stage or present economic order) । हम यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि इन अवस्थाओं के बीच हम कोई समय-रेखा नहीं खींच सकते और न यही कह सकते हैं कि अमुक निधि में मानव समाज ने एक अवस्था का छोड़कर दूसरी अवस्था में रैर गया है । यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि विश्व के विभिन्न देशों में ये अवस्थाएँ एक साथ नहीं आई हैं और न ऐसा ही हुआ है कि जब एक अवस्था चिन्तक समाप्त हो चुकी हो, सभी दूसरे पाठ का प्रारम्भ हुआ हो । भिन्न-भिन्न देशों की प्रगति पृथक्-पृथक् रही है । यही नहीं, एक ही देश में एक ही समय में तीन अवस्थाओं की विशेषताएँ देखने में आती हैं ।

### आखेटावस्था

(Hunting Stage)

आदिम निवासियों की आवश्यकताएँ थोड़ी और साधारण थीं । उनकी पूर्ति का सब भी सीधा था । आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे प्रकृति पर निर्भर थे । वे स्वयं वस्तुओं को बनाता नहीं जानते थे । इसलिए जो वस्तु बिना रूप में प्रकृति में मिलती उसे उनी कर के प्रयोग करते थे । उनका प्रवास पैदा शिकार, मछली पकड़ना तथा फल-पूत तोड़ना था । जानवरों के चमड़े तथा वृक्ष की छालों से अपने शरीर को ढकते थे । शिकार का कार्य अत्यन्त अनिश्चित होने के कारण कभी-कभी तो शिकार बहुत आसानी से मिल जाता, पर कभी ऐसा भी होता कि दिन भर चक्कर लगाने के बाद भी थोड़ा शिकार नसोब न होता । अतएव कभी तो लोपा के पक्ष लागू-नामची काफी होती और कभी भूख मरना पड़ता था ।

जीवनोपार्जन के साधन अनिश्चित होने के कारण, लोगोंमें पारस्परिक सघर्ष का होना आवश्यक था । युद्ध द्वारा निर्बल व्यक्तियों को दाम बना लिया जाता था और जब भोजन के लिए कोई सामग्री नहीं मिलती थी तो उन दामों को मार कर उनके मांस पर विजेता अपना नियंत्रण करने में । अस्तु उम समय के लोग नरमक्षी थे ।

भोजन के अभाव के कारण उम समय का मनुष्य एक स्थान में ठूमे स्थान पर शिकार की खोज में घूमता फिरता था । न उसका कोई घर था न दर । वह सान्नायवोश था । यही कारण है कि उस समय की जनमर्या बहुत कम थी । पर्यटनशील जानियों के बीच मर्त्य का होना एक तरह से स्वाभाविक था ।

आर्थिक विकास की इस अवस्था में न तो धर्म-विभाजन था, और न वस्तुओं का विनिमय । मनुष्य पूर्ण रूप में स्वावलम्बी (self-sufficient) था । वह अपना सब काम स्वयं ही करता था । उनकी आवश्यकता, प्रयत्न तथा सुख के बीच सीधा सम्बन्ध था ।

यह स्वतन्त्र आर्थिक अवस्था का समय था । इस समय व्यक्तिगत सम्पत्ति का स्थान न था । नृमि सब की सम्मिलित सम्पत्ति थी ।

### पशुपालनावस्था (Pastoral Stage)

प्रगति के साथ धीरे-धीरे मनुष्य इस बात पर पहुँचा कि पशुओं को मारने की अपेक्षा उन्हें पालना कहीं लाभदायक है । आलेटावस्था में मनुष्य अपना निर्वाह शिकार और मछली पकड़ कर करता था । वह साधन पर्याप्त और निश्चित न था क्योंकि कभी शिकार मिल जाता, और कभी नहीं । इसलिए मनुष्य ने पशुपालन का कार्य प्रारम्भ किया जिसमें शिकार आदि न मिलने पर भी भोजन का काम चलता रहे । इस विशेषता के कारण इस अवस्था को 'पशुपालनावस्था' कहते हैं । आर्थिक विकास की यह दूसरी अवस्था थी ।

अभी तक लोगों को कृषि-कला का ज्ञान न था। वे किसी प्रकार का पीदा या घाम नहीं उतजा सकते थे। कारणवश इस समय के निवासी घाम तथा चारागाहों की खोज में जानवरों सहित एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। किसी एक स्थान पर घर बनाकर रहना उनके लिए सम्भव न था। बहुधा ऐसी जानियाँ, चारागाहों की खोज में, परस्पर सटा-जगड़ा करती थीं। परन्तु इस समय के युद्ध में पहले की अपेक्षा एक विशेषता यह थी कि युद्धवन्दिशों को मारने के बजाय उन्हें दामता की चेड़ियों में जकड़ लिया जाता था। विजेता उन्हें अपन जानवरों की रखवाली तथा अन्य लाभदायक कार्यों को सौंप दिया करते थे। इस तरह नरभक्षण का स्थान अब दामता ने ले लिया।

अभी तक भूमि पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार न था। केवल दाम, जानवर और हथियार ही व्यक्तिगत सम्पत्ति में गिने जाने थे। चारागाहों पर एक जाति केवल घाम नैप रहने तक अपना अधिकार रखती थी। जगहों एक चारागाह की घाम चर ले जाती, वैसे ही लोग दूसरे चारागाहों की खोज में चल पड़ते।

विनिमय की द्रव्य में अभी तक लोभ अनभिज्ञ थे। वे अपनी आवश्यकताओं की स्वयं ही अपने उद्योग द्वारा पूर्ति करते थे। आवश्यकता, उद्योग तथा नृत्ति के बीच का सम्बन्ध पहले ही जैसा सीधा था।

### कृषि-अवस्था

(Agricultural Stage)

अभी तब मानव जीवन अत्यन्त ही अनिश्चित था। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य बराबर घूमता-फिरता रहता था। फिर भी उसे नियमित रूप से भोजन, वस्त्र आदि की सामग्री प्राप्त न हो पाती थी। धीरे-धीरे उसे कृषि कला का बोध हुआ जिसके द्वारा प्रकृति उसके लिए प्रचुर मात्रा में भोजन की सामग्री प्रदान करने लगी। अब कृषि लोगों

का मुख्य उद्योग बन गई। इसलिए इस अवस्था को कृषि अवस्था कहा जाता है।

कृषि द्वारा लोगों को कई प्रकार की रास सामग्री उपलब्ध होन लगी। मनुष्य की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई और इस तरह आर्थिक उन्नति का मार्ग खुला। कृषि की देल भाल के लिए मनुष्य का एक स्थान पर बसना आवश्यक था। लोग अपने घरों के आस-पास घर बना कर रहने लगे। पशुस्वरूप प्राणियों की अवस्था में दिशिप्यता मान लगी और प्राण निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ। धीरे-धीरे जन-संख्या भी बढ़ने लगी।

कृषि-अवस्था में दासता की प्रथा और भी मजबूत बन गई। खेती-बाड़ी का काम आसानी से दासों को सौंपा जा सकता था। इसलिए विजयता दासों को अनूत्य सम्पत्ति मानने लग। इसके अतिरिक्त भूमि में व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रथा का भी चलन प्रारम्भ होने लगा। जो जिन भूमि पर खेती करता उस पर अपना विशेष अधिकार रखने लगा। अस्तु भूमि लोगों की व्यक्तिगत सम्पत्ति बन गई।

इस काल में प्रत्येक माव पुण्यतया स्वावलम्बी था। उनके निवासों अन्ती समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के माधन मिलजुल कर स्वयं जुटाने थे। सामूह्य तोर में धर्म विभाजन प्रारम्भ हुआ और साथ ही साथ वस्तुओं का विनिमय भी। अब इस अवस्था में आकर जावश्यकता उद्योग तथा नृत्ति के बीच कुछ अन्त में परीक्ष सम्पन्न स्थानि होने लग।

हस्तकला अवस्था

(Handicraft Stage)

अभी तक मनुष्य प्रकृतिदत्त तथा स्वयं में उपकाड हई वस्तुओं पर ही निर्भर था। कपडा वृद्धि के विकास के माध उसे हाथ में साधारण चीज बनाने की कला शत हुई। अब लोग कृषि में अतिरिक्त मृद्भिन्त्य अथवा घरेलू उद्योग बंधों का काम करने लग। धीरे-धीरे लोग अलग अलग वस्तुओं के बनाने में विशेषता प्राप्त करने की चष्टा करने लग। फल-



स्वल्प धन विभाजन न चोर पकड़ा। कोई बड़ई का काम करन लगा कोई कुम्हार बन बैठा कोई कपड़ा बुनन लगा और इस तरह लाग भित भित वस्तुओं के वतान में अबका उद्योग धंधा चल गया। ये लोग चारों तरफ अथवा कलाहारी के नाम से पुकारे जाते थे। इस काल में अधिकतर काम मनुष्य अपने हाथों से ही करता था। मशीनों का प्रयोग अभी प्रारम्भ न हुआ था। इसलिए इस युग को कला-कला युग कहते हैं।

विशिष्टीकरण अथवा धनविभाजन के लिए वस्तुओं का विनिमय आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति अपना कुल समय किसी एक वस्तु के वतान में लगा देता तो उसे अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी वस्तुओं को दूसरों को बनाई वस्तुओं से अवश्य विनिमय करना पड़ता। यही तो वह किस प्रकार अपनी भित भित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा। इसलिए कुम्हार अपने बरतनों की जुगाहे के कपड़ों से किसान अपने अनाज को लोहार के औजारों से बदल बदल करन लग। इस तरह वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय (barter) प्रारम्भ हुआ। आगे चलकर वस्तुओं के पारस्परिक बदल-बदल में अनेक कठिनाइयाँ आन लगीं। जो वस्तु एक के पास जपिक होती उसके लेन वाले हर समय हर स्थान पर नहीं मिलते। और प्रायः जिन्हें उस वस्तु की आवश्यकता होती वे उस वस्तु की आवश्यकता की सभी वस्तुएं नहीं दे पाते। इस तरह बीच तौर में वस्तुओं के बदल-बदल या विनिमय में बहुत असुविधा होती थी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए लोग अपनी वस्तु को खोज करन लग जिसे सभी विनिमय करते समय बिना किसी हिचक के स्वीकार कर लें। भित भित स्थान और समय पर भित भित वस्तुएं विनिमय का माध्यम बनाई गईं। अब चीजों का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से न होकर इन वस्तुओं के माध्यम से किया जान लगा। ऐसी वस्तु को जो विनिमय के माध्यम का काम करती है द्रव्य या मुद्रा (money) कहते हैं। धीरे धीरे द्रव्य न वस्तुओं के पारस्परिक बदल बदल का स्थान ले लिया। इसके कारण व्यापार में काफी उत्पत्ति हुई। द्रव्य का चलन इस काल की एक मुख्य विशेषता है।

पहले ही कारीगर स्वतन्त्र रूप में काम करने थे, किसी की आधीनता में नहीं। वे अपने-अपने औजार रखते थे और अपनी ही पूँजी में कच्चा माल आदि आवश्यक वस्तुओं को खरीदते थे। जो बन्तु तैयार होती थी, उसके बेचने का प्रबन्ध स्वयं करते थे और अपने बेचने में जो कुछ मिलता, वह सब उनका ही होता था। इस अवस्था में उत्पत्ति छाट पैमाने पर की जाती थी। कारीगर उत्पत्ति के कार्य में अधिकतर अपने कुटुम्बियों से ही सहायता लेते थे। क्रमशः उद्योग-धर्मों में उत्पत्ति होते लगे। वस्तुओं की मांग का धेन बढ़ता गया। वस्तुओं के बनाने में अब अधिक पूँजी की आवश्यकता पड़ने लगी। फलस्वरूप अधिक पूँजी वाले व्यापारी कारीगरों को मजदूरी देकर अपना माल तैयार करवाने लगे। इसके कारण कारीगरों की स्वतन्त्रता कुछ अंशों तक जाती रही। जब उन्हें निश्चित समय पर माल तैयार करने व्यापारी-पूँजीपतियों को देना पड़ता था, जिसके बदले उन्हें मजदूरी मिलती थी। उत्पत्ति की इस प्रथा को पारिवारिक प्रणाली (Domestic System) कहा जाता है।

औद्योगिक तथा व्यापारिक उत्पत्ति के साथ-साथ नगरों का बनना आवश्यक था। कारीगर उन स्थानों पर बसने लगे, जहाँ काम के लिए कच्चा माल मिलता, और तैयार माल के बेचने में सुविधा होती। जैमे-जैमे आर्थिक जीवन जटिल होता गया और पारस्परिक सम्बन्ध बढ़ता गया, लोगों को एक-दूसरे के निकट रहने में अधिक सुविधा होने लगी। इस तरह प्रमुख सड़कों पर, नदी तथा समुद्र के किनारे नगरों या ग्रहों का बनना शुरू हुआ। यह इस काल की दूसरी एक विशेषता है।

अब आवश्यकता, प्रयत्न तथा तृप्ति के बीच पहले की तरह मोटा सम्बन्ध न रहा। एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी वस्तुएँ खरीद उत्पन्न न करता था। वह किसी एक वस्तु के बनाने में लग जाता था, जिसके विनिमय द्वारा अन्य इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करता था। हमारे शब्दों में, अब आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए विनिमय का गठारा लेना आवश्यक हो गया।

## वर्तमान औद्योगिक काल

(Present Industrial Stage)

सामान्य-समाज आगे बढ़ता गया। अपनी तन्मयी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य बराबर प्रयत्नशील रहा। आविष्कार करने वाली शक्ति से मनुष्य का हम ओर बढ़ने की महापता मिली। अठारहवीं शताब्दी के दौरान में और उसके बाद अनेक आविष्कारजनक आविष्कार हुए, जैसे जेम्स वाट का 'स्टीम-एजिन' जानके का 'फ्लाइंग शटल' हाररीज का 'स्पिनिंग जेनी', कार्रराण्ट का 'पावर लूम' आदि। इन और दूसरे अनेक आविष्कारों के कारण उत्पादित व्यापार, यातायात, द्रव्य प्रेषण आदि सभी क्षेत्रों में महान परिवर्तन हुए, जिसके फलस्वरूप आर्थिक जगत का सारा रूप और ढांचा ही बदल गया। ये परिवर्तन इतने व्यापक और नातिनारी थे कि इन्हें 'औद्योगिक क्रांति' (Industrial Revolution) का नाम दिया जाता है। इस क्रांति के साथ मनुष्य वर्तमान औद्योगिक काल में पैर रखता है। आर्थिक विकास का यह सबसे नया युग है।

वर्तमान आर्थिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता श्रम विभाजन (division of labour) है। श्रम विभाजन वर्तमान युग की देन तो नहीं है लेकिन पहिले की अपेक्षा यह बहुत बढ़ गया है, बारीक और जटिल हो गया है। अब आम तौर से कोई व्यक्ति किसी वस्तु को आदि से जन्म तक नहीं तैयार करता। एक ही काम के अब अनेक छोटे छोटे भाग कर दिये जाते हैं, जिन्हें भिन्न-भिन्न व्यक्ति या व्यक्ति-समूह करते हैं। वर्तमान काल में श्रम-विभाजन इस सीमा को पहुँच चका है कि शायद छोटे से ही व्यक्ति ऐसे होंगे जो यह कह सकेंगे कि "मैंने स्वयं इस चीज को बनाया है।"

श्रम-विभाजन के फलस्वरूप व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों प्रकार के स्वावलम्बन का करीब-जगीव अन्त हो चुका है। आधुनिक काल में लोग अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ स्वयं तैयार नहीं करते। अपनी विभिन्न

आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए वे एक-दूसरे पर निर्भर हैं। यही हाल अब समार के भिन्न-भिन्न देशों का भी है।

आधुनिक अर्थ-व्यवस्था की एक दूसरी विशेषता बड़े-बड़े मशीनों का उपयोग है। हस्तकला का स्थान अब मशीनों में ले लिया है। यंत्रोत्पादन का अधिकतर कार्य अब विशाल कारखानों में होता है जहाँ हजारों मजदूर एक साथ काम करते हैं। इन कारखानों में भाप, बिजली आदि शक्तियों में चलने वाली मशीनों से काम लिया जाता है। मशीनों के उपयोग में मनुष्य की शक्ति बहुत बढ गई है। अनेकानेक नई चीजें मरने-दाँभों में मिलने लगी हैं। बहुत सी चीजें जो पहिले केवल कुछ धनी मनुष्यों के पहुँच के भीतर थी, अब साधारण व्यक्तियों के पहुँच के भीतर आ गई हैं।

धन-वित्ताङ्गन और मशीनों के परस्पर प्रभाव में उत्पत्ति बड़े पैमाने पर होने लगी है। वर्तमान अर्थ-व्यवस्था की यह एक और मुख्य विशेषता है। आमतौर से अब वस्तुएँ बड़े पैमाने पर बाजार में विप्री के लिए तैयार की जाती हैं। पहिले की अपेक्षा अब मशी का शोध बहुत फँड गया है। बहुत सी वस्तुओं का बाजार किन्नी एक शहर या एक राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, अपितु समार-व्यापी है। बाजारों के विस्तृत करने में यातायात के साधनों में उन्नति, साख और द्रव्य के चलन तथा बैंकिंग कारोबार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वर्तमान आर्थिक जगत में द्रव्य का प्रयोग बहुत बढ गया है। विनिमय का कार्य इसी के माध्यम द्वारा होता है और यही मूल्य का मान और ऋण के लेन-देन का साधन है। द्रव्य के चलन से आर्थिक व्यवहार में बहुत सुविधा हो गई है। विनिमय और हिसाब आवि रखने में जो पहिले कठिनाइयाँ होती थी, वे अब दूर हो गई हैं।

बाजार के विस्तृत होने से उत्पादन-क्षेत्र में छतरे (rural) का अर्थ बहुत बढ गया है। उत्पादक बाजार में बेचने के लिए वस्तुएँ तैयार करते हैं। वे इस बात का अनुमान लगाते हैं कि अमुक वस्तु की भविष्य में किन्नी माण होगी और इसी के आधार पर उत्पात्ति का काम चलता है। लेकिन अब पहिले की तरह मूल्य सीमित नहीं है, और न ही बेचने-खरीदने

वाता में प्रत्यक्ष सम्बन्ध रह गया है। इसलिए उत्पत्ति-कार्य में सतरे का अंग आजकल बहुत बढ गया है।

बाजार के सम्बन्ध में एक बात और याद रखनी होगी, जिसका आधुनिक काल में विशेष महत्व है। वह यह है कि एक प्रकार से बाजार ही वर्तमान आर्थिक समाज की व्यवस्था का आधार और संचालक है। उत्पादक, व्यापारी, उपभोक्ता आदि सभी की आध मटी पर लगी होती है। बाजार के रूप को देखकर ही वे आना-जाना नाम रखते हैं और उनकी सफलता बहुत-कुछ इसी बात पर निर्भर रहती है। जब किसी वस्तु का दाम बाजार में बढ़ने लगता है तो उत्पत्तिकर्ता इस बात में यह समझ लेते हैं कि उस वस्तु की बाजार में कमी है और इस कारण उनकी उत्पत्ति की मात्रा बढ़ाने में उन्हें अधिक लग्न होगा और जब बाजार में दाम गिरने लगते हैं, तो उन्हें यह संकेत मिलता है कि उत्पत्ति की मात्रा कम कर दी जाए। इसी प्रकार उपभोक्ता को भी बाजार-भाव के घटन-बढ़न में अधिक या कम लरोदने का संकेत मिलता है। इस तरह माग और पूर्ति (supply) के बीच समुचित स्थापित होता रहता है। जिस वस्तु की मात्रा माग की अपेक्षा कम है या अधिक है उस बात का पता बाजार-भाव में होता है और उसी के अनुसार माग और पूर्ति में परिवर्तन लये जाते हैं ताकि उनके बीच फिर से समुल्लस आ जाय। अतः, हमसे स्पष्ट है कि आजकल के समय में बाजार का कितना महत्वपूर्ण स्थान है।

वर्तमान आर्थिक समाज को कुछ और विशेषताएँ हैं जिनकी ओर ध्यान दिलाना आवश्यक जान पड़ता है। एक तो यह कि अब आर्थिक व्यवहार में पुराने रीति-रिवाजों का स्थान उठना गया है। पहले बचने-खरीदने वाले में प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता था। वे एक दूसरे को जानते थे और चीजों के भाव आदि तय करने में पुराने रीति-रिवाजों का काफी मानते थे। लेकिन अब लोगों के बीच बहुत परोक्ष सम्बन्ध है और रीति-रिवाजों का स्थान ठेके और प्रतियोगिता ने ले लिया है।

## आर्थिक जीवन का विकास

दूसरी बात यह है कि इस अवस्था में आकर मजदूरों पर काम करने वाले कारीगरों का एक नया वर्ग बन गया है जो श्रमिक-के-साथ साथ और घटता जा रहा है। आम तौर पर कारीगरों ने किए भारी और कीमती मशीनों को खरीद कर स्वतन्त्र रूप से अपने धन्धों को चलाया सम्भव नहीं है, और न ही कारखानों के मस्ते माल ने सामने टिकना उनके लिए आसान है। पन्द्रहवें अरने स्वतन्त्र धन्धों को छोड़ कर बहुत-से कारीगरों ने कारखानों में नौकरी कर ली है। ये अपनी आजीविका के लिए मालिक-मालिक पर निर्भर हैं। पहले की तरह अब ये स्वतन्त्र नहीं रहे। इस तरह आज का समाज दो भागों में बंट गया है—एक तो पूँजीपति जयवा मालिक और दूसरे शोषण करने वाले मजदूर। पूँजी मालिक और मजदूर में कोई विशेष अन्तर नहीं था। दोनों के बीच अच्छा सम्बन्ध था और मिलजुल कर साथ ही काम करने थे। इसलिए मतभेद और झगड़े की गुंजाइश बहुत कम थी। किन्तु अब पहली जैसी बात नहीं रही। मालिक और मजदूर के बीच अब अन्तर किसी न किसी बात पर झगड़े होते रहने हैं, जिसके कारण सभी मजदूर हड़ताल कर बैठने हैं तो सभी मालिक मालाबन्दी की धमकी देते हैं। इन झगड़ों का दुष्परिणाम केवल उन्हें ही नहीं बल्कि मारे समाज को भुगतना पड़ता है।

इन विरोधताओं को देखने से पता चलता है कि आधुनिक अर्थ-व्यवस्था पहले से कितनी भिन्न है। इस अवस्था में आकर आवश्यकता और तृप्ति के बीच बहुत ही परोक्ष सम्बन्ध रह गया है। अब मनुष्य अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ स्वयं तैयार नहीं करता। वह तो अब किसी एक काम के करने में लग जाता है, जिसके बदले में उसे स्पष्ट-पैसा मिलता है। इस रुपये-पैसे से वह मर्चा में आकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदता है और उनके उपयोग में अपनी तरह-तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

आर्थिक जीवन के विकास के इस विवेचन में ऐसा मालूम पड़ता है कि

मनुष्य और प्रकृति के बीच एक प्रकार का संघर्ष चलता रहा है जिसमें विजय मनुष्य की हुई है। आदिम मनुष्य प्रकृति के सहारे ही जीवित था। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह पूर्णरूप में प्रकृति पर निर्भर था। उस समय प्रकृति सर्वशक्तिशाली थी और मनुष्य एन दाम के गमान था। प्रकृति पर काबू पाने के लिए मनुष्य बराबर प्रयत्नशील रहा और धीरे-धीरे उसे सफलता मिलती रही। प्रकृति पर प्रायः विजय के साथ, मनुष्य की शक्ति बढ़ती गई। वह अधिक विकास की नई-नई सोचियों पर चला रहा और आज वह समझ आ गया है कि प्रकृति मनुष्य का एक प्रकार में खिलाता बन गई है। इसकी अनेक शक्तियों पर विज्ञान की महामत्ता द्वारा मनुष्य ने विजय प्राप्त कर ली है। अब मनुष्य प्रकृति के नीचे नहीं, बल्कि उसके ऊपर है। प्राकृतिक शक्तियों को वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काफी सफलता के साथ उपयोग करता है।

यहां कहने का यह आशय नहीं है कि चूनि अब प्रकृति पर मनुष्य का आधिपत्य एक तरह से हो गया है, इसलिए वर्तमान अर्थ-व्यवस्था प्रत्येक दृष्टि से सन्तोषजनक है या अब आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से हो सकती है। निश्चय ही अधिक विकास का वर्तमान रूप पहले से अच्छा है। मनुष्य की उत्पादन-शक्तियों में बहुत वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन अच्छा और अधिक होने लगा है। अनेक नई चीजें सस्ते दामों में मिलने लगी हैं, जिनके उपयोग में मनुष्य का जीवन-स्तर (standard of living) ऊपर उठ गया है। लेकिन जहां एक ओर इस प्रकार की अच्छाइयां दिखाई देती हैं, वहां दूसरी ओर जटिल समस्याएं भी पैदा हो गई हैं, जिनके कारण आजकल बहुत असंतोष और अशांति है। लाखों विभिन्न और पृथक् व्यक्तियों के हाथों में होने के कारण उत्पादन अत्यन्त ही अनिश्चित हो गया है। कभी मांग की अपेक्षा उत्पादन बहुत कम रह जाता है, और कभी बहुत अधिक जिसके कारण सारी अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। साथ ही अब उत्पादन का आधार बान्धव में लोगों की आवश्यकताओं नहीं, बल्कि

धनिकता व निजी लाभ हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि आराम और विलास की वस्तुओं के उत्पादन को ओर अधिक ध्यान दिया जाता है क्योंकि इनके उत्पादन में लाभ का अंश बहुत होता है। आवश्यक वस्तुओं की उत्पत्ति पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता जिसके कारण जन-साधारण को बहुत कठिनाई होती है। यही कारण है कि उत्पादन में वृद्धि होने पर भी गरीबी और भुखमरी दिखाई देती है। इसके अलावा जन-वितरण में भी बहुत असमानता आ गई है और इसमें बराबर वृद्धि होती चली जा रही है। इसके कारण अनेक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, जिनका अभी तक कोई सन्तोषजनक हल नहीं हो पाया है। इन समाज बानों से आवश्यकताओं की पूर्ण तृप्ति में बड़ी बाधा होती है। अस्तु, वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में भी अनेक कृटियाँ और कमजोरियाँ हैं, जिनको दूर करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। कई देश समुचित रूप से योजना बना कर आधुनिक अर्थ-व्यवस्था के दोषों को दूर करने में लग्न हैं।

### QUESTIONS

1. Trace the development of economic life through the various stages from the earliest to the modern times, giving briefly the characteristics of each stage of development
2. What do you understand by 'domestic system'? Compare it with the factory system
3. What are the important features of the present economic order? Point out its main defects
4. "The development of economic life is mainly a record of man's struggle against Nature" Explain
5. Bring out the main features of the present economic order. Does it enable us to satisfy our wants fully?



## अध्याय ६

### कुछ पारिभाषिक शब्द

(Some Fundamental Terms)

विज्ञान में परिभाषा का बहुत ऊँचा स्थान है। परिभाषा का कार्य शब्दों के जहाँ उनकी विगोचरता तथा उनके वाय शत्रु का बोध कराना है जिसमें उनके प्रयोग या रणपटीकरण में कोई आपत्ति अथवा अडचन न हो। जब तक किसी विज्ञान के विषय शब्दों को उचित रूप से समझ न लिया जाय तब तक उनका बोध ठीक तरह में नहीं हो सकता। बहुधा यह देखा गया है कि शब्दों को एक ढंग से प्रयोग न करने के कारण भ्रम तथा आपस में मतभेद हो जाता है। कभी कभी एक व्यक्ति इस बात का अनुभव करता है कि बाद-विवाद में वह अपने विपक्षी को अच्छी तरह नहीं समझ पाया अथवा उसका सलाह समाधान नहीं कर सका क्योंकि विपक्षी कतिपय शब्दों के विभिन्न अर्थों में व्यवहार कर रहा था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उन शब्दों को जो एक विज्ञान में निगम रूप में प्रयोग किए जाते हैं भली भाँति समझ लें।

अर्थशास्त्र में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके उचित अर्थ ज्ञान बिना इस विज्ञान को स्पष्ट रूप में समझना असम्भव है। इसका एक विशेष कारण है। प्रतिदिन के साधारण कार्यों के अध्ययन होने के नाते अर्थशास्त्र में बहुधा आम बोझाल के ही शब्द प्रयोग किये जाते हैं जैसे सम्पत्ति, मूल्य, आय, पूँजी, माँग, उपयोगिता। ऐसे शब्दों के साधारण अर्थ या अर्थों से हम भली-भाँति परिचित होते हैं। पर जब ये शब्द अर्थशास्त्र में प्रयोग होते हैं तो प्रायः हमें एक विशेष अर्थ दे दिया जाता है क्योंकि साधारण अर्थ इतने ढीले-डाले होते हैं कि विज्ञान का काम उचित ढंग में नहीं चल सकता। इसलिए

यह आवश्यक है कि इस विज्ञान के विषय स दो को हमने वैज्ञानिक अथवा आर्थिक रूप में जान लिया जाय । एवं कुछ आधारभूत स दो की विक्षेप-नामा का विश्लेषण नीचे किया जाता है ।

### उपयोगिता

(Utility)

उपयोगिता वस्तु की आवश्यकता-पूरक शक्ति को कहते हैं । यदि कोई वस्तु हमारी किसी आवश्यकता की पूर्ति करने की शक्ति व गुण रखती है, तो हम कहें कि उस वस्तु में उपयोगिता है । दूध, दूध की ताब, शराब आदि वस्तुओं में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की शक्ति है । अतः उनमें उपयोगिता है ।

इस सम्बन्ध में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है । सर्वप्रथम यह कि अध्यास में उपयोगिता शब्द को निम्न धार्मिक या नैतिक दृष्टि से प्रयोग नहीं किया जाता और न इसका प्रयोग 'आभ' या 'आनन्द' के अर्थ में ही होता है । चाहे कोई वस्तु नैतिक दृष्टि में बुरा हो या अच्छे 'आभदायक' अथवा हानिकारक बडो या स्यादित यदि वह किसी भी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है तो उसमें उपयोगिता अवश्य है । शराब, अफीम आदि नशीली वस्तुएँ हानिकारक हैं परन्तु इनमें कुछ मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की शक्ति होती है । इसलिए ये भी उपयोगितायुक्त वस्तुएँ हैं । किसी वस्तु के उपयोग का क्या परिणाम होगा अथवा वह इच्छा कैसी है जिसकी पूर्ति करने की शक्ति उसमें है इससे कोई प्रयोजन नहीं । उपयोगिता के लिए उस वस्तु का किसी के लिए अभीष्ट होता ही पर्याप्त है ।

दूसरी बात यह है कि उपयोगिता मनुष्य की आवश्यकता की तीव्रता (intensity) पर निर्भर करती है । जितनी अधिक या कम किसी वस्तु की आवश्यकता होगी उतनी ही अधिक या कम उस वस्तु में उपयोगिता होगी । प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएँ एक ही नहीं होती और न हर समय वे बेशी ही बनी रहती हैं । इसलिए किसी एक वस्तु की उपयोगिता प्रत्येक व्यक्ति

के लिए एक समान नहीं होती। सामाहरी के लिए साम उपयोगिता रखता है, पर साकाशरी के लिए नहीं। जो बहुत मिमरेट पीते हैं, उनके लिए मिमरेट में बहुत उपयोगिता है। वग पीने वालों के लिए कम और जो बिल्कुल ही नहीं पीते, उनके लिये मिमरेट कुछ भी उपयोगिता नहीं रखती। यही नहीं, बल्कि एक ही वस्तु एक ही मनुष्य के लिये अलग-अलग समय पर भिन्न-भिन्न उपयोगिता रखती है। जैसे, यदि हमें किसी समय बहुत तेज भूख लगी हो तो उस समय रोटी में हमारे लिए बहुत उपयोगिता होगी। दूसरे समय जब इतनी भूख नहीं है, तो रोटी की उपयोगिता कम होगी और तीसरे समय जब भूख नहीं है, तो रोटी की उपयोगिता उस समय बिल्कुल भी नहीं होगी। वस्तु, किसी एक वस्तु की उपयोगिता अलग-अलग व्यक्तियों के लिये भिन्न-भिन्न समय और स्थान पर भिन्न-भिन्न हो सकती है।

उपर्युक्त बातों से यह पता चलता है कि किसी वस्तु की उपयोगिता उस वस्तु की आवश्यकता के साथ जन्म लेती है और आवश्यकता की तृप्ति के साथ दूर हो जाती है। यदि किसी कारण से मनुष्य एक वस्तु की चाह नहीं करता है, तो उस वस्तु की उपयोगिता उसके लिए जाती रहेगी, चाहे उस वस्तु के समान के समान गुण वैसे ही क्यों न हों। सारांश यह है कि उपयोगिता वस्तु के आंतरिक गुणों (internal qualities) के अर्थ में प्रयोग नहीं की जाती। यह तो केवल वस्तु और उसके उपभोक्ता के बीच का सम्बन्ध बताती है। यह एक बाह्य-गुण (external quality) है, जो आवश्यकता के कारण किसी वस्तु को प्राप्त होता है, चाहे वह वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों न हो। आवश्यकता के न होने पर वस्तु का यह गुण खिन जायगा और फलस्वरूप उसकी उपयोगिता जाती रहेगी।

### मूल्य (Value)

वस्तु की विनिमय अथवा खय-शक्ति (purchasing power) को 'मूल्य' कहते हैं। दूसरे शब्दों में, मूल्य वस्तु की उस शक्ति को कहते हैं जिसके बदले में दूसरी वस्तु या वस्तुएँ मिलती हैं। जो कुछ एक वस्तु के विनिमय

में प्राप्त होता है, उसे उस वस्तु का 'मूल्य' कहते हैं। जैसे यदि एक सेर गेहूं के बदले में चार सेर चना मिले, तो हम यह कहेंगे कि एक सेर गेहूं का मूल्य चार सेर चना है। अस्तु, जितनी अधिक या कम एक वस्तु में विनिमय-शक्ति होगी, उतना ही अधिक या कम उसका मूल्य होगा।

किसी वस्तु में मूल्य होने के लिये यह आवश्यक है कि उसमें कुछ उपयोगिता हो। जब तक किसी वस्तु में उपयोगिता न होनी, तब तक कोई व्यक्ति उसके बदले में कुछ भी मूल्य देने के लिये तैयार न होगा। पर इसका यह मतलब नहीं कि यदि किसी वस्तु में उपयोगिता है, तो मूल्य का होना भी आवश्यक है अथवा जितनी अधिक या कम उसमें उपयोगिता होगी, उतना ही अधिक या कम उस वस्तु का मूल्य होगा। कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिनका मूल्य तो बहुत होता है, पर उनमें उपयोगिता उतनी नहीं होती जैसे—गोना, हीरा आदि। इनके विपरीत कुछ चीजों में उपयोगिता तो होती बहुत है, पर उनका मूल्य कम या नहीं के बराबर होता है, जैसे अल, हवा आदि।

यह बात बहुत अजीब-सी लगती है। किन्तु ध्यान देने से स्पष्ट हो जायगा कि ऐसा क्यों बर सम्भव है। मूल्य दो बातों पर निर्भर होता है (१) उप-योगिता और (२) परिमितता (scarcity)। यदि किसी वस्तु में उपयोगिता बहुत है, लेकिन माग की अपेक्षा उसकी मात्रा सीमित नहीं है, तो उसमें कुछ भी नहीं या बहुत कम मूल्य होगा। जैसे पानी में सोने से कहीं अधिक उपयोगिता है, लेकिन माग की अपेक्षा पानी की पूर्ति या मात्रा (supply) उतनी सीमित नहीं है जितनी सोने की पूर्ति है। इसलिए पानी का मूल्य सोने से कहीं कम है।

### कीमत

(Price)

जब किसी वस्तु का मूल्य द्रव्य या रुपये-पैसे में व्यक्त किया जाता है, तो उसे कीमत या दाम कहते हैं। जैसे यदि किसी पुस्तक का मूल्य द्रव्य में दस रुपये है तो यह कहा जायगा कि उस पुस्तक की कीमत दस रुपये है। वास्तविक जीवन में विनिमय अधिकतर द्रव्य के माध्यम द्वारा किया जाता

है। इसलिए हम किसी वस्तु का मूल्य अन्य वस्तुओं के रूप में बनाने के बदले उसकी कीमत द्रव्य के हिसाब में बनाने हैं।

मूल्य और कीमत के सम्बन्ध में हम वान ध्यान देने योग्य है। सब वस्तुओं की कीमतें तो एक साथ घट-बढ़ सकती हैं, परन्तु उन सबके मूल्य के साथ ऐसी बात नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि सब वस्तुओं की कीमत दो बातों पर निर्भर रहती है। एक तो उन सब चीजों की कुल मात्रा जिसका वित्तिय द्रव्य में होता है और दूसरी द्रव्य की कुल मात्रा जो चलन (circulation) में है। चलन न जा द्रव्य है, उसकी गाना में यदि वृद्धि होती है और अन्य बातों में कोई परिवर्तन नहीं होता तो आग तौर में चीजों के दाम बढ़ जायेंगे और यदि द्रव्य की मात्रा घटती है तो वस्तुओं के दाम गिर जायेंगे। वस्तुओं के दामों में इस तरह उतार-चढ़ाव बराबर होता रहता है। जैसे आजकल हमारे देश में दामों का स्तर (level) बहुत ऊंचा है। परन्तु सब वस्तुओं के मूल्य में एक साथ घट-बढ़ नहीं हो सकती, क्योंकि मूल्य तो एक अनुपात है। यह वस्तुओं के परस्पर वित्तिय मूल्य की दर है। इसलिए यदि यह बड़ा जाय कि गेहूँ का मूल्य बढ़ गया है, तो इसका अर्थ यह है कि गेहूँ के बदले में अधिक वस्तुएँ प्राप्त की जा सकती हैं। अर्थात् गेहूँ की तुलना में अन्य वस्तुओं का मूल्य गिर गया है। सभी तो गेहूँ के बदले अन्य वस्तुएँ अधिक मात्रा में मिल सकेंगी। अस्तु, वस्तुओं का मूल्य एक साथ घट-बढ़ नहीं सकता उनकी कीमतें अवश्य एक साथ घट-बढ़ सकती हैं।

वस्तु

(Goods)

वस्तु उन सब चीजों को कहते हैं, चाहे वे भौतिक हो या अमौलिक, जिनमें उपयोगिता होती है, अर्थात् जिनमें इच्छा-पूर्ति करने की शक्ति होती है। पुस्तक, मेज, कुर्सी, साइकिल, भोजन, प्रेम, दिया आदि चीजों में हमारी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करने की शक्ति है। अस्तु, ये सभी वस्तुएँ हैं।

वस्तु के कई भेद हों सकते हैं। इनमें मुरम-मुत्प निम्नलिखित हैं—  
भौतिक और अभौतिक वस्तुएं (Material and Non-material Goods)—जिन वस्तुओं को हम दे-छू सकते हैं, उन्हें भौतिक वस्तुएं (material goods) कहते हैं जैसे मोहन, कुर्सी, पुस्तक, मोटर आदि। अभौतिक वस्तुएं (non material goods) उन वस्तुओं को कहते हैं, जिन्हें हम दे-छू नहीं सकते, जैसे सेवाएँ, प्रमिद्धि आदि। इनके दो विभाग हैं आन्तरिक (internal) और बाह्य (external)। आन्तरिक वस्तुओं में वे सब गुण और शक्तियाँ समा-  
वेशित हैं, जो मनुष्य के अन्दर पाई जाती हैं और जिन्हें मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे किन्हीं व्यक्ति की व्यापारिक योग्यता, कला, ज्ञान, काम करने की शक्ति आदि। बाह्य-वस्तुओं के अन्तर्गत वे सब चीजें आती हैं जो मनुष्य के बाहर होती हैं जिनसे दूसरों का सम्बन्ध होता है जैसे मित्रता, व्यवसाय की रथाति, आदि अन्य सागप्रद सम्बन्ध।

नैसर्गिक और आर्थिक वस्तुएं (Free and Economic Goods)—कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको प्रकृति मनुष्य के उपयोग के लिये प्रचुर मात्रा में प्रदान करती है। इन पर किसी की मिल्कियत व स्वत्व नहीं होता और इनको पाने के लिए कोई परिश्रम ही करना पड़ता है। इनकी इतनी प्रचुरता होती है कि जो चाहे बिना किसी उद्योग या कठिनाई के इनका प्रयोग कर सकता है। इनमें उपयोगिता तो बहुत होती है परन्तु प्रचुर मात्रा में विद्यमान होने के कारण साधारणतः इनमें मूल्य नहीं होता, जैसे प्रारम्भिक स्थिति में प्राप्त जंगल, पर्वत, नदी, हवा, सूर्यकिरण आदि। इन वस्तुओं को प्रकृति-दत्त अथवा नैसर्गिक वस्तुएं (free goods) कहते हैं।

इनके विपरीत जो वस्तुएं परिमित मात्रा में विद्यमान हैं और मनुष्य के प्रयत्न से प्राप्त होती हैं, जिन पर मनुष्य की मिल्कियत व स्वत्व होता है, उन्हें 'आर्थिक वस्तुएं' (economic goods) कहते हैं, जैसे पुस्तक, मोटर, मकान आदि। आर्थिक वस्तुओं में उपयोगिता और मूल्य दोनों ही

होते हैं। इनको पाने के लिए हमें कुछ मूल्य देना पड़ता है। चुनने व निर्णय की आवश्यकता अपना आर्थिक समस्याएँ इन्हीं के कारण पैदा होती हैं। इसलिए अर्थशास्त्र का सम्बन्ध साधारणतः इन्हीं वस्तुओं से रहता है।

इस सम्बन्ध में एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है। एक वस्तु जो किसी स्थान पर प्रकृति-दत्त है, यही दूसरे स्थान या समय पर आर्थिक वस्तु हो सकती है। जैसे जल समुद्र के किनारे प्रकृति-दत्त वस्तु है, पर बड़े-बड़े जहूँ में जब इसे नली द्वारा लोरी के उपयोग के लिए लाया जाता है, तो यह आर्थिक वस्तु बन जाती है। अस्तु, अमक वस्तु प्रकृति-दत्त है या आर्थिक, यह समय, स्थान तथा परिस्थितियों पर निर्भर है। इनमें हेर-फेर होने में वस्तुएँ एक श्रेणी से निकल कर दूसरी श्रेणी में आ सकती हैं।

विनिमय-साध्य और अविनिमय साध्य वस्तुएँ (Transferable and Non-transferable Goods)—विनिमय की दृष्टि से वस्तुएँ दो तरह की होती हैं विनिमय-साध्य (transferable) और अविनिमय-साध्य (non-transferable)। बहुत-सी वस्तुएँ ऐसी होती हैं, जिनका उद्य-विषय हो सकता है, जैसे वस्त्र, अन्न, कलम, मकान आदि। इनको विनिमय-साध्य वस्तुएँ कहते हैं। जिन वस्तुओं का हम उद्य-विषय नहीं कर सकते, अर्थात् जिनको एक दूसरे के साथ अदल-बदल नहीं सकते, उन्हें अविनिमय-साध्य वस्तुएँ कहते हैं, जैसे गायक का झुरीला स्वर, अध्यापक का ज्ञान, डाक्टर की कुशलता आदि। विनिमय-साध्यता या हस्तान्तरकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का गूण हो। केवल अधिकार-परिवर्तन का गुण होना ही पर्याप्त है। उदाहरणार्थ मकान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, पर फिर भी इसे अर्थशास्त्र में विनिमय-साध्य वस्तु कहते हैं, क्योंकि इसके अधिकार में परिवर्तन लाया जा सकता है, मूल्य बेकर इसे खरीदा जा सकता है। विनिमय-साध्यता के लिए यही पर्याप्त है।

उपभोग और उत्पादक वस्तुएं (Consumer and Producer Goods)—वस्तुओं का विभाजन एक और दृष्टि में किया जाता है। वह यह कि वस्तु मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से कर सकती है, या परोक्ष रूप से। जो वस्तुएं मनुष्य की आवश्यकताओं की सीधे तौर पर पूर्ति करती हैं, उन्हें उपभोग की वस्तुएं (consumer goods) कहते हैं। गाय-सामग्री, पुस्तक, साइकिल, घर आदि वस्तुओं के उपभोग में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की सीधे तौर से पूर्ति करता है। अतः ये उपभोग-वस्तुएं हैं। उत्पादक-वस्तुओं (producer goods) से आशय उन वस्तुओं से है जो उपभोग-वस्तुओं के उत्पादन करने में सहायक होती हैं, जैसे मशीन, कच्चा माल आदि। इनमें मनुष्य की आवश्यकताओं की सीधे तौर से अथवा प्रत्यक्ष रूप से पूर्ति नहीं होती।

### धन या सम्पत्ति

(Wealth)

अर्थशास्त्रियों ने 'सम्पत्ति' शब्द की अनेक प्रकार से व्याख्या की है। कुछ के अनुसार सम्पत्ति में वे सभी वस्तुएं समावेशित हैं, जिनमें उपयोगिता है, अर्थात् जिनमें आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। इस दृष्टि में दाम, धूप, दवा, मनुष्य की नक़्तिया और मेवाएँ, नमक, कुर्मी-मेज, कपड़ा, हीरे-पेराहिरात आदि सभी वस्तुएं सम्पत्ति मानी जायगी क्योंकि इन सब में उपयोगिता का गुण है। पर बहुत से अर्थशास्त्री सम्पत्ति की इस व्याख्या से सहमत नहीं हैं। वे इसे अत्यधिक व्यापक ठहराते हैं। उनके अनुसार वस्तु में उपयोगिता के साथ-साथ परिमाण में परिमितता का भी गुण होना आवश्यक है। अर्थात् सम्पत्ति बहलाने के लिए वस्तु में उपयोगिता होनी चाहिए और मात्र ही उसकी मात्रा परिमित या सीमित होनी चाहिए। यदि ये दोनों गुण किसी वस्तु में हैं, तो चाहे वह भौतिक हो या अमौलिक, सम्पत्ति मानी जायगी। पर कुछ अर्थशास्त्री इसे भी स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि वस्तु में, सम्पत्ति बहलाने के लिए, उपयोगिता और परिमितता



का गुण होना तो आवश्यक है ही पर सम्पत्ति में केवल भौतिक पदार्थों का ही समावेश हो सकता है। अभौतिक वस्तुएँ सम्पत्ति में शामिल नहीं की जा सकती। उन्हीं के लिए वे यह दलील दते हैं कि अभौतिक वस्तुएँ भौतिक पदार्थों के केवल गुणस्वरूप हैं वे उनके अन्दर विद्यमान होते हैं। अस्तु जब भौतिक पदार्थों को धन मान लिया जाता है तो फिर उनके गुणों को अर्थात् अभौतिक वस्तुओं को अर्थ में धन में सम्मिलित करना ठीक न होगा। ऐसा करने में वही वस्तु कई बार धन में गिन ली जायेगी।

इन सब बातों में स्पष्ट है कि अध्यात्म में धन शब्द का प्रयोग बर्बरता से किया जाता है। वही ठीक बहुत व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है और कहीं बहुत संकुचित अर्थ में। यहाँ भिन्न भिन्न परिभाषाओं की छान बान करने के बजाय यह अधिक ठीक होगा कि साधारणतः जिस अर्थ में 'धन' शब्द का अध्यात्म में प्रयोग होता है उसे समझ लिया जाय। प्रसंग के अनुसार इनके अर्थ में अंतर बताया जा सकता है।

आम तौर से अध्यात्म में आधिव वस्तुओं को ही धन माना जाता है। आर्थिक वस्तुओं में मूल्य होता है उनका क्या विनय हो सकता है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि धन में वे सब वस्तुएँ सम्मिलित हैं जिनको खरीदा-बचा जा सकता है अर्थात् जिनमें मूल्य होता है। अस्तु जिन वस्तुओं में मूल्य नहीं होता अथवा जिनका क्या विनय नहीं हो सकता वह धन नहीं मानेंगे। इनमें सूर्य किरण आदि में उपयोगिता तो बहुत है पर साधारणतः इनमें मूल्य नहीं होता इन्हें खरीदा-बचा नहीं जाता। इसलिए इन्हें धन न मानेंगे। मकान कपड़ा पुस्तक मोटर आदि वस्तुएँ विनिमय साध्य हैं इनमें मूल्य है। इसलिए इस प्रकार की सभी वस्तुएँ सम्पत्ति मानी जायगी।

इसके पहिले कि किसी वस्तु में मूल्य हो और वह सम्पत्ति मानी जा सके उसमें निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है—

उपयोगिता (Utility)—वस्तु में मूल्य होने के लिए और इस प्रकार

सम्पत्ति की गणना में आने के लिए उसमें उपयोगिता का गुण होना परमावश्यक है। यदि किसी वस्तु में उपयोगिता नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति उसे प्राप्त न करना चाहेगा, उसके बदले में कोई भी मूल्य देने के लिये तैयार न होगा। दूसरे शब्दों में, उपयोगिता के न होने पर वस्तु में मूल्य नहीं होगा। फलस्वरूप वह वस्तु सम्पत्ति नहीं मानी जा सकती।

**परिमितता (Scarcity)**—सम्पत्ति कहलाने के लिए वस्तु में यह भी गुण होगा आवश्यक है कि मांग की अपेक्षा उसकी मात्रा कम या सीमित हो। यदि कोई वस्तु अपरिमित मात्रा में है और जो चाहें उसे आसानी से प्राप्त कर सकता है, तो उसे कुछ मूल्य देकर लेने के लिये कौन तैयार होगा। ऐसी वस्तु का अर्थ-विनश्य न होगा। उसमें कोई मूल्य न होगा। इस कारण उसे धन न मानेंगे। प्रकृति-दत्त वस्तुओं में उपयोगिता होती है, पर परिमितता का गुण न होने के कारण उनमें मूल्य नहीं होता। इसलिए साधारण तौर से उन्हें धन नहीं मानते।

**विनिमय-साध्यता (Transferability)**—उपयुक्त गुणों के अतिरिक्त वस्तु में मूल्य होने के लिए विनिमय-साध्यता या हस्तान्तरकरण का भी गुण होना चाहिए। इन गुणों के न होने पर वस्तु को कोई प्राप्त ही न कर सकेगा। उसका कम-विक्रय असम्भव हो जायगा और इस प्रकार उस वस्तु की गिनती धन में न की जा सकेगी। अर्थात् जो वस्तुएं हस्तान्तरित होने वाली नहीं हैं, अविनिमय-साध्य हैं, जिनका अदला-बदला नहीं हो सकता, उन्हें धन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

मक्षेप में, अब हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में सम्पत्ति में आधाय उन त्रयाम वस्तुओं से है, जिनमें उपयोगिता, परिमितता और विनिमय-साध्यता के तीनों गुण होते हैं। यह मान्य करने के लिए कि अमुक वस्तु धन है या नहीं, हमें इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि उस वस्तु में ये तीनों गुण हैं, या नहीं। यदि हैं, तो वह अवश्य सम्पत्ति मानी जायगी, अन्यथा नहीं। एक-दो उदाहरणों द्वारा इसे और स्पष्ट किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए मनुष्य के आंतरिक गुणों, शक्तियों, अथवा योग्यताओं को ही ले लें। मान लें, बोर्ड डाक्टर अपनी योग्यता तथा बुद्धिबल के लिये प्रसिद्ध है। प्रश्न यह है कि क्या उसकी यह योग्यता या शक्ति धन है? निश्चय ही अपनी विशेष योग्यता से वह डाक्टर बहुत सम्पत्ति पैदा कर सकता है। गरीब नहीं, वह उसके द्वारा ऐसी वस्तुएँ तैयार कर सकता है, जो वृत्तियों के उपयोग में आ सकें। दत्तता होने हूँ भी यह गुण स्वतः सम्पत्ति नहीं है। कारण यह अविनिमय-साध्य है। डाक्टर उसे अपने से पूँछकर बरके हस्तान्तरित नहीं कर सकता। जो वस्तुएँ धन में रूपावत हो सकती हैं, वे सदा मनुष्य के बाहर होती हैं, अन्दर नहीं। अम्न, मनुष्य की आंतरिक शक्तियाँ, विभूतियाँ आदि सम्पत्ति नहीं मानी जा सकती।

यद्यपि सम्पत्ति में व्यक्तिगत गुणों और शक्तियों की गणना नहीं की जाती, मनुष्य की वैयक्तिक सेवाओं को सम्पत्ति माना जाता है। डाक्टर, कबोल्, अध्यापक आदि की सेवाएँ धन हैं। इनमें उपयोगिता और परिमितता के ही गुण नहीं हैं, बल्कि वे विनिमय-साध्य भी हैं। इनका अय-विन्य भी होता है। इसी प्रकार किसी व्यवसाय या धर्म की रूयानि (Goodwill) सम्पत्ति मानी जायगी क्योंकि इसमें उपयोगिता, परिमितता और हस्तान्तरकरण तीनों गुण हैं। रेगिस्तान में पड़ी हुई बालू या समुद्र में मछलियाँ सम्पत्ति नहीं हैं, क्योंकि वहाँ उनकी मात्रा सीमित नहीं है।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि किसी वस्तु के स्वल्प या गुण द्वारा यह निश्चित नहीं होता कि वह वस्तु सम्पत्ति है या नहीं। यह तो परिस्थिति और मनुष्य के मनोभावों पर निर्भर है। हो सकता है कि कोई वस्तु किसी परिस्थिति में सम्पत्ति न हो और वही वस्तु अन्य परिस्थितियों में सम्पत्ति की गणना में आ जाय। जैसे समुद्र के तट पर पानी सम्पत्ति नहीं है, लेकिन सहरो में, परिस्थितियों में अन्तर आ जाने से, पानी सम्पत्ति की श्रेणी में शामिल हो जाता है।

## सम्पत्ति का वर्गीकरण (Classification of Wealth)

सम्पत्ति के कई भाग विधे जा सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत सम्पत्ति राष्ट्रीय सम्पत्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्पत्ति। व्यक्तिगत सम्पत्ति में दो तरह की वस्तुएँ गिनी जाती हैं—(अ) वे भौतिक और अभौतिक वस्तुएँ, जिन पर किसी व्यक्ति का निजी अधिकार या स्वामित्व होता है, जैसे उसका मकान, वस्त्र, खेवर, व्यवसाय की रथाति आदि। यदि उस व्यक्ति ने कुछ ऋण ले रखा है, तो उसे उसकी कुल सम्पत्ति में से घटा देना चाहिए। सभी उसकी कुल सम्पत्ति का ठीक-ठीक अनुमान लगाया जा सकता है। (आ) उन भौतिक और अभौतिक वस्तुओं में से उसका हिस्सा जिन पर दूसरों के साथ उस व्यक्ति का साझे का स्वत्व होता है, जैसे मटके, पुल, जलबान, पार्क, ग्याय, शिक्षा आदि। इन वस्तुओं का सामाजिक या मामूहिक सम्पत्ति कहते हैं। इन पर किसी एक व्यक्ति का निजी अधिकार नहीं होता। सभी समान रीति से इनका उपयोग कर सकते हैं।

राष्ट्रीय सम्पत्ति में इन वस्तुओं को गणना की जाती है—(१) राष्ट्र के कुल व्यक्तियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा सम्मिलित सामूहिक सम्पत्ति, (२) राष्ट्र की समस्त भौतिक वस्तुएँ, (३) वे मुख वस्तुएँ जो प्रकृति से देश को प्राप्त हैं, जैसे पहाड़, जंगल, नदिमा, जलवायु आदि; (४) राष्ट्र की समस्त अभौतिक वस्तुएँ जैसे राष्ट्रीय रथाति, मुद्रागठित अवका मुद्रावस्थित राष्ट्रीय प्रबन्ध बहा के निवासीधो की विद्यापताएँ, आदि।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्पत्ति से आशय इन दो बातों से है—(क) सब राष्ट्रों की सम्पत्ति का जोड़, और (ख) जिन पर सब का अधिकार होता है, जैसे समुद्र, वैज्ञानिक आविष्कार, आदि।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जब राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सम्पत्ति का विचार किया जाता है, तो 'सम्पत्ति' शब्द बहुत ही व्यापक रूप से प्रयोग होता है। कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं, जो राष्ट्रीय सम्पत्ति में

ममावेनित है, पर साधारण परिभाषा के अनुसार उन्हें सम्पत्ति में सम्मिलित नहीं किया जा सकता ।

अन्य आवश्यक वस्तु की परिभाषा उन्हें उचित स्थानों पर की जायेगी ।

### QUESTIONS

- 1 What is meant by the term 'utility' ? Discuss it fully
- 2 Define value and price Show how there cannot be a general rise or fall in value
- 3 What is wealth ? What are its essential features ?
- 4 Are the following wealth or not ?  
 (i) Love of mother for her child, (ii) Surgeon's skill, (iii) Services of a doctor, (iv) Goodwill of a business (v) B A degree, (vi) Money (vii) Fish in the sea Give reasons for your answer .
- 5 What are economic goods ? Differentiate them from free goods
- 6 What is meant by goods ? Discuss the various classes of goods, giving appropriate illustrations

## अध्याय ७

### अर्थशास्त्र के विभाग

#### (Division of Economics)

अध्ययन की सुविधा के लिए अर्थशास्त्र के विषय को साधारणतया निम्नलिखित पाच भागों में विभक्त किया जाता है—(१) उपभोग, (२) उत्पाति, (३) विनिमय, (४) वितरण और (५) राजकीय अर्थ-व्यवस्था। वैज्ञानिक दृष्टि में यदि देखा जाय तो आर्थिक विषय को इस प्रकार में विभक्त करना ठीक नहीं है। कारण, ये सब आर्थिक कार्य के रूप अथवा उदाहरण हैं, जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो किसी एक भाग में नहीं, बल्कि सभी भागों में सम्बन्धित हैं। उन्हें किसी एक विभाग में अलग रख कर अध्ययन करना ठीक न होगा। उदाहरणार्थ व्याज का विवेचन वितरण-विभाग में किया जाता है, पर व्याज का प्रभाव विनिमय और उत्पाति पर भी विशेष रूप से पड़ता है। आधुनिक आर्थिक जगत में तो उत्पाति का सारा रूप, ढाँचा, उसका परिमाण बहुत कुछ अज्ञात तक व्याज की दर पर निर्भर है। इसी प्रकार मूल्य केवल विनिमय-विभाग का ही अंग नहीं है। यह तो सारे आर्थिक क्षेत्र में छाया हुआ है। वास्तव में, आर्थिक समस्या एक प्रकार से केवल मूल्य की समस्या है। अतः उपर्युक्त विभागों के विषय को पृथक् करना वैज्ञानिक दृष्टि में ठीक नहीं है। लेकिन अर्थशास्त्र का अध्ययन-विषय इतना विस्तृत है कि बिना इसे कतिपय भागों में विभक्त किये इसको अच्छी तरह से समझना कठिन है। अस्तु, केवल अध्ययन की सुविधा के लिए ही अर्थशास्त्र-विषय को कई भागों में बांट दिया जाता है।

संक्षेप में, हम महा यह विचार करेंगे कि इन विभागों का क्या कार्य-क्षेत्र है और साथ ही निम्न तरह के एक दूसरे में सम्बन्धित है।

### उपभोग

(Consumption)

आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन के प्रत्यक्ष प्रयोग को 'उपभोग' कहते हैं। यदि हम किसी वस्तु का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की सीधे तौर से पूर्ति करने के हेतु करते हैं, तो उसे 'उपभोग' कहेंगे। जैसे भोजन करना, पुस्तक पढ़ना, मकान में रहना, तस्वीर देखना आदि। कारखानों में मशीन के प्रयोग को अथवा कोयले के जलाने को 'उपभोग' न कहेंगे क्योंकि इनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष अथवा सीधे तौर से नहीं होती। यह तो ठीक है कि कोयले और मशीन के प्रयोग में जो वस्तुएं बनेंगी, उनसे आगे चलकर मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, पर कोयले और मशीन का तात्कालिक उत्प्रेरक किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की सीधे तौर से पूर्ति करना नहीं है। अतः धन के इस तरह के प्रयोग को 'उपभोग' न मानेंगे।

उपभोग-विभाग के अन्तर्गत यह विचार किया जाता है कि आवश्यकताओं की क्या-क्या विशेषताएं हैं, उपभोग के नियम क्या हैं, कितना तरह धनोपयोग से अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो सकती है, इत्यादि।

### उत्पत्ति

(Production)

उपयोगिता-वृद्धि को अर्थशास्त्र में 'उत्पत्ति' कहते हैं। यह तो सभी को भली भांति विदित है कि मनुष्य कोई तथा पदार्थ पैदा नहीं कर सकता। यदि मनुष्य कुछ कर सकता है तो केवल विद्यमान पदार्थों को अपने उद्योग द्वारा अधिक उपयोगी बना सकता है। वस्तुओं के रूप, स्थान, स्वामित्व तथा समय आदि में परिवर्तन करके उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है। अर्थशास्त्र में 'उत्पत्ति' या 'उत्पादन' का यही अर्थ होता है।

इस विभाग में हम यह अध्ययन करेंगे कि धनोत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति के कौन-कौन से साधन हैं, उत्पत्ति के नियम और ढंग क्या हैं, इत्यादि।

### विनिमय

(Exchange)

प्राचीन काल में प्रत्येक व्यक्ति स्वावलम्बी था। वह अपने उपभोग की सभी वस्तुएँ स्वयं उत्पन्न करता था। अतएव उस समय विनिमय की कोई आवश्यकता न थी। पर अब हम अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ स्वयं उत्पन्न नहीं करने और न कर सकते हैं। कारण, हमारी आवश्यकताएँ बहुत ही बड़ गई हैं। अब हम अपनी आवश्यकता की तमाम चीजें स्वयं न उत्पन्न करके केवल एक विशेष कार्य में अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार लग जाते हैं। फिर अपने परिश्रम के फलस्वरूप दूसरे से उनकी बनाई हुई चीजों को पाते हैं। इस तरह वस्तुओं की अदल-बदल से आज हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

विनिमय-विभाग में यह विचार रिया जाता है कि किम तरह और क्यों कर विनिमय होता है, कैसे वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है, किन-किन संस्थाओं में इस कार्य में सहायता मिलती है, इत्यादि।

### वितरण

(Distribution)

आधुनिक काल में उत्पत्ति व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक है। कई व्यक्ति मिलकर एक साथ उत्पत्ति का कार्य करते हैं। कोई अपना परिश्रम लगाता है, कोई अपनी पूँजी, कोई भूमि और इस तरह इन सबके सहयोग से धनोत्पादन होता है। फलस्वरूप जो कुछ भी सम्पत्ति उत्पन्न की जाती है, वह उन सब उत्पत्ति-कर्ताओं की होती है। उसे इनके बीच बाँटा जाता है। धन के इस विभाजन को 'वितरण' कहते हैं।

इस विभाग के अन्तर्गत यह विचार रिया जाता है कि उत्पत्ति के साधनों का प्रतिफल किस प्रकार और किन सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित



होता है, वैसे धन के वितरण में असमानता आ जाती है, उसका वश परिणाम होता है, आदि ।

### राजकीय अर्थ व्यवस्था

(Public Finance)

देश में शांति और मुख्यतः रखने के लिए सरकार अनेक कार्य करती है । इनमें से कुछ का सम्बन्ध धन में होता है जिन्हें आर्थिक कार्य कह माने हैं । आधुनिक काल में सरकार के आर्थिक कार्य का धेन बहुत बढ गया है । आर्थिक जीवन में सरकार अब काफी भाग लेती है । परिणामस्वरूप अनेक आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जिनका समाधान जल्द आवश्यक है । अर्थशास्त्र का वह भाग, जिसमें सरकार के आर्थिक प्रयत्नों तथा समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उसे राजकीय अर्थ-व्यवस्था कहते हैं । इसका प्रमुख विषय राजस्व है, जिसमें सरकार की आय और व्यय का विवेचन होता है ।

### विभागों का पारस्परिक सम्बन्ध

(Inter relation of the Divisions)

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अर्थशास्त्र का उपर्युक्त भागों में विभाजित करने समय हम बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ये भाग एक-दूसरे में भिन्न अथवा स्वतन्त्र नहीं हैं । ये भाग केवल अध्ययन की सुविधा के लिये ही किए गए हैं । इनमें पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध है, जिसका उल्लेख नीचे किया जाता है ।

उपभोग और उत्पत्ति—इन दोनों का परस्पर बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है । उपभोग उत्पत्ति का मूल कारण है । वस्तुओं की उत्पत्ति तभी की जाती है, जब कि उनके उपभोग की इच्छा होती है । यदि उपभोग की इच्छा ही न हो तो उत्पत्ति क्यों की जायगी । कौन-कौन-सी और कितनी कितनी मात्राओं में वस्तुएँ उत्पन्न की जायें, यह सब उपभोग पर निर्भर है । वस्तु स्पष्ट है कि उपभोग के कारण उत्पत्ति की जाती है । पर बिना उत्पत्ति के

उपभोग सम्भव नहीं। चाहे कितनी ही प्रचुर किसी वस्तु की इच्छा क्यों न हो, किन्तु उसकी पूर्ति तभी हो सकती है, जबकि इच्छित वस्तु का उत्पादन किया जा चुका हो। मनुष्य उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करता है जो उत्पन्न की जा चुकी हैं। यही नहीं बल्कि उत्पत्ति उपभोग की मात्रा अवधि सीमा का निर्धारित करती है। उनका ही उपभोग किया जा सकता है, जितनी उत्पत्ति हुई है उमरे अधिक नहीं। हम मरतः हम देखते हैं कि उपभोग और उत्पत्ति में परस्पर कितना निकट सम्बन्ध है। उपभोग की इच्छा से उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति द्वारा उपभोग सम्भव होता है।

**विनिमय, उपभोग और उत्पत्ति**—हमारी आवश्यकताएँ बहुत ही बड़ गई हैं। अब यह सम्भव नहीं कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की सभी चीजें स्वयं अपने प्रयत्न से पैदा कर सकें। हम केवल एक या दो चीजों का बनाने में ही अपना समय और शक्ति लगाते हैं। इसलिए अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम दूसरों की बनाई हुई वस्तुओं का प्रयोग करें। यह कार्य विनिमय द्वारा ही सम्भव है। अस्तु वर्तमान काल में उपभोग के लिए विनिमय कितना आवश्यक है, यह विस्तृत स्पष्ट है। दूसरी ओर विनिमय का आधार उपभोग पर है। यदि मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग करना छोड़ दे या सर्वजन स्वावलम्बी हो जाय, तो विनिमय का प्रश्न ही न उठता।

उत्पत्ति और विनिमय का पारस्परिक सम्बन्ध भी स्पष्ट है। आज-कल उत्पत्ति भण्डों में प्रचुर-विषय के लिए की जाती है, जहाँ दूर समय विनिमय की आवश्यकता पड़ती है। उत्पत्ति उस समय पूरी समझी जाती है जबकि उत्पन्न पदार्थ उपभोक्ता के पास तक पहुँच जाय। यह कार्य बिना विनिमय की माध्यमता से नहीं हो सकती। अस्तु, आधुनिक उत्पत्ति-प्रणाली का विनिमय एक आवश्यक अंग है। उत्पत्ति और उपभोग के बीच विनिमय एक तरह से जोड़ अथवा मिलाने का काम करता है। यह उत्पत्ति की पूर्ति करता है और उपभोग को तरल बनाता है। उत्पत्ति का भी प्रभाव विनिमय पर पड़ता है। यदि उत्पत्ति न हो, तो फिर विनिमय ही, कितना होगा।

वितरण तथा अन्य विभाग—आजकल धनोत्पत्ति व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक अथवा सामुदायिक है। कई व्यक्ति मिलकर उत्पत्ति का कार्य करते हैं। जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वह सभी उत्पत्ति के सहायक साधनों की सम्मिलित सम्पत्ति होती है। इसके पहिले कि उम समुदाय या समूह के व्यक्ति अपनी-अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, यह आवश्यक है कि उत्पन्न पदार्थ या उसके बेचने में जो मूल्य आयें, वह उनके बीच बाटा जाय। जब तक ऐसा न किया जायेगा, तब तक उपभोग सम्भव न हो सकेगा। इस तरह हम देखते हैं कि आवश्यकताओं की तृप्ति अथवा उपभोग के लिए वितरण कितना आवश्यक है।

वितरण और उत्पत्ति में भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि वितरण का ठग उचित और निष्पक्ष है, तो उत्पत्ति में वृद्धि होगी। कारण ऐसी दशा में उत्पत्तिकर्ताओं को सम्पूर्ण शक्ति और मन लगाकर काम करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। और अगर वितरण का तरीका बुरा है, तो इसका प्रभाव उत्पत्ति पर उल्टा पड़ेगा। उत्पत्ति घटने लगेगी और इसका फल यह होगा कि लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जायेगी। दूसरी ओर, उत्पत्ति का भी प्रभाव वितरण पर काफी पड़ता है। अगर उत्पत्ति न हो तो वितरण भी न होगा। कितनी अधिक या कम उत्पत्ति होगी, उतना ही अधिक या कम वितरण हो सकेगा।

इसी तरह विनिमय और वितरण भी परस्पर सम्बन्धित हैं। वितरण विनिमय का केवल एक दूसरा नाम है। यदि विनिमय का कार्य न हो तो वितरण का प्रश्न ही न उठेगा। विनिमय के सिद्धान्त पूर्णरूप से वितरण-औष में लागू होते हैं। विनिमय के अन्तर्गत यह विचार किया जाता है कि वस्तुओं का मूल्य कैसे निर्धारित होता है और कैसे कुछ वस्तुओं का मूल्य दूसरों की अपेक्षा कम या अधिक होता है। ठीक इसी तरह वा विचार वितरण-विभाग में भी किया जाना है। अन्तर इसका ही है कि वितरण-विभाग में हम उत्पादक की सेवाओं की मूल्य-निर्धारण सम्बन्धी समस्याओं का विवे-

चन करते हैं। जो कुछ उत्पादन होता है, वह उत्पत्ति के साधनों के बीच बांट दिया जाता है। वितरण के इस कार्य में विनिमय के सिद्धांतों से ही महायत्ना लेनी पड़ती है। यदि विनिमय के सिद्धान्त ठीक हैं तो वितरण-विभाग की समस्याएँ उचित रूप में हल की जा सकती हैं, अन्यथा नहीं।

राजकीय अर्थ-व्यवस्था तथा अन्य विभाग—राजकीय अर्थ-व्यवस्था और अन्य विभागों के बीच भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। आजकल सरकार के आर्थिक उद्योग का क्षेत्र बहुत ही बढ गया है। हमारे आर्थिक जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है, जहाँ पर सरकार को आर्थिक नीति अपना उसके कार्य का प्रभाव न पड़ता हो। सधीप में, हम यहाँ यह देखेंगे कि किस तरह राजकीय अर्थ-व्यवस्था और अन्य विभाग एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं।

सर्वप्रथम उपभोग और राजकीय अर्थ-व्यवस्था का ही सम्बन्ध ले लो। प्रत्येक देश की सरकार बड़ा के घनोपभोग पर काफी रोक-टोक रखती है। कुछ वस्तुओं के सेवन का फल बुरा होता है। उपभोक्ता को दक्षिप्त जातो रहनी है और गाय ही समाज में उनके कारण अनेक दुरीतियाँ फैलने लगती हैं। अतएव सरकार इस प्रकार के उपभोग को या तो बिलकुल बन्द कर देती है, या रोक-टोक लगाती है, जिससे उनका उपभोग स्वतन्त्र रूप से न हो सके। जैसे, तबीन्की वस्तुएँ हर जगह और हर समय नहीं बेची जा सकती। सरकार उनके बेचने के स्थान, समय और खरीदार पर बहुत बन्दिशें लगाती है। इसी तरह अन्य वस्तुओं के उपभोग पर भी सरकार काफी प्रभाव डालती है। रोक-टोक का यह कार्य सरकार अधिकतर टैक्स की सहायता से करती है। वस्तुओं पर कर (tax) लगाने से उपभोक्ता को पहले की भाँति प्रोत्साहन नहीं मिलता। दूसरी ओर, उपभोग का भी राजकीय अर्थ-व्यवस्था पर काफी असर पड़ता है। सरकार की आय कुछ अंश तक टैक्स जमी हुई वस्तुओं के उपभोग पर निर्भर होती है। यदि लोग ऐसी वस्तुओं का उपभोग छोड़ दें तो निश्चय ही सरकार की आय में बहुत कमी

आ जायगी। फलस्वरूप सरकार अपने विभिन्न कार्यों को भली भाँति न कर सकेगी। बहुधा उपभोग में परिवर्तन के कारण सरकारी बजट में काफी अनिश्चितता आ जाती है।

अब राजकीय अर्थ-व्यवस्था और उत्पत्ति का सम्बन्ध ले लो। उचित रूप से उत्पत्ति होने के लिए देश में शांति और सुन्यवस्था का होता परमावश्यक है। ऐसा न होने पर न तो लोग पूँजी संचय कर सकेंगे और न ही मन लगाने का काम करने की तैयार होंगे। फिर भला किस प्रकार उत्पत्ति का कार्य अच्छी तरह से हो सकेगा। देश में शांति स्थापित करना तथा लोगों की सम्पत्ति और जीवन-रक्षा का कार्य सरकार का ही होता है। इनके अलावा उत्पत्ति बहुत अज्ञ तक यातायात के साधन और सरकारी सुरक्षण तथा अन्य आर्थिक नीतियों पर निर्भर रहती है। दूसरी ओर, उत्पत्ति का भी राजकीय अर्थ-व्यवस्था पर काफी असर पड़ता है। सरकार की आय लोगों की आय पर निर्भर है। यदि उत्पत्ति ठीक ढंग में हो रही है, तो वहाँ के निवासी धनी होंगे। फलस्वरूप गृहा की सरकार भी धनवान होगी। पर यदि धनोत्पादन कम होता है, तो सरकार भी धन कम होगी। फिर भला किस प्रकार सरकार देश में धामन और सुधार का कार्य उचित ढंग में कर सकेगी। यही नहीं, सरकार की आर्थिक नीति काफी हद तक देश की उत्पत्ति-प्रणाली और अर्थ-व्यवस्था पर निर्भर होती है।

विनिमय और राजकीय अर्थ-व्यवस्था के बीच भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। विनिमय का कार्य उसी समय ठीक ढंग से चल सकता है, जबकि सरकार इस ओर काफी देखभाल रखे। जब भी सरकार विनिमय-क्षेत्र में असावधानी से काम लेती है तो समाज के आर्थिक जीवन में उथल-पुथल मच जाती है। इसलिए, कामगार-द्रव्य, केन्द्रीय-बैंक, विदेशी विनिमय आदि क्षेत्रों में सरकारी देख-भाल और नियन्त्रण बहुत ही आवश्यक है।

इसी तरह वितरण और राजकीय अर्थ-व्यवस्था एक-दूसरे से सम्बन्धित है। सरकार वितरण के कार्य में काफी भाग लेती है। साम्यवादी

देश में वितरण का कार्य सरकार स्वयं करती है। जो कुछ उत्पन्न होता है, उसे सरकार लोगो की आवश्यकतानुसार बांट देती है। अन्य देशों में भी सरकार अपनी कर और व्यय-नीति द्वारा वितरण को विषम असमानता को दूर करने के लिए अनेक प्रयत्न करती है। अमीरों के ऊपर तथा उनके व्यवहार में आने वाली वस्तुएँ (उदाहरणार्थ मोटर, रेडियो, रेफ्रिजरेटर आदि) पर अधिक कर लगा कर सरकार वितरण-समस्या की विषमता को कम करती है। मजदूरों के न्यूनतम वेतन को निर्धारित करके तथा सामाजिक बीमा की प्रथा चलाकर सरकार धन-वितरण पर काफ़ी प्रभाव डालती है। इसमें स्पष्ट है कि ये दोनों विभाग एक दूसरे से कितने सम्बन्धित हैं।

अस्तु, जैसा हम पहले कह चुके हैं, अर्थशास्त्र के उपर्युक्त विभाग केवल अध्ययन की सुविधा के लिए ही किए गये हैं। इनमें से कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो दूसरे से पृथक् या स्वतन्त्र हो। एक भाग के बिना दूसरे भाग का अध्ययन मदा अपूर्ण ही रहेगा।

### QUESTIONS

1. What are the main divisions of Economics ?  
Briefly describe each of them
2. Discuss the inter-relations between the different branches of Economics

# उपभोग

(Consumption)

## अध्याय ८

### उपभोग और उसका महत्त्व

(Consumption and its Importance)

आवश्यकताएँ मनुष्य को सदा घेरे रहती हैं। उनके कारण वह तरह-तरह के कार्य करके धनोपार्जन करता है, और फिर उपार्जित धन के प्रयोग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसमें उसे तृप्ति और सतोष प्राप्त होते हैं।

अर्थशास्त्र में धन के ऐसे प्रयोग अथवा सेवन को 'उपभोग' कहते हैं जिसमें आवश्यकताओं की पूर्ति सीधे तौर से हो, जिसमें उपभोक्ता को प्रत्यक्ष और तात्कालिक तृप्ति और सतोष प्राप्त हो। अब हम किसी वस्तु अथवा सेवा का प्रयोग आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप में तृप्ति करने के लिए करते हैं तो उसे 'उपभोग' कहा जाता है। उदाहरणार्थ जब मोहन खाना खाता है, पानी पीता है, तो उसकी आवश्यकताओं की तृप्ति प्रत्यक्ष रूप से अथवा सीधे तौर से हो जाती है। अतएव हम कहेंगे कि मोहन इन वस्तुओं का उपभोग करता है।

इसी तरह जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, तस्वीर देखते हैं, वस्त्र पहिनते हैं अथवा साइकिल पर चढ़ते हैं, तो हमारी आवश्यकताएँ इन वस्तुओं के प्रयोग से सीधे तौर से तत्काल तृप्त हो जाती हैं। इसीलिए ये सभी उपभोग के उदाहरण हैं।

उपभोग की परिभाषा देते समय 'सीधे' अथवा 'प्रत्यक्ष' शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द उपभोग की परिभाषा में बहुत महत्वपूर्ण है। इस-लिए इसको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। ऐसा न करने से भ्रम में



पह जाने की सम्भावना है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन को दो तरह से प्रयोग कर सकता है। एक तो प्रत्यक्ष रूप में, और दूसरे अप्रत्यक्ष रूप में। जब वह पुस्तक पढ़ता है अथवा भोजन करता है, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप में होती है। यहाँ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप में किया गया है। धन के केवल इसी तरह के प्रयोग को 'उपभोग' कहते हैं। दूसरी ओर, जब हम बारखाने में कच्चे गाल का प्रयोग करते हैं अथवा मशीन चलाने के लिए कोयले या बिजली को प्रयोग में लाते हैं, तो हमारी आवश्यकताएँ सीधे तौर से पूरी नहीं हो पाती। कारण, यहाँ धन का प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप में किया गया है। यह गन्ध है कि धन के इस प्रयोग से जो वस्तु तैयार होगी, उसमें किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति होगी। पर हम प्रचार की पूर्ति और तृप्ति अप्रत्यक्ष रूप में होती है। इसलिए इसे उपभोग न मानें। वास्तव में जब धन का अप्रत्यक्ष रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसे उपभोग नहीं कहते बल्कि उत्पत्ति कहते हैं।

अस्तु, उपभोग धन के उस प्रयोग को कहते हैं, जिसमें आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष या सीधे तौर से होती है।

साधारण नीतिचाल में वस्तु के नष्ट होने को उपभोग कहा जाता है। जब कोयला जलाया जाता है, तो कुछ देर बाद वह जल कर राख हो जाता है। उग समय यह कहा जाता है कि उसका उपभोग हो गया है। इसी तरह जब हम फल खाते हैं या दूध पीते हैं, तो यह कहा जाता है कि इन वस्तुओं का उपभोग हो गया है, क्योंकि वे नष्ट हो चुकी हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि यह क्या है, जो नष्ट होता है? यह तो सभी जानते हैं कि पदार्थ नष्ट नहीं होता उसको नष्ट करना मनुष्य की शक्ति के बाहर है। ऊपर के उदाहरण को ही ले लिया जाय। जब कोयला जलाया जाता है, तो क्या नष्ट होता है? साधारण तौर से ऐसा लगता है कि पदार्थ नष्ट हो गया है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। केवल कोयले के रूप में परिवर्तन होता है। वह राख, धुआँ, आदि

के रूप में बदल जाता है। किन्तु यह बात अवश्य है कि इस रूप में परिवर्तन से कोपले की उपयोगिता नष्ट हो जाती है। अब हम उसमें आग जलाने का काम नहीं ले सकते। अस्तु, आम बोलचाल में जब यह कहा जाता है कि अमुक पदार्थ का उपभोग हुआ है, तो इसका यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि वह पदार्थ नष्ट हो चुका है। कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता, केवल उसकी उपयोगिता ही नष्ट होती है।

इसलिए यदि हम साधारण अर्थ को भी अपनाएँ, तो भी यही कहा जा सकता है कि उपभोग किसी वस्तु की उपयोगिता के नष्ट होने को ही कहते हैं। पर ध्यान रहे कि उपभोग का आशय केवल उपयोगिता के नष्ट होने में नहीं है। यदि किसी मकान में आग लग जाय, और फलस्वरूप उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाय तो इसे उपभोग न मानेंगे। इसी तरह यदि चाय का भेट हाथ में गिर कर टूट जाय, तो इसे उपभोग न कहेंगे, क्योंकि उसकी उपयोगिता जाती रहेगी। उपभोग तभी माना जायगा, जब वस्तु के प्रयोग से किसी मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हो और उसे तृप्ति तथा सतोष प्राप्त हो।

इस बात को ध्यान में रखते हुए हम उपभोग की परिभाषा इस प्रकार भी कर सकते हैं—प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकताओं की तृप्ति करने में वस्तु की उपयोगिता के नष्ट होने को 'उपभोग' कहते हैं।

यह बेलने में आता है कि कुछ वस्तुओं का उपभोग शीघ्र ही समाप्त हो जाता है और कुछ का देर तक चलता रहता है। जब हम भोजन करते हैं, मिगरेट पीते हैं अथवा कोपला अलाते हैं तो इन सब की उपयोगिता और प्रयोग दोनों ही शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। किन्तु दूसरी ओर जब हम मोटर, मकान आदि का प्रयोग करते हैं, तो उनका उपभोग बहुत समय तक चलता है। ये वस्तुएँ अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं। पर चाहे किसी वस्तु का उपयोग देर तक चलता रहे या शीघ्र ही समाप्त हो जाय, इससे उपभोग की परिभाषा में कोई अन्तर नहीं पड़ता।

### अन्तिम और उत्पादक उपभोग

(Final and Productive Consumption)

ई अर्थशास्त्री उपभोग को दो भागों में विभाजित करते हैं (१) अन्तिम उपभोग (Final Consumption) और (२) उत्पादक उपभोग (Productive Consumption) । जब किसी वस्तु का उपभोग प्रत्यक्ष रूप में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो उसे 'अन्तिम उपभोग' कहते हैं । जैसे जब कोई व्यक्ति भूख मिटाने के लिए रोटी खाता है, व्याम बुझाने के लिए पानी पीता है, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप में हो जाती है । अतः वस्तुओं के इस प्रकार के उपभोग को 'अन्तिम उपभोग' कहेंगे ।

दूसरी ओर, बहुत-सी वस्तुओं का उपभोग अन्य वस्तुओं के बनाने के लिए किया जाता है । जैसे कपड़ा तैयार करने के लिए सूत और मशीनों का उपभोग । इस प्रकार के उपभोग को 'उत्पादक उपभोग' कहते हैं । इस उपभोग में किसी आवश्यकता की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती । इसलिए यथायथं में, 'अन्तिम उपभोग' को ही उपभोग मानना चाहिए । 'उत्पादक उपभोग' तो उत्पादन का एक अंग है । यह अन्तिम उपभोग का एक माध्यम मात्र है । अतः अन्तिम उपभोग को ही उपभोग मानना उचित होगा । आधुनिक अर्थशास्त्रियों का भी यही मत है ।

उपभोग-विभाग के अन्तर्गत यह विचार किया जावेगा कि किस प्रकार आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित साधनों को प्रयोग में लाया जाता है, कैसे अधिकतम पूर्ति प्राप्त हो सकती है, माग और मूल्य किस तरह एक-दूसरे से प्रभावित होते हैं, उपभोगिता और माग सम्बन्धी नियम क्या हैं ?

### उपभोग का महत्त्व

(Importance of Consumption)

अर्थशास्त्र में उपभोग का अपना गहव महत्व है । वास्तव में एक तरह से उपभोग पर ही अर्थशास्त्र का सारा आधार और महत्व निर्भर है । अर्थशास्त्र का आदि और अन्त उपभोग में ही है ।

मनुष्य की अनेक आवश्यकताएँ होती हैं। उनकी पूर्ति और तृप्ति के लिए वह उद्योग करता है। यदि उसे आवश्यकताएँ न सताएँ, तो वह काम न करेगा और फिर उत्पत्ति का कोई प्रश्न ही न उठेगा। अतः, उपभोग ही आर्थिक उद्योग का प्रारम्भ और मूल कारण है। इसी के लिए उत्पत्ति की जाती है। इस प्रकार उपभोग अर्थशास्त्र का आदि या आधार कहा जा सकता है।

साध ही जो कुछ उत्पन्न किया जाता है, वह अन्त में उपभोग के ही काम आता है। उपभोग के कारण और उसी के लिए ही वस्तुओं का उत्पादन होता है। उत्पादित वस्तुओं का विनिमय, वितरण आदि सब इसीलिए किया जाता है कि उनका उपभोग हो, बिनागे आवश्यकताओं की तृप्ति हो सके। इस प्रकार आर्थिक उद्योग अर्थात् अर्थशास्त्र का, आदि और अन्त उपभोग में ही निहित है।

प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति, कार्य-क्षमता और योग्यता काफी जरा तक उसके उपभोग पर निर्भर होती है। यदि उसके उपभोग का ढंग अच्छा है, तो निष्पत्ति ही उसकी शक्ति और योग्यता बढ़ेगी। वह अधिक धनोत्पत्ति कर सकेगा और उसका जीवन-स्तर ऊँचा होगा। फलस्वरूप उसकी सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी। और चूँकि समाज की शक्ति और क्षमता व्यक्तिद्वारा पर निर्भर होती है, इसलिए कहा जा सकता है कि समाज की क्षमता-शक्ति, सुख-समृद्धि बहुत कुछ उपभोग पर ही निर्भर है। इसके विपरीत यदि उपभोग का ढंग अनुचित अथवा गिरा हुआ है तो उसका परिणाम व्यक्ति और समाज पर उल्टा पड़ेगा। उसकी कार्य-कुशलता, शक्ति और योग्यता गिरेगी। वह निर्बल, दुःखी और गरीब हो जायेगा। अतः, प्रत्येक व्यक्ति के निम्न उपभोग के महत्व को समझना, उसके नियमों को जानना नितांत आवश्यक है। इसके बिना उपभोक्ता अपने अधिकतम तृप्ति के लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेगा।

उत्पादक, व्यापारी आदि के लिए उपभोग का अध्ययन और भी

अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है। उनकी सफलता बहुत कुछ अंश तक उपभोग सम्बन्धी बातों के समझने पर निर्भर है। यह तो सभी जानते हैं कि उत्पत्ति उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं पर अर्पित है। उपभोग के कारण और उसी के लिए ही उत्पत्ति की जाती है। इसलिए उत्पादक को उपभोग का पूरा-पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। उसके लिए हम की जानकारी आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को किस वस्तु की, कब, कहाँ और कितनी आवश्यकता है। यदि उत्पादक मांग का ठीक-ठीक अनुमान कर सका है, तो उसे लाभ होगा और साथ ही समाज को भी। किन्तु यदि उसका अनुमान गलत निकला, तो उसे हानि होगी और आगे चल कर इसका बुरा प्रभाव मारे समाज पर पड़ेगा। व्यापारिक तेजी-मंदी का, जिससे समस्त संसार में गड़बड़ी और हलचल मच जाती है, मुख्य कारण यह है कि उत्पादक इस बात का ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाते कि कौन-सी वस्तु कब और कितनी मात्रा में बनानी चाहिए। फल यह होता है कि उत्पत्ति या तो आवश्यकता से बहुत अधिक हो जाती है, या बहुत कम। इससे बहुत गड़बड़ी मच जाती है। इसीलिए उत्पादक, व्यापारी आदि के लिए उपभोग सम्बन्धी बातों का मंली माति समझना बहुत जरूरी है।

समाज की दृष्टि से भी उपभोग का विषय बहुत महत्व रखता है। प्रायः समाज की शक्ति, धन-धान्य, सुख-समृद्धि बहुत-कुछ अंश तक उपभोग पर ही निर्भर रहती है। उचित वस्तुओं के उपभोग से समाज की उत्पादक और औद्योगिक क्षमता निरंतर बढ़ती है और सभी आर्थिक विकास और प्रगति संभव है। अनुचित उपभोग होने से समाज की उत्पादक क्षमता क्षीण हो जाती है और साथ ही अनेक जटिल समस्याएँ आ खड़ी होती हैं। ऐसी वस्था में वह समाज जिससे भी विश्वास में उत्पत्ति नहीं कर सकता। अतः सामाजिक उत्पत्ति और कल्याण के लिए उपभोग की समस्याओं का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है।

ऊपर के वर्णन से पता चलता है कि अर्थशास्त्र में उपभोग का क्या

और कितना महत्व है। उपभोग के लिए ही वस्तुएं उत्पन्न की जाती हैं और उसी के निमित्त वस्तुओं का वितरण और विनिमय होता है। इस प्रकार आर्थिक विकास तथा प्रगति का मूल कारण और लक्ष्य उपभोग ही है। यही सब बातों का आदि और अन्त है। अर्थशास्त्र का सारा धारोमदार इसी पर अवलम्बित है।

अगले अध्यायो में उपभोग-सम्बन्धी मुख्य बातों का विवेचन किया जायगा।

### QUESTIONS

1. Define and explain the meaning of Consumption as clearly as possible
2. What do you understand by 'Productive Consumption' and 'Final Consumption'? Do you think that productive consumption should be treated as consumption?
3. "Consumption is the beginning and the end of all economic activities" Explain fully
4. Bring out the importance of the study of Consumption both from the individual and the social points of view

## अध्याय ९ आवश्यकताएँ (Wants)

मनुष्य अपने साधारण जीवन में किसी न किसी आवश्यकता (want) वा, तृप्ति के अभिगम वा, अनुभव करता है। उसकी तृप्ति के लिए वह इच्छित वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और फिर उपभोग में उस आवश्यकता अथवा अभिगम की पूर्ति करता है। इसमें उसे तृप्ति और सतोष प्राप्त होता है। आवश्यकताओं और उनकी तृप्ति के लिए वस्तुओं के उपभोग का क्रम जीवन भर चलता रहता है। मनुष्य और समाज की उन्नति, प्रगति सुख-समृद्धि इसी पर निर्भर है। अस्तु, मानव-जीवन में आवश्यकताओं और उनकी तृप्ति का विशेष महत्व है। चूंकि अर्थशास्त्र मानव-जीवन के अध्ययन का एक अंग है, इसलिए अर्थशास्त्र भर में आवश्यकता का आभास और उसकी महत्ता व्याप्त है। आवश्यकताओं के लिए ही आर्थिक उद्योग किये जाते हैं। आर्थिक उद्योग के जितने भी रूप और प्रकार हैं, उन सबका मूल कारण और अन्तिम उद्देश्य आवश्यकताएँ ही हैं। धन की उत्पत्ति, उसका विनिमय, वितरण और उपभोग सब आवश्यकताओं के लिए ही किया जाता है।

### आवश्यकता का अर्थ (Meaning of Want)

इस सम्बन्ध में इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि अर्थशास्त्र में 'आवश्यकता' शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। आम बोल-चाल में तो 'इच्छा', 'चाह', और 'आवश्यकता' सब एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। वे

एक दूसरे के पर्याय समझे जाते हैं। किन्तु अर्थशास्त्र में 'आवश्यकता' शब्द को एक विशेष अर्थ दिया जाता है, जो 'चाह' और 'इच्छा' के अर्थ से भिन्न है। अर्थशास्त्र में 'आवश्यकता' तृप्ति के ऐसे अभाव के अनुभव को कहते हैं, जो मनुष्य को उद्योग तथा कुछ त्याग करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे तृप्ति की वह कमी पूरी हो जाय। दूसरे शब्दों में, आवश्यकता मनुष्य में किसी वस्तु की कमी का संकेत करती है, जिससे उस मनुष्य को एक प्रकार का कष्ट अनुभव होता है। फलस्वरूप वह दृष्टित वस्तु को पाने के लिए उद्योग करता है, जिसमें उस कमी की पूर्ति हो और उसे तृप्ति और शान्ति प्राप्त हो। अन्तु, अर्थशास्त्र में 'आवश्यकता' शब्द तृप्ति की कमी का भाव प्रदर्शित करता है, तृप्ति का अभाव जिसकी पूर्ति के लिए मनुष्य उद्योग करता है। 'इच्छा' और 'चाह' का साधारणतः यह अर्थ नहीं होता। उनसे तो केवल किसी वस्तु की कामना ही व्यक्त होती है। इसलिए अर्थशास्त्र में दोनों के अर्थ भिन्न हैं। 'आवश्यकता' शब्द 'इच्छा' में भिन्न भाव प्रदर्शित करता है।

### आवश्यकता और उद्योग

(Want and Effort)

आवश्यकता और उद्योग का परस्पर सम्बन्ध किसी से छिपा नहीं है। आवश्यकता उद्योग का मूल कारण है। मनुष्य कार्य इसलिए करता है जिसमें उसकी आवश्यकताओं की तृप्ति हो। यदि आवश्यकताएँ उसे न सताएँ तो वह किसी प्रकार का काम न करना चाहेगा। उस दशा में ससार का सब काम बन्द हो जायेगा; फिर नयी किमान कड़ी धूप में और बर्षा में काम करेंगे, या मजदूर बड़े-बड़े कारखानों में अपना पसीना बहायेंगे। अन्तु, इसमें सन्देह नहीं कि ममार में जितने भी काम होते हैं, वे सब आवश्यकताओं के ही कारण किये जाते हैं। जैसे-जैसे मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं, वैसे-वैसे उनकी तृप्ति के लिये नये-नये उद्योग किये जाते हैं। यदि आवश्यकताओं का कोई अन्त नहीं, इस कारण उन प्रयत्नों का भी कोई अन्त नहीं, जो उनकी तृप्ति के लिए किये जाते हैं।



प्रारम्भिक अवस्था में आवश्यकता और उद्योग के बीच ऐसा ही सम्बन्ध होता है। आवश्यकता के कारण मनुष्य को उद्योग करना पड़ता है। किन्तु जब मनुष्य उत्पत्ति के पथ पर आगे कदम बढ़ाता है, तो उद्योग द्वारा भी तर्द-नई आवश्यकताएँ उत्पन्न होने लगती हैं। जब मनुष्य प्रयत्न करता है, तो केवल आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं होती, बल्कि उसके द्वारा कई नई आवश्यकताएँ भी पैदा हो जाती हैं। इतिहास में इस तरह के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें यह पता चलता है कि आवश्यकता से ही उद्योग का जन्म नहीं होता, बल्कि आगे चलकर उद्योग के कारण भी नई आवश्यकताओं की सृष्टि होती है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड के इतिहास पर ही दृष्टि डालिए। आठ से करीब २०० वर्ष पहले इंग्लैंड में कई नई मशीनों का आविष्कार हुआ, जिनसे उत्पत्ति बड़े पैमाने पर होने लगी। जब मशीन द्वारा उत्पत्ति की मात्रा अधिक बढ़ी तो इस बात की आवश्यकता हुई कि माल को दूर-दूर के देशों में भेजा जाय, जिससे माल की खपत बड़े। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अच्छे और सस्ते यातायात के साधनों की आवश्यकता हुई। फलस्वरूप पक्की सड़के और नहरें बनाई गईं। किन्तु जब इसने भी काम न चल सका, तो रेल का आविष्कार हुआ। अब माल आसानी और शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जाने लगा। इसी तरह जब व्यापार और उद्योग-धन्धों में वृद्धि हुई तो दूर-दूर स्थानों में व्यापार-सम्बन्धी समाचार मगाने और भेजने की आवश्यकता पड़ी। परिणाम-स्वरूप तार, डाक, टेलीफोन, रेडियो आदि का आविष्कार हुआ।

यह क्रम बराबर चलता रहता है। आवश्यकताओं के कारण मनुष्य काम करता है और उद्योग के फलस्वरूप अनेक नई आवश्यकताएँ उत्पन्न होती हैं। ये एक दूसरे के जन्म के कारण हैं। मानव-समाज की प्रगति और उत्पत्ति बहुत-कुछ इसी पर निर्भर करती है।

### आवश्यकताओं की विशेषताएँ

(Characteristics of Wants)

वैसे तो सभी की कुछ न कुछ आवश्यकताएँ होती हैं, किन्तु सबकी

आवश्यकताएँ एक-सी नहीं होती । भिन्न-भिन्न लोगों की भिन्न-भिन्न आवश्यकताएँ होती हैं । पूर्वजों की और हमारी आवश्यकताओं में बमीन-आमान का अन्तर है । इसी तरह इंग्लैंड अपना अपनी काँचों की आवश्यकताएँ भारतवासियों की आवश्यकताओं से काफी भिन्न हैं । इसका एक मुख्य कारण है । आवश्यकताएँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा धार्मिक व्यवस्था तथा मनुष्य के स्वभाव, चरित्र आदि बातों पर निर्भर होती हैं । ये सब बातें हर समय और हर स्थान पर एक समान नहीं होती । इस कारण आवश्यकताओं में बहुत भिन्नता पाई जाती है । देश, काल और परिस्थिति के अनुसार आवश्यकताओं की संख्या, तीव्रता, भिन्नता आदि में अन्तर पड़ता रहता है । फिर भी इनमें कुछ विशेषताएँ, लक्षण या गुण ( characteristics ) पाये जाते हैं । इन विशेषताओं का बहुत महत्व है । अर्थशास्त्र के कई नियम इन्हीं विशेषताओं पर निर्भर हैं । संक्षेप में, अब आवश्यकताओं की मुख्य विशेषताओं और उन पर जो नियम स्थापित हैं, उनका वर्णन करेंगे ।

( १ ) आवश्यकताएँ असंख्य हैं—मनुष्य की आवश्यकताओं का कोई अन्त नहीं । वे अपरिमित हैं । जीवन में कभी भी ऐसा अवसर नहीं आता, जब हम यह कह सकें कि अब हमारी कोई भी आवश्यकता तृप्ति के लिए बाकी नहीं है । जन्म से लेकर मृत्यु तक आवश्यकताएँ हमें घेरें रहती हैं । एक ओर तो हम उनकी पूर्ति करते जाते हैं और दूसरी ओर वे और भी बढ़ती जाती हैं । ज्यों ही किसी एक आवश्यकता की तृप्ति होती है, त्यों ही दूसरी उसके स्थान पर आ खड़ी होती है । इसलिए हर तरह प्रयत्न करने पर भी मनुष्य अपनी कुल आवश्यकताओं की तृप्ति नहीं कर पाता । मनुष्य और समाज की संप्रति आवश्यकता की इस विशेषता पर निर्भर है । जैसे-जैसे नई आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं, वैसे-वैसे मनुष्य उनकी पूर्ति के लिए नए-नए उद्योग करता है, नई-नई बातें सोचता है । प्रगति और उत्थति इसी प्रकार सम्भव हो सक्ती है ।

(२) प्रत्येक आवश्यकता की पूरी पूर्ति हो सकती है—वैसे तो मनुष्य की आवश्यकताएँ असंख्य हैं और उन सब की पूर्ति सम्भव नहीं है, किन्तु एक आवश्यकता की पूर्ति पूरी तौर से हो सकती है। यदि उसके पास पर्याप्त साधन हैं तो उसकी एक विशेष आवश्यकता की पूर्ति खास सामान के लिए पूर्ण रूप से की जा सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को चाय की आवश्यकता है। यथेष्ट साधन होने पर वह अपनी इस आवश्यकता की एक खास समय के लिए पूरी तौर से पूर्ण कर सकता है। तीन-चार घण्टे चाय पीने के बाद उसकी आवश्यकता पूर्ण हो जायगी। यह कहेंगे कि वह अब में और अधिक चाय नहीं पी सकता। मेरी यह आवश्यकता पूर्ण रूप से पूर्ण हो चुकी है।" इसी प्रकार मनुष्य की अन्य आवश्यकताओं को भी यथेष्ट साधन होने पर एक-एक करके किसी विशेष समय में पूर्ण किया जा सकता है।

आवश्यकता की इस विशेषता पर सीमान्त उपयोगिता-ह्रास नियम (Law of Diminishing Utility) निर्भर है, जिसके आधार पर कई और नियम स्थापित किए गये हैं।

(३) आवश्यकताएँ एक दूसरे की पूरक होती हैं—कुछ आवश्यकताएँ एक-दूसरे की पूरक (complementary) होती हैं। वे एक साथ उत्पन्न होती हैं और एक ही साथ उनकी पूर्ति होती है। एक के बिना दूसरे की पूर्ति नहीं की जा सकती, जैसे पेट्रोल के बिना मोटर, स्टाइलो के बिना कलम या घोड़े के बिना टागा। ये एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। एक की पूर्ति के लिए दूसरे की पूर्ति करना आवश्यक है।

(४) आवश्यकताएँ प्रतियोगी (competitive) होती हैं—आवश्यकताओं में परस्पर प्रतियोगिता भी होती है। कारण यह है कि पूर्ति के साधन तो परिमित हैं, पर आवश्यकताओं की कोई गिनती नहीं। फलस्वरूप आवश्यकताओं के बीच घोर संघर्ष और प्रतियोगिता होती है। साधनों के सीमित होने के कारण यदि किसी एक आवश्यकता की पूर्ति को जानें

है, तो अन्य बहुत-सी आवश्यकताएं अतृप्त ही रह जाती हैं। इसलिए हमको यह निर्णय करना पड़ता है कि किस आवश्यकता की पूर्ति की जाय, और किस की नहीं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक लड़के के पास चार रुपये हैं और वह बाजार जाता है। उस समय उसके सामने अनेक ऐसी आवश्यकताएं आ सकती होंगी जो चार रुपये में तृप्त की जा सकती हैं। चाहे वह एक पुस्तक खरीद ले, या कमीज का कपड़ा, या जूता या और कोई दूसरी वस्तु, जो चार रुपये में मिल सकती हो। इन तमाम आवश्यकताओं में से वह उस समय केवल एक ही को पूर्ति कर सकता है, सब की नहीं। कारण, उसके पास कुल चार ही रुपये हैं। इसलिए उसे इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा कि इनमें से किस आवश्यकता की पूर्ति की जाय। वह उन सब आवश्यकताओं की एक दूसरे से तुलना करेगा और जितने वह सबसे अधिक आवश्यक समझेगा, उसे ही पूरा करेगा। बाकी सबको छोड़ देगा। इस तरह मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताएं एक दूसरे से इस बात में प्रति-षेधिता करती हैं कि वे दूसरों की अपेक्षा सर्वप्रथम तृप्त की जायें। आवश्यकता की इस विशेषता पर सम-सीमान्त-उपयोगिता नियम (Law of Equi-marginal Utility) अथवा प्रतिस्थापन नियम (Principle of Substitution) अवलम्बित है।

(५) आवश्यकताएं बार-बार उत्पन्न होती हैं—हमारी बहुत-सी आवश्यकताएं ऐसी हैं, जो एक बार पूर्ति करने के बाद भी बार-बार उत्पन्न होती रहती हैं। जब हम किसी आवश्यकता की पूर्ति बार-बार करते हैं, तो उस आवश्यकता को तृप्त करने की हमारी आदत पड़ जाती है। इस प्रकार की आदतों में बराबर वृद्धि होती रहती है। इनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन है। जीवन-स्तर अथवा रहन-सहन के उग का आशय इन्हीं आवश्यकताओं से है, जिनके हम आदी हो जाते हैं। वेतन निर्धारित करते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(६) वर्तमान आवश्यकताएं अधिक तीव्र लगती हैं—एक साधारण

व्यक्ति वर्तमान आवश्यकताओं को भावी आवश्यकताओं की अपेक्षा अधिक तीव्र समझता है। कारण, भविष्य अनिश्चित है। “नी नगद न तेरह उधार” की कहावत आवश्यकता की इसी विशेषता को और स्पष्ट करती है। हम इतने दूरदर्शी नहीं होते कि भावी आवश्यकताओं को वर्तमान आवश्यकताओं के बराबर महत्व दें। व्याज के कई मिश्रान्त इस विशेषता पर अवलम्बित हैं।

### आवश्यकताओं का वर्गीकरण

(Classification of Wants)

मनुष्य अपने साधारण जीवन में अनेक आवश्यकताओं का अनुभव करता है। पर वे सब एक समान तीव्र नहीं होती। उनमें कुछ अधिक आवश्यक होती है, और कुछ कम। हमारी कुछ आवश्यकताएँ ऐसी हैं जिनकी पूर्ति बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इन्हे मूल अथवा प्रमुख आवश्यकताएँ कहते हैं। जो वस्तुएँ इन प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं उन्हें आवश्यक पदार्थ कहते हैं। शेष सब आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं को आराम तथा विलास की वस्तुएँ कहते हैं। दूसरे शब्दों में, उपयोग की वस्तुओं को उनकी आवश्यकतानुसार तीन भागों में विभाजित किया जाता है—आवश्यक पदार्थ (Necessaries), आराम के पदार्थ (Comforts) और विलासिता के पदार्थ (Luxuries)।

(१) आवश्यक पदार्थ—आवश्यक पदार्थ उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका उपयोग मनुष्य के जीवन, स्वास्थ्य और निपुणता के लिए जरूरी होता है। इन वस्तुओं के न मिलने से मनुष्य को बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, यहाँ तक कि जीवन ही न चल सकेगा। इनके उपयोग से जीवन की रक्षा होगी है और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।

वस्तुएँ मित्र-मित्र कारणों से आवश्यक हो सकती हैं। फलस्वरूप, आवश्यक पदार्थों को तीन भागों में बाँट दिया जाता है—जीवन-रक्षक पदार्थ (Necessaries of life) निपुणता-दायक पदार्थ, (Necessaries

for efficiency), और रिवाजी आवश्यक पदार्थ (Conventional necessities)

(क) जीवन रक्षक पदार्थ—इसके अन्तर्गत वे वस्तुएँ आती हैं, जिनमें शरीर और जीवन की रक्षा होती है। इनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, जैसे न्यूनतम भोजन, वस्त्र, आदि। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन-रक्षा के लिए इन वस्तुओं की जरूरत होती है, चाहे वे सस्ती मिले या महंगी।

(ख) निपुणतादायक पदार्थ—जो वस्तुएँ मनुष्य की कार्य-क्षमता और योग्यता बनाये रखने अथवा उनकी वृद्धि के लिये जरूरी होती हैं और जिनके न होने से कार्य-क्षमता गिर जाती है, उन्हें निपुणतादायक पदार्थ कहते हैं, जैसे पुष्टिकारक भोजन, ताफ और अच्छे वस्त्र, हवादार मकान, आदि। इन वस्तुओं के उपभोग से मनुष्य की योग्यता अथवा निपुणता में, वस्तुओं के मूल्य की अपेक्षा, कहीं अधिक वृद्धि होती है।

(ग) रिवाजी आवश्यक पदार्थ—कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका रोचन रीति-रस्म, आचार-व्यवहार के दबाव, अथवा यादत पड़ जाने के कारण विचार होकर जरूर करना पड़ता है। इन्हें रिवाजी आवश्यक पदार्थ या कृत्रिम आवश्यकता की वस्तुएँ कहते हैं। ये वस्तुएँ जीवन-रक्षा या कार्य-क्षमता के लिए आवश्यक नहीं होती। प्रायः इनके सेवन से कार्यकुशलता कम हो जाती है। किन्तु लोक-निन्दा, आदत, रीति-रस्म के कारण इनका उपयोग बहुत जरूरी समझा जाता है।

(२) आराम के पदार्थ—आराम के पदार्थ उन वस्तुओं को कहते हैं, जिनके उपभोग से मनुष्य की कार्य-कुशलता में उन वस्तुओं के मूल्य की अपेक्षा कम वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में जितना व्यय इन वस्तुओं के उपभोग पर किया जाता है, उस अनुपात से मनुष्य की कार्यक्षमता नहीं बढ़ती। योग्यता के बढ़ने की दर वस्तुओं के मूल्य की दर से कम होती है। इनके उपभोग से मनुष्य अपना जीवन सुखमय बना सकता है। इनमें कार्य-कुशलता में भी वृद्धि होती है, पर वृद्धि इतनी नहीं होती, जितना कि इन वस्तुओं पर खर्च करना पड़ता है।

(३) विलासिता के पदार्थ—विलासिता की वस्तुओं का आशय उन वस्तुओं से है, जिनके उपभोग में मनुष्य की दान-शौकत या शौक की इच्छाओं की पूर्ति होती है। इनके सेवन में उपागोचता की निगुणता में वृद्धि नहीं होती। प्रायः इन वस्तुओं के उपभोग से योग्यता कार्य-शक्ति, आदि गिरने लगती है।

उपभोग की वस्तुओं को उपर्युक्त तीन श्रेणियों में विभक्त तो अवश्य कर दिया गया है, पर कौन-सी वस्तुएँ किस श्रेणी में या वर्ग में आती हैं, इसे निश्चित रूप से कहना बहुत कठिन है। हम यह नहीं कह सकते कि अमुक वस्तु सबके लिए आवश्यक पदार्थ अथवा आराम की वस्तु है। यह समझना भूल है कि बहुत आवश्यक पदार्थ है, मोटर आराम की वस्तु है और हीरे-जवाहिरात विलासिता की सामग्री है। वस्तुओं का वर्गीकरण कई बातों पर निर्भर है, जैसे रहन-सहन की रीति, देश-काल, जलवायु, मनुष्य का स्वभाव, विचार, उसकी आय तथा आर्थिक, सामाजिक स्थिति, आदि। में सब बातें हर समय और हर स्थान पर एक समान नहीं होती। इन सब बातों में परिवर्तन होने से भिन्न-भिन्न वस्तुएँ एक श्रेणी से हट कर दूसरी श्रेणी में आ जाती हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक वस्तु सब मनुष्यों, देशों और समय के लिए आवश्यक पदार्थ है या विलासिता की वस्तु है। एक ही वस्तु किसी एक के लिए आवश्यक पदार्थ हो सकती है, दूसरे के लिए सुख का पदार्थ, और तीसरे के लिए वही वस्तु विलासिता की वस्तु हो सकती है। उदाहरणार्थ, मोटर एक प्रसिद्ध डाक्टर के लिए आवश्यक वस्तु है, क्योंकि उसकी महायत्ना में वह कम समय में बहुत मरीजों को देखता है, किन्तु एक अमीर आदमी के लिए मोटर सुख का पदार्थ है और एक साधारण व्यक्ति के लिए वही विलासिता की वस्तु है। इस तरह हम देखते हैं कि भिन्न-भिन्न श्रेणी वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न वस्तुएँ आवश्यक अथवा विलासिता की वस्तुएँ होती हैं। अमीर आदमी के लिए जो वस्तु आवश्यक है, वही एक गरीब आदमी के लिए आराम या विलासिता की सामग्री बन सकती है।

इसी तरह स्थान-परिवर्तन के साथ-साथ वस्तुओं के वर्गीकरण में भिन्नता आ जाती है। जो वस्तु एक स्थान पर आवश्यक मानी जाती है, वही दूसरे स्थान पर आराम या विलासिता की श्रेणी में गिनी जा सकती है। कारण, भिन्न-भिन्न स्थानों पर जलवायु, रीति-रिवाज, फैशन आदि में बहुत भिन्नता होती है। ठंडे देशों में ऊनी वस्त्र आवश्यक वस्तु हैं, क्योंकि इसके बिना मनुष्य अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकता। किन्तु ऊनी वस्त्र गर्म देश में आवश्यक नहीं समझा जाता। गहनों का चलन भारतवर्ष में बहुत है। भारतीय नारियों के लिए गहने रिवाजी आवश्यक-पदार्थ हैं। लेकिन पाश्चात्य देश की नारियाँ गहनों को विलासिता की श्रेणी में गिनती हैं। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं का उदाहरण लेकर दिखाया जा सकता है कि कैसे फैशन, रीति, प्रथा, आदि में अन्तर होने के कारण एक ही वस्तु भिन्न-भिन्न देशों में आवश्यक, आराम तथा विलासिता की वस्तु मानी जाती है।

समय में परिवर्तन होने से वस्तुएँ एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में आ जाती हैं। बहुत-सी वस्तुएँ, जो पहले आराम और विलासिता की सामग्री थी, आज आवश्यक हो गई हैं। अस्तु, अब तक हम जलवायु, देशकाल, मनुष्यों की आयु, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर विचार न कर लें तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक वस्तु को किस श्रेणी में रखना आए। कोई भी वस्तु अपने आप किसी भी वर्ग में शामिल नहीं की जा सकती।

दूसरे शब्दों में, आवश्यक, आराम और विलासिता तुलनात्मक शब्द हैं। ये व्यक्ति, समय और स्थान के साथ सम्बन्धित होते हैं।

### वर्गीकरण का आधार

(Basis of Classification)

इस सम्बन्ध में वर्गीकरण का आधार जान लेना अत्यन्त आवश्यक है। इसके बिना हम आवश्यकताओं के वर्गीकरण का उचित ज्ञान नहीं प्राप्त



कर सकते। उपभोग की वस्तुओं का वर्गीकरण कार्य-कुशलता अथवा निपुणता के आधार पर किया जाता है। अमय वस्तु को किस वर्ग में रखा जाय, इसको तय करने के लिये हमें यह देखना पड़ेगा कि उसके उपभोग से उपभोक्ता की कार्य-कुशलता पर बंसा प्रभाव पड़ता है। यदि उन् वस्तु से उपभोक्ता की योग्यता में बढ़ते हुए अनुपात में वृद्धि होती है और उसके उपभोग न करने से उसकी योग्यता बहुत गिर जाती है तो उस वस्तु को आवश्यक-वस्तु की श्रेणी में रखेंगे। यदि उसमें उपभोक्ता की योग्यता घटते हुए अनुपात से बढ़ती है, तो वह आराम की वस्तु मानी जायगी और यदि उपभोक्ता की कार्य-कुशलता घट जाती है, अथवा बंसी ही रहती है, तो उस वस्तु को विलासिता की वस्तु कहेंगे।

### QUESTIONS

- 1 Define want Show how it differs from a mere desire
- 2 "Wants lead to economic activities and economic activities to fresh wants" Discuss it fully
- 3 Mention the important characteristics of wants and the laws based on them
- 4 What are Necessaries, Comforts and Luxuries? What is the basis of such a classification?
- 5 Show how Necessaries, Comforts and Luxuries are relative terms

## सीमान्त उपयोगिता-हास नियम

### (Law of Diminishing Marginal Utility)

अर्थशास्त्र के कुछ पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या करते समय यह पहले कहा जा चुका है कि उपयोगिता किमी वस्तु की आवश्यकता-पूरक शक्ति अथवा गुण को कहते हैं। वस्तु की यह शक्ति आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर होती है। जितनी अधिक या कम तीव्र किसी वस्तु की आवश्यकता होगी, उतनी ही अधिक या कम उस वस्तु में उपयोगिता होगी। यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएँ एक-सी नहीं होती। देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। आवश्यकताओं के सम्बन्ध में यह भी कहा जा चुका है कि वे एक समान तीव्र नहीं होती, और न ही उनकी तीव्रता सदा एक-सी बनी रहती है। इसलिए सभी वस्तुओं की उपयोगिता एक समान नहीं होती और न ही प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता सभी मनुष्यों के लिए एक-सी हो सकती है। यही नहीं, एक ही वस्तु की उपयोगिता एक ही व्यक्ति के लिए भिन्न-भिन्न समय और परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न हो सकती है। इस सम्बन्ध में यह पूछा जा सकता है कि क्या उपयोगिता की माप और तुलना की जा सकती है? और यदि हाँ, तो किस प्रकार?

### उपयोगिता की माप

#### (Measurement of Utility)

हम अपने साधारण जीवन में अनेक वस्तुओं की माप और तुलना करते हैं। जैसे कपड़े की माप रज में करते हैं, अनाज को मन-सेर में तोलते

है, पेट्रोल को गैलन में मापते हैं। इसी तरह अनेक वस्तुओं की माप और तुलना के लिए भिन्न-भिन्न मापन या यंत्र हैं। किन्तु उपयोगिता की माप के लिए इस प्रकार का कोई माप-दंड नहीं है। उपयोगिता की माप फुट-इंच, मीटर या इस प्रकार के और किसी परिचित यंत्र आदि से नहीं की जा सकती। इसका कारण यह है कि उपयोगिता तृप्ति और सन्तोष की एक भावना है। इसका सम्बन्ध उपभोगिता और उसके मन से होता है और मानसिक वृत्तियों की माप अथवा तुलना प्रत्यक्ष रूप में सम्भव नहीं है।

यह तो ठीक है कि चूंकि उपयोगिता का सम्बन्ध मनुष्य के मन से अथवा उसके आवश्यकता में है और आवश्यकता की तीव्रता सब के लिए एक समान नहीं होती, इसलिए प्रत्यक्ष रूप में इसका ठीक-ठीक माप सम्भव नहीं है, फिर भी परोक्ष रूप में मोटे तौर से उपयोगिता की माप-तुलना हो सकती है। इस प्रकार की माप-तुलना निम्नलिखित दो तरह से की जा सकती है।

मान लो कोई व्यक्ति किसी एक वस्तु के लिए (१०) देने को तैयार है। वह (१०) देने को तभी तैयार होगा जबकि उसके विचार से उस वस्तु में (१०) के बराबर उपयोगिता होगी। यदि ऐसा नहीं है, तो उस वस्तु के लिए वह (१०) देने को तैयार न होगा। अस्तु, हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के लिए उस वस्तु की उपयोगिता (१०) के बराबर है। इसके आधार पर अन्य वस्तुओं में श्राप होन वाली उपयोगिता की तुलना की जा सकती है। जैसे यदि वह व्यक्ति दूसरी वस्तु के लिए (२०) देने को तैयार है, तो इसका यह अर्थ होगा कि दूसरी वस्तु की उपयोगिता पहली वस्तु की उपयोगिता से दुगुनी है। इस प्रकार जो कुछ एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए देने को तैयार है उससे उस वस्तु की उपयोगिता का अन्दाजा लगाया जा सकता है।

उपयोगिता का अनुमान एक दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता है। कभी-कभी हम मानसिक वृत्तियों का अन्दाजा इकाइयों अथवा आवाजों

में लगती है। शायद हम लोगों को इस तरह कहते हुए मुन्ते है कि "मरीज पहले से अब १२ आने अच्छा है", या, "इन दोनों में केवल १८-१९ का फर्क है", अथवा "इस वर्ष रुपये में केवल ६ आने ही फरक हुई है"। इनके अर्थों को सभी अच्छी तरह समझ जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम उपयोगिता की भाव इकाइयों में करें, तो कोई विशेष आपत्ति या अशुविधा न होगी। जब कभी किसी एक व्यक्ति के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न वस्तुओं की उपयोगिता की तुलना करनी होती है, तो उपयोगिता की कोई एक इकाई मान ली जाती है और फिर उस समय अन्य वस्तुओं की उपयोगिता का अनुमान इसी इकाई के अनुसार लगाया जाता है। जैसे मान लो, एक खास समय और परिस्थिति में पुस्तक, घड़ी और मेज की उपयोगिताओं की तुलना करनी है। ऐसे समय तुलना के लिए यह मान लेना पड़ेगा कि मेज की उपयोगिता एक के बराबर है। फिर हमें यह देखना होगा कि पुस्तक और घड़ी की उपयोगिता कितनी है। अब यदि हमें पुस्तक से दस गुना सतीष प्राप्त होने की सम्भावना है, तो हम कहेंगे कि पुस्तक की उपयोगिता १० है। और इसी प्रकार यदि घड़ी से २० गुना सतीष प्राप्त होने का अनुमान है, तो कहा जा सकता है कि घड़ी की उपयोगिता २० है।

### समस्त और सीमान्त उपयोगिता

(Total and Marginal Utility)

समस्त या कुल उपयोगिता (total utility) से अभिप्राय उन सब उपयोगिताओं के जोड़ से है, जो किसी वस्तु की कुल संख्याओं या इकाइयों के खरीदने द्वारा उपभोग में प्राप्त होती है। जैसे मान लो एक आदमी २० आम खरीदता है, तो बीस आमों से कुल मिला कर जो उपयोगिता उसे प्राप्त होगी उसे 'समस्त उपयोगिता' कहेंगे।

'सीमान्त उपयोगिता' (marginal utility) किसी वस्तु की उपभोग से लाई जाने वाली अन्तिम इकाई की उपयोगिता को कहते हैं। वस्तु की वह इकाई जो किसी व्यक्ति की खरीद की सीमा होती है, जिसके बाद

वह खरीद या उपभोग बन्द कर देता है, सीमान्त इकाई (marginal unit) कहलाती है। इस सीमान्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमान्त उपयोगिता कहते हैं। मान लो, कोई व्यक्ति पाच आम खरीदता है। तो पाचवा आम सीमांत इकाई है और इससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता होगी। यदि वह केवल तीन ही आम खरीदता है, तो तीसरा आम उसको सीमांत खरीद होगी और इससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता होगी।

सीमान्त उपयोगिता की परिभाषा एक और तरह से की जा सकती है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से ज्यादा ठीक है। किसी वस्तु की मरस्त उपयोगिता में जो उसकी एक और इकाई खरीदने अपना उपभोग में वृद्धि होती है, उसे 'सीमान्त उपयोगिता' कहते हैं। जैसे मान लो, एक आदमी दस आम खरीदता है और इन सबसे उसे १०० मरस्त उपयोगिता प्राप्त होती है। मान लो वह एक और आम खरीदता है और इससे मरस्त उपयोगिता १०० में १०६ हो जाती है, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति के लिए आम की सीमान्त उपयोगिता  $(१०६ - १००) = ६$  है। यह ग्यारहवाँ आम की उपयोगिता नहीं है, क्योंकि सब आम एक जैसे हैं। यह तो आम की सीमान्त उपयोगिता है, जबकि ग्यारह आम खरीदे जाते हैं।

### सीमान्त उपयोगिता-ह्रास नियम

(Law of Diminishing Marginal Utility)

जैसे तो मनुष्य की कुल आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं। ये अनन्त हैं और उन सब की पूर्ण तृप्ति सम्भव नहीं है। पर यदि हम किसी एक आवश्यकता पर विचार करें तो यह देखेंगे कि उसकी एक सीमा है, जहाँ वह पूर्ण तृप्त हो सकती है। मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकता सीमित और परिमित होती है। एक क्षण समय में पर्याप्त साधन होने पर किसी एक आवश्यकता को पूरी तौर से तृप्ति की जा सकती है। जब हम अपनी किसी एक आवश्यकता की तृप्ति करना शुरू करते हैं, तो धीरे-धीरे उस आवश्यकता की तीव्रता घटनी नली जाती है और कुछ देर बाद वह बिल्कुल तृप्त हो

जाती है। यह तो हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं कि जैसे-जैसे हमें कोई वस्तु अधिकाधिक परिमाण में मिलती जाती है, वैसे ही वैसे उस वस्तु की आवश्यकता की तेजी कम होती जाती है, और परिस्थिति के अपरिवर्तित रहने पर, अन्त में बिल्कुल पूरी हो जाती है।

यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि उपयोगिता-आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर होती है। इसलिए आवश्यकता की तेजी के घटने के साथ-साथ, उस वस्तु की उपयोगिता भी क्रमशः घटती जाती है और जब वह आवश्यकता पूर्ण रूप से तृप्त हो जाती है, तब उस समय उपयोगिता भी शून्य हो जाती है।

उदाहरण के लिए मान लें कि किसी भादमी को बहुत तेज भूख लगी है। ऐसी दशा में पहली रोटी की उपयोगिता उसके लिए बहुत होगी, क्योंकि रोटी की आवश्यकता बहुत तेज है। दूसरी रोटी की भी उपयोगिता काफी होगी, पर पहली रोटी के बराबर नहीं, क्योंकि उसको भूख कुछ अंश तक मिट चुकी है, अर्थात् आवश्यकता की तेजी पहले से कम है। इसी कारण तीसरी रोटी की उपयोगिता दूसरी रोटी की उपयोगिता में कम होगी, चौथी रोटी की तीसरी से कम होगी। इस तरह जैसे-जैसे वह और रोटियाँ खाता जायगा, वैसे ही वैसे उसकी रोटी की आवश्यकता कम होती जायगी; उसकी भूख मिटती जायगी। इसके फलस्वरूप बाद में ली जाने वाली रोटियों की उपयोगिता अर्थात् सीमांत उपयोगिता क्रमशः गिरती जायगी। कुछ देर बाद वह सीमा भी आ जायगी, जब वह कह उठेगा कि “मेरी आवश्यकता पूर्णतया पूरी हो चुकी है, मेरी भूख बिल्कुल शांत हो गई है, अब भूख और रोटियाँ नहीं चाहिए।” उस समय रोटी की सीमांत उपयोगिता शून्य हो जायगी। यदि वह इसके बाद भी रोटियाँ खायगा तो उपयोगिता के स्थान में उसे अनुपयोगिता (disutility) प्राप्त होगी, उसे तृप्ति के बजाय कष्ट, हानि अपना अमतोष होगा।

इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि जैसे-जैसे हमें कोई वस्तु अधिक-

धिक माना में मिलती जाती है, बँगे-ही बँगे उसकी आवश्यकता कम होती जाती है और फलस्वरूप वस्तु की सीमात उपयोगिता भी घटती जाती है। वस्तु की मात्रा न बढ़ि होने में उसकी सीमात उपयोगिता में प्रमश घटने की प्रवृत्ति, केवल रोटी के साथ ही नहीं, बल्कि सभी वस्तुओं के साथ लागू है। दूसरी वस्तु की उपयोगिता पहली वस्तु में प्राप्त होने वाली उपयोगिता में कम होगी, तीसरी की दूसरी में कम होगी। इसी तरह पहली कमीज की उपयोगिता बहुत अधिक होगी क्योंकि शरीर की रक्षा के लिए यह नितान्त आवश्यक है। पर दूसरी की उपयोगिता उतनी न होगी, अर्थात् कम होगी। तीसरी की और भी कम होगी और इस तरह कमीज की सीमात उपयोगिता घटती चली जायगी। अस्तु, प्रत्येक वस्तु के साथ यह अनुभव होता है कि परिमाण में वृद्धि होने के साथ-साथ सीमात उपयोगिता प्रमश कम होती चली जाती है। यदि यह बात न होती, तो जब हम किसी एक वस्तु को खरीदना शुरू करते तो उसे ही खरीदते रहते और किसी वस्तु को नहीं। किन्तु जीवन में ऐसा नहीं होता। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो एक सीमा के बाद उसकी खरीद बन्द कर देते हैं और फिर दूसरी वस्तुओं को खरीदने लग जाते हैं। यह इसलिए होता है कि किसी के पास किसी वस्तु का जितना ही अधिक परिमाण होता जाता है, उतनी ही कम उसकी सीमात उपयोगिता होती जाती है।

यही सीमात-उपयोगिता-हारा नियम है। इसकी परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है—अन्य सब बातों के पूर्ववत् रहने पर, किसी एक समय किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु का जो सचय है, उस सचय में प्रत्येक बढ़ती के साथ उस मनुष्य के लिए उस वस्तु की सीमात उपयोगिता घटती जाती है। इसी बात को यदि हम कीमत के रूप में प्रकट करें तो कहेंगे जितनी अधिक मात्रा किसी वस्तु की एक व्यक्ति के पास होती जायगी, उतनी ही कम कीमत वह उस वस्तु की आगे मिलने वाली इकाइयों के लिए देने को तैयार होगा।

इस नियम को उदाहरण द्वारा और स्पष्ट किया जा सकता है। मान लो एक व्यक्ति को किसी समय चाय पीने की बड़ी तेज आवश्यकता है। ऐसी दशा में चाय के पहले प्याले से जो उपयोगिता उसे प्राप्त होगी, वह बहुत अधिक होगी। कारण, चाय पीने की उसकी आवश्यकता बहुत प्रबल है। और यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि जितनी अधिक या कम आवश्यकता की तीव्रता अथवा तेजी होगी उतनी ही अधिक या कम वस्तु की उपयोगिता होगी। एक प्याला पीने के बाद उसकी आवश्यकता की तेजी कुछ कम हो जायगी। इसके फलस्वरूप दूसरे प्याले में उसे उतना सतोष न मिलेगा, जितना कि पहले प्याले से प्राप्त हुआ था। अर्थात् दूसरे प्याले से जो उपयोगिता प्राप्त होगी, वह पहले प्याले से प्राप्त उपयोगिता के बराबर न होगी अपितु कम होगी। दो प्यालों के बाद उसकी आवश्यकता और घट जायगी। अतएव तीसरे प्याले से प्राप्त होने वाली उपयोगिता दूसरे प्याले की उपयोगिता से कम होगी। इसी तरह जैसे-जैसे उसे और चाय मिलती जायगी, वैसे ही वैसे चाय की सीमांत उपयोगिता घटती जायगी। मान लो, पांच प्यालों से उसकी आवश्यकता पूर्ण रूप से तृप्त हो जाती है। ऐसी अवस्था में सीमांत उपयोगिता शून्य होगी। यदि इसके बाद वह और अधिक चाय लेगा तो उपयोगिता के स्थान पर उसे अनुपयोगिता प्राप्त होगी। यह उदाहरण निम्नलिखित कोष्टक से और भी स्पष्ट हो जायगा।

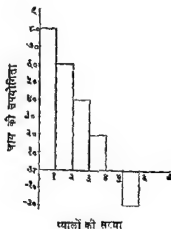
प्यालों की संख्या	समस्त उपयोगिता (इकाइयों में)	सीमान्त उपयोगिता (इकाइयों में)
एक	८०	८०
दो	१४०	६०
तीन	१८०	४०
चार	२००	२०
पांच	२००	०
छ.	१८०	२०



ऊपर के कोष्टक को देखने में विदित होगा कि चाय की सीमात उपयोगिता क्रमशः कम होती जाती है। पहले प्याले की उपयोगिता ८० के बराबर है, दूसरे प्याले की ६०, तीसरे की ४० और चौथे की २०। पाचवें प्याले से प्राप्त होने वाली उपयोगिता शून्य के बराबर दिखाई गई है, क्योंकि महा पर आवश्यकता की पूर्ण तृप्ति हो चुकी है। पूर्ण तृप्ति के समय सीमात उपयोगिता शून्य होती है। इसके बाद जो भी इकाई खान की जाएगी, उससे सन्तोष के बजाय हानि होगी। उपयोगिता के स्थान में अनुपयोगिता प्राप्त होगी। छठा प्याला पूर्ण तृप्ति के बाद लिया गया है। इसलिए इसे ऋण-उपयोगिता द्वारा दिखाया गया है।

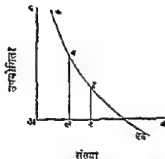
इस कोष्टक में यह भी स्पष्ट है कि वस्तु के परिमाण में वृद्धि होने से सीमान्त उपयोगिता गिरती है, समस्त उपयोगिता नहीं। जैसे-जैसे बाद में सी खाने इनाइया की गम्या बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे सीमात उपयोगिता घटती जाती है और समस्त उपयोगिता एक सीमा तक बढ़ती जाती है। हा, यह बात अवश्य है कि समस्त उपयोगिता के बढ़ने का अनुपात क्रमशः कम होता जाता है। समस्त उपयोगिता में क्रमशः घटती हुई दर में वृद्धि होती है। प्राप्त होने वाली समस्त या कुल उपयोगिता तब तक बढ़ती जाती है जब तक कि वह आवश्यकता पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हो जाती, अर्थात् अब तक कि सीमात उपयोगिता शून्य नहीं हो जाती। सीमात उपयोगिता के शून्य होने पर समस्त उपयोगिता अपनी अधिकतम सीमा पर पहुँच जाती है। इस स्थान में उसका बढ़ना बन्द हो जाता है। और यदि किसी वस्तु का खान पूर्ण तृप्ति के बाद भी जारी रहता है, तो अनुपयोगिता प्राप्त होने के कारण समस्त उपयोगिता बढ़ने के बजाय क्रमशः घटने लगती है। ऊपर के उदाहरण में समस्त उपयोगिता चौथे प्याले तक बढ़ती जाती है। पाचवें प्याले की उपयोगिता शून्य है, इसलिए समस्त उपयोगिता उसी ही है, बढ़ती नहीं। छठे प्याले में अनुपयोगिता प्राप्त होती है। इस कारण समस्त उपयोगिता से से २० इकाई उपयोगिता कम हो जाती

है। पाच प्याले में कुल मिलाकर २०० इकाई समस्त उपयोगिता हुई, लेकिन एक और प्याले के लेने से यह १८० इकाई ही रह जाती है, क्योंकि छठे प्याले से २० इकाई उपयोगिता की घटती होती है। इस कोष्टक को चित्र के रूप में दिखाया जा सकता है। इसमें उपयोगिता-हानि नियम और स्पष्ट हो जाएगा।



इस चित्र में लम्ब की ऊँचाई प्यालों की उपयोगिता बताती है। प्रत्येक लम्ब की ऊँचाई घटती-कम होती जाती है, जिससे धन्य की सीमांत उपयोगिता के समान कम होने पर बांध जाता है। छठे प्याले की उपयोगिता बतलाने वाला लम्ब ऋण की ओर चला गया है, क्योंकि इस प्याले में अव्यवस्था प्राप्त होती है।

इस चित्र की एक रेखा द्वारा भी दिखाया जा सकता है।



इस बिन्दु में 'क' से 'रेखा' पटती सीमात उपयोगिता की रेखा है। यह रेखा इस बात को प्रदर्शित करती है कि जैसे-जैसे वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है, सीमान्त उपयोगिता प्रत्यक्ष कम होती जाती है। जैसे 'अ' से 'स' स्थिति की सीमान्त उपयोगिता 'ब' से के बराबर है, और 'अ' से 'र' की सीमात उपयोगिता केवल 'द' है, जो 'ब' से कम है।

अन्य सब बातें पूर्ववत् रहे

(Other things being the same)

उपयोगिता-ह्रास नियम की परिभाषा करते समय यह मान लिया जाता है कि 'अन्य सब बातें पूर्ववत् रहे'। ये शब्द बड़े महत्व के हैं। उपयोगिता-ह्रास नियम लागू होने के लिए अन्य सब बातों का, परिस्थितियों का पूर्ववत् रहना नितांत आवश्यक है। यदि अन्य सब बातें पहले जैसी नहीं रहती अर्थात् उनमें कुछ परिवर्तन होता है, तो यह नियम लागू न होगा। अस्तु, इस नियम के सम्बन्ध में इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। जब यह कहा जाता है कि 'अन्य सब बातें पूर्ववत् रहे' तो इसका आशय साधारणतः निम्नलिखित बातों से होता है —

(१) उपयोगिता-ह्रास नियम के लागू होने के लिये यह आवश्यक है कि वस्तु की भिन्न-भिन्न इकाइयों का उपयोग एक खास समय में लगातार

हो। यदि उपभोग का समय लगातार नहीं है, तो नियम लागू न हो सकेगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति एक प्याला चाय सुबह ले, दूसरा दोपहर को और तीसरा प्याला रात को, तो यह जरूरी नहीं कि दूसरे प्याले से प्राप्त होने वाला उपयोगिता पहले में और तीसरे प्याले की उपयोगिता दूसरे से प्रमश कम हो। कारण, चाय का उपभोग एक खास समय में लगातार नहीं हुआ। भिन्न-भिन्न प्यालों के उपभोग के बीच में काफी समय का अंतर है। इसलिए नियम लागू न होगा।

(२) इस नियम के लिये यह भी आवश्यक है कि उपभोगिता को आय, रुचि, स्वभाव और परिस्थिति आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। इनमें परिवर्तन होने से किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता में अंतर पड़ जायेगा, और फलस्वरूप नियम लागू न हो सकेगा। जैसे यदि कोई मनुष्य एकाएक अधिक श्रमवान हो जाय, तो उसकी सारी परिस्थितियां बदल जायेंगी। वही वस्तुएं उसे भिन्न लगने लगेंगी। एक प्रकार से वह स्वयं बदल जायेगा। वह पहले जैसा न रहेगा। इस कारण सम्भव है कि किसी एक वस्तु की बाढ़ में आने वाली इकाइयों की उपयोगिता प्रमश न पड़े। इसी प्रकार यदि रुचि में फर्क आ जाय तो सम्भव है कि उपयोगिता-ह्रास नियम लागू न हो। रुचि के बदल जाने से किसी वस्तु की भिन्न-भिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता में फर्क आ जायेगा। यदि वही वस्तु रुचि के बदल जाने से अधिक अच्छी लगने लगी है, तो आगे आने वाली इकाइयों की उपयोगिता प्रमश घटने की बजाय बढ़ेगी। अस्तु, आय, रुचि, स्वभाव, परिस्थिति आदि का पूर्ववत् रहना बहुत जरूरी है अन्यथा नियम लागू न हो सकेगा।

(३) साम ही वस्तु की भिन्न-भिन्न इकाइयों का गुण और परिमाण एक समान होना चाहिए। यदि इकाइयों का गुण एक-सा नहीं है, तो नियम लागू न होगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी एक मनुष्य को पहले एक सट्टा आम दिया जाय और फिर मोठा, तो दूसरे आम की उपयोगिता घटने के बदले

वदेगी, क्योंकि दोनों आम के गुण एक समान नहीं हैं। इसी प्रकार, द्रव्यादयो का परिमाण बराबर न होने पर नियम लागू न हो सकेगा।

किसी वस्तु की भिन्न-भिन्न द्रव्यादयो के सम्बन्ध में एक और बात स्पष्ट कर देना जरूरी है। वह यह है कि द्रव्यादयो का परिमाण या मात्रा उचित होनी चाहिए। यदि द्रव्यादयो की मात्रा बहुत छोटी या कम है, तो सम्भव है कि बाव न ली जान वाली प्रत्येक द्रव्याद से कुछ समय तक क्रमशः कम उपयोगिता प्राप्त होने के बजाय बढ़ती हुई उपयोगिता प्राप्त हो।

(४) वस्तु की कीमत का पूर्ववत्, अपरिवर्तित रहना भी बहुत आवश्यक है। यदि वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तो उपभोक्ता की उस वस्तु के पाने की इच्छा तेज हो जायगी। और चूंकि उपयोगिता इच्छा की तेजी पर निर्भर है, इसलिए उपयोगिता भी बढ़ जायगी। किसी वस्तु की उपयोगिता इस कारण भी बढ़ सकती है कि उसके स्थान पर प्रयुक्त हो सकने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ जायें। इसलिए उपयोगिता-हास-निमय के सम्बन्ध में यह मान लेना जरूरी है कि किसी एक वस्तु की और उसके स्थान पर प्रयुक्त हो सकने वाली अन्य वस्तुओं की कीमतों पहले जैसी ही रहें, उनमें कोई परिवर्तन न हो।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करने में पता चलता है कि सीमांत उपयोगिता-हास नियम सार्वभौमिक है। परिस्थिति के पूर्ववत् रहने पर, यह नियम लगभग सभी स्थानों पर लागू होता है। चाहे कोई वस्तु कितनी ही सुन्दर क्यों न हो उसे देखते-देखते कुछ देर के बाद आस थक जाती है, मन ऊब जाता है। इसी प्रकार मुरीले में मुरीले गाने को बार-बार सुनने से कान पक जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ समय बाद वह गाना बुरा लगने लगता है। अर्थात् इस प्रकार की वस्तुओं की भी सीमांत उपयोगिता क्रमशः कम होती जाती है।

## इस नियम के अपवाद (Exceptions to the Law)

कुछ लोग इस नियम के कई अपवाद (exceptions) बतलते हैं, जहाँ, उनके कल्पनानुसार, सीमांत उपयोगिता ह्रास-नियम लागू नहीं होता। किन्तु ध्यानपूर्वक विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि इन नियम के जितने भी अपवाद पेश किये जाते हैं वे लगभग सभी बौधे हैं; उनमें तथ्य नहीं है। वे केवल नाममात्र के ही अपवाद हैं, वास्तविक नहीं। इनमें से कुछ अपवादों का उल्लेख नीचे किया जाता है।

(१) यदि किसी वस्तु का बहुत सूक्ष्म परिमाण में उपयोग किया जाय तो कुछ समय तक उसकी सीमांत उपयोगिता में क्रमशः कमी होने के बड़े कृत्रिम होमो। उदाहरण के लिए यदि एक प्याले आधमी को एक-एक बूंद पानी दिया जाय, अथवा रेलवे इंजिन को छटाब-छटाब बोझला धार-धार दिया जाय तो पानी और कोयले की सीमांत उपयोगिता कुछ समय तक बढ़ती ही जायगी, घटेगी नहीं। इसी प्रकार यदि एक मनुष्य के पास एक पैर का जूता है, तो दूसरे पैर के जूते से प्राप्त होने वाली उपयोगिता पहले से अधिक होगी क्योंकि बिना दूसरे पैर के जूते के एक पैर का जूता बेकार है। ऊपरी तौर से देखने में ऐसा मालूम पड़ता है कि इन स्थानों पर उपयोगिता-ह्रास-नियम ठीक नहीं उतरता। किन्तु हम इन्हें वास्तविक अपवाद नहीं मान सकते। क्या हम साधारण जीवन में एक-एक पैर के जूते विकते देखते हैं या कोयला और पानी कहीं इतने सूक्ष्म परिमाण में दिये जाते हैं? एक बूंद पानी या एक पैर का जूता सम्पूर्ण इकाई नहीं है। वे इकाई के केवल छोटे-छोटे भाग हैं। इसलिए सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। 'अल्प बातों' में यह मान लिया जाता है कि वस्तु की इकाईया आकार और परिमाण में व्याप्योचित हो।

(२) कभी-कभी यह कहा जाता है कि शराबों के लिए शराब की सीमांत उपयोगिता बराबर बढ़ती जाती है। जैसे-जैसे वह शराब पीता जाता है, उसकी शराब पीने की इच्छा तेज होती जाती है और चूँकि उप-

योगिता इच्छा की तेजी पर निर्भर है, इसलिए उपयोगिता भी बढ़ती जाती है। जब तक शराबी बिल्कुल घूर होकर गिर नहीं पड़ता, उमका हाथ और शराव पीने के लिए फैला रहता है। अस्तु, यह कहा जाता है कि शराबी के सम्बन्ध में उपयोगिता-हानि-नियम ठीक सिद्ध नहीं होता। किन्तु इसे भी अव-बाध नहीं माना जा सकता। कारण, शराव के प्रभाव के कारण शराबी की परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। वह अपने होश-हवास में नहीं रहता। अस्तु, अन्य बातों में परिवर्तन हो जाने के कारण नियम लागू नहीं हो पाता। फिर किस प्रकार इसकी सचाई में आघ आ सकती है।

इसी प्रकार कुछ का कहना है कि यदि किसी सुन्दर कविता या पुस्तक को बार-बार पढ़ा जाय तो सीमात-उपयोगिता कम न होगी, बल्कि बढ़ेगी। ऐसा इसलिए होता है कि उस कविता या पुस्तक को दूसरी बार पढ़ने से उमका अर्थ पहले से अधिक स्पष्ट हो जाता है। तीसरी बार पढ़ने से अर्थ और अधिक समझ में आने लगता है। इस कारण उपयोगिता में वृद्धि होती है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि उपयोगिता-हानि-नियम ठीक नहीं है। एक बात तो यह है कि उपभोक्ता के स्वभाव और रुचि में फर्क आ जाता है। इसलिए वही कविता या पुस्तक उसके लिए एक नया रूप धारण कर लेती है, और फलस्वरूप उपयोगिता नहीं गिरती। दूसरे, यहाँ पर भी एक सीमा के बाद उपयोगिता-हानि-नियम अवश्य लागू होने लगेगा। किसी एक कविता को एक सीमा के बाद बार-बार पढ़ने-सुनने से मन ऊँच जायेगा, कान धक जायेंगे। उसके पढ़ने या सुनने का आनन्द क्रमशः कम होता जायगा, अर्थात् उसकी सीमात उपयोगिता एक सीमा के बाद क्रमशः कम होती जायगी। यही बात संगीत और अन्य कलाओं के साथ भी कही जा सकती है।

(३) हम प्रायः यह सुनते हैं कि कजूरों की धन जोड़ने की इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती। जितना अधिक धन उसे मिलता है, उतनी ही उसकी धन जोड़ने की इच्छा और प्रबल होती जाती है। इसलिए धन की सीमात

उपयोगिता कजूस के लिए कमजोर बढ़ती जाती है। पर वास्तव में इसे भी अपवाद नहीं माना जा सकता। कारण, यहां 'अन्य बातें पूर्ववत् नहीं रहती। धन-मचय की क्रिया एक साथ समय में लगातार नहीं होती और व रचि, स्वभाव, परिस्थिति आदि ही पूर्ववत् रहती हैं। जैसे-जैसे कजूस धनसंचय करता जाता है, जैसे-जैसे परिस्थितियां बदलती जाती हैं। धीरे-धीरे उसका स्वभाव बदलता जाता है। वह धनसंचय करने की कला में प्रवीण होता जाता है। अस्तु, वह पहले जैसा कजूस नहीं रहता वह स्वयं बदलता जाता है।

जो कुछ कजूस की धन-मचय करने की इच्छा के लिए कहा गया है, वही लोगों की शक्ति पाने अथवा सामाजिक प्रभुता प्रदर्शन करने की इच्छा के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है।

(४) टेलीफोन के सम्बन्ध में कहा जाता है कि जैसे-जैसे अधिक संख्या में लोग टेलीफोन लग, जैसे-जैसे टेलीफोन की उपयोगिता कमजोर बढ़ती जायगी क्योंकि ऐसा होना पर एक व्यक्ति अधिकतम एक टेलीफोन द्वारा बातचीत कर सकता है। इसमें यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहां पर उपयोगिता-ह्रास नियम ठीक सिद्ध नहीं होता। किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। उपयोगिता नियम तभी लागू होता है जब कि किसी एक वस्तु की भिन्न-भिन्न इकाइयों का उपयोग एक ही व्यक्ति करता है। यदि वस्तु की भिन्न-भिन्न इकाइयों का उपयोग भिन्न-भिन्न लोग करते हैं तो इस नियम का लागू होना जरूरी नहीं है। ऐसी दशा में सीमान्त उपयोगिता का प्रभाव कम होना आवश्यक नहीं है। पर यदि कोई व्यक्ति अधिक संख्या में टेलीफोन लेगा, तो निश्चय ही सीमान्त उपयोगिता गिरेगी। उस व्यक्ति के लिए दूसरे टेलीफोन की उपयोगिता पहले से कम होगी और तीसरे की दूसरे से कम होगी। और इस प्रकार जैसे-जैसे वह और टेलीफोन लेगा, टेलीफोन की सीमान्त उपयोगिता प्रभाव कम होती चली जायगी।



(५) प्रायः यह कहा जाता है कि मुद्रा तथा रुपये-पैसे के सम्बन्ध में यह नियम लागू नहीं होता क्योंकि मुद्रा की इच्छा कभी भी तृप्त नहीं होती। वह बराबर बढ़ती ही जाती है। अन्य वस्तुओं के साथ तो यह कहना ठीक है कि एक सीमा के बाद यदि किसी व्यक्ति को और अधिक परिमाण में एक वस्तु दी जाय, तो वह मना कर देगा, किन्तु मुद्रा के सम्बन्ध में ऐसा कहना ठीक न होगा। क्या यह सम्भव है कि कोई मनुष्य कभी यह कहेगा कि “बरा, अब मुझे और अधिक मुद्रा व द्रव्य पाने की इच्छा नहीं है, मेरी यह इच्छा पूर्णतः तृप्त हो चुकी है।” साधारणतः किसी को इस प्रकार कहने हुए सुना नहीं जाता। इनका एक मुख्य कारण है। मुद्रा कोई एक वस्तु नहीं है। यह तो भिन्न-भिन्न वस्तुओं का एक सम्मिलित रूप है। यह एक वय-शक्ति है जिससे प्रायः सभी वस्तुएँ प्राप्त की जा सकती हैं। चूँकि मनुष्य की कुल आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं है, इसलिए मुद्रा की इच्छा भी साधारणतः सीमित नहीं होती। इससे आवश्यकता-पूर्ति की अनेकानेक वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। अतः मुद्रा को बजाय एक वस्तु मानने के वस्तुओं का समुच्चय या सम्मिलित रूप मानना अधिक न्यायोचित होगा।

फिर भी यह मानना पड़ेगा कि सीमान्त उपयोगिता-हानि-नियम मुद्रा के सम्बन्ध में भी लागू होता है। जैसे-जैसे किसी के पास मुद्रा का परिमाण बढ़ता जाता है, वैसे-ही-वैसे उसके लिए मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता कम होती जाती है। यही कारण है कि एक गरीब मनुष्य के लिए मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता एक धनी मनुष्य से अधिक होती है। उदाहरण के लिए एक आना अमीर आदमी के लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता। उसकी जेब से यदि कहीं वह गिर जाय, तो शायद ही वह उसके लिए चिन्ता करेगा। पर वही एक आना एक गरीब व्यक्ति के लिए बड़ी रकम है। यदि उसकी जेब से कहीं वह इकट्ठी गिर जाय तो वह अनित रातकी कई घण्टों तक तलाश करेगा और न मिलने पर अपने

भाष्य को कोमेगा। इसमें यह साफ जाहिर है कि रुपये की सीमान्त उपयोगिता गरीब आदमी के लिए अधिक होती है और धनी के लिए कम। गरीब आदमी के पास रुपये की कमी होती है। इस कारण रुपये की सीमान्त उपयोगिता उसके लिए अधिक होती है। एक धनवान के पास मुद्रा अधिक परिमाण में होने के कारण मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता उसके लिए कम होती है।

एक दूसरा उदाहरण लेंगे। महीन के शुरू में जब किसी विद्यार्थी को घर में रुपये मिलते हैं तो वह कुछ दिना दल खोज कर खप करता है। वह सिनगा देखता है अगले हॉटल जाता है और अच्छे टग से अपने शक्वियों की दोस्ती गिवाहता है। पर जब महीन के अंत में जब छात्रों होन लगती है तो वह सावधानी से खच करने लग जाता है। हर तरह की किस्तुखर्चों बंद बन्द कर देता है। उस समय एक रुपया उसे दो रुपये के बराबर मालूम होन लगता है। अतः रुपये की सीमान्त उपयोगिता महान के अंत में बहुत बढ़ जाती है। यह रुपये की कमी के कारण होता है। महीने के शुरू में जब रुपये का अधिकता होती है तब रुपये की सीमान्त उपयोगिता इतनी नहीं होती। जैसे-जैसे पास में रुपया कम होता जाता है वैसे-वैसे रुपये की सीमान्त उपयोगिता बढ़ती जाती है। अस्तु घटती उपयोगिता का नियम मुद्रा के सम्बन्ध में भी लागू होता है।

उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि सीमान्त उपयोगिता हास-नियम व्यापक सभी स्थानों पर लागू होता है। अर्थशास्त्र का यह सच से मौलिक और महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। इसी पर मान का नियम उपयोगिता की वृद्धि का सिद्धान्त सम-सीमान्त उपयोगिता नियम आधुनिक कर सिद्धान्त आदि अनेक आर्थिक नियम अवलम्बित हैं। व्यावहारिक जीवन में भी इस सिद्धान्त का विनियम महत्व है।

### QUESTIONS

- 1 What is utility? Can it be measured? If so, how?

- 2 What is marginal utility ? Examine the relation between marginal and total utility
- 3 Define and fully illustrate the Law of Diminishing Marginal Utility
- 4 Explain the Law of Diminishing Utility What is the implication of 'other things being equal' ?
- 5 Is the Law of Diminishing Utility universal ? Examine some of the alleged exceptions to this law
- 6 What is marginal utility ? Do you think that the marginal utility of money also decreases as its stock increases ?

## अध्याय ११

### मांग

#### (Demand)

अर्थशास्त्र में 'मांग' (demand) शब्द का आशय मनुष्य की उस इच्छा से है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त साधन हैं और वह उस साधन को उस इच्छा की तृप्ति के लिए खर्च करने को तैयार भी है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को चाह करता है, पर उसमें उस वस्तु को खरीदने की शक्ति नहीं है या वह उस शक्ति को काम में लाने के लिए तैयार नहीं है, तो उसकी वह चाह इच्छा ही कही जायगी, मांग नहीं। अस्तु किसी वस्तु की मांग से तीन बातों का बोध होता है। एक तो यह कि उस वस्तु की इच्छा है, दूसरे उसके खरीदने के लिए पर्याप्त साधन हैं और तीसरे यह कि उस वस्तु को उसका मूल्य देकर खरीदने की मानसिक प्रेरणा भी है। मनुष्य की उन्ही इच्छाओं को हम मांग में सम्मिलित करेंगे जिनमें ये तीनों बातें मौजूद हों। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक मेज, जिसका मूल्य दस रुपये है, खरीदने की इच्छा है। यदि उसके पास दस रुपये हैं, और वह उन रुपयों को अपनी इच्छा-पूर्ति के लिए देने को तैयार है, तो उसकी वह इच्छा मांग कही जायगी।

मांग के साथ एक खास कीमत और समय का होना बहुत जरूरी है। मांग सदा एक निश्चित कीमत पर होती है। बिना किसी खास कीमत के मांग का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे केवल यदि इतना कहा जाय कि १०० साइकिलों की मांग है, तो इसका कोई अर्थ न होगा, क्योंकि साइकिल की मांग हर कीमत पर एक समान न रहेगी। भिन्न-भिन्न कीमतों पर साइकिल

की भिन्न-भिन्न मत्प्राप्ति मोल ली जाएगी, अर्थात् सादकिल की माग भिन्न-भिन्न होगी। इसलिए प्रत्येक माग के साथ हमेशा एक खास कीमत जुड़ी रहती है। माग के सम्बन्ध में दूसरी जरूरी बात है समय। कोई भी माग एक खास समय में ही कारगर मानी जायगी जैसे प्रतिदिन, सप्ताह, माह या वर्ष। हम यह कह सकते हैं कि अमुक वस्तु की माग प्रति सप्ताह या माह १०० है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम माग की परिभाषा इस ढंग से कर सकते हैं—माग किसी वस्तु की उस मात्रा को कहते हैं जो एक निश्चित कीमत और समय में मरीदी जाती है।

### मांग-सूची

(Demand Schedule)

किसी वस्तु की माग को पूरी जानकारी के लिए यह मालूम करना आवश्यक है कि भिन्न भिन्न कीमतों पर उस वस्तु की कितनी-कितनी माग होगी। जब तक हमें इस बात का पूरा पता न हो, तब तक हम उस वस्तु की माग का ठीक-ठीक अनुमान नहीं कर सकते। यदि एक कोष्टक तैयार किया जाय जिसमें एक ओर किसी वस्तु की कीमतें दी गयी हों और दूसरी ओर उन कीमतों के सामने उस वस्तु की माग दिखाई गई हो, तो उस कोष्टक को उस वस्तु की माग की सारिणी अथवा मांग-सूची (Demand Schedule) कहेंगे। अर्थात् माग की सारिणी वह सूची या फेहरिस्त है जिसमें यह गान्धूय होता है कि किसी वस्तु की भिन्न-भिन्न मात्राएँ एक व्यक्ति या कई लोग किन दामों में खरीदेंगे।

मांग-सूची से यह ज्ञात होता है कि किसी समय में एक वस्तु की माग भिन्न-भिन्न कीमतों पर कितनी-कितनी होगी। यह बात उदाहरण द्वारा और स्पष्ट की जा सकती है। नीचे एक मनुष्य की आम की मांग-सूची का एक नमूना दिया जाता है।

कीमत की आम	माग की मात्रा
८ पैसे	२
७ "	४
६ "	६
५ "	८
४ "	१०
३ "	१४

ऊपर दी हुई सूची एक व्यक्ति की माग-सूची (Individual Demand Schedule) है। इसमें उसकी माग की पूरी जानकारी हो सकती है। इसके देखने से हमें पता चलता है कि जैसे-जैसे कीमत घटती है, जैसे-जैसे माग बढ़ती है और जैसे-जैसे कीमत बढ़ती है, वैसे ही वैसे माग घटती है। जब कीमत ८ पैसे की आम है, तो माग की मात्रा केवल २ है। जब कीमत ५ पैसे है तो माग की मात्रा बढ़कर ८ आम हो जाती है, और ३ पैसे की आम होने पर माग की मात्रा १४ हो जाती है। अस्तु, माग-सूची से यह पता चलता है कि भिन्न-भिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की कितनी-कितनी मात्राएँ खरीदी जाएंगी।

बाजार की माग-सूची (Market Demand Schedule) भी इसी प्रकार तैयार की जा सकती है। यदि हम बाजार के सभी व्यक्तियों की माग-सूचियों को मिलाकर एक में जोड़ दें, तो बाजार की माग-सूची

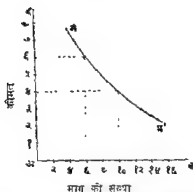
निकल आयेगी। किन्तु यह बाग बहुत कठिन है। सभी व्यक्तियों की एक सम्मिलित माग-सूची निश्चित करना निश्चिन्त बहुत कठिन है। कारण, सब व्यक्ति एक ही तरह के नहीं होते। उनकी आय, रचि, रवभाव, आदि में बहुत भिन्नता होती है। इसलिए उनको माग-सूचीया एक-सी नहीं होंगी और फिर सबकी पुष्क-पुष्क सूची तैयार करके एक में मिलाना और भी कठिन है। वास्तव में बाजार की माग-सूची विष्कूल ठीक-ठीक तैयार करना असम्भव-सा है। यहाँ पर तो केवल अन्दाजे के आधार पर ही काम किया जा सकता है। बाजार की माग-सूची बनाने के लिए हमें एक औसत दर्जे के साधारण व्यक्ति की माग-सूची को लेकर बाजार के कुल व्यक्तियों की संख्या से गुणा करना पड़ेगा। इसके गुणन द्वारा जो सूची निकलेगी, वही बाजार की माग-सूची होगी। इस सूची से बाजार की माग की पूरी जानकारी हो सकेगी। इस जानकारी का बहुत महत्व है, विशेष-कर सरकार और व्यापार की दृष्टि से।

माग-सूची के सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने योग्य है। किसी वस्तु की माग बहुत-सी बातों पर निर्भर होती है, जैसे उस वस्तु की कीमत, प्राप्ति की संख्या, उनकी रचि, आय, प्रतियोगी वस्तुओं की कीमतें, आदि। जब कोई माग-सूची तैयार की जाती है, तो यह मान लिया जाता है कि उस वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य बातों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अन्य बातों में परिवर्तन होने पर माग की एक नयी सूची तैयार करनी पड़ेगी। स्पष्ट शब्दों में, माग-सूची केवल यह बताती है कि अन्य चीजों के पूर्ववत् रहने पर, किसी वस्तु की माग की मात्रा भिन्न-भिन्न कीमतों पर कितनी होगी।

### माग-रेखा

(Demand Curve)

माग-सूची को रेखा-चित्र द्वारा भी प्रकट किया जा सकता है जिसे 'माग-रेखा' कहते हैं। ऊपर दी हुई एक व्यक्ति की माग-सूची को रेखा द्वारा इस प्रकार दिखाया जा सकता है —



इस चित्र में 'ग म' भाग की रेखा है। इसका झुकाव नीचे की ओर है, और साधारणतः माग-रेखा का झुकाव नीचे की ओर ही होता है। ऊपर दिए हुए रेखा-चित्र को देखने से मालूम होता है कि जब आम की कीमत ६ पैसों है, तो माग की मात्रा ४ है, और २ पैसों की आम की कीमत होने पर माग की मात्रा बढ़कर २४ हो जाती है। इसमें भी यही प्रकट होता है कि कीमत के घटने से माग बढ़ती है, और कीमत के बढ़ने से माग घटती है। यही भाग का नियम है जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन नीचे किया जाता है।

### माग का नियम

(Law of Demand)

माग का नियम कीमत और माग के बीच का परस्पर सम्बन्ध बतलाता है। साधारणतया माग कीमत के विपरीत घटती-बढ़ती है। कीमत के घटने पर माग बढ़ती है, और कीमत के बढ़ने पर माग घटती है। यही माग का नियम है। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है : अन्य बातें पूर्ववत् रहने पर, कीमत के घटने से माग में वृद्धि होने की प्रवृत्ति



होती है, और कीमत के बढ़ने पर माग में घटने की प्रवृत्ति होगी है। अर्थात् अन्य चीजों के मर्यादास्थिति रहने पर, किसी वस्तु की माग का घटना-बढ़ना कीमत के घटने-बढ़ने पर निर्भर रहता है। कीमत के कम होने से माग बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने से माग घट जाती है। पर यहाँ ध्यान रहे कि माग का नियम कीमत और माग के घटने-बढ़ने में कोई अनुपातिक सम्बन्ध निर्धारित नहीं करता। यह जरूरी नहीं है कि जिस अनुपात से कीमत घटे-बढ़े, माग भी उसी या किसी निश्चित अनुपात से बढ़े-घटे। माग का नियम केवल इतना ही बतलाना है कि अन्य बातों के वैसे ही रहने पर, माग कीमत के विपरीत घटती-बढ़ती है।

प्रश्न यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों माग की रेखा का मुकाबला नीचे की ओर होता है? अर्थात् क्यों कीमत के घटने से माग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने से माग घटती है? इसका उत्तर यह है कि माग का यह नियम सीमांत उपयोगिता-ह्रास नियम से निकला है। सीमांत उपयोगिता-ह्रास नियम में यह पता चलता है कि किसी वस्तु के परिमाण में वृद्धि होने में उसकी सीमांत उपयोगिता क्रमशः गिरती जाती है। अब बाद में ली जाने वाली इकाइयों के लिए मनुष्य कम ही कम कीमत देने को तैयार होगा क्योंकि उनमें उसे क्रमशः घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होगी। वस्तु, कीमत कम होने पर मनुष्य किसी वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदने को तैयार हो जायगा क्योंकि एनी दत्ता में बाद वाली इकाइयों के खरीदने में उसे हानि न होगी। इसी प्रकार यदि कीमत बढ़ जाय तो वह उन इकाइयों को न खरीदना निजकी उपयोगिता कीमत से कम होगी। फलस्वरूप माग घट जायगी।

इसी बात को एक दूसरे तरीके से और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। मान लो किसी वस्तु की कीमत घट जाती है। इसका एक परिणाम तो यह होगा कि मनुष्य की खय-शक्ति (purchasing power) बढ़ जायगी। इससे कारण यह उस वस्तु को और खरीदने

के लिए तैयार हो सकेगा, अर्थात् माग में वृद्धि होगी। दूसरा परिणाम यह होगा कि वह वस्तु अन्य प्रतिযোগी वस्तुओं की अपेक्षा सस्ती हो जायेगी। इसलिए लोग उसे अधिक खरीदने लगेगे और फलस्वरूप माग बढ़ जायेगी। इसी प्रकार मान लो कि वस्तु की कीमत घट जायगी है। इसका परिणाम यह होगा कि एक तरफ तो खेपों की वृद्धि-प्रवृत्ति और उनकी वास्तविक आय घट जायेगी, और दूसरी ओर वह वस्तु अन्य प्रतियोगी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक महूगी हो जायेगी। इन दोनों के प्रभाव में उस वस्तु की माग घट जायेगी।

अन्य आर्थिक नियमों की तरह यहाँ पर भी यही कर्न लगी हुई है कि "अन्य बातें पूर्ववत् रह"। हम ऊपर कह चुके हैं कि माग की मात्रा भाव के घटने पर बढ़ती है, और भाव के बढ़ने पर घटती है। पर सम्भव है कि अन्य बातों में परिवर्तन होने में ऐसा न हो। उदाहरणार्थ यदि किसी वस्तु का फैशन हट गया है, तो उसकी कीमत में काफी कमी होने पर भी वस्तु की माग न बढ़ेगी, अपितु घटती ही जायेगी। इसी तरह मान लो किसी वस्तु की कीमत उतनी ही रहती है, परन्तु उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में सम्भव है वह उस वस्तु को पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में मोल लेगा। जलमय्या, रीति-रिवाज, वस्तु के गुण आदि में परिवर्तन होने में, सम्भव है, माग में उलटा परिवर्तन हो। इसलिए माग का नियम तभी सिद्ध हो सकेगा जबकि अन्य बातें पूर्ववत् या यथास्थिति रहे।

### माग में परिवर्तन

(Changes in Demand)

माग में परिवर्तन दो कारणों में हो सकता है एक तो कीमत में परिवर्तन होने के कारण और दूसरे फैशन, जनसंख्या, धन-वितरण, लोगों की आध, आदत, परिस्थिति आदि अन्य बातों के बदलने के कारण। कीमत का प्रभाव माग पर बहुत पड़ता है, पर माग में केवल कीमत के द्वारा ही परिवर्तन नहीं होता, बल्कि अन्य बातों का भी काफी प्रभाव पड़ता

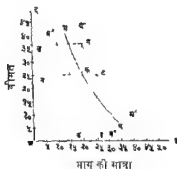
है। मनुष्य की आदत अथवा फैशन में उलट-फेर होने के कारण माग में बहुत परिवर्तन हो जाता है। कितनी ही वस्तु ऐसी है जिनकी माग, फैशन बदलने के कारण, बिलकुल ही गिर गई है। इसके विपरीत फैशन के प्रभाव से बहुत-सी वस्तुओं की माग में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। जनसंख्या के घटने और बढ़ने के कारण भी माग में बहुत परिवर्तन आ जाता है। यदि जनसंख्या किसी कारण बढ़ जाय, तो साधारणतः इसका परिणाम यह होगा कि वस्तुओं की माग में वृद्धि होगी। सम्भव है कुछ वस्तुओं की माग बीरो की अपेक्षा कम या अधिक बढ़े। इसी तरह यदि कुछ लोग पहले से धनी हो जाय और कुछ गरीब, तो कई वस्तुओं की माग पहले से अधिक हो जायगी, और कई वस्तुओं की कम।

इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि केवल कीमत के ही घटने-बढ़ने का प्रभाव माग पर नहीं पड़ता, बल्कि अन्य बातों से भी माग में परिवर्तन होता है। माग में इन दो तरह के परिवर्तनों में काफी अन्तर और भिन्नता है। इसलिए इन दो तरह के परिवर्तनों का अलग-अलग विवेचन करना आवश्यक है।

जब फैशन, रुचि, स्वभाव, स्थिति, आय, आदि अन्य बातों के बदल जाने के कारण माग में वृद्धि होती है, तो उसे माग की प्रबलता (Increase of Demand) कहते हैं। इसका यह अर्थ होता है कि उसी कीमत पर लोग किसी वस्तु को पहले की अपेक्षा अधिक परिमाण में खरीदते हैं या पहले से अधिक कीमत पर भी उतने ही परिमाण में उस वस्तु को खरीदते हैं। जब कीमत कम हो जाने से माग में वृद्धि होती है, तो उसे माग का प्रसार (Extension of Demand) कहते हैं। अस्तु, माग की प्रबलता और प्रसार का अन्तर स्पष्ट है। माग की प्रबलता अन्य बातों के कारण होती है और माग का प्रसार कीमत के कारण होता है। माग की प्रबलता वस्तु की कीमत के बढ़ने का एक कारण होती है, परन्तु माग का प्रसार कीमत के कम होने का फल है।

इसके विपरीत जब फैशन, अगस्त्या, आय, आदि में परिवर्तन होने के कारण किसी वस्तु की माग कम हो जाती है तो उसे माग की क्षियिलता (decrease of demand) कहते हैं। इसका आशय यह है कि लोग उस वस्तु को उन्नी कीमत पर पहले की अपेक्षा कम खरीदने को तैयार हैं, अथवा कम कीमत पर भी उतने ही परिमाण में वे उस वस्तु को खरीदते हैं। मूल्य के बढ़ने से जब माग गिर जाती है, तो उसे माग की घटी अथवा सिकोठ (contraction of demand) कहते हैं। माग की क्षियिलता से कीमत में कमी होने की सम्भावना रहती है, लेकिन माग की घटी कीमत के बढ़ने का परिणाम है।

माग में इन परिवर्तनों को एक रेखा-चित्र खींच कर दिखाया जा सकता है। इसी बात को समझने में और भी आसानी होगी।



‘अ ब’ पर माग की मात्रा दिखाई गई है और ‘अ द’ पर कीमत। मोटी म म रेखा माग की पहली रेखा है। यह इस आधार पर खींची गई है कि अन्य बातें पूर्ववत् हैं। इस रेखा पर चलते हुए माग का प्रसार और माग की घटी दिखाई जा सकती है। जैसे जब हम दूध रेखा पर

नीचे की ओर चलेगे, तो इसने माग का प्रसार (कीमत के घटने पर माग की वृद्धि) प्रकट होगी। और जब ऊपर की ओर चलेगे तो माग की घटी (कीमत के बढ़ने से माग का घटना) दिखाई देगी। यदि कीमत 'ज न' है तो माग की मात्रा 'अ ब' होगी। जब कीमत घटेगी तो माग की मात्रा बढ़ेगी, और कीमत के बढ़ने पर माग की मात्रा कम होगी।

मान लो अन्य बातों में परिवर्तन हो जाता है, तो उग दशा में 'ग म' रेखा ब्रेकार हो जायगी क्योंकि यह रेखा अन्य बातों के यथास्थिति रहने के आधार पर खींची गयी थी। जब अन्य बातें (रीति-रिवाज, फैशन, स्वभाव, रसि, आय, जनसंख्या, आदि) बदल जायेंगी, तो निश्चय ही हमें एक नई माग की रेखा खींचनी पड़ेगी। वह नई परिस्थितियों के आधार पर खींची जायगी। मान लो रीति-रिवाज, आमदनी, स्वभाव, आदि के बदल जाने के कारण लोग उसी वस्तु को पहली कीमत पर अधिक माना में खरीदने लग जाते हैं अथवा पहले से ऊंची कीमत पर उतनी ही मात्रा में खरीदते हैं, अर्थात् माग प्रबल हो गई है। तो इस बात को (अर्थात् माग की प्रबलता को) दिखाने के लिए हमें माग की एक दूसरी रेखा खींचनी पड़ेगी। यह रेखा पहली रेखा के ऊपर होगी। इस चित्र में 'म म' रेखा माग की प्रबलता को दिखाती है। इसके देखने से पता चलता है कि लोग पहली कीमत (ज न) पर अधिक मात्रा में ('अ र' मात्रा जो 'अ ब' से अधिक है) खरीदते हैं, अथवा उसी मात्रा के लिए ('अ ब') अधिक कीमत देते हैं ('अ ल' जो 'अ न' कीमत से अधिक है)। इसी को माग की प्रबलता कहते हैं।

इसी तरह जब हमें माग की शिथिलता दिखानी होगी तो पहली माग की रेखा की नीचे ओर, अर्थात् उसके नीचे रेखा खींचेंगे। जैसे इस चित्र में 'म म' रेखा माग की शिथिलता दिखाती है। इससे ज्ञात होता है कि वस्तु, अब परिस्थिति के बदल जाने के कारण, पहली कीमत पर कम परिमाण में खरीदी जाती है अथवा पहले से कम कीमत पर भी पहल

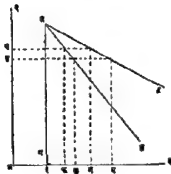
के बराबर ही मात्रा में खरीदी जाती है। मांग की क्षिप्रता का यही अर्थ होता है।

## मांग की लोच

(Elasticity of Demand)

मांग के नियम के सम्बन्ध में कहा जा चुका है कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन हो जाता है। साधारणतः किसी वस्तु की कीमत के बढ़ जाने से, उस वस्तु की मांग घट जाती है और कीमत के घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। मांग में इस प्रकार के परिवर्तन होने के गुण, यत्कि अथवा विशेषता को अर्थशास्त्र में 'मांग की लोच' (elasticity of demand) कहते हैं, अर्थात् कीमत के बदलने पर मांग जिस गति से बदलती है, उसे मांग की लोच कहते हैं। भिन्न-भिन्न वस्तुओं की मांग की लोच भिन्न-भिन्न होती है। कुछ वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है, और कुछ की कम। यदि कीमत में थोड़ा-सा परिवर्तन होने से किसी वस्तु की मांग में बहुत परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु की मांग बहुत लोचदार कही जायेगी। इसके विपरीत यदि कीमत में परिवर्तन होने से, किसी वस्तु की मांग में कम परिवर्तन होता है तो वह मांग कम लोचदार होगी, और यदि मांग में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता, तो उसे बेलोचदार मांग कहेंगे। उदाहरण के लिए मांस लो कि साइकिल की कीमत कुछ गिर जाती है। यदि इसके कारण साइकिल की मांग बहुत बढ़ जाती है, तो हम कहेंगे कि साइकिल की मांग बहुत लोचदार है। यदि साइकिल की मांग में थोड़ी-थोड़ी ही वृद्धि होती है, तो मांग कम लोचदार मानी जायेगी, और यदि मांग पर मूल्य के कम होने का लेशमात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस वस्तु में साइकिल की मांग बिल्कुल बेलोचदार कही जायेगी।

मांग की लोच को रेखा द्वारा आसानी से प्रदर्शित या समझा है।



इस चित्र में माग की तीन रेखाएँ दिखाई हुई हैं। मांग की 'म म' रेखा 'अ ब' पर सीधी पिरती है। कीमत के परिवर्तन का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। 'अ न' और 'अ स' कीमतों पर माग की मात्रा 'अ र' ही रहती है। इसलिए यह रेखा बेलोचदार माग प्रदर्शित करती है। 'म म' रेखा माग की दूसरी रेखा है। इस रेखा के अनुसार कीमत के 'अ न' से 'अ स' तक घटने पर माग की मात्रा 'अ क' से 'अ घ' तक बढ़ जाती है, अर्थात् कीमत में परिवर्तन होने से माग में परिवर्तन होता है। इसलिए माग की इस रेखा में लोच है। ठीक इसी कारण 'म र' रेखा द्वारा प्रदर्शित माग और भी लोचदार है। कीमत में परिवर्तन होने से इस माग में बहुत परिवर्तन होता है। वस्तु माग की जो रेखा जितनी ही 'अ ब' पर सीधी गिरेगी, उतनी ही कम लोचदार होगी और जो रेखा जितनी ही 'अ ब' से दूर हटती और उसके समानान्तर होती जायगी, उतनी ही अधिक वह लोचदार होगी। एक ही रेखा के भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर माग की लोच भिन्न-भिन्न हो सकती है।

## लोच का निर्धारित होना

(Factors Determining Elasticity)

भिन्न-भिन्न वस्तुओं की माग की लोच भिन्न-भिन्न होती है। यही नहीं, बल्कि एक ही वस्तु की माग की लोच अलग-अलग भेदी बाल व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न होती है। अब हम यहाँ पर यह विचार करेंगे कि कुछ वस्तुओं की माग, अन्य वस्तुओं की माग की अपेक्षा, कब अधिक या कम लोचदार होती है। माग की लोच कई बातों पर निर्भर करती है। इनमें से मुख्य-मुख्य पाँच नीचे दी जाती हैं —

(१) वस्तु की प्रकृति—साधारणतः आवश्यक वस्तुओं की माग बेलोचदार होती है और आराम तथा शोक की वस्तुओं की माग में अधिक लोच होती है। कारण यह है कि जो वस्तुएँ जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, उनकी माग में हम कोई विशेष परिवर्तन नहीं कर सकते। चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो, हमें ऐसी वस्तुओं को एक परिमाण में खरीदना ही पड़ता है। दूसरे शब्दों में, कीमत के घटने-बढ़ने पर आवश्यक वस्तुओं की माग को मात्रा बढ़ाने और घटाने की अभिव्यक्ति मूलादृष्टि नहीं रहती। पर आराम तथा शोक की वस्तुओं के साथ ऐसी बात नहीं है। उनकी कीमतों में परिवर्तन होने से उनकी माग काफी घटाई-बढ़ाई जा सकती है। यदि शोक की वस्तुओं की कीमतें बढ़ जायें तो उनकी खरीद कुछ समय के लिए बन्द या कम की जा सकती है। इसी तरह यदि उनकी कीमत कम हो जाय, तो ऐसी वस्तुओं की माग बहुत बढ़ सकती है। इसलिए आराम तथा शोक की वस्तुओं की माग अपेक्षाकृत अधिक लोचदार होती है, और आवश्यक वस्तुओं की माग कम लोचदार।

(२) कीमत—माग की लोच कीमत के साथ सीधे तौर से घटती-बढ़ती है। साधारणतः किसी वस्तु की माग की लोच ऊँची कीमत पर अधिक होती है, बीच की कीमत पर कुछ कम और बहुत नीची कीमत पर माग लगभग बेलोच होती है। यदि किसी ऊँची कीमत वाली वस्तु की



कीमत गिर जाय, तो बहुत-से लोग जो पहले नहीं खरीद सकते थे, अब उसे खरीदने लगेगे, और यदि उसकी कीमत बढ़ जाय तो कुछ लोग उस वस्तु को खरीदना बन्द कर देंगे, और कुछ अपनी माग की मात्रा पहले से कम कर देंगे। इस तरह कीमत में परिवर्तन होने से कीमती वस्तु की माग बहुत बदल जाती है। अतः ऊँची मूल्य वाली वस्तु की माग बहुत लोचदार होती है। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की कीमत बहुत कम है जिसमें कि वह सभी लोगों की पहुँच के भीतर है और सब अपनी आवश्यकता-नुसार उस वस्तु को पहले से ही खरीद रहे हैं, तो मूल्य के थोड़ा घटने या बढ़ने पर उस वस्तु की माग में कोई विशेष परिवर्तन न होगा। अस्तु, कम कीमत वाली वस्तुओं की माग लगभग बेलेच होती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि माग की लोच कीमत के साथ-साथ बदलती है।

इस सम्बन्ध में एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों के लिए ऊँची, मध्यम और कम कीमतों का स्तर अलग-अलग होता है। एक ही कीमत धनी के लिए नीची लेकिन मजदूरों के लिए ऊँची होगी। वो रुपये रोर अतः पनी मनुष्य के लिए कम कीमत वाली वस्तु होगी, परन्तु गरीब के लिए वही ऊँची कीमत वाली वस्तु है। इसलिए किसी वस्तु को ऊँची, मध्यम और नीची कीमतों को एक विशेष श्रेणी के मनुष्यों के सम्बन्ध में ही समझना चाहिए। स्वतन्त्र रूप से उनका कोई अर्थ न होगा।

(३) आदत—मनुष्य की आदतों का भी माग की लोच पर काफी प्रभाव पड़ता है। जिन वस्तुओं के उपभोग के हम आदी बन जाते हैं, उनकी माग लोचदार नहीं होती। ऐसी वस्तुओं की माग में मूल्यानुसार परिवर्तन करने की शक्ति हममें नहीं रहती। कारण, हम अपनी आदतों के एक तरह से मुलाम होते हैं, अपनी आदतों को हम आसानी से नहीं बदल सकते। किन्तु अन्य वस्तुओं के माग ऐसी बात नहीं है। कीमत के घटने-बढ़ने के साथ-साथ हम उन वस्तुओं की माग अच्छी तरह से बढ़ा-घटा

सकते हैं। अतएव उन वस्तुओं की मांग, जिनके हम आदी नहीं बन गये हैं, अधिक लोचदार होती है।

(४) विभिन्न उपयोग (variety of uses)—कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जो अनेक कार्यों में प्रयोग की जा सकती हैं, जैसे बिजली, कोयला, लोहा, दूध, आदि। इन वस्तुओं की कीमत घट जाने पर इनकी मांग बहुत बढ़ जाती है। कीमत कम हो जाने से ये वस्तुएँ उन स्थानों में भी प्रयोग की जाने लगती हैं जहाँ पहले, कीमत अधिक होने के कारण, इसका प्रयोग नहीं होता था। उदाहरण के लिए बिजली को ही ले लें। बिजली को कई स्थानों या कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसमें रोगनी का काम ले सकते हैं, भोजन तैयार कर सकते हैं, पखा अथवा रेडियो चला सकते हैं। ये सब काम एक समान आवश्यक नहीं हैं। इसलिए जब बिजली की कीमत घट जायगी तो कम आवश्यक स्थानों में भी इसका प्रयोग होने लगेगा। अर्थात् बिजली की मांग बहुत बढ़ जायगी। इसके विपरीत जब बिजली की कीमत बढ़ जायगी, तो इसका उपयोग कम आवश्यक स्थानों पर बन्द कर दिया जायगा। तब बिजली केवल आवश्यक मामलों में ही प्रयोग की जाने लगेगी और वहाँ भी बहुत सीमित मात्रा में। फलस्वरूप बिजली की मांग कम हो जायगी। अतः, विभिन्न उपयोग में आ सकने वाली वस्तुओं की मांग बहुत लोचदार होती है।

(५) स्थानान्तरित वस्तुओं की संख्या (number of substitutes)—जिन वस्तुओं के स्थान पर दूसरी वस्तुएँ प्रयोग में आ सकती हैं, उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। जितनी अधिक या कम एक वस्तु की स्थानान्तरित या प्रतिस्पर्धी वस्तुएँ होंगी, उतनी ही अधिक या कम उस वस्तु की मांग की लोच होगी। मोटर और ट्राम एक दूसरे की स्थानान्तरित वस्तुएँ (substitutes) हैं, ये एक दूसरे के बदले में उपयोग हो सकती हैं। यदि मोटर का किराया बढ़ जाय, तो लोग ट्राम पर जाने लगेंगे। परिणामस्वरूप मोटर सवारी की मांग कम

हो जायगी। यदि ट्रेम का किराया मोटर के किराये से अधिक हो जाय, तो लोच मोटर से आने-जाने लगेंगे। ट्रेम सवारी की माग, किराया बढ़ने से, कम हो जायगी और मोटर सवारी की माग बढ़ जायगी। अतः एक दूसरे के स्थान में प्रयोग आने वाली वस्तुओं की माग लोचदार होती है।

नमक का स्थान कोई दूसरी वस्तु नहीं ले सकती। कीमत बढ़ने पर भी हमें नमक खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बदले में किसी अन्य वस्तु का प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए नमक की माग लोच-रहित है।

(६) धन का वितरण—साधारण तौर से माग की लोच धन के वितरण की समानता में बदती है और असमानता से घटती है। यदि किसी देश में धन के वितरण में बहुत असमानता है, तो माग की लोच बहुत कम होगी। जैसे-जैसे असमानता कम होती जायगी, माग की लोच बढ़ती जायगी।

(७) आय का प्रतिपात व्यय—जिन वस्तुओं के खरीदने में आय का बहुत बड़ा भाग सर्ब होता है, उनको माग कम लोचदार होती है, जैसे दियासलाई, मुँई, जूनादि। इनके मूल्य में परिवर्तन होने पर भी हम इन्हे करीब-करीब पहले के ही परिमाण में खरीदते हैं।

उपर्युक्त बातों में यह स्पष्ट है कि भिन्न-भिन्न वस्तुओं की माग की लोच कभी भिन्न-भिन्न होती है, अथवा कभी एक ही वस्तु की माग की लोच भिन्न-भिन्न श्रेणी के मनुष्यों के लिए भिन्न-भिन्न होती है। साधारणतः उन वस्तुओं की माग लोचदार होती है जिनकी कीमतें अपेक्षाकृत ऊँची होती है, जिनके विभिन्न उपयोग होते हैं, जिनका उपयोग भविष्य के लिए टांग्न जा सकता है, जिनके बदले में अन्य वस्तुएँ प्रयोग की जा सकती हैं और जो शोक व आराम की श्रेणी व वर्ग में आती हैं। इसके विपरीत जिन वस्तुओं की कीमतें नीची होती है, जिनके स्थान पर अन्य वस्तुएँ उपयोग नहीं हो सकती, जिनके विभिन्न उपयोग सम्भव नहीं होते, जिन

पर आमदनी का थोड़ा भाग खर्च होता है अथवा जो सावधानता के वर्ग में जाती है, उनकी माप कम लोचदार या वेलोच होती है।

### लोच की माप

(Measurement of Elasticity)

माप की लोच के सम्बन्ध में केवल इतना ही जान लेना पर्याप्त नहीं है कि अमृक वस्तु की माप लोचदार है, या वेलोचदार। साथ ही हमें यह देखना होगा कि माप की लोच कितनी है। सभी व्यावहारिक जीवन में इससे लाभ उठाया जा सकेगा।

माप की लोच मापने के दो मुख्य तरीके हैं। माप की लोच मापने का एक सरल तरीका इस प्रकार है। किसी एक विशेष कीमत पर माप की लोच मापने के लिए हम यह देना पड़ेगा कि कीमत में परिवर्तन होने से माप में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। दोनों के प्रतिशत परिवर्तन को भाग देने से जो भागफल निकलेगा, वही माप की लोच होगी। उदाहरण के लिए मान लें कि किसी वस्तु की कीमत २ प्रतिशत घट जाती है और इस कारण उस वस्तु की माप में १० प्रतिशत वृद्धि होती है, तो ऐसी परिस्थिति में माप की लोच  $10/2 = 5$  होगी। अस्तु, माप की लोच निम्नलिखित तरीके या रीति से मापी जा सकती है —

$$\text{माप की लोच} = \frac{\text{माप में प्रतिशत अन्तर}}{\text{कीमत में प्रतिशत अन्तर}}$$

माप की लोच एक दूसरे तरीके से भी मापी जा सकती है। यदि कीमत में परिवर्तन होने से किसी वस्तु के खरीदने में उतना ही खर्च होता है जितना कि पहले होता था, तो उस वस्तु की माप की लोच सम व इकाई में बराबर (equal to unit) मानी जाती है। यदि कीमत के घटने से उस वस्तु पर किया गया कुल खर्च बढ़ जाता है और कीमत बढ़ने पर कुल खर्च कम हो जाता है, तो उस वस्तु की माप की लोच सम व इकाई में अधिक मानी जायगी। और जब कीमत के घटने पर किसी वस्तु के मोल लेने में कुल खर्च कम हो जाता है अथवा

कीमत बढ़ने पर कुल खर्च बढ़ जाता है, तो कहा जायगा कि उस वस्तु की माग की लोच इकाई व सम से कम है। नीचे दिये गये कोष्टक में यह बात अकी में बिललाई गई है।

कीमत आने में	माग की मात्रा	कुल खर्च आने में	माग की लोच
१०	३	$१० \times ३ = ३०$	इकाई व सम से अधिक
९	४	$९ \times ४ = ३६$	
८	५	$८ \times ५ = ४०$	
७	६	$७ \times ६ = ४२$	इकाई व सम के बराबर
६	७	$६ \times ७ = ४२$	
५	८	$५ \times ८ = ४०$	इकाई व सम से कम
४	९	$४ \times ९ = ३६$	
३	१०	$३ \times १० = ३०$	

इस कोष्टक से माग की लोच का अनुमान ठीक तरह से किया जा सकता है। जब कीमत दस आने में घट कर ८ आने हो जाती है, तो कुल खर्च ३० आने से बढ़ कर ४० आने हो जाता है। (माग की मात्रा की कीमत से गुणा करने से कुल खर्च निकल आता है)। अतएव माग की लोच इकाई से अधिक है। जब कीमत ७ आने और ८ आने है तो कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता। दोनों ही कीमतों पर कुल खर्च ४२ आने है। इसलिए यहाँ पर माग की लोच इकाई के बराबर है। इसके बाद जैसे-

जैसे कीमत घटती जाती है, वैसे-वैसे कुल खर्च भी घटना जाता है। अस्तु, यहाँ पर माग की लोच इकाई से कम है।

### माग की लोच का महत्व

(Importance of Elasticity of Demand)

सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों ही रूपों में माग की लोच से बड़ी सहायता मिलती है। इसका विशेष महत्त्व कर, मूल्य और वितरण के क्षेत्रों में है। माग की लोच से पता चलता है कि कीमत में परिवर्तन होने में भिन्न-भिन्न वस्तुओं की माग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके द्वारा यह भी मालूम होता है कि भिन्न-भिन्न परिस्थितियों अथवा भिन्न-भिन्न प्रेमी के मनुष्यों की मागों पर कीमत के घटने-बढ़ने का क्या-कसा फल होगा। उत्पादकों, विशेष कर एकाधिकारी, को इसमें बड़ी सहायता मिलती है। माग की लोच मालूम कर एकाधिकारी यह भली प्रकार जान सकता है कि किस कीमत पर बेचने से उसे अधिकतम लाभ हो सकेगा। उदाहरणार्थ यदि किसी वस्तु की माग बहुत लोचदार है, तो एकाधिकारी वस्तु को कम कीमत रखकर अधिक लाभ उठा सकता है क्योंकि उस वक्ता से लोग उस वस्तु को अधिक परिमाण में खरीदेंगे। किन्तु यदि माग बेलोचदार है, तो ऊँची कीमत रखने से उसको अधिक लाभ होगा।

सरकार को भी वस्तुओं पर कर लगाते समय इन ओर काफी ध्यान देना पड़ता है। सरकार को यह देखना पड़ता है कि कर लगाने से वस्तु की कीमत में जो वृद्धि होगी उसका माग पर क्या असर पड़ेगा। यदि माग बहुत लोचदार है, तो उस पर कर लगाने में सरकार को कम आय होगी क्योंकि मूल्य बढ़ने में लोग उस वस्तु की माग कम कर देंगे। इसका फल यह होगा कि सरकार को कम माल पर कर मिल सकेगा। इसके विपरीत जिन वस्तुओं की माग कम लोचदार होती है, उन पर कर लगाने में सरकार को काफी आमदनी हो सकेगी। अस्तु, माग की लोच का अध्ययन विशेष महत्त्व रखता है।

## QUESTIONS

- 1 What is meant by 'demand' in Economics ?
- 2 Prepare an imaginary demand schedule and represent it in the form of a curve
- 3 Explain and illustrate the law of demand and indicate its relationship with the law of diminishing marginal utility ?
- 4 What do you mean by 'elasticity of demand' ? Explain the factors on which elasticity of demand depends
- 5 Show why demand expands with a fall in price and contracts with a rise in price
- 6 What is meant by 'increase' and 'decrease' of demand ? How do they differ from 'extension' and 'contraction' of demand ?
- 7 How can you measure elasticity of demand ? State the importance of elasticity of demand

## अध्याय १२

### उपभोग सम्बन्धी कुछ अन्य नियम

(Some Other Laws Concerning Consumption)

पिछले दो अध्यायों में उपयोगिता और माय सम्बन्धी नियमों का उल्लेख किया गया है। उनमें इस बात का बोध होता है कि जैसे-जैसे किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु का अधिक परिमाण होता जाता है, वैसे ही वैसे उनकी सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है और इस कारण वह व्यक्ति उस वस्तु की वाद में मिलने वाली इकाइयों के लिए, परिस्थिति के अपरिवर्तित रहने पर, कमरा घटती हुई कीमत देने को तैयार होगा। इसी के आधार पर हम इस अध्याय में उपभोग या उपयोगिता सम्बन्धी कुछ अन्य नियमों का विवेचन करेंगे।

### उपभोक्ता की वचत का नियम

(Doctrine of Consumer's Surplus)

साधारणतः हम बाजार से अनेक वस्तुएँ खरीदते हैं जिनके उपभोग में हमारी आवश्यकताओं की तृप्ति होती है। हम इच्छित वस्तुओं को इसलिए खरीदते हैं कि उनमें उपयोगिता होती है, अर्थात् उनमें आवश्यकताओं की पूर्ति करने की शक्ति होती है। किन्तु ये वस्तुएँ हमें बाजार में मुफ्त नहीं मिलती। इनके लिए हमें पर्याप्त मूल्य देना पड़ता है। जो मूल्य हम देते हैं उसमें भी कुछ उपयोगिता होती है क्योंकि उस मूल्य से अन्य इच्छित वस्तुएँ खरीदी जा सकती हैं, और उनके उपभोग में तृप्ति प्राप्त की जा सकती है। अस्तु, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो हम उस वस्तु से कुछ उपयोगिता प्राप्त होती है, पर साथ-ही-साथ हमें उस वस्तु की कीमत के रूप



से कुछ उपयोगिता व तृप्ति का त्याग करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, हमें एक ओर तो वस्तु से उपयोगिता मिलती है और दूसरी ओर उसके पाने के लिए कुछ उपयोगिता देनी पड़ती है। यदि वह उपयोगिता, जिसको हमें किसी वस्तु से मिलने की संभावना है, उस उपयोगिता से कम है जो उग वस्तु के प्राप्त करने में हमें त्याग करनी पड़ेगी, तो हम उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे। साधारणतः किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता त्याग की जाने वाली उपयोगिता की अपेक्षा अधिक होती है। तृप्ति के इस अन्तर अथवा वचत की अर्थशास्त्र में “उपभोक्ता की वचत” कहते हैं जो तृप्ति-भाव किसी वस्तु के पाने में उस सतोप से अधिक होता है जिसका उभके लिए त्याग करना पड़ता है, उसे ‘उपभोक्ता की वचत’ (consumer surplus) कहते हैं। दूसरे शब्दों में, ‘उपभोक्ता की वचत’ इन दो तृप्तियों के बीच का अन्तर है—एक तो जो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से प्राप्त होती है और दूसरी जो उसे उस वस्तु के पाने में त्याग करनी पड़ती है। मान लो किसी वस्तु के खरीदने से एक व्यक्ति को ५० इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है और उसका मूल्य देने में ४० इकाई उपयोगिता देनी पड़ती है। तो, इस उदाहरण के अनुसार, उस व्यक्ति को  $50 - 40 = 10$  इकाई उपयोगिता की वचत हुई। यही अन्तर ‘उपभोक्ता की वचत’ कहलाता है। यही उसकी ‘उपभोक्ता की वचत’ है।

‘उपभोक्ता की वचत’ को हम इस प्रकार माप सकते हैं। जितनी उपयोगिता या तृप्ति एक व्यक्ति को किसी वस्तु से मिलती है, वह लगभग उस मूल्य के बराबर होती है जो वह व्यक्ति उस वस्तु के लिए देने को तैयार हो सकता है। और जितनी उपयोगिता का वह त्याग करता है, वह उस मूल्य के बराबर होती है जो वास्तव में उसे देना पड़ता है। इन दोनों मूल्यों के अन्तर से (एक तो जो वह देने को तैयार हो सकता है और दूसरे जो उसे देना पड़ता है) उपभोक्ता की वचत का ज्ञाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लो कि तुम्हें एक भोज की बहुत आवश्यकता है और तुम उसके लिए

१५ रुपये तक देने को तैयार हो। किन्तु जब तुम बाजार जाते हो, तो मान लो, उस तरह की मेज तुम्हें १० रुपये में ही मिल जाती है। इस दशा में तुम्हें ५ रुपये की बचत होगी। उपयोगिता के हिसाब से तुम मेज के लिए १५ रुपये देने को तैयार हो, लेकिन बाजार भाव के कारण तुम्हें केवल १० रुपये ही देने पड़े। अस्तु, १० रुपये खर्च करने में तुम्हें ५ रुपये के बराबर अधिक वृत्ति प्राप्त हुई। इसलिए हम यह कहेंगे कि मेज से तुम्हें ५ रुपये के बराबर 'उपभोगिता की बचत' हुई। इसी तरह अन्य वस्तुओं में प्राप्ति होने वाली 'उपभोगिता की बचत' की माप की जा सकती है। अधिकतर जो कीमतें हम वस्तुओं के बदले में देते हैं, वे उन कीमतों में कम होती हैं जो हम देने के लिए तैयार हो सकते हैं। दैनिक समाचार-पत्रों का मूल्य इधर कुछ समय में काफी बढ़ गया है, फिर भी हम उन्हें खरीदते हैं। सम्भव है, मूल्य के और बढ़ जाने पर भी हम उन्हें और खरीदते रहें। यही दशा अन्य वस्तुओं की भी है। इससे यह सिद्ध होता है कि बहुधा हमें वस्तुओं के उपभोग से बचत होती है जिसे अधशास्त्र में "उपभोगिता की बचत" कहते हैं।

उपभोगिता बात की इस तरह भी स्पष्ट किया जा सकता है। उपयोगिता-ह्रास-नियम से यह स्पष्ट है कि वस्तु की पहली इकाइयों से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है और जैसे-जैसे उस वस्तु का परिमाण बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे बाद में ली जाने वाली इकाइयों की उपयोगिता गिरती जाती है। किन्तु क्या हम पहली इकाई के लिए अधिक मूल्य देते हैं, दूसरी इकाई के लिए कुछ कम, तीसरी इकाई के लिए और भी कम? बाजार में प्रत्येक इकाई का मूल्य एक ही होता है। हम किसी वस्तु को तब तक खरीदते जाते हैं, जब तक कि उसकी सीमान्त उपयोगिता मूल्य से अधिक होती है। जब सीमान्त उपयोगिता और मूल्य दोनों बराबर हो जाते हैं, तब हम उस वस्तु की खरीद बन्द कर देते हैं। अस्तु, सब इकाइयों का मूल्य तो एक होता है, पर उनकी उपयोगिता एवं समान नहीं होती। केवल सीमान्त इकाई की ही उपयोगिता मूल्य के बराबर होती है। इसके पहले

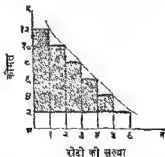
बाली इकाइयों से मूल्य से अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी है, अर्थात् सीमान्त इकाई को छोड़कर बाकी सब इकाइयों में तृप्ति की बचत होगी है। जब उपभोक्ता की बचत का अन्दाजा इस प्रकार भी हो सकता है — उपभोक्ता की बचत = कुल प्राप्त उपयोगिता-सीमान्त उपयोगिता  $\times$  खरीद की मात्रा ।

उदाहरण द्वारा 'उपभोक्ता की बचत' को और स्पष्ट किया जा सकता है। मान लो कोई व्यक्ति भूखा है और भूख मिटाने के लिए वह रोटियाँ खरीदता है। प्रत्येक रोटी को उपयोगितानुसार वह निम्नलिखित कीमत देने को तैयार हो सकता है। मान लो कि बाजार में प्रति रोटी की कीमत २ आने है।

रोटी की संख्या	मूल्य जो वह देने को तैयार हो सकता है	बाजार भाव	उपभोक्ता की बचत
पहली	१२ आने	२ आने	$(१२-२) = १०$ आने
दूसरी	१० "	२ "	$(१०-२) = ८$ "
तीसरी	८ "	२ "	$(८-२) = ६$ "
चौथी	६ "	२ "	$(६-२) = ४$ "
पाँचवी	४ "	२ "	$(४-२) = २$ "
छठी	२ "	२ "	$(२-२) = ०$ "
कुल ६ रोटियाँ	४२ आने	१२ आने	३० आने

ऊपर के कोष्टक से यह स्पष्ट है कि वह व्यक्ति कुल ६ रोटियां खरीदेगा। कारण, रोटी की सीमान्त उपयोगिता और कीमत दोनों यहां बराबर है। यदि वह सातवीं रोटी लेगा, तो उसे कीमत की तुलना में कम तृप्ति मिलेगी। कीमत तो उसे दो आने देनी पड़ेगी लेकिन उपयोगिता उतनी न मिलेगी। इसलिए वह छठी रोटी के बाद और रोटियां न खरीदेगा। वह ६ रोटियों से कम भी न खरीदेगा क्योंकि इससे पहले की रोटियों से उसे कीमत की तुलना में अधिक तृप्ति प्राप्त होती है। अब वह कुल ६ रोटियां खरीदेगा, इससे न कम, न अधिक। वह ६ रोटियों की उपयोगिता के अनुसार कुल ४२ आने देने को तैयार है, पर बाजार भाव दो आने प्रति रोटी होने के कारण उसे कुल १२ आने ही देने पड़ेंगे। अस्तु, उसे  $(४२-१२) = ३०$  आने के बराबर 'उपभोगिता की बचत' मिलेगी।

ऊपर के उदाहरण को रेखा-चित्र द्वारा इस प्रकार दिखाया जा सकता है। चित्र का रंग भूया भाग 'उपभोगिता की बचत' दर्शाता है।



भिन्न भिन्न वस्तुओं से भिन्न भिन्न मात्राओं में उपभोगिता की बचत मिलती है। साधारणतः आवश्यक पदार्थों में अधिक 'उपभोगिता की बचत' मिलती है और आराम तथा शौक की वस्तुओं से कम। साधारण जीवन में काम आने वाली अनेक वस्तुओं से बहुत अधिक तृप्ति की बचत होती है, जैसे

दियामलाई, नमक, समाचार-पत्र, पोस्टकार्ड, अन्न, दूध, आदि। इन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जो चीजें हमें देनी पड़ती हैं, वे उनसे कहीं कम होती हैं जो हम देने के लिए तैयार हो सकते हैं। साधारणतः इन वस्तुओं की माग कम लोचदार होती है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि जिन वस्तुओं की माग की लोच कम होती है, उनसे अधिक 'उपभोक्ता की वचत' मिलती है।

उपर यह बतलाया गया है कि किसी वस्तु की जरूरत में 'उपभोक्ता की वचत' कैसे निराली जाती है। जब हम किसी व्यक्ति के उपभोग की सभी वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपभोक्ता की वचतों को जोड़ लेंगे, तो उस व्यक्ति की कुल 'उपभोक्ता की वचत' गलूम हो जायगी। और इसी प्रकार कुल व्यक्तियों की व्यक्तिगत उपभोक्ता की वचतों को जोड़कर मण्डी की 'कुल उपभोक्ता की वचत' प्राप्त की जा सकती है। इसके आधार पर हम भिन्न-भिन्न समय और स्थानों पर भिन्न-भिन्न मनुष्यों की सम्पत्तियों की तुलना कर सकते हैं। साधारण रूप से यह माना जाता है कि उपभोक्ता की वचत जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक सम्पन्नता होगी।

जिन्नु 'उपभोक्ता की वचत' के सिद्धान्त पर अनेक प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका विवेचन केवल कपोल-कल्पित है, वास्तविक नहीं। यह कहना कि किसी व्यक्ति को अपनी १०० रुपये की आमदनी में १००० रुपये की उपयोगिता प्राप्त होती है, किबूल है; इसमें कोई लाभ नहीं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जीवन-रक्षक वस्तुओं के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त लागू नहीं होता। कोई व्यक्ति किसी-जीवन-रक्षक पदार्थ के लिए कितना दे सकता है, इसका हिसाब लगाया ही नहीं जा सकता। और फिर इसके बिना 'उपभोक्ता की वचत' का अनुमान कैसे हो सकता है। इसलिए यह नियम अधूरा है। साथ ही कुछ लोग यह कहते हैं कि 'उपभोक्ता की वचत' की माप नहीं की जा सकती।

इसके ये कई कारण बताते हैं। एक तो यह है कि मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता बराबर नहीं रहती, वह बदलती जाती है। दूसरे, पूरी-पूरी मांग की सूची तैयार नहीं की जा सकती। यह पता लगाना कठिन है कि लोग भिन्न-भिन्न सम्भव कीमतों पर किसी वस्तु को कितनी-कितनी मात्रा में खरीदने को तैयार होंगे। साधारणतः जो कीमते मण्डी में चालू होती हैं, उनके आस-पास की कीमतों की सूची तो बनाई जा सकती है, लेकिन अन्य कीमतों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए पूरी मांग की सूची तैयार करना असम्भव है। फिर भला किस प्रकार 'उपभोक्ता की बचत' को ठीक-ठीक मापा जा सकता है। और बिना इसके 'उपभोक्ता की बचत' का क्या-कितना वैज्ञानिक महत्त्व रह जायगा।

इस तरह के अनेक आक्षेप 'उपभोक्ता की बचत' के सिद्धान्त पर लगाए जाते हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह केवल श्रमात्मक है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। यह तो ठीक है कि 'उपभोक्ता की बचत' का सही माप नहीं हो सकता, पर यह मानना पड़ेगा कि यह कपोल-कल्पित नहीं है। हम अपने दैनिक जीवन में इसका प्रतिदिन अनुभव करते हैं। कितनी ही वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे हमें उनकी कीमतों से कहीं अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। यही 'उपभोक्ता की बचत' है।

### उपभोक्ता की बचत का महत्त्व

#### (Importance of Consumer's Surplus)

सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से 'उपभोक्ता की बचत' का बहुत महत्त्व है। इस सिद्धान्त से वस्तु की कीमत और उसकी उपयोगिता के बीच का अन्तर स्पष्ट हो जाता है। इससे हमें इस बात का बोध होता है कि कीमत के द्वारा किसी वस्तु की कुल उपयोगिता का सही-मही अन्दाजा नहीं हो सकता। कीमत सीमान्त उपयोगिता के बराबर होती है। इसलिए हमसे वस्तु की केवल सीमान्त उपयोगिता को ही माप हो सकती है,

उसकी समस्त उपयोगिता की नहीं। आम तौर से बाजार में वस्तुओं के लिए जो कीमते देनी पड़ती है, उनसे कहीं अधिक उन वस्तुओं से उपयोगिता प्राप्त होती है। अर्थात् उनसे 'उपभोक्ता की बचत' मिलती है।

दूसरे, 'उपभोक्ता की बचत' के द्वारा उन लाभों का अनुमान हो सकता है जो मनुष्यों की परिस्थितियों के कारण, राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक वातावरण के कारण अनायास प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति सम्य समान में, उन्नत तथा प्रगतिशील देश में रहते हैं, उन्हें विविध प्रकार की वस्तुएँ बहुत सस्ते दामों में प्राप्त हो जाती हैं। असम्य या पिछड़े हुए देशों में ये वस्तुएँ कई गुना अधिक खर्च करने पर भी आमानी से नहीं मिल सकती। अस्तु, सम्य देश या स्थान के निवासियों को वहाँ की परिस्थितियों के कारण अधिक 'उपभोक्ता की बचत' प्राप्त होती है।

तौसर, इस सिद्धान्त के द्वारा भिन्न-भिन्न मनुष्यों की, भिन्न-भिन्न समाज, समय और स्थान की सम्पत्तियों की तुलना करके आर्थिक दशा और प्रगति का पता लगाया जा सकता है। यदि किसी देश में, दूसरे देश के भुकावले में 'उपभोक्ता की बचत' अधिक मात्रा में प्राप्त होती है तो, अन्य बातों के समान रहने पर, वह देश अधिक सम्पन्न, सम्य और सुसंगठित माना जायगा। इसी प्रकार एक ही देश के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न समय पर आर्थिक दशा व प्रगति का तुलनात्मक विवेचन किया जा सकता है। इस तरह का तुलनात्मक विवेचन हर दृष्टि में महत्त्वपूर्ण है।

चौथे, कर लगाते समय सरकार को इस सिद्धान्त से बड़ी सहायता मिलती है। सरकार को यह दखना पड़ता है कि लोग किसी वस्तु के लिए कितना देने को तैयार हैं, और कर लगाने से कीमत में जो वृद्धि होगी, उसका उन पर क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा। 'उपभोक्ता की बचत' के अध्ययन से इस तरह की जानकारी हो सकती है। अस्तु, कर लगाते समय इस सिद्धान्त से काफी सहायता मिलती है। इसी भाँति जब सरकार किसी उद्योग-धन्ये को सहायता या प्रोत्साहन देती है, तो इस बात का ध्यान रखती है कि

‘उपभोक्ता की वचत’ की मात्रा पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा । यदि उससे ‘उपभोक्ता की वचत’ में वृद्धि होती है, तो उस उद्योग-धन्धे की सरकारी सहायता और प्रोत्साहन मिलना, जनता की दृष्टि से, लाभप्रद होगा ।

पाचने, मूल्य-निर्धारण में भी इससे बड़ी सहायता मिलती है । किसी वस्तु की कीमत तय करते समय विक्रेता को, विनोदकर एकाधिकारी को, ‘उपभोक्ता की वचत’ पर दृष्टि रखनी पड़ती है । यदि उस वस्तु से अधिक मात्रा में ‘उपभोक्ता की वचत’ मिल रही है, तो एकाधिकारी आसानी से उसकी कीमत ऊँची रख सकता है । लेकिन अपने लाभ के साथ-साथ उसे यह भी ध्यान में रखना होगा कि ऊँची कीमत से ‘उपभोक्ता की वचत’ में कहीं इतनी कमी न आ जाय जिससे ग्राहक उसके खिलाफ हो जाय और आगे चलकर उस वस्तु का उपभोग कम या बन्द न कर दे ।

अस्तु, ‘उपभोक्ता की वचत’ के सिद्धान्त का सम्बन्ध अनेक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों और समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ है । इससे दस सिद्धान्त का महत्त्व स्पष्ट है ।

### सम-सीमन्त उपयोगिता नियम

(Law of Equimarginal Utility)

प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि उसे अपनी आय से अधिक से अधिक तृप्ति और सतोष प्राप्त हो । यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताओं का कोई अन्त नहीं है, वे अक्षय्य हैं । किन्तु मनुष्य की आय, जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की तृप्ति करता है, अपेक्षाकृत सीमित होती है । इसलिए उसे बराबर इस बात पर विचार करना पड़ता है कि वह अपनी कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे और कितनी अतृप्त हो छोड़ दे । आय को सीमित होने के कारण वह सभी वस्तुओं को इच्छा-पुसार नहीं खरीद सकता । उसे यह निर्णय करना पड़ता है कि कितनी-कितनी वस्तुओं को किस समय और कितने परिमाण में खरीदे । यदि वह कितनी वस्तु के खरीदने में अधिक व्यय खर्च कर देगा तो निश्चय ही उसके पास



अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए पर्याप्त साधन न रहे, अर्थात् द्रव्य की कमी पड़ जायगी। इसका परिणाम यह होगा कि उनकी कुल तृप्ति में कमी आ जायगी। ऐसी स्थिति में यदि वह अपने खर्च से उन में उचित परिवर्तन करे तो उगे और अधिक तृप्ति प्राप्त हो सकती है।

यह कार्य वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिताओं की तुलना करके किया जा सकता है। जिन वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता कम है, उनकी मात्रा कम करने से हमें लाभ होगा। यह पहले कहा जा चुका है कि वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से उनकी सीमान्त उपयोगिता गिर जाती है। यदि हमने किसी वस्तु को अधिक परिमाण में खरीदा है और दूसरी को कम परिमाण में, तो पहली वस्तु की सीमान्त उपयोगिता दूसरी वस्तु की सीमान्त उपयोगिता से कम होगी। इस दशा में यदि हम पहली वस्तु की मात्रा को कुछ कम कर दें और दूसरी वस्तु को अधिक खरीदें, तो हमें इस परिवर्तन में लाभ होगा। इस तरह की अदल-बदल में दोनों वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिताएँ एक सीमा पर आकर बराबर हो जायेंगी। जब खरीदी हुई वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिताएँ एक समान हो जाती हैं, तो तृप्ति अधिकतम सीमा पर पहुँच जाती है। जब तक सीमान्त उपयोगिताएँ बराबर न होंगी, जब तक कुछ वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि करने से और कुछ के घटाने से हम लाभ होगा। ऐसा करने से हम सम-सीमान्त उपयोगिता की सीमा पर पहुँच जायेंगे। तभी हमें अपनी सीमित आय से अधिकतम तृप्ति प्राप्त हो सकेगी।

संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि मनुष्य को किसी वस्तु से, जिसके विभिन्न प्रयोग हैं, सभी मन्गों अधिक-संतोष या उपयोगिता प्राप्त हो सकती है, जबकि वह उस वस्तु को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बाँटे कि प्रत्येक उपयोग में उस वस्तु की सीमान्त उपयोगिता बराबर हो। यदि वह वस्तु मुद्रा है, तो उसे विविध वस्तुओं के खरीदने में इस प्रकार लगाना पड़ेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किये गये अन्तिम रुपये की सीमान्त उप-

योगिता बराबर हो। तभी उससे अधिक से अधिक तृप्ति की प्राप्ति हो सकती है। यदि सीमान्त उपयोगिताएँ बराबर नहीं हैं, तो स्त्रियों को एक स्थान से हटाकर, जहाँ उनकी सीमान्त उपयोगिता कम है, उस स्थान पर लगाने में लाभ होगा जहाँ सीमान्त उपयोगिता अधिक है। इस तरह के उलट-फेर से मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता हर स्थान पर बराबर हो जायेगी और तभी अधिकतम तृप्ति प्राप्त होगी। इसी की अर्थशास्त्र में सम-सीमान्त उपयोगिता नियम' अथवा 'प्रतिस्थापन नियम' कहते हैं। इस नियम की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है—मुद्रा अथवा और किसी वस्तु में तभी अधिक से अधिक तृप्ति प्राप्त हो सकती है, जबकि उसका विभिन्न प्रयोगों में इस दृष्टि में उपयोग किया जाय कि प्रत्येक प्रयोग में उसकी सीमान्त उपयोगिता एक समान हो।

इस नियम को एक उदाहरण लेकर और स्पष्ट किया जा सकता है। मान लो किसी मनुष्य के पास आठ आने हैं और वह तीन चीजें—दूध, चीनी और मक्खन—खरीदना चाहता है। इन तीनों वस्तुओं को प्रत्येक इकाई का मूल्य, मान लो एक आना है और भिन्न-भिन्न इकाइयों की उपयोगिता इस प्रकार है—

आना	सीमान्त उपयोगिता		
	दूध	चीनी	मक्खन
पहला	12	10	8
दूसरा	10	8	6
तीसरा	8	6	4
चौथा	6	4	3
पाँचवा	4	3	2
छठा	3	2	1
सातवा	2	1	0
आठवा	1	0	-1

अब हमको यह देखना है कि यह व्यक्ति अपने आठ आने को इन तीनों वस्तुओं पर किस प्रकार खर्च करे जिससे उसे अधिकतम नृप्ति हो। वह पहले आने को दूध पर खर्च करेगा जिसमें उसे १८ इकाई उपयोगिता मिलती है। यदि पहले आने को वह चीनी या मक्खन पर खर्च करेगा, तो उसे केवल १७ या १६ आने इकाई ही उपयोगिता प्राप्त होगी। इसलिए वह पहले आने को दूध पर खर्च करेगा। दूसरे आने को वह चीनी पर खर्च करेगा जिससे उसे १७ इकाई उपयोगिता मिलती है। तीसरे आने को मक्खन पर खर्च करेगा और चौथे आने को फिर दूध पर। इस तरह से उपयोगिताओं की तुलना करते हुए, वह पाचवा आना चीनी पर, छठा आना दूध पर, सातवा आना चीनी पर और आठवा आना मक्खन पर खर्च करेगा। इस तरह वह आठ आने में से ३ आने दूध पर खर्च करेगा, ३ आने चीनी पर, और २ आने मक्खन पर। इस ढंग से खर्च करने पर तीनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता एक समान (१४ इकाई) हो जाती है और उसे कुल १२४ इकाई उपयोगिता मिलती है। अन्य किसी ढंग से खर्च करने पर उसे इतनी उपयोगिता न मिलेगी। उदाहरण के लिए मान लो यह दो आने दूध पर खर्च करता है, तीन आने चीनी पर और तीन आने मक्खन पर। ऐसा करने से उसे कुल १२२ इकाई ही उपयोगिता मिलेगी जो कि पहले से कम है। इससे यह सिद्ध होता है अधिकतम नृप्ति तभी मिल सकती है जबकि खरीदी हुई वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिताएँ बराबर हो।

यह नियम केवल मुद्रा के खर्च के साथ ही गृही, बल्कि हर प्रकार के साधन के उपयोग के साथ लागू है। हम अपने समय, शक्ति, आदि साधनों से तभी अधिकतम नृप्ति प्राप्त कर सकते हैं, जबकि हम उनका इस प्रकार प्रयोग करें जिससे हर स्थान में उनकी सीमान्त उपयोगिताएँ एक समान हो। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने सीमित समय को किसी एक कार्य में अधिक लगा देते हैं, तो अन्य कार्यों के लिए समय नहीं रहेगा या कम पड़ जायेगा। फलस्वरूप हमें उनका सतोष न मिल सकेगा जितना कि

समय को उचित ढंग से प्रयोग करने से मिल सकता है। यदि समय को भिन्न-भिन्न कार्यों के बीच इस तरह बांटे जिससे प्रत्येक घण्टे की सीमान्त उपयोगिता बराबर हो जाय, तो उस दशा में हमें अधिकतम तृप्ति प्राप्त होगी। अन्य साधनों के लिए भी यह बात लागू है।

प्रत्येक मनुष्य अपने प्रतिदिन के जीवन में इसी प्रकार की तुलना करके समय-सीमान्त उपयोगिता के नियम के अनुसार अपनी आय और अन्य सीमित साधनों को उपयोग में लाता है। कारण, केवल इसी तरीके में सबसे अधिक उपयोगिता और तृप्ति प्राप्त हो सकती है। इसका यह आशय नहीं कि हर समय मनुष्य ऊपर की तरह एक कोष्टक बनाकर ही यह निश्चय करता है कि किसी वस्तु पर कितना खर्च करे। इस तरह से खर्च करना उसका स्वभाव हो जाता है। उसे कोष्टक बनाने की फिर जरूरत नहीं रहती।

### पारिवारिक आय-व्यय

(Family Budgets)

किसी परिवार के आय और व्यय के भिन्न-भिन्न मदों के विवरण भण्डा व्योरे को पारिवारिक बजट या आय-व्यय-पत्र कहते हैं। इसमें यह पता चलता है कि किसी कुटुम्ब की कितनी आमदनी है और भिन्न-भिन्न पदार्थों पर कितना खर्च होता है। इस तरह के अध्ययन से समाज के रहन-सहन का माप-दण्ड ज्ञात होता है। यह जानना बहुत आवश्यक और लाभ-प्रद है कि भिन्न-भिन्न देशों के रहने वाले अपनी आय को किस ढंग से खर्च करते हैं। मनुष्य किस प्रकार और कितना खर्च करता है, यह कई बातों पर निर्भर है, जैसे उसकी आय, उस देश की जलवायु, प्रथा, आदि। ये बातें हर जगह एक-ही नहीं होतीं। इसलिए खर्च करने के ढंग में बहुत भिन्नता पाई जाती है। हा, यह बात अवश्य है कि प्रत्येक कुटुम्ब अपनी आय के अनुसार ही व्यय करता है।

पाश्चात्य देशों में पारिवारिक बजट के विषय में बहुत खोज की गई है जिससे यह पता चलता है कि भिन्न-भिन्न आमदनी वाले कुटुम्ब अपनी

साथ को किम प्रकार विभिन्न मर्दी में खर्च करते हैं। जर्मनी के एक प्रसिद्ध लेखक, डाक्टर एन्जिल ने इस विषय पर काफी महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। विचारपूर्वक विस्तरेषण करने से बाद उन्होंने निम्नलिखित कोष्टक तैयार किया :—

व्ययार्थ	मजदूर के परिवार का खर्च	मध्यम श्रेणी के परिवार का खर्च	सम्पन्न परिवार का खर्च
१ भोजन-नामची	६० प्रतिशत	५५ प्रतिशत	५० प्रतिशत
२. वस्त्र	१६ "	१८ "	१८ "
३ मकान का किराया	१० "	१२ "	१० "
४. डेपन तथा रोसनी	५ "	५ "	५ "
५ शिक्षा, स्वास्थ्य, मकूर, सौच की सामग्री, आदि	५ "	१० "	१५ "
कुल	१००	१००	१००

इस कोष्टक में तीन श्रेणियों के परिवारों की आमदनी का औसत प्रतिशत खर्च विभिन्न-विभिन्न वस्तुओं पर दिखाया गया है। इस आसरे में डाक्टर एन्जिल ने निम्नलिखित परिणाम व निष्कर्ष निकाले हैं जिन्हें एन्जिल का उपमार्ग-निदान कहना जाता है —

(१) जैसे-जैसे किसी परिवार की आमदनी बढ़ती जाती है, वैसे ही धीरे भोजन-नामची पर प्रतिशत खर्च कम होता जाता है। अर्थात् एक गरीब

आदमी एक धनी व्यक्ति की अपेक्षा अपनी आय का अधिक भाग भोजन पर खर्च करता है।

(२) आय का प्रतिशत मांस जो वस्त्र, किराया, रोजगार और ईंधन पर खर्च होता है, वह करीब-करीब सब परिवारों में बराबर होता है।

(३) आय के बढ़ने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य-रक्षा, सफर, इत्यादि पर प्रतिशत खर्च बढ़ता जाता है और जैसे-जैसे आमदनी कम होती जाती है, इन पर खर्च घटता जाता है। यहाँ तक कि बहुत कम आमदनी के होने पर इन पर खर्च होता बन्द-सा हो जाता है।

उपर्युक्त परिणाम जो डाक्टर एन्गिल ने निकाले हैं, वे काफी अग तक ठीक हैं। लम्बे-समय की स्थानों में ऐसा ही देखने में आता है। यह एक साधारण-सी बात है कि जैसे-जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है, वह अपनी आय का अधिक भाग आराम और विलासिता की वस्तुओं पर व्यय करने लगता है। वस्त्र, मकान, ईंधन, आदि पर प्रतिशत खर्च लगभग वही होना रहता है, पर भोजन-सामग्री पर प्रतिशत खर्च कम हो जाता है।

भारतवर्ष में भी अब कुछ समय से पारिवारिक बजटों के अध्ययन की ओर ध्यान दिया जाने लगा है। मेजर जेक, प्रोफेसर फिदले गिराज, आदि ऐसे व्यक्तियों ने इस विषय पर काफी काम किया है। कई प्रान्तों में, विशेषकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बम्बई, बंगाल और बिहार में पारिवारिक बजट अध्ययन के लिए इकट्ठे किए गए हैं। भारतवर्ष में पारिवारिक बजट इकट्ठे करने का कार्य बहुत कठिन है। कारण, मिला-मिला प्रान्तों की जलवायु, रहने-सहन की रीति, सामाजिक प्रथाओं, आदि में बहुत भिन्नता है। दूसरे, लंबा अनेक होने के कारण अपने आय-व्यय का ठीक तरह से हिमाय नहीं रखते। यहाँ तक कि अब खोज करने वाले उनसे प्रश्न पूछने हैं, तो वे अच्छी तरह से उत्तर भी नहीं देते। वे कहते हैं कि जातिर ह्य क्यों पराये व्यक्ति के सामने अपने परिवार का निरुद्ध खोले ?

पारिवारिक बजटों का अध्ययन केवल रुचिकर ही नहीं, बल्कि लाभ-प्रद भी है। उपभोक्ता, समाज-सुधारक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, आदि सभी के लिए पारिवारिक आय-व्यय का अध्ययन बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। घर के मुखिया को इससे पर्याप्त सहायता मिलनी है। उसको यह मालूम हो जाता है कि किन वस्तुओं पर आवश्यकता से अधिक खर्च हो रहा है और किन वस्तुओं पर आवश्यकता से कम। यह मालूम होने पर कि कक्षा फिजूलखर्ची हो रही है, वह अपनी त्रुटियों को आसानी से सुधार सकता है। इस तरह से वह अपने परिवार के लोगों की दृष्टि बढ़ा सकता है।

पारिवारिक बजट का अध्ययन अर्थशास्त्री के लिए विशेष महत्व रखता है। इसके द्वारा उसे किसी देश की आर्थिक दशा का यथोचित ज्ञान हो सकता है। इसकी सहायता से वह लोगों के जीवन-स्तर अथवा रहन-सहन के दर्जे का ठीक-ठीक अनुमान लगा सकता है। उसे यह भी ज्ञात हो जाता है कि किम परिवार में व्यय ठीक तरह से हो रहा है और किस में नहीं। इसके अलावा पारिवारिक बजटों की सहायता से कुछ आवश्यक आंकड़े तैयार किये जाते हैं जो भ्रम और पूँजी के खजानों के शुल्काने में बहुत सहायक होते हैं।

समाज-सुधार और राजनीतिक क्षेत्रों में भी पारिवारिक बजट का विशेष स्थान है। पारिवारिक बजट द्वारा यह पता चल सकता है कि भिन्न-भिन्न श्रेणी के लोगों में टैक्स का भार चठाने की कितनी शक्ति है। किसी वस्तु पर कर लगाने का क्या प्रभाव होगा, इसको मालूम करने के लिए पारिवारिक बजट सर्वोत्तम साधन है। इसके अध्ययन से यह पता चल सकता है कि लोगों की आय में कितनी असमानता है। इसे मालूम करके समाज-सुधारक और राजनीतिज्ञ अपने सुधार के कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

## QUESTIONS

- 1 Explain and illustrate the doctrine of consumer's surplus. How far is it possible to measure it in terms of money? What is its importance?
  - 2 On what principle should a person regulate his expenditure in order to obtain the maximum satisfaction from it?
  - 3 "Economic expenditure involves distributing the income in such a way as to secure the greatest possible amount of satisfaction" Explain and give examples.
- What are family budgets? What purposes do they serve to (a) an householder, (b) an economist, and (c) a social reformer?
- 5 State Engel's Law of Consumption



## व्यय और बचत की समस्या

(Problem of Spending and Saving)

मनुष्य की अनेक आवश्यकताएँ होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए वह उद्योग करता है। उद्योग के फलस्वरूप उसे वृत्ति और सतोप की प्राप्ति होती है। मानव-जीवन की प्रारम्भिक अवस्था में आवश्यकता, उद्योग और सतोप के बीच सीधा सम्बन्ध था। उस समय मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक वस्तु स्वयं ही जुटाता था। जब उसे भूख लगती तो वह स्वयं फल, शाक-पात, मांस, आदि प्राप्त करने का प्रयत्न करता था और उनको खाकर भूख मिटाना था। इसी प्रकार जब उसे घुष, वर्षा, आदि से बचने की आवश्यकता होती तो वह स्वयं गुफा या ओपडी, आदि का प्रबन्ध करता था। अस्तु, उस समय मनुष्य पूर्णतः से स्वावलम्बी था। आवश्यकता के कारण वह उद्योग करता था और उद्योग के फलस्वरूप उसे सीधा सतोप प्राप्त होता था।

किन्तु वर्तमान समय में ऐसा सम्बन्ध बहुत कम देखने में आता है। अब अधिकतर मनुष्य अपनी-अपनी आवश्यकताओं की प्रत्येक वस्तु स्वयं नहीं बनाते। वे अलग-अलग उद्योगों में लग जाते हैं और फिर एक-दूसरे के उद्योग द्वारा बनाई हुई वस्तुओं को खरीद-बेच कर अपनी-अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। माधारणतः आवश्यक वस्तुओं का अदल-बदल या विनिमय वस्तुओं में न होकर मुद्रा या रुपये-पैसे में किया जाता है। मनुष्य को आवश्यक उसके उद्योग के बड़े मुद्रा के रूप में आय या आमदनी मिलती है। इसके द्वारा वह अपनी विभिन्न वर्तमान और भावी आव-

‘श्रवकता-पूर्ति’ की वस्तुओं को खरीदता है जिसके उपयोग अथवा सेवन से उसे तृप्ति और सन्तोष की प्राप्ति होती है। अस्तु, वर्तमान समय में उद्योग और मतोप के बीच पहले जैसे सीधा सम्बन्ध नहीं रहा। अब मनुष्य को उसके उद्योग के बदले में रुपये-पैसे में आमदनी हाँती है जिसके खर्च करने या उपयोग में उसे तृप्ति मिलती है।

### व्यय

(Spendiug)

अभी हम यह चुके हैं कि वर्तमान युग में मनुष्य को अपने उद्योग द्वारा आमदनी हाँती है। इस आमदनी का थोड़ा हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता है। आमदनी का शेष भाग मनुष्य अपनी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की तृप्ति में उपयोग करता है। आमदनी के उस प्रयोग को जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रानु में तृप्ति होती है ‘व्यय’ या ‘खर्च’ कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का एक भाग वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाता है। माधारणतः यह मण्डी में जाकर आवश्यकता-पूर्ति की वस्तुओं को खरीदता है। उसके बदले में वह द्रव्य, रुपये-पैसे देता है। इसी को ‘खर्च’ कहते हैं।

यह पहले कहा जा चुका है कि खर्च करना एक कला है, जिसका दशोचित ज्ञान सबको नहीं होता। किन्तु कुछ लोग ऐसे हैं जिनका यह विचार है कि व्यय करना एक साधारण-सी बात है। इसमें कोई ऐसी पैचीदी बात नहीं जिसे सीखने की मनुष्य को आवश्यकता हो। खर्च करना तो सभी जानते हैं। वे कहते हैं कि यदि मनुष्य के पास पर्याप्त द्रव्य है, तो वह बाजार जाकर आसानी से वस्तुओं को खरीद सकता है, और इस तरह बिना किसी कठिनाई के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है। आय की उचित ढंग से व्यय करने की कला सबको मालूम नहीं। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें यह नहीं मालूम कि आय को कब और किस प्रकार खर्च करना चाहिए जिसमें अधिकतम

तृप्ति प्राप्त हो। कमी तो वे कजूम बन बैठते हैं और कमी अपव्ययी होकर द्रव्य को फिजूल कामों में फुवने लग जाते हैं। यही कारण है कि बराबर खर्च करने पर भी कुछ को अधिक सतोप मिलता है, और कुछ को कम।

मनुष्य को जो तृप्ति और सतोप अपनी आय के व्यय से मिलता है, वह दो बातों पर निर्भर है (१) व्यय का ढग, और (२) वस्तुओं की कीमत।

(१) व्यय का ढग—कुछ व्यक्ति धन के व्यय में निपुण होते हैं। उनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनकी सहायता से उन्हें अपने व्यय से अधिकतम तृप्ति मिलती है। यह प्रश्न उठ सकता है कि कैसे उन्हें दूसरों की अपेक्षा द्रव्य के व्यय से अधिक तृप्ति प्राप्त होती है। इसके कई कारण हैं जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं —

(क) वे अपनी आवश्यकताओं को भली भाँति समझते हैं। वे यह जानते हैं कि उन्हें ठीक-ठीक किम वस्तु की जरूरत है। अन्तु, दुकानदार के बहकाने अधया जल्प लोगों की देखा-देखी में वे नहीं जाते। वे उन्हीं वस्तुओं को खरीदते हैं जिनसे अधिकतम तृप्ति मिलने की सम्भावना होती है।

(ख) वे वस्तुओं के गुण की परीक्षा करने में विशेषज्ञ होते हैं। उन्हें वस्तुओं की खूब पहचान होती है। बाहरी दिखावट अथवा रंग-रूप से वे आकर्षित नहीं होते। दिखावटी वस्तुएँ खराब होने के साथ-साथ कम टिकाऊ भी होती हैं।

(ग) वे सौदा करने में बहुत कुशल होते हैं। उनमें सौदा करने का गुण होता है जिससे वे दूसरों की अपेक्षा कम मूल्य पर वस्तुओं को खरीद लेते हैं।

(घ) उनको यह भी ज्ञान होता है कि किम स्थान पर अच्छी और सस्ती वस्तुएँ मिलती हैं। वहाँ तक आने-जाने का कष्ट उठाने के लिए वे सदैव तैयार रहते हैं।

(८) वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के बीच उचित तुलना करके यह निश्चय करने में वे कुशल होते हैं कि किन आवश्यकताओं की पूर्ति पहले की जाय। दूसरे शब्दों में उन्हें खर्च करते समय भविष्य का पूरा-पूरा खयाल रहता है।

इन सब कारणों से सबको एक समान खर्च करने पर भी एक-सा सतोष प्राप्त नहीं हो पाता।

(२) वस्तुओं का मूल्य—उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त मनुष्य को जो तृप्ति अपनी आय के व्यय से प्राप्त होती है, वह काफी अतः तब उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य पर निर्भर करता है जिन पर वह अपनी आय को खर्च करता है। यदि वस्तुओं के मूल्य अधिक हैं, तो मनुष्य अपनी आय से कम बचत खरीद सकेगा। फलतः उसकी तृप्ति भी कम होगी। इसके विपरीत यदि वस्तुओं का मूल्य कम है, तो वह उसी आय में अधिक बचत खरीद सकेगा। अतएव उसे अपनी उसी आय से पहले से अधिक तृप्ति प्राप्त होगी।

### व्यय का सामाजिक पहलू

(Social aspect of Spending)

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जो कुछ वह करता है, उसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सारे समाज पर पड़ता है। यदि वह अच्छा काम करता है, तो उसकी और समाज दोनों की उन्नति होगी। इसी तरह उसके खर्च का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है और दूसरों का उस पर। समाज की उन्नति काफी अतः तक लोगों के व्यय करने के रूप पर निर्भर है। यदि व्यय का दग अच्छा है, तो समाज का कल्याण होगा, अन्यथा हानि। हमारे खर्च का प्रभाव धनोत्पत्ति और अन्य उप-भोग्यताओं पर बहुत पड़ता है। यह तो सभी जानते हैं कि उत्पत्ति मांग पर निर्भर होती है। जिन वस्तुओं की मांग होती है, उन्हीं की उत्पत्ति की जाती है। उत्पत्ति के लिये भूमि, पूँजी, श्रम और अन्य कई साधनों की

आवश्यकता पड़ती है। जिस वस्तु पर हम खर्च करने हैं, उसकी मांग पैदा हो जाती है। फिर उसकी उत्पत्ति के लिए लोग साधन जुटाने लग जाते हैं। धीरे धीरे उस वस्तु की उत्पत्ति की जान लगती है। यदि वह बिलास अथवा ऐश-आराम की वस्तु है जिससे उपभोगिता की काय-कृशालता गिर जाती है तो उसका फल केवल उपभोगिता को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। कारण जब उस वस्तु की मांग है तो उसकी उत्पत्ति अवश्य होगी। देश की पूँजी और धन का एक भाग इस ओर खिंच जायगा जिसका प्रयोग हमारे आवश्यक और लाभदायक उद्योग क्षेत्रों में किया जा सकता था। इसका परिणाम यह होगा कि आवश्यक और निपुणतादायक पदार्थों की उत्पत्ति घट जायगी या उतनी न होगी जितनी कि हो सकती थी। ऐसा होने से इन वस्तुओं की कीमत बढ़ जायगी और फिर वाधारण लोग इन वस्तुओं का उचित मात्रा में भवनों न कर सकेंगे। फलस्वरूप उनकी योग्यता और उत्पादन क्षमता गिर जायगी। इससे भविष्य में उत्पत्ति और भी कम और असंतोषजनक होगी। यह दुष्चक्र इस प्रकार चलता रहेगा जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों को ही हानि होगी।

अस्तु सच का सामाजिक पहलू भी होता है। समाज को उत्तरी और गुप्त-गमूडि के लिए दृढ़ बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि लोग अपनी आमदनी को किस ढंग से खर्च करते हैं।

यही कारण है कि आजकल सभी सम्य देशों में सरकार लोगों को खर्च करने की पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं देती। सावजनिक हित के लिए सरकार उपभोग-जनन में अनेक रोक-टोक लगाती है, उस पर नियन्त्रण रखती है। उदाहरणार्थ नशीली वस्तुएँ हर समय और हर स्थान पर नहीं बची जा सकती। उनके बचन के लिए लोगों को सरकार से आज्ञा पत्र लेना पड़ता है। वे नियत समय और स्थान पर ही बची जा सकती हैं। ठीक इसी प्रकार खाद्य पदार्थों का भी निरीक्षण होता है और इस बात के लिए निरोधक

निवृत्त किये जाते हैं जिससे जनता को शुद्ध और साफ भोजन-सामग्री मिल सके।

बचन

(Saving)

साधारणतया हम अपनी कुल आय को वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में ही खर्च नहीं कर देते। वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय हम अपनी भावी आवश्यकताओं का भी खयाल रखना पड़ता है। इसलिए हम अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचा लेते हैं जिससे आगे चलकर आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई बाधा न पड़े। इस बचो हुई रकम को कुछ लोग तो जमीन में गाड़ देते हैं और कुछ उत्पादन-कार्यों में लगाते हैं। मुरखिन अथवा गढ़े हुए धन को 'बचत' नहीं कहते। बचत से अभिप्राय उस संचित धन में है जो और घनोत्पादन के काम में जाता है। इससे पूँजी का निर्माण होता है, जिसका उत्पादन-क्षेत्र में, विशेषकर आधुनिक युग में, बहुत महत्व है। पूँजी की सहायता से घनोत्पत्ति की मात्रा और शक्ति बहुत बढ़ जाती है। अतः, बचन द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप में नहीं बल्कि परोक्ष रूप में होती है। इससे दृष्टित वस्तुओं की उत्पत्ति में सहायता मिलती है और आगे चलकर आवश्यकताओं की पूर्ति करने में काम आती है।

मनुष्य कई कारणों से धन-मचय करने ह जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन आगे किया जायगा। यहाँ केवल इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि बचत में व्ययित और समाज दोनों को बहुत लाभ पहुँचता है।

व्यय और बचत का सम्बन्ध

(Relation of Spending and Saving)

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है व्यय और बचत धन के प्रयोग के दो रूप हैं। दोनों का उद्देश्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। व्यय में वर्तमान आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप में पूर्ति होती है

और बचत से भायी आवश्यकताओं की। व्यय और बचत दोनों ही जीवन में प्रगति और उन्नति के लिए आवश्यक हैं। पर कभी-कभी इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि दोनों में से कौन अधिक आवश्यक अथवा महत्वपूर्ण है। कुछ व्यय को अधिक आवश्यक और लाभप्रद मानते हैं और कुछ बचत को। मक्षेप में, हम यहाँ यह विचार करेंगे कि दोनों पक्ष वालों की बातें कहाँ तक और कितनी ठीक हैं।

कुछ लोगों का कहना है कि अधिक खर्च करने से ही समाज की उन्नति हो सकती है। अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए वे इस प्रकार दलील देते हैं। वे कहते हैं कि यदि लोग अधिक खर्च करेंगे तो वस्तुओं की माग में वृद्धि होगी। इससे उत्पत्ति बढ़ेगी और जब उत्पत्ति में वृद्धि होगी तो पूँजी, भूमि और अन्य साधनों की अधिक काम मिलने लगेगा। इनके फलस्वरूप बेकारी की समस्या हल हो जायगी और श्रमिकों की मजदूरी बढ़ेगी। व्यापारियों और उद्योगपतियों को भी अधिक लाभ होगा। इस तरह हर क्षेत्र में उन्नति होगी। लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा हो जायगा, और देश की आर्थिक दशा सुधर जायगी। ये बातें कहाँ तक ठीक हैं, यही हमें देखना है। उत्पत्ति बढ़ाने के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। पूँजी की मात्रा तभी बढ़ सकती है जबकि लोग अपनी आय का काफी भाग बचायें। यदि लोग अपनी पूरी आय वर्तमान आवश्यकताओं की ही पूर्ति में लगा देंगे तो फिर बचत कहाँ से हो सकेगी। बचत न होने पर भविष्य में पूँजी का निर्माण कैसे होगा। पूँजी के अभाव में उत्पत्ति में वृद्धि लाना सम्भव न होगा। इसका फल यह होगा कि देश में बेकारी, गरीबी, आदि अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याएँ फैलेगी और देश की उन्नति रुक जायेगी। अस्तु, यह सोचना भूल है कि अत्यधिक खर्च करने से व्यक्ति और समाज की उन्नति होगी।

इसके विपरीत कुछ लोग यह कहते हैं कि अधिक बचत करने से व्यक्ति और समाज दोनों को लाभ पहुँचेगा। अधिक बचत होने पर पूँजी

की मांग बढ़ेगी । इसकी सहायता से उत्पत्ति बड़े पैमाने पर की जा सकेगी । उत्पादन में वृद्धि होने से लोगों का जीवन-स्तर ऊपर उठेगा और पूँजी की मांग बढ़ेगी । इस तरह उत्पत्ति का यह चक्र बराबर चलता रहेगा । किन्तु प्रश्न यह है कि उत्पादित वस्तुओं को खरीदेगा कौन ? जब लोग खर्च कम करेंगे तो वस्तुओं की मांग कहाँ से होगी ? कैसे उनका निपटारा होगा ? चाहकों की कमी होने के कारण वस्तुएँ बाँटामे में ही पड़ी रहेंगी । उत्पत्तिकर्ताओं को इसमें बहुत हानि होगी । फलस्वरूप वे उत्पत्ति को कम करेंगे । उत्पत्ति के घटने से लोग बेकार हो जायेंगे । उनके आर्थिक जीवन को गहरा धक्का लगेगा । साथ ही समाज की भी उत्पत्ति रुक जायगी ।

इसमें यह स्पष्ट है कि व्यय और वचत दोनों ही आर्थिक उत्पत्ति के लिए आवश्यक हैं । जिस प्रकार दो पैर मनुष्य के चलने के लिए आवश्यक हैं, उसी प्रकार आर्थिक जीवन के लिए व्यय और वचत दोनों के बीच तालमेल होना परमावश्यक है । खर्च कम होने से वस्तुओं की मांग कम हो जायगी और इसमें बेकारी बढ़ेगी । इसके विपरीत वचत कम होने से पूँजी की कमी होगी जिससे उद्योग-धन्धों और व्यापार की उत्पत्ति में रुकावट पहुँचेगी । इसलिए खर्च और वचत दोनों के बीच एक प्रकार के समुल्लस का होना आवश्यक है ।

## विलासिता की समस्या

(Problem of Luxuries)

संक्षेप में, अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि समाज की दृष्टि में विलासिता की वस्तुओं पर क्या गया खर्च लाभप्रद है अथवा हानिकारक । यह एक टेढ़ी समस्या है । इस पर विद्वत्-मिश्र रायें प्रकट की जाती हैं । कुछ लोगों का कहना है कि विलासिता की वस्तुओं का उपभोग न्यायपूर्ण है । हमने मनुष्य सम्म बन जाता है और समाज की भी उत्पत्ति होती है । किन्तु दूसरे पक्ष वाले बिल्कुल इससे उल्टा कहते हैं । उनके कथना-



नुसार विलासिता के पदार्थों पर बिया गया खर्च निम्न है। इससे मनुष्य विलासी और आलसी हो जाते हैं। उनकी कार्यकुशलता गिर जाती है और इस कारण समाज की भी अव्यवस्था होती है। इसके पहले कि हम इस विषय पर अपनी राय प्रकट करें यह जान लेना आवश्यक है कि विलासिता के पक्ष और विपक्ष में क्या-क्या दलीलें पेश की जाती हैं, और वे कहा तक ठीक हैं।

विलासिता की वस्तुओं का उपभोग निम्नलिखित बातों द्वारा न्याय-मूल और हितकर बनाया जाता है —

(१) विलासिता की वस्तुओं के उपभोग में मांग बढ़ती है। इससे उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन मिलता है। इसके फलस्वरूप रोजगार में उन्नति होती है और अनेक बेकार लोगों को काम मिलता है। इस प्रकार बेकारी को दूर करने में इससे बड़ी सहायता मिलती है।

(२) विलासिता की वस्तुओं को तैयार करने में ऊँचे दर्जे के कलाकार, कुशल और निपुण श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अतएव विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करने से कला, कुशल-धर्म और सुसंस्कृति में वृद्धि होगी।

(३) इससे जाविज्जार-श्रेष्ठ में प्रगति होती है जिससे देश के प्राकृतिक और अन्य साधनों को उचित ढंग में काम में लाया जा सकता है। इससे व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण होगा।

(४) इससे धन-वितरण की असमानता भी कम हो जाती है। विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करने से धनवानों के ढव्य का कुछ हिस्सा गरीबों के पास पहुँच जाता है जो उसे अधिक आवश्यक कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। यदि विलासिता की वस्तुओं का उपभोग न हो, तो धनवानों के पास कुछ धन व्यर्थ ही पड़ा रहेगा। इससे समाज को हानि होगी।

(५) विलासिता की वस्तुओं के प्रयोग से जन-संख्या में अत्यधिक वृद्धि नहीं होने पाती। कारण, इन वस्तुओं के प्रयोग से जीवन-स्तर,

में उन्नति होती है। और अब तक ऊंचे रहन-सहन वाले व्यक्ति को यह विश्वास नहीं हो लेता कि वे अपनी सन्तान का उनी ठग से पालन-पोषण कर सकेंगे, तब तक वे विवाह नहीं करते, बच्चे पैदा नहीं करते। इस प्रकार जन-संख्या में अत्यधिक वृद्धि नहीं होने पाती।

(६) विलासिता की वस्तुओं के सेवन से जीवन की नीरसता दूर हो जाती है और मनुष्य को नई स्फूर्ति और कर्म-शक्ति प्राप्त होती है। निश्चय ही फिर वह व्यक्ति अधिक उन्नति कर सकेगा। और यह तो सभी जानते हैं कि समाज की क्षमता, शक्ति और उन्नति व्यक्तियों पर निर्भर है।

संक्षेप में, विलासिता द्वारा व्यापार, उद्योग, उत्पादन, आदि को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है। यह उन्नति का चिह्न है। इससे गानव-जीवन अधिक गम्भ, सुखमय और समृद्धिवाली बन सकती है।

विलासिता के विषयी उपर्युक्त बातों को ठीक नहीं मानते। वे विलासिता के विनाश निम्नलिखित तर्क पेश करते हैं —

(१) यह सोचना भूल है कि विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करने से व्यापार और उद्योग-धन्धों की उन्नति होती है। अव्यय से पूँजी की वृद्धि कम हो जाती है जिससे उत्पादन-कार्य को भारी क्षति पहुँचती है। यही नहीं, यदि विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन में देश के सीमित साधनों को लगाया जायगा, तो अन्य आवश्यक स्थानों पर उन साधनों की कमी पड़ेगी। इस कारण अपेक्षाकृत अधिक आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन कम हो सकेगा। इससे निश्चय ही समाज की हानि होगी।

(२) जिस देश में अधिकतर लोगों को मर पेट भोजन भी नहीं मिल पाता, वहाँ पर विलासिता की वस्तुओं पर किया गया खर्च किमी तरह न्यायसुबन नहीं हो सकता। यह कहा तक ठीक माना जा सकता है कि एक ओर जो लोग भूख के मार मौत के भिन्न हो रहे हैं और दूसरी ओर थोड़े-से लोग विलासिता की वस्तुओं के साथ गुलछरें उड़ाते हैं।

ऐसा होने से देश में अशान्ति की आग फैल जाती है और अनेक आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक समस्याएँ उपस्थित होने लगती हैं जिनसे आसानी से छुटकारा नहीं मिल पाता ।

(३) धनी लोगों का विलासिता के पदार्थों में किया गया खर्च अनुचित है, परन्तु गरीब लोगों का इन पदार्थों में किया गया खर्च और भी अधिक अनुचित है । कारण, गरीब लोग बहुधा जीवन-रक्षक और निपुणतादायक पदार्थों में कमी करके विलासिता की वस्तुओं को खरीदते हैं । इससे उनके चरित्र और स्वास्थ्य दोनों ही गिर जाते हैं । इसका फल उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे समाज को भुगतना पड़ता है ।

(४) विलासिता की वस्तुओं में कला, आविष्कार, आदि की उन्नति होती है, पर यह समझना भूल है कि आवश्यक अथवा निपुणतादायक वस्तुएँ कला की उन्नति में कम सहायक होती हैं । कभी-कभी विलासिता की वस्तुओं को बनाने में केवल साधारण धम की ही आवश्यकता पड़ती है । इसलिए यह आवश्यक नहीं कि जितने भी आविष्कार होते हैं, वे सभी विलासिता की वस्तुओं के सेवन के ही कारण होते हैं ।

इस तरह की अनेक बातें विलासिता के पक्ष और विपक्ष में कही जाती हैं । दोनों पक्षों की बातें कुछ अस्त राक ठीक हैं । विलासिता की कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जो नैतिक या सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं होती । उनके उपभोग में मनुष्य का स्वास्थ्य गिर जाता है, चरित्र बिगड़ जाता है, और कार्य-कुशलता में भी कमी आ जाती है । इन वस्तुओं पर किये गये खर्च को किसी भी दृष्टिकोण से व्यापयुक्त नहीं बताया जा सकता । निम्न इससे यह निष्कर्ष निकालना ठीक न होगा कि विलासिता की सभी वस्तुओं का उपभोग बन्द कर देना चाहिए । ऐसा करने से उन्नति में रुकावट पड़ेगी । आज जो विलासिता की वस्तु मानी जाती है, कल वही आवश्यक पदार्थ हो सकती है । जतएव हर प्रकार की विलासिता को बन्द करना ठीक न होगा । विलासिता की कुछ वस्तुएँ हानिरहित हैं । उनके उपभोग से कोई हानि न होगी, बल्कि लाभ ही होगा ।

## QUESTIONS

"Spending is more important than saving for the material welfare" Comment

Is it of any consequence to society how an individual spends his income ? Should society interfere with a man's liberty in spending money ?

What are luxuries ? Is the expenditure on luxuries justifiable from social point of view ?

Examine the various arguments that are put forward in favour of and against the use of luxuries

## अध्याय १४

### जीवन-स्तर

(Standard of Living)

आवश्यकताओं की विशेषताओं पर विचार करते समय यह कहा गया था कि मनुष्य की कुछ आवश्यकताएँ ऐसी हैं जो एक बार तृप्त हो जाने पर भी बार-बार उत्पन्न होती रहती हैं। उनके जन्म और तृप्ति का चक्र सदैव चलता रहता है। जब मनुष्य अपनी किसी आवश्यकता की पूर्ति पर्याप्त समय तक बार-बार करता रहता है, तो उस आवश्यकता की तृप्ति करने का उसका स्वभाव-सा पड़ जाता है। धीरे-धीरे इस प्रकार की आवश्यकताएँ उस व्यक्ति की आदतों में परिवर्तित होनी जाती हैं। आदत पड़ जाने के कारण वह उन आवश्यकताओं को आसानी से छोड़ नहीं पाता। यही नहीं, बिना उनकी पूर्ति के उसे कष्ट होता है, उसकी योग्यता-क्षमता में फर्क पड़ जाता है। इस कारण वे उसके प्रतिदिन के साधारण जीवन का एक आवश्यक अंग बन जाती हैं। 'जीवन-स्तर' (standard of living) का आशय मनुष्य की इन्हीं आवश्यकताओं से है जिनकी तृप्ति का वह आदी हो जाता है। इसी बात को हम तरह-सी कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के 'जीवन-स्तर' का आशय उन वस्तुओं में है जिनके उपभोग का उसका स्वभाव पड़ जाता है।

सबका जीवन-स्तर अथवा रहन-सहन का दर्जा एक समान नहीं होता। प्रत्येक काल, देश और व्यक्ति के जीवन-स्तर का दर्जा भिन्न भिन्न होता है। अमरीका-निवासियों का जीवन-स्तर भारतवासियों के जीवन-स्तर की अपेक्षा आज बहुत अधिक ऊँचा है। और जो जीवन-स्तर अम-

रीका में सौ वर्ष पूर्व था, वह वहाँ के वर्तमान जीवन-स्तर की तुलना में कहीं अधिक नीचा था । इसी प्रकार एक ही समय और देश में भिन्न-भिन्न श्रेणी के लोगों का जीवन-स्तर अलग-अलग हो सकता है ।

किसी व्यक्ति का जीवन-स्तर मुख्यतः दो बातों पर निर्भर होता है । एक तो उस व्यक्ति की आय, और दूसरे उसके खर्च करने का ढंग । सामान्य बोलचाल में तो ऊँचे जीवन-स्तर का अर्थ यह होता है कि मनुष्य अपनी आय को अधिकतर खाराम तथा विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करता है । अर्थात् अधिक खर्चाले रहन-सहन को जीवन-स्तर का ऊँचा दर्जा माना जाता है । जो अधिक खर्च नहीं करते, उनके जीवन-स्तर का दर्जा नीचा समझा जाता है । किन्तु अर्थशास्त्र में ऊँचे या नीचे जीवन-स्तर का यह आशय नहीं होता । अर्थशास्त्र के अनुसार जीवन-स्तर के ऊँचे दर्जे का यह अर्थ है कि मनुष्य अपनी आय को इस विधि से खर्च करे जिससे उसकी धारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक उन्नति हो, उसकी कार्य-क्षमता, योग्यता-क्षमता में वृद्धि हो । जब तक कोई व्यक्ति आय को इस ढंग से खर्च नहीं करता जिससे उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो, तब तक उसके रहन-सहन का दर्जा ऊँचा नहीं माना जाता । केवल अधिक खर्च करना ही ऊँचे जीवन-स्तर का चिह्न नहीं है । यदि किसी व्यक्ति को आय अधिक है, तो यह कोई आवश्यक बात नहीं कि उसके रहन-सहन का ढंग भी ऊँचा हो । सम्भव है वह अपनी आय को उचित ढंग से न खर्च करता हो । असु, किसी व्यक्ति के जीवन-स्तर का दर्जा मापने के लिए हमें यह देखना होगा कि उसकी कितनी आय है, उसके व्यय का ढंग कैसा है, वह किन-किन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा उनकी पूर्ति का उसकी कार्य-कुशलता पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ता है ।

### भारतवासियों का जीवन-स्तर

(Standard of Living of Indians)

भारतवासियों का औसत जीवन-स्तर बहुत ही नीचा और असतोषजनक

है। इसके कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण यहाँ का गरीबी है। भारत-वासी भयंकर गरीबी के बोझ से घुरी तरह दबे हुए हैं। यहाँ के अधिकांश लोगों की आमदनी इतनी थोड़ी है कि जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो सकती। दूसरे महायुद्ध के पहले एक भारतीय की औसत सालाना आमदनी मुद्रिकल से ६५ रुपये थी जबकि एक अमेरिकन की आमदनी १४०६ रुपये, कनेडा निवासी की १०३४ रुपये, अंग्रेज की ९८० रुपये, और एक जर्मन की ६०३ रुपये थी। अनुमान है कि अब देश की व्यक्तिगत वार्षिक आय लगभग २६५ रुपये है। यह वृद्धि नई आमदनी (money income) में ही हुई है, वास्तविक आमदनी (real income) में नहीं। वास्तविक आमदनी मालूम करने के लिए हमें चीजों की कीमतों को देखना होगा। पिछले कई सालों से कीमतें बराबर ऊपर चढ़ती रही हैं जिसके कारण रुपये की कय-शक्ति पहले से बहुत गिर गई है। यदि एक ओर औसत आमदनी ६५ रुपये से बढ़कर २६५ रुपये हो गई है तो दूसरी ओर कीमतें भी कई गुना बढ़ गई हैं। अस्तु, 'वास्तविक' आमदनी में कोई वृद्धि नहीं हुई, बल्कि कई अर्थशास्त्रियों के अनुमान के अनुसार इसमें कुछ घटो ही हुई है। जब लोगों की आमदनी इतनी कम है, तो उनका जीवन-स्तर क्या हो सकता है, इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। कुल माल को यदि केवल भोजन पर ही खर्च किया जाय तो भी भर पेट और उचित प्रकार का भोजन मिलना कठिन है। फिर भला किस प्रकार अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति मज्जी-भाति हो सकती है।

देश की गरीबी का मुख्य कारण यह है कि यहाँ की अर्थ-व्यवस्था पिछड़ी हुई और अर्ध-विकसित अवस्था में है। ऐसा होने से देश के मानवीय और प्राकृतिक साधनों का उचित ढंग से उपयोग नहीं हो पाता। फलस्वरूप उत्पादन की मात्रा कम है और फिर उसका बटवारा भी ठीक-ठीक नहीं होता। साथ ही देश की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है जिसके कारण गरीबी का रोग और बढ़ता जा रहा है।

निर्धनता के अतिरिक्त दूसरा कारण, जिसके फलस्वरूप भारत-वासियों का जीवन-स्तर नीचा है, यह यह है कि यह लोगो का खर्च करने का ढंग ठीक नहीं है। कुछ अवसरों पर लोग अपनी शक्ति से अधिक खर्च करते हैं। पुराने रीति-रिवाजों के पालन करने में वे अपने आपको एक तरह में लुटा देते हैं। चाहे उन्हें कितनी सुसीबतो का सामना करना पड़े, वे शादी, आदि अवसरों पर खूब खर्च किये बिना नहीं मानते। वे खर्च की उपयोगिता और अपनी शक्ति पर पूरा-पूरा ध्यान नहीं देते। बहुत कुछ यह शिक्षा की कमी के कारण है। इससे उनका जीवन-स्तर और भी गिर जाता है।

उस सम्बन्ध में प्रायः यह पूछा जाता है कि जीवन-स्तर की प्रवृत्ति किस ओर है। क्या यहाँ के निवासियों का नीचा जीवन-स्तर समय के साथ-साथ गिरता रहा है, या उसमें कुछ उन्नति हो रही है? कुछ लोग यह प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं कि भारतवासियों का जीवन-स्तर ऊँचा हो रहा है। इस बात की पुष्टि के लिए वे हमारा ध्यान शहरों की ओर आकर्षित करते हैं जहाँ पर पक्की और बड़ी-बड़ी इमारतें, लम्बी-चौड़ी सीमेंट की सड़क, मोटर, वाणी व तरह-तरह के खेल-तमाशों के साधन गजर आते हैं। शहरों में आराम तथा विलासिता की वस्तुएँ अधिक मात्रा में बाहर से आने लगी हैं जिससे यह पता चलता है कि इन वस्तुओं का उपयोग पहले से अब अधिक हो रहा है। रेसमी और ऊनी वस्त्र, तेल, गन्धक, चाय, मिश्रित, सोडावाटर, आदि वस्तुओं के उपयोग में काफी वृद्धि हुई है। धीरे-धीरे लोग शिक्षित और सम्पन्न बनते जा रहे हैं। शहरों और कल-कारखानों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। इन सब बातों में कुछ लोग यह सिद्ध करना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का रहन-सहन का दर्जा नमश ऊँचा होता जा रहा है।

यह तो ठीक है कि शहर के रहने वालों का रहन-सहन देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि लोगों का जीवन-स्तर नीचा है अथवा नीचे



गिर रहा है । पर शहरो में रहने ही कितने लोग हैं ! मुस्लिम में १३ प्रतिशत, बाकी सब गावों में रहने हैं । अतएव शहरो को देखकर भारतवर्ष के असली रूप का पता नहीं चल सकता । यदि हम भारतवर्ष का ग्राम-विश्व चित्र देखना चाहते हैं, तो हमें गावों पर दृष्टि डालनी पड़ेगी जहाँ लगभग ८७ प्रतिशत लोग रहते हैं । इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन-स्तर की प्रवृत्ति किस ओर है, अर्थात् जीवन-स्तर गिर रहा है या ऊँचा हुआ है ।

गावों की दशा किसी से छिपी नहीं है । वहाँ की कीचड़ में सनी हुई सड़के, टूटे-फूटे कच्चे मकान, अर्धनग्न और भूख से पीड़ित लोगों की दशा किसे नहीं मालूम । सड़प में, हम यहाँ कुछ ही बातों पर विचार करेंगे जिनके आधार पर यह निश्चय किया जा सकता है कि भारत-वासियों का जीवन-स्तर किस ओर है ।

सर्व प्रथम गाव के मकानों पर ही दृष्टि डालिए । लगभग हर गाव में लोगों के कच्चे और पृथ के मकानों को छोड़कर एक दो पुरानी टूटी-फूटी पक्की सराय, घर्मशालाएँ और कुएँ दिखाई पड़ेंगे । ये सब जनता के हित के लिए बनाये जाते हैं । इसमें पता चलता है कि पहले लोगों की आय इतनी होती थी कि वे सार्वजनिक हित के लिए इमारतें बनवा सकते थे । निन्तु आज लोगों की आय इतनी कम हो गई है कि वे अपने पूर्वजों की वनाई हुई इमारतों की मरम्मत तक नहीं करवा सकते, नई इमारतें बनवाने की बात तो दूर रही । जब वे अपने मकानों की ही देखभाल करने में असमर्थ हैं, तो क्या किस प्रकार वे परोपकार के लिए घर्मशालाएँ, कुएँ बनवा या सुधरवा सकते हैं । इसमें यह ज्ञात होता कि समय के साथ-साथ लोगों की वास्तविक आय गिरती रही है, और इस कारण उनका जीवन-स्तर भी ।

इसके अतिरिक्त हम हर तरफ यह सुनते हैं कि गाव वाले बड़े अपथ्ययी होने हैं । वे अपने धन को उचित ढंग से खर्च नहीं करते । सादी-

विवाह, आदि अवसरों पर वे बहुत फिजूल खर्च करते हैं। इस बात के लिए उन्हें बहुत धिक्कारा जाता है। यदि एक धनी व्यक्ति शादी के अवसर पर उतना या उससे अधिक खर्च करता है तो हम कुछ भी नहीं कहते। किन्तु अब गांव का एक गरीब मादमी इस तरह से खर्च करता है, तो उसकी ओर हम तुरन्त उगली उठाते हैं, उसे बुरा-भला कहते हैं। कारण, उसकी इतनी आय नहीं कि उस खर्च की वीक्ष सभाल सके। इस खर्च के लिए उसे भूभाग के सामने हाथ पसारना पड़ता है, जिसके चंगुल से यह जीवन भर नहीं निकल पाता। पर प्रश्न यह है कि सामाजिक तथा धार्मिक अवसरों पर इतना खर्च करने की प्रथा कैसे आरम्भ हुई जिसके कारण आज गांव वालों का इतना सुनना पड़ता है। यदि उनके पूर्वजों को भी इतनी ही आय होतो जितनी आजकल लोगों की है, तो उम्र तरह की खर्चीली प्रथाओं की नींव कभी नहीं पड़ सकती थी। इनका चलन इस कारण हुआ कि पूर्वजों की आय पर्याप्त थी। जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद उनके पास इन अवसरों पर खर्च करने के लिए द्रव्य बच रहता था। पर आज वसा बैसी अच्छी नहीं रही। रीति-रस्म आसानी से नहीं छोड़ जा सकत। कारण, मनुष्य अपनी आदतों का दास है। अतः पुराने समय के रीति रिवाज अब भी चल रहे हैं। किन्तु आय कम हो जाने के कारण लोगों में उनको पूरा करने की शक्ति नहीं रही। यही कारण है कि अब आज भी लोग अपनी गिरा हुई आय को पुराने रीति रिवाजों के पालन करने में खर्च करते हैं तो उन्हें दोषी ठहराया जाता है। क्या इससे यह गुता नहीं चलता कि प्रमदा लोगों का जीवन-स्तर नीचे की ओर ही रहा है ?

इस बात की पुष्टि के लिए एक और बात पर विचार किया जा सकता है। भारतवर्ष की नारियों को सोने चांदी के आभूषणों से बहुत प्रेम है। कुछ समय पहले गांवों की स्त्रियां गहनों से लदी रहती थी। पर आज उनके शरीर पर एक-आध गहने मुश्किल से दिखाई पड़ते

है। क्या उनको अब गहने अच्छे नहीं लगने ? क्या मनुष्य उनकी इस इच्छा की पूर्ति करना नहीं चाहते ? ऐसी बात नहीं है। वास्तव में वे लाचार हैं। उनकी आय बहुत कम हो गई है। प्रतिदिन की माभारण आवश्यकताओं की भी तृप्ति करवा उनके लिए कठिन हो गया है। फिर भला गहने कहा से बनाये जाय ? अन्तर पुराने आभूषणों को बेचने तक की नीबत या पठती है, तब कहीं मुश्किल से उनका काम चल पाता है। दूसरे शब्दों में, उनकी आय इतनी कम हो गई है कि जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो सकती। इस काम के लिए उन्हें पूँजी की शरण लेनी पड़ती है या भेठ-साहूकारों से उधार लेना पड़ता है। क्या इसे ऊँचे जीवन-स्तर का चिह्न माना जा सकता है ?

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि भारतवासियों का जीवन-स्तर समय के साथ और भी असतोषजनक बन गया है। इसमें संदेह नहीं कि देश की आन्तरिक शान्ति और पाश्चात्य सम्प्रदाय के समर्थ स जनता के हृदय में कुछ नवीन विचारों का समावेश हुआ है और कुछ लोगों की आय में भी वृद्धि हुई है। इस तरह पाँच-दस फीसदी लोगों का जीवन-स्तर अवश्य ऊँचा हो गया है। किन्तु पाँच-दस फीसदी आदिमियों के रहन सहन के दर्जों के ऊँचे होने से ही किसी देश के रहन-सहन का दर्जा उन्नत नहीं माना जा सकता। इसमें यह अनुमान लगाना कि औसत जीवन-स्तर ऊँचा होगा जा रहा है, सरासर भूल है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार यहाँ के लोगों का जीवन स्तर उठाने में प्रयत्नशील है। इसके लिए पञ्चवर्षीय योजना के आधार पर काम हो रहा है और पिछले तीन-चार वर्षों में इस काम में कुछ सफलता भी मिली है। लेकिन गरीबी दूर करके जीवन-स्तर को ऊपर उठाने का काम ऐसा नहीं है जो दो-चार वर्षों में ही पूरा हो सके। इस काम में काफी समय लगेगा। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि योजना के आधेन काम होता रहा तो यहाँ के लोगों का जीवन-स्तर ऊपर उठने लगेगा।

## QUESTIONS

1. What is meant by the phrase 'standard of living' ?  
On what factors does it depend ?
2. Write an essay on the standard of living in India
3. How can you show that standard of living in India has been steadily going down ?
4. What is the implication of 'high' and 'low' standard of living ? Why is standard of living in India low ?

उत्पत्ति

(Production)

## अध्याय १५

### उत्पत्ति और उसके साधन

#### (Production and its Factors)

उपयोगिता सम्बन्धी नियमों और समस्याओं पर विचार करते समय यह मान लिया गया था कि उपभोग के लिए जो वस्तुएं उपलब्ध हैं, वे कीमत देकर बाजार से खरीदी जा सकती हैं। पर इनके पहले कि उपभोग के लिए बाजार में वस्तुएं उपलब्ध हो सकें, हमें उनकी उत्पत्ति करनी होगी। इस सम्बन्ध में यह ज्ञान लेना आवश्यक है कि 'उत्पत्ति' कहते किसे है, उत्पादन-कार्य में किन साधनों की आवश्यकता होती है, उन साधनों की क्या-क्या विशेषताएं हैं, और उत्पत्ति के क्या नियम हैं? इस और अगले कुछ अध्यायों में इन्हीं बातों पर विचार किया जायगा।

### उत्पत्ति का अर्थ

#### (Meaning of Production)

साधारण बोलचाल में उत्पत्ति का आशय भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में होता है। किसान, बडई, कुम्हार, आदि को उत्पादक कहा जाता है क्योंकि इनके उद्योग द्वारा भौतिक वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, जैसे अन्न, मेज, कुर्सी, बर्तन, आदि। डाक्टर, वकील, अध्यापक, घरेलू नौकर आदि जैसे व्यक्तियों को साधारणतः उत्पादक नहीं माना जाता क्योंकि इनके उद्योग का सम्बन्ध भौतिक वस्तुओं की उत्पत्ति से नहीं होता। पर प्रश्न यह उठता है कि 'उत्पत्ति' का वास्तविक अर्थ क्या है? वह कौन-सा काम है जिसके करने से मनुष्य को उत्पादक कहा जा सकता है? यह तो सभी को मालूम है कि मनुष्य कोई भी ऐसा नया पदार्थ नहीं

बना सकता जो किसी-न-किसी रूप में पहले से ही विद्यमान न हो। प्रकृति का जितना स्वरूप सत्कार में है वैसे उतना ही रहेगा। उसमें कभी-कभी छाना मनुष्य की शक्ति के बाहर है। मनुष्य तो केवल विद्यमान पदार्थों में ही कुछ परिवर्तन करके उन्हें पहले से अधिक उपयोगी या मूल्यवान बना सकता है। इसमें अतिरिक्त वह और कुछ नहीं कर सकता। कुछ पदार्थ अपनी प्राकृतिक स्थिति में निम्न उपयोगी नहीं होते, किन्तु यदि मानव-प्रयत्न द्वारा उन्हें एक नया रूप दे दिया जाता है तो उनकी उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए एक बड़ई का काम ले लो। वह लकड़ी स्वयं उत्पन्न नहीं करता। लकड़ी तो उसे प्रकृति की ओर से प्राप्त होती है। वह अपने औजारों की सहायता से लकड़ी को काट-छाट कर कुर्सी, मेज, आदि बनाता है। इस नये रूप में लकड़ी की उपयोगिता पहले की अपेक्षा कहीं अधिक हो जाती है। इसी तरह दर्जी तर्बन्धा कोई नया पदार्थ नहीं बनाता। वह कपड़े को काट कर विशेष नाप का कोट या कमीज सी देता है। पहले रूप में तर्बन्धा इतना उपयोगी नहीं था जितना कि अब उसे दर्जी ने बना दिया है। इन उदाहरणों में यह स्पष्ट है कि मनुष्य कोई ऐसा पदार्थ नहीं बना सकता जो सर्वथा नया हो। वह केवल विद्यमान पदार्थों की उपयोगिता ही बढ़ा सकता है। इसी उपयोगिता-वृद्धि को अर्थशास्त्र में "उत्पत्ति" कहते हैं। जो व्यक्ति किसी भी ढंग से उपयोगिता बढ़ाता है, उसे उत्पादक कहेंगे। किसान, बड़ई, व्यापारी, बकाल, डाक्टर, कुली, आदि सभी उत्पादक कहलाने के अधिकारी हैं, क्योंकि इनके उद्योग द्वारा उपयोगिता का उत्पादन होता है, अथवा उसमें वृद्धि होती है।

### उपयोगिता-वृद्धि के रूप

(Kinds of Utility)

ऊपर कहा आ चुका है कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता वृद्धि को ही उत्पत्ति कहते हैं। उपयोगिता-वृद्धि का कार्य अर्थात् उत्पादन-कार्य अनेक ढंगों से किया जा सकता है जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं —

(१) रूप-परिवर्तन—वस्तुओं के रूप में आवश्यक परिवर्तन करने से उनकी उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है। उदाहरणार्थ जब कुम्हार मिट्टी में बर्तन बनाता है, तो इस नये रूप में मिट्टी की उपयोगिता पहले की अपेक्षा अधिक हो जाती है। जब कच्चा माल तैयार माल में परिवर्तित होता है, तब धान पर परिवर्तन होने से उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार जब बड़ई लकड़ी चीर कर कुर्सी बनाता है, मुनार सोना-धादी से आभूषण तैयार करता है, तो रूप-परिवर्तन से इन वस्तुओं की उपयोगिता बढ़ जाती है।

(२) स्थान-परिवर्तन—वस्तु में स्थान सम्बन्धी परिवर्तन द्वारा भी उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है। यदि किसी स्थान पर कोई वस्तु आवश्यकता से अधिक मात्रा में है, तो वहाँ पर उस वस्तु की उपयोगिता कम होगी। यदि उस वस्तु को ऐसे स्थान पर ले जाया जाय जहाँ वह कम मात्रा में हो, तो इससे उसकी उपयोगिता बढ़ जायगी। जैसे लकड़ी जंगल से काटकर बाजार में लाई जाय या लोहा, कोयला, पत्थर, आदि को खानों में निकाल कर वहाँ से लाया जाय। खनिज पदार्थों की उपयोगिता स्थान के पास बहुत कम होती है। पर जब इन चीजों को बहा में घाटी या मोटर द्वारा शहरों या बाजारों में लाया जाता है, तो स्थान-परिवर्तन होने से इनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इसी प्रकार अन्न, शाक और फलों को खेतों से मण्डों में ले जाने पर उनकी उपयोगिता में वृद्धि होती है।

(३) अधिकार-परिवर्तन—कुछ दशाओं में केवल वस्तुओं के अधिकार व स्वामित्व-परिवर्तन से ही उनकी उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। इसमें रौबदारों, आदतियों और बलालों का कार्य सम्मिलित है। जैसे एक व्यापारी के पास एक हजार मन मल्ला है। मल्ले की उपयोगिता साधारण गृहस्थियों के लिए उस व्यापारी की अपेक्षा कहीं अधिक है। जब वह उस मल्ले को उपभोक्तार्यों को बेचता है, तो इस स्वामित्व-परिवर्तन से मल्ले की उपयोगिता बढ़ जाती है। अतएव जो व्यक्ति या



संस्थाएँ इस कार्य में सहायक होती हैं, उनका उद्योग उत्पादन-कार्य माना जायगा ।

(४) समय-परिवर्तन—वस्तुओं को कुछ समय तक संचय करके भी उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है । कुछ वस्तुएँ किमी खारा समय या ऋतु में बहुत होती हैं । यदि उन वस्तुओं को भविष्य के लिए संचय किया जाय तो उनकी उपयोगिता बहुत बढ़ सकती है । इस वर्ग में व्यापार द्वारा होने वाले कार्य सामिल हैं । गुड़, चावल, सराब, आदि पदार्थ गुराने होने पर अधिक उपयोगी होने हैं । फसल के समय अन्न की इतनी उपयोगिता नहीं होती जितनी कि दूसरे समय में होती है । अस्तु, यदि अन्न को फसल के समय लेकर रख छोड़े और एगें समय के लिए सुरक्षित रखें जब वे कम प्राप्त होते हैं, तो उपयोगिता में अवश्य वृद्धि होगी । दूकानदार, व्यापारी, आदि इसी तरह समय-सम्बन्धी परिवर्तन सत्तर उपयोगिता को बढ़ाते हैं । इस कारण वे भी उत्पादक माने जायगे ।

✓ (५) सेवा द्वारा उपयोगिता-वृद्धि—भौतिक वस्तुओं के रूप, स्थान, समय या स्वामित्व परिवर्तन में जो नहीं, बल्कि सेवाओं द्वारा भी उपयोगिता वृद्धि होती है । उगे अभौतिक उत्पत्ति कहते हैं । नानने-गाने वाले तथा तमाशा दिखाने वाले अपनी-अपनी कला से दर्शकों और श्रोताओं को आनन्दित करने उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अर्थात् उपयोगिता बढ़ाते हैं । अतः ये भी आर्थिक दृष्टि से उत्पादक हैं । इसी प्रकार डॉक्टर, बँच, न्यायाधीश, सिपाही, अध्यापक, वकील, धरेलू नौकर, आदि भी उत्पादक हैं क्योंकि वे सब अपनी सेवाओं में उपयोगिता का उत्पादन करते हैं ।

(६) ज्ञान द्वारा उपयोगिता-वृद्धि—वस्तुओं के सम्बन्ध में लोगों को ज्ञान कराने में भी उपयोगिता का उत्पादन होता है । बहुत-सी वस्तुओं के लाभ या प्रयोग से हम परिचित नहीं होते । इस कारण हमारे लिए उनमें उपयोगिता नहीं होती । लेकिन जब विज्ञापन आदि के द्वारा हमें

उनका ज्ञान हो जाता है तो हम उनको उपयोग में लाने लग जाते हैं। इससे उपयोगिता-वृद्धि होती है। अस्तु, विज्ञापन-कार्य भी उत्पादन-कार्य है। इससे लोगों को वस्तुओं के उपयोग का ज्ञान प्राप्त होता है और फलस्वरूप उपयोगिता की उत्पत्ति और वृद्धि होती है।

उपसृक्त बातों से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता-उत्पादन या वृद्धि को "उत्पत्ति" कहते हैं, चाहे उपयोगिता का उत्पादन किसी भी ढंग से किया जाय। इस परिभाषा के अनुसार किसान, व्यापारी, दलाल, अध्यापक, वकील, सिपाही, मजदूर, आदि सभी के कार्य उत्पत्ति में समावेसित हैं क्योंकि इन सब कार्यों का सम्बन्ध किसी न किसी रूप में उपयोगिता-उत्पादन से होता है।

### उत्पत्ति के साधन

(Factors of Production)

उत्पत्ति में धनेक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। बिना उनकी सहायता के उत्पत्ति असम्भव है। खेती का ही सुपरिचित उदाहरण लें। इसके पहले कि किसान कुछ अन्न पैदा कर सके, उसके पास भूमि, बीज, पानी, खाद, हल, बैल, आदि का होना आवश्यक है। इनके बिना वह किसी प्रकार का अन्न पैदा नहीं कर सकता। उत्पत्ति के अन्य कार्यों के लिए भी यही बात लागू है। उन वस्तुओं को, जो उत्पत्ति के कार्य में सहायक होती हैं, 'उत्पत्ति के साधन' (Factors of Production) कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए उत्पत्ति के साधनों को पांच भागों में विभक्त कर दिया जाता है—भूमि, श्रम, पूँजी, प्रबन्ध और ग्राह्य।

**भूमि (Land)**—अर्थशास्त्र में 'भूमि' का अर्थ साधारण बोल-चाल के अर्थ से बहुत भिन्न होता है। साधारणतया भूमि से अभिप्राय पृथ्वी तल से होता है। किन्तु अर्थशास्त्र में इसके अन्तर्गत वे सब उपयोगी पदार्थ और शक्तियाँ समावेशित हैं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं और मनोरपत्ति में प्रयोग की जाती हैं। अर्थात् भूमि उन वस्तुओं को कहते हैं जो प्रकृति की

देन है, जिनमें मनुष्य के धर्म का कोई भी अंश नहीं लगा होता। जैम पृथ्वी-तल, पहाड़, जंगल, नदी, वायु, वर्षा, गर्मी, आदि अन्य पदार्थ और सन्तिया जो पृथ्वी-तल पर या उसके ऊपर और नीचे पाई जाती है।

**श्रम (Labour)**—‘श्रम’ से अभिप्राय मनुष्य के उत्तम मान-सिक्त तथा शारीरिक प्रयत्नो से है जो धनोत्पत्ति के लिए किये जाते हैं। मशीनजन के लिए किये गये प्रयत्न को अर्थशास्त्र में ‘श्रम’ नहीं कहते। अर्थशास्त्र में केवल उन्हीं उद्योगों को श्रम में शामिल किया जाता है जिनका सम्बन्ध धनोत्पत्ति से होता है, जो धनोपाजन के उद्देश्य से किये जाते हैं।

**पूँजी (Capital)**—धन का वह भाग, जो और अधिक धन पैदा करने में सहायक होता है, ‘पूँजी’ कहलाता है। पूँजी के अन्तर्गत विविध वस्तुएँ सम्मिलित हैं, जैसे कच्चा माल, औजार, मशीन, कारखाना, आदि।

**प्रबन्ध (Organisation)**—उपर्युक्त साधनों को एकत्र करके उनका व्यवस्थित रूप से संगठन निरोक्षण, गणना व्यवस्था करने के कार्य को ‘प्रबन्ध’ कहा जाता है। आधुनिक उत्पत्ति-प्रणाली में प्रबन्ध का बड़ा महत्त्व है। इसके बिना कल-कारखानों में धनोत्पत्ति का कार्य नहीं चल सकता।

**साहस (Enterprise)**—उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को ‘साहस’ कहते हैं। जो व्यक्ति हानि और लाभ का उत्तरदायित्व अपने ऊपर स्वीकार करता है, उसे साहसी कहते हैं। बड़े पैमाने पर होने वाले आधुनिक धनोत्पादन में इस कार्य का विशेष महत्त्व है। अब यह उत्पत्ति का एक पृथक् साधन माना जाने लगा है।

भूमि और श्रम उत्पत्ति के दो प्रमुख और मूल साधन हैं। मनुष्य बिना प्रकृति या भूमि की सहायता के उत्पादन का कोई भी कार्य नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ मछली पकड़ने वाला अपना काम तभी कर सकता है जब

प्रकृति की ओर से नदियों में मछलियाँ हो। इसी तरह किमान खेती का काम तभी कर सकता है जबकि उसके लिए भूमि, हवा, पानी, वर्षा, आदि प्राकृतिक वस्तुएँ पहले से ही विद्यमान हों। इन प्रकृति-दत्त वस्तुओं को ही 'भूमि' कहा जाता है। अस्तु उत्पत्ति के लिए भूमि का होना अनिवार्य है। यद्यपि प्रकृति मनुष्य के लिए बहुत-सी वस्तुएँ स्वयं प्रदान करती है, फिर भी मनुष्य के परिश्रम के बिना उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। चाहे कितने ही अच्छे प्राकृतिक साधन क्यों न हों, किन्तु जब तक मनुष्य अपना श्रम न लगायेगा, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सकेगी। यही कारण है कि भूमि और श्रम उत्पत्ति के प्रमुख अथवा मूल साधन माने जाते हैं।

किन्तु भूमि और श्रम के सहयोग से ही मनुष्य बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। उसे भूमि के अतिरिक्त कई और वस्तुओं की भी आवश्यकता पड़ती है। प्राचीन निवासों शिकार करने के लिए शत्रु-राज का प्रयोग करते थे, मछली पकड़ने के लिए जाल और काटे को काम में लाते थे। आज मनुष्य विविध प्रकार की मशीनों तथा औजारों में काम लेते है। अर्थशास्त्र में इनको 'पूँजी' कहा जाता है। आधुनिक उत्पत्ति का दारो-मदार काफ़ी अंश तक पूँजी पर ही है। पूँजी की सहायता से मनुष्य को उत्पादन-शक्ति बहुत बढ़ जाती है। इसलिए उत्पत्ति में, विशेषकर आधुनिक उत्पादन-क्षेत्र में, पूँजी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

आजकल अधिकतर उत्पत्ति कल-कारखानों द्वारा की जाती है जहाँ पर हजारों मजदूर एक साथ काम करते हैं। इन कारखानों में बड़ी-बड़ी मशीनों का प्रयोग होता है जो बिजली आदि को शक्ति से चलाई जाती है। कारखानों में निरीक्षक अपना प्रबन्ध करने वालों की बहुत आवश्यकता होती है। उन्हें यह विचार करना पड़ता है कि कौन-सा काम, कब और किस प्रकार किया जाय, कहाँ से आवश्यक साधन लाने और अच्छे मिल सकते हैं तथा काम को किस तरह मजदूरों को दीया जाय। उन्हें

यह भी विचार करना होता है कि उत्पादित वस्तु को किन-किन मण्डियों में बचा जाय, किंम उन्हें उन स्थानों तक ल जाया जाय, किस ढंग से उस वस्तु का वितरण किया जाय इत्यादि। इन सब बातों का तप करना 'प्रबन्ध' व संगठन कहलाता है। जो व्यक्ति यह काम करता है उस प्रबन्धक कहते हैं। वैसे तो प्रबन्ध एक प्रकार का श्रम का ही एक विशेष रूप है, लेकिन आधुनिक उत्पादन-क्षेत्र में इसका महत्त्व इतना बढ़ गया है कि इस एक पृथक साधन माना जाता है। इसी के द्वारा अन्य साधनों का संगठन, उनके उपयोग का निरीक्षण और नियन्त्रण किया जाता है।

आधुनिक युग में उत्पत्ति व्यक्तिगत अथवा प्रत्यक्ष उपभोग के लिए नहीं बल्कि मशीन व बिजली के लिए की जाती है। मशीन व बिजली वस्तु की भाँति चलकर कितनी भाग होगी उतना बढ़ते में कितनी कीमत मिल सकती इसी के आधार पर उत्पत्ति की जाती है। उत्पत्ति की इस प्रणाली के कारण उत्पादन और अन्तिम उपभोग के बीच बहुत सम्बन्ध खल्ल हो गया है। जिसके कारण उत्पादन-क्षेत्र में रोज़ रोज़ नौकरी की समस्या बढ़ गई है। सम्भव है जो वस्तु उत्पन्न की जाय वह न बिक सके या जिसका उस पर खर्च आया हो उससे कम कीमत मिले। ऐसा होने पर हानि होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि कोई न कोई व्यक्ति या व्यक्ति-समूह (कंपनी आदि) हानि लाभ का जोखिम उठाने के लिए तैयार हो। बिना इस तरह के साहस के आधुनिक उत्पादन-क्षेत्र नहीं चल सकता।

अस्तु उत्पत्ति के लिए भूमि, श्रम व पूँजी प्रबन्ध और साहस की आवश्यकता पड़ती है। उत्पत्ति के प्रत्यक्ष भाग में चाहे बड़े छोटे हो, या बड़ा इन पाँचों साधनों की आवश्यकता होती है। कोई भी भाग हो, वह बिना श्रम के नहीं किया जा सकता। श्रम मनुष्य करता है, लेकिन हमें पहले कि मनुष्य किस प्रकार का श्रम कर सके उस भूमि की आवश्यकता होती है। साथ ही श्रम करने वाले के लिए औजार और सहायक वस्तुओं की जरूरत होती है जो पूँजी कहलाती है। इन साधनों

के उपयोग के निरीक्षण और नियंत्रण के लिए 'प्रबन्ध' की आवश्यकता पड़ती है। और फिर यह भी जरूरी है कि कोई व्यक्ति उत्पादन-कार्य चलाने का साहस करे, लाभ-हानि के जोखिम की जिम्मेवारी ले।

उत्पन्न साधनों में भूमि और श्रम प्रधान माने जाते हैं। इन दोनों के फलस्वरूप पूँजी उत्पन्न होती है। इसलिए पूँजी का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं। प्रबन्ध और साहस भी श्रम के विशेष रूप हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के केवल दो ही प्रधान साधन रह जाते हैं—भूमि और श्रम। इन दोनों साधनों में श्रम अधिक महत्वपूर्ण है। यह तो ठीक है कि भूमि के बिना कोई भी काम नहीं चल सकता। पर भूमि निष्क्रिय है; यह स्वयं कुछ नहीं कर सकती। वह श्रम को उत्पादन-कार्य में सहायता देती है। काम तो स्वयं भनप्य करता है। इस दृष्टि से श्रम ही अधिक महत्वपूर्ण ठहरता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उत्पत्ति के लिए केवल श्रम ही पर्याप्त है और अन्य साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। उत्पादन-कार्य में तो उपर्युक्त सभी साधनों की आवश्यकता पड़ती है।

अगले अध्यायों में इन साधनों के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक विवेचन किया जाएगा।

### उत्पत्ति पर प्रभाव

(Influences on Production)

उत्पत्ति कई बातों से प्रभावित होती है जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैं —

(१) प्राकृतिक परिस्थिति—प्राकृतिक बातों का उत्पत्ति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। किन्हीं देश में कितनी, किस ढंग की उत्पत्ति होती, यह बहुत अंश तक वहाँ की जलवायु, पर्वत, नदी, पहाड़, भूमि की उपजावट आदि प्राकृतिक बातों पर निर्भर है। यदि प्राकृतिक साधन अच्छे हैं, तो उत्पत्ति भी अच्छी होती। यदि किसी देश में अच्छे प्राकृतिक साधनों की कमी है जयवा अक्सर बाढ़, आधी, भूचाल, आदि बातें रहते हैं, तो उत्पत्ति अवश्य ही कम और अनिश्चित होगी।

(२) वैज्ञानिक ज्ञान—वैज्ञानिक ज्ञान और उसके प्रयोग का उत्पत्ति पर काफी प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक ज्ञान में जितनी अधिक वृद्धि और उन्नति होगी, उतनी ही अच्छी और अधिक परिमाण में उत्पात्ति हो सकेगी। वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे होने के कारण इंग्लैण्ड, अमरीका, आदि देशों ने उत्पादन-कार्य में बहुत उन्नति की है। वैज्ञानिक आविष्कारों तथा उनके उपयोग से मनुष्य की कार्य-कुशलता बहुत बढ़ जाती है। इससे उत्पादन का परिमाण ही नहीं बढ़ता बल्कि अच्छे ढंग की उत्पत्ति भी होने लगती है।

(३) उत्पत्ति के साधन—इसके अतिरिक्त उत्पादन का परिमाण उत्पत्ति के साधनों की मात्रा और उनकी क्षमता अथवा उत्पादन-शक्ति पर निर्भर है। जितने अधिक या कम परिमाण में उत्पत्ति के साधन होंगे, उतनी ही अधिक या कम उत्पत्ति हो सकेगी। यदि किसी आवश्यक साधन की कमी है, तो उत्पत्ति की मात्रा कम होगी। अधिक उत्पत्ति के लिए केवल यही आवश्यक नहीं है कि उत्पत्ति के साधन अधिक हों, साथ ही यह भी आवश्यक है कि उत्पत्ति के साधन अच्छे ढंग के हों और उचित ढंग से उनका उपयोग हो। उनके बीच घटे हुए सम्बन्ध और सुव्यवस्था न होने पर उत्पत्ति का परिमाण निश्चय ही कम रहेगा।

(४) साख, बैंक, यातायात की सुविधाएँ—उत्पादन का परिमाण बहुत-कुछ अंश तक साख (credit), बैंक और यातायात की सुविधाओं पर निर्भर है। यदि साख और वित्त (finance) की दृष्टि में ठीक व्यवस्था नहीं है, तो उत्पादन-कार्य में अनेक कठिनाइयाँ और रुकावट आयेगी। इसी प्रकार यातायात सम्बन्धी सुविधाओं का भी उत्पत्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। व्यापार, उद्योग, आदि अच्छे और सस्ते यातायात के साधनों के होने पर ही प्रगति कर सकते हैं, अन्यथा नहीं।

(५) राजनीतिक स्थिति और व्यवस्था—उत्पत्ति राजनीतिक स्थिति और व्यवस्था से भी बहुत प्रभावित होती है। यदि राजनीतिक

सगड़ों के कारण देश में शान्ति न हो, या देश की सरकार से उत्पादन-कार्य में सहायता-प्रोत्साहन न मिलता हो अथवा सरकार को आर्थिक नीति ठीक न हो, दोषपूर्ण हो, तो निश्चय ही उत्पादन कम होगा। ऐसी परिस्थिति में आर्थिक उन्नति या विकास कठिन ही नहीं, बल्कि असम्भव है।

उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि उत्पत्ति घटाने के लिए हमें किन-किन बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा।

## उत्पत्ति का महत्त्व

(Importance of Production)

अर्थशास्त्र में उत्पत्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। बिना उत्पत्ति सम्बन्धी विषयों के अध्ययन के, अर्थशास्त्र का अध्ययन अधूरा ही रहेगा। मनुष्य वस्तुओं के उपभोग से अपनी आवश्यकताओं को तृप्ति करता है। विन्तु यह तृप्ति तभी सगव है जबकि वस्तुएं उत्पन्न की जा सकें। मनुष्य को कितनी तृप्ति प्राप्त हो सकती है, यह उत्पत्ति के परिमाण पर निर्भर है। उत्पत्ति द्वारा ही मनुष्य का जीवन-स्तर निर्धारित होता है। भारतवासियों का जीवन-स्तर बहुत गिरा हुआ है। इसका मुख्य कारण मनोत्पत्ति की कमी है। जीवन-स्तर तभी ऊँचा हो सकता है, जबकि उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि हो। अतएव इस बात का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है कि उत्पत्ति किन-किन साधनों द्वारा होती है, और किन् प्रकार बढ़ाई जा सकती है।

सामाजिक दृष्टि से भी उत्पत्ति का अध्ययन विशेष महत्त्व रखता है। अनेक आर्थिक तथा सामाजिक समस्याएँ, जिनमें आधुनिक समाज पीड़ित है, अधिकार कम अथवा घुरी उत्पत्ति के कारण ही पैदा होती हैं। समाज को इन घटिल समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए हमें उत्पत्ति-विषय पर यथेष्ट रूप से ध्यान देना होगा। निर्भरता की समस्या का ही उदाहरण लें। कभी-कभी यह कहा जाता है कि धन-वितरण सम्बन्धी असमानता दूर करके लोगों की आर्थिक बर्षा मुधारी जा सकती है, गरीबी दूर की



जा सकती है। यह तो ठीक है कि कुछ हद तक वितरण की विषमता दूर करने से निर्धनता का बोझ हल्का किया जा सकता है, पर निर्धनता की समस्या को हल करने के लिए केवल सममानता को ही दूर करना पर्याप्त न होगा। यदि देश में पर्याप्त मात्रा में उत्पात्ति नहीं होगी तो अर्थ-काश लोग गरीब बन रहेंगे, चाहे जिस ढंग में बटवारा किया जाय। जब तक निर्धनता का साम्राज्य रहेगा, तब तक वह देश शांति और मतों का अनुभव नहीं कर सकता, और उस समय तक उन्नति का मार्ग बन्द ही रहेगा। अस्तु, सामाजिक समृद्धि और उन्नति के लिए उत्पत्ति का पर्येष्ठ रूप से अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है।

### QUESTIONS

1. Define production. What are the different ways in which production can take place?
2. "Man produces and consumes utilities only"  
Discuss
3. Indicate the various factors of production and show which of them should be regarded as primary factors
4. Bring out the importance of the study of production. Examine briefly the factors that affect the volume of production

## अध्याय १६

### भूमि

(Land)

साधारण बोलचाल में पृथ्वी-तल को, जिस पर मनुष्य को रहने और काम करने के लिए म्थात मिलता है, 'भूमि' कहते हैं। किन्तु अर्थशास्त्र में 'भूमि' शब्द को हमने कही व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अर्थ-शास्त्र में 'भूमि' शब्द से अभिप्राय उन समस्त पदार्थों और शक्तियों से है जो प्रकृति धनोत्पादन के लिए मनुष्य को पृथ्वी तल पर अथवा उसके नीचे और ऊपर देती है। उदाहरणार्थ समुद्र, नदी, झील, तालाब, झरने, वन, पर्वत, मैदान, खान तथा इन सबमें पाये जाने वाले पदार्थ जैसे वन-स्पतिया, जीव-जन्तु, आदि भूमि में समावेक्षित हैं। साथ ही गर्मो-मर्दो, वायु, वर्षा, श्रुतु, आदि भी भूमि के अन्तर्गत आ जाते हैं। इस सम्बन्ध में यह याद रखना आवश्यक है कि अर्थशास्त्र में प्रकृति का वही भाग 'भूमि' में सम्मिलित किया जाता है जिसकी उत्पत्ति में मनुष्य के श्रम का कोई भी अंश नहीं लगा होता और जो धनोत्पत्ति के काम में जरूरी होता है।

### भूमि की विशेषताएँ

(Peculiarities of Land)

उत्पत्ति के अन्य साधनों की तुलना में भूमि में कुछ खास विशेषताएँ हैं जिनका कई स्थानों या बातों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अतः उनको ध्यान में रखना आवश्यक है। इन विशेषताओं में मुख्य निम्नलिखित हैं :

(१) भूमि प्रकृति की देन है। अस्तु, इसके उत्पादन में कुछ भी लागत या खर्च नहीं पड़ता। भूमि मनुष्य को बिना किसी श्रम या खर्च के ही

प्राप्त होती है। पर भूमि की यह विशेषता केवल प्रारम्भिक स्थिति के लिए ही लागू है। आगे चलकर जब किसी व्यक्ति का किसी भू-भाग पर अधिकार हो जाता है, तो वह उसके उपयोग के लिए दूसरों से कुछ न कुछ मूल्य या उजरत अवश्य चाहेगा। प्राकृतिक भूमि को काम में लाने के लिये मनुष्य को श्रम करना पड़ता है, अपनी पूँजी लगानी पड़ती है। ऐसी दशा में भूमि प्रकृति की स्वतन्त्र देन नहीं रह जाती, वह पूँजी का रूप धारण कर लेती है। इसलिए उसके उपयोग के लिए मनुष्य को कीमत देनी पड़ती है।

(२) दूसरी विशेषता यह है कि भूमि का परिमाण परिमित है। उसे घटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता। उत्पत्ति के अन्य साधनों को समय मिलने पर घटाया-बढ़ाया जा सकता है। किन्तु भूमि के साथ वह बात सम्भव नहीं है। प्रकृति द्वारा भूमि का परिमाण परिमित है। भूमि का जितना परिमाण है, वस उतना ही रहेगा। यदि भूमि की कीमत बढ़ जाय, तो वही से नई भूमि पैदा नहीं की जा सकती। वह उतनी ही रहेगी, चाहे उसकी माप थोड़े या बड़े। अस्तु, जितनी भूमि प्रकृति द्वारा हमें मिली है, उसी पर हमें सदोप करना पड़ेगा क्योंकि हम स्वयं भूमि पैदा नहीं कर सकते। भूमि की इस विशेषता का उत्पादन-कार्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी विशेषता के कारण श्रम में अमागत-उत्पादन-ह्रास नियम सीधे ही लागू होने लगता है। भूमि की कीमत भी इसी कारण चढ़ती जाती है।

(३) भूमि अजर तथा अविनाशी है। यह जलज है। मनुष्य इसको नष्ट नहीं कर सकता। भूमि की उर्वर-शक्ति, उत्पादन-शक्ति नष्ट हो सकती है। पर जब हम यह कहते हैं कि भूमि अक्षय है, भूमि नष्ट नहीं होनी, तो हमारा आशय भूमि के तल से होता है। उसकी उर्वरता में नहीं।

(४) भूमि की चौथी विशेषता उसकी स्थिरता है। आवश्यकता-

## भूमि

नुसार हम दूसरी वस्तुओं व साधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। किन्तु भूमि में यह गुण नहीं है। यह स्थिर है। भूमि का जो भाग जहाँ है, वहीं रहेगा। उसका स्थान नहीं बदला जा सकता। इस कारण भिन्न-भिन्न स्थानों पर भूमि की कीमतों में बहुत अन्तर होता है।

(५) भूमि धनोत्पत्ति में स्वयं कार्य नहीं करती। वह निष्क्रिय है। किन्तु यह स्मरण रहे कि भूमि के बिना उत्पत्ति का कोई भी काम नहीं चल सकता।

(६) भूमि की उर्वरा क्षमता, स्थिति, आदि में बहुत भिन्नता पाई जाती है। भूमि के कोई भी दो भाग बिल्कुल एक समान नहीं होते। उनकी क्षमता और स्थिति में कुछ न कुछ अन्तर अवश्य होता है।

### भूमि का महत्त्व

(Importance of Land)

भूमि धनोत्पत्ति का आधारभूत साधन है। इसके बिना उत्पत्ति का कोई भी काम नहीं हो सकता। समार में जितने भी काम होने हैं, उन सबके लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है। भूमि ही मनुष्य को रहने और काम करने के लिए स्थान और आधार मिलता है। बिना स्थान के तो कुछ भी काम नहीं हो सकता। स्थान के साथ-साथ ही मनुष्य को वायु, पानी, प्रकाश, आदि परमावश्यक चीजें प्राप्त होती हैं। भूमि पर खेतों की जाती है जिसमें मनुष्य को तरह-तरह के खाद्य-पदार्थ मिलते हैं। इसी से भाति-भाति के कच्चे मालों की प्राप्ति होती है जिनके बिना कोई भी उद्योग-धन्धा या व्यवसाय नहीं चल सकता। लोहा, कोयला, सोना, चांदी, आदि खनिज पदार्थों का उत्पादन-क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और फिर जंगलों से अनेक प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं और समुद्र, नदियों, झीलों में मछली, आदि अनेक पदार्थ मिलते हैं। नदियों के पानी से बिजली पैदा की जाती है जो केवल रोशनी के ही काम नहीं आती बल्कि मशीनों

के चलाने में भी प्रयोग होती है। इनके अतिरिक्त भूमि से एक और महत्वपूर्ण लाभ है। वह यह है कि भूमि यातायात के साधनों के लिए पाम में आती है। भूमि पर ही हथ अपने तथा व्यापार की सुविधा के लिए रेल, सड़क, नहरें आदि, बनाते हैं। अस्तु, भूमि एक प्रकार का भंडार है जहाँ से हमें खाद्य पदार्थ, कच्चा माल, हवा, पानी, तरह-तरह के खनिज पदार्थ, काम करने और रहने का स्थान और आधार मिलता है।

उपरोक्त बातों में भूमि का महत्त्व स्पष्ट है। मानव जाति की उन्नति, सुख-समृद्धि में भूमि का बहुत हाथ है। किसी देश की आर्थिक उन्नति बहुत कुछ अंश तक वहाँ के प्राकृतिक साधनों पर निर्भर है। यदि किसी देश की भूमि उपजाऊ है, भौगोलिक स्थिति अच्छी है, नदी, पहाड़, जंगल तथा खानें पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं, वहाँ की जलवायु अच्छी है और वर्षा नियत समय पर होती है, तो वह देश अन्य देशों की अपेक्षा अधिक उन्नति कर सकता है। उदाहरणार्थ आज जो अमेरिका, इंग्लैण्ड, आदि देशों की आर्थिक उन्नति का अंश समस्त भंडार में लहरा रहा है, वह बहुत-कुछ अंश तक उन देशों के प्राकृतिक साधनों तथा उनके सदुपयोग का फलस्वरूप है। वैसे तो भारतवर्ष भी प्राकृतिक साधनों के दृष्टिकोण से काफी धनी है। देश की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है, भूमि उपजाऊ है और विविध जलवायु और ऋतुओं के कारण अनेक प्रकार का अन्न, कच्चा माल, आदि यहाँ पैदा होता है। आवश्यक खनिज पदार्थों की भी देश में कोई कमी नहीं। विद्युत-शक्ति का भी यहाँ बहुत बड़ा भंडार है। पर इस प्रकार धनवान् देश होते हुए भी, भारतवर्ष बहुत गरीब है। आर्थिक उन्नति में यह औरों से कहीं पीछे है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ के प्राकृतिक साधनों को राष्ट्र के हित के लिए उचित ढंग से प्रयोग नहीं किया जाता। यदि इन साधनों को ठीक तरह से प्रयोग में लाया जाय, तो निश्चय ही भारत आर्थिक क्षेत्र में बहुत उन्नति कर सकता है और यहाँ के लोगों का जीवन-स्तर ऊपर उठ सकता है।

## भूमि की उत्पादन-शक्ति पर प्रभाव (Influences on Productivity of Land)

भूमि की उत्पादन-शक्ति का महत्त्व ऊपर बताया जा चुका है। अब हम यह विचार करेंगे कि भूमि की उत्पादन-शक्ति पर किन-किन बातों का प्रभाव पड़ता है।

(१) प्राकृतिक सुविधाएँ—भूमि की उत्पादन-शक्ति बहुत-कुछ अंश तक हवा, वर्षा, नदी, जंगल, पहाड़, आदि प्राकृतिक वानों पर निर्भर है। औद्योगिक उत्पत्ति पर जलवायु का काफी प्रभाव पड़ता है। भिन्न-भिन्न वस्तुओं की उत्पत्ति में विभिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। लकड़ा-सागर और कच्ची ईंट की जलवायु हई के व्यवसाय के लिए बहुत उत्तम है। इस कारण इन स्थानों पर हई के बड़े-बड़े कारखाने दिखाई पड़ते हैं। खनिज पदार्थों का भी भूमि की कार्य-शक्ति पर विशेष प्रभाव पड़ता है।

(२) स्थिति—भूमि की उत्पादन-शक्ति के सम्बन्ध में हम प्राकृतिक साधनों की स्थिति पर विचार करना आवश्यक है। दोनों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्राकृतिक साधनों की स्थिति अच्छी होने पर भूमि की उत्पादन-शक्ति अधिक होगी। बहुत उपजाऊ भूमि होने हुए भी, वह बेकार है, यदि उसकी स्थिति ऐसी है कि वहाँ तक मनुष्य आसानी से नहीं पहुँच सकता। प्राकृतिक पदार्थों को उसी समय नियन्त्रित रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जबकि उन पदार्थों तक पहुँचने के साधन हों। कितने ही स्थान ऐसे हैं जहाँ अच्छे प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं, किन्तु मण्डों में दूर होने के कारण वे बेकार हैं। अतः, भूमि की अधिक उत्पादन-शक्ति के लिए अच्छी स्थिति का होना आवश्यक है। अर्थात् स्थिति का भूमि की उत्पादन-शक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

(३) मानव-उद्योग—प्राकृतिक साधनों और उनकी स्थिति के अतिरिक्त मानव-उद्योग का भी भूमि की उत्पादन-शक्ति पर काफी प्रभाव पड़ता है। मनुष्य अपने प्रयत्न में प्राकृतिक स्थितियों को बहुत-

कुछ अंग तक दूर कर सकता है। विज्ञान की सहायता से मनुष्य जलवायु को बदल कर अपने अनुकूल बना सकता है। बड़े पैमाने पर पेड़ों के लगाने में जलवायु में अन्तर आ जाता है। इसी तरह उचित ढंग की खाद डालने में अथवा कमल-परिवर्तन, आदि में खेत की उपज बढ़ाई जा सकती है। मनुष्य अपने उद्योग द्वारा स्थिति में भी काफी परिवर्तन ला सकता है। यातायात के साधनों में उन्नति करके प्राकृतिक साधनों को मण्डी के निकट लाकर भूमि की उत्पादन-शक्ति बढ़ाई जा सकती है।

संक्षेप में, भूमि की उत्पादन-शक्ति मुख्यतः मानव-उद्योग, यातायात के साधनों और भौगोलिक बातों पर निर्भर करती है।

### विस्तृत और गहरी खेती

(Extensive and Intensive Cultivation)

उपर नज़र आ चुका है कि मनुष्य अपने उद्योग द्वारा भूमि की शक्ति बढ़ाकर, उसकी स्थिति सुधार कर, उत्पादन का परिमाण बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए कृषि-उपज दो प्रकार से बढ़ाई जा सकती है—एक तो विस्तृत खेती द्वारा और दूसरे गहरी खेती द्वारा। जब नई भूमि को जोत कर उपज बढ़ाई जाती है, तो उसे विस्तृत खेती (extensive cultivation) कहते हैं। जिन देशों में जनसंख्या कम होती है और भूमि का परिमाण अधिक होता है, वहाँ विस्तृत खेती के ढंग को अपनाया जाता है। लगातार फसलें बोने से पुराने खेतों की उपज कम होने लगती है। इसलिए जहाँ आवश्यकतानुसार नई भूमि पर्याप्त मात्रा में मिल सकती है, वहाँ के किसान पुराने खेतों में अधिक पूँजी, श्रम, आदि को न लगाकर उन्हें नए खेतों में लगाते हैं और नई भूमि को प्रयोग में लाकर उपज बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। खेतों का यह ढंग नये देशों में ही किया जा सकता है जहाँ बे-जोती हुई भूमि उपलब्ध हो सकती है।

कृषि-वैदाचार बढ़ाने का दूसरा उपाय गहरी खेती (intensive cultivation) है। पुराने देशों में जहाँ बे-जोती हुई नई भूमि

उपलब्ध नहीं होती, बड़ा माँग के बढ़ने पर पुराने खेतों में ही अधिक पूँजी और धन लगाकर उपज बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। जब उसी भूमि पर पूँजी, धन, आदि साधनों की मात्रा बढ़ाकर खेती की जाती है, तो उसे 'गहरी खेती' अथवा 'दिगिष्ट खेती' कहते हैं। जहाँ भूमि का परिमाण अन्य साधनों की तुलना में सीमित होता है, वहाँ इस ढंग से खेती की जाती है। कारण, वहाँ आवश्यकतानुसार नई भूमि कृषि के लिए नहीं मिल सकती। जन-संख्या में वृद्धि होने पर अब सीमा के बाद कृषि-उपज बढ़ाने का एकमात्र साधन गहरी खेती ही रह जाती है।

### QUESTIONS

1. What is meant by 'Land' in Economics? State its peculiarities and importance in production
2. State and explain the main factors which influence the productivity of land
3. What do you mean by intensive and extensive cultivation? Under what conditions can they be followed successfully?



## अध्याय १७

### श्रम और उसके लक्षण

(Labour and its Peculiarities)

‘श्रम’ शब्द के साधारण और आर्थिक अर्थों में काफी भिन्नता है। आम बोल-चाल में हर तरह के प्रयत्न, काम अथवा उद्योग को श्रम कहते हैं। किन्तु अर्थशास्त्र में ‘श्रम’ शब्द को इनके व्यापक अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाता। एक तो अर्थशास्त्र में श्रम से अभिप्राय केवल मनुष्य के प्रयत्नो और बायों में ही है। जो काम पशुओं अथवा मशीनों द्वारा किया जाता है, वह श्रम में शामिल नहीं किया जाता। बेल खेतों के जोतने में बड़ी मेहनत से काम करते हैं। इन्हीं प्रकार ऊट, घोड़े, आदि भी कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन पशुओं और मशीनों के द्वारा जो काम होते हैं, उनकी गिनती श्रम में नहीं होती क्योंकि पशुओं और मशीनों की गिनती तो पूँजी में की जाती है। दूसरे, मनुष्य के सभी प्रयत्न अथवा कार्य ‘श्रम’ नहीं हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तरह-तरह के उद्योग करता है। लेकिन उसका वही कार्य श्रम माना जाता है जो धनोपार्जन के उद्देश्य से किया जाता है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ‘श्रम’ की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है अर्थशास्त्र में ‘श्रम’ से अभिप्राय मनुष्य के उन मानसिक तथा शारीरिक प्रयत्नों से है जो पूर्णतः या अंशतः धनोपार्जन के लिए किये जाते हैं।

अस्तु, मनुष्य के वे उद्योग, जो केवल मनोरञ्जन, आनन्द या मन-बहुलाव के लिए किए जाते हैं, ‘श्रम’ नहीं माने जायेंगे। उदाहरणवत् यदि कोई गायक अपने या दूसरों के मनोरञ्जन के लिए गाना गाता है, तो उसके

इस कार्य को 'धर्म' में न सामिल करेंगे। लेकिन यदि वह किसी को सगेत सिखाने के लिए गाना गाता है जिसके बदले में उसे रुपये की प्राप्ति होती है, तो उसके इस उद्दीग को 'धर्म' माना जायगा। पर इसका यह अर्थ नहीं कि धर्म में गनुष्य के उसी काम की गिनती होती है जिसमें मनोरञ्जन नहीं होना, जिसमें कड़ी मेहनत लगती है अथवा जो कष्ट-दायक हो। प्रत्येक कार्य में कुछ न कुछ आनन्द मिलता है और साथ ही उसमें थोड़ी-बहुत मेहनत भी पड़ती है। अस्तु, यह निर्णय करने के लिए कि श्रमिक कार्य 'धर्म' है या नहीं, हम उस काम के उद्देश्य पर विचार करना होगा। यदि कोई काम धनोपाजन के लिए किया गया है, तो मनोरञ्जक होने पर भी वह काम 'धर्म' कहलाएगा। इसके विपरीत यदि काम केवल आनन्द या मनोरञ्जन के लिए ही किया गया है, तो यह धर्म न माना जायगा, चाहे उसमें कितनी कड़ी मेहनत क्यों न पड़ती हो। अर्थात् धनोपाजन के उद्देश्य को सामन रखकर जो काम किया जाता है, वही अर्थशास्त्र में धर्म माना जाता है, चाहे उस काम में आनन्द मिलता हो या नहीं, अथवा उसमें कड़ी मेहनत पड़ती हो या नहीं।

### धर्म के भेद

(Kinds of Labour)

धर्म के कई भेद किये जाते हैं जैसे साधारण तथा कुशल धर्म, मानसिक और शारीरिक धर्म, उत्पादक और अनुत्पादक धर्म, आदि। इनमें से एक दो पर यहाँ विचार किया जायगा।

(१) साधारण तथा कुशल धर्म (Unskilled and Skilled Labour)—'साधारण धर्म' से अभिप्राय उन कार्यों से है जिनके करने में किसी विशेष शिक्षा, अभ्यास या निपुणता की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे कुली का काम। इसके विपरीत 'कुशल धर्म' उस धर्म को कहते हैं जिसके करने में विशेष अभ्यास, शिक्षा, आदि की जरूरत होती है जैसे डाक्टर, अज, इंजीनियर, आदि के काम। इस

सम्बन्ध में यह बात याद रखनी चाहिए कि 'साधारण' और 'कुशल' शब्द सापेक्षित हैं। इनका कोई निरपेक्ष अर्थ नहीं है। देश, काल, आदि के अन्तर से कुशल-अथ साधारण-अथ हो सकता है और साधारण-अथ कुशल-अथ बन सकता है।

१. (२) उत्पादक तथा अनुत्पादक श्रम—(Productive and Un-productive Labour) श्रम उत्पादक अथवा अनुत्पादक हो सकता है। अर्थशास्त्र में उत्पत्ति या अर्थ उपयोगिता-उत्पादन या वृद्धि में है। अतः, जिन श्रम में उपयोगिता की उत्पत्ति अथवा वृद्धि होती है, उसे 'उत्पादक-श्रम' कहेंगे। इससे विपरीत जिस श्रम से किसी प्रकार की उपयोगिता उत्पन्न न हो या उपयोगिता में वृद्धि न हो, उसे 'अनुत्पादक-श्रम' कहेंगे। अर्थात् अनुत्पादक श्रम वह है जो व्यर्थ किया गया हो, जिसमें उपयोगिता-उत्पादन न हुआ हो। फिर भी यह ध्यान रहे कि यदि कोई श्रम उपयोगिता-उत्पादन में लगा हुआ है तो वह अवश्य उत्पादक श्रम माना जायगा, चाहे अन्त में उद्देश्य की पूर्ति संभव हो सके या नहीं।

पूर्वकाल के अर्थशास्त्री उत्पादक-श्रम को बहुत संकुचित अर्थ में लेते थे। अठारहवीं सदी में फ्रांस के अर्थशास्त्री केवल कृषि-कार्य को ही उत्पादक-श्रम मानते थे। बाकी सब काम अनुत्पादक-श्रम माने जाते थे। आगे चलकर एडम स्मिथ ने, जो अर्थशास्त्र को एक बहुत बड़े विद्वान् माने जाते हैं, धारत्वानो, उद्योग-धर्मों में लगे हुए श्रम को उत्पादक-श्रम में शामिल कर लिया। फिर भी उनके अनुसार गायक, अध्यापक, धरेलू नीकर का काम अनुत्पादक था। किन्तु अब वर्तमान समय में उत्पादक-श्रम को बहुत व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार वे सभी श्रम उत्पादक श्रम हैं जिनमें किसी भी प्रकार की उपयोगिता की उत्पत्ति या वृद्धि होती है। अब निसानो, उद्योग-धर्मों वाले का ही काम नहीं बल्कि डाक्टरों, गायकों, अध्यापकों, फौज वालों, आदि सभी का काम उत्पादक श्रम माना जाता

है क्योंकि इन सबका सम्बन्ध उपयोगिता के उत्पादन अथवा वृद्धि से होता है। और अर्थशास्त्र में इसी को 'उत्पत्ति' कहते हैं।

### श्रम के लक्षण

(Peculiarities of Labour)

श्रम के लक्षणों पर विचार करने से पता चलता है कि श्रम अन्य साधनों से कितना भिन्न है। साथ ही इन लक्षणों का श्रम-सम्बन्धी बातों तथा समस्याओं पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अस्तु, इन लक्षणों को ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है। श्रम के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं —

(१) सबसे बड़ी बात यह है कि श्रम को धमिक से अलग नहीं किया जा सकता। इस कारण धमिक को स्वयं उस स्थान पर जाना पड़ेगा जहाँ पर वह श्रम करने के लिए तैयार है। अन्य वस्तुओं को हम उनके अधिकारियों या मालिकों से पृथक् करके जहाँ चाहे भेज सकते हैं, किन्तु श्रम और धमिक एक दूसरे में अलग नहीं किए जा सकते। पत्थर बेचने वाला इस बात पर ध्यान नहीं देता कि नरोदार कीज या कैसा है अथवा उसका पत्थर किस काम या स्थान में प्रयोग होगा—गद्दी माली में या एक गुम्बर महल में। यदि उसको ठीक कीमत मिल जाती है, तो वह इन बातों का तनिक-सा भी खयाल नहीं करता। किन्तु एक धमिक को अपना श्रम बेचते समय इन बातों पर विचार करना पड़ता है कि उसे कहाँ काम करना होगा, वहाँ का वातावरण, रहन-सहन कैसा है, किसके अधीन रह कर काम करना पड़ेगा, किन लोगों के साथ काम करना होगा, आदि। इन जनेक बातों का विचार करना उनके लिए जरूरी होता है क्योंकि इन सबका प्रभाव उस पर पड़ता है।

(२) श्रम क्षीय नष्ट होने वाली वस्तु है। अन्य साधनों और वस्तुओं को काफी समय तक संचय कर या बचाकर रखा जा सकता है। एक व्यापारी अपनी किसी वस्तु को कीमत में वृद्धि होने की सम्भावना से कुछ समय तक रोक कर लाभ उठा सकता है। पर श्रम इस प्रकार संचित

करने नहीं रखा जा सकता । यदि एक श्रमजीवी एक माह काम न करे, तो वह दूसरे महीने उसे पूरा न कर सकेगा क्योंकि समय के साथ-साथ श्रम भी बीतता जाता है, श्रम का ह्रास होना जाता है । यही कारण है कि श्रमिक में मोल-भाव करने की क्षमता अपेक्षाकृत बहुत कम होती है ।

(३) एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रम उत्पादक और उप-भोग्य दोनों ही हैं । भूमि और पानी तो उत्पत्ति के केवल साधन मात्र ही हैं । इनमें उपयोगिता का उत्पादन में, इच्छित वस्तुओं के तैयार करने में सहायता मिलती है । पर श्रम उत्पादन करने वाला ही नहीं बल्कि उत्पन्न वस्तुओं का उपभोग करने वाला भी है । अतः, श्रम का स्थान अन्य साधनों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग न करने समय श्रम की इस विशेषता का पूरा-पूरा ध्यान रखना परमावश्यक है ।

(४) श्रम की पूर्ति श्रम की माग के अनुसार आगामी और वीर्यता से घटाई-बढ़ाई नहीं जा सकती । यदि माग एकदम बढ़ जाय या घट जाय, तो श्रम की पूर्ति उसके अनुसार जल्दी नहीं बढ़ाई जा सकती । श्रम की पूर्ति जन-गण्यता पर निर्भर है, पर जन-गण्यता की वृद्धि केवल आर्थिक बातों पर ही निर्भर नहीं करती और न पैदा होते ही मनुष्य काम में लग सकता है । उसके पालन-पोषण, शिक्षा, आदि में काफी समय लगता है । इस कारण श्रम की पूर्ति में बहुत धीरे-धीरे परिवर्तन लाया जा सकता है ।

(५) अन्य साधनों की तरह श्रम में भी रक्ष्यता लगाया जा सकता है । लेकिन श्रम के साथ एक खास बात है । वह यह है कि श्रम के शिक्षण आदि में जो रक्ष्यता लगाया जाता है, वह सदा के लिए उसी में लग जाता है और बहुत ही धीरे धीरे निकलता है ।

### श्रम का महत्त्व

(Importance of Labour)

उत्पत्ति के साधनों में श्रम का स्थान सर्वश्रेष्ठ है । हर प्रकार की उपयोगिता-उत्पादन अथवा वृद्धि के लिए श्रम अनिवार्य है । इसके बिना

कोई भी काम सही चल सकता, किसी भी प्रकार की उत्पात्ति नहीं हो सकती। यह बात तो भूमि के लिए भी कही जा सकती है। लेकिन भूमि निष्क्रिय है, वह स्वयं कुछ भी नहीं कर सकती। इसके विपरीत श्रम सक्रिय है। श्रमिक श्रुद काम कर सकता है। बिना उसके न तो भूमि ही कुछ उत्पात्ति कर सकती है और न पृथ्वी ही। वास्तव में पृथ्वी तो श्रम पर ही निर्भर है। अस्तु, श्रम उत्पात्ति का सर्वप्रधान साधन है। इसी पर उत्पात्ति निर्भर है।

श्रम का महत्त्व इस कारण भी है कि वह उपभोग करने वाला भी है। सारी उत्पात्ति उमी के उपभोग के लिए ही की जाती है। अस्तु, श्रम उत्पात्ति और उपभोग का एक मात्र केन्द्र है। इस बात से श्रम का महत्त्व स्वयं स्पष्ट है।

श्रम की महत्ता को ध्यान में रखते हुए श्रम की पूर्ति पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। कारण, श्रम की पूर्ति पर किसी देश की आर्थिक उन्नति, सुख-समृद्धि बहुत कुछ निर्भर होती है। श्रम की पूर्ति दो बातों पर निर्भर है (१) श्रमिकों की संख्या, और (२) श्रमिकों की कार्य-क्षमता अथवा योग्यता। इनका वर्णन हमले अध्यायों में किया जाएगा।

## QUESTIONS

1. Define and explain the meaning of labour
2. What are the important peculiarities of labour ?  
What is their importance ?
- (3) Distinguish between productive and unproductive labour as clearly as you can.
4. Is the labour of the following productive ?  
(a) a house-wife,  
(b) a domestic servant,  
(c) a teacher  
(d), an amateur painter.

## अध्याय १८

### श्रम की पूर्ति

#### (Supply of Labour)

श्रम की पूर्ति देश की जन-संख्या पर निर्भर होती है। जितनी ही अधिक या कम किसी देश की जन-संख्या होगी, साधारणतः उतनी ही अधिक या कम श्रम की पूर्ति होगी। किसी देश की जन-संख्या दो बातों पर निर्भर करती है (१) जन्म तथा मृत्यु-संख्या और (२) आवास-प्रवास। यदि किसी देश में जन्म-दर मृत्यु-दर में अधिक है, तो जन-संख्या बढ़ेगी। इसी प्रकार यदि देश में बाहर से आने वालों की संख्या जाने वालों में अधिक है, तो जन-संख्या बढ़ेगी, और देश से बाहर जाने वालों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होने पर जन-संख्या घटेगी। संक्षेप में, हम यहां उन बातों पर विचार करेंगे जिनमें जन-संख्या प्रभावित होती है।

#### जन्म-दर

##### (Birth-Rate)

जन्म-दर कई बातों पर निर्भर होता है जिनमें से मुख्य निम्न-लिखित हैं —

(१) जलवायु—जलवायु का जन्म-दर पर काफी प्रभाव पड़ता है। गर्म देशों में विवाह जल्दी और कम उम्र में हो जाते हैं। शीत-प्रधान देशों में विवाह देर में होते हैं। इस कारण गर्म देशों में प्रत्येक विवाह के पीछे अधिक सन्तानें होती हैं, अर्थात् जन्म-दर अधिक होती है।

(२) सामाजिक और धार्मिक कारण—सामाजिक तथा धार्मिक कारणों का भी जन्म-दर पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे भारत में

विवाह का आम रिवाज है। विवाह एक आवश्यक और धार्मिक बन्धन माना जाता है और सो भी छोटी ही उम्र में। इस कारण भारत में जन्म-संख्या का अनुपात अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। पश्चिमी देशों में ऐसी सामाजिक या धार्मिक प्रथाएँ प्रचलित नहीं हैं। वहाँ विवाह की प्रथा इतनी व्यापक नहीं है, और न ही वहाँ बाल-विवाह या बहु-विवाह प्रचलित हैं। फलस्वरूप वहाँ पर जन्म-दर कम है।

(३) राजनीतिक परिस्थिति—कभी-कभी सरकारी नीति के कारण भी जन्म-दर की वृद्धि कम या अधिक हो जाती है। सरकार जन्म-दर की वृद्धि कम या अधिक करने के लिए लोगों को अनेक प्रकार से सहायता या प्रोत्साहन दे सकती है। जर्मनी, इटली, रूस, आदि देशों में सरकारी नीति का जन्म-दर पर बहुत प्रभाव पड़ा है।

(४) आर्थिक दशा—सबसे अधिक प्रभावपूर्ण कारण लोगों की आर्थिक स्थिति है। साधारणतः गरीबी की अवस्था में जन्म-दर अधिक होती है। यह देखने में आता है कि रहन-सहन का दर्जा जितना ही नीचा होता है, उतनी ही अधिक जन्म-दर होती है। इसके कई कारण हैं। एक गरीब आदमी जल्दी विवाह करता है और बौद्धिक उन्नति कम होने के कारण वह भविष्य की कम चिन्ता करता है। यही नहीं मनोरञ्जन के लिए उसके पास और कोई साधन नहीं होता। फलस्वरूप गरीब मनुष्य के अधिक बच्चे हुआ करते हैं। इसके विपरीत, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, जिनके रहन-सहन का दर्जा ऊँचा होता है, वे देर में शादी करते हैं और अपेक्षाकृत कम मताने पैदा करते हैं ताकि उनके रहन-सहन का दर्जा नीचे न गिरे।

मृत्यु-दर

(Death Rate)

अन्य बातों के समान रहने पर, जितनी ही कम या अधिक मृत्यु-दर होगी, जन-संख्या की वृद्धि उतनी ही अधिक या कम होगी। यदि किसी देश में १०० जन्मों के पीछे प्रतिवर्ष २५ मौतें होती हैं और दूसरे



देश में केवल १५ सीतें होती हैं तो, अन्य बातों के पूर्ववत् रहने पर, हमारे देश की जन-संख्या में पहले देश की अपेक्षा अधिक वृद्धि होगी। मृत्यु-दर पर विभिन्न प्रकार की बातों का प्रभाव पड़ता है जैसे जलवायु, प्राकृतिक पटनाएँ, रहन-सहन का दर्जा, विवाह-सम्बन्धी रीति-रिवाज, शिक्षा-प्रचार, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आदि के साधन। यदि किसी देश की जलवायु ठीक नहीं है अथवा वहाँ प्रायः बाढ़, भूकम्प, आदि के रूप में दैवी प्रकोप होते रहते हैं, तो उस देश की मृत्यु-दर अपेक्षाकृत अधिक होगी। इसी प्रकार यदि किसी देश में शिक्षा का प्रचार कम है, लोग गरीब हैं, उनके रहन-सहन का दर्जा नीचा है और देश में स्वास्थ्य, चिकित्सा, आदि के अच्छे साधन सुलभ नहीं हैं, या उस देश में बाल-विवाह आदि की प्रथाएँ प्रचलित हैं, तो निश्चय ही वहाँ की मृत्यु-दर बहुत बढ़ी-घड़ी होगी।

भारत में मृत्यु-दर अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। इसके अनेक कारण हैं। एक तो, देश के कुछ भागों को जलवायु गर्म है जिसके कारण लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं हो पाता और देश में तरह-तरह के घातक रोगों का धावा रहता है। दूसरे, लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उनके जीवन-स्तर का दर्जा बहुत ही नीचा है। वे भोजन गरीबों में पिसे हुए हैं। तीसरे, देश में स्वास्थ्य, चिकित्सा, आदि के अच्छे साधनों की विषय कमी है, और फिर देश में शिक्षा का प्रचार भी कम है। लोग अंध और अन्ध-विश्वासी हैं। बाल-विवाह, आदि की प्रथाएँ भी देश में प्रचलित हैं। अस्तु, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भारत में मृत्यु-दर अत्यधिक है।

जन्म-दर में से मृत्यु-दर निकाल कर किसी देश की जन-संख्या की प्राकृतिक वृद्धि मालूम की जा सकती है। यदि दोनों दर बराबर हों, तो जन-संख्या उतनी ही बनी रहेगी। यदि मृत्यु-दर अपेक्षाकृत अधिक है, तो जन-संख्या में घटी होगी और इसके विपरीत यदि जन्म-दर का आधिक्य है, तो जन-संख्या बढ़ेगी।

## आवास-प्रवास

(Immigration and Emigration)

जन-संख्या पर आवास-प्रवास का भी काफी असर पड़ता है। यदि किसी देश में प्रवासी देशवासियों की संख्या देश में विदेशियों की संख्या से अधिक है, तो जन-संख्या घटेगी, और इसके विपरीत यदि विदेश से बहुत-से लोग आकर बसेंगे, तो जन-संख्या में वृद्धि होगी। अमरीका और ऑस्ट्रेलिया में बाहर के देशों से आकर बहुत से लोग बस गए। फल-स्वरूप इन देशों की जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई। पर वर्तमान समय में आवास-प्रवास स्वतन्त्र नहीं है। इस पर बहुत नियन्त्रण होता है। भिन्न-भिन्न देश अब आवास-प्रवास पर अनेक प्रतिबन्ध लगाते हैं। विदेश में जाकर बसने में अब लोगों को अनेक कठिनाइयाँ होती हैं। तरह-तरह की अड़चनों के कारण आवास-प्रवास की संख्या अब बहुत कम होती जा रही है। फलस्वरूप इसके द्वारा अब जन-संख्या में कोई विशेष उतार-भड़ाव नहीं होता।

## माल्थस का जन-संख्या सम्बन्धी सिद्धान्त

(Malthusian Theory of Population)

जैसा कि पहले कहा जा चुका है जन-सम्पदा ही राष्ट्र की नयने बड़ी संपत्ति है। व्यक्ति और समाज की उन्नति, सुख-समृद्धि बहुत-कुछ इसी पर निर्भर है। और आज जब अनेक प्रकार में प्रकृति मनुष्य की दास बन चुकी है, तो इस कथन की सत्यता और भी स्पष्ट हो जाती है। अब जन-संख्या के प्रश्न पर विचार करना, उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है। आधुनिक काल में इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आर्थिक दृष्टि में विचार करने वालों में सर्वप्रथम स्थान इंग्लैण्ड के पादरी टागम राबर्ट माल्थस का है। जन-संख्या और साधन-सामग्री का जिस हद तक सम्बन्ध है, उसके बारे में सबसे पहले उन्होंने ही वैज्ञानिक ढंग से विचार किया। बहुत गम्भीर अध्ययन के अनन्तर माल्थस ने १७९८ ई० में

“जन-संख्या के सिद्धान्त पर निबन्ध” नामक एक सुविख्यात पुस्तक लिखी। इसका संशोधित संस्करण पाच वर्ष बाद १८०३ ई० में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में इन्होंने जन-संख्या और साध-सामग्री के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों अथवा सिद्धान्तों की स्थापना की है—

(१) भोजन-सामग्री जीवन-निर्वाह के लिए नितान्त आवश्यक है। इसी के द्वारा जन-संख्या की वृद्धि की अधिकतम सीमा निर्धारित होती है।

(२) मनुष्य की इन्द्रिय-लोलुपता के कारण जन-संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। साधारणतः यदि जन-संख्या पर कोई रोकथाम न हो, तो वह २५ वर्ष में दुगुनी हो जाती है। दूसरे शब्दों में जन-संख्या में रेखागणित के अनुपात (geometric ratio) में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, जैसे—१, २, ४, ८, १६, ३२, आदि। यदि जन-संख्या किसी समय १ इकाई मान ली जाय, तो वह २५ वर्ष में २ इकाई हो जायगी, ५० वर्ष में ४ इकाई, ७५ वर्ष में ८ इकाई और इस प्रकार कोई हकाबट न होने पर जन-संख्या रेखागणतीय प्रगति में बढ़ती जायगी।

(३) भूमि की परिमितता के कारण, साध-सामग्री इतनी तेजी में नहीं बढ़ती। साधारणतः यह अकमन्य दर (arithmetical ratio) से बढ़ती है, जैसे—१, २, ३, ४, ५, ६, आदि।

उपर्युक्त वर्णन से जन-संख्या और साध-सामग्री के बढ़ने की दरों का अन्तर स्पष्ट है। जितनी जल्दी जन-संख्या बढ़ती है, उतनी जल्दी अन्न की मात्रा नहीं बढ़ती। यदि कोई रोक-थाम न हो, तो पच्चीस वर्ष में जन-संख्या दुगुनी हो जाती है परन्तु भोजन-पूर्ति (food supply) दुगुनी नहीं होती। इसलिए किसी भी स्थान की जन-संख्या वहाँ की भोजन-पूर्ति से अधिक होगी। ऐसा होने पर साध-सामग्री कम पड़ जायगी, भुलमरी बढ़ेगी और तरह-तरह के रोग और तपस् फँसने। जनानिधन की यह समस्या (problem of over-population) सदैव बनी रहती है। भूतकाल में ऐसा देखने में आया है, और भविष्य में भी ऐसा ही होने की सम्भावना है।

जन-संख्या की वृद्धि की रोकथाम के लिए माल्थस ने सुझाया कि इसके दो ही उपाय हैं—एक तो नैसर्गिक उपाय ( Positive Checks) और दूसरे प्रतिबन्धक उपाय (Preventive Checks) । नैसर्गिक उपाय व रोक प्रकृति द्वारा काम में लाये जाते हैं, जैसे प्लेग, हैजा, महामारी, अकाल, लडवाई, आदि। इनसे मृत्यु-दर बढ़ जायगी और अन्त में जन-संख्या छीजती-छीजती बेचल उतनी ही रह जायगी जितनी कि निर्वाह के लिए उस देश या स्थान पर खाद्य-सामग्री पर्याप्त हो सकेगी। अर्थात् मृत्यु-दर बढ़ जाने से जन-संख्या का बाधक्य कम हो जायगा। जनम-दर कम करने में भी जन-संख्या की वृद्धि रोकी जा सकती है, जैसे दर में विवाह करना, संयम, प्रसूच्यसं रहना, आदि। इन्हें दनावटी विरोध अध्या प्रतिबन्धक उपाय कहते हैं। ये मनुष्य के वश में हैं। इन उपायों के द्वारा मनुष्य नैसर्गिक उपायों से होने वाले अनेक कष्टों और दुखों में बच सकता है। यदि जन-संख्या की वृद्धि प्रतिबन्धक उपायों से न रोकी जायगी तो निश्चय ही प्रकृति द्वारा नैसर्गिक उपाय काम में लाये जायेंगे।

मक्षेप में, माल्थस के सिद्धान्त का निचोड़ यह है कि जन-संख्या का मुकाबला खाद्य-सामग्री की प्राप्य मात्रा से अधिक तेजी से बढ़ते की ओर होता है। फलस्वरूप जन-संख्या हमेशा ज्यादा हो पाई जाती है। इसे रूक करने के लिए नैसर्गिक उपाय काम में लाये जाते हैं, जिसके कारण समाज को अनेक कष्टों और दुखों का सामना करना पड़ता है। भूतकाल में ऐसा ही होता रहा है और इसलिए भविष्य में भी ऐसा ही होने की संभावना है। इसे विचारधारा के कारण माल्थस एक निराशावादी विचारक माना जाता है।

### माल्थस के सिद्धान्त की समीक्षा

(Criticism of Malthusian Theory)

माल्थस के इस सिद्धान्त पर अनेक आक्षेप किये जाते हैं जिनमें से मुख्य निम्नालिखित हैं —

(१) माल्थस का यह कहना कि जन-संख्या की वृद्धि रेखा-नग्नित के अनुपात में और खाद्य-सामग्री की वृद्धि अक-नग्नित के अनुपात में होती है ठीक नहीं है, निराधार है। वास्तव में जन-संख्या और खाद्य-सामग्री की उत्पत्ति रेखा-नग्नित और अक-नग्नित के अनुपात की कड़ाई पर न कभी स्थिर रह सकी है और न रहेगी। दोनों की वृद्धि के बीच इस तरह का कोई अनुपात सिद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके आधार पर माल्थस के मिद्धान्त को काटा नहीं जा सकता। कारण, माल्थस के सिद्धांत के ये आवश्यक अंग नहीं हैं। माल्थस ने रेखा-नग्नित और अक-नग्नित का व्यवहार केवल सुविधा और स्पष्टीकरण के लिए ही किया था। प्रवृत्ति के रूप में माल्थस का मिद्धान्त ठीक और विचारणीय है।

(२) कहा जाता है कि माल्थस ने प्राणिसारत्र पर पुरा-पुरा ध्यान नहीं दिया। सन्तान-प्राप्ति की इच्छा सदा एक-सी नहीं रहती। यह इच्छा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, आदि अनेक बातों से प्रभावित होती है। पर ये बातें सदा एक समान नहीं रहती। इस कारण सन्तान-वृद्धि की इच्छा हमेशा वैसी ही बनी नहीं रहती। उसमें परिवर्तन होता रहता है। फलस्वरूप यह कहना कि जन-संख्या हमेशा तीव्र गति से बढ़ती रहेगी या २५ वर्ष में दुगुनी हो लेगी, ठीक नहीं है।

प्राणिसारत्र के अध्ययन से पता चलता है कि जैसे-जैसे मनुष्य अधिकाधिक सम्पन्न होता जाता है, सन्तान पैदा करने की उसकी इच्छा वैसे ही वैसे कम होती जाती है। अस्तु, सम्यता के बढ़ने के साथ-साथ जन-संख्या की वृद्धि की तीव्रता पूर्ववत् नहीं रहती। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जन-संख्या सम्पत्ति की वृद्धि की अपेक्षा कम बढ़ती है। सम्पत्ति में वृद्धि होने से लोगो का जीवन-स्तर, रहन-सहन का दर्जा ऊंचा हो जाता है। ऊंचे दर्जे के बगाने रखने के लिए छोटे परिवार का होना आवश्यक है। अस्तु, जैसे-जैसे जीवन-स्तर ऊंचा होता जाता है, वैसे ही वैसे लोगो में अधिक सन्तान-प्राप्ति की इच्छा घटती जाती है। इस कारण जन-संख्या की वृद्धि में कमी आ जाती है।

(३) माल्थस ने यह भी भूल की कि उन्होंने साधन-पदार्थों को स्थिर प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में मान लिया। उन्होंने इस बात की ओर उचित ध्यान नहीं दिया कि किस हद तक मानवीय शक्तों, सुधारों और आविष्कारों के द्वारा उत्पत्ति में उत्पत्ति सम्भव है। फलस्वरूप उनके बाद रासार के आर्थिक इतिहास में माल्थस के विचारों को काफी झूठा साबित कर दिया। वर्तमान समय में नये-नये उपायों और सुधारों द्वारा उत्पत्ति में कहीं अधिक वृद्धि हुई है। १९१३ और १९२५ ई० के बीच रासार भर की जन-संख्या कुल ५ प्रतिशत बढ़ी लेकिन इन्हीं दिनों में साधन-सामग्री में १० प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९२५ और १९२९ ई० के बीच रासार की जन-संख्या और साधन-सामग्री में क्रमशः ४ और १० प्रतिशत में वृद्धि हुई। इससे पता चलता है कि उत्पत्ति सतत से, अर्थात् जन-संख्या से पीछे नहीं रही बल्कि आगे ही रही है। वास्तव में कुछ देशों की तो सारी स्थिति ही पलट गई है। वहा तो यह प्रश्न उठने लगा है कि जन-संख्या को किन प्रकार बढ़ाया जाय। अस्तु, उत्पत्ति के साधनों के उत्पन्न और विकसित हो जाने पर माल्थस के सिद्धान्त व्यर्थ से लगने लगे हैं।

(४) कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जन-संख्या की समस्या पर विचार करते समय हमें देश के कुल साधनों व कुल जनोत्पत्ति पर ध्यान देना चाहिए, न केवल साधन-पदार्थों की उत्पत्ति पर ही नहीं। एक औद्योगिक प्रचलन देश अपने विभिन्न प्रकार के तैयार मान के बदले में दूसरे देशों से अधिकाधिक साधन-पदार्थ प्राप्त कर सकता है। जैसे इंग्लैण्ड में मुद्रिकन से बहा के १६ फीसदी लोगों के लिए साधन-सामग्री उत्पन्न की जाती है। शेष साधन-सामग्री तैयार माल के बदले में दूसरे देशों से जाती है। देश में साधन-पदार्थों की कम उत्पत्ति होती हुए भी, वहा के लोगों का जीवन-स्तर तुलनात्मक दृष्टि से कहीं ऊँचा है। फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि इस प्रकार से साधन-पदार्थों की प्राप्ति एक सीमा तक ही सम्भव हो सकेगी। रासार के साधन-सामग्री की कमी अभीरूपित नहीं है।

(५) माल्यस के सिद्धान्त पर एक ओर आक्षेप यह किया जाता है कि मनुष्य को उपभोक्ता की ही दृष्टि से नहीं बल्कि उत्पादक की दृष्टि से भी देखना चाहिए। मनुष्य उपभोक्ता और उत्पादक दोनों ही है। जब मनुष्य सत्तार में पैर रखता है, तो वह केवल मूह और उदर लेकर ही नहीं जाता, काम करने के लिए वो हाथ और सोचने के लिए बुद्धि भी उसके पास होती है। वस्तु, यह सोचना भूल है कि जन-संख्या में वृद्धि का होना व्यापत्तिधो को बुलाना है। कुछ हद तक जन-संख्या का बढ़ना लाभप्रद ही नहीं बल्कि आवश्यक है।

यह बात ठीक है कि मनुष्य उत्पादक है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य पैदा होते ही उत्पादक नहीं बन जाता। उसका मुँह तो पैदा होते ही चलने लगता है लेकिन हाथ-पैर और दिमाग कुछ समय के बाद चलने हैं। उस समय तक यह मुख्यतः उपभोक्ता ही रहता है।

इस तरह के अनेक आक्षेप लगाकर यह कहा जाता है कि माल्यस का जन-संख्या सम्बन्धी सिद्धान्त ठीक नहीं है, वह व्यर्थ है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाय तो माल्यस का सिद्धान्त निराधार नहीं है। यह करीब-करीब ठीक है। उसकी मच्चाई को काटा नहीं जा सकता। यदि बिना निमी बाधा और रोक-बाम के मनुष्य अपनी सन्तान पैदा करने की शक्ति का प्रयोग करता रहे, तो जन-संख्या की वृद्धि की कोई सीमा न होगी। वह निरन्तर बढ़ती जायगी। लेकिन जीवित रहने के लिए मनुष्य को खाद्य-सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। यह भूमि से उपजाई जाती है। पर भूमि का परिमाण निश्चित और परिमित है। यह घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। इस कारण भूमि की उपज वमागन उत्पात्ति-ह्रास नियम से बाध्य है। इसके फलस्वरूप भूमि से जो खाद्य-सामग्री उत्पन्न की जायगी वह भी परिमित ही होगी। ऐसी दशा में यदि जन-संख्या की वृद्धि पर

रोकथाम न रखी गयी, तो वह खाद्य-सामग्री की वृद्धि से आगे निकल जायेगी और कलस्वरूप जनाधिक्य का प्रश्न उठ खड़ा होगा। संक्षेप में, माल्थस का यही कहना था, और इसमें कोई असत्यता नहीं है। हा, यह बात अवश्य है कि मनुष्य नए-नए उपायों और सुधारों के द्वारा अगाध उत्पत्ति-ह्रास नियम को लागू न होने देने का प्रयत्न करता रहता है और इस दिशा में उसे विज्ञान के द्वारा काफी सफलता भी मिलती रही है। इससे उत्पादन की वृद्धि की दर घटने को बचाव साधारणतः बढ़ती रही है। साथ ही वह अपने रहन-सहन के दर्जे को ऊँचा करने के लिए जन-मध्या को रोकने का भी प्रयत्न करता है। अनेक पश्चिमी देशों में ऐसा ही किया जा रहा है, जिसके कारण जनाधिक्य का प्रश्न टलता जाता है, दूर हटता जाता है। भारत जैसे देशों में इस तरह के प्रयत्न कम दिखाई पड़ते हैं। इसलिए इन देशों में जनाधिक्य का प्रश्न मौजूद है और माल्थस के सिद्धान्त की सत्यता साफ नजर आती है।

माल्थस के विचारों की महत्ता इन बातों में है कि सबसे पहले उन्होंने जन-संख्या को समझ-बूझकर अपने कानू में रखने की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने यह सुझाव कि रोकथाम के माधनों का प्रयोग करके मनुष्य जन-संख्या को कम रख सकता है, और इस तरह जनाधिक्य के कष्टों से बच सकता है।

### QUESTIONS

1. What are the factors on which the growth of population of a country depends? Explain them fully
2. Name the important factors which influence birth-rate in a country. In that light show why birth-rate in India is so high?
3. State and examine the Malthusian theory of population. How far do you agree with it?



## श्रम की क्षमता (Efficiency of Labour)

जन-संख्या के अतिरिक्त श्रम की पूर्ति श्रम की क्षमता या कार्य-कुशलता पर निर्भर करती है। श्रम की क्षमता का सम्बन्ध श्रम की उत्पादन-शक्ति से है। क्षमता का आशय श्रमजीवी के उस गुण से है जिससे वह एक निश्चित समय के भीतर अधिक कार्य करने अथवा उसी कार्य को और अच्छी तरह से करने के योग्य हो जाता है। किसी श्रमिक की योग्यता, कार्य-कुशलता अथवा क्षमता की परीक्षा निम्नलिखित जांचों द्वारा हो सकती है—(क) उत्पादन का परिमाण और गुण तथा (ख) उत्पादन में कितना समय लगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित समय में अधिक उत्पादन करता है, या दूसरों से वह पहले काम समाप्त कर लेता है, अथवा उसका उत्पादन अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हुआ है, तो वह दूसरों की तुलना में अधिक कार्य-कुशल या क्षम माना जायगा। 'श्रम की क्षमता' एक सापेक्षिक शब्द है और तुलनात्मक अर्थ में ही इसका प्रयोग होता है। दो श्रमजीवियों की क्षमता की तुलना के लिए यह आवश्यक है कि उन दोनों के पास एक-सा सामान, एक-से यंत्र और एक-सी व्यवस्था हो। अन्य बातें समान होने पर, श्रमजीवियों की कार्य-क्षमता की जांच उस अन्तर से की जा सकती है जो एक निश्चित समय के भीतर उनके उत्पादन के परिमाणों और गुणों में पाया जाता है।

यह तो सभी जानते हैं कि सब श्रमिकों की कार्य-क्षमता एक-सी नहीं होती; किसी में कम होती है और किसी में अधिक। एक ही काम तथा

एक-सी दशा में काम करने वालों में से प्रत्येक का उत्पादन भिन्न-भिन्न हो सकता है। इसका कारण यह है कि श्रमिकों की उत्पादन की क्षमता अलग-अलग होती है। किसी भी देश के उत्पादन के परिमाण पर वहाँ के श्रमिकों की कार्य-क्षमता का बहुत प्रभाव पड़ता है। श्रमिक जितने अधिक कार्य-कुशल होंगे, देश का कुल उत्पादन उतना ही अधिक और अच्छा होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि जिन बातों पर कार्य-क्षमता निर्भर करती है, उनकी जाँच की जाय।

### क्षमता पर प्रभाव

(Influence on Efficiency)

वैसे तो जिन बातों का श्रमजीवियों की कार्य-क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, वे विभिन्न प्रकार की हैं, किन्तु हम उन्हें सुविधा के लिए दो विशेष भागों में बाँट सकते हैं—(१) श्रमजीवी की कार्यशक्ति और उसकी इच्छानुकूलता या रुचि, और (२) कार्य-व्यवस्था और श्रम का समझन।

(१) कार्यशक्ति और कार्य के प्रति इच्छानुकूलता—श्रमजीवी की कार्य-क्षमता उसके कार्य करने की योग्यता और कार्य के प्रति रुचि पर बहुत-कुछ निर्भर करती है। कार्य-क्षमता उस समय अधिक होगी जब शरीर और मन की शक्तियाँ सुचारु रूप से विकसित हो चुकी हों। किन्तु केवल शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ ही पर्याप्त नहीं हैं। कार्य के प्रति श्रमिक की इच्छानुकूलता भी अवश्य होनी चाहिए। इच्छा अथवा रुचि का कार्य-सम्पादन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि श्रमिक की क्षमता उसके शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य तथा शक्ति पर निर्भर होती है। किसी श्रमिक का शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य तथा शक्ति मुख्यतः निम्नलिखित बातों पर निर्भर होती है :—

(क) जातीय तथा पूर्वजों के गुण—श्रमिक अपने मा-बाप और

अपनी जाति के कुछ गुणों तथा विशेषताओं को विरासत में पाता है। इन गुणों का उसकी कार्य-क्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों की अपेक्षा, अपनी जातिगत विशेषताओं व गुणों के कारण, अधिक तगड़े, मेहनती और कार्य-कुशल होते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे देश में एक सिक्ख अथवा एक जाट का शारीरिक स्वास्थ्य अन्य भाग के निवासियों की अपेक्षा साधारणतः श्रेष्ठतर होता है। इसी प्रकार एक इटली निवासी श्रमिक की अपेक्षा एक अंग्रेज श्रमिक अधिक स्वस्थ और कुशल होता है। कार्य-क्षमता पर जातिगत गुणों का प्रभाव थोड़ा-बहुत पड़ता तो अवश्य है, फिर भी प्रत्येक जाति प्रयत्न करने पर कुशल हो सकती है। जापानी इस बात के मथूत हैं।

(ख) प्राकृतिक दशाएँ तथा जलवायु—कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार देश की प्राकृतिक दशाओं और जलवायु का श्रमिक की कार्य-क्षमता तथा उसके शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उनके अनुसार समशीतोष्ण जलवायु में लोग अधिक मानसिक और शारीरिक परिश्रम कर सकते हैं। अतः वे दूसरों से अधिक कार्य-कुशल होते हैं। जहाँ बहुत गर्मी व सर्द पड़ती है, वहाँ के लोग अधिक समय तक मेहनत के साथ काम नहीं कर सकते और इस कारण उनकी कार्य-कुशलता घट जाती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कार्य-क्षमता जलवायु से प्रभावित होती है, किन्तु इस पर अधिक बल देना ठीक नहीं है। यह बात बहुत-कुछ अभ्यास और परिस्थिति पर निर्भर करती है। गर्म देश के एक मोहार को ले लीजिए। वह अभ्यास और परिस्थिति के कारण आग की भट्ठी के सामने गर्मी के दिनों में घण्टों लगातार काम करता रहता है। अभ्यास न होने पर समशीतोष्ण देश का रहने वाला उसी भट्ठी के सामने एक घंटा भी नहीं ठहर सकता; अस्तु, जलवायु से कहीं अधिक प्रभाव अभ्यास, परिस्थिति, स्वभाव, आदि बातों का पड़ता है।

(ग) रहन-सहन का दर्जा—यह उन बातों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जिन पर धर्म की कार्य-क्षमता निर्भर करती है। प्रत्येक श्रम-जीवी को ठीक तरह से काम करने के लिए पर्याप्त और स्वास्थ्यप्रब मोजन, उचित वस्त्र, हवादार और स्वच्छ मकान, दवा और विश्राम-सम्बन्धी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। जिनको ये सब चीजे उचित मात्रा में उपलब्ध होती है, उनकी कार्य-क्षमता अधिक होती है। इन वस्तुओं के अभाव में, रहन-सहन का दर्जा गिर जायेगा। उस दशा में रोग, चिन्ता, कमजोरी, आदि बातें मनुष्यों को सदा घेरे रहेगी जिनके कारण वह ठीक से काम करने योग्य न रह जायेगा। चिन्ता मनुष्य और उसकी कार्य-क्षमता के लिए काल-स्वरूप है।

(घ) नैतिक गुण—ईमानदारी, सच्चाई, निर्भयता, धैर्य, उत्तरदायित्व, दृष्टाशक्ति, आदि नैतिक गुणों का धर्मिक की कार्य-क्षमता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ये सब गुण 'चरित्र' शब्द में समावेष्टित हैं। मनुष्य के चरित्र का मुख्य आधार शिक्षा होता है। घर, समाज और धर्म आदि बातों का भी चरित्र पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि किसी धर्मिक का चरित्र अच्छा है, तो निमन्देह उसकी कार्य-क्षमता अधिक होगी वह अधिक कर्तव्यपरायण और उत्तरदायित्व समझने वाला होगा। चरित्रहीन मनुष्य में कार्य-कुशलता बहुत कम होती है।

(ङ) साधारण और वैज्ञानिक शिक्षा—कार्य-क्षमता के लिए शारीरिक शक्ति की ही नहीं, बल्कि बौद्धिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। शिक्षा से लोगों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। उनकी मानसिक और नैतिक दृष्टियों को मकीर्णताएँ दूर हो जाती हैं और उनमें उत्तरदायित्व, युक्ति, धैर्य, निर्णय, आदि के गुण आ जाते हैं।

साधारण शिक्षा के अतिरिक्त, कार्य-क्षमता के लिए थोड़ी-बहुत वैज्ञानिक व टेक्नीकल शिक्षा भी आवश्यक है। ऐसी शिक्षा में व्यावहारिक रूप में किसी काम का ऐसा ज्ञान हो जाता है जिससे उसे ठीक

तरह से कार्य-मे-कर्म समय और लागत में लिया जा सकता है। टेक्नीकल शिक्षा द्वारा श्रमजीवी कार्य विशेष में दक्षता प्राप्त कर लेता है जिससे उमरी कार्य-क्षमता बहुत बढ़ जाती है।

(घ) स्वतन्त्रता और उन्नति की आशा—इसने पहले कि धर्मिक अपना काम सुचारु रूप में कर सके तथा उस कार्य में दक्षता प्राप्त कर सके, उसने जीवन में स्वतन्त्रता, कपीकता और उन्नति की आशा का समावेश होता आवश्यक है। स्वतन्त्र और आशापूर्ण धर्मिक में कार्य-क्षमता बहुत होती है। धर्मिक कार्य-क्षमता के लिए धर्मिक को इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि यदि उसका काम अच्छा हुआ तो उसे धर्मिक में आगे बढ़ने में उन्नति करने का मौका मिलेगा। मुसलमान तो स्वतन्त्र होते हैं और न ही उनके लिए कोई आशा होती है। फलस्वरूप उनकी कार्य-क्षमता बहुत कम होती है। इसके अलावा काम ऐसा होना चाहिए कि उसमें मातृसिक्त न रहे। यदि कार्य की प्रकृति थोड़ी-बहुत बदलती रहे तो धर्मिक में गई स्फूर्ति, गई उत्पादन-शक्ति आ जाती है। अतः कुछ अलग तब धर्म की कार्य-क्षमता धर्मिक की आशा, स्वतन्त्रता और परि-कलन पर निर्भर करती है।

(ङ) मजदूरी का स्तर—जो मजदूरी निम्नी धर्मिक को उसके काम के बदले में मिलती है, उसका उत्तरी कार्य-क्षमता और इच्छा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक सीमा तक जिसकी अधिक मजदूरी निम्नी धर्मिक को मिलेगी, उतनी ही अधिक इच्छा-शक्ति और कार्य-क्षमता उसमें होगी। पर्याप्त और उचित मजदूरी मिलने पर धर्मिक सन्तुष्ट रहेगा और उसका जीवन-स्तर भी ऊँचा हो सकेगा। स्वास्थ्यप्रद भोजन, पर्याप्त वस्त्र, हवादार मकान, आदि जरूरी चीजें उसे मिल सकेंगी। फलस्वरूप उसकी कार्य-क्षमता अधिक होगी। चिन्तु यदि मजदूरी कम है, तो धर्मिक बराबर असन्तुष्ट रहेगा और वह जीवन तथा कार्य-क्षमता सामान्यी आश-

इयकलाओं को पूरा न कर सकेगा। ऐसी दशा में वह किसी भी प्रकार की उत्पत्ति न कर सकेगा। फलस्वरूप उसकी कार्य-क्षमता कम होगी।

कार्य-क्षमता के लिए उचित मजदूरी के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि मजदूरी ठीक ढंग से और नियत समय पर दी जाय। जब किसी श्रमिक को यह विश्वास होता है कि जो कार्य वह कर रहा है उसके बदले उसे शीघ्र और प्रत्यक्ष रूप में उचित मजदूरी मिलेगी, तो वह उस कार्य को ठीक और जल्दी से पूरा करने की अवश्य कोशिश करेगा।

(घ) काम करने के घटे—श्रमिकों की कार्य-कुशलता इस बात पर भी बहुत-कुछ निर्भर करती है कि उन्हें मिलने वाले काम कारना पड़ता है और काम के बीच में विधाय के लिए पर्याप्त समय मिलता है या नहीं। अधिक घटो तक काम करने में श्रमिक के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उसे थकावट लगने लगती है, उसका ध्यान बैठने लगता है, और एक सीमा को बाद ठीक तरह से काम करता उसके लिए असम्भव-सा हो जाता है। अस्तु, काम करने का समय अधिक न होने पर श्रमिक की कार्य-क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा काम के बीच में विधाय के लिए समय देने से भी कार्य-क्षमता बढ़ जाती है। इसमें शकावट दूर हो जाती है और फिर से काम करने के लिए श्रमिक की नई स्फूर्ति और शक्ति मिल जाती है।

(ङ) काम करने की सुविधाएँ—अनुभव में यह भी देखा गया है कि जिस स्थान पर श्रमिक काम करता है, वहाँ के वातावरण का उसके स्वास्थ्य और नैतिक विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि कारखानों में हवा, सफाई, रोशनी, पानी, आदि अन्य स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातों का उचित प्रवण हो तो श्रमिकों की कार्य-क्षमता बढ़ जाती है। यहाँ तक देखा गया है कि यदि कारखानों में कम शोरगुल होता है, अथवा दीवारों पर अच्छा रंग हो तो श्रमिकों की कार्य-कुशलता बढ़ जाती है।

(च) सामान की अच्छाई—कार्य-क्षमता कुछ अंश तक इस बात पर भी निर्भर है कि श्रमिक जिस ठान की मशीनों और कच्चे माल की सहा-

यता मे काम करता है। जितना ही अच्छा उसे काम करने के लिए सामान दिया जायगा, उतनी ही अधिक उनकी कार्य-क्षमता होगी। एक अव्रेन के काम में जो सफाई और तेजी दिखाई देती है, उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि वह अच्छी मशीनों पर काम करता है और उसे श्रद्धा किस्म का कच्चा माल दिया जाता है।

(२) धर्म की व्यवस्था और उसका संचालन—श्रमिक की कार्य-क्षमता इस पर भी बहुत-कुछ निर्भर है कि धर्म की व्यवस्था, उसका प्रबन्ध और संचालन किस ढंग से किया जाता है। यदि मालिक व मजदूर का व्यवहार और रस अच्छा हो तथा कार्य का वैज्ञानिक रूप में विभाजन किया जाय और प्रत्येक श्रमिक को वही काम दिया जाय जिसके वह योग्य हो, तो धर्म की कार्य-क्षमता अवश्य अधिक होगी। इसी प्रकार यदि धर्म का उपयोग व मिलान उत्पत्ति के अन्य साधनों के साथ ठीक ढंग से हो और श्रमिक की भिन्न-भिन्न शक्तियों के समुचित विकास के लिए यथेष्ट साधन उपस्थित हो, तो धर्म की उत्पादन-शक्ति में अवश्य वृद्धि होगी। श्रमिकों के समुचित संगठन से भी उनकी कार्य-कुशलता बहुत बढ़ जाती है। यदि श्रमिक अच्छे और प्रभावपूर्ण ढंग से मजदूर संघ के रूप में संगठित हों, तो कार्य-क्षमता अधिक होगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म की कार्य-कुशलता विभिन्न बातों पर निर्भर होती है। संक्षेप में, हम यह सकते हैं कि श्रमिकों की कार्य-क्षमता कुछ अंश तक उनके शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य पर निर्भर रहती है, कुछ मालिक की समझ-बुद्धि पर, कुछ काम करने के घरे, मजदूरी और मशीन व कच्चे माल पर तथा कुछ अंश तक कारखानों के वातावरण, भविष्य की ज्ञान और स्वतन्त्रता पर निर्भर करती है। इससे यह भी स्पष्ट है कि कार्य-कुशलता के कम होने का दोष केवल श्रमिकों पर ही नहीं थोपा जा सकता। इनमें से अनेक बातें ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध श्रमिकों से नहीं बल्कि कारखानों के वातावरण, काम करने की

दशाओं तथा अन्य बाहरी बातों से है।

कार्य-कुशल श्रम से सबको लाभ पहुँचता है। अपनी कार्य-कुशलता से श्रमिकों को तो लाभ मिलता ही है। वे कार्य को जल्दी सीख लेते हैं और उन्हें अधिक मजदूरी भी मिलती है और फलस्वरूप वे अपने जीवन-स्तर को उभार उठा सकते हैं। मालिक को भी बड़ा लाभ नहीं पहुँचता। कार्य-कुशल श्रमिक पर देखरेख की बराबर जरूरत पड़ती है। वे सामान को ठीक और किरायावत से इस्तेमाल करते हैं और काम को दिये हुए समय में पूरा कर लेते हैं। उत्पादन अधिक और अच्छा होता है और प्रति इकाई लागत कम बैठती है। इससे मालिकों को ही नहीं बल्कि सारे देश को लाभ पहुँचता है। ऐसा देश आर्थिक क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर सकता है। भारत कुछ देशों से आर्थिक क्षेत्र में इस कारण भी पिछड़ा हुआ है कि यहां के श्रमिकों की कार्य-क्षमता अपेक्षाकृत कम है।

### भारतीय श्रम की कार्य-क्षमता

(Efficiency of Indian Labour)

साधारण तौर पर यह कहा जाता है कि भारतीय श्रमिकों की कार्य-क्षमता बहुत कम है। इंग्लैंड और भारतवर्ष के श्रमिकों की कार्य-क्षमता की तुलना करने के लिये ही प्रयत्न किये गये हैं। कहा जाता है कि एक निश्चित समय में एक अंग्रेज मजदूर हिन्दुस्तानी मजदूर की अपेक्षा चार गुना उत्पादन करता है। इससे यह परिणाम निकाला जाता है कि भारतीय श्रमिक की अपेक्षा एक अंग्रेज मजदूर की कार्य-क्षमता चार गुना अधिक है। यह तो सच है कि भारतीय श्रम की कार्य-कुशलता कम है, किन्तु इस तरह की तुलना करना ठीक नहीं है। दोनों देशों में मजदूरी, मशीन, बच्चा माल, श्रम-विभाजन, मनोरंजन की सुविधाएँ, कारखानों के प्रबंध, आदि में इतना अन्तर है कि श्रम की कार्य-क्षमता की तुलना नहीं की जा सकती। तुलना तभी ठीक सिद्ध हो सकती है जबकि दोनों देशों में अन्य सब बातें एक समान हों। एक अंग्रेज मजदूर का उत्पादन अवश्य अधिक है, पर यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसे एक भारतीय



मजदूर की अपेक्षा कहीं अधिक मजदूरी मिलती है। जान करने के लिए उसे नई मशीनें और अच्छे किस्म का कच्चा माल दिया जाता है। उसे और बहुत-सी सुविधाएँ मिलती हैं जो यहाँ के मजदूरों को नहीं मिलती हैं। इन सब कारणों से एक अंग्रेज मजदूर एक भारतीय श्रमिक की अपेक्षा अधिक उत्पादन करता है। भारतीय श्रमिक की कार्य-क्षमता जग से ही कम नहीं है। कार्य-क्षमता की कमी बहुत-कुछ यहाँ की परिस्थितियों का फल है।

इसके विपरीत कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय श्रमिक बहुत कार्य-कुशल है। अपनी इस बात की पुष्टि के लिए वे कहते हैं कि भारत-वर्ष में और देशों की अपेक्षा उसी मजदूरी पर अधिक परिमाण में उत्पादन होता है। यदि एक अंग्रेज मजदूर एक हिन्दुस्तानी मजदूर का चार गुना उत्पादन करता है, तो उसे चार गुना अधिक वेतन भी तो मिलता है। हिन्दुस्तान में मजदूरी इतनी कम है कि प्रति इकाई उत्पत्ति की लागत बहुत कम पड़ती है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भारतीय श्रम में बहुत क्षमता है। किन्तु कार्य-क्षमता की इस प्रकार में जांच करना ठीक नहीं है। श्रम की कार्य-क्षमता को श्रम-सम्पन्नी व्यक्ति में नहीं जाचना चाहिए। किसी श्रमिक की कार्य-क्षमता की जांच करने का एकमात्र साधन यह है कि जिस वस्तु का वह एक निश्चित समय में उत्पादन करता है, उसके परिमाण और गुणों की जांच की जाय। इस दृष्टि से देखने पर भारतीय श्रमिक निरसदेह अपेक्षाकृत कम कार्य-कुशल है। यहाँ का एक श्रमिक दिये हुए समय में जो कुछ उत्पादन करता है वह निश्चय ही बहुत थोड़ा है। हा, यह अवश्य है कि इस बात के लिए उसे बहुत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। विभिन्न कारण ऐसे हैं जिन पर उनका कोई बल नहीं। अतएव यह बहना अधिक उपयुक्त होगा कि वह स्वयं अकुशल नहीं है, परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया है।

भारतीय श्रमिकों की असंगतता अथवा कम कार्य-कुशल होने के अनेक कारण हैं जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं —

(१) गरीबी और नीचा जीवन-स्तर—अधिकांश भारतीय मजदूरों को बहुत खोपी मजदूरी मिलती है। वे बहुत गरीब हैं और इस कारण उनका जीवन-स्तर अत्यन्त ही नीचा और अमनोपजनक है। गरीबी के कारण वे जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं तक को भी पूरा नहीं कर पाते। उन्हें स्वास्थ्यप्रद भोजन उपयुक्त मात्रा में नहीं मिलता। वे अचपेट खाते हैं और भूखे मरते हैं। फलस्वरूप वे कमजोर और प्रायः रोगग्रस्त होते हैं। ऐसी दशा में मला किस प्रकार कार्य-क्षमता अधिक हो सकती है। जब गरीबी के कारण अचपेट और अच्छा भोजन मिलना मुश्किल है तो दवा, मनोरंजन, आदि की सुविधाएँ कैसे मिल सकती हैं। इन सब बातों का कार्य क्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

(२) मकानों की असंतोषजनक व्यवस्था—जिस प्रकार श्रमिकों के लिए स्वास्थ्यप्रद भोजन का प्रश्न महत्त्वपूर्ण है, उसी प्रकार साफ और हवादार मकानों का भी प्रश्न उतना ही महत्त्वपूर्ण है। अधिकांश भारतीय श्रमिकों के रहने के लिए कोई ठीक प्रबन्ध नहीं है। वे गन्दी बस्तियों में छोटे-छोटे कमरों में रहते हैं जिनमें हवा, रोशनी, आदि का कोई भी प्रबन्ध नहीं होता। इसका उनके स्वास्थ्य और चरित्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उनको एक न एक रोग घेरे रहते हैं और साथ ही शराबखोरी, जुआवाजी आदि बुराईयाँ भी तेजी से फैलती हैं। इन सबसे उनके जीवन और कार्य-क्षमता को बहुत क्षति पहुँचती है।

इसके अलावा मकान का उचित प्रबन्ध न होने से श्रमिक अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते। प्रायः वे परिवार के अन्य लोगों को गाँव में ही छोड़ आते हैं। इससे केवल पारिवारिक जीवन को ही धक्का नहीं लगता बल्कि कई अन्य समस्याएँ पैदा होती हैं। श्रमिक स्थायी रूप से कारखानों व काम के स्थानों पर नहीं बसते। वे बराबर घर लौट जाने के लिए में रहते हैं। इसलिए न तो वे दिल लगाकर काम कर पाते हैं और न ही उपयुक्त ट्रेनिंग पाने की कोशिश करते हैं। फलस्वरूप उनका बौद्धिक

उत्पादन कम बैठता है और जैसाकि ऊपर का जा चुका है इसी के बाधा पर कार्य-क्षमता की माप की जाती है ।

(३) शिक्षा और ट्रेनिंग की कमी—एक अन्य महत्वपूर्ण कारण जिसके फलस्वरूप कार्य-क्षमता कम है, वह है देश में शिक्षा और ट्रेनिंग का अभाव । महा के अधिकांश श्रमिक अनिश्चित हैं और उन्हें काम करने के लिए ठीक प्रकार से ट्रेनिंग नहीं मिलती । फलस्वरूप कारीगरी और बुद्धिमत् विश्वास में बाधा पड़ती है । और यह वो सर्व-विदित है कि एक शिक्षित श्रमिक, अनिश्चित श्रमिक की अपेक्षा, अधिक और अच्छा उत्पादन करता है ।

(४) जलवायु और काम के अधिक घटे—कहा जाता है कि देश की उष्ण जलवायु का श्रमिक के स्वास्थ्य और उसको कार्य-क्षमता पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । साथ ही उसे अधिक घटो तक काम करना पड़ता है । इससे उसकी कार्य-क्षमता और भी कम हो जाती है । फेवरी कानूनो के धन जाने से काम करने के घटे कम हो गये हैं, फिर भी कुछ स्थानों पर श्रमिकों को अधिक घटो तक काम करना पड़ता है ।

(५) दूषित वातावरण—भारतीय मिलों और कारखानों में काम करने का जो वातावरण है वह भी बहुत दूषित और असुविधाजनक है । अनेक कारखाने गन्दी और घनी बस्तियों में स्थित हैं । उनमें न तो सफाई है और न ही हवा और रंगती का अच्छा प्रवण है । श्रमिकों के विधाय और मनोरंजन के लिए सुविधाएँ नहीं के बराबर हैं । ऐसी परिस्थितियों में श्रम की कार्य-क्षमता अवश्य ही कम होगी ।

(६) घटिया सामान और त्रुटिपूर्ण व्यवस्था—निस्संदेह भारतीय श्रमिकों की कम कार्य-क्षमता का प्रमुख कारण यह है कि उन्हें काम करने के लिए घटिया और पुराना सामान दिया जाता है और कारखानों की व्यवस्था भी ठीक नहीं होती । भारतीय मिलों में अच्छी और नवीनतम मशीनों का कम प्रयोग होता है । प्रायः मशीनें पुरानी और घिसी हुई

होती है। श्रमिकों को जो कच्चा माल काम करने के लिए दिया जाता है, वह भी अच्छा नहीं होता। काफी समय उसके सुधारने और ठीक करने में निकल जाता है। इसके अलावा भारतीय कारखानों में वैज्ञानिक प्रबन्ध और व्यवस्था का भी अभाव रहता है। वैज्ञानिक श्रम-विभाजन और व्यवस्था से श्रमिक की क्षमता को विकसित कर तथा उनको पूर्ण रूप से उपयोग में लाकर कार्य-क्षमता बढ़ाई जा सकती है। किन्तु हमारे अधिकांश कारखानों में इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। फिर यदि कार्य-क्षमता कम है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं।

इस तरह के अनेक कारणों से भारतीय श्रमिकों की कार्य-क्षमता कम है। इनके विश्लेषण और अध्ययन से स्पष्ट है कि भारतीय श्रमिकों में कोई निजी दोष व कमी नहीं है जिसके कारण वे अपने काम में कुशल नहीं हैं। जिन परिस्थितियों और वातावरण में वे रहते और काम करते हैं, वे इतने खराब हैं कि कार्य-क्षमता कम हुए बिना नहीं रह सकती। इनमें सुधार लाकर भारतीय श्रमिकों की कार्य-क्षमता काफी बढ़ाई जा सकती है।

## श्रम की गतिशीलता

(Mobility of Labour)

कार्य-क्षमता पर श्रम की गतिशीलता का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। श्रम के स्थान अथवा व्यवसाय-परिवर्तन को श्रम की गतिशीलता (mobility of labour) कहते हैं। श्रम की गतिशीलता में यह अभिप्राय है कि श्रमजीवी अधिक बेतन मिलने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में आसानी से जा-जा सकते हैं। यदि यथेष्ट रूप से श्रमिक के लिए स्थान व व्यवसाय-परिवर्तन सम्भव हो तो उसकी कार्य-क्षमता में अवश्य वृद्धि होगी और साथ ही धन-वितरण की असमानता भी काफी हद तक दूर हो जायगी। इतना ही नहीं,

फिर तो देश की अर्थ-व्यवस्था में आवश्यकतानुसार और आसानी से परिवर्तन लाया जा सकता है। अर्थ-व्यवस्था में लोभ का गुण होने पर अनेक कठिनाइयों और समस्याओं को सुगमता से दूर किया जा सकता है। वैसे तो यम में उत्पत्ति के अन्य साधनों की अपेक्षा कहीं अधिक गतिशीलता है। भूमि एक दम स्थिर है और कुछ हद तक पूँजी भी स्थिर होती है। फिर भी धन की गतिशीलता में, चाहे वह स्थान-परिवर्तन हो या व्यवसाय-परिवर्तन, अनेक रुकावटें होती हैं। सर्वप्रथम परिवार, मित्र, आदि का मोह लोगों के घर छोड़ने में बाधक होता है। दूसरे, भिन्न-भिन्न स्थानों का रहन-सहन, जलवायु, बोल-चाल, रीति-रिवाज, आदि अलग-अलग होते हैं। ये सब बातें मनुष्य को अपरिचित स्थानों में जाने से रोकती हैं। कभी-कभी अधिक वेतन मिलने पर भी लोग यह सोचकर दूसरे स्थानों पर जाते हुए हिचकते हैं कि पता नहीं उन स्थानों पर किस प्रकार का भोजन मिलेगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, उनकी भाषा समझ में आयेगी या नहीं। इसके अतिरिक्त स्थान-परिवर्तन में कुछ खर्च भी लगता है। कई तो खर्च के कारण ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं आ-जा पाते। अतः जहाँ भी धन की भौगोलिक गतिशीलता में रुकावट डालती है। कुछ लोगों को यह ज्ञान नहीं होता कि किन स्थानों में अधिक वेतन मिल सकता है, और वहाँ कैसे और कब जाया जाय।

भारतवर्ष के श्रमिकों में गतिशीलता विशेष रूप से कम है। इसके कई कारण हैं। देश में अज्ञानता और निर्धनता का साम्राज्य है। अधिकतर लोग गृहप्रिय और भाग्यवादी हैं। वे यह सोचते हैं कि जो भाग्य में लिखा है, वह तो होकर ही रहेगा। उसे मिटाया नहीं जा सकता। फिर दूधर-उधर घूमने-फिरने में क्या लाभ। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में कई ऐसी सामाजिक तथा धार्मिक रीतियाँ हैं जिनमें धन की गतिशीलता में बाकी रुकावट पड़ती है। निम्न जीवन-संक्रम के बढ़ते में उपर्युक्त बाधाएँ धीरे-धीरे दूर होती जा रही हैं। यातायात के साधनों में उन्नति होने से

इस ओर काफी सहायता मिली है। अब शहर के कारखानों में बहुत दूर-दूर के लोग काम करते दिखाई पड़ते हैं।

अधिक गतिशीलता अथवा व्यवसाय-परिवर्तन में भी अनन्त बाधाएँ होती हैं। एक धंधे को छोड़ कर दूसरे धंधे को अपनाने के पहले उस धंधे की ज्ञानकारी आवश्यक है। यदि उस धंधे के सीखने में अधिक समय, शिक्षा और अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, तो श्रम की गतिशीलता अवश्य कम होगी। जिन धंधों में किसी विशेष प्रकार की योग्यता अथवा निपुणता की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ गतिशीलता अधिक होती है। उदाहरण के लिए मान लो एक रेलवे कुली इंद्र ढाँने का काम करना चाहता है, क्योंकि उस काम में अधिक गजदूरी गिलने की आस है। वह अब चाहे इस तरह का परिवर्तन कर सकता है। उसे इसके लिए किसी प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। अतएव साधारण कार्यों में श्रम की गतिशीलता अधिक होती है। किन्तु यदि कोई जाबदारी का काम करना चाहे, तो यह आसानी से सम्भव नहीं है। इसके लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा और ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। उस ढंग की शिक्षा प्राप्त करने में काफी समय और धन लगेगा। इसलिए कुशल कार्यों में साधारण कार्यों की अपेक्षा गतिशीलता कम होती है।

## QUESTIONS

1. What do you mean by efficiency of labour? In what ways can it be measured?
2. What are the main factors on which efficiency of labour depends? Explain them fully
3. Is Indian labour inefficient? If so, why?
4. What is mobility of labour? Examine main hindrances which obstruct the movement of labour from place to place and occupation to occupation.

## अध्याय २०

### श्रम-विभाजन

#### (Division of Labour)

श्रम-विभाजन वर्तमान अर्थ व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है और श्रम की कार्य-क्षमता पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है। सर्वप्रथम यह जान लेना उचित होगा कि श्रम विभाजन का अर्थ क्या है। किसी एक काम के कई भाग और उप-विभाग करता और उन्हें भिन्न-भिन्न श्रमिकों के बीच उनकी शक्ति और योग्यतानुसार बांटना, अर्थशास्त्र में, श्रम-विभाजन (division of labour) कहलाता है। श्रम-विभाजन के अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिक को किसी काम का साधारणतः केवल वही भाग दिया जाता है जिसमें उसकी विशेष रुचि होती है। वह सभी को बराबर करता है जिससे आसानी से वह उस काम में विशिष्ट या विशेषज्ञ हो जाता है। श्रम-विभाजन में सब व्यक्ति अलग-अलग भागों पर एक साथ मिलकर काम करते हैं और सबके सहयोग से काम पूरा होता है। अस्तु, व्यक्तिगत दृष्टि से श्रम विभाजन को 'विशिष्टीकरण' (specialisation) कह सकते हैं और समाज की दृष्टि से उसे 'सहकारिता' (co-operation) कहा जा सकता है।

मानव-जीवन के प्रारम्भिक काल में, जब आवश्यकताएँ बहुत थोड़ी और सरल थीं, प्रत्येक मनुष्य अपनी छोटी-बड़ी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं ही अपने-आप प्रत्येक वस्तु को जुटाता था। जिस वस्तु की उसको आवश्यकता होती थी, वह अपने आप ही उसे प्राप्त

करने का प्रयत्न करता था। धीरे-धीरे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गईं, और उसे अपनी थनाई हुई चीजों से अपनी आवश्यकताओं की तृप्ति करने में असुविधा होने लगी। ज्ञान और अनुभव से वह इस बात पर पहुँचा कि यदि लोग मिल-जुलकर काम करें और भिन्न-भिन्न कार्यों को आपस में बाँट लें, तो बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति यथेष्ट रूप में सम्भव हो सकती है। फलतः धीरे-धीरे लोग अपनी-अपनी शक्ति, क्षमता, रुचि, सुविधा और परिस्थिति के अनुसार अलग-अलग काम व पेशे में लग गये। कुछ व्यक्तियों ने एक काम ले लिया, और कुछ ने दूसरा। कोई किसान दान बैठा, कोई जुलाहा और इस तरह हर एक व्यक्ति अपनी शक्ति और योग्यतानुसार पृथक्-पृथक् काम करने लगा। अपने वनाशे हुए पदार्थ अन्य व्यक्तियों को देकर उनसे उनकी थनाई हुई वस्तुएं लेकर आवश्यकताएं तृप्त की जाने लगी। इससे आवश्यकताओं की तृप्ति में बहुत सुविधा हुई। सम्पत्ता की वृद्धि के साथ-साथ आगे चलकर प्रत्येक कार्य के बहुत से विभाग और उपविभाग होते गए और प्रत्येक विभाग या उपविभाग का कार्य एक व्यक्ति या व्यक्ति-समूह करने लगा। उदाहरणार्थ पिन बनाने का काम ले लो। यह छोटा-सा काम अब कई सूक्ष्म भागों में विभाजित है। कोई तार को खींचता है, कोई उसे पतला करता है, कोई उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटता है, कोई उसको नुकीला करता है, कोई उस पर घुंछी लगाता है, कोई पालिश करता है, इत्यादि। इस तरह हम देखते हैं कि समय के साथ-साथ श्रम-विभाजन के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है। वर्तमान समय में श्रम विभाजन बहुत विकसित अवस्था में है। अब यह पहले से बहुत अधिक चारों ओर जटिल हो गया है।

श्रम-विभाजन आधुनिक जगत का आधार है। बिना इसके आर्थिक जीवन मुबारक रूप से नहीं चल सकता। मनुष्य ने जो कुछ उन्नति आज तक की है उसमें श्रम-विभाजन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की कार्य-क्षमता की वृद्धि का मुख्य कारण श्रम-विभाजन



है। यदि श्रम-विभाजन की सुविधा न हो, तो वर्तमान जन-संख्या के एक छोटे से भाग का भी निर्वाह होना कठिन हो जायगा। उस समय मनुष्य की अनेक आवश्यकताएँ अतृप्त ही रह जायगी, और उमका जीवन-स्तर बहुत ही नीचे गिर जायगा।

### श्रम-विभाजन के रूप

(Forms of Division of Labour)

ऊपर कहा जा चुका है कि श्रम-विभाजन आधुनिक आर्थिक मसाले का आधार स्वरूप है। लेकिन इसका यह आशय नहीं कि श्रम-विभाजन आधुनिक काल की देन है और यह पहले नहीं था। वास्तव में बहुत पूर्व-काल में ही श्रम-विभाजन चलता आया है। हा, यह बात अवश्य है कि पहले इसका रूप बहुत सीधा-सादा और साधारण था। शुरु-शुरु में सुविधा का त्याग करके पुरुष और नारी के बीच काम का बंटवारा किया गया। पुरुष ने शिकार आदि का काम अपने ऊपर ले लिया और स्त्री बाल-बच्चों और घर का काम सम्भालने लगी। कुछ समय बाद भिन्न-भिन्न काम पेशे के अनुसार बंट गये और लोग अलग-अलग पेशों में लग कर काम करने लगे। धीरे-धीरे उन्नति और सम्पत्ता में वृद्धि के साथ एक ही पेशे का काम विभिन्न उपविभागों में बंट गया और फल-स्वरूप श्रम-विभाजन पहले से अधिक प्रभावपूर्ण और जटिल हो गया। आगे चलकर अब यह स्थिति आ पहुची है कि उपविभागों के भी अनेक उपविभाग कर दिये गये हैं और श्रमिक इन्हीं अपूर्ण उपविभागों को करते हैं। यही नहीं, वर्तमान समय में भिन्न-भिन्न स्थान, सुविधा और परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग कार्यों को अपना रहे हैं। अस्तु, श्रम-विभाजन अनेक स्थितियों में गुजरा है और इसके रूप और विस्तार में बहुत परिवर्तन हुए हैं। विशेष में, मोटे तौर पर श्रम-विभाजन के तीन रूप व स्थितियाँ हैं —

(१)\* साधारण श्रम-विभाजन (Simple Division of Labour)—श्रम-विभाजन के इस रूप या स्थिति में एक व्यक्ति

सब प्रकार का काम करने के बजाय अपनी योग्यतानुसार किसी एक विशेष व्यवसाय अथवा पेशे में लग जाता है। उस पेशे को वह आदि स अनन्त तक करता है। उदाहरणार्थ कोई कृषि कार्य करता है, कोई कपड़ा तैयार करता है, कोई बर्तन का काम करता है और कोई लोहार का। स्पष्ट शब्दों में, साधारण धम-विभाजन में मिश्र-मिश्र पेशों को अलग-अलग कर दिया जाता है और प्रत्येक धर्मिक अपनी कुल शक्ति को एक ही पेशे में लगाता है। विनिमय द्वारा वह अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

(२) जटिल व मिश्रित धम-विभाजन (Complex Division of Labour)—विभाजन के इस रूप में एक ही पेशे अथवा कार्य के कई भाग कर दिये जाते हैं, और एक व्यक्ति कार्य का केवल एक ही भाग करता है। उदाहरण के लिए कपड़े के व्यवसाय को कई भागों में बांट दिया जाता है। कोई व्यक्ति कपास पैदा करता है, कोई उसे ओढ़ता है, कोई सूत कातता है, कोई कपड़ा बुनता है, इत्यादि। इस तरह एक ही कार्य के अनेक हिस्से कर दिये जाते हैं जिसे अलग-अलग व्यक्ति या व्यक्ति-संग्रह करते हैं। हर काम का प्रत्येक भाग स्वतः पूर्ण होता है और उसके परिणामस्वरूप तैयार होने वाली वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए कच्चे माल का काम देती है जिससे वह उसी भाग की क्रिया करने लग जाता है।

धम-विभाजन का विकास-काल और आगे बढ़ता है। एक काम के कई सूक्ष्म उपविभाग कर दिये जाते हैं। प्रत्येक उपविभाग अपूर्ण होता है और बहुत से उपविभागों का काम समाप्त होने पर ही अभीष्ट वस्तु तैयार होती है। आधुनिक कल-कारखानों में, जहाँ उत्पत्ति बड़े पैमाने पर होती है, इस तरह के धम-विभाजन का अनुकरण किया जाता है।

(३) प्रादेशिक व भौगोलिक धम-विभाजन (Geographical Division of Labour)—इसको उद्योग-धर्मों का स्थानीयकरण

भी रहते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक श्रमिक को उमकी शक्ति और रुचि के अनुसार एक विशेष काम सौंप दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार एक स्थान पर वहाँ की प्राकृतिक तथा अन्य सुविधाओं के अनुसार एक विशेष धन्धा किया जाने लगता है। वह स्थान उस धन्धे के लिए धीरे-धीरे केन्द्र बन जाता है। भिन्न-भिन्न स्थानों पर अलग-अलग उद्योग-धन्धों के केन्द्रित होने को अर्थशास्त्र में प्रादेशिक श्रम-विभाजन अथवा उद्योग-धन्धों का स्थानीयकरण (*Localisation of Industries*) कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में जूट के कारखाने बंगाल में, कपड़े की मिलें बम्बई और अहमदाबाद में तथा चूनी का व्यवसाय फिरोजपुर में केन्द्रित हैं। श्रम-विभाजन के इस पहलू या रूप का अध्ययन एक अगले अध्याय में किया जाएगा।

### श्रम-विभाजन से लाभ

(*Advantages of Division of Labour*)

श्रम-विभाजन से मानव-शक्ति को बहुत लाभ पहुँचा है। आदिम, सामाजिक, यदि अन्य क्षेत्रों में जो आज तक इतनी उन्नति व प्रगति हो पाई है, उमका बहुत-कुछ श्रेय श्रम-विभाजन को है। इसके द्वारा व्यक्ति और राष्ट्र की शक्तियों का पूरा-पूरा उपयोग सम्भव हो जाता है। इससे उत्पादन-शक्ति बहुत बढ़ जाती है और साथ ही उत्पादन के प्रकार में भी बहुत उन्नति होती है। आज हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की, वैश्व-विदेश को बनी हुई वस्तुओं का सेवन करते हैं जिनमें हमारी सुख-समृद्धि में बहुत वृद्धि हुई है। यह श्रम-विभाजन के कारण ही सम्भव हो पाया है। इसकी अनुपस्थिति में हर व्यक्ति को अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रत्येक वस्तु स्वयं ही तैयार करनी पड़ेगी। निस्संदेह वह आज तक जितनी वस्तुओं का उपयोग करता है, उसका एक सूक्ष्म भाग भी तैयार न कर सकेगा। अस्तु, सम्यक् जीवन के लिए, उन्नति और प्रगति के लिए, श्रम-विभाजन अनिवार्य है। इसके मुख्य लाभों का वर्णन नीचे किया जाता है।

(१) कार्य-क्षमता में वृद्धि—किसी एक काम को लगातार करते रहने से मनुष्य की शारीरिक तथा मानसिक शक्तिया उस विशेष काम के लिए ऐसी बढ़ जाती है कि उसके करने में उसे कुछ जोर नहीं लगाना पड़ता, मानो वह अपने आप हो जाता है। अभ्यास से उसकी कार्य-क्षमता बहुत बढ़ जाती है। वह अपने काम में विशेषज्ञ हो जाता है, अच्छी तरह मज जाता है। इससे उसकी निपुणता और कार्य-कुशलता में बहुत वृद्धि होती है।

(२) समय की घटत—जब मनुष्य को भिन्न-भिन्न काम करने पड़ते हैं, तो उसका बहुत-सा समय काम के बदल-बदल और भिन्न-भिन्न औजारों को उठाने-थरने में नष्ट हो जाता है। श्रम-विभाजन में मनुष्य को केवल एक ही क्रिया करनी पड़ती है। इसलिए जो समय भिन्न-भिन्न काम तथा औजारों के बदलने-बदलने में व्यर्थ नष्ट होता है, वह श्रम-विभाजन से बच जाता है।

(३) औजार तथा कच्चे माल में बचत—जब एक आदमी दो-तीन काम साथ करता है, तो उसे प्रत्येक काम के लिए अलग-अलग औजार रखने पड़ते हैं। परन्तु इन सबको वह एक साथ प्रयोग नहीं कर सकता। अतः जब वह एक औजार से काम लेता है, तो दूसरे सब औजार बेकार व फालतू पड़े रहते हैं। सब औजारों में खर्च भी ज्यादा होता है, साथ ही वह उतनी सावधानी से उन्हें रख भी नहीं सकता। श्रम-विभाजन में प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही क्रिया करनी होगी है, इसलिए उसे उसी काम के औजारों की आवश्यकता होगी है और उन्हें वह बराबर प्रयोग करता रहता है। इस तरह श्रम-विभाजन द्वारा औजारों में बहुत बचत होती है। औजार कम लगते हैं, उन पर खर्च कम होता है और उनका बराबर उपयोग भी होता रहता है। इसके अतिरिक्त कम औजारों से होने पर प्रत्येक श्रमिक उनकी अच्छी तरह से देख-भाल भी कर सकता है। इससे औजारों की जीवन-अवधि बढ़ जाती है, वे ज्यादा दिन तक चल सकते हैं।

श्रम-विभाजन में कच्चे माल के प्रयोग में भी काफी बचत होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने काम में निपुण होने के कारण माल का उचित ढंग में प्रयोग कर सकता है। अन्त्याम से उस कच्चे माल के प्रयोग करने का सर्वोत्तम ढंग मालूम हो जाता है। अस्तु वह कच्चे माल को उतना खराब न करेगा और जो छीज वचगी उमरवा भी उचित उपयोग सम्भव हो सकेगा।

(४) काम सीखने के समय में कमी—श्रम विभाजन में एक काम में कई उपविभाग कर दिए जाते हैं और एक व्यक्ति को केवल एक ही उपविभाग सीखा जाता है जो आसानी से और थोड़े ही समय में सीखा जा सकता है। फलतः काम सीखने में समय परिश्रम और धन कम लगता है।

(५) मशीनों के उपयोग तथा आविष्कार में उन्नति—एक कार्य को बहुत से उपविभागों में विभक्त कर देने से प्रत्येक उपविभाग में की जान वाली क्रिया बहुत सरल हो जाती है। ऐसा होने से मशीनों का उपयोग सरल हो जाता है। इससे कार्य बहुत जल्दी तथा कम श्रम से सम्पादित होता है, उत्पादन कार्य की क्षमता बढ़ जाती है और समय की भी बचत होती है।

श्रम विभाजन से आविष्कार की भी उन्नति होती है। जब मनुष्य लगातार एक ही काम में लगा रहता है तो उसे यह सोचने का पर्याय अवसर मिल जाता है कि उस काम के करने की विधि में किस प्रकार और अधिक उन्नति की जा सकती है। इस तरह उस कार्य से सम्बन्ध रखने वाला आविष्कार करना आसान हो जाता है।

(६) श्रम शक्ति का समुचित उपयोग—श्रमिकों की कार्य शक्ति निम्न भिन्न होती है। किसी में शारीरिक शक्ति अधिक होती है और किसी में मानसिक। किसी की कोई कर्मेन्द्रिय तब होती है किसी की कोई। सबकी शक्तियों को उचित ढंग से काम में लाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी शक्ति और योग्यता के अनुसार

काम दिया जाय । तभी श्रमिकों की कार्य शक्ति या कुशलता का पूरा पूरा लाभ उठाया जा सकता है । श्रम विभाजन में ऐसा ही होता है । जो जिन काम के लिए उपयुक्त होता है, उसको वही काम दिया जाता है । जहाँ पर अधिक शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है वहाँ बलवान मनुष्य रख जाते हैं और जहाँ थोड़े शक्तियों की जरूरत होती है वहाँ दूसरी शक्तियों के श्रमिक रखा जाते हैं । इस तरह श्रम विभाजन द्वारा सबकी शक्तियों को यथार्थ रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है । श्रम विभाजन के न होने पर एक ही व्यक्ति का उत्पादन बाप का आदि से अंत तक सभी काम निभाकर पड़ेगा । ऐसा होने पर बहुत से व्यक्तियों का उपयोग न हो सकना और कुशल श्रमिक को बहुत सा साधारण काम भी करना पड़ेगा । जिसमें उनकी कुशलता का पूरा लाभ न उठाया जा सकेगा । फलस्वरूप राष्ट्र की बहुत-सी शक्ति व्यर्थ जायेगी । श्रम विभाजन में यह अवस्था दूर हो जाती है । इसके द्वारा शारीरिक और मानसिक शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग सम्भव हो जाता है ।

(५) उत्पादन में वृद्धि और लागत घटने में कमी—जब मनुष्य किसी काम को करते करते उसमें निपुण हो जाता है तो उसके कार्य करने की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है । वह थोड़े ही समय में अधिक उत्पादन कर लेता है । इसमें उत्पादन का परिमाण बढ़ जाता है और लागत-खर्च कम हो जाता है । लागत घटने इस कारण कम हो जाता है कि व्यवस्था-विभाजन में समय की बचत होती है और लोगों के उपयोग तथा कल्प भाव आदि में बहुत भिन्नविधिता होती है ।

(६) उत्पादन की श्रेष्ठता—श्रम विभाजन में श्रमिक अपने काम में निपुण हो जाता है । निपुण होने के कारण जो चीज वह तैयार करता है वह अच्छी और श्रेष्ठतर होता है । उसमें सफाई और सुन्दरता होती है ।

(७) उद्योग पद्धति में वृद्धि—आविष्कार और नई नई मशीनों के उपयोग में उद्योग पद्धति में वृद्धि होती है, जिससे स्त्री वस्त्र, आभूषण,

सूले, लगाड़े घट्टे आदि सभी प्रकार के लोगों को कमा करने का मौका मिल जाता है ।

(१०) सहयोग और सपठन की उन्नति—श्रम-विभाजन के कारण बड़े-बड़े कारखाने खुल जाते हैं, जहाँ पर प्रभुत्व में श्रमिक एक साथ काम करते हैं । एक साथ काम करने और रहने से श्रमिकों में संगठन, सहयोग और एकता का भाव जागृत हो जाता है । संगठित होकर वे अपनी दशा को काफी सुधार सकते हैं ।

### श्रम-विभाजन से हानियाँ

#### (Disadvantages of Division of Labour)

श्रम-विभाजन में होने वाले लाभों पर ऊपर प्रकाश डाला गया है । किन्तु श्रम-विभाजन से केवल लाभ ही नहीं होते, इसमें कई प्रकार की हानियाँ भी होती हैं । इनमें से मुख्य ये हैं —

(१) नीरसता और मनहूसियत—श्रम-विभाजन के कारण प्रत्येक मनुष्य को सर्वत्र एक ही काम में लगा रहना पड़ता है । दिन पर दिन उसी काम को करते रहने से मनहूसियत आ जाती है । काम नीरस बन जाता है, जिसके करने में मनुष्य का मन नहीं लगता । वह उस काम में ऊब जाता है । फल यह होता है कि शीघ्र ही वह थक जाता है, उसकी बुद्धि मंद पड़ जाती है और साथ ही दृष्टि संकुचित हो जाती है । इसलिए यह कहा जाता है कि श्रम-विभाजन से सबसे बड़ी हानि यह है कि इसमें नीरसता और मनहूसियत पैदा होगी है जिससे मनुष्य के चरित्र, बुद्धि और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है ।

इस बात में थोड़ी सचाई अवश्य है कि श्रम विभाजन के कारण काम में कुछ विविधता न होने से काम नीरस बन जाता है । लेकिन साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि श्रम-विभाजन द्वारा अधिक और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन सम्भव हो जाता है जिनके उपभोग में जीवन में एक ही डब में डूबे रहना नहीं पड़ता । जीवन में नीरसता नहीं

धान पाती; जीवन सुखिमय बन जाता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि जीवन की नीरसता काम की नीरसता से अधिक भयानक है।

(२) उन्नति में रुकावट—काम के एक सूक्ष्म भाग के कारण मनुष्य की विभिन्न शक्तियों को समुचित रूप से बढ़ने व विकास के लिए पूरा-पूरा मौका नहीं मिल पाता। मनुष्य बराबर एक ही काम में लगा रहता है। इसलिए उस काम से सम्बन्धित शक्तियों का ही उपयोग हो पाता है। उन्हीं में ही वृद्धि होती है। शेष शक्तियों के विकास के लिए अवसर नहीं मिलता। वे अविकसित ही पड़ी रहती हैं। फलस्वरूप मनुष्य पूर्णरूप से उन्नति नहीं कर सकता।

लेकिन इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि धम-विभाजन द्वारा काम के समय में काफी बचत होती है। इस बचे हुए समय को ठीक ढंग से उपयोग करके मनुष्य अपनी तरह-तरह की उन्नति कर सकता है। वास्तव में धम-विभाजन से उन्नति में सुविधा मिलती है, रुकावट नहीं पड़ती।

(३) बेकारी का खतरा—धम-विभाजन के कारण प्रत्येक व्यक्ति का सम्बन्ध काम के केवल एक ही भाग से होता है। उसी को वह सीखता और जानता है और उसी में वह लगा रहता है। अन्य कार्यों की ओर कोई जानकारी नहीं होगी। यदि किसी कारण से उसके काम की माग न रहे या घट जाय तो उसे बेकारी का सामना करना पड़ेगा। अन्य कामों की जानकारी न होने के कारण उसे और वही काम न मिल सकेगा। वह बेकार हो जायेगा। इसलिए यह कहा जाता है कि अत्यधिक धम-विभाजन से बेकारी का खतरा बहुत बढ़ जाता है।

लेकिन यह आशय पूर्णतः सत्य नहीं है। धम विभाजन के कारण प्रत्येक उपविभाग का काम सरल हो जाता है। उसे आसानी से, कम समय और थोड़े खर्च में सीखा जा सकता है। अस्तु, बेकार मनुष्य अन्धी दूसरे काम को सीख कर उसमें लग सकते हैं।



(४) कुशलता और जिम्मेदारी में कमी—थम-विभाजन के कारण काम बहुत सरल हो जाता है, जिसके करने में किसी विशेष योग्यता अथवा कुशलता की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्रमिक केवल मशीन चलाने वाला रह जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि श्रम-विभाजन से कुशलता कम हो जाती है। कुशल श्रम का कार्य-क्षेत्र घट जाता है। निपुण या कुशल श्रम की कम आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यह बात बहुत हद तक ठीक नहीं है। थम-विभाजन से काम बंट जाता है, काम के कई उपविभाग कर दिये जाते हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक उप-विभाग का काम सरल हो जाता है। कुछ उपविभागों में विशेष योग्यता और निपुणता की आवश्यकता पड़ती है। उन उपविभागों का कार्य केवल वृक्ष श्रमिक ही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नित्य नये पदार्थों और मशीनों की उत्पत्ति के कारण निपुणता और कुशलता की अधिकाधिक आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में थम-विभाजन के कारण देश के हर प्रकार के लोगों को उनकी योग्यता, शिक्षा, सामर्थ्य के अनुसार काम में लगाया जा सकता है। इस कारण शक्ति का ह्रास नहीं होने पाता।

श्रम-विभाजन से एक दूसरी हानि यह बताई जाती है कि इससे जिम्मेदारी कम हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पूर्ण-रूप में बनाता हो, तो उस काम की अच्छाई-बुराई की पूरी जिम्मेदारी उसी पर होगी। किन्तु यदि उस काम की जिम्मेदारी हजारों लोगों में बंटो हुई हो, तो वास्तव में वह किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। सभी एक-दूसरे पर उस जिम्मेदारी को टालने की कोशिश करने हैं। कोई भी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता। ऐसा होने से काम कम सावधानी से किया जाता है।

(५) स्त्रियों और बच्चों का शोषण—थम-विभाजन के कारण काम बहुत सरल और परिमित हो जाता है, जिसे स्त्रियाँ और बच्चे भी कर सकते हैं। मिल-मालिक पुरुषों के स्थान पर स्त्रियों और बच्चों को रण

रहे हैं, क्योंकि उनको अपेक्षाकृत कम मजदूरी देनी पड़ती है। इसमें कुछ पुरुषों को बेकारी का सामना ही नहीं करना पड़ता बल्कि स्त्रियों और बच्चों को स्वास्थ्य, चरित्र और भावी जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। समाज के लिए यह निश्चय ही विचारणीय बात है। कमजोर स्त्रियाँ कमजोर बच्चों को जन्म देती हैं। बच्चे कमजोर होने के कारण वे आगे चलकर जीवन का भार उठाने में असमर्थ होंगे। ऐसी दशा में भविष्य में किसी प्रकार की उन्नति समझ न होगी।

लेकिन यह दोष धर्म-विभाजन पर नहीं थोपा जा सकता। धर्म-विभाजन से काम बढ़ जाता है। प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति को उसकी शिक्षा और शक्ति के अनुसार काम में लगाना सम्भव हो जाता है। इसमें सभी की शक्तियों का उचित उपयोग हो सकता है। स्त्रियों और बच्चों का शोषण पूँजीपतियों के निजी लाभ के कारण होता है, धर्म-विभाजन के कारण नहीं। सभी सम्य देशों में इस ओर सुधार हो रहा है।

(६) कारखाना-प्रणाली की बुराइयाँ—धर्म-विभाजन के कारण कारखानों की प्रथा का बहुत बोलबाला हो गया है। इसलिए कारखाना-प्रणाली की बुराइयों को धर्म-विभाजन की हानियों की सूची में शामिल किया जा सकता है। कारखाने की प्रथा से जो अनेक बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं, उनसे हम भली-भाँति परिचित हैं। कारखाने की प्रथा में धर्मिकों की स्वतन्त्रता थली गई है। उनके और मिल-मालिकों के बीच व्यक्तिगत-सम्बन्ध नहीं रहा। इसके कारण हड़ताल आदि अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। कारखानों में मकड़ों व हजारों व्यक्तियों को कई घण्टों तक अस्वाम्यकार वातावरण में काम करना पड़ता है। उन्हें अस्वास्थ्यकर बस्तियों में रहना पड़ता है। इन सबका उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और साथ ही दूषित अतृप्तिकता भी शीघ्र फैलने लगती है।

धर्म-विभाजन से इस तरह की हानियाँ होती हैं। लेकिन धर्म-विभा-

जन्तु में जो लाभ होने है, वे इन हानियों से कहीं अधिक है। श्रम-विभाजन से मनुष्य की उत्पादन-शक्ति बहुत बढ़ जाती है। गन्धे, मारी और अप्रचिकर कामों से मनुष्य को छूटकारा मिल जाता है। ये काम मशीनों से किये जाते हैं या श्रम-विभाजन की प्रमुख देन हैं। कार्य करने का समय घट जाता है जिसके उपयोग से श्रमिक अपनी आत्मोन्नति कर सकता है। श्रम-विभाजन से नये-नये आविष्कार होते हैं, ज्ञान और सम्यता की वृद्धि होती है। इससे उत्पादन अधिक से अधिक होता है और उत्पादन की लागत में भारी कमी होती है। श्रम-विभाजन में जो कुछ हानियाँ हैं, वे बहुत-कुछ दूर की जा सकती हैं। वे श्रम-विभाजन के आवश्यक अंग नहीं हैं। अधिकतर वे श्रम-विभाजन के दुस्प्रयोग के कारण उत्पन्न होती हैं। अस्तु, उनको उचित व्यवस्था के द्वारा दूर किया जा सकता है। वर्तमान समय में उनका तेजी से प्रतिकार किया जा रहा है।

### श्रम-विभाजन की सीमा

(Limits to Division of Labour)

हम ऊपर देख चुके हैं कि श्रम-विभाजन में अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। लेकिन इसका यह आशय नहीं कि श्रम-विभाजन को जब और जितना चाहे, उतना बढ़ाया जा सकता है। श्रम-विभाजन कुछ विशेष दशाओं में ही सम्भव और लाभदायक हो सकता है, और वहाँ भी एक सीमा तक ही। अनेक बातों से श्रम-विभाजन के विस्तार की सीमा निर्धारित होती है। इनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं —

(१) व्यवसाय अथवा काम की प्रकृति व स्वरूप—श्रम-विभाजन के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन-कार्य कई भागों और उपविभागों में विभक्त हो सके और उत्पादन-कार्य लगातार होना रहे। इन दोनों में से किसी एक बात के न होने पर श्रम-विभाजन सम्भव न होगा। कुछ ऐसे उत्पादन-कार्य हैं जो विभक्त नहीं हो सकते या उनको विभाजन करने पर सब भागों पर एक साथ काम नहीं चल सकता। कृषि का ही उदा-

हरण ले लो । कृषि-कार्य को कई भागों में बांटा तो अवश्य जा सकता है लेकिन सब भागों का काम एक साथ नहीं चल सकता । यह सम्भव नहीं है कि एक ही समय खेत में कोई हल चलाता रहे, कोई खाद और पानी देता रहे, तो कोई फसल काटता जाय । ऐसा सम्भव न होने पर कैसे प्रत्येक श्रमिक अपने एक खास श्रम-विभाग को कायम रख सकेगा । यही कारण है कि अन्य उद्योग-धंधों की अपेक्षा कृषि में श्रम-विभाजन की बहुत कम गुंजायश होती है । अस्तु, श्रम-विभाजन व्यवसाय अथवा काम की प्रकृति पर निर्भर है । जितने अधिक विभाग और उपविभाग किसी काम के हो सकेंगे और उत्पादन-कार्य लगातार चल सकेंगे, श्रम-विभाजन उतना ही आगे उस काम में बढ़ सकेगा ।

(२) मशीन का विस्तार—श्रम-विभाजन मशीन के विस्तार अथवा माप की मात्रा से सीमित होता है । किसी वस्तु के उत्पादन में श्रम-विभाजन भी सम्भव और लाभप्रद होगा जबकि उस वस्तु की मशीन बड़ी हो, अर्थात् उस वस्तु की बाजार में अधिक मांग हो । यदि उस वस्तु की मांग कम है, तो श्रम-विभाजन सम्भव न होगा, और यदि होगा भी तो बहुत आगे न बढ़ सकेगा । कारण यह है कि श्रम-विभाजन ने उत्पादन की मात्रा बढ़ाती है । जब किसी वस्तु के उत्पादन-कार्य को विभिन्न भागों में बांटा जायगा और भिन्न-भिन्न व्यक्ति उन भागों पर एक साथ लगातार काम करेंगे तो निश्चय ही उत्पादन बड़े पैमाने पर होगा । लेकिन यह तभी लाभप्रद होगा जबकि उस वस्तु की मशीन बड़ी हो । यदि मशीन बड़ी नहीं है तो बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से हानि होगी । और जब तक बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की आवश्यकता न होगी तब तक श्रम-विभाजन आगे न बढ़ सकेगा । उदाहरण के लिए मान लो, चाय में कोई मोची जूता बनाने का काम करता है और वहाँ पर प्रति मप्ताह केवल दो जोड़ी जूतों की मांग है । ऐसी दशा में श्रम-विभाजन से उसे लाभ न होगा । यदि वह श्रम-विभाजन करता है, अर्थात् जूते बनाने के काम को भिन्न-

भिन्न भागों में बांटकर अलग-अलग व्यक्तिों को दी जाता है, तो जो अधिक मात्रा में तैयार होंगे । लेकिन भाग कम होने के कारण वे विक्रय नहीं कर पाएंगे । फलस्वरूप उसे हानि होगी और इस कारण वह श्रम-विभाजन नहीं करेगा । मशीन बड़ी हो जाने पर उसके लिए श्रम-विभाजन का महाराज लेना सम्भव हो जायगा और जैसे-जैसे मशीन बड़ी होती जायगी, वैसे-वैसे श्रम-विभाजन बढ़ सकता है । इसलिए यह कहा जाता है कि श्रम-विभाजन मशीन के विस्तार द्वारा सीमित होता है । जितना कम या अधिक किसी वस्तु की मशीन का विस्तार होगा उतना ही कम या अधिक उस वस्तु के उत्पादन में श्रम-विभाजन सम्भव हो सकेगा ।

(३) उत्पत्ति के साधनों की मात्रा—श्रम-विभाजन उत्पत्ति के साधनों की प्राप्य मात्रा से भी सीमित होता है । श्रम-विभाजन में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है । बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अधिक श्रम और पूँजी की आवश्यकता पड़ेगी । यदि ये साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, तो श्रम-विभाजन का कार्य नहीं बढ़ सकेगा । पिछड़े हुए देशों में उत्पत्ति के साधनों की, विशेष रूप से पूँजी और प्रबन्ध की, बहुत कमी होती है । इस कारण इन देशों में श्रम-विभाजन के कार्य में बहुत उन्नति नहीं हो सकती । उन्नत और प्रगतिशील देशों में उत्पत्ति के साधन अधिक मात्रा में होते हैं । वहाँ के लोगों की आवश्यकताएँ भी बहुत बढ़ी-बढ़ी होती हैं और लोग मिल-जुल कर काम करने को तैयार भी रहते हैं । यही कारण है कि ऐसे देशों में श्रम-विभाजन की बड़ी आवश्यकता होती है और इसके लिए वहाँ पर क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है ।

### QUESTIONS

1. What is division of labour? Describe its various forms
2. What are the main advantages and disadvantages of division of labour? Explain them fully.
3. Explain the main forms of division of labour and

show how division of labour increases productive efficiency

- 4 "Division of labour is limited by the extent of market" Discuss
- 5 Explain what is meant by division of labour  
What are the main factors that limit division of labour?

## अध्याय २१

### पूँजी

#### (Capital)

उत्पत्ति के दो प्रमुख साधन, भूमि और श्रम, का पिछले अध्यायों में अध्ययन किया जा चुका है। अब हम उत्पत्ति के एक अन्य साधन, पूँजी, का विवेचन करेंगे। आधुनिक उत्पत्ति-प्रणाली में पूँजी का स्थान बहुत ऊँचा और महत्वपूर्ण है। सच तो यह है कि आज तो इसके मामले में अन्य सब साधन बहुत-कुछ पीछे पड़ गये हैं। इसके पहले कि हम इसके कार्य व महत्व पर विचार करें, यह समझ लेना जरूरी है कि अर्थशास्त्र में "पूँजी" शब्द निम्न अर्थ में प्रयोग किया जाता है।

#### पूँजी का अर्थ और विशेषता

##### (Meaning and Features of Capital)

पूँजी क्या है और इसमें कौन-कौन सी वस्तुएँ शामिल हैं, इन पर अर्थशास्त्री एकमत नहीं हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने पूँजी की भिन्न-भिन्न रूप में परिभाषा की है। कुछ के अनुसार पूँजी और सम्पत्ति दोनों एक हैं। कुछ उत्पत्ति के उन सब साधनों को पूँजी मानते हैं जो स्थायी नहीं हैं, और कुछ अर्थशास्त्री पूँजी की यह परिभाषा देते हैं कि यह उत्पत्ति का उत्पन्न किया गया साधन है। इन विभिन्न परिभाषाओं की छान-बीन करने के बजाय यह अधिक अच्छा होगा कि हम पूँजी के उस अर्थ को समझ लें जो माधारणतः अर्थशास्त्र में अधिक मान्य है और जिसमें पूँजी की मुख्य विशेषताएँ स्पष्ट हो जाती हैं।

भूमि के अतिरिक्त, उन सब प्रकार की सम्पत्तियों को पूँजी कहा जाता है जो उत्पादन में सहायक होती हैं। मोटे तौर से उत्पादन में सहायता

देने वाली वस्तुओं के दो भाग किये जा सकते हैं—भूमि और पूजी । इनमें से जो वस्तुएँ प्रकृति की मुफ्त देन हैं, वे भूमि में शामिल की जाती हैं । जेप सब वस्तुएँ, जो उत्पत्ति में सहायक होती हैं, पूजी कहलाती हैं । इस प्रकार की वस्तुओं में वे मजान व स्थान शामिल हैं जहाँ पर उत्पादन का कार्य होता है, वे मशीन और औजार जो यहाँ इस्तेमाल होते हैं, वे कच्चे माल जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बनाने में काम आते हैं और साथ ही वह सब सामान जो उत्पादन करने के दौरान में श्रमियों के भरण-पोषण के लिए आवश्यक है । अस्तु, मक्षेप में, पूजी का अन्वय, भूमि और श्रम को छोड़कर, उन सब वस्तुओं में है जो उत्पत्ति में सहायक होती हैं ।

इस परिभाषा से पूजों की मुख्य विशेषता स्पष्ट है । वह यह है कि यह एक उत्पन्न किया हुआ साधन है । भूमि और श्रम उत्पत्ति के दो मूल व मौलिक साधन हैं । इनके परस्पर सहयोग से सम्पत्ति का उत्पादन होता है । इस सम्पत्ति का एक भाग बचाकर और अधिक उत्पादन में लगाया जाता है । सम्पत्ति के इसी भाग को पूजी का नाम दिया जाता है । अस्तु, पूजी एक स्वतन्त्र साधन नहीं है । यह भूमि और मनुष्य के विगत श्रम का फल है । इस निष्पत्ति को लेकर पूजी को इस प्रकार परिभाषा की जाती है कि यह उत्पत्ति का उत्पन्न किया गया साधन (produced means of production) है ।

पूजी तथा सम्पत्ति, भूमि व मुद्रा में क्या किन्ना अन्तर है, इसको समझ लेने पर पूजी का अर्थ और स्पष्ट हो जायगा । बतएव, मक्षेप में, हम इस पर विचार करेंगे ।

पूजी और सम्पत्ति—ऊपर दी हुई परिभाषा के अनुसार उन तमाम उत्पादित वस्तुओं को पूजी कहते हैं जो उत्पादन-कार्य में इस्तेमाल होती हैं जैसे कच्चा माल, औजार, मशीन आदि । धर्मशास्त्र में इन वस्तुओं की गिनती सम्पत्ति में की जाती है । सम्पत्ति कहलाने की सब चीजें ये पूरा करती हैं । ये सुनिश्चित हैं, विनिमयसाध्य हैं और इनमें उपयोगिता भी है ।



दूसरे शब्दों में इनमें मूल्य है, और मूल्य रखने वाली वस्तुएँ सम्पत्ति कहलाती हैं। तो क्या पूँजी और सम्पत्ति दोनों एक ही हैं? नहीं, दोनों आवश्यक रूप में एक नहीं हैं। सम्पत्ति का उपयोग दो तरह से हो सकता है। एक तो वर्तमान आवश्यकताओं की तत्काल पूर्ति के लिए उसका भ्रष्टाचार प्रयोग हो सकता है और दूसर उसे और अधिक सम्पत्ति उत्पादन करने के काम में लगाया जा सकता है। जब सम्पत्ति पहले रूप में दस्तमाल होनी है, तब यह तुष्टि का एक साधन होती है और वह मुक्ति सम्पत्ति है। जब सम्पत्ति दूसरे प्रकार में प्रयोग की जाती है, तब यह उत्पादन का एक साधन बन जाती है और तब यह पूँजी कहलाती है। अस्तु, सब पूँजी धन है किन्तु सब धन पूँजी नहीं है। अमुक वस्तु पूँजी है या नहीं, यह उसके उपयोग के आधार पर तय किया जा सकता है। उपयोग के कारण वही वस्तु पूँजी भी हो सकती है और पूँजी नहीं भी हो सकती है। जैसे, जिस मकान में तुम रहते हो, यह केवल धन है। किन्तु यदि उसी मकान में कोई कारखाना खुल जाय अथवा उत्पादन-कार्य होना लगे तो वह पूँजी हो जाएगा। जो कोयला भोजन बनाने के लिए रसोईघर में जलाया जाता है वह पूँजी नहीं है, लेकिन जो कोयला कारखान की भट्टियों में और अधिक उत्पादन के लिए जलाया जाता है वह पूँजी है। इसी तरह जब गेहूँ भोजन के लिए दस्तमाल होता है तब केवल धन है, परन्तु जब बीज के काम में लिया जाता है तब वह पूँजी बन जाता है। अस्तु, उपयोग के उद्देश्य में ही यह निश्चय किया जा सकता है कि अमुक वस्तु केवल धन है या पूँजी। दोनों में कोई भौतिक अन्तर नहीं है। अन्तर केवल इतना है कि वही धन जो बागे चलकर और अधिक धनोत्पादन के काम में आता है पूँजी माना जाता है।

**पूँजी और भूमि**—बहुत पुराने समय से पूँजी और भूमि का अलग-अलग ध्येयी में रखा जाता है। भूमि को पूँजी में शामिल न करने इनके उत्पादन का एक स्वतन्त्र साधन माना जाता है। इनके कई कारण बताये जाते हैं। एक तो भूमि प्रकृति की मुफ्त देन है। दूसरे, भूमि अमर है;

यह नष्ट नहीं होती। तीसरे, भूमि की मात्रा निश्चित है, इसे घटाया-वढ़ाया नहीं जा सकता। इसके विपरीत पूजी श्रम का फल है। यह नष्ट हो जाती है और इसकी मात्रा घट-बढ़ सकती है। अतः दोनों में काफी भेद व अन्तर है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री पूजी और भूमि को अन्त-अन्त गनी रखते। वे भूमि को पूजी में शामिल कर लेते हैं। ऊपर जो भेद बतलाये गये हैं, उनको वे नहीं मानते। उनके हिसाब में ये भेद निराधार और गलत है। वे कहते हैं कि उत्पादन में जो भूमि इस्तेमाल होती है, उस पर मनुष्य का श्रम लगा होता है। वह उसी प्रकार श्रम का फल है जैसे कि मशीन, औजार आदि हैं। इस दृष्टि में दोनों में कोई भेद नहीं है। इसके अलावा वे यह भी कहते हैं कि न तो भूमि वास्तविक रूप में बमर है और न ही इसकी गन्ना बिल्कुल निश्चित है। बराबर खाद न देने रहने में अच्छी से अच्छी भूमि कुछ पदों के बाद बेकार हो सकती है। उसका उपजाऊपन सदा एक-सा नहीं बना रहता। उसमें वृद्धि और कमी हो सकती है। अतएव पूजी और भूमि में कोई स्पष्ट और निश्चित भेद नहीं है। भूमि एक प्रकार की पूजी ही है।

इन बातों में बहुत-कुछ सत्यता है। दोनों में अनेक समानताएँ हैं। फिर भी इन दोनों को अलग-अलग रखना ही अधिक उपयुक्त है। भूमि और पूजी में एक-दो महत्वपूर्ण भेद हैं। भूमि की कमी एक स्थायी बात है। कीमत में बाहे जो परिवर्तन हो, भूमि की पूर्ति में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। अर्थात् भूमि की पूर्ति लोचरहित है। लेकिन पूजी के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है। समय मिलने पर पूजी की मात्रा में कमी-बढ़ी लाई जा सकती है। इसके अलावा उन्नति के साथ-साथ दूसरी चीजें सस्ती होती जाती हैं, किन्तु भूमि का मूल्य बढ़ता जाता है।

पूजी और मुद्रा—आम तौर से पूजी और मुद्रा दोनों एक वस्तु मानी जाती है। एक व्यक्ति अपनी मुद्रा को पूजी मानता है। वह मुद्रा के रूप में पूजी जमा करता है और उसे काम में लाकर आमदनी प्राप्त करता है। लेकिन वास्तव में मुद्रा पूजी नहीं है। यह ठीक है कि वर्तमान समय में

सचय और मुहमाकन मुद्रा के रूप में होना है और मुद्रा के द्वारा विभिन्न प्रकार के पूजा-पदार्थों का खरीदा जा सकता है। फिर भी मुद्रा स्वयं पूजा नहीं है। मुद्रा का मापना बढ़ी होना से पूजा का मान-मूल्य अपन-आप अपना आवश्यक रूप में बढ़ नहीं जाता। यदि ऐसा होता तो तब भी मुद्रा का मापना बढ़कर पूजा का पूर्ति मननाया जाता। फिर तो पूजा का कभी कोई अर्थन का बात ही न होता। वास्तव में पूजा का आगम एक उत्पन्न किया गया साधना से है जो उत्पादन में सहायक होता है। मशीन में बज्ज इन साधना का मूल्य आका जाता है। जब हम यह कहते हैं कि समुद्र के किनारे के कारखाने में बगल-बगल का पूजा है तो वास्तव में हमारा मतलब यह होता है कि वहाँ पर जो विभिन्न प्रकार का सामान है उसमें कच्चा माल मगान आजार इमारत आदि बहुत कम मात्रा में पूजा के बराबर है। अब मुद्रा स्वयं पूजा नहीं है। यह पूजा के मूल्य के मापन का एक सुविधान है। पूजा के सचय और प्रयोजन में हमने बहुत सविधा मिली है। यदि हमका यह मतलब नहीं कि जाना एक ही है।

### पूजा के रूप

(Forms of Capital)

पूजा के रूप धारण कर सकता है और इसका कई दृष्टियों में विभाजन किया जा सकता है। इसके दो महत्वपूर्ण रूप हैं — (१) चल पूजा (circulating capital) और (२) अचल पूजा (fixed capital)। चल या अस्थायी पूजा जग कहते हैं जो उत्पादन कार्य में बचकर एक ही बार में उपयोग में खर्च हो जाती है और दूसरा नाम में गए जान के लिए नहीं रह जाता, जब कच्चा माल कोटिंग याज इत्यादि। जब बचत का सून बन जाता है तब यह कपान नहीं रह जाता बह काम हो जाता है। इस प्रकार कोयला भी एक बार के प्रयोग से खत्म हो जाता है। अचल अथवा स्थायी पूजा का आगम उन वस्तुओं से है जो टिकाऊ होता है और जिसका प्रयोग उत्पादन के लिए बार-बार

किया जा सकता है। कारखानों की इमारतें, मशीनें, रेल, मोटर, इत्यादि इस प्रकार की पूँजी के उदाहरण हैं। ये वस्तुएँ एक बार के ही प्रयोग में खत्म नहीं हो जाती, बल्कि बहुत समय तक इनका इस्तेमाल चलता रहता है। आधुनिक काल में अचल पूँजी का विशेष महत्व है। लेकिन दोनों में कोई निश्चित और स्पष्ट अन्तर नहीं है। स्थिति-भेद के कारण वही पूँजी एक कार्य के लिए बल पूँजी और दूसरे के लिए अचल पूँजी हो सकती है। उदाहरणार्थ किसान के लिए भवशी अचल पूँजी है लेकिन फसार्द्ध व व्यापारी के लिए वे चल पूँजी हैं।

पूँजी के कई और भेद किये जाते हैं जैसे उत्पत्ति और उपभोग-पूँजी, बेतन और सहायक-पूँजी, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय पूँजी। जिन वस्तुओं में अन्य वस्तुओं की प्रत्यक्ष रूप में उत्पत्ति होती है, उन्हें 'उत्पत्ति-पूँजी' (production-capital) कहते हैं, जैसे कच्चा माल, मशीन आदि। इसके विपरीत जो वस्तुएँ प्रत्यक्ष रूप में उत्पादक की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उत्पादन में सहायक होती हैं, उन्हें 'उपभोग-पूँजी' (consumer-capital) कहते हैं जैसे श्रमिकों का भोजन, वस्त्र आदि।

'बेतन-पूँजी' (wage-capital) का अभिप्राय व्यवसाय की उम पूँजी में है जो श्रमिकों के वेतन देने के लिए उपयोग होती है। व्यवसाय में लगी हुई अन्य पूँजी को 'सहायक-पूँजी' (auxiliary capital) कहते हैं।

जिस पूँजी पर किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति-समूह का अधिकार होता है, उसे 'व्यक्तिगत या निजी पूँजी' (individual or private capital) कहते हैं। राष्ट्र के सब व्यक्तियों की-व्यक्तिगत और मार्ग-जनिक पूँजी के जोड़ को 'राष्ट्रीय पूँजी' (national capital) कहते हैं।

## पूँजी का महत्त्व और उसके कार्य

(Importance and Functions of Capital)

पूँजी धनोत्पत्ति का एक बहुत महत्त्वपूर्ण साधन है। प्रारम्भिक काल से ही मनुष्य किसी न किसी रूप में पूँजी की सहायता लेता आया है। जैसे-जैसे आर्थिक स्थिति में विकास होता रहा, वैसे ही वैसे पूँजी का महत्त्व बढ़ता गया। आधुनिक समय में पूँजी का महत्त्व इतना बढ़ गया है कि आधुनिक काल पूँजी-युग माना जाता है। पूँजी के सम्मुख और सब साधन पीछे पड़ गये हैं।

यह तो माना जा सकता है कि पूँजी के न होने पर भी मनुष्य कुछ न कुछ कर ही लेगा। लेकिन इसकी सहायता बिना मनुष्य बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। एक उनडहारा जमल ने अपने हाथों से ही लकड़ी तोड़कर खा सकता है पर कुल्हाड़ी अपना पूँजी की सहायता से वह कहीं अधिक लकड़ी काट सकेगा। इसी प्रकार एक किसान हठ-बल के जरिये अधिक शीघ्रता और वासानी से खेत को जोत कर जल पैदा कर सकता है। कहने कााराय यह है कि पूँजी की सहायता से धनोत्पत्ति की मात्रा और धन की उत्पादन-शक्ति बहुत बढ़ जाती है।

पूँजी के अभाव में बाँझ भी काम, चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों न हो, ठीक ढंग से नहीं किया जा सकता। इसके अभाव में भूमि और श्रम बेकार पड़े रहेंगे। उत्पादन बहुत ही कम होगा और फलस्वरूप लोगों का जीवन-स्तर भी उतना ही नीचा होगा। यही कारण है कि जिन देशों में पूँजी की विशेष कमी होती है, वे आर्थिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते। वे न तो बड़े पैमाने पर उत्पत्ति कर सकते हैं और न ही दूसरों की प्रतिযোগिता में ठहर सकते हैं। यही बात व्यक्तियों के लिए भी कही जा सकती है। जिसने अधिक पूँजी जिस व्यक्ति के पास होनी, उसने ही अधिक उसकी उत्पादन-शक्ति होगी, प्रतियोगिता में ठहरने की उसने ही अधिक शक्ति उसमें होगी। पूँजी का क्या-कितना महत्त्व है, वह इस बात से स्पष्ट हो

मरना है कि उत्पादन-क्षेत्र में पूजी क्या-क्या कार्य करती है। धनोत्पत्ति में पूजी द्वारा जो काम होने हैं, उनमें में मुख्य निम्नलिखित हैं —

(१) पूजी द्वारा काम करने के लिए तरह-तरह का कच्चा माल प्राप्त होता है जिसे बिना उत्पादन-कार्य नहीं चल सकता। इसमें केवल वही वस्तुएं शामिल नहीं हैं जो मनुष्य को सीधी प्रकृति से मिलती हैं, बल्कि वे वस्तुएं भी सम्मिलित हैं जो श्रम द्वारा इस तरह बनाई हुई होती हैं कि तैयार व उनके माल के बनाने में उनका उपयोग हो सके।

(२) पूजी से धनोत्पादन के लिए स्थान, मशीन, औजार, चालक-शक्ति आदि अनेक आवश्यक चीजों की प्राप्ति होती है। इनकी सहायता के बिना उत्पादन ठीक और अच्छे ढंग का नहीं हो सकता।

(३) वर्तमान समय में उत्पादन मशीन में न्य-विक्रय के लिए किया जाता है। इसलिए तैयार माल को भिन्न-भिन्न मंडियों में ले जाना पड़ता है और उसके लेबने का प्रयत्न करना पड़ता है। यह काम पूजी को ही सहायता से होता है।

(४) उत्पादन में काफी समय लगता है। किसी वस्तु के पूरी तरह से तैयार होने में लंबा समय लग जाता है। तैयार होने के बाद उसका न्य-विक्रय होता है। तब कहीं जाकर उत्पादकों को तैयार माल की कीमत मिल पाती है। उस समय तक जीवन-निर्वाह के लिए भोजन, वस्त्र आदि पर जो खर्चा होता है, वह पूजी से गृहार्थ ही होता है। अर्थात् उत्पादन और विक्री के दौरान में पूजी के द्वारा ही उत्पादकों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति उस समय तक रोकी नहीं जा सकती। अस्तु पूजी धन और उपयोग का-मिलान कर देती है।

इससे पूजी का महत्व स्पष्ट है। उत्पादन-क्षेत्र में यदि से अन्त तक पूजी की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान समय में पूजी के बिना धनोत्पत्ति या कोई काम न तो शुरू किया जा सकता है, और न चलाया ही जा सकता है। छोटे-बड़े हर काम में पूजी की विशेष आवश्यकता पड़ती है।

इससे कुल उत्पादन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और उत्पादन का खर्च कम हो जाता है। पूँजी के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि हम उन बातों का जाल लें जिन पर पूँजी की वृद्धि निर्भर करती है।

### पूँजी की वृद्धि

(Growth of Capital)

बचत से पूँजी का संचय और निर्माण शुरू होता है। बचत द्वारा धन का पूँजी का रूप दिया जाता है। पूँजी के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि लोग अपनी आय का कुल हिस्सा खर्च न करके उसका कुछ भाग बचाएँ। जितनी ज्यादा बचत की जायगी, साधारणतः उतनी ही अधिक पूँजी का निर्माण होगा। अस्तु, यह कहा जा सकता है कि पूँजी की वृद्धि बचत की मात्रा पर निर्भर करती है।

बचत अथवा पूँजी की वृद्धि दो बातों पर निर्भर होती है — (अ) संचय-शक्ति (power to save) और (आ) संचय करने की इच्छा (will to save)।

(अ) संचय-शक्ति—संचय करने की शक्ति उपभोग की अपेक्षा उत्पादन के अधिक होने पर निर्भर है। उत्पादन के परिमाण में वृद्धि होने से संचय-शक्ति में वृद्धि होगी। यदि किसी देश में उत्पादन का परिमाण अधिक है और उपभोग कम है, तो उस देश के लोगों में बचत करने की शक्ति अधिक होगी। व्यक्तिगत दृष्टि से भी बचत तभी सम्भव है जबकि व्यय की अपेक्षा आय अधिक हो। यदि किसी की आय इतनी कम है कि जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो सकती, तो उसमें बचत करने की शक्ति विरुद्ध नहीं होगी। अस्तु, आय और व्यय के स्तर पर बचत की शक्ति निर्भर होती है।

(आ) संचय करने की इच्छा—केवल संचय करने की शक्ति में ही पूँजी का निर्माण नहीं होता। इसके लिए लोगों में संचय करने की इच्छा का होना भी आवश्यक है। संचय की इच्छा न होने पर पूँजी में वृद्धि न हो सकेगी। पूँजी की वृद्धि के लिए संचय की इच्छा उतनी ही आवश्यक

है जितनी कि संचय करने की शक्ति। संचय करने की इच्छा पर विभिन्न प्रकार की बातों का प्रभाव पड़ता है। इनको दो भागों में विभक्त किया जा सकता है (१) निजी बातें और (२) बाहरी बातें। इन बातों का पृथक्-पृथक् अध्ययन नीचे किया जाता है।

(१) निजी या व्यक्तिगत बातें—इस विभाग में उन शक्तियों, इच्छाओं और धानों को रखा जाता है जो मनुष्य को अन्दर से धन-संचय करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये मुख्यतः चार भागों में विभक्त की जा सकती हैं —

(क) दूरदर्शिता—दूरदर्शिता के कारण लोग भविष्य की अनेक आपत्तियों में बचने के लिए अपनी आय का कुछ भ्रज बचाने का दरअसर प्रयत्न करते हैं। ये आपत्तियाँ बीमारी, बेकारी, आकस्मिक दुर्घटनाओं आदि के कारण हो सकती हैं। इन बुरे दिनों के दर में मनुष्य कुछ धन बचाकर रखने की सोचता है। फिर बूढ़ हो जाने पर काम करने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। इसलिए उस समय वे अवस्था में काम में लाने के लिए लोग धन-संचय करते हैं।

(ख) पारिवारिक स्नेह—यह स्नेह धन-संचय के लिए सबसे अधिक प्रेरक शक्ति रखती है। प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि अपनी सन्तान की शिक्षा, मरण-पोषण, विवाह आदि के लिए कुछ धन इकट्ठा करे और जो लोग उस पर निर्भर हैं उनके लिए कुछ छोड़ जाये। अनेक कठिनाइयों को सहकर भी बहुत से लोग इस कारण बचत करते हैं कि उनके बाल-बच्चे सुख और सम्मान से रह सकें।

(ग) सम्मानादि की आकांक्षा—मनुष्य चाहते हैं कि उनका समाज में प्रभाव और प्रभुत्व बढ़े, उन्हें सामाजिक, राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो। वर्तमान समाज में यह सब काम धन के बिना असम्भव-से है। धन द्वारा समाज में आदर, मान-प्रतिष्ठा, प्रभाव आदि प्राप्त करना बहुत सरल हो जाता है। बहुत-से लोग इसी आकांक्षा से धन-संचय करते हैं।



(घ) आर्थिक प्रेरणाएँ—आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने व रहन-सहन का दर्जा ऊँचा करने की प्रेरणा भी धन के संचय में विशेष सहायक होती है। आजकल प्रतियोगिता का जमाना है। जिसके पास अधिक पूँजी होती है, साधारणतः उसी को व्यापार, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में सफलता मिलती है। पूँजी के सहारे मनुष्य तेजी से आर्थिक क्षेत्र में उन्नति कर सकता है और अपने जीवन-स्तर को ऊपर उठा सकता है। इस कारण भी लोग बचाने का प्रयत्न करते हैं।

(२) बाह्यी बातें—इस तरह हम बताने हैं कि सचय करने की इच्छा को प्रेरित करने वाली विभिन्न बातें हैं। पर इन प्रेरणाओं की शक्ति देश की कुछ विशेष दशाओं और परिस्थितियों पर निर्भर होती है। जब ये दशाएँ अनुकूल होती हैं, तभी लोग सचय करने को तैयार होते हैं। ये दशाएँ अथवा परिस्थितियाँ मुख्यतः निम्नलिखित हैं। —

(क) जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा—जब तक किसी देश में जीवन और धन की सुरक्षा के साधन विद्यमान न होंगे, तब तक बच्चा के लोभों में पूँजी सचय करने की इच्छा उत्पन्न न होगी। यदि लोगों को यह डर है कि उनकी पूँजी सुरक्षित न रहेगी, उसे चोर-धाकू उठा ले जायेंगे, या सरकार अनुचित टैक्स लगाकर ले लेगी, तो वे बचन करने के लिए कष्ट उठाने को तैयार न होंगे। जिस देश में शान्ति नहीं होती, जहाँ बराबर लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं, वहाँ ये लोग अपनी आय का कुछ भाग बचाने की अपेक्षा उसे वर्तमान आवश्यकताओं की ही पूर्ति में व्यय करना अच्छा समझते हैं, क्योंकि उन्हें यह आशा नहीं रहती कि जो कुछ उनके पास है, वह भविष्य में भी उनके पास रहे सकेगा। अतः धन-सचय तभी सम्भव है जबकि देश में शान्ति और मुख्यवस्था हो। पूँजी की वृद्धि के लिए माल तथा जीवन-रक्षा के साधनों का होना आवश्यक है।

(ख) मुद्रा का चलन—मुद्रा के व्यवहार अथवा चलन से धन-सचय में बहुत सुविधा होती है। मुद्रा मूल्य का भंडार है। इसमें स्थायित्व

का गुण होता है। इसकी माय बराबर बनी रहती है। यह शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है, और न इसके मूल्य में बहुत उतार-चढ़ाव ही होता है। अन्य वस्तुओं के संचय करने में अनेक असुविधाएँ होती हैं। एक तो उनके संचय करने में अधिक स्थान लगता है। दूसरे, उनको गुप्त रूप से छिपाकर रखना कठिन है। और तीसरे, यह भी डर रहता है कि कहीं बे खराब न हो जाय, या उनकी कीमत बहुत गिर न जाय। ये सब कठिनाइयाँ मुद्रा के व्यवहार से बहुत-कुछ दूर हो जाती हैं। मुद्रा से अन्य सभी वस्तुएँ प्राप्त हो सकती हैं। वस्तु, जिस स्थान में मुद्रा का अधिक चलन होता है, और ठीक ढंग से उसकी व्यवस्था की जाती है, वहाँ पर धन-संचय की अधिक सुविधा होती है।

(ग) पूँजी के उपयोग की सुविधा—संचय करने की इच्छा तभी तेज होगी, जबकि पूँजी के जमा और उपयोग करने के सुरक्षित तथा लाभदायक साधन और सुविधाएँ हों। यदि पूँजी जमा करने के सुरक्षित साधन नहीं हैं, अथवा उनके उपयोग के लिए लाभप्रद खोज नहीं हैं, तो लोग संचय करने के लिए अधिक उत्साहित न होंगे। बैंक, बीमा-कम्पनी आदि संस्थाओं से पूँजी के जमा करने में बड़ी सुविधा होती है। संचित धन को अपने पास रखने में बहुत असुविधा होती है। चिन्ता के अतिरिक्त उसकी सुरक्षा में खर्च भी होता है। बैंक के होने से यह सब दूर हो जाता है। वस्तु, बैंक आदि के द्वारा संचय की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। साथ ही, यदि उस स्थान पर पूँजी लगाने के लाभप्रद क्षण भी हैं, तो धन-संचय की प्रवृत्ति और भी अधिक बढ़ेगी। औद्योगिक उन्नति और विप्लव के साथ-साथ पूँजी के उपयोग करने का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है।

(घ) व्याज-दर का प्रभाव—व्याज-दर का भी वचत की इच्छा पर घोटा-बहुत असर पड़ता है। साधारणतः अन्य सब बातों के समान रहने पर, व्याज-दर जितनी ऊँची होगी अर्थात् वचत पर जितना अधिक लाभ होगा, धन-संचय उतना ही अधिक होगा। इसके विपरीत व्याज-दर के कम होने पर वचत की इच्छा कमजोर होगी।

## भारत में पूँजी का संचय

(Accumulation of Capital in India)

भारतवर्ष में पूँजी की बहुत कमी है। इसके संचय व निर्माण की दर अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। इसमें देश की आर्थिक उन्नति में विशेष बाधा पड़ रही है। पूँजी की इस कमी से न तो प्राकृतिक पदार्थों का और न मनुष्यकृत साधनों का ही ठीक प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। उन बातों पर अमर विचार किया जा चुका है, जिनसे पूँजी की वृद्धि में सहायता मिलती है। इसलिए इस देश में पूँजी की कमी के कारणों को समझने में कोई कठिनाई न होगी। नीचे वे मुख्य कारण दिये गये हैं जो देश में पूँजी के निर्माण व वृद्धि में बाधक हैं।

इस देश के साधारणतः सभी लोगों में वे निजी कारण मौजूद हैं जो पूँजी की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। हममें पारिवारिक स्नेह है और अपने लिए तथा अपने घनिष्ठ सम्बन्धियों के लिए कुछ न कुछ बचत करने की इच्छा भी है। किन्तु धनवानों को छोड़कर सर्वसाधारण लोगों में न तो सामाजिक सम्मान की प्राप्ति की इच्छा है और न उनमें पर्याप्त सुरक्षिता ही है। फिर उनमें हमके लिए बचत की भावना कैसे हो? इसका मुख्य कारण वह भ्राम्यवाद और अज्ञानता है जिसमें वे सदियों की निर्धनता और दमन के कारण जकड़े हुए हैं।

किन्तु मुख्य कारण जिससे लोग पूँजी-संचय नहीं कर पाते, वह है उनकी भीषण निर्धनता। अधिकांश जनता में पूँजी-संचय करने की कोई भी शक्ति नहीं है। उनकी आमदनी इतनी कम है कि जीवन की मुख्य आवश्यकताओं से भी वे बहुधा वंचित रहते हैं। ऐसे लोग क्या-कितनी बचत कर सकते हैं, यह आसानी से सोचा जा सकता है। और फिर जिन लोगों में बचत की कुछ शक्ति है भी, उनमें 'धर्मोत्तिष्ठ' पर किये हुए हैं। यह अजिज्ञा, अन्ध-विश्वास, और बुरे सामाजिक-रीति-रिवाजों का दुष्परिणाम है।

पूँजी की कमी का एक कारण यह भी है कि देश में पूँजी जमा करने

और लगाने के सुरक्षित और लाभकारी क्षेत्रों की अभी तक बहुत कमी रही है। नये व्यापारिक क्षेत्रों और उद्योग-धंधों का भव्य विकास हो रहा है, बड़ी-बड़ी व्यावसायिक कम्पनियाँ भी बढ़ रही हैं। फिर भी दूसरे अनेक देशों के मुकाबले में यह देश इस दिशा में अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। बैंकों, बीमा-कम्पनियों आदि जैसी संस्थाओं की भी देश में पर्याप्त कमी है और इनका प्रबन्ध भी ठीक प्रकार से नहीं होता। अक्सर ऐसी संस्थाएँ टूटती रहती हैं जिससे पूँजी-संचय को बहुत धक्का लगता है। इधर कुछ समय से उद्योग-धंधों के राष्ट्रीयकरण के डर से तथा मुद्रा-स्फीति और करोड़ों में वृद्धि से भी पूँजी-संचय में थोड़ी बहुत बाधा पड़ रही है।

इसके अलावा कुछ लोगों में धन साठने की भी बुरी आदत है। जो कुछ वे बचत करते हैं, उसे जोड़कर जमीन में गाड़ देते हैं। इस प्रकार से जोड़े व गड़े हुए धन से पूँजी की वृद्धि नहीं होती। काफी धन गहनो आदि में फँसा दिया जाता है। अतः बचत का कुछ भाग पूँजी के रूप में उत्पादन-कार्य के लिए नहीं मिल पाता। लोग अपनी बचत को उत्पादन-कार्य में लगाते हुए हिचकते हैं। किन्तु यदि उन्हें लाभ और सुरक्षा का विश्वास दिलाया जाय तो उनकी हिचक जाड़ी रहेगी। लाभ के अवसरों की कमी से और सुरक्षा में अनिश्वास के कारण देश की काफी बचत यों ही पड़ी रह जाती है।

## QUESTIONS

1. Define and explain capital. How does it differ from wealth and money?
2. Is land capital? Explain the grounds on which land is generally distinguished from capital?
3. What is capital? Distinguish between fixed and circulating capital.
4. Describe the importance and functions of capital in production.
5. Explain briefly the main factors on which the growth of capital depends.
6. Account for the slow growth of capital in India.

## अध्याय २२ मशीन का उपयोग

(Use of Machinery)

आजकल मशीन का उपयोग बहुत जोर-शोर से बढ़ रहा है। छोटे-बड़े सभी कार्यों में अब मशीन में काम लिया जाने लगा है। आधुनिक उत्पत्ति-व्यवस्था में मशीनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मशीनों के प्रयोग से उत्पादन-क्षेत्र में एक क्रांति मी जा गई है। उत्पादन का सारा ढांचा ही बदल गया है। इसके परिणामस्वरूप समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवस्था में भी बहुत परिवर्तन हुए हैं। धर्म की कार्य-क्षमता और उत्पत्ति की मात्रा पर मशीन का विशेष प्रभाव पड़ा है। वास्तव में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर मशीनों का कुछ न कुछ प्रभाव न पड़ा हो। अस्तु, यदि आधुनिक युग को 'मशीन या कल-युग' माना जाए तो अनुचित न होगा।

### मशीन से लाभ

(Advantages of Machinery)

मशीन से अनेक और विभिन्न प्रकार के लाभ हैं और यही कारण है कि सभी दिशाओं में मशीन का उपयोग बढ़ रहा है। संक्षेप में, मशीन से मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं —

(१) मशीन की सहायता से मनुष्य ने प्रकृति पर काफी विजय प्राप्त कर ली है। जो कार्य पहले मनुष्य की शक्ति से परे थे, वे अब सुसमता से मशीन द्वारा किये जाने लगे हैं। अनेक प्राकृतिक शक्तियों का, जिनका पहल उपयोग नहीं हो पाता था, अब आसानी से प्रयोग किया

जा रहा है, जैसे जलशक्ति, वायुशक्ति आदि। इनसे उत्पादन की मात्रा में बहुत बृद्धि हुई है।

(२) बहुत-से काम ऐसे हैं जो केवल भारी ही नहीं होते, बल्कि साथ-साथ गंदे, अशुद्ध और नीरस भी होते हैं। इन कार्यों के करने में श्रमिक की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है और उसके चरित्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उसकी आयु भी कम हो जाती है। अब भारी और नीरस काम मशीनें करने लगी हैं जिससे मनुष्य का यह कष्ट दूर हो गया है। उसकी शारीरिक शक्ति का पहले जैसा ह्रास नहीं होता। उसके जीवन की नीरसता और गन्दगी बहुत-कुछ दूर हो गई है। अस्तु, भारी, नीरस और गंदे कामों को करके मशीनें मनुष्य के शारीरिक और मानसिक कष्टों को कम करती हैं और साथ ही मूल तथा उत्पत्ति के साधनों को बढ़ाती हैं।

(३) मशीनों के चलाने के दग करीब-करीब एक-से होते हैं। इस लिए धंधों के परिवर्तन में श्रमिकों को बहुत आसानी होती है। वे अब आसानी से और कम-समय में एक उद्योग-धन्धे से उसी तरह के दूसरे उद्योग-धन्धे में आ-जा सकते हैं। मशीन-युग के पहले ऐसा सम्भव नहीं था। तब उद्योग-धन्धों में बहुत भिन्नता थी। वे एक दूसरे से बहुत पृथक्-पृथक् थे। इसलिए प्रत्येक उद्योग-धन्धे के काम को सीखने में बहुत समय लगता था। पर मशीनें के कारण अब उद्योग-धन्धों की भिन्नता बहुत-कुछ दूर हो गई है। अस्तु, मशीनें से धर्म की गतिशीलता बहुत बढ़ गई है, और फलस्वरूप कार्यक्षमता भी।

(४) मशीनें द्वारा उत्पत्ति की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और माल सस्ता और मुलभ हो जाता है। इससे उपभोगों को बहुत लाभ होता है। जो वस्तुएँ पहले धनी पुरुषों को भी ठीक तरह से नमीब नहीं थी, वे आज सर्व-साधारण के दैनिक उपभोग की वस्तुएँ हो गई हैं। आजकल घर-घर में साइकिल, पंखी आदि वस्तुएँ दिखाई पड़ती हैं जो पहले मुश्किल से

कुछ धनी लोगों ही के पास होती थी। इन वस्तुओं के उपयोग में जीवन स्तर ऊँचा हो गया है, जीवन मूलमूल धन गया है। अस्तु, मशीन से सम्पत्ति, सुख-समृद्धि में बहुत वृद्धि होती है।

(५) मशीन की सहायता से समय और दूरी की समस्याएँ बहुत-कुछ हल हो गई हैं। अब माल बहुत ही कम समय और खर्च में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। घर बैठे हम दूर-दूर के समाचार और बातें सुन सकते हैं। इससे व्यापार-क्षेत्र में बहुत सुविधा और उन्नति हुई है।

(६) मशीन के काम करने की रफ्तार बहुत तेज होती है और वह बराबर एक-ही गती रहती है। इसके अतिरिक्त मशीन बारीक-बारीक काम कर सकती है जिसे हाथों द्वारा करना असम्भव है, या बहुत कठिन।

(७) मशीन द्वारा एक ही माप, नमूने, आकार-प्रकार की वस्तुएँ लाखों की संख्या में तैयार की जा सकती हैं। साधारणतया मनुष्य एक ही बनावट और माप की वस्तु बार-बार नहीं बना सकता। उसमें कुछ न-कुछ अन्तर अवश्य आ जाता है। आवश्यक वस्तुओं के जलग-अलग नाम भी मशीन द्वारा तैयार किये जाते हैं। वे एक ही साचे के होते हैं। जब भी हम किसी वस्तु के विशेष भाग या गुणों की आवश्यकता होती है, हम ठीक वही गुर्जा आनामी से और कम दाम में खरीद सकते हैं। इससे उपभोक्ता की बहुत सुविधा मिलती है और साथ ही उत्पादन की शक्ति और भी बढ़ जाती है।

(८) मशीन से एक यह भी लाभ है कि इसके प्रयोग से अनेक प्रकार के नये-नये उपयोग-धंधे खुलते हैं जिनमें श्रमिकों को अधिकाधिक काम मिल सकता है। मशीन का माल सस्ता होता है। सस्ता होने के कारण लोग माल को अधिक मात्रा में खरीदते हैं। इससे उत्पादन, व्यापार और व्यवसाय को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इनमें उन्नति होती है और फलस्वरूप नियोजन की मात्रा में वृद्धि होती है।

(९) मशीन पर काम करने से श्रमिक अधिक विचारशील और कुशल बन जाता है । उसकी निरीक्षण तथा निर्णय-शक्ति बढ जाती है । वह एकाग्रचित्त होकर काम करता सीख लेता है । श्रम की उत्पादन-शक्ति में विशेष रूप से वृद्धि होती है । मशीन की सहायता से वह नियत काम को कम समय में ही पूरा कर लेता है जिससे उसको अपनी उन्नति के लिए पर्याप्त अवकाश मिल जाता है । उसका जीवन-स्तर ऊचा हो जाता है और साथ ही उसकी मजदूरी भी बढ जाती है ।

इस तरह हम देखते हैं कि मशीन के उपयोग से व्यवस्थापक, उप-भोक्ता और श्रमिक सभी को लाभ पहुचता है । उत्पादन की लागत घट जाने से व्यवस्थापक को अधिक लाभ मिलता है । उपभोक्ता को अनेक प्रकार की वस्तुएँ कम मूल्य में मिलने लगती है । श्रमिक की उत्पादन-शक्ति में उन्नति होती है जिससे मजदूरी बढ जाती है । मशीन की सहायता से काम करने का समय भी कम हो जाता है क्योंकि मशीन से काम जल्दी पूरा हो जाता है । अस्तु, मशीन के उपयोग में समाज के सभी व्यक्तियों को किसी न किसी रूप में थोड़ा-बहुत लाभ अवश्य होता है ।

## मशीन से हानियाँ

(Disadvantages of Machinery)

मशीन से केवल लाभ ही लाभ नहीं है, इससे कुछ हानियाँ भी होती हैं । कहा जाता है कि मशीन के कारण अनेक आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक बुराईयाँ उत्पन्न होती हैं जिनके कारण समाज में बहुत असंतोष फैलता है । कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मशीन मानव-सकटो का मूल कारण है । इसमें बेकारी फैलती है, बुद्धि-विकास में रुकावट पड़ती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है और चरित्र गिर जाता है । मशीन-युग से पहले मजदूर केवल अपना श्रम ही बेचता था, पर अब उसे अपने बीबी-बच्चे भी बेचने पड़ते हैं, अर्थात् श्रम का प्रोत्पन्न बढ गया है । संक्षेप में, हम यहाँ पर मशीन की मुख्य-मुख्य हानियों पर विचार करेंगे ।



(१) सबसे बड़ी हानि यह बताई जाती है कि मशीनों के प्रयोग से बेकारी फैलती है। पहले जिस काम के लिए दस थमिकों की आवश्यकता होती थी, उसे केवल अब एक-दो मजदूर मशीन की सहायता से पूरा कर लेते हैं। इस तरह मशीन के कारण बहुत-से लोग बेकार हो जाते हैं। और यह तो सभी मानते हैं कि बेकारी सबसे बुरा रोग है।

यह निस्संदेह सच है कि मशीन के प्रयोग का तत्कालीन परिणाम बेकारी फैलाना है। किन्तु, आगे चलकर, लोगों को काम मिलने में अशु-विधा नहीं होती। मशीन की बनी हुई चीजें सस्ती होती हैं। इस कारण उनकी माग बढ़ेगी। माग के बढ़ने पर उत्पत्ति की मात्रा बढ़ाई जायेगी। इसके लिए अधिक थमिकों की आवश्यकता होगी। इस तरह कुछ बेकार मजदूरों को काम मिल जायगा। इसके अतिरिक्त जब वस्तुएं अधिक मात्रा में तैयार की जाने लगेंगी, तो और अधिक कच्चे माल और मशीनों की आवश्यकता होगी। फलस्वरूप कुछ मजदूरों को कच्चे माल के उत्पादन तथा मशीनों के बनाने और सुधारने में काम मिल जायगा। अस्तु, मशीन के प्रयोग से केवल कुछ ही समय के लिए बेकारी फैलती है, हमेशा के लिए नहीं।

(२) कुछ लोग यह कहते हैं कि मशीनों से कला-कारीगरी को बड़ा धक्का पहुंचता है। मशीन की बनी हुई वस्तुएं हाथ की बनी हुई चीजों की अपेक्षा बहुत सस्ती होती हैं। इस कारण सर्वसाधारण मशीन की ही बनी चीजें पसंद करते हैं। इससे स्वतन्त्र तथा कुशल कारीगरों का निर्वाह नहीं हो पाता। फलस्वरूप उन्हें अपनी कारीगरी को छोड़कर मशीन की जरूरत लेनी पड़ती है। इस तरह मशीन के कारण कला-कौशल को भारी धक्का लगता है।

ऊपर के आरोप के उत्तर में कहा जा सकता है कि वास्तव में मशीन-युग में कला-कौशल की हानि नहीं होती। कुशल कारीगर मशीन के बनाने तथा चलाने के काम में लग सकते हैं। इस काम में कौशल और बुद्धि की बड़ी जरूरत पड़ती है। नई-नई डिजाइनों के सोचने और बनाने

में भी कारीगरी, कला-कौशल की मांग होगी। अस्तु, मशीन के कारण कला-कौशल का ह्रास नहीं होता।

(१) मशीन की बनी हुई चीजे केवल सस्ती और दिशाबदी होती हैं। उनमें वास्तविक सुन्दरता नहीं होती, और न वे स्थायी ही होती हैं। हाथ की बनी हुई चीजे अधिक टिकाऊ होती हैं।

यह तो ठीक है कि मशीन का बना हुआ माल बहुत सुन्दर नहीं होता। मशीन से ज्ञान की मध्यमता जैसी सुन्दर वस्तु तैयार नहीं की जा सकती। लेकिन प्रश्न यह है कि ये वस्तुएँ कितनों को सुख हो सकती हैं। साधारणतः इन वस्तुओं का बहुत मूल्य होता है। इसलिए दो-चार घनी व्यक्तियाँ ही इन्हें खरीद सकते हैं। लेकिन मशीन के कारण वस्तुएँ सस्ती और बहुत सुख हो गई हैं। इससे जन-साधारण को बहुत लाभ पहुँचा है।

(४) मशीन पर काम करने के लिए कोई विशेष शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। इस कारण कारखानों में स्त्री-बच्चे बहुत संख्या में काम पर लगा दिये जाते हैं। इससे उनके श्रम का बहुत अनुचित शोषण होता है जिससे केवल उन्हें ही नहीं बल्कि सारे समाज की भारी हानि होती है। इससे व्यक्ति और समाज दोनों की उन्नति रुक जाती है।

निम्न यह दोष मशीन का नहीं है। यह दोष तो मशीन के मालिकों और समाज पर घोषा जा सकता है, जो ऐसा करते हैं या होने देते हैं। सम्यक् समाजों में स्त्री और बच्चों के श्रम के उपयोग पर काफी रोक-टोक होती है।

(५) मशीन से मजदूरों की स्वतन्त्रता का अन्त हो जाता है। मशीनों का मूल्य अधिक होने के कारण साधारण श्रमिक उन्हें नहीं खरीद पाते। फलतः उन्हें बड़े-बड़े कारखानों में जाकर नौकरी करनी पड़ती है। काम करने के लिए अब वे पूर्ण रूप से मालिक पर ही निर्भर रहते हैं। इससे काफी अनिश्चितता पैदा होती है।

यह अवश्य मानता पड़ेगा कि मशीन से श्रमिक की स्वतन्त्रता काफी कम हो गई है। लेकिन यह दुराई भी गृह-उद्योग-धन्धों के समुचित विकास से दूर की जा सकती है। अब छोटी और सस्ती मशीनें भी बनने लगी हैं।

(६) मशीन से माल जल्दी और अधिक परिमाण में तैयार होता है। लेकिन तैयार माल की खपत उतनी जल्दी और ठीक से नहीं हो पाती। इसके कारण व्यापारिक तेजी-मन्दी की समस्या उत्पन्न होती है जिसमें फिर बेकारी आदि की कठिनाइयाँ आ सकती होती हैं। यही नहीं, तैयार माल की खपत बढ़ाने के लिए दूर-दूर की मंडियों पर कच्चा पान के लिए उत्पादनार्थ उचित-अनुचित उपायों का प्रयोग करने हैं। इसमें सत्तार में अस्थान्ति फैलती है। युद्ध की प्रवृत्ति भी इस कारण बोर पकड़ती है।

किन्तु इसका मुख्य कारण मुख्यतः का अभाव और परस्पर का वैर-विरोध है। उचित वितरण न होने से भी उपर्युक्त समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

(७) मशीन से एक दूसरी हानि यह है कि श्रमिकों के स्वास्थ्य और चरित्र पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मशीन के कारण बड़े कारखाने खोले जाते हैं जहाँ पर पुरुष, स्त्री और बच्चे हजारों की संख्या में एक साथ काम करते हैं। इससे उनके आचार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर, मशीनों के काम करने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि श्रमिकों को बराबर भय लगा रहता है। इससे उनके स्वास्थ्य को बहुत धक्का लगता है और उनकी आयु भी कम हो जाती है।

(८) इसका अलावा प्रायः कारखानों का वातावरण स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होता। धनी आबादी होने के कारण गन्दखुरों के रहने-सहने का उचित प्रबंध नहीं हो पाता। स्वच्छ जल और हवा की भी कमी रहती है। कारखानों के धोर और धुएँ में लोगों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। उनकी कार्यक्षमता गिर जाती है और अनेक प्रकार की बीमारियाँ उन्हें गकड़ सेही है।

(९) मशीनों के अधिक प्रयोग से श्रमिकों और पूँजीपतियों में संघर्ष, वैर-विरोध बढ़ जाता है। इसमें हड़ताल और ताल्लबन्दी की भीषण परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इन बातों से आर्थिक और सामाजिक जीवन को बहुत धक्का पहुँचता है, जीवन अनिश्चित हो जाता है।

फिर इन दोषों को मशीन पर नहीं धोपा जा सकता। यदि स्त्री-पुरुष के साथ-साथ काम करने से नैतिक आधार टूट जाता है, सदाचार का ह्रास होता है, तो यह बात केवल कारखानों के लिए ही, जहाँ मशीनों का प्रयोग होता है, नहीं कही जा सकती। खेतों में भी स्त्री-पुरुष साथ-साथ काम करते हैं। मन्दिर, मिनेमा आदि स्थानों में भी तो वे साथ-साथ आते-जाते हैं। फिर तो वहाँ भी सदाचार के विगड़ने का भय अवश्य होगा। और यह कहना कि मशीन यही तेज रफ्तार से चलती है, इसलिए श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसकी आयु कम हो जाती है अथवा वह समय में पहले ही मर जाता है, ठीक नहीं है। वास्तव में, इसमें मशीन का क्या दोष? दोष तो उसके मालिक का है जो श्रमिकों को इस बात के लिए भजवूर करता है कि वह मशीन को बयानक रफ्तार से चलाए। श्रम और पूँजी के संघर्ष को, कारखानों के आस-पास की गंदगी को, सहयोग और सुव्यवस्था द्वारा दूर किया जा सकता है।

अस्तु, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं मशीन के द्वारा मनुष्य की उत्पादन और उपयोग-शक्ति बहुत बढ़ गई है। ठमका जीवन-स्तर ऊँचा हो गया है। साथ ही मध्यता में वृद्धि हुई है। मशीन के कारण जो कुछ हानियाँ होती हैं, वे अधिकतर मशीन के कारण उत्पन्न नहीं होंगी, वे पूँजीपतियों के स्वार्थ और मशीन के दुरुपयोग के कारण उत्पन्न होती हैं। इन्हें सहयोग, सुव्यवस्था और सरकारों कानूनों द्वारा दूर किया जा सकता है। मशीन के उचित प्रयोग से व्यक्ति और समाज दोनों को लाभ पहुँचता है।

## QUESTIONS

- 1 Discuss the advantages and disadvantages of the use of machinery in production
- 2 Examine the effects of machinery on labour
- 3 Do you think that the progress of mechanical invention is injurious to labouring classes? Give reasons

## प्रबन्ध और साहस

(Organisation and Enterprise)

भूमि, श्रम और पूँजी की विशेषताओं तथा उनके कार्यों पर विचार किया जा चुका है। इन तीनों साधनों का अपना-अपना महत्त्व है और हर प्रकार के उत्पादन के कार्य में इनकी आवश्यकता पड़ती है। किन्तु इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जब तक इन तीनों साधनों को एक साथ जुटाया या मिलाया न जायगा, तब तक इनसे उत्पादन का कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। भूमि, श्रम या पूँजी का पृथक्-पृथक् कोई महत्त्व नहीं है। इनका महत्त्व तथा इनकी कार्यक्षमता पारस्परिक मिलाव और सहयोग पर निर्भर है। ठीक प्रकार की उत्पत्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है कि इन तीनों में उचित सहयोग हो, इनका उचित ढंग में संगठन हो।

इन सबको एक साथ जुटाकर इनका सम्मिलित, सामूहिक रूप से संचालन करना उत्पत्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस कार्य को अर्थशास्त्र में 'संगठन', 'प्रबन्ध' या 'व्यवस्था' कहते हैं। संगठन अथवा प्रबन्ध का अर्थ भूमि, श्रम और पूँजी को अच्छे ढंग में मिलाकर उन तीनों के बीच उचित व्यवस्था करना है। जब तक उत्पत्ति के इन तीनों साधनों को उचित रूप से प्रयोग में न लाया जायगा, तब तक किसी भी घन्ये अथवा व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति संगठन करने का भार अपने ऊपर लेता है, वह संगठनकर्ता, व्यवस्थापक या सूक्ष्मता कहलाता है।

उत्पादन का चाहे जो रूप या टग हो अबवा उसकी कोई भी प्रणाली हो, संगठन आवश्यक है। प्रारम्भिक अवस्था में भी कुछ हद तक संगठन और प्रबन्ध की आवश्यकता पड़ती है। एक छोटे से खेतिहर को भी अपनी मजदूर-शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। उसे यह निर्णय करना पड़ता है कि भूमि का कितना भाग जलने, कौन-सा जल बोए, उत्पत्ति के अन्य साधनों को किस अनुपात में मिलावे जिससे उत्पादन अधिक से अधिक हो। समाज की प्रगति के साथ-साथ संगठन की उपयोगिता और उसका महत्व बहुत बढ़ गया है। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में संगठन अनिवार्य बन गया है। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के स्वामी अलग-अलग होते हैं। अतएव एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो इन साधनों को उत्पादन-कार्य के लिए इकट्ठा करे। उत्पत्ति की वृद्धि के साथ मशीनों का प्रयोग, मंडियों का विकास, धर्म विभागन आदि के कारण आधुनिक व्यवस्था का प्रबन्ध बहुत ही जटिल और जटिल का बन गया है। जो छोटे प्रबन्ध-कार्य में निपुण तथा विशेषज्ञ होते हैं, वे ही इस काम को भली प्रकार कर सकते हैं। अस्तु, आजकल की उत्पत्ति में संगठनकर्ता, प्रबन्धक और माहमी-व्यवसायी का निरूपण रमान है।

### संगठनकर्ता के कार्य

(Functions of an Organizer)

आधुनिक उत्पादन में संगठनकर्ता कई प्रकार के लाभदायक और महत्वपूर्ण कार्यों की व्यवस्था करता है। व्यवस्था का सम्पूर्ण भाग्य उसी पर निर्भर होता है। उसकी रीति-नीति और उसके कार्यों का उत्पत्ति के अन्य साधनों की उत्पादन-शक्ति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। एक चतुर सेनापति की भाँति उसको आन्तरिक तथा बाह्य अनुशासन रखना आवश्यक होता है। वह उत्पत्ति-कार्य में लगे हुए सब साधनों का प्रबन्ध करता है, उन्हें संचालित करता है और निर्देश देता है। उसके कार्यों का, संक्षेप में, नीचे विचार किया जाता है।

सर्वप्रथम वह पूरे कार्य की, आदि से अन्त तक, एक मुख्यस्थिति योजना बनाता है। वह यह निर्णय करता है कि किन वस्तुओं की उत्पत्ति की जाय ? उत्पत्ति का परिमाण क्या हो ? उत्पादन के लिए कौन-कौन से शरीरों के काम में लाये जाय ? व्यवसाय का मुख्य स्थान कहा हो ? इन बातों का निर्णय करके वह उत्पत्ति के आवश्यक साधनों को खरीदता व जुटाता है और उनके बीच उचित ढंग से संगठन करता है। यह एक गहनपूर्ण और जटिल कार्य है। फिर कई भागों में वह कार्य को विभक्त करता है। संगठनकर्ता का यह काम होता है कि उत्पादन इस ढंग में करे जिसमें उत्पत्ति अधिक से अधिक हो और व्यय कम से कम। इसलिए वह सदैव उत्पादन के क्षेत्रों में उपायों की खोज करता रहता है। उसे यह देखना होता है कि प्रत्येक साधन यह कार्य कर रहा है या नहीं जो उसे करने के लिए दिया गया है, अथवा कोई शक्ति बेकार तो नहीं जा रही है। वह उत्पादन के सम्पूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है।

जब उत्पत्ति पूरी हो जाती है अर्थात् माल तैयार हो जाता है, तब उसकी बिक्री के लिए उसे प्रबन्ध करना पड़ता है। बिक्री की व्यवस्था करना संगठनकर्ता का एक दूसरा मुख्य कार्य है। उसे यह विचार करना होता है कि उसके माल की कहा-कहा खपत हो सकेगी, उस माल का किस तरह विज्ञापन किया जाय जिसमें माग में वृद्धि हो, तथा तैयार माल को किन उपायों द्वारा मण्डियों में पहुँचाया जाय। किसी भी व्यवसाय की सफलता काफी अण तक इनही बातों पर निर्भर करती है।

संगठनकर्ता को उत्पत्ति के अन्य साधनों के लिए पारिश्रमिक देने का भी प्रबन्ध करना पड़ता है जैसे श्रम के लिए मजदूरी, पूँजी के लिए व्याज व भूमि के लिए लगान। जो साधन तरह-तरह से उसके काम में सहायक होते हैं, उन सबको उनके काम के बदले में कुछ न कुछ देना होता है। व्यवसाय में चाहे हानि हो या लाभ, उन साधकों को एक पूर्व निर्धारित रकम देनी ही पड़ती है।



ऊपर के कार्यों से एक और काम निकलता है जो इन सबसे बड़कर है। वह है माहूम अथवा जॉखिम उठाने का काम। उत्पत्ति में जितना हानि-लाभ का जोखिम होता है, उसकी कुल जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। आधुनिक उत्पत्ति भावी माग के आधार पर ही की जाती है। समठन-कर्त्ता इस बात का अनुमान लगाता है कि भविष्य में उसकी वस्तु की कितनी माग होगी। उस अनुमान पर वह उत्पादन की योजना तैयार करता है। बाजार में तैयार सामान के आने के गहले काफी समय लग जाता है। सम्भव है उस कीच माग में परिवर्तन हो जाय। यदि उसका अनुमान ठीक उतरा तो उसे लाभ होगा, अन्यथा हानि। इस जोखिम का भार वह स्वयं उठाता है। जब तक कोई व्यक्ति इस काम को करने के लिए आगे न आवेगा, तब तक वर्तमान उत्पत्ति अमभव है। हर एक प्रकार की उत्पत्ति में कुछ न कुछ जोखिम का वज्र होता है। अन्य माधनों को एक निश्चित रकम देनी पड़ती है। उत्पत्ति होने के पहले ही यह तय हो जाता है कि मनोत्पादन में योग देने वाले श्रम, पूँजी, भूमि और प्रबन्ध को कितना और किस हिसाब में प्रतिफल दिया जायगा। व्यवसाय में होने वाले हानि-लाभ में उनका कुछ मतलब नहीं होता। वे तो अपना प्रतिफल सेगै ही, चाहे व्यवसाय में हानि हो या लाभ। उनका प्रतिफल पहले से ही निश्चित होता है। जॉखिम उठाने वाले को क्या मिलेगा, यह निश्चय नहीं किया जा सकता। यह तो मनोत्पादन के बाद जब तैयार माल बिक जाना है, तब कही जाकर यह मालूम पड़ता है कि उसे कितना लाभ या हानि हुई।

कभी-कभी समठनकर्त्ता और जॉखिम उठाने वाले अलग-अलग व्यक्ति होते हैं और कभी एक ही व्यक्ति दोनों काम अपने ऊपर ले लेता है। यह आवश्यक नहीं कि जो गगठन का काम करता है, वह जोखिम या हानि-लाभ का भी भार अपने ऊपर ले। आधुनिक काल में अधिकतर प्रबन्ध और साहस का कार्य अलग-अलग व्यक्ति करते हैं। इसलिए गगठन और साहस उत्पत्ति के दो अलग-अलग माधन माने जाते हैं।

-दुर्लभ उत्पत्ति की व्यवस्था करता है और इस सम्बन्ध में अनेक

निर्भर-कार्य करता है। साहसी-व्यवसायी का काम मुख्यतः जोखिम का भार अपने ऊपर लेना है।

ऊपर के वर्णन से पता चलता है कि सगठनकर्त्ता और साहसी-व्यवसायी के कार्य कितने महत्वपूर्ण हैं। आधुनिक आर्थिक संसार के ये एक प्रकार से सेनानायक हैं। उन्हीं पर उत्पत्ति का सारा दारोमदार है। अस्तु, जिस देश में जितने ही अधिक योग्य, दूरदर्शी और क्षमताशील सगठनकर्त्ता और साहसी व्यवसायी होंगे, वह देश उतनी ही अधिक और तेजी से आर्थिक उन्नति कर सकेगा।

ऊपर कहा जा चुका है कि आर्थिक क्षेत्र में सगठनकर्त्ता और साहसी अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। व्यवसाय की सफलता व उन्नति बहुत-कुछ इन्हीं की योग्यता और क्षमता पर निर्भर करती है। लेकिन इसके पहले कि वे अपने विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकें, उनमें कई गुणों का होना आवश्यक है। विस्तारण द्वारा पता चलता है कि ये गुण न तो साधारण हैं और न सब जगहों पर एक से ही गुण आवश्यक होते हैं। विभिन्न-भिन्न उद्योगों और परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न गुणों की आवश्यकता होती है। फिर भी मोटे तौर से एक सकल साहसी और सगठनकर्त्ता के लिए निम्नलिखित गुण आवश्यक हैं।

सबसे आवश्यक गुण यह है कि उनमें धनप्राप्ति और खर्चों की पूरी परख होनी चाहिए। उनमें उत्पत्ति के अच्छे और सस्ते साधनों को ढूँढकर उचित ढंग से काम में ला सकने की योग्यता होनी चाहिए। व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक है कि कम व्यय में अधिक से अधिक और अच्छा में अच्छा उत्पादन हो। यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि प्रतिस्थापन सिद्धान्त के अनुसार वे महंगे साधनों के स्थान पर सस्ते साधनों को उपयोग में ला सकें, और उनको उन्हीं कामों में लगायें जिनके लिए वे उपयुक्त हों। निश्चय ही इसने लिए यह आवश्यक है कि उनमें अपने उद्योग की पूरी जानकारी हो और अच्छे तथा सस्ते साधनों की

पूरी परख हो। उन्हें यह ज्ञान और अनुभव होना चाहिए कि क्या कहा, कैसे और कितने में साधनों को खरीद या प्राप्त कर उत्पादन किया जाय और किन स्थानों पर तथा किस तरह माल को बचने के लिए ले जाया जाय। दूसरे शब्दों में, उन्हें बाजार की स्थिति, मांग, पूर्ति, देश, काल, सामाजिक मनोविज्ञान आदि बातों का पूरा-पूरा ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। साथ ही उनमें ठीक और जल्दी से जल्दी विचार और निर्णय करने की भी शक्ति होनी चाहिए ताकि वे हर परिस्थिति में ठीक समय पर उचित निर्णय कर सकें। इन सबके अतिरिक्त उनमें दूरदर्शिता, धैर्य, बुद्धि, गम्भीरता आदि गुणों का होना बहुत आवश्यक है जिससे वे दूसरों में ठीक-ठीक काम ले सकें और यदि हानि हो तो हिम्मत न हार दें।

ये सब गुण बहुत-कुछ स्वाभाविक होते हैं। पर कुछ हद तक उपयुक्त शिक्षा के द्वारा भी इनकी प्राप्ति हो सकती है।

### QUESTIONS

- 1 What is organisation? Should enterprise be distinguished from organisation? Give reasons
- 2 State the importance and functions of organiser in production
- 3 What are the qualities of a good organiser? Why is he called 'captain of industry'?
- 4 Why is enterprise indispensable in the present system of production?

## व्यवसाय-व्यवस्था के रूप (Forms of Business Organisation)

उत्पादन-कार्य शुरु करने के पहले व्यवस्थापक को यह निश्चय करना पड़ना है कि व्यवसाय के संगठन का क्या रूप हो ? उस काम के जोखिम उठाने की व्यवस्था किस ढंग या प्रकार में की जाय ? क्या वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से उस काम के जोखिम उठाने का भार अपने ऊपर ले, या दो-चार और व्यक्तियों को मिलाकर साझेदारी की व्यवस्था करे अथवा मिश्रित पूँजी वाली कम्पनी स्थापित करके जोखिम का भार कम्पनी के विभिन्न हिस्सेदारों के बीच बाँटे ? यदि हम मही में जाकर देखें तो व्यवसाय-व्यवस्था व संगठन के इस तरह के अनेक रूप या भेद दिखाई पड़ेंगे । मुख्यतः व्यवसाय-व्यवस्था के निम्नलिखित भेद हैं —

- (१) वैयक्तिक या एकाकी साहस-प्रणाली (single proprietorship)
- (२) साझेदारी (partnership),
- (३) मिश्रित पूँजी वाली कम्पनी (joint-stock company),
- (४) सहकारी व्यवस्था (co-operative organisation) और
- (५) सरकारी उद्योग (state enterprise) । संक्षिप्त रूप में हम इनका अलग-अलग अध्ययन करेंगे ।

### वैयक्तिक साहस-प्रणाली (Single Proprietorship)

व्यवसाय-व्यवस्था के इस रूप में जोखिम और प्रबन्ध का कुल भार एक ही व्यक्ति पर होता है । वह अपने काम का स्वयं ही व्यवस्थापक

होता है। काम को मजालता, संगठन करना, जोखिम उठाना आदि सब बातों की जिम्मेदारी उसी पर होती है। आवश्यकता होने पर वह दूसरों से पूँजी उधार लेता है और बाहरी मजदूरों और प्रबन्धकों को रखता है। फिर भी वह अकेला ही व्यवसाय की सफलता व असफलता के लिए जिम्मेदार होता है।

जो कुछ उस धन में लाभ होता है, वह सब उसी का होता है और यदि उसमें नुकसान हुआ तो भी उसे स्वयं ही सहन करना पड़ता है।

वैयक्तिक साहस-श्रमाली व्यवसाय-व्यवस्था का सबसे पुराना और सरल रूप है। आज भी उत्पादन के कई क्षेत्रों में व्यवस्था का यह रूप दिखाई पड़ता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ उत्पादन छोटे परिमाण में होता है अथवा जहाँ उत्पत्तिकर्त्ता को उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से सेवाएँ करनी पड़ती हैं, जैसे डाक्टरों, बकालान आदि। लेकिन इस प्रथा का महत्व और क्षेत्र अब धीरे-धीरे कम होना जा रहा है।

वैयक्तिक साहस-श्रमाली अथवा व्यक्तिगत उद्योग-व्यवस्था के अनेक लाभ हैं। एक तो यह कि इस तरह के काम शुरू करने में व्यवस्थापक को बहुत आसानी होती है। दूसरे, व्यवस्थापक को अधिक धन कमाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि उसके परिश्रम का प्रतिफल सीधा उसी को मिलता है। दस अपनेपन के भाव के कारण वह खूब जोर लगाकर काम करता है जिससे काम ज्यादा और अधिक अच्छा होता है। ग्राहकों की आवश्यकताओं पर वह खूब ध्यान दे सकता है जिससे उसके व्यवसाय की स्थािति में वृद्धि होती है। उसे साझेदारों के द्वारा व्यवसाय के मुक्त भेदों के प्रकट होने का डर नहीं रहता। इसके अतिरिक्त यह जैसे चाहे जैसे अपने व्यवसाय का प्रबन्ध कर सकता है। उसे इन सम्बन्धों में किसी से सलाह लेनी अनिवार्य नहीं होती। फलस्वरूप मटी का रुख देखकर वह शीघ्र में शीघ्र अपने व्यवसाय में उसके अनुसार परिवर्तन ला सकता है।

किसी बात के निर्णय करने में उसे देरी नहीं लगती । व्यावसायिक उन्नति के लिए यह परमावश्यक है ।

वैयक्तिक साहस-प्रणाली में अनेक कठिनाइयाँ और दोष भी हैं । साधारणतया एक व्यक्ति के पान पूँजी की मात्रा परिमित होती है और व्यक्तिगत रूप से ऋण लेने की शक्ति भी कम होती है । ठीक यही बात उसकी व्यावसायिक योग्यता और कुशलता के सम्बन्ध में लागू है जिसके कारण किसी बड़े व्यवसाय के सब विभागों का उचित निरीक्षण तथा संचालन करना उसके लिए सम्भव नहीं होता । फलस्वरूप विविधोक्ति और बड़े परिमाण पर उत्पादन करने के जो अनेक लाभ हैं, वे उसे प्राप्त नहीं हो सकते । लेकिन सच्चे बड़ी कठिनाई यह है कि इसमें व्यवस्थापक की देनदारी अपरिमित होती है । जहरत पड़ने पर उसकी मारी निजी सम्पत्ति कानूनन ली जा सकती है । इस भय के कारण न तो वह उत्तम उत्साह और दृढ़ता से काम कर सकता है, और न नये-नये तरीकों के उपयोग करने का साहस कर सकता है । इन सब कारणों से एकलौता उत्पादन-प्रणाली का महत्व घटता जा रहा है । यह केवल उन्हीं कारोबारों के लिए उपयुक्त है, जिनमें कम पूँजी, परिमित योग्यता और साधारण कुशलता की आवश्यकता पड़ती हो जैसे सेती, फुटकर बिक्री ।

## साझेदारी

(Partnership)

जब दो या अधिक व्यक्ति व्यवसाय को अपने हाथ में लेते हैं, तो उसे साझेदारी कहते हैं । साझेदार अपने साधनों को मिलाकर व्यवसाय चलाते हैं और सारे कार-बार के लिए अलग-अलग और मात्र ही सम्मिलित रूप में भी जिम्मेदार होते हैं । साधारणतः प्रत्येक साझेदार की देनदारी अपरिमित होती है । यदि उस कार्य में दूसरों से रुपया लेकर लगाया गया है, तो ऋणदाता को कानूनी तौर पर अपनी तमाम रकम एक ही मानेदार से प्राप्त करने का अधिकार होता है, अर्थात् साझेदारी व्यवस्था में प्रत्येक

साक्षदार व्यवसाय की हर बात का व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में जिम्मेदार होता है।

वैयक्तिक माहम प्रणाली की बहुत-सा अनुविधाएँ साक्षदारी की व्यवस्था से दूर हो जाती है। भीषित व्यावसायिक योग्यता और पूँजी का अभाव के कारण प्रायः जो स्कावट उद्योग घनों की उन्नति में जाती हैं वह काफी हद तक साक्षदारी द्वारा टूट हो जाती है। प्रबन्ध मन्त्रालय काय या यथोचित विभाजन करके भिन्न भिन्न साक्षदारों के बीच उनकी विशेष योग्यतानुसार बाँटा जा सकता है। जहाँ एक व्यक्ति खरीद का काम अपने हाथ में ले सकता है और दूसरा बिक्री का। इससे कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और व्यवसाय की उन्नति में पर्याप्त सहायता मिलती है। अपरिमित दानदारी के कारण प्रत्येक साक्षदार एक दूसरे पर पूरा पूरा ध्यान रखता है जिसके फलस्वरूप कार्य ठीक ढंग से चलता रहता है। व्यक्तिगत उद्योग में साक्षदारी व्यवसाय की माँग अधिक होती है इसलिए कर्म और पूँजी के मिलन में सहजियत होती है। और फिर बूँक काम कई लोगों की सहायता में होता है इसलिए उद्यम गलती की सम्भावना कम रहता है। इनके अलावा परिस्थितियों के अनुसार साक्षदारी व्यवसाय में परिवर्तन लाना कोई कठिन काम नहीं। साक्षदारों की सहायता कम होने के कारण किसी बात के निश्चय करने में देर नहीं लगती और अपने में काम बँट होने से प्रबन्ध आदि पर कोई विशेष खर्चा भी नहीं होता।

साक्षदारी प्रणाली की जो अच्छाइयाँ ऊपर बताई गई हैं वे ठीक ठो अवश्य हैं किन्तु वे उन्नी सभ्य होती हैं जबकि सब साक्षदार मिल जुल कर अच्छी तरह से काम करते हैं। बहुधा यह देखने में आता है कि साक्षदारी में किसी न किसी बात पर मतभेद हो जान से विश्वास उठ जाता है और आपस के बीच विराध ग उनकी सारी शक्ति लुप्त जाती है और कारखाना बंद हो जाता है, इसका अतिरिक्त किसी भी साक्षदार की मृत्यु होने पर अवसाद दिवालिया हो जाना पर व्यवसाय टूट जाता है। इन सब कारणों से साक्षदारी बहुत दिन तक नहीं चल पाती। साक्षदारी की एक मुख्य

हाणि यह भी है कि इसमें प्रत्येक साझेदार का उत्तरदायित्व अपरिमित होता है। किन्ती एक साझेदार की त्रुटि में दूसरे साझेदार को अपनी कुछ जायदाद से हाथ धोना पड़ सकता है। इस भय से धनी लोग साझेदारी पसन्द नहीं करते। फलस्वरूप बहुत ओखिम वाले व्यवसाय नहीं किये जा सकते। इन सब हाणियों में छुटकारा पाने के लिए, एक नयी प्रकार की व्यवस्था का अग्र प्रादुर्भाव हुआ है जिसका नाम है 'मिश्रित पूजी वाली कम्पनी'।

### मिश्रित पूजी वाली कम्पनी

(Joint-Stock Company)

आधुनिक व्यावसायिक समार में मिश्रित पूजी वाली कम्पनियों का विशेष महत्त्व है। यद्यपि अभी सैती-बाड़ी में इसका प्रभाव कम है, फिर भी इसका चलन औद्योगिक, खानो तथा घाटायाण के क्षेत्रों में दिन प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है। मिश्रित पूजी वाली कम्पनी कतिपय व्यक्तियों का सुष है। ये लोग हिस्सेदार कहे जाते हैं। हिस्सेदार पूजी लगाते हैं और कारोबार का जोशिम अपने ऊपर लेते हैं। पूजी को भिन्न-भिन्न मून्ध के हिस्सों (shares) में बाट दिया जाता है। जो व्यक्ति उन हिस्सों को खरीदता है, वह उस कम्पनी का हिस्सेदार बन जाता है, या वो कहिए कि वह कम्पनी के अनेक मालिकों में से एक मालिक हो जाता है। हिस्से-दारों की संख्या प्रायः बहुत अधिक होती है। फलस्वरूप वे प्रत्यक्ष रूप में कम्पनी के प्रबन्ध-कार्य में हाथ नहीं घोंटते। वे वोट द्वारा अपने में से कम्पनी को चलाने तथा उसकी नीति आदि निर्धारित करने के लिए एक छोटी कार्यकारिणी समिति चुनते हैं जिसे आम तौर से 'मंचालक समिति' (Board of Directors) कहते हैं। यह समिति कम्पनी के प्रतिदिन के साधारण कार्यों से सम्बन्ध नहीं रखती। ये सब काम तो बेंतन पाने वाले मैनेजर और अन्य कर्मचारियों द्वारा किये जाते हैं। अतः इस प्रकार की व्यवस्था में स्वामित्व और प्रबन्ध एक दूसरे से वृथक् होंगे हैं।



कम्पनी के मालिक हिस्सेदार होते हैं, परन्तु वे उनके प्रबन्ध-कार्य में कोई भाग नहीं लेते ।

इसके पहिले कि कम्पनी के लाभ और हानि पर विचार किया जाय, कम्पनी की उन विनोदताओं को जान लेना आवश्यक है जिसमे इसके और साझेदारों के बीच जो अन्तर है वह मालूम हो सके । सर्वप्रथम, कम्पनी की पूँजी सम्मिलित होती है और मालिकों की मर्यादा बहुत होती है । दूसरे, कम्पनी के हिस्सों का बदल-बदल हो सकता है । अर्थात् एक हिस्सेदार जब चाहे अपने हिस्से को दूसरों के हाथ बेच सकता है । हिस्सेदारों के बदलने से कम्पनी टूटती नहीं । तीसरे, प्रत्येक हिस्सेदार की देनदारी उसके हिस्से के मूल्य तक ही सीमित होती है । अधिक से अधिक रकम जो किसी हिस्सेदार को चुकानी पड़ सकती है या हानि हो सकती है, वह केवल उसके खरीदे हुए हिस्सों की रकम तक ही सीमित है । उसकी बाकी सब सम्पत्ति सुरक्षित रहती है । उसे कोई छू नहीं सकता ।

कम्पनी-व्यवस्था के अनेक लाभ हैं । इसके द्वारा बड़े-से बड़े कारोबार के खोलने के लिए आसानी से पूँजी इकट्ठा करना सम्भव हो जाता है । पूँजी इकट्ठी करने तथा उसके उपयोग करने व लगाने में इरागें काफी प्रोत्साहन मिलता है और साथ ही यह काम बहुत सुविधाजनक और सरल हो जाता है । व्यक्तिगत तौर से बचत की छोटी-छोटी रकमों को लाभप्रद कारोबार में लगाना सम्भव नहीं होता, लेकिन यदि उनको एक में मिला लिया जाय, तो उनका उपयोग लाभप्रद ढंग से आसानी से हो सकता है । कम्पनी-व्यवस्था द्वारा बिलसी हुई छोटी रकमों को इकट्ठा किया जा सकता है और फिर उनको कारोबार में आसानी से लगाया जा सकता है । कम मूल्य वाले हिस्सों को खरीदकर साधारण व्यक्ति भी अपनी थोड़ी-सी बचत से फायदा उठा सकते हैं । परिमित देनदारी होने से उन्हें थोड़ी ही जोखिम उठानी पड़ती है । घनी लोपों को भी कम्पनी-व्यवस्था से बहुत लाभ होते हैं । इसके द्वारा वे अपनी पूँजी को भिन्न-भिन्न कारोबार

में लगा सकते हैं। पूँजी के इस प्रकार बँट जाने से जोखिम का खतरा उनके लिए कम हो जाता है। चूँकि हिस्से का क्रय-विक्रय हो सकता है, इसलिए कोई भी हिस्सेदार अर्थात् पूँजीदाता दिना कारोबार को छोड़ ही अपनी पूँजी निकाल सकता है। समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों के व्यक्ति कम्पनी के हिस्सेदार होते हैं। इस कारण जोखिम बहुमन्यक हिस्सेदारों में बँट जाती है। फलस्वरूप जोखिम का भार एक या दो व्यक्तियों पर ही नहीं पड़ता।

कम्पनी द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन सम्भव तथा मुगम हो जाता है जिसके साथी से हम भली-भाँति परिचित हैं। उत्पादन के अनेक कार्य ऐसे हैं जिनको छोटे पैमाने पर चलाने में लाभ नहीं हो सकता, जैसे रेल, जहाज आदि। कम्पनियों के पास पर्याप्त साधन होने हैं, इसलिए कुछ ल तथा योग्य धर्मिकों और अनुभवी व्यवसायियों को मेवाएँ प्राप्त हो सकती हैं। फलस्वरूप उच्च कौशल का यम निमाजन सम्भव हो जाता है। इसमें किसी की पूँजी और किसी की योग्यता की जुटाकर काम लेना सम्भव हो जाता है जिससे केवल व्यक्ति विशेष को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को लाभ होता है। हममें से कुछ के पास पूँजी होती है लेकिन योग्यता नहीं होती, और यदि योग्यता होती है तो प्रायः पास में पूँजी नहीं होती। यदि इन दोनों को एक साथ मिलाया न जाय, तो यह एक बहुत बड़ी सामाजिक हानि होगी। मिथित पूँजी वाली कम्पनी स्थापित और प्रवृत्त को अलग करके यह कमी या कठिनाई आसानी से दूर कर देती है।

व्यवस्था के इस रूप में एक और लाभ है। वह यह कि कम्पनियाँ अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती हैं। वे बहुत दिन तक चल सकती हैं। किसी एक हिस्सेदार के मर जाने या बदल जाने से कम्पनी की व्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कारण ऐसी कम्पनियाँ दीर्घकालीन तथा विस्तृत दृष्टिकोण वाली नीति आसानी से अपना सकती हैं। कम्पनी-व्यवस्था उन उद्योग-वृत्तों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जिनमें बहुत पूँजी की आवश्यकता होती है और साथ ही जिनमें जोखिम का अंश बहुत

होता है। कोई व्यक्ति न तो इतनी पूँजी जमा कर सकता है और न इतना जोनिम ही उठा सकता है। रेल, जहाज आदि ऐसे व्यवसाय कम्पनी द्वारा ही ठीक तरह से चलाये जा सकते हैं।

संक्षेप में, कम्पनी-व्यवस्था में उन सभी लाभों की प्राप्ति हो सकती है जो श्रम-विभाजन, मशीन के प्रयोग तथा बड़े पैमाने की उत्पत्ति से होने हैं।

कम्पनी-व्यवस्था के अनेक दाप भी हैं। एक मुख्य दाप यह है कि हिस्से के आसानी से खरीदे-बेचे जा सकने के कारण व्यवसाय वा प्रबन्ध और स्वाभिमित्व अयोग्य और बेईमान लोगों के हाथों में चले जाने का डर रहता है। प्रायः सीधे-सादे हिस्सेदारों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। कभी-कभी तो केवल उनके धन के लिए झूठ-मूठ कही कम्पनियाँ खड़ी कर दी जाती हैं। संचालक, प्रबन्धकर्ता तथा अन्य महत्वपूर्ण कर्मचारी हिस्सेदारों की खरीद-बेचकर उनके दाम ऊँचे-नीचे गिरकर ग्राह्यजन फायदा उठाने का प्रयत्न करते हैं। कारोबार बिगड़ने पर अन्य हिस्सेदारों को बिना वसूलाए, वे अपने-अपने हिस्से बेचकर अलग हो जाते हैं जिसमें व्यवसाय का सारा नुकसान सीधे-सादे हिस्सेदारों को ही सहना पड़ता है। अथवा जब वे यह देखते हैं कि कम्पनी के हिस्सों पर अधिक लाभ मिलने लगा है तो एक क्षण वे बहुत से हिस्से खरीद लेंगे और बाद में उन्हें ऊँचे दामों में बेच देते हैं। इस प्रकार अनेक चालों से बंधन पैदा करने का प्रयत्न करते हैं और सीधे-सादे हिस्सेदारों को ठगने और हानि पहुँचाते हैं।

दूसरे, हिस्सेदारों में आपस की भलाई के लिए सहयोग अथवा एकता की भावना बहुत कम रह जाती है। इसका एक कारण तो यह है कि हिस्सेदार जितने अधिक होते हैं कि एक-दूसरे को अच्छी तरह जानना-पहचानना असम्भव-ना हो जाता है। दूसरे, हिस्सों के हस्तान्तरकरण में हिस्सेदार जल्दी-जल्दी बदलते रहते हैं। इसलिए उनमें पारस्परिक सम्बन्ध नहीं रह पाता। साक्षंकारी में जो आपस में

भाईचारा होता है, वह कम्पनी के हिस्सेदारों के बीच नहीं पाया जाता। वे तो केवल अपने-अपने निजी लाभ की चिन्ता करते हैं। अस्तु, त्रिम प्रारम्भिक उद्देश्य तो कम्पनी की स्थापना होनी है कि हानि और लाभ सब मिलकर बांटेंगे उसे लोग भूल जाते हैं। वास्तव में यदि देखा जाय तो साधारण हिस्सेदारों वा, जो कम्पनी के मालिक होते हैं, कम्पनी की पूँजी के उपयोग पर कोई प्रत्यक्ष रूप में नियन्त्रण नहीं रहता। इससे बेखबर पूँजीवाद का जन्म होता है जिसके कारण विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं।

एक अन्य दोष यह है कि व्यवस्था के इस रूप में प्रयत्न और प्रतिफल के बीच सीधा सम्बन्ध नहीं रह जाता। हिस्सेदार कम्पनी के मालिक होते हैं किन्तु कम्पनी के प्रबन्ध आदि में उनका हाथ नहीं होता। प्रबन्ध का कार्य तो मैनेजर और सचालकों के द्वारा होता है जिनका प्रत्यक्ष रूप में कम्पनी की सफलता में कोई विशेष उगाव नहीं होता। उनको तो अपने प्रबन्ध के कार्य के बदले में एक निश्चित वेतन मिलना है। अधिक परिश्रम करने के लिए उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। इन कारण काम-काज में ढिलाई आ जाती है। साथ ही काम हिस्सेदारों, सचालकों और वेतन-भोगी मैनेजर्स अथवा प्रबन्धकों के बीच बँटा होने के कारण जिम्मेदारी में कमी आ जाती है। कोई भी अपने उत्तरदायित्व का ठीक से विचार नहीं करता। एक तरफ तो वेतन-भोगी प्रबन्धक सचालकों की नीति को दोषपूर्ण बताकर अपने सिर में खराब काम की जिम्मेदारी टाल देते हैं, और दूसरी तरफ सचालकगण प्रबन्धकों और हिस्सेदारों को दोषी ठहराने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह कोई भी जिम्मेदारी महसूस नहीं करता। वास्तव में जब जिम्मेदारी बँट जाती है तो वह किसी को भी नहीं होती। इससे कारोबार को बड़ा धक्का लगता है। कार्य-क्षमता गिर जाती है और फिजूलखर्ची में वृद्धि होती है।

इसके अतिरिक्त कम्पनी-व्यवस्था में बदलती हुई परिस्थितियों के

अनुमात्र परिवर्तन लाने में बहुत देर लगती है क्योंकि विभिन्न विभागों और पक्षों में सलाह-मन्त्राविरा लेना अनिवार्य होता है। इस दृष्टि से मिथित पूँजी वाली कम्पनी एक भीमी चालने वाली मशीन के समान है।

साथ ही व्यवसाय-व्यवस्था के इस रूप में श्रम और पूँजी का मजपै बढ़ता है। कम्पनी के हिस्सेदारों (मालिकों) और मजदूरों में कोई निजी सम्पर्क नहीं होता। हिस्सेदारों को अपने लाभ से मतलब होता है। मजदूरों की शिकायतों और आराम-नकलोफ का उन्हें कोई ख्याल नहीं होता। फलस्वरूप श्रम और पूँजी का विरोध बढ़ जाता है।

एक अन्य दोष यह है कि अपनी बड़ी पूँजी के बल पर मिथित पूँजी वाली कम्पनी अपने प्रतियोगियों को मही में उचित-अनुचित उपायों द्वारा हटाकर एकाधिकार प्राप्त कर लेती है। इससे एकाधिकार की अनेक बुराईयाँ पैदा होती हैं जिनके कारण उपभोक्ता, मजदूर और सम्प्रदाय की बहुत भारी क्षति पहुँचती है। यही नहीं, बहुधा बड़ी कम्पनियाँ सरकारी अफसरों को मिलाकर अपने निजी लाभ के लिए अनेक अनुचित पास और कानून पास करा लेती हैं। इससे जनहित को बहुत पक्का लगता है, नैतिक आधार टूट जाता है तथा राजनीतिक क्षेत्र में तरह-तरह की जटिल समस्याएँ बाँझ लड़ी होती हैं।

किन्तु सब बातों को ध्यान में रखने हुए यह कहा जा सकता है कि इस प्रथा में लोगों की अपेक्षा लाभ बड़ी अधिक है। इस व्यवस्था में इतने लाभ हैं कि ऊपर की हानियों को होने हुए भी आधुनिक आर्थिक अर्थ इसमें छोड़ नहीं सकता। इसका बिना बड़े पैमाने पर उत्पादन सम्भव नहीं हो सकता। इस पद्धति की श्रेष्ठता इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि आधुनिक उत्पादन के सब क्षेत्रों में अन्य प्रथाओं की अपेक्षा व्यवसाय-संगठन का यह तरीका अधिक प्रचलित हो रहा है। अस्तु, सरकारी कानून और सामाजिक नियन्त्रण द्वारा इस प्रथा की त्रुटियों को दूर करने का भरपूर प्रयत्न करना चाहिए जिससे व्यक्ति और समाज के हितों की रक्षा हो सके और उसमें वृद्धि हो।

## सहकारी उद्योग

(Co-operative Enterprise)

सहकारिता व्यवसाय-व्यवस्था का एक विशेष रूप है जिसका महत्त्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका उद्देश्य पूँजीवादजनित दोषों को निर्मूल्य करना है। व्यवसाय की पूँजीवादी व्यवस्था के द्वारा गमिकों, छोटे उत्पादकों और दलबोक्ताओं पर अनेक प्रकार से अन्याय किया जाता है। उनके हितों को बुरी तरह कुचला जाता है। इन गरीब और पीड़ित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए सहकारिता का प्रादुर्भाव हुआ है। सहकारिता व्यवसाय-व्यवस्था का वह रूप है जिसमें सामान्यता के आधार पर लोग स्वैच्छा से अपनी आर्थिक तथा सामाजिक हितों की वृद्धि के लिए सह-स्थापित करते हैं। सहकारिता के दो मुख्य आधार हैं स्वच्छा और जनतन्त्रवाद। जो लोग सहकारी मध्य या समिति के सदस्य बनते हैं, उन पर कोई बाध्य-बन्धन या दबाव नहीं होता। वे अपनी स्वच्छा से सदस्य बनते हैं। साथ ही सहकारी समिति का सब काम जनतन्त्रवाद के आधार पर होता है। समिति के सब सदस्य बराबर होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता। सबको एक से अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रत्येक सदस्य का केवल एक ही वोट होता है। इसमें जनतन्त्रवाद की छाप साफ-साफ प्रकट हो जाती है।

इन सब बातों से कम्पनी-व्यवस्था और सहकारिता का भेद स्पष्ट है। कम्पनी-व्यवस्था पूँजी के आधार पर बनती है। कम्पनी के हिस्सेदार एक बराबर नहीं होते। जिसके पास कम्पनी के जितने हिस्से होते हैं, उतने ही वोट उसे मिलते हैं। अतः, हिस्सेदारों में समानता नहीं होती। निर्णय के आधार पर उनकी क्षमता, उनके अधिकार निर्भर होते हैं। यही नहीं, हिस्सेदारों को केवल अपने लाभ से सरोकार होता है, और किसी बात से नहीं। वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी नहीं। इसके विपरीत सहकारिता सम का संगठन है। यह मनुष्यत्व की संस्था है, पूँजीपतियों और मुनाफाखोरों का अभाव नहीं। इनके सदस्य एकता के

धन में बंधकरी समझि होकर काम करते हैं। प्रारम्भिक मध्याय के द्वारा सहकारी व्यवस्था सामूहिक लाभ मुक्त समझि को प्राप्त करना चाहती है। इसका संदेशों के साथ कोई अंतर नहीं होता। वे समानता के आधार पर अपने ही नहीं बल्कि सबके लाभ के लिए काम करते हैं।

सहकारी व्यवस्था में जनक लाभ होता है। इसमें श्रम और पूँजी का विरासत व अधिकार दूर हो जाता है। इसका द्वारा धन के रूप में मुनाफा लोगों का भी अंत हो जाता है जो दूसरों के योगदान पर धनवान बनते हैं। सहकारी व्यवस्था के आधार पर ही कमजोर और गरीब लोग अपनी विभिन्न क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करके अपना उत्थिति कर सकते हैं। इसमें अच्छा उत्थिति के लिए और कोई रास्ता नहीं। सहकारिता लोगों में प्रारम्भिक सहयोग संगठन प्रकृति और सामाजिक ज्ञान करता है जो हर प्रकार की उत्थिति के लिए पर्याप्त है। इस प्रथा में अपनाते से समाज को भी जनक प्रकृति और समस्याओं के हलकारा मिल जाता है। यहाँ कारण है कि आज समाज के सभी सम्य केगा। यह सहकारिता के सिद्धांतों और उत्थिति होने वाले लोगों का अधिकाधिक प्रचार हो रहा है।

यस तो सहकारिता के सिद्धांतों को जनक कार्यों में उपयोग में लाया गया है पर मुख्यतः सहकारी व्यवस्था के दो भेद हैं एक तो सहकारी उत्पादन और दूसरा सहकारी वितरण। जब कुछ धर्मिक मिशनर उत्पादन का कार्य करते हैं और लाभ को आपस में बाँटते हैं तो उन्हें सहकारी उत्पादन कहते हैं। इसमें धर्मिक ही संगठन और व्यवस्था का कार्य करते हैं और जो लोग उठाते हैं वे स्वयं प्रकृति करते हैं व्यवस्था का प्रबंध करते हैं और उत्थिति जो हानि लाभ होता है उस आपस में बाँटते हैं। इस प्रकार वे स्वयं मालिक और नौकर दोनों ही होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे खुद पर दूसरों से पूँजी लेते हैं और प्रबंधक भी नियुक्त करते हैं। लेकिन हर हाल में वे स्वयं ही व्यवस्था का रीति-नीति निर्धारित करते हैं और हानि लाभ की जाँच करते हैं।

सहकारी उत्पादन प्रकृति के जनक लाभ हैं। स्वयं मालिक होने से

धार्मिक वही सावधानी और कड़ी मेहनत से काम करते हैं। वे सदा इस बात का ध्यान रखते हैं कि सभी काम ईमानदारी और ठीक ढंग से हो। इसने निरीक्षण कम करना पड़ता है और कार्यक्षमता की वृद्धि होती है। वे मन्दीनो, ओजारी आदि को सभाल कर रखते और काम में रखते हैं। कच्चे माल के उपयोग में वे हर तरह से बचत करने का प्रयत्न करते हैं जिससे कोई भाग व्यर्थ न हो। इन सब बातों ने उत्पादन अधिक, सस्ता और ठीक होता है। बर्ग-मार्घ्य दूर हो जाने के कारण हड़ताल आदि की शोषण नहीं आती और इस कारण उत्पादन में कोई रुकावट नहीं पड़ती। इसके अलावा सहकारी उत्पादन में लाभ किसी एक व्यक्ति या समूह के पास नहीं जाता बल्कि श्रमिकों के बीच बंट जाता है। इससे समाज में पन-पितरण में उचित समानता आ जाती है।

कई क्षेत्रों में सहकारी उत्पादन-पद्धति को अपनाया गया है। कृषि और छोटे उद्योगों में इस प्रथा से काफी सफलता मिली है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में बहुत कम सफलता मिल सकी है। इसका एक कारण तो यह है कि इसमें माहुरी-उद्योगपति के लिए कोई स्थान नहीं होता और सहकारी प्रबन्धक साधारण योग्यता के व्यक्ति होते हैं। श्रमिक-मालिक प्रबन्धक की कार्यक्षमता के महत्त्व को पूर्ण रूप से नहीं समझते। वे उन्हें उचित वेतन देने के लिए तैयार नहीं रहते। इसलिए उन्हें अच्छे प्रबन्धक कम मिलते हैं। यहाँ नहीं, धुँक श्रमिक उद्योग के स्वयं ही स्वामी होते हैं, इसलिए वे प्रबन्धकर्ता की धाजा और नियमों का समुचित आदर नहीं करते। उनके नियमनों को वे भंग करते रहते हैं। इसमें कार्य-क्षमता गिर जाती है और फिर उन्हें उपयुक्त माना में पूँजी और बिजली के लिए मही प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है।

महकारी-वितरण उपभोक्ताओं का समूह होता है। यह समूह बस्तुओं की पोक और फुटकर बिजली के लिए बनाया जाता है। किसी मुहूर्त के लोग मिलकर एक दुकान या स्टोर खोल लेते हैं। इसका उद्देश्य सदस्यों



को आवश्यक वस्तुएं देना होता है। स्टोर वस्तुओं को थोक भाव पर खरीदता है और फुटकर भाव से मरस्यों को बेचता है। जो लाभ होना है वह सदस्यों के बीच, उनकी खरीद के अनुसार, बांट दिया जाता है।

सहकारी उत्पादन की अपेक्षा सहकारी वितरण को बहुत सफलता मिली है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसके ग्राहक बंधे रहते हैं। ग्राहकों की चिन्ता इसमें नहीं होती। इसलिए विज्ञापन आदि पर खर्च नहीं करना पड़ता और न ही ग्राहकों को खोजने के लिए विभिन्न प्रकार की मुविद्याएं प्रदान करने की व्यवस्था की आवश्यकता रहती है। इन सब बातों से बहुत बचत होती है। स्टोर का काम इस कारण बड़ा जाता है। साथ ही जो लाभ आमतौर पर दुकानों को जाता, वह भी स्टोर के पास रह जाता है। अस्तु, भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं से सहकारी वितरण को बहुत सफलता मिलनी है। यही कारण है कि हर देश में यह प्रथा जोर पकड़ रही है।

### सरकारी उद्योग

(State Enterprise)

कुछ व्यवसायों का स्वामित्व और प्रबन्धन सरकार अथवा स्थानीय अधिकारियों के हाथ में होता है। उन्हें सरकारी उद्योग कहते हैं। भारत में रेल, तार, टांक, टेलीफोन गैरकारी उद्योग हैं। पश्चिमी देशों में बहुत-सी म्यूनिसिपल कमेटियां शहर में स्वयं पानी, बिजली आदि को वास्तव में पकाती हैं।

सरकारी उद्योग के कुछ विशेष लाभ हैं जो अन्य प्रकार के व्यवसाय-व्यवस्थाओं को नहीं मिल पाते। उदाहरणार्थ, एक निश्ची व्यक्ति-हकूमती की तुलना में सरकार में साक्ष्य व उधार लेने की शक्ति बड़ी अधिक होती है। इस कारण सरकार को औरों की अपेक्षा कम मूल्य पर और आसानी से कर्ज मिल सकता है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में एक विशेष आवर्पण-शक्ति होती है जिसके कारण सरकार को अपने उद्योगों के चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के योग्य से योग्य और अनुभवी कर्मचारी

मिल सकते हैं। इसके अलावा साधारणतः सरकारी उद्योग एकाधिकार की स्थिति में होते हैं। इस कारण उन्हें एकाधिकार के सब लाभ उपलब्ध होते हैं।

किन्तु सरकारी उद्योग में कुछ कमजोरियाँ भी हैं। इसमें अणुनापन नहीं होता। लोग सरकारी उद्योग में न तो उतने उत्साह और कड़ी मेहनत से काम करते हैं, और न ही उत्पादन की रीतियों में उन्नति लाने और लागत-सर्च कम करने में प्रयत्नशील रहते हैं। सरकारी पिस-विसु से किसी बात के निर्णय करने में बहुत देरी लगती है, और समय व्यर्थ नष्ट होता है। जिम्मेदारी में भी काफी कमी आ जाती है। राजनीतिक दबाव, पक्षपात और घुमसुमारी भी बढ़ जाती है।

इन कमजोरियों और दोषों के बावजूद भी कुछ क्षेत्रों में सरकारी उद्योग लाभप्रद ही नहीं बल्कि आवश्यक है। वास्तव में सरकारी उद्योग के दोषों को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर रखा जाता है। इनमें से कुछ दोष तो वास्तविक नहीं हैं और कुछ उपाय द्वारा दूर किये जा सकते हैं। धीरे-धीरे यह अनुभव हो रहा है कि सार्वजनिक कल्याण और हितों की सुरक्षा तथा वृद्धि के लिए सरकारी उद्योग का क्षेत्र समय के साथ-साथ और आगे बढ़ेगा।

## QUESTIONS

1. Describe briefly the main forms of business organisation
2. What are the advantages and disadvantages of single proprietorship ?
3. Discuss briefly the merits and demerits of partnership
4. What is Joint-Stock Company ? How does it differ from partnership ?
5. Discuss clearly the main advantages and disadvantages of joint-stock company

- 6 What is a co operative enterprise ? In what respects does it differ from joint stock company ?
- 7 What are the advantages of co-operative enterprise ? Show why distributive co-operation has achieved greater success than producers' co-operative ?
- 8 Write a brief note on state enterprise

## उद्योग-धन्वों का स्थानीयकरण

(Localisation of Industries)

जैसा कि पहले कहा जा चुका है उद्योग-धन्वों का स्थानीयकरण ध्रुम-विभाजन का एक विशेष स्थ है। इसको प्रादेशिक अथवा भौगोलिक ध्रुम विभाजन भी कहते हैं। बहुधा यह देखने में आता है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर कुछ खास-खास उद्योग-धन्वें जम जाते हैं। वे स्थान अलग-अलग उद्योग-धन्वों के केन्द्र बन जाते हैं। एक खास स्थान पर एक विशेष प्रकार के उद्योग के केन्द्रित होने को, जमकर चलने को अर्थशास्त्र में उद्योग-धन्वों का स्थानीयकरण (localisation of industries) कहते हैं। उदाहरणस्वरूप भारतवर्ष में लोहे के कारखाने अधिकतर बिहार प्रान्त के जमशेदनगर में केन्द्रित हैं। सूती कपड़े का उद्योग बहुत-कुछ बम्बई और अहमदाबाद में केन्द्रित है और पटसन के कारखाने कलकत्ता के आम-पाम के स्थानों में पाये जाते हैं। इसी प्रकार इगलेश्वर में लकानायर और मैनचेस्टर वपडा उद्योग के प्रसिद्ध केन्द्र हैं।

अपने व्यवसाय के लिए स्थान चुनते समय व्यवस्थापक को अनेक बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। उसे यह देखना पड़ता है कि उस स्थान पर उत्पत्ति के आवश्यक माधन द्रव्येष्ट मात्रा में मिल सकने है या नहीं, वहाँ की जलवायु और स्थिति कैसी है, भूमी का क्षेत्र कितना बड़ा है, यातायात के साधन किस ढंग के हैं, आदि। वह उन बातों पर विशेष ध्यान देगा जिनसे उत्पादन-व्यय कम से कम हो और माल की खपत में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके। जिस स्थान पर यह उपर्युक्त बातों को

अपने अनुकूल पायेगा, वही अपना कारखाना स्थापित करेगा। उस व्यवसाय के अन्य व्यवस्थापक भी इसी बातों को ध्यान में रखते हुए उसी स्थान को चुनेंगे। फलस्वरूप वह स्थान धीरे-धीरे उस व्यवसाय के लिए केंद्र बन जायेगा।

### स्थानीयकरण के कारण

(Causes of Localisation)

देश के विभिन्न भागों में विभिन्न उद्योगों के स्थानीयकरण के अनेक कारण होते हैं। इन कारणों को हम प्राकृतिक, जादिक और राजनीतिक विभागों में बांट सकते हैं।

(१) प्राकृतिक कारण—प्राकृतिक या भौतिक बानों का स्थानीयकरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इनमें जलवायु, भौगोलिक परिस्थिति, उस स्थान की खास बनस्पति, खनिज पदार्थ, संचालक-शक्ति आदि शामिल हैं। कुछ उद्योग-धंधों के लिए एक विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता पड़ती है जो हर स्थान पर नहीं मिल सकती। इसलिए वे उस स्थान पर स्थापित होंगे जहाँ उस तरह की जलवायु होगी। बम्बई और लकाशावर की जलवायु कपड़े के व्यवसाय के लिए विशेष रूप से अच्छी है क्योंकि इन स्थानों में वायुमण्डल में नमी होने के कारण धागा मजबूत और मुलायम रहता है जिसमें वह जल्दी नहीं टूटता। इस कारण कपड़े के अनेक कारखाने इन स्थानों पर केंद्रित हैं।

कच्चा माल पाने की सुविधा के कारण भी भिन्न-भिन्न उद्योग भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थापित हो जाते हैं। यदि कच्चा माल बहुत बजती है और उपयोग करने में उसका वजन कम हो जाता है तो निश्चय ही व्यवसाय को उस स्थान के निकट स्थापित करने में सुविधा होगी जहाँ वह कच्चा माल पैदा होता हो। ऐसा करने में माल की हानि में अपेक्षाकृत कम खर्च होगा जिससे कुल लगत-जर्न घट जायेगा। बिहार और बंगाल में लोहे और कोयले की खानें पाम-पास हैं। इसलिए वहाँ लोहे के कई

कारखाने स्थापित हो सके हैं। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भीनी के अनेक कारखाने हैं क्योंकि वहाँ बहुत सस्ती पैदा होता है।

यदि पास में उत्पादन के लिए चालक-शक्ति प्राप्त हो तो वह भी स्थानीयकरण का एक कारण हो जाती है। कभी-कभी कारखाने चालक-शक्ति के स्थानों के पास स्थापित किये जाते हैं ताकि चालक-शक्ति वास्तविकी से और कम दाय में प्राप्त हो सकें। पहले जमाने में तेज बहने वाली नदियों के किनारे कारखाने खोले जाते थे। आजकल चालक-शक्ति अधिकतर कोयला या जल-प्रपात द्वारा पैदा की जाती है। इसलिए आजकल कारखाने उन स्थानों पर केन्द्रित होते हैं जहाँ जल, विद्युत-शक्ति या कोयले की खदानें हों।

(२) आर्थिक कारण—आर्थिक कारण भी किसी एक स्थान को किसी विशेष उद्योग-धन्यो के लिए अधिक सुविधाजनक बना देते हैं। आर्थिक कारणों में मजदूरी का निरुद्ध होना सबसे महत्वपूर्ण है। किसी उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करने में सुविधा होगी जहाँ उस उद्योग के लिए मजदूरी हो, जहाँ उसके ग्राहक अधिक संख्या में हों या जहाँ से माल जल्दी और कम खर्च से बाजारों में भेजा जा सके। अतः, आमनौर से बड़े-बड़े बाहरी के आसपास कारखाने स्थापित किये जाते हैं जिससे माल के विक्रय में आसानी हो। बहुत से उद्योग बड़े-बड़े रेलवे जंक्शनों के निकट केन्द्रित हो जाते हैं क्योंकि वहाँ से माल को ले-आने ले-जाने में बहुत सुविधा होगी और खर्च भी कम पड़ता है। अतः, जो स्थान मजदूरी के निरुद्ध होगा अथवा जहाँ माल ले-आने ले-जाने के लिए अच्छे और सस्ते वातायात के साधन होंगे, वहाँ अन्य बातों के समान रहने पर अधिक स्थानीयकरण होगा।

स्थानीयकरण का एक दूसरा महत्वपूर्ण आर्थिक कारण बाजारों में श्रम और पूँजी मिलने की सुविधा है। अन्य बातों के समान रहने पर जहाँ बहुत अधिक संख्या में, अधिक निपुण और सस्ते मिलेंगे, वहाँ

स्थानीयकरण की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी । कलकत्ता, बम्बई आदि स्थानों में विभिन्न उद्योगों के स्थानीयकरण का एक कारण यह भी है कि वहाँ मजदूर काफ़ी सरलता से मिलने रहते हैं । इसी प्रकार जहाँ अपेक्षाकृत पूँजी-प्राप्ति की अधिक सुविधा होगी, जहाँ वेतन आदि वित्त सम्बन्धी समस्याएँ होंगी, वहाँ भी स्थानीयकरण अधिक होगा । कारण, समय पर काफ़ी मात्रा में और उचित म्याज की दर पर पूँजी के मिलने से व्यापार में, उद्योग मध्यों के विकास में बहुत सुविधा होती है । वास्तव में इस तरह की व्यवस्था के बिना कोई उद्योग ठीक प्रकार से नहीं चलाया जा सकता । इसलिए जिन स्थानों पर पूँजी मिलने की उचित व्यवस्था और सुविधा होगी, वहाँ उद्योग धन्यों का स्थानीयकरण होना स्वाभाविक है ।

(३) राजनीतिक कारण—सरकारी सहायता, सुरक्षा या प्रोत्साहन से भी उद्योगों के स्थानीयकरण में बहुत सहायता पहुँचती है । यदि किसी स्थान पर सरकार या राजा की ओर से किसी विनय प्रकार के उद्योग धन्यों की सहायता या प्रोत्साहन मिलता है, तो वहाँ उस उद्योग-धन्य का स्थानीयकरण होना स्वाभाविक ही है । ऐसा करने से सरकारी सुविधाओं से लाभ उठाया जा सकता है । अपने इतिहास के देखने से पता चलता है कि छात्रा में मुसलमान का उद्योग और मुस्लिमवाद में रश्म का उद्योग वहाँ के हिन्दू और मुसलमान राजाओं की कृपा से उत्पन्न हुआ था ।

(४) पहले प्रारम्भ होना—कभी-कभी किसी उद्योग का किसी स्थान में केवल इसलिए स्थानीयकरण हो जाता है कि उस स्थान में कुछ अवसर-प्राप्ति कम भये हैं और उस उद्योग को शुरू कर दिया है । धीरे-धीरे वह स्थान उस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो जाता है और आगे चलकर वहाँ अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त होने लगती हैं । उनसे लाभ उठाने के लिए उस उद्योग के और नये-नये कारखाने वहाँ खुल जाते हैं । लंबे समय में वह स्थान उस उद्योग का केन्द्र बन जाता है । अस्तु, पहले किसी कारखाने का प्रारम्भ होना भी स्थानीयकरण का एक अवर्द्धक कारण हो जाता है ।

उपर्युक्त बातों से पता चलता है कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न उद्योगों का स्थानीयकरण किन कारणों से होता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि स्थानीयकरण के लिए इन सब कारणों का एक साथ होना आवश्यक है। किसी उद्योग का स्थानीयकरण किसी कारण से हो सकता है और किसी का दूसरे से। हाँ, यह बात अवश्य है कि प्रत्येक उत्पादक अपने व्यवसाय को ऐसे स्थान पर स्थापित करने का प्रयत्न करेगा जहाँ उत्पादन का खर्च कम से कम हो सके।

### स्थानीयकरण से लाभ

(Advantages of Localisation)

उद्योग-धंधों के स्थानीयकरण से जलता और उत्पादकों को जनेक लाभ होते हैं। इनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं —

(१) अब कोई उद्योग-धंधा किसी एक स्थान पर केन्द्रित हो जाता है तो उसके लिए उस स्थान का नाम दूर-दूर तक फैल जाता है। वहाँ की बनी हुई चीज की भाँक मंडी में जम जाती है। मशहूर हो जाने के कारण दूर-दूर के खरीदार उसे बिना किसी हिचक के ख़ूब खरीदते हैं और उस वस्तु के दाम भी अच्छे मिलते हैं। इसमें उत्पादकों और व्यापारियों को बहुत लाभ होता है। उदाहरण के लिए बाग़मोरी दुनाले, अलोगढ़ के ताले, मेरठ की कैंचियाँ, सिव्हरलैंड की बनी हुई घड़ियाँ आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। लोगों को इनके गुणों में विश्वास है और इस कारण ये ख़ूब बिकती हैं।

(२) स्थानीयकरण में धन के विशिष्टीकरण में भी पर्याप्त सहायता मिलती है। एक ही व्यवसाय में लगे रहने के कारण उनके विषय में मजदूरों को विस्तृत जानकारी हो जाती है। वे उस उद्योग में गरमरामन कुशलता पाते आते हैं। इस कारण वे इस काम में विशेषज्ञ हो जाते हैं। उनकी कार्य-क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही उनके बच्चों को उस व्यवसाय का ज्ञान प्राप्त करना बहुत सरल और सुविधाजनक हो जाता है। एक शब्द से यह उद्योग की विशेषता, उस स्थान के स्थापत्य से यह



जाती है और वच्च उस अपन आप मीस लेते ह । इस कारण कान सोसत क समय और सच म बहुत बचत होती है ।

३ (३) यह स्थान एक विजय प्रकार क श्रम का कद्र व बाजार बन जाना है । उस प्रकार क श्रमिक बड़ा गर अपन आप गहुचते रहत ह । इस श्रमिको और मिल मालिको दोनो को बहुत सुविधा होगी है । श्रमिको को आसानी म काम मिल जाना है और मिठ मालिको को उस काम म सम्बध रखन थाल श्रमिको को दहन के त्रिए सुसोबत नही उठानी पडती ।

(४) स्थानीयकरण म कारखाने क मालिको प्रयत्नको तथा वैज्ञानिको म परस्पर मिलन और विचार विनिमय करन का पाप्री मौका मिलता है । नई नई उत्पादन प्रणालियो और मशीनो आदि क सम्बध में उत्तति करण की बहुत सम्भावना रहती है । इस प्रकार जे उत्तति आविष्कार व सुधार एक कारखाने म होना ह उसकी जानकारी आसानी म दूसरो को भी हो जाती ह । अस्तु उत्तति का प्रभाव केवल एक या दो कारखानो तक ही सीमित नही रहता बल्कि सब कारखानो को उसने लाभ होना है ।

(५) बहुत-से एव ही प्रकार क कारखानो क एक स्थान पर स्थापित हो जान म अनक अग पूरक और सहायक उद्योग धंध चल पडत है । ये प्रधान कर्त्रीय उद्योग की विभिन्न प्रकार मे सहायता करत ह । ये उसके लिए कच्चे माल मशीन आदि की व्यवस्था करत ह और यातायात, बैंकिंग तथा इस प्रकार की अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करत है ।

(६) उद्योग क स्थानीयकरण मे पूजी मिलन म बड़ी सुविधा होती है । बक और पूजी देन वाली अन्य संस्थाएं एग स्थानी और उद्योगो पर विभय रूप से अपनी दृष्टि रखती ह । वहा की स्थिति म पूज परिवर्तन होन म व पूजी लगान क लिए अधिक आसानी म तैयार रहती ह । अस्तु, उस उद्योग म लग हुए अथवा लगन बाठ लोगो को पूजी आसानी से मिल सकती है ।

(७) किसी उद्योग-धर्म के स्थानीयकरण में उसके अवशिष्ट पदार्थों अथवा छीज को लाभप्रद ढंग से उपयोग में लाया जा सकता है। यदि उस धर्म के कारखाने अलग-अलग क्षेत्रों में हों तो सम्भव है कि प्रत्येक कारखाने का अवशिष्ट पदार्थ इतना कम हो कि उसे काम में लाने के लिए एक स्वतन्त्र कारखाना खोलना लाभप्रद न हो सके। यदि अवशिष्ट पदार्थ की मात्रा नाफी है, तो उसे काम में लाने के लिए उपाय सोचे जा सकते हैं। इसके लिए एक अलग कारखाना खोला जा सकता है। इससे सबको लाभ होगा और व्यर्थ का नुकसान बचाया जा सकता है।

### स्थानीयकरण से हानियाँ

(Disadvantages of Localisation)

उद्योग-धर्मों के स्थानीयकरण में कुछ हानियाँ भी होती हैं। जब किसी उद्योग-धर्म में एक विशेष प्रकार के ही धर्म की आवश्यकता होती है, तो उससे बड़ी असुविधा और हानि होती है। क्योंकि कुछ लोग बेकार रह जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि वह व्यवसाय ऐसा है जिसमें काम करने के लिए अधिक शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होगी है, तो उस स्थान के कमजोर मजदूरों को काम न मिल सकेगा। वे बेकार रहेंगे। इसलिए चाहे काम पर लगे हुए मजदूरों की मजदूरी अधिक हो, फिर भी एक मजदूर के परिवार की औसत आय कम ही होगी। उद्योगपतियों को अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी देनी पड़ेगी, फिर भी श्रमिकों को प्रति कुटुम्ब के विचार से औसत रूप से कम आमदनी होगी। इनसे सभी को हानि होगी। इस दोष को दूर करने का उपाय यह है कि बहुत पर महायक तथा पूरक उद्योग-धर्मों की स्थापना की जाय जिससे दूसरे प्रकार के धर्मिकों की भी आवश्यकता पड़ती हो।

दूसरी मुख्य हानि यह है कि किसी भी स्थान की वार्षिक समृद्धि का एक ही धर्म पर आश्रित होना बहुत ही असंतोषजनक और खतरा की बात है। यदि किसी कारण से, धर्म के कम हो जाने से या कच्चा माल

ठीक समय पर न मिलने से अथवा अन्य किसी कारण से उस धंधे पर कोई आपत्ति आ जाय तो समस्त क्षेत्र में आर्थिक संकट छा जाता है। मजदूर बेकार हो जाते हैं, व्यापार मंदा पड़ जाता है और फलस्वरूप उस स्थान की रहने वालों को अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। अतः स्थायीकरण से वहाँ के लोगों में बेकारी बढ़ने और आर्थिक मन्दी तथा हलचल का बड़ा भय रहता है। इस आपत्ति से बचने के लिए यह आवश्यक है कि उस स्थान पर दूसरे धंधे भी हों जिनमें आर्थिक संकट के समय कुछ सहायता मिल सकें।

### विकेंद्रीकरण

(De-localisation)

जाड़कल कई कारणों से विकेंद्रीकरण जोर पकड़ रहा है। स्थायीकरण के जगहों पर जन-संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इसमें जमीन की कीमतें ऊपर चढ़ती चली जाती हैं और रहन-सहन का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। लोगों के रहने के लिए मकान और कारखानों के लिए खाली जमीन का मिलना कठिन हो जाता है। इन सब कारणों से रहन-सहन का खर्चा और उत्पादन-व्यय बहुत बढ़ जाता है। साथ ही, आवासीय में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण अनेक सामाजिक और नैतिक बुराइयाँ वहाँ तेजी से फैलने लगती हैं। इसके अनिश्चित केन्द्रित उद्योग राष्ट्र के शत्रुओं द्वारा वम-वर्षा का सरल लक्ष्य बन सकते हैं और परिणामस्वरूप सारे राष्ट्र का जीवन कुछ ही क्षण में अस्त-व्यस्त हो सकता है। अतः, स्थायीकरण से सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और देश की सुरक्षा-सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ और समस्याएँ उत्पन्न होनी हैं। इनमें बचने के लिए संसार के सभी बड़े-बड़े देश अब विकेंद्रीकरण की ओर घड़ेष्ट ध्यान दे रहे हैं।

बिजली और यातायात के साधनों में आसानी होने से हम और काफी सहायता मिल रही है। बिजली अन्य कालक-शक्तियों की अपेक्षा

बहुत सस्ती पड़ती है और इसे दूर-दूर तक आसानी से ले जाया जा सकता है। साथ ही यातायात के साधनों में उन्नति होने के कारण अब माल को ले-आने ले-जाने में कोई असुविधा नहीं होती और न अब यह काम बहुत महंगा ही पड़ता है। अस्तु, अब किसी खास बाजार, चालक-शक्ति व कच्चे माल के स्थान आदि के पास कारखानों का स्थापित होना उतना जरूरी नहीं रह गया है। कारखानों के विकेंद्रीकरण से उपर्युक्त कठिनाइयों में बचने के अलावा अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इससे द्वारा देश के विभिन्न भागों में जन-संख्या और उद्योग-धन्धों को समुचित ढंग से बांट कर देहाती और शहरी क्षेत्रों के भेद व अन्तर को मिटाया जा सकता है। इसके द्वारा स्थानीय साधनों को वहीं पर ठीक प्रकार से उपयोग में लाकर विभिन्न भागों के समुन्नति और स्वास्थ्यप्रद विकास को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इन तमाम बातों के कारण विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति अब जोर पकड़ती जा रही है।

## QUESTIONS

- 1 Explain the meaning of localisation of industries  
What causes give rise to localisation ?
- 2 Explain fully the advantages and disadvantages of localisation of industries ?
- 3 What are the forces which are encouraging de-localisation these days ?

## उत्पादन की मात्रा (Scale of Production)

छोटे और बड़े दोनों पैमानों पर उत्पत्ति की जा सकती है। जब किसी एक वस्तु का उत्पादन एक समय में, एक उत्पादन इकाई में अधिक मात्रा में होता है तो उसे बड़े पैमाने की उत्पत्ति कहते हैं। इसके विपरीत जब थोड़े से श्रम और पूँजी में एक उत्पादन इकाई में कोई वस्तु कम मात्रा में तैयार की जाती है, तो उसे छोटे पैमाने की उत्पत्ति कहते हैं। कपड़े और चीनी की बड़ी-बड़ी मिलें, लोहे और इस्पात के नारखाने, रेलवे आदि बड़े पैमाने की उत्पत्ति के उदाहरण हैं। छोटे ढंग के उत्पादन के उदाहरण गाव के जुआहों, कुम्हारों, मुनारों आदि के काम तथा बेलगाड़ी आदि हैं। कुछ व्यवसायों में साधारणतया उत्पत्ति बड़े पैमाने पर की जाती है और कुछ में छोटे पैमाने पर। कभी-कभी एक ही व्यवसाय में बड़े और छोटे दोनों ढंग के उत्पादन साथ-साथ चलते दिखाई पड़ते हैं।

आवकल बड़े पैमाने की उत्पत्ति बहुत जोर पकड़ रही है। सभी प्रगतिशील देशों में लोग बड़े पैमाने की उत्पत्ति-वृद्धि को अपनाते जा रहे हैं। आधुनिक आर्थिक जीवन को यह एक प्रमुख विशेषता बन गई है। किन्तु इसका यह आशय नहीं कि छोटे पैमाने की उत्पत्ति-प्रणाली खत्म हो गई है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ में छोटी मात्रा में उत्पत्ति करने वाले उत्पादकों को हटाया नहीं जा सकता। जिन उद्योग-धन्धों में उत्पादक के व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता पड़ती है या जिनमें व्यक्तिगत सचिवा और फैसलों के अनुसार काम करना पड़ता है, उनमें बड़ी मात्रा की उत्पत्ति संभव नहीं

हो सकती । वास्तव में दोनों प्रकार के उत्पादनों के अपने कुछ विशेष लाभ हैं जिनके कारण दोनों आज तक बने हुए हैं । हा, यह बात अवश्य है कि वर्तमान समय में बाजार, विस्तृत श्रम-विभाजन मशीन के उपयोग आदि से बड़ी मात्रा की उत्पत्ति को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है । संशय में, अब हम बड़ी और छोटी मात्रा की उत्पत्ति के लाभ-हानि पर विचार करेंगे । इस अध्ययन से हमें यह मली-भाति मालूम हो जायगा कि क्यों आवश्यक बड़ी मात्रा की उत्पत्ति जोर पकड़ रही है और साथ ही यह भी कि क्यों और कैसे छोटी मात्रा की उत्पत्ति आज भी चल रही है ।

### बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के लाभ

(Advantages of Large Scale Production)

बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के बहुत से लाभ होते हैं । इससे उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बचत होती है जिसमें लागत-खर्च कम हो जाता है और इस कारण माल तैयार करने वालों को अधिक लाभ मिलता है । उपभोक्ताओं को अधिक मात्रा में और कम दामों में अनेक प्रकार की वस्तुएँ प्राप्त होती हैं । साथ ही श्रमिकों को काम करने में तरह-तरह की सुविधाएँ मिलती हैं और अधिक मजदूरी भी । इन सब कारणों से बड़ी मात्रा की उत्पत्ति हर क्षेत्र में तेजी से फैल रही है ।

प्रो० मार्शल के अनुसार बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में होने वाले लाभों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—(१) बाह्य बचत (external economies) और आन्तरिक बचत (internal economies) । 'बाह्य बचत' से अभिप्राय उन लाभों या बचतों में है जो किसी स्थान पर किसी उद्योग के विस्तार अथवा उत्पत्ति के कारण होती हैं । जब कोई उद्योग एक निश्चित स्थान पर स्थापक रूप से उत्पत्ति करता है, बढ़ता और फैलता है, तो वहाँ पर अनेक प्रकार की बचतें और सहूलियतें पैदा हो जाती हैं जिनमें उस उद्योग में लगे हुए सभी कारखाने फायदा उठा सकते हैं । जैसे उस उद्योग में सम्बन्ध रखने

वाले थम, औजार, मशीन, कच्चे माल आदि वहाँ आप से आप पहुँचने लगते हैं। उस स्थान पर एक विशेष प्रकार के थम के लिए एक बाजार-सा बन जाता है जिससे उस व्यवसाय-सम्बन्धी थम के मिलने में बड़ी सुविधा होती है। पूँजी भी बाजारी में मिल जाती है क्योंकि वहाँ की स्थिति से भली-भाँति परिचित होने से बैंक आदि उस काम में पूँजी लगाने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं। अधिक मात्रा में उस उद्योग के लिए मशीनें बनने से उनकी कीमतें कम हो जाती हैं। साथ ही वहाँ पर अनेक सहायक और पूरक उद्योग-धन्धे स्थापित हो जाते हैं जो विभिन्न ढंग से प्रधान उद्योग की सहायता करते हैं। वे उसे कच्चा माल, औजार, मशीन आदि देते हैं, उसके माल को ले-जाने ले-जाने के लिए उचित सगुन करते हैं, और उसकी उप-उत्पत्तियों (by-products) को कई प्रकार से काम में लाते हैं। इन सब बातों से इस उद्योग में लगे हुए लोगों को काफी लाभ होता है। इसके अलावा वह स्थान उस व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। फलस्वरूप उस व्यवसाय द्वारा तैयार हुई वस्तु की मदी बड़ी हो जाती है। उसके दाम अच्छे मिलते हैं और बेचने में भी कठिनाई नहीं होती।

ये सब बाह्य बचत के उदाहरण हैं। स्थानीयकरण के लाभ इसी ढंग में आते हैं। ये लाभ किसी एक कारखाने या फर्म की अन्दरूनी व्यवस्था या उसके विस्तार के कारण नहीं, बल्कि उस पूरे उद्योग के विस्तार के कारण होते हैं। सभी कारखाने इन बातों से लाभ उठाने हैं। उत्पादन-व्यय में इनसे काफी कमी हो जाती है।

‘आन्तरिक बचत’ इन बातों को कहते हैं जो किसी फर्म व कारखाने को उसके विस्तार के कारण प्राप्त होती है। ये उसे बाहरी व्यवहार द्वारा नहीं, बल्कि अपनी आन्तरिक व्यवस्था की कुशलता, क्षमता या उत्तमता के कारण मिलती है। केवल वही इन बातों में लाभ उठा सकता है, दूसरी फर्म नहीं। जब कोई फर्म अपना काम बढ़ाती है, अर्थात् काम बढ़े पैमाने पर करती है, तो उसके लिए उच्च स्तर के थम-विभाजन का

सहारा देना, विनोपजो और कुशल धमिको को काम पर लगाना तथा नई व कीमती मशीनों को अधिक अच्छी तरह से उपयोग में लाना सम्भव हो जाता है। इनसे उम्मे अनेक प्रकार की बचत होती है और उत्पादन-व्यय कम हो जाता है। चूंकि यह बचत उस फर्म की अन्दरूनी बातों से, उसकी व्यवस्था में सुधार या उन्नति से होती है, इसलिए इसे 'आन्तरिक बचत' कहते हैं। बड़ी मात्रा में उत्पादन करने में जो किसी फर्म या कारखाने की आन्तरिक बचत हो सकती है, उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं —

(१) बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में श्रम-विभाजन को उच्चतम सीमा तक पहुंचा कर उसके विभिन्न लाभ प्राप्त हो सकते हैं। धमिकों और प्रबन्धकों के बीच काम का उत्तरण दृष्ट से विभाजन किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित काम लगातार करने को दिया जा सकता है जिसमें वह अपनी अधिक से अधिक कुशलता और योग्यता दिखा सक्ता हो। इससे श्रम और योग्यता में बहुत बचत होती है और उत्पादन अधिक और उच्च कोटि का होता है।

(२) अच्छी से अच्छी और नवीनतम मशीनों का उपयोग किया जा सकता है तथा प्रत्येक विशेष कार्य के लिए एक विशेष मशीन काम में लाई जा सकती है। इसमें अनेक लाभ होते हैं। छोटी मात्रा के उत्पादनो के लिए बड़ी और कीमती मशीनों का उपयोग सम्भव नहीं होता। वह इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा नहीं होता, बल्कि इसलिए कि मशीन में पूरा फायदा उठाने के लिए उत्पादन बड़ी मात्रा में करना पड़ता है। यदि भाग सीमित होने के कारण उत्पत्ति छोटी मात्रा में करनी है, तो मशीन का उपयोग लाभप्रद न होगा।

(३) जितना ही बड़ा कारखाना होगा, उतना ही कम सामान व्यर्थ जायगा। बड़े कारखाने के अवशिष्ट पदार्थों या उप-उत्पत्तियों (by-products) को अच्छी तरह से उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें खर्च पट जाता है और लाभ में वृद्धि होती है। छोटी मात्रा की



उत्पत्ति में अवशिष्ट वस्तुओं का लाभप्रद उपयोग नहीं हो पाता । वे व्यर्थ जाते हैं ।

(४) बड़ी मात्रा के उत्पादक कच्चा माल, मशीन, बीमार आदि अधिक तादाद में खरीदते हैं । इस कारण उन्हें ये सब चीजें, सस्ते भाव में मिल जाती हैं । यह तो साधारण-सी बात है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को थोक में खरीदता है, तो उसे वह चीज कुछ सस्ते दर से मिल जाती है । इसलिए बड़े परिमाण में उत्पत्ति करने वालों को सामान खरीदने में काफी क्लिफायर होती है । उनकी दुकानें आदि का खर्चा भी औसतन कम पड़ता है । इसी प्रकार अपने तैयार माल के बेचने में उन्हें बहुत बचत होती है । रेलवे और यातायात के अन्य साधन, अधिक मात्रा में माल पाने के कारण, कम भाड़े पर माल लादने को तैयार रहते हैं । कुछ बड़े कारखाने वाले अपनी-अपनी रेलवे ट्रक भी रखते हैं जिस पर सामान लादकर मजदूरों के स्टेशन तक माल भेजते हैं । इसमें सामान के लादने और उतारने में काफी बचत होती है । साथ ही माल के बेचने के लिए वे अपनी दुकानें खोलकर दलाल का मुनाफा खुद ले सकते हैं ।—

इस सम्बन्ध में प्रचार और प्रभावदायक विज्ञापनों के लाभों को भी ध्यान में रखना चाहिए । बड़ी मात्रा के उत्पादक दूर-दूर तक और खूब अच्छे ढंग में अपने माल का विज्ञापन कर सकते हैं । सामान के विज्ञापन और उसकी बिक्री के लिए वे कुशल और अनुभवी व्यक्तियों को रख सकते हैं । इसमें आधुनिक आर्थिक जगत में सफलता प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलती है । छोटी मात्रा के उत्पादकों के लिए यह सब सम्भव नहीं है ।

(५) बाजार के उतार-चढ़ाव का बड़े कारखानों पर छोटे कारखानों की अपेक्षा कम प्रभाव पड़ता है । इसका एक कारण तो यह है कि बड़े कारखानों के प्रबन्धकर्त्ता कुशल, अनुभवी और दूरदर्शी होते हैं । वे इस बात का काफी ठीक अनुमान लगा लेते हैं कि उनके माल की माग भविष्य

में कँधी होगी। उसी के आधार पर उत्पादन-कार्य चलता है जिससे आगे चलकर किसी विशेष आपत्ति का सामना करना नहीं पड़ता। वे अपने समय और शक्ति को कारखाने की छोटी-छोटी बातों में नष्ट नहीं करते। अपने आपको वे बाजार की परिस्थिति की पूर्ण जानकारी और बाजार-माम्यन्धी समस्याओं को हल करने के लिए स्वतन्त्र रखते हैं। वे बराबर उन बातों की खोज में लगे रहते हैं जिनमें लागत-खर्च में कमी हो और माल को बिक्री अधिक से अधिक हो सके। दूसरा कारण यह है कि उनका माल अनेक बाजारों में बिकता है। इस कारण स्थायित्व रहता है और आर्थिक सफटो में कम पड़ना पड़ता है। अनेक बाजार होने से किसी एक बाजार की तेजी-मंदी में विशेष हानि नहीं होती क्योंकि दूसरे बाजारों द्वारा लाभ उठाकर हानि पूरी की जा सकती है। छोटी मात्रा के उत्पादक के लिए यह सम्भव नहीं है क्योंकि उनका माल एक-दो मंडियों में ही जाता है। इस कारण बाजार की तेजी-मंदी का उन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। साथ ही बड़े कारखाने वालों के पास काफी पूँजी होती है जिसकी सहायता से वे आर्थिक सफटो का अपेक्षाकृत आसानी से सामना कर सकते हैं।

(६) बड़े कारखाने में नये-नये प्रयोगों, गुणों तथा आविष्कारों के लिए एक स्वतन्त्र व्यवस्था की जा सकती है। इनके लिए एक विभाग खोला जा सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में बहुत काम होते हैं। इससे नये-नये कच्चे मालों का उपयोग सम्भव हो जाता है और उत्पादन के अच्छे से अच्छे तरीके मालूम होते रहते हैं। इन सब बातों से उत्पात्ति अधिक और अच्छी होने लगती है और उत्पादन-खर्च कम हो जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान पर बहुत खर्च जाता है। इसलिए छोटे कारखानों के लिए यह सम्भव नहीं है। बड़े कारखानों में इसका प्रति इकाई खर्च अधिक नहीं बैठता।

(७) इसके अलावा बड़ी मात्रा के उत्पादक को यह भी लाभ होता है कि उगकों, छोटे पैमाने पर काम करने वालों की अपेक्षा, कहीं

अधिक लोभ जान जाते हैं। उसकी ख्याति दूर-दूर तक फैल जाती है। उसका माल स्वयं ही उसके विज्ञापन का साधन बन जाता है। इससे उसे अनेक लाभ होते हैं। उसकी विप्री बढ जाती है और दाम अच्छे मिलते हैं। पूँजी भी आवश्यकतानुसार आसानी से और कम व्याज पर बैंक वगैरा में मिल जाती है।

इस तरह हम देखते हैं कि बड़ी मात्रा के उत्पादक को उत्पादन-क्षेत्र में, खरीद और बिक्री में, व्यवस्था और प्रबन्ध आदि कार्यों में तरह-तरह की बचतें प्राप्ता होती हैं। इससे उसका लाभ बढ जाता है। उपभोक्ताओं तथा समाज को भी इससे बड़ा लाभ होता है। उन्हें अनेक तरह की सस्ती वस्तुएँ आसानी से अधिक मात्रा में मिल सकती हैं।

### बड़ी मात्रा की उत्पत्ति की सीमा

(Limits to Large Scale Production)

बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के इतने अधिक लाभ हैं कि यह सोचा जा सकता है कि काम के विस्तार की कोई सीमा नहीं होगी। काम फैलता ही जायगा। किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इसका कारण यह है कि बड़ी मात्रा की उत्पत्ति से होने वाले लाभ की भी एक सीमा होती है। जैसे-जैसे किसी फर्म या कारखाने का विस्तार फैलता जाता है, उसके सामने धीरे-धीरे बहुत-सी कठिनाइयाँ आने लगती हैं और छान म जमागत होता होने लगता है। एक समय वह भी आ जाता है जबकि बचन बन्द हो जाती है और उत्पादन-व्यय बढ़ने लगता है। इस स्थिति पर पहुँच कर उत्पत्ति की मात्रा में और अधिक वृद्धि लाने की मुझाईश नहीं रह जाती क्योंकि बचत के स्थान पर हानि होने लगती है। अस्तु, काम का विस्तार रोक दिया जाता है। काम के विस्तार को सीमित करने वाली बातों में से मुख्य निम्नलिखित है —

(१) सबसे मुख्य बात उपरि व्यवस्था, प्रबन्ध और सम्बद्ध करने की कठिनाई है। प्रत्येक व्यवस्थापक व प्रबन्धक की योग्यता, क्षमता

और संगठन-शक्ति की एक सीमा होती है। एक सीमा तक ही वह संगठन और देख-रेख का काम अच्छी तरह से कर सकता है। उस सीमा के बाहर विभिन्न विभागों को सम्बद्ध और संगठित करना, कई शाखाओं को सभालना तथा काम की उचित देख-भाल करना उसके लिए बटन हो जायगा। काम में त्रुटियाँ होने लगेंगी। उत्पादन-व्यय बढ़ जायगा। लाभ कम होगा और हानि अधिक। इस प्रकार संगठन और प्रबन्ध की कठिनाइयाँ निजी काम के विस्तार का एक सीमा के बाद रोक देती हैं। उस सीमा के बाद काम के फलदायक में लाभ न होगा।

(२) बड़ी मात्रा की उत्पत्ति तभी तक लाभदायक होगी जब तक कि बाह्य और आन्तरिक शक्तों की गुंजाइश होगी। कारण, इन सधमें उत्पादन-व्यय कम होता जाता है। लेकिन एक सीमा के बाद थम-विभाजन, स्वामीयकरण और मशीन के उपयोग से होने वाली बचत खत्म हो जाती है। इस सीमा के आगे विस्तार करने में लाभ नहीं होगा।

(३) कोई कारखाना कितना बड़ा या फैला सकता है, यह मात्र और मशीन पर निर्भर है। जितनी ही बड़ी और खायी मशीन होगी, उतना ही अधिक विस्तार सम्भव होगा, किन्तु मशीन की सीमा के बाहर नहीं। यदि विस्तार इसमें अधिक हुआ तो कुछ माल बिना बिके व्यर्थ पड़ा रहेगा और फलस्वरूप उत्पादक को हानि होगी।

(४) बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए उत्पत्ति के साधनों की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। जितना अधिक विस्तार दिया जायगा, उतनी ही अधिक साधनों की आवश्यकता होगी। पर सम्भव है विस्तार करने के लिए उपयुक्त समय पर पूँजी और अन्य साधन पर्याप्त मात्रा में न मिल सकें। फिर भला किस प्रकार अधिक विस्तार सम्भव हो सकेगा। अस्तु, किसी व्यवसाय का विस्तार इस कारण भी सीमित हो जाता है।

(५) एक-दो बातें और हैं जिनसे विस्तार सीमित होता है। जैसे-

जैसे हम किसी व्यवसाय को बढ़ायेगे, उत्पत्ति के साधनों की मांग बढ़ती जाएगी और इस कारण उनकी कीमते भी। हमें अधिक मजदूरी, किराया, म्याज आदि देना पड़ेगा। इससे उत्पादन-व्यय बढ़ जायेगा। साथ ही बिक्री के संगठन में भी अधिक खर्च करना पड़ेगा। इन सब बातों से खर्च इतना बढ़ सकता है कि विस्तार में कोई लाभ न हो। दूसरी ओर उत्पादन की मात्रा में भी अधिक वृद्धि लाने से मशीनें उस चीज की कीमत निरसकती हैं। इससे बड़ा कारखाना नुकसान में आ सकता है क्योंकि उसका ढांचा ऐसा होता है कि उसमें जल्दी से परिवर्तन लाना कठिन होता है। अस्तु, व्यवसाय के विस्तार की एक सीमा होती है। उसके आगे विस्तार करना लाभप्रद नहीं होता।

### बड़ी मात्रा की उत्पत्ति से हानियाँ

(Disadvantages of Large Scale Production)

बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में धमन-विभाजन और मशीनों का विशेष रूप में उपयोग किया जाता है, इसलिए इनसे होने वाली हानियों को बड़ी मात्रा की उत्पत्ति की हानियों की सूची में शामिल किया जा सकता है। इनके अलावा बड़ी मात्रा की उत्पत्ति से कई और हानियाँ होती हैं जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं

(१) बड़े कारखानों का ढांचा और प्रबन्ध इस प्रकार का होता है कि उनमें आसानी से परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। फंडा, अम-दनी, जन-संख्या आदि में परिवर्तन होते रहने से प्रायः मांग का रख बढलना रहता है। इस कारण मशीनें नई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। किन्तु नई परिस्थितियों के अनुगार बढलने में बड़े कारखाने की काफी कठिनाई होती है।

(२) दूसरी बात यह है कि बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में मालिकों और मजदूरों के बीच सीधा सम्बन्ध नहीं रहता। मालिकों का मजदूरों के साथ निजी सम्पर्क नहीं होता। इससे दोनों के बीच संघर्ष बढ़ता है, जिनके दुष्परिणाम से वर्तमान आर्थिक संसार भली-भाँति परिचित है।

(३) बड़े कारखानों में अनेक विभाग होते हैं और विस्तार के साथ-साथ वे और भी बढ़ते जाते हैं। उनकी देख-रेख और सम्बद्ध करने में बड़ी कठिनाई होती है और खर्चे भी बहुत पड़ता है। फिर भी सुप्रबन्ध और कुशलता विघटने का भय लगा रहता है क्योंकि बेतन-भोगी मैनजर साधारणतः उतनी कड़ी मेहनत और दिलचस्पी में काम नहीं करते। यही नहीं, निर्णय करने में भी बड़ी देरी लगती है। विभिन्न विभागों में पूछताछ, सलाह और आज्ञा लेनी पड़ती है जिसके कारण निर्णय में बहुत समय लग जाता है।

(४) एक और हानि ध्यान देने योग्य है। वह यह है कि बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में प्रायः गुटबन्दी (combination) का प्रोत्साहन मिलता है और एकाधिकार (monopoly) स्थापित हो जाता है। जैसे तो एकाधिकार में कुछ लाभ भी होते हैं, लेकिन अक्सर एकाधिकारी की नीति में आम लोगों को लाभ नहीं होता। इससे कीमत ऊँची हो जाती है और मजदूरों तथा उत्पादन के अन्य साधनों का शोषण होता है। वितरण की विषम समस्या आ सही होती है और अनेक प्रकार के झगड़े उत्पन्न लगत हैं। राजनीतिक बातावरण भी स्पष्ट हो जाता है।

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में केवल लाभ ही नहीं हासिल करना अनेक हानियाँ भी हासिल हूँ।

### छोटी मात्रा की उत्पत्ति में लाभ

(Advantages of Small Scale Production)

यह ठीक है कि बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में अनेक लाभ हैं और इस ओर लोगों का झुकाव भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इतना यह अर्थ नहीं कि छोटे पैमाने की उत्पत्ति का अन्त आ चुका है अथवा अब इसका कोई भविष्य नहीं है। छोटे उत्पादक आज भी अनेक क्षेत्रों में माहुर और सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। कुछ काम ऐसे हैं, जिनमें बहुत कीमती कच्चा माल लगता है, जिनमें व्यक्तिगत ध्यान और विशेष कला-कौशल

के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें प्रामाणिकता या दर्जाबन्दी (standardisation) सम्भव नहीं होती। इस प्रकार के उद्योगों में छोटी मात्रा की उत्पत्ति ही ठीक और लाभप्रद होती है। फिर कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनकी माग न तो अधिक होती है और न स्थायी हो रहती है। उसमें बराबर उतार-चढ़ाव होता रहता है। यहाँ भी छोटे फर्म ही सफलतापूर्वक उन्नति कर सकते हैं। इसी प्रकार जिन उद्योगों में अलग-अलग विभाग नहीं किये जा सकते अथवा जिनमें जल्दी-जल्दी तत्काल निर्णय करने पड़ते हैं, वहाँ भी छोटे उत्पादक ही सफल हो सकते हैं। अस्तु, कुछ उद्योग ऐसे हैं जहाँ बड़ी मात्रा की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। वहाँ छोटी मात्रा में ही उत्पादन लाभदायक हो सकता है।

छोटे उत्पादक को कुछ विशेष लाभ भी होते हैं जिनके कारण उनका अस्तित्व अभी तक बना है और आगे भी बना रहेगा। इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया जाता है। सर्वप्रथम, छोटे उत्पादक स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से काम के प्रत्यक्ष अंश की खूब अच्छी तरह देख-भाल कर सकते हैं। उनकी दृष्टि हर तरफ होती है। इसलिए कागचोरी का कोई मौका नहीं आ पाता। मजदूर पूरी तरह से अपना काम करते हैं जिससे काम अधिक और अच्छा होता है। बड़े कारखानों के खर्चाले प्रबन्ध और देख-रेख की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं होती। इससे काफी बचत होती है।

दूसरे, छोटे परिमाण पर उत्पादन करने वालों को सब विभागों का स्वयं अध्ययन होने और काम की अन्तिम सफलता और असफलता के लिए उत्तरदायी होने से विभिन्न विभागों का समन्वय और उनके बीच सामंजस्य रखने में किसी विशेष धटिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। थोड़े से ही लोगों से उसे सलाह और पूछताछ करनी पड़ती है, इसलिए किसी बात के निर्णय करने में उसे देरी नहीं लगती।

तीसरे, छोटी मात्रा की उत्पत्ति में मालिक का मजदूरों के साथ सीधा सम्बन्ध रहता है। इससे घर्षण बढने नहीं पाता। जो कुछ कठिनाइयाँ और गिरावटें होती हैं उन्हें बानानी से शुरू में ही दूर किया जा सकता है।

इस कारण हड़ताल और तालाबन्दी की मौकत कम आने पाती है।

चौथे, छोटे उत्पादक उपभोक्ताओं के बहुत सम्पर्क में रहते हैं। इस कारण उनकी आवश्यकताओं की जानकारी और उनके अनुसार उत्पादन करने में कोई कठिनाई नहीं होती। जो कुछ माल तैयार होता है वह शीघ्र ही खप जाता है। इससे वह तो अधिक माल व्यर्थ पड़ा रहना है और न ही तेजी-मंदी की समस्या ज़ोर पकड़ती है।

पाचवे, छोटे उत्पादक को अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार काम करने की स्वतन्त्रता होती है। वे स्वतन्त्र रूप से अपने परों में काम करते हैं। इससे काम अधिक और अच्छा होता है। मन और शरीर पर भी इनका अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही छोटे उत्पादकों को कृत्यात्मक वस्तुएं बनाने की भी सुविधाएं रहती हैं। वे अधिक समय देकर बारीकी और कला-कौशल दिखा सकते हैं। साधारणतः उनकी वस्तुओं में अधिक सुन्दरता होती है।

छोटे पैमाने के उत्पादकों को आज और कई सुविधाएं मिलने लगी हैं जिनसे उनकी जड़ और मजबूत हो गई हैं। समाचार-पत्र, व्यापार-सम्बन्धी साहित्य तथा अन्य साधनों से उन्हें आवश्यक बातों की जानकारी होती रहती है। तार, डाक, टेलीफोन, रेल, जहाज आदि साधनों के कारण उन्हें अनन्त सुविधाएं मिलती हैं जिनसे वे सफलतापूर्वक बड़े-बड़े उत्पादकों का मुकाबला कर सकते हैं। अनुसंधान और अनुभव के क्षेत्रों में वे अब चलने पीछे नहीं हैं। बिजली और छोटी-छोटी मशीनों के उपयोग से वे सस्ती वस्तुएं बना सकते हैं और सहकारी संस्थाओं में संगठित होकर ख़य-विख़य, माल ले-आने ले-जाने तथा पूँजी के उधार लेने में वे उन सब सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं जो बड़े उत्पादकों को मिल सकती हैं। वे बाह्य बचत से भी लाभ उठा सकते हैं जिसका महत्व बराबर बढ़ता जा रहा है। इन तमाम बातों और बड़ी मात्रा की उत्पात्ति की सीमा के कारण छोटे उत्पादक अनेक उद्योगों में सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं।



## QUESTIONS

- 1 What are internal and external economies? Explain how they arise
- 2 Examine the main advantages and disadvantages of large scale production
- 3 Discuss the principal economies of large scale production. Is there no limit to the growth of the size of a firm?
- 4 "The advantages of large scale production are so great that it should drive out small scale production in all branches of production. But that is not so." Explain
- 5 Bring out the main advantages of small scale production

## अध्याय २३ उत्पत्ति के नियम

### (Laws of Returns)

इस अध्याय में हम उत्पत्ति के नियमों का विवेचन करेंगे। यह पहले ही कहा जा चुका है कि उत्पत्ति के लिए कई साधनों की आवश्यकता पड़ती है। व्यवस्थापक आवश्यक साधनों को मिलाकर उत्पादन-कार्य चलाना है। साधनों की मात्रा बढ़ाने से कुल उत्पत्ति में वृद्धि होगी किन्तु यह निश्चित नहीं है कि उत्पत्ति किस दर या अनुपात में बढ़ेगी। यदि उत्पत्ति के साधनों को १० प्रतिशत में बढ़ाया गया है, तो हो सकता है कि उत्पत्ति १० प्रतिशत से बढ या उससे कम या अधिक। इसी के आधार पर उत्पत्ति के निम्नलिखित तीन नियम स्थापित किये गये हैं—(१) वर्मागत उत्पत्ति-वृद्धि नियम ( Law of Increasing Returns ), (२) क्रमागत उत्पत्ति-ह्रास नियम (Law of diminishing Returns) और (३) वर्मागत उत्पत्ति-स्थिर व समता नियम (Law of constant Returns)।

(वर्मागत वृद्धि नियम) यह बतलाता है कि यदि साधनों की मात्रा बढ़ा दी जाये तो उत्पादन उस अनुपात से अधिक बढ़ेगा। (क्रमागत ह्रास नियम) में यह बोध होता है कि उत्पत्ति, साधनों में वृद्धि के अनुपात में, कम बढ़ेगी है। और क्रमागत उत्पत्ति स्थिर व समता नियम यह बतलाता है कि उत्पादन उन्ही अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है। अस्तु, यह जानने के लिए कि किसी व्यवसाय में कब, कौन-सा नियम काम कर रहा है, हमें साधनों की वृद्धि की दर की

तुलना उत्पत्ति की वृद्धि की दर से करनी होगी। यदि जिन अनुपात से उत्पत्ति बढ़ रही है, वह उस अनुपात से अधिक है जिसमें साधनों को बढ़ाया गया है तो हम कहेंगे कि उस समय उस व्यवसाय में क्रमागत वृद्धि नियम लागू है। यदि उत्पत्ति की वृद्धि का अनुपात साधनों की वृद्धि के अनुपात के बराबर है, तो उत्पत्ति स्थिर नियम लागू समझा जायगा। और यदि साधनों की वृद्धि के अनुपात से उत्पत्ति की वृद्धि का अनुपात कम है, तो क्रमागत ह्रास नियम लागू समझा जायगा।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना जरूरी है कि साधनों की वृद्धि को मूल्य में मापा जाता है और उत्पत्ति की मात्रा की माप उत्पन्न होने वाली वस्तु के रूप में की जाती है। इन नियमों का सम्बन्ध उत्पत्ति की मात्रा से है, उत्पन्न वस्तु के मूल्य से नहीं। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह जरूरी नहीं है कि जिस सीमा से क्रमागत-ह्रास नियम शुरू हो, वहां से उत्पादक को हानि होने लगे जबवा उस सीमा पर आकर वह उस काम में और अधिक रूपरा लगाना बन्द कर देगा।

इन नियमों को अच्छी तरह से समझने के लिए यह जरूरी है कि हम साधनों के आदर्श मिलाव या मिश्रण को जान लें।

### आदर्श मिश्रण

(Ideal Combination)

किसी वस्तु के उत्पादन के लिए एक निश्चित रकम दिये होने पर उत्पत्ति के लावश्यक साधनों को विभिन्न अनुपातों में मिलाया जा सकता है। अधिक धूम को कम पूँजी के साथ या अधिकांश पूँजी को धूम की कम मात्रा में मिलाया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य साधनों को भी विभिन्न मात्राओं में मिला सकते हैं। अलग-अलग मिश्रण के फल भी भिन्न भिन्न होंगे। इन सबमें से एक मिश्रण ऐसा होगा जिससे, खर्च की तुलना में, उत्पत्ति अधिकतम होगी और औसत व्यय कम से कम। इन प्रकार के मिश्रण को "आदर्श मिश्रण" कह सकते हैं। उत्पादक का हित इसी में है कि आवश्यक साधनों को इसी आदर्श अनुपात में मिलावे, और

काम के विस्तार की हर अवस्था में उसे बनाये रखे। यदि वह ऐसा कर सका तो उसका औसत उत्पादन-व्यय कम से कम होगा और खर्च के हिसाब से उत्पत्ति अधिक से अधिक होगी।

लेकिन साधनों को इस प्रकार से मिलाना हमेशा समभव नहीं होता क्योंकि मनचाही मात्रा या इकाई में उत्पत्ति के साधन उपलब्ध नहीं होते। एक सीमा के बाद ये अविभाज्य (indivisible) होते हैं, और छोटी इकाइयों में उनका विभाजन नहीं हो सकता। सम्भव है, आदर्श मिश्रण के लिए हमें किसी साधन की ऐसी इकाई या मात्रा की आवश्यकता हो जो उस इकाई या मात्रा में कम हो, जिसमें वह मिल सकता हो। चूंकि अविभाज्यता के कारण उसके और छोटे भाग नहीं हो सकते, इसलिए हमें आवश्यकता से अधिक बड़ी इकाई में उसे खरीदना पड़ेगा। अन्य साधन इसके हिस्से से कम पड़ जायेंगे। फलस्वरूप साधनों का मिश्रण आदर्श न हो सकेगा। कुल खर्च के हिसाब से उत्पत्ति अधिकतम न होगी और प्रति इकाई उत्पादन-व्यय ज्यादा बढ़ेगा।

आगे चलकर जब हम उस व्यवसाय में और रुपया खर्चाना चाहेंगे तो हमें अन्य साधनों की मात्रा बढ़ाने में खर्च करेंगे। अविभाज्य साधन पर कुछ भी खर्च न किया जायगा क्योंकि वह तो पहले से ही अधिक मात्रा में है। ऐसा करने से अविभाज्य साधन का आधिक्य व फलवृत्त कम हो जायगा और साथ ही अन्य साधनों की कमी भी बुरा होती जायगी। इससे उत्पत्ति में, खर्च के हिसाब से, अधिक वृद्धि होगी और औसत उत्पादन-व्यय घटने लगेगा। यह उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि साधनों का मिश्रण आदर्श न हो लेंगे। जब आदर्श मिश्रण की अवस्था आ लेगी, तब उस समय उत्पत्ति की मात्रा अधिकतम होगी और औसत उत्पादन-व्यय न्यूनतम। यदि आदर्श मिश्रण को टूटने न दिया जाय, उसे बनाये रखा जाय, तो उत्पत्ति उसी अनुपात से बढ़ती रहेगी जिस अनुपात से साधनों को बढ़ाया जायगा। अर्थात् जमागत स्थिर नियम के अनुसार उत्पत्ति

बढ़ती रहेगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि साधनों की पूर्ति पूर्ण रूप से सोचदार हो; ये हर मात्रा में मिल सके अथवा एक दूसरे के स्थान पर पूर्णतः उपयोग में लाये जा सकें। पर वास्तविक जीवन में ऐसी बातें नहीं दिखाई देती। प्रायः कोई साधन एक सीमा तक ही उपलब्ध होता है, उसके बाद नहीं। और यदि मिलता भी है तो पहले से बहुत ऊँचे दाम पर, फल-स्वरूप आदर्श मिश्रण को स्थिर रखने में बड़ी कठिनाई होती है, वह दूढ़ जाता है। इसके कारण उत्पत्ति की वृद्धि सर्व के अनुपात में घटने लगेगी और औद्योगिक उत्पादन-व्यय बढ़ेगा, अर्थात् क्रमागत उत्पत्ति ह्रासनिष्ठ काम करने लगेगा।

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि जितना ही हम आदर्श मिश्रण की ओर चलेंगे, उत्पत्ति में बढ़ती हुई दर में वृद्धि होगी और औसत लागत-स्तर कम होगा अर्थात् क्रमागत वृद्धि नियम लागू होगा। इसके विपरीत जितना हम आदर्श मिश्रण से दूर हटेंगे या हटना पड़ेगा, उत्पत्ति में घटती हुई दर से वृद्धि होगी और प्रति इकाई लागत स्तर बढ़ेगा, अर्थात् उत्पादन में क्रमागत ह्रास नियम लागू होगा। आदर्श मिश्रण की पहुँच से परे और उसे स्थिर रखने पर उत्पत्ति में बराबर के अनुपात में वृद्धि होगी। प्रति इकाई लागत स्तर वैसा ही बना रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय तक उत्पत्ति में क्रमागत समता व स्थिर नियम काम करेगा।

इन बातों को ध्यान में रखत हुए उपर्युक्त नियमों को समझने में बड़ी आसानी होगी। संक्षेप में, अब हम इन नियमों का पृथक्-पृथक् अध्ययन करेंगे।

### क्रमागत उत्पत्ति-ह्रास नियम

(Law of Diminishing Returns)

इस नियम की परिभाषा इन शब्दों में की जा सकती है: "यदि साधनों के मिश्रण में किसी साधन की मात्रा सीमित है, वह उतनी ही रहती है और अन्य साधनों की मात्राएँ बढ़ायी जाती हैं, तो एक सीमा के बाद,

उत्पत्ति घटने हुए अनुपात में बढ़ेगी और प्रति इकाई उत्पादन-व्यय में वृद्धि होगी।" यह नियम तब लागू होता है जबकि उत्पत्ति की वृद्धि का अनुपात साधनों की वृद्धि के अनुपात से कम होता है। जैसे यदि उत्पत्ति के साधनों को २५ प्रतिशत में बढ़ाया जाय और इसके फलस्वरूप उत्पत्ति में २५ प्रतिशत में कम वृद्धि हो, तो हम कहेंगे कि घटती उत्पत्ति का नियम लागू है। इसका यह अर्थ नहीं कि कुल उत्पत्ति घटने लगेगी। उसमें वृद्धि होगी लेकिन घटती हुई दर में। अर्थात् केवल मीमान्न उत्पत्ति में नमन घटी होगी।

यहां यह पूछा जा सकता है कि किन कारणों से यह नियम लागू होने लगता है? साधनों को बढ़ाने में उत्पत्ति में उसी अनुपात में वृद्धि क्यों नहीं होती? इसके कारणों को आसानी से समझा जा सकता है। ऊपर कहा जा चुका है कि उत्पत्ति के साधनों का, किन्हीं दो हुई दशाओं में एक आदर्श मिश्रण होता है। साधनों के इस प्रकार के मिश्रण या मिलाव से उत्पत्ति अधिकतम होगी और औषध लागत-खर्च कम में कम। यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि उत्पत्ति के साधनों की प्राप्ति ऐसी मात्राओं में होती रहे जिससे आदर्श मिश्रण में कोई गड़बड़ी न हो। किन्तु व्यवहार में ऐसी उपलब्धि संभव नहीं होती। कभी-कभी किसी साधन की मात्रा बिल्कुल सीमित हो जाती है। उसकी संकलित हो जाने पर भी उसकी और मात्रा नहीं मिल पाती और यदि मिलती भी है तो उसके लिए पहले की अपेक्षा बहुत अधिक दाम देने पड़ते हैं। उसके स्थान पर किसी अन्य साधन का भी उपयोग सम्भव नहीं होता। इस कारण आदर्श मिश्रण चाल नहीं पाता। वह टूट जाता है। उसके टूटने से उत्पत्ति-ह्रास नियम लागू होने लगता है। कभी-कभी यह भी होता है कि कोई विशेष साधन उस परिमाण में मिल ही नहीं पाता जिस परिमाण में उस साधन की आवश्यकता होती है। यह इसलिए कि प्रत्येक साधन का एक निम्नतम परिमाण होता है। इतने कम परिमाण में उसे खरीदा नहीं जा सकता। अतः, यदि हमें उस साधन की जितनी आवश्यकता है, वह

उसकी अविभाज्य इकाई से कम है, तो हमें एक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। या तो हम उस साधन को न खरीदें या आवश्यकता से अधिक मात्रा में उसे खरीदें। दोनों ही वस्तुओं में आदर्श मिलाव टूट जायगा जिसके फलस्वरूप औसत दाम बढ़ने लगेंगे।

इस प्रकार हम बैसेते हैं कि साधनों के आदर्श मिश्रण के टूटने से उत्पत्ति-ह्रास नियम लागू होने लगता है। अतः, आदर्श मिश्रण के न रहने या टूटने के मुख्य कारण है साधनों की लोचरहित पूर्ति। साधनों की प्रति-मितता, साधनों की शक्तियों की समाप्ति, साधनों की अविभाज्यता तथा साधनों में परस्पर प्रतिस्थापन की कमी। इन्हीं के कारण क्रमागत उत्पत्ति-ह्रास नियम लागू होता है।

### कृषि और उत्पत्ति ह्रास नियम

(Agriculture and Law of Diminishing Returns)

कृषि के सम्बन्ध में यह नियम विशेष महत्त्व रखता है और इसकी महत्वायता से इस नियम को समझने में भी मृषिषा होती है। प्रत्येक किसान यह जानता है कि भूमि के किसी टुकड़े में, चाहे वह कितना ही उपजाऊ क्यों न हो, मनमानी उपज पैदा करना असम्भव है। किसी खेत को जितना ही अधिक जाता जायगा, उतनी ही अधिक उसकी उपज में वृद्धि नहीं होनी रहेगी। शुरु में यह सम्भव है कि जो धर्म और पूँजी की मात्रा उसके जोतने में लगाई जाती है, उसका दुगुना करने पर उस खेत की उपज भी दुगुनी या उससे भी अधिक हो जाय। परन्तु बराबर ऐसा नहीं होता रहेगा। यदि सब ऐसा हुना रहे तो एक एकड़ भूमि में ही हम जानानी से देश या गन्धार भर के लिए अन्न पैदा कर लें। जोतने-बोने की एक सीमा के पश्चात् एक ऐसी अवस्था आ जाती है जबकि किसी खेत में धर्म और पूँजी की मात्रा बढ़ाने से उत्पाति में क्रमशः कम वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए यदि किसी खेत में धर्म और पूँजी की दूसरी इकाई में ३५ मन गेहूँ की उपज होती है, तो तीसरी इकाई में उपज ३५ मन से कम होगी, चौथी इकाई से उपज और भी कम होगी। इस प्रकार प्रत्येक इकाई में जो

उत्पत्ति होगी वह कम होती जायगी। कुल उपज में वृद्धि तो होगी किन्तु कमजोर पड़ती हुई दर से। यही कृषि के सम्बन्ध में क्रमागत उत्पत्ति-ह्रास का नियम है। प्रो० मार्शल ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है खेतिहर भूमि में लगी हुई पूँजी और श्रम की मात्रा बढ़ाने से सामान्य रूप से उपज की मात्रा अनुपात में कम बढ़ती है बशर्ते कि उस बीच में कृषि-कला में कोई उन्नति न हो।\*

इस नियम को एक उदाहरण केवर इस प्रकार समझाया जा सकता है। मान लो एक किसान के पास ५ बीघा जमीन है और वह उस पर श्रम और पूँजी की इकाइयों को बढ़ाता है। नीचे दी हुई तालिका में प्रत्येक बार की कुल उपज दिखाई गई है। तीसरे खाने में एक अधिक व अतिरिक्त इकाई से उपज में जो वृद्धि होती है, वह दिखाई गई है, अर्थात् सीमान्त उपज दिखाई गयी है।

श्रम और पूँजी की इकाईयाँ	कुल उपज	सीमान्त उपज
१	४० मन	४०
२	९० "	५०
३	१५० "	६०
४	२०५ "	५५
५	२५० "	४५
६	२८० "	३०

इस तालिका में यह साफ़ बाहिर है कि कुछ समय तक उपज अनुपात से अधिक बढ़ती है। दूसरी इकाई से उत्पत्ति पहली इकाई से अधिक

\* "An increase in the capital and labour applied in the cultivation of land causes, in general a less than proportionate increase in the amount of produce raised, unless it happens to coincide with an improvement in the art of agriculture".



है। तीसरी इकाई से उत्पत्ति और भी अधिक है। तीन इकाइयों तक सीमान्त उपज बढ़ती जाती है। इसका कारण यह है कि उस समय तक भूमि की शक्तियों का पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। जल की पर्याप्त मात्रा में जोता-बोया नहीं गया है। दूसरे शब्दों में, उत्पत्ति के साधनों का आदर्श मिथुन नहीं हो पाया है। इस अवस्था को पहुँच लेने पर, तीसरी इकाई के बाद सीमान्त उपज क्रमशः कम होने लगती है, और क्रमागत ह्रास नियम का सामूहिक शुरु हो जाता है।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह निचम उपज के मूल्य में सम्मिलित नहीं रहता। इसका सम्बन्ध केवल उपज की मात्रा से है। दूसरे, यह नियम यह नहीं कहता कि उत्पत्ति घटती है। उत्पत्ति तो बढ़ती है, किन्तु वह घटती हुई दर में बढ़ती है।

### नियम की परिमिततायें

(Limitations of the Law)

इस नियम की कुछ बातें हैं जिनके पूरा होना पर ही यह लागू हो सकता है, अन्यथा नहीं। पहली बात तो यह कि खेत पूरी तरह से जोत लिया गया है और कृषि कार्य अच्छे में अच्छे तरीके से होता है। अर्थात् उचित आवश्यक धन और पूँजी की मात्रा लगाई जा चुकी है। यदि भूमि में कम धन और पूँजी का उपयोग किया गया है तो इन साधनों के बढ़ाने से उत्पत्ति में क्रमागत वृद्धि होगी, ह्रास नहीं, क्योंकि धन और पूँजी की मात्रा बढ़ाने से भूमि की उत्पादन-शक्ति का और अधिक उपयोग होने लगता है। इसलिए हम यह मान लेना होगा कि भूमि खूब अच्छी तरह से जोती जा चुकी है। दूसरी बात यह है कि कृषि-सम्बन्धी ज्ञान और तरीकों में कोई परिवर्तन न हो। यदि कृषि के तरीकों में कोई परिवर्तन होता है अथवा वैज्ञानिक अनुसन्धान के द्वारा नया साधन उपयोग में लाये जाने लगते हैं, तो क्रमागत ह्रास नियम लागू न होगा। उसकी क्रिया रक जायगी। इस लिए यह मान लेना जरूरी है कि कृषि-सम्बन्धी ज्ञान और तरीके नहीं रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता।

क्रमागत उत्पत्ति-ह्रास के कारणों को समझ लेने पर यह बताना कठिन नहीं है कि यह नियम खेती के सम्बन्ध में कैसे और क्यों लागू होना है। यह पहले बताया जा चुका है कि अगर कोई साधन ज्यों का त्यों रहे और अन्य साधनों में वृद्धि की जाय तो कुछ समय पश्चात् क्रमागत-ह्रास नियम काम करने लगेगा। खेती में भूमि की मात्रा निश्चित मान ली जाती है। इसलिए जब हमको उत्पत्ति के अन्य साधनों के साथ मिलाया जाता है, जिसकी मात्रा में क्रमशः वृद्धि होती रहती है, तो अन्य बातों के पूर्ववत् रहने पर, कुछ समय पश्चात् क्रमागत-ह्रास का नियम लागू होने लगता है। यदि भूमि के अतिरिक्त और किसी दूसरे साधन का परिमाण एक-सा रहता जाय और बाकी साधनों को बढ़ाया जाय, तो भी यही परिणाम होगा। एक मशीन का उदाहरण ले लो। यदि उसके चलाने के लिए धन की मात्रा में वृद्धि करते जाय या उसमें कोयले की मात्रा को बढ़ाते रहें, तो उसी अनुपात में उत्पत्ति में वृद्धि न होगी। अत्यधिक कोयला या धन-लगाने से मशीन की कार्य-क्षमता गिर जायगी। इसी भाँति यदि धन का परिमाण बढ़ी रहे और भूमि तथा पूँजी की मात्रा में वृद्धि की जाय, तो भी एक सीमा के बाद क्रमागत उत्पत्ति-ह्रास नियम काम करने लगेगा। अस्तु, उत्पत्ति के प्रत्येक साधन के साथ क्रमागत उत्पत्ति-ह्रास नियम लागू होता है।

संक्षेप में, क्रमागत-ह्रास नियम उत्पत्ति के किसी आवश्यक साधन में कमी होने के कारण लागू होता है। यह एक सार्वभौमिक नियम है। प्रत्येक उत्पादन-कार्य में यह नियम लागू होता है, चाहे उस कार्य का सम्बन्ध कृषि से हो अथवा उद्योग-वधो या वातावरण से। इस नियम के लागू होने का कारण ही एक ही है या कारणों से सारे समार के पालन-पोषण के लिए आवश्यक अन्न या अन्य वस्तुएं प्राप्त नहीं की जा सकती। हाँ, यह बात अवश्य है कि अनेक प्रकार के उपायों द्वारा इस नियम को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। नये-नये आविष्कार, सुधार,

प्रतिस्थापन नियम आदि की सहायता में इस नियम की क्रिया को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। लेकिन हमेशा के लिए नहीं। यह प्रवृत्ति सदैव उपस्थित रहती है। जैसे ही अनुसन्धान और मुधार आदि के कार्य बन्द हो जाते हैं, यह प्रवृत्ति फिर नियासील हो जाती है।

### क्रमागत उत्पत्ति-वृद्धि नियम

(Law of Increasing Returns)

इस नियम के अनुसार साधनों की मात्रा बढ़ाने से, एक विशेष सीमा तक, उत्पादन उस अनुपात से अधिक बढ़ता है। यदि किसी व्यवसाय में एक या अधिक साधनों की मात्रा में वृद्धि होने से उत्पत्ति समानुपात से अधिक बढ़ती है और औसत लागत क्रमशः घटती है, तो हम कहेंगे कि उस व्यवसाय में उस समय क्रमागत उत्पत्ति-वृद्धि नियम लागू है।

ऐसा इस कारण होता है कि साधनों की मात्रा बढ़ाने में उत्पत्ति का पैमाना बढ़ जाता है। बड़ी मात्रा की उत्पत्ति से अनेक बाह्य और आन्तरिक बचतें होती हैं जिनसे लाभ उठाया जा सकता है। उत्पादन में और अधिक विशिष्टीकरण लाया जा सकता है जिससे बचत में बहुत वृद्धि होती है। भाष्य ही संगठन में उन्नति और मुधार की अधिक सम्भावना हो जाती है। इससे उत्पादन के साधनों की क्षमता-शक्ति और भी बढ़ जाती है। इन बचतों और साधनों के और अधिक अच्छे तरीके से उपयोग में लाने के फलस्वरूप उत्पादन समानुपात से अधिक बढ़ता है और औसत लागत-खर्च घटता जाता है।

इसी बात को हम इस प्रकार भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसाकि पहले कहा जा चुका है कि साधनों का एक आदर्श मिश्रण होता है जिनमें खर्च के हिसाब से उत्पादन अधिक से अधिक होगा और औसत व्यय कम से कम। लेकिन साधनों की अभिमाज्यता के कारण सम्भव है शुरु में ही आदर्श मिश्रण की प्राप्ति न हो सके। उत्पादक को एक बहुत छोटी मशीन की जरूरत हो सकती है लेकिन सम्भव है वह उसे न मिल सके क्योंकि इतनी छोटी मशीन न बनती हो। मान लो उस प्रकार की मशीन

उसके लिए आवश्यक है । ऐसी दशा में उसे उस प्रकार की बड़ी मशीन ही खरीदनी पड़ेगी । वह मशीन पूरी तरह से काम में न लाई जा सकेगी, क्योंकि अन्य साधन उसके हिमाय से कम पड़ेगे । वह कुछ अंश तक फलतः पड़ी रहेगी । इस कारण जो कुछ खर्च हुआ है, उसके हिमाय से उत्पत्ति अधिकतम न होगी । आगे चलकर जब उस उत्पादक को उस काम में और रखे लगाने होंगे, तो वह उन्हे अन्य साधनों पर खर्च करेगा, मशीन पर नहीं क्योंकि मशीन तो पहले से ही अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में है । अन्य साधनों के बढ़ने से मशीन भी बची हुई शक्तियों का उपयोग होने लगेगा । इससे मशीन की क्षमता-शक्ति बढ़ जायगी, यद्यपि उसके ऊपर अब और खर्च नहीं किया गया है । इसका फल यह होगा कि उत्पत्ति में, खर्च के अनुपात से, अधिक वृद्धि होगी और औसत उत्पादन-व्यय घटेगा । जैसे-जैसे अन्य साधनों पर खर्च होता रहेगा, उनकी कमी दूर होती चली जायगी और मशीन का फलरूपन घटता जाएगा । एक समय वह भी आ जायगा जबकि इस प्रकार की क्रिया में साधनों का आदर्श मिथ्य आ जायगा । इस सीमा पर पहुँच कर क्रमागत उत्पत्ति-वृद्धि नियम का लागू होना बन्द हो जायगा ।

इतना ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि साधनों की अविमात्र्यता, बाह्य और आन्तरिक बचत, साधनों की बची हुई शक्ति के उपयोग आदि के कारण उत्पत्ति में समानुपात से अधिक वृद्धि होती है । यह वृद्धि उस समय तक होती रहती है जब तक कि आदर्श मिथ्य की सीमा नहीं आ जाती । इस सीमा के पहुँच लेने पर बढ़ती उत्पत्ति के नियम की क्रिया सन्द हो जाती है ।

कारखानों में यह नियम विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि उनमें विज्ञान के प्रयोग का, धन-विन्याजन और बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र होता है । अतएव, आदर्श मिथ्य तक पहुँचने की दशा बहुत सम्भावना रहती है । कृषि-कार्य में भूमि का बहुत ऊँचा स्थान होता है । लेकिन इसकी पूर्ति बहुत बेलोबदार होती है । इसकी पूर्ति प्रकृति पर निर्भर

है। इसमें कभी-बेशी लगाना कठिन है। इसलिए उत्पत्ति-ह्रास नियम महा अपेक्षाकृत अधिक और जल्दी लागू होता है। कारखानों में भूमि का उतना महत्वपूर्ण म्यान नहीं रहता। जिन साधनों की कारखानों में विशेष रूप से आवश्यकता पड़ती है, उनकी पूर्ति में अपेक्षाकृत अधिक लोच होती है। इसके अलावा कारखानों में वैज्ञानिक तरीकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो सकता है, जिसमें उत्पत्ति-ह्रास नियम की त्रिया को सफलतापूर्वक रोक जा सकता है। अस्तु, यह कहा जा सकता है कि जिन क्षेत्रों में प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का प्रभाव अधिक होता है, वहाँ क्रमागत उत्पत्ति-वृद्धि नियम अधिक समय तक लागू होता है।

किन्तु इसका यह आशय नहीं कि कारखानों या उद्योग-धन्धों में क्रमागत वृद्धि नियम काम करता है और कृषि-क्षेत्र में क्रमागत ह्रास नियम। इन दोनों के अलग-अलग क्षेत्र नहीं हैं। चाहे कोई भी उद्योग हो, जब तक आदर्श मिश्रण की अवस्था नहीं जाती, तब तक साधनों की मात्रा बढ़ाने से उत्पत्ति समानुपात में अधिक बढ़ेगी। और जब वह अवस्था पार हो जाती है और आदर्श मिश्रण टूट जाता है, तो उत्पत्ति-ह्रास नियम लागू होने लगता है। हा, यह बात अवश्य है कि कृषि की अपेक्षा कारखानों में आदर्श मिश्रण की अवस्था पहुँचने के लिए कहीं अधिक सम्भावनाएँ रहनी हैं। इसलिए क्रमागत उत्पत्ति-ह्रास नियम खेती जैसे कार्यों में जल्दी लागू होने लगता है और कारखानों में अपेक्षाकृत देर में लागू होता है।

### क्रमागत उत्पत्ति-समता व स्थिर नियम

(Law of Constant Returns)

जब किसी वस्तु की उत्पत्ति की मात्रा उसी अनुपात में बढ़ती है, जिस अनुपात से उत्पाद के साधन बढ़ाये जाते हैं अथवा लागत खर्च बढ़ाया जाता है, तो उस समय क्रमागत उत्पत्ति-समता का नियम लागू माना जाता है। इस स्थिति में लागत-खर्च के अनुपात में उत्पत्ति की

मात्रा बराबर रहती है, अर्थात् औसत उत्पादन-व्यय उतना ही बना रहता है ।

साधनों के आदर्श-मिश्रण को बनाये रखने से क्रमागत उत्पत्ति-समता व स्थिर नियम लागू हो सकता है, अर्थात् स्थिर लागत पर उत्पत्ति हो सकती है । यह तभी सम्भव है जबकि उत्पत्ति के सभी साधनों की पूर्ति पूर्णतः लोचदार हो, और अच्छी तरह से वे विभक्त हो सकते हो । लेकिन वास्तविक जीवन में तो उत्पत्ति के साधन पूर्ण रूप से विभाजित हो सकने हैं और न ही उनकी पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है । साथ ही वैज्ञानिक, आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं जिनके कारण आदर्श मिश्रण को स्थिर रखना असम्भव सा हो जाता है । इस कारण वास्तविक जीवन में यह नियम बहुत कम लागू हो पाता है ।

### QUESTIONS

1. Examine and illustrate the law of diminishing returns. What are its limitations ?
2. State and explain the law of diminishing returns. Does it apply to all productive activities or only to agriculture ?
3. Why is it not possible to raise food for the whole world on one acre of land ? Explain clearly.
4. What are the causes of diminishing returns in production ?
5. "While the part which Nature plays in production conforms to the Law of Diminishing Returns, the part which man plays conforms to the Law of Increasing Returns" Comment.
6. State the Law of Increasing Returns ? Why is it specially applicable to manufacturing industries ?
7. What is meant by indivisibility of a factor ? How does it lead to increasing and decreasing returns ?

विनिमय

( EXCHANGE )

## अध्याय २८

### विनिमय

(Exchange)

विनिमय का अर्थ और उसकी आवश्यकता के विषय में पहले लिखा जा चुका है। विनिमय और अर्थशास्त्र के अन्य विभागों के परस्पर सम्बन्ध का भी विवेचन किया जा चुका है। अब विनिमय-विभाग में हम यह अध्ययन करेंगे कि कैसे और क्यों वस्तुओं का विनिमय होता है? कैसे निम्नी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है? किन संस्थाओं द्वारा विनिमय-क्षेत्र में विशेष महायाना मिलती हैं, आदि?

प्राचीन निवासी पूर्णरूप से स्वावलम्बी था। अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ वह स्वयं तैयार करता था। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह किसी दूसरे पर निर्भर न था। उत्पत्ति और उपभोग के बीच सीधा सम्बन्ध था। अतएव उस समय विनिमय की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर अब उस समय जैसी बातें नहीं रही। आधुनिक उत्पत्ति का सारा ढाँचा ही बदल गया है। आजकल धर्म-विभाजन और मशीनों की सहायता से बड़े परिमाण पर उत्पादन होता है। अब हम अपनी आवश्यकता की हर एक वस्तु स्वयं उत्पन्न नहीं करते, और न ऐसा करना अब सम्भव ही है। कारण, हमारी आवश्यकताएँ पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई हैं। वर्तमान उत्पात्ति व्यक्तिगत उपभोग के लिए नहीं, बल्कि मंडी में क्रय-विक्रय के लिए की जाती है। यह निगिप्योकरण का युग है। जो जिस वस्तु के बनाने में निपुण होता है, वह वही वस्तु तैयार करता है, चाहे उसे प्रत्यक्ष रूप से उस वस्तु की आवश्यकता हो या नहीं। बड़े-बड़े



कारखानों में जो कुछ माल तैयार होता है, वह मंडी में क्रय-विक्रय के लिए भेज दिया जाता है। ऐसी दशा में जब तक उत्पन्न की हुई वस्तुओं को उपभोक्ता तक न पहुँचाया जायगा, तब तक उत्पत्ति जबूरी ही रहेगी और उस समय तक उपभोग सम्भव न होगा। फिर भला किस प्रकार भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी? इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि उत्पत्ति और उपभोग को मिलाया जाए। यह कार्य विनियम द्वारा ही सम्भव है। उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए विनियम की क्रिया आवश्यक है। विनियम से उत्पत्ति भी पूर्ति होती है, और उपभोग सम्भव हो जाता है। अस्तु, आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में विनियम का विशेष स्थान है। मानव-शक्ति की उन्नति में विनियम काफ़ी हाथ बटाता है। यही कारण है कि अर्थशास्त्र में विनियम-सम्बन्धी विषय का प्रथम रूप से अध्ययन किया जाता है।

कुछ लोग यह सोचते हैं कि विनियम से एक पक्ष को लाभ होता है और दूसरे पक्ष को हानि। किन्तु यह धारणा नितान्त निर्मूल है। विनियम पूर्णतया स्वच्छानुसार होने में जब तक दोनों पक्ष वालों को लाभ न दिखाई देगा, तब तक विनियम न किया जायगा। विनियम को लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्ष के स्वीय विनियम करने के लिए इच्छुक हों। यह इच्छा उनमें तभी उत्पन्न होगी जब उन्हें यह विश्वास होया कि विनियम की क्रिया में उन्हें लाभ होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेने को, जिसकी उपयोगिता कम है, कमो भी तैयार न होगा। उदाहरण के लिए मान लो कि मोहन के पास एक चाकू है और सोहन के पास एक टार्न और दोनों विनियम करना चाहते हैं। यह तभी सम्भव होगा जबकि मोहन के लिए टार्न की उपयोगिता चाकू से अधिक हो और सोहन के लिए चाकू की उपयोगिता टार्न में अधिक हो। दोनों को यह विश्वास होना चाहिए कि विनियम द्वारा प्राप्त उपयोगिता उससे अधिक होगी जो देनी पड़ेगी। अब जब दोनों पक्ष वालों को विनियम से लाभ दिखाई देगा, तभी क्रय-विक्रय होया, अन्यथा नहीं।

## विनिमय के भेद

(Kinds of Exchange)

विनिमय के दो भेद होते हैं (१) बदला-बदला या वस्तु-विनिमय (barter), और (२) क्रय-विक्रय (purchase and sale)। जब एक वस्तु का विनिमय किसी दूसरी वस्तु से प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है, तो इसे "बदला-बदला" अथवा वस्तु-विनिमय कहते हैं। जब द्रव्य व मुद्रा के बदले में कोई वस्तु ली या दी जाती है तो उस विनिमय को "क्रय-विक्रय" कहते हैं। आबकल अधिकतर क्रय-विक्रय के रूप में ही विनिमय होता है।

(१) बदला-बदला—यदि प्रत्यक्ष रूप में एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दी जाती है, तो इस प्रकार के विनिमय को वस्तु-विनिमय व 'बदला-बदला' कहते हैं। जैसे यदि एक मछ के बदले में एक कुर्मी दी जाती है, तो इस विनिमय को बदला-बदला कहेंगे। इसी तरह यदि दो व्यक्ति अपनी सेवाओं को मोमों तौर से विनिमय करते हैं, तो उसे भी बदला-बदला कहेंगे। वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से बदल-बदल करने में बहुत-सी दिक्कत होती हैं। आवश्यकताओं और विनिमय की जाने वाली वस्तुओं की संख्या में वृद्धि होने से ये दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं, यहां तक कि एक सीमा के बाद इस प्रकार में विनिमय का कार्य कठिन हो नहीं बल्कि असम्भव-सा हो जाता है। आज यदि कोई मनुष्य 'बदला-बदला' की सहायता से अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहें तो वह बुरी तरह से असफल रहेगा। आधुनिक आर्थिक क्षेत्र इनका विस्तृत और जटिल बन गया है कि वस्तु-विनिमय में काम नहीं चल सकता। वस्तु-विनिमय व 'बदला-बदला' की मुख्य कठिनाइया निम्नलिखित हैं —

(क) इस तरह के विनिमय के लिए यह नितांत आवश्यक है कि जो वस्तु एक व्यक्ति चाहता है, वह दूसरे के पास हो और जो वस्तु दूसरा व्यक्ति चाहता है, वह पहले के पास हो। जब तक आवश्यकताओं का इस तरह मिलान न होगा, तब तक वस्तुओं का 'बदला-बदला' न हो

सकेंगा। इस तरह का मिलान बहुत कठिनाई में हो जाता है। मान लो मोहन के पास एक गाय है और वह उसके बदले में एक घोड़ा चाहता है। अब उसे एक ऐसे व्यक्ति की खोज करनी पड़ेगी जिसके पास एक घोड़ा हो और उसे गाय की आवश्यकता भी हो। सम्भव है उसे कोई व्यक्ति मिल जाय जिसके पास घोड़ा हो, पर गाय के साथ वह विनिमय करने को तैयार न हो। ऐसी दशा में विनिमय न हो सकेगा। इससे पता चलता है कि वस्तुओं के सीधे तौर से बदला-बदला करने में कितनी कठिनाई होती है, और साथ ही कितना समय नष्ट होता है।

(ख) कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिनका विभाग और उपविभाग नहीं हो सकता, जैसे गाय, भेड़, गाव, हल, गाड़ी आदि। टुकड़े करने से इनका मूल्य बहुत घट जायगा या नष्ट हो जायगा। यदि सब वस्तुओं का एक समान मूल्य हो, तो इस प्रकार के विनिमय में कोई विशेष कठिनाई न होगी। पर वास्तव में वस्तुओं का मूल्य भिन्न-भिन्न होता है। ऐसी स्थिति में किस तरह भिन्न-भिन्न मूल्य वाली वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से बदला-बदला हो सकता है? वस्तुओं को कई भागों में बांटकर मूल्य बराबर करना हर समय सम्भव नहीं होता। यदि हम चाहे कि गाय, हल, मकान, आदि के टुकड़े करके अन्य-अन्य लोगों को अलग-अलग भाग देकर उनसे उनको वस्तुएँ लें, तो यह सम्भव नहीं है क्योंकि बांटने या तोड़ने से इनकी उपयोगिता नष्ट हो जायगी। तो फिर कैसे बदला-बदला किया जाय?

(ग) तीसरी कठिनाई जो वस्तुओं को सीधे तौर से बदलने में होती है, यह यह है कि भिन्न-भिन्न वस्तुओं का मूल्य जानने और तुलना करने के लिए कोई मापदण्ड या साधन नहीं होता। फिर किस आधार पर वस्तुओं का एक दूसरे से बदला-बदला किया जाय? माप-दण्ड न होने से यह निश्चय करने में बहुत कठिनाई पड़ती है कि वस्तुओं का किस दर से विनिमय हो। इससे फिर और दूसरी दिक्कत आ लगी होगी है।

(२) कय-विकय—‘अदला-बदला’ की कठिनाइयों से बचने के लिए क्रमशः मुद्रा का प्रयोग आरम्भ हुआ । लोगों को यह अनुभव हुआ कि यदि किसी एक विशेष वस्तु को विनिमय का माध्यम बनाया जाय और उसी के द्वारा वस्तुओं के मूल्यों की तुलना आदि की जाय तो विनिमय का कार्य बहुत सरल हो जायगा । अस्तु, भिन्न-भिन्न स्वाग और समय पर अलग-अलग वस्तुएँ इस काम के लिए चुनी गईं । जो वस्तु यह काम करती है, उसे ‘मुद्रा’ या ‘द्रव्य’ कहते हैं ।

मुद्रा के प्रयोग से विनिमय के दो भाग होते हैं (१) क्रय और (२) विक्रय । जब मुद्रा के बदले में वस्तुएँ दी जाती हैं तो उसे ‘विक्रय’ कहते हैं, और जब वस्तुओं के बदले में मुद्रा दी जाती है तो उसे ‘क्रय’ कहते हैं । विनिमय के इस तरह के दो विभाग हो जाने से विनिमय के कार्यों में बहुत सुवीता हो गया है । इसके द्वारा वस्तु-विनिमय की अनेक असुविधाएँ से मनुष्य बच जाता है । आसकल विनिमय का लगभग सभी काम मुद्रा के माध्यम द्वारा ही होता है ।

### विनिमय का महत्त्व

(Importance of Exchange)

आधुनिक जीवन में विनिमय का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है । जीवन का कोई भी ऐसा अंग या पहलू नहीं मिलेगा पर विनिमय का प्रभाव न पड़ता हो । विनिमय का हमारे जीवन से इतना निकट सम्बन्ध हो गया है कि यदि विनिमय-क्रिया बन्द हो जाय, तो सभ्य जीवन की बहुत-कुछ अच्छाईयाँ और सुविधाएँ दूर हो जायेंगी । उस दशा में मनुष्य सम्यक्ता और उत्थिति के पथ से बहुत नीचे गिर जायगा ।

यद्यपि विनिमय स्वतः अन्त व सद्यः नहीं है, फिर भी हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है । विनिमय की गहायता में सम्यक्ता को सर्वोत्तम उपाय से उपयोग में लाना सम्भव हो जाता है । इससे वस्तुओं की उपयोगिता बढ़ जाती है जिससे प्रत्येक

प्राणी को लाभ पहुँचता है। विनिमय के न होने पर यही नहीं कि बहुत-सी वस्तुएँ बेकार पड़ी रह जायेंगी बल्कि उनका उत्पादन ही नहीं होगा। बिना विनिमय के पाकिस्तान अपने जूट का, इंग्लैण्ड अपने कोयला का, अथवा आस्ट्रेलिया अपने ऊन का बिम्ब हथ में उपयोग कर सकेगा। फलस्वरूप उत्पत्ति कम हो जायगी और लोगों का जीवन-स्तर गिर जायगा।

विनिमय की सह्यता से मनुष्य और प्रकृति की उत्पादक शक्तियों को यथेष्ट रूप में उपयोग में लाना सम्भव हो जाता है जो बिना विनिमय के या तो व्यर्थ पड़ी रह जायेगी, या उतनी अच्छी तरह से काम में न लाई जा सकेगी। विनिमय के न होने पर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएँ स्वयं तैयार करनी पड़गी, चाहे वह उनके उत्पादन करने में कुशल हो या नहीं। फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र की विविध शक्तियों का अच्छा उपयोग न हो सकेगा। विनिमय की उपस्थिति में उत्पादन व्यक्तिगत आवश्यकतानुसार न किया जाकर योग्यतानुसार किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति या राष्ट्र अपनी शक्तियों तथा कुशलताओं के अनुसार उत्पादन-कार्य में लग जाता है, और फिर विनिमय के द्वारा अन्य वस्तुओं को प्राप्त करता है। इससे उत्पादन-शक्ति और कुशलता बहुत बढ़ जाती है। उत्पादन अच्छा और अधिक परिमाण में होने लगता है। इस प्रकार विनिमय द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों को लाभ होता है।

विनिमय के कारण उत्पादन में वृद्धि और उन्नति होती है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ अधिक परिमाण में और सस्ती पैदा होने लगती हैं। इससे मूल्य का विस्तार बढ़ जाता है और फलस्वरूप उत्पत्ति बढ़े पैमाने पर होने लगती है। ऐसा हमारे कारण अम-विभाजन और मनीनों के उपश्रम में उन्नति होती है जिनके विभिन्न लाभों में हम भली-भाँति परिचित हैं। ये वर्तमान अर्थ-व्यवस्था के विशेष अंग हैं। इनके बिना वर्तमान अर्थ-व्यवस्था टिक नहीं सक्ती, यह स्पष्टतापूर्वक गिर पड़ेगी। अतः, विनिमय पर ही वर्तमान अर्थ-व्यवस्था अवलम्बित है। जैसे-जैसे समाज उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही वैसे विनिमय का महत्त्व

## विनिमय

बढ़ता जाता है। आजकल तो विनिमय के बिना ~~कोई भी काम नहीं~~ चल सकता। उत्पादन-शक्ति तथा साधनों की प्रगतिशील उत्तरोत्तर वृद्धि का एकमात्र कारण विनिमय ही है।

विनिमय के सब काम मंडी में होते हैं। इस कारण अगले अध्याय में हम मंडी का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।

## QUESTIONS

1. What is 'barter'? Examine the main difficulties of barter
2. Explain how the use of money helps in the removal of the difficulties of barter
3. Bring out fully the importance of exchange

## अध्याय २९

### मंडी

(Market)

आम बोलचाल में हम उस स्थान को मंडी कहते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ बेची और खरीदी जाती हैं। किन्तु अर्थशास्त्र में किसी खास स्थान को मंडी नहीं कहते। मंडी का वास्तविक अर्थ यह है कि किसी वस्तु के क्र्रेताओं और विक्रेताओं में प्रभावपूर्ण प्रतियोगिता हो जिससे वस्तु के मूल्य में समानता की प्रवृत्ति हो। यदि एक वस्तु किसी विशेष स्थान पर बेची जाती है, तो वह स्थान उस वस्तु के लिए मंडी है, यदि उसका क्रय-विक्रय वहाँ नहीं होता, तो उस स्थान को उस वस्तु की मंडी न मानेंगे। यद्यपि एक ही स्थान पर बहुत-सी वस्तुएँ बिकती हैं फिर भी हर एक वस्तु की अपनी-अपनी मंडी होती है। जितनी वस्तुएँ एक स्थान पर बिकती हैं, उतनी ही मंडियाँ उस स्थान में मानी जायगी। अस्तु, आर्थिक मंडी की यह एक विशेषता है कि उसका सम्बन्ध एक विशेष वस्तु के साथ होता है, स्थान के साथ नहीं।

मंडी की दूसरी विशेषता यह है कि वस्तु के बेचने और खरीदने वालों में परस्पर प्रतियोगिता हो। प्रतियोगिता आर्थिक मंडी का मुख्य चिह्न है। पर प्रतियोगिता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि बेचने और खरीदने वाले एक खास स्थान पर हों। वे भिन्न-भिन्न स्थानों में रहते हुए भी रेल, डाक, तार, रेडियो आदि की सहायता से आपस में अच्छी तरह से प्रतियोगिता कर सकते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की कि दोनों पक्ष वालों में प्रभावपूर्ण प्रतियोगिता हो। यह प्रतियोगिता

तभी सम्भन है जबकि बेचने और खरीदने वालों की मर्दी की परिस्थितियों का पूरा-पूरा ज्ञान हो ।

प्रतियोगिता के प्रभाव में किसी वस्तु का मूल्य समस्त मर्दी में एक समय में एक ही होगा । यदि किसी एक वस्तु के बेचने और खरीदने वालों में पूर्ण प्रतियोगिता है और उन्हें इस बात की स्थिति है कि जब और जहाँ चाहे बेचें और खरीदें, तो उस दशा में उस वस्तु का मूल्य मर्दी के प्रत्येक भाग में एक ही होगा । मान लो कोई विक्रेता एक वस्तु को औरो से कम मूल्य पर बेचने को तैयार है । उस दशा में सब ग्राहक उसकी ओर खिंच आयेगे । बाकी सब बेचने वाले उस वस्तु को न बेच सकेंगे क्योंकि उनके पास कोई भी खरीदार न आया । यदि वे बेचना चाहते हैं, तो उन्हें भी वही मूल्य स्वीकार करना पड़ेगा । इसी तरह यदि कोई ग्राहक अन्य ग्राहकों की अपेक्षा अधिक मूल्य देने को तैयार है, तो सभी विक्रेता अपने माल को उसी के हाथ बेचना चाहेंगे । अन्य ग्राहकों को वह वस्तु न मिल सकगी, जब तक कि वे भी उतना ही मूल्य देने को तैयार न हो जाय । यदि मर्दी में प्रतियोगिता है, तो कोई भी खरीदार किसी वस्तु के लिए उस मूल्य से अधिक देने को तैयार न होगा जितना कि अन्य खरीदारों को देना पड़ता है । और न कोई विक्रेता उस मूल्य से कम पर अपनी वस्तु को बेचने के लिए तैयार होगा जितना कि अन्य विक्रेताओं को उस वस्तु के बदले में मिलता है । इस तरह प्रतियोगिता के प्रभाव से किसी एक वस्तु का मूल्य मर्दी के भिन्न-भिन्न भागों में, यातायात के लायत खर्च को छोड़कर, एक समान होगा । एक विशेष वस्तु का किसी सास समय में एक ही मूल्य का होना आर्थिक मर्दी की तीसरी मुख्य विशेषता है ।

उपर्युक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए मर्दी की परिभाषा इन शब्दों में दी जा सकती है — अर्थशास्त्र में मर्दी से अभिप्राय एक विशेष वस्तु और उसके बेचने और खरीदने वालों से है जिनके परस्पर प्रति-



योगिता के प्रभाव में वस्तु के मूल्य में शीघ्रता और सुगमता से समानता की प्रवृत्ति होती है ।

### मंडी का वर्गीकरण

(Classification of Markets)

स्थान और समय के अनुसार मंडी को कई विभेद किये जाते हैं जो दस प्रकार हैं (अ) स्थान की दृष्टि से मंडी को तीन भेद होते हैं—स्थानीय मंडी, राष्ट्रीय मंडी, और अन्तर्राष्ट्रीय मंडी । यदि किसी वस्तु के खरीदने और बेचने वाले एक खास स्थान, गांव या नगर में ही पाये जाते हैं अर्थात् प्रतियोगिता एक खास स्थान तक ही सीमित है तो उस वस्तु की मंडी को स्थानीय मंडी कहेंगे । साधारणतः सजनी और शीघ्र लपट होने वाली वस्तुओं की मंडी स्थानीय होती है । उनकी मंडी एक विशेष स्थान तक ही सीमित रहती है । यदि किसी वस्तु के खरीदने और बेचने वाले केवल एक ही देश में ही फैले हुए हैं अर्थात् प्रतियोगिता देशव्यापी है तो उस वस्तु की मंडी को राष्ट्रीय मंडी कहेंगे । इसी तरह यदि एक वस्तु के खरीदने-बेचने वाले समस्त मर में फैले हुए हैं अर्थात् प्रतियोगिता समस्त-व्यापी है तो वह मंडी अन्तर्राष्ट्रीय मंडी मानी जायगी । सोना, चांदी, गेहूँ, कपास आदि वस्तुओं की मंडी विश्व-व्यापक है । इसके खरीदने-बेचने वाले सारे समार में फैले हुए हैं ।

(आ) समय के अनुसार मंडी को मुख्यतः दो भेद होते हैं । एक अल्प-कालीन मंडी ( short period market ) और दूसरी दीर्घ-कालीन मंडी ( long period market ) । एक दिन, एक हफ्ता या थोड़े समय तक चलने वाले बाजार से अल्प-कालीन मंडी का बोध होता है । समय कम होने के कारण पूर्ति में आवश्यकतानुसार परिवर्तन नहीं लाया जा सकता । इसलिए अल्पकाल में मंडी का भाव अधिकतर मांग पर निर्भर रहता है । पर्याप्त समय तक चलने वाली मंडी को दीर्घ-कालीन मंडी कहते हैं । दीर्घकाल में वस्तु की पूर्ति आपसानी से बढ़ाई-घटाई

जा सकती है। इसलिए वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन-व्यय के बराबर होगा।

### मंडी का विस्तार

(Extent of Market)

मंडी के विस्तार से यह आशय है कि किसी वस्तु के बेचने और खरीदने वालों में मत्सार के कितने भाग में प्रतियोगिता होती है। यदि प्रतियोगिता का क्षेत्र बड़ा है, तो मंडी का विस्तार भी विस्तृत होगा, और यदि प्रतियोगिता का क्षेत्र सीमित है तो मंडी परिमित अथवा छोटी होगी। कुछ वस्तुओं की मंडी बहुत बड़ी होती है, जैसे सोना, चादी, व्यापारिक साख-मन आदि वस्तुओं की मंडी और कुछ की छोटी, जैसे दूध, फल, सब्जी आदि चीजों की मंडी। मंडी के विस्तार का व्यापक अथवा समुचित होना कई बातों पर निर्भर होता है। इनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं। इनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि क्यों कुछ वस्तुओं की मंडी सारारब्बापी होती है और कुछ की मंडी छोटी व स्थानीय होती है।

(१) मंडी का क्षेत्र बहुत-कुछ वस्तु की माग पर निर्भर करता है। सार्वदेशिक माग वाली वस्तुओं की मंडी बहुत बड़ी होती है। जितनी अधिक किसी वस्तु की माग होगी, उतनी ही बड़ी और विस्तृत उस वस्तु की मंडी होगी। सोना, चादी, गेहूँ आदि वस्तुओं की मंडियों का क्षेत्र सारारब्बापी है क्योंकि सभी देशों में इन वस्तुओं की माग होती है।

(२) किसी वस्तु की मंडी का क्षेत्र उस बात पर भी निर्भर होता है कि वह वस्तु कैसी है—शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है, या स्थायी? शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की दूर-दूर के स्थानों पर नहीं भेजा जा सकता। इस कारण इन वस्तुओं की मंडियाँ केवल स्थानीय मंडियाँ ही होती हैं, जैसे दूध, फल आदि की मंडियाँ। इसके विपरीत जो वस्तु जितनी ही टिकाऊ होगी, उतनी ही विस्तृत उसकी मंडी होगी।

(३) बड़ी मंडी के लिए यह भी आवश्यक है कि वस्तु का मुख्य

उसके वजन की अपेक्षा अधिक हो। जिन वस्तुओं का घनत्व या वजन कम होता है और मूल्य अधिक होता है, उनकी मडिया विस्तृत होती है, जैसे सोना, हीरा, सिल्क आदि की मडिया। यह इसलिए कि इनके भेजने बंढोने में खर्च कम लगता है और अडचन भी कम पड़ती है। सामान्यतः ईट-पत्थर की मडिया बड़ी नहीं होती। कारण, मूल्य के हिस्से से इनका वजन बहुत अधिक होता है, और फलस्वरूप उनकी दुलाई का खर्च उनकी कीमत से अधिक बैठ जाता है। अस्तु, ये बहुत दूर तक नहीं भेजे जा सकते। अतः इनका बाजार सीमित होता है।

(४) जो वस्तुएं सुगमता से पहिचानी जा सकती हैं अथवा जिनके नमूने, नम्बर और दर्जे आसानी से तैयार किये जा सकते हैं, उनकी मडियों का विस्तार अधिक होता है, जैसे चाय, गेहूँ, चीनी, ईई आदि। इसका कारण यह है कि खरीदार माल से दूर रहकर भी सीदा कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु के सही नमूने नहीं बन सकते तो खरीदार को स्वयं माल के स्थान पर आना पड़गा। फलस्वरूप मंडी का क्षेत्र सीमित हो जायगा।

(५) वस्तु की पूर्ति की प्रकृति पर भी मंडी का क्षेत्र निर्भर होता है। यदि पूर्ति सीमित या अनिश्चित है, तो मंडी अवश्य छोटी होगी। विस्तृत मंडी के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु की पूर्ति पर्याप्त और निश्चित हो। जो वस्तु जितनी ही अधिक मात्रा में तैयार की जा सकेंगी, उसकी मंडी उतनी ही विस्तृत होगी।

(६) किसी वस्तु की मंडी का क्षेत्र इस बात पर भी निर्भर होता है कि उसके बदले में प्रयोग हो सकने वाली वस्तुओं की मर्यादा कितनी है। यदि एक वस्तु के स्थान पर बहुत सी अन्य वस्तुएं प्रयोग में लाई जा सकती हैं, तो उस वस्तु की मंडी का क्षेत्र कम होगा। उदाहरण मिल के कपड़ों की मंडी कम विस्तृत है, क्योंकि विदेशी मिलों में तैयार हुए मल्ले कपड़े इनके साथ प्रतिस्पर्धिता करने हैं। इसी प्रकार यदि काफी का चलन न हो, तो चाय की मंडी और भी विस्तृत हो सकती है।

(७) वस्तुएँ एक-दूसरे की प्रतियोगी ही नहीं होती, बल्कि पूरक भी होती हैं। यदि किसी वस्तु की पूरक वस्तुएँ उपलब्ध हों, तो उसकी मंडी विस्तृत होगी, अर्थात् मंडी का क्षेत्र बढ़ेगा। पेट्रोल के मिलने पर मोटर की मंडी का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जायगा।

इन सबके अतिरिक्त मंडी का विस्तार कई और बातों में भी प्रभावित होता है, जैसे सरकार की आर्थिक नीति, यातायात के साधन, द्रव्य और वस्तु-व्यवस्था, धर्म-विभाजन, देश में शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था इत्यादि। यदि यातायात के साधन अच्छे और सस्ते हों, द्रव्य और वस्तु की उचित व्यवस्था है, देश अथवा मसालों में शान्ति है, तो मंडी विस्तृत होगी। इन बातों के न होने पर मंडी का विस्तार बहुत कम होगा। सरकार अपनी आर्थिक नीति से किसी वस्तु की मंडी के क्षेत्र को घटा-बढ़ा सकती है। सरकारी सहायता और प्रोत्साहन मिलने से मंडी विस्तृत हो जाती है, और उसके अभाव में मंडी का क्षेत्र घट जाता है।

इन बातों से पता चलता है कि क्यों किसी वस्तु की मंडी बड़ी या छोटी होती है। सोना, चांदी, मसालों-प्रसिद्ध कम्पनियों के हिस्से आदि वस्तुओं की मंडियाँ मसालोंवाली हैं। इसका कारण यह है कि ये उपयुक्त गतियों को बहुत अच्छी तरह पूरा करती हैं। इनकी मांग सब देशों में होती है। ये बहुत टिकाऊ होती हैं। इनको आगानी से और कम खर्च में दूर-दूर तक भेजा जा सकता है और राख ही ये जल्दी पहचानी जा सकती हैं। इसके विपरीत दूध, फल आदि वस्तुएँ हैं जो जल्दी तप्ट हो जाने वाली होने के कारण बहुत दूर नहीं भेजी जा सकती। साधारण हट-वस्तुओं का बज्र उनके मूल्य के हिसाब से बहुत होता है। इसलिए इनको भी बहुत दूर तक नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि इनकी दुलाई का खर्च इनकी कीमत से अधिक पड़ जाता है। सास-किस्म, बनावट और नाग के कपड़े सास-खाम मनुष्यों के लिए तैयार हो सकते हैं, सबके लिए नहीं। अर्थात् इनकी मांग अधिक नहीं हो सकती। इन सब कारणों से, यह तरह की वस्तुओं की

मंडी छोटी व सीमित होती है। वर्तमान समय में रेल मंडी के विस्तृत होने की ओर है। रेल, तार, टेलीफोन आदि से मंडी का विस्तार बहुत बढ़ गया है।

मंडी किसी देश की व्यापारिक तथा आर्थिक उन्नति की माप है। जो देश जितना ही अधिक उन्नत और प्रगतिशील होगा, उसकी मंडी उन्नती ही अधिक विस्तृत और सुसंगठित होगी।

मूल्य निर्धारण मंडी की मुख्य समस्या है। वहाँ विनिमय के सब काम हात हैं और इस बात का निर्णय होता है कि अमुक वस्तु किस मात्रा में अन्य वस्तुओं के बदल में दी जाय। अर्थात् मंडी में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है और उनका क्रय विक्रय होता है। अतः वगले अध्यायों में अब हम मूल्य-सम्बन्धी बातों पर विचार करेंगे।

## QUESTIONS

- 1 What is meant by the term 'market' in Economics? How does it differ from its popular concept?
- 2 Examine fully the factors which determine the extent of market
- 3 Explain why the markets for gold, silver and shares are wider than markets for such commodities as bricks vegetables, cows, etc

## अध्याय ३०

### पूर्ति

(Supply)

मूल्य निर्धारण की समस्या पर विचार करने से पूर्व, पूर्ति सम्बन्धी बातों की जानकारी आवश्यक है। किमा वस्तु का मूल्य उसका माग और पूर्ति पर निर्भर होता है। उपभोग विभाग में माग का अध्ययन किया जा चुका है। अब हम इस अध्याय में पूर्ति का अध्ययन करेंगे।

किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ वस्तु को कुल मात्रा के उस भाग में है जो एक विशेष मूल्य पर एक समय में मंडी में बचन के लिए लाई जाती है। जैसे यदि किसी दिन मंडी में आठ बान सर पर व्यापारी लोग १०० मन आलू बचन को तैयार है तो यह कहा जायगा कि उस दिन उस कीमत पर आलू की पूर्ति १०० मन है। इस सम्बन्ध में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक तो कुल माल (stock) और पूर्ति को ध्यान में रखना चाहिए। पूर्ति और कुल माल में यह अन्तर है कि माल वस्तु को कुल सरवा या मात्रा को कहते हैं और पूर्ति कुल माल का केवल एक भाग है जिसे व्यापारी किसी समय एक विशेष मूल्य पर बचन के लिए तैयार है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के माल और पूर्ति में कोई अन्तर नहीं होता क्योंकि ऐसी वस्तुओं को पर्याप्त समय तक संचय नहीं किया जा सकता। किन्तु स्थायी या टिकाऊ वस्तुओं की पूर्ति और कुल माल में काफी अन्तर हो सकता है। मूलानुसार कुल माल का भिन्न भिन्न भाग अलग अलग समय में बचन के लिए निकाला जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि माग की तरह पूर्ति का भी बिना मूल्य के कोई अर्थ नहीं होता। किसी समय में एक वस्तु का पूर्ति कितनी होगा यह

मूल्य पर निर्भर है। भिन्न-भिन्न मूल्य पर वस्तु की पूर्ति भिन्न-भिन्न होती है। मूल्य में वृद्धि होने से पूर्ति बढ़ती है, और मूल्य के घटने से पूर्ति घटती है। अर्थात् मूल्य और पूर्ति में सीधा सम्बन्ध है। ये एक साथ उभी दिशा में घटते-बढ़ते हैं। इस प्रवृत्ति को पूर्ति का नियम (Law of supply) कहते हैं। पूर्ति का नियम यह नहीं बतलाता कि मूल्य के घटने या बढ़ने पर पूर्ति किम अनुपात से घटेगी या बढ़ेगी। वह केवल इतना ही बतलाता है कि मूल्य के बढ़ने से पूर्ति में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है और मूल्य के घट जाने पर पूर्ति में घटने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात् किन्नी वस्तु की कीमत जंगे बढ़ती या घटती है, उन्नी प्रकार उन्की पूर्ति में भी बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

### पूर्ति-सूची और रेखा

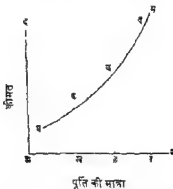
(Supply Schedule and Curve)

जिग तरह माग-सूची तैयार की जाती है, ठेक उसी तरह पूर्ति-सूची भी बनाई जा सकती है। यदि एक सूची तयार की जाय, जिसमें एक ओर ती वस्तु के भिन्न-भिन्न मूल्य दिखे हों और दूसरी ओर उन मूल्यों के सामने वस्तु की भिन्न-भिन्न मात्राएँ, जो बिकने के लिए आती हैं, दर्शाई जाय, तो उसे पूर्ति-सूची (supply schedule) कहेंगे। उदाहरणार्थ चाय की पूर्ति-सूची नीचे दी जाती है —

चाय का प्रति पौड मूल्य	चाय की पूर्ति
६ रुपया	१००० पौड
५ " "	८०० "
४ " "	६०० "
३ " "	४०० "
२ " "	१०० "

इन सूची में इन बात का बोध होना है कि चाय की कीमत में वृद्धि होने से चाय की पूर्ति बढ़ती है और कीमत कम होने से पूर्ति घटती है।

इस बात का कारण स्पष्ट है । जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो ज़नेब नये उत्पादक उस ओर खिंच आते हैं और पुराने उत्पादक अधिक मात्रा में वस्तु को तैयार करने लग जाते हैं । फलस्वरूप पूर्ति बढ़ जाती है । दूसरी ओर जब कीमत घट जाती है, तो कुछ उत्पादक, जिनका उत्पादन-व्यय अधिक होता है, काम को छोड़ देने में या उत्पादन की मात्रा कम कर देते हैं । अतः पूर्ति में कीमत बढ़ने की आशा से व्यापारी लोग कम माल बेचने को तैयार रहते हैं । इसलिए कीमत के घटने से पूर्ति भी कम हो जाती है । पूर्ति मूची को एक रेखा द्वारा भी दिखाया जा सकता है ।



उपरोक्त चित्र में अ ब पर वस्तु की वे मात्राएँ दिखाई गई हैं जो विभिन्न कीमतों पर बिक्री के लिए हैं और अ द पर उस वस्तु की विभिन्न कीमतें दिखाई गई हैं । 'म म' रेखा पूर्ति-रेखा (supply curve) है, इस रेखा से पता चलता है कि जैसे-जैसे मूल्य बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती जाती है । जब मूल्य 'क ख' है तो पूर्ति की मात्रा 'अ ख' के बराबर है, जब मूल्य 'क ख' में गड़ कर 'ग छ' हो जाता है, तो उस समय पूर्ति की मात्रा 'अ छ' हो जाती है । इस तरह मूल्य के बढ़ जाने से पूर्ति में



वृद्धि होती है। साधारणतः पूर्ति की रेखा का झुकाव ऊपर की ओर होता है।

### पूर्ति की लोच

(Elasticity of Supply)

मूल्य में परिवर्तन होने के साथ-साथ पूर्ति में भी घट-बढ़ होती रहती है। पूर्ति में इस तरह के परिवर्तन होने के गुण अथवा शक्ति को अर्थशास्त्र में 'पूर्ति की लोच' कहते हैं। पूर्ति की लोच का आशय उस दर में है जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति, मूल्य में परिवर्तन होने के कारण, घटती-बढ़ती है। साधारणतः मूल्य के बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है, और मूल्य के घटने में पूर्ति घटती है। जब मूल्य में थोड़ा-सा परिवर्तन होने में किसी वस्तु की पूर्ति में बहुत परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु की पूर्ति लोचदार मानी जाती है। इसके विपरीत यदि मूल्य में थोड़े-से परिवर्तन का किसी वस्तु की पूर्ति पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता अथवा बहुत थोड़ा पड़ता है तो उस वस्तु की पूर्ति बेलोचदार कही जायगी।

सब वस्तुओं की पूर्ति की लोच एक जैसे नहीं होती और न सब परिस्थितियों में किसी एक वस्तु की पूर्ति की लोच एक समान ही रहती है। कुछ वस्तुओं की पूर्ति की लोच अधिक होती है, और कुछ की कम। ऐसा क्यों है? इसके कई कारण हैं। पूर्ति की लोच पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है। इनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं —

(१) किसी वस्तु की पूर्ति की लोच पर इस बात का विशेष प्रभाव पड़ता है कि वह वस्तु शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है, या स्थायी। दूध, फल, मछली आदि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की पूर्ति बेलोचदार अथवा कम लोचदार होती है क्योंकि उन्हें गचप करके काफी समय तक नहीं रखा जा सकता। यदि किसी कारण से इन वस्तुओं की कीमत घट या बढ़ जाती है, तो इनकी पूर्ति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया जा सकता। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की पूर्ति और स्टॉक या कुल मांग में विशेष अन्तर नहीं होता। किन्तु टिकाऊ या स्थायी वस्तुओं के माप

ऐसी बात नहीं है। आवश्यकतानुसार इन वस्तुओं की पूर्ति काफी घटाई-बढ़ाई जा सकती है। मूल्य के बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा में वृद्धि लाई जा सकती है और मूल्य में कमी होने पर पूर्ति की मात्रा घटाई जा सकती है। इस कारण स्थायी वस्तुओं की पूर्ति अधिक लोचदार होती है, और अस्थायी वस्तुओं की पूर्ति कम लोचदार।

(२) किसी वस्तु के उत्पादन-अपग का उसकी पूर्ति की लोच पर बहुत अंतर पड़ता है। यदि किसी वस्तु का उत्पादन में सीमान्त लागत-खर्च (marginal cost of production) पहले की अपेक्षा बढ़ता जाता है, तो उस वस्तु की पूर्ति बहुत कम लोचदार अथवा बेलोच होगी। क्योंकि मध्यम है कीमत में थोड़ी वृद्धि होने पर भी पूर्ति की मात्रा में अधिक वृद्धि लाना लाभप्रद नहीं होगा। इसके विपरीत यदि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ सीमान्त लागत-खर्च कम होता जाता है, तो पूर्ति बहुत लोचदार होगी। मान लो किसी वस्तु के उत्पादन में सीमान्त लागत-खर्च कम होता जाता है। यदि एसी वस्तु की कीमत थोड़ी-सी और जाय तो उत्पादक उत्पात्ति की मात्रा बढ़ा देने क्योंकि ऐसा करने से उन्हें लाभ होगा। संक्षेप में, जब सीमान्त लागत-खर्च तेजी से बढ़ता है, तब पूर्ति में लोच कम होगी, जब सीमान्त-खर्च में धीरे-धीरे वृद्धि होती है, तब लोच अधिक होगी, और यदि सीमान्त लागत-खर्च कम-से-कम घटता जाता है, तो उस समय पूर्ति अधिक लोचदार होगी।

(३) उत्पादन के ढंग (system of production) से भी पूर्ति की लोच प्रभावित होगी है। यदि किसी वस्तु के उत्पादन का ढंग बहुत जटिल है, अथवा उसके उत्पादन में बहुत विशिष्ट साधनों का प्रयोग किया जाना है, तो उस वस्तु की पूर्ति कम लोचदार होगी। कारण, ऐसी दशा में आसानी से पूर्ति में मूलदानुसार परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। दूसरी ओर, यदि उत्पादन-ढंग सीधा और सरल है जिसमें स्थायी पूँजी की बहुत कम आवश्यकता होती है, तो मूल्य को घटने-बढ़ने

पर पूर्ति में इच्छानुसार परिवर्तन लाया जा सकता है। फलस्वरूप पूर्ति लोचदार होगी।

(४) विक्रेता के भावी मूल्य के अनुमान पर भी पूर्ति को लोच निर्भर करती है। यदि भविष्य में कीमत में और अधिक वृद्धि होने की आशा है, तो विक्रेता वर्तमान समय में उस वस्तु की कम मात्रा बेचने को तैयार होंगे। कीमत में वृद्धि होने पर भी वे पूर्ति को अधिक न बढ़ायेंगे। अस्तु, पूर्ति में कम लोच होगी। इसके विपरीत यदि भविष्य में कीमत के गिरने का डर है अथवा कीमत में बहुत कम वृद्धि की आशा है तो पूर्ति अपेक्षा-कृत बहुत लोचदार होगी।

### उत्पादन-व्यय

(Cost of Production)

किसी वस्तु के उत्पादन में अनेक साधनों की सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। उत्पत्तिकर्ता को ये सेवाएँ मुफ्त में ही नहीं मिल जाती। उसे उन सेवाओं के बदले में कुछ मूल्य देना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में कुछ न कुछ लागत लगती है। कुछ वस्तुओं के उत्पादन में बहुत लागत लगती है, और कुछ में कम। किसी वस्तु के तैयार करने में जो कुछ खर्च होता है, उसे उत्पादन-व्यय या लागत-खर्च कहते हैं।

उत्पादन-व्यय के मुख्यतः दो अर्थ हो सकते हैं (१) वास्तविक उत्पादन-व्यय (real cost of production) और (२) द्राव्यिक-उत्पादन-व्यय (money cost of production)। वास्तविक उत्पादन-व्यय का आशय उन प्रयत्नों तथा त्यागों से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में आवश्यक होते हैं। मान लो किसी वस्तु की उत्पत्ति में एक दिन लगता है और कुछ पूँजी की आवश्यकता होती है, तो एक दिन में जो कुछ परिश्रम करना पड़ेगा और आवश्यक पूँजी संचय करने में जो वर्तमान मुद्रा और तृप्ति का त्याग करना पड़ेगा, वह वस्तु का वास्तविक उत्पादन-व्यय माना जायगा। दूसरी ओर जो द्रव्य भिन्न-भिन्न उत्पत्ति के साधनों को किसी वस्तु के उत्पादन करने में दिया जाता है, उसे 'द्राव्यिक लागत' कहते

है। अर्थात् जो कुछ किमी वस्तु के उत्पादन में खर्च होता है, यदि उसे मुद्रा या द्रव्य में अंकित किया जाय तो वह 'द्राव्यिक-उत्पादन-व्यय' कहलायेगा। व्यक्तिगत दृष्टि से उत्पादन-व्यय का आशय द्राव्यिक उत्पादन-व्यय से ही होता है। वास्तविक लागत का ठीक-ठीक अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है।

### प्रमुख और पूरक लागत

(Prime and Supplementary Costs)

किमी वस्तु के कुल उत्पादन-व्यय को दो भागों में बांटा जा सकता है (१) प्रमुख लागत (prime cost) और (२) पूरक लागत (supplementary cost)। 'प्रमुख लागत' से अभिप्राय उत्पादन-व्यय के उन अंशों या खर्चों से है जो उत्पत्ति की धारा के साथ घटते-बढ़ते हैं, जैसे कच्चे माल का मूल्य, माधारेण धमिकों की मजदूरी आदि। जैसे-जैसे उत्पत्ति की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे प्रमुख लागत में वृद्धि होती जाती है। उत्पत्ति की मात्रा को घटाने में प्रमुख लागत कम हो जाती है। यदि किमी कारण से कुछ समय के लिए उत्पादन-कार्य रूकगिर कर दिया जाय, तो उस बीच में प्रमुख लागत सम्बन्धी खर्च कुछ भी नहीं होगा। इसके विपरीत उत्पादन-व्यय के उन स्थायी खर्चों को जो उत्पत्ति की मात्रा के साथ एक मीमा तक घटते-बढ़ते नहीं 'पूरक लागत' कहते हैं, जैसे कारखाने का किराया, मशीनों का खर्च, प्रदूषणको का वेतन, उधार ली हुई पूँजी पर ब्याज, बीमा-सम्बन्धी खर्च आदि। कारखाने में चाहे पूरे समय तक काम हो या थोड़े समय तक, पूरक लागत में कोई विशेष अन्तर न पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान लो कि किमी कारण से एक सप्ताह के लिए कारखाना बन्द हो जाता है। उस समय तक कारखाने के मालिक को कच्चे माल, बालक-शक्ति आदि पर कुछ भी खर्च न करना पड़ेगा क्योंकि काम बन्द है। दूसरे शब्दों में, प्रमुख लागत कुछ न होगी। किन्तु मालिक को कारखाने का किराया, मासिक वेतन पाने वाले मजदूरों

और प्रबन्धकों का बेतन आदि तो हर हालत में देना ही पड़ेगा, चाहे काम चालू हो या नहीं। अर्थात् पूरक लागत में थोड़े समय के लिए काम के बन्द हो जाने के कारण कमी न होगी। यह खर्च सभी बन्द होगा जब उस काम को हमेशा के लिए बिलकुल बन्द कर दिया जाय।

प्रमुख और पूरक लागत के भेद का अपना एक महत्व है। लम्बे समय अथवा दीर्घकाल में किसी वस्तु की कीमत इतनी होनी चाहिए जिससे उसके उत्पादन का कुल खर्च निकल आये। ऐसा न होने पर उसका उत्पादन बन्द कर दिया जायगा। कोई भी उत्पादक घाटा सहकर उत्पादन नहीं करता रहेगा। इसलिए लम्बे समय की दृष्टि से प्रमुख और पूरक लागत के भेद का कोई खास महत्व नहीं रहता। परन्तु अल्पकाल की दृष्टि में इस भेद का विशेष महत्व है। वैसे तो उत्पादक हर समय यही चाहेंगा कि कीमत ऐसी हो जिससे उसका कुल खर्च निकल सके। पर सम्भव है किमी मास समय में माग घट जाने के कारण कीमत कुल लागत में कम हो जाय। ऐसी परिस्थिति में उत्पादक क्या करेगा? उनके लिए दो रास्ते होंगे। या तो वे अपना कारखाना बन्द कर दें अथवा कुल लागत में कम कीमत पर बेचने को तैयार हो। पहला रास्ता कठिन है। एक बार नाम बन्द कर देने पर उसे फिर चलाना कठिन हो जाता है। और हो सकता है माग की कमी भी अस्थायी हो। ऐसी परिस्थिति में कोई भी अनुभवी उत्पादक अपना कारखाना बन्द न करेगा। साधारणतः वह काम बन्द करने के बजाय कुछ समय के लिए कुल लागत में कम कीमत पर माल बेचने को तैयार हो जायगा। लेकिन प्रश्न यह है कि वह कितनी कम कीमत तक बेचने के लिए तैयार हो सकेगा? यह हम पहले कह चुके हैं कि पूरक लागत-सम्बन्धी खर्च स्थायी होता है, बचा हुआ होता है। उत्पादक उत्पत्ति की मात्रा घटाकर पूरक लागत को फिलहाल कम नहीं कर सकते। वह उतनी ही बनी रहेगी, चाहे उत्पादन-कार्य थोड़े समय के लिए स्थगित हो क्यों न कर दिया जाय। वे केवल प्रमुख लागत को ही

अल्पकाल में घटा सकते हैं। इसलिए कीमत को कम से-कम-इतना होना पड़ेगा जिससे प्रमुख लागत-सम्बन्धी खर्च निकल सके। ऐसा न होने पर उत्पादक उत्पात्ति को और अधिक कम करके प्रमुख लागत को घटाने का प्रयत्न करेंगे। यह प्रयत्न उस समय तक चलना रहेगा जब तक कि कीमत प्रमुख लागत के बराबर नहीं हो जायगी। अस्तु, अल्पकाल में प्रमुख लागत की न्यूनतम सीमा है। इसके नीचे कीमत नहीं जा सकती। वेमै साधारणतः अल्प-काल में मूल्य प्रमुख लागत से अधिक ही रहना है।

मक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि अल्प-काल में यदि कीमत इतनी भी हो कि प्रमुख लागत निकल सके तो भी आगे लागत मिटाने की आशा से उत्पादक उत्पादन-कार्य चलाते रहेंगे। पूरक लागत आगे की विक्री में पूरी की जा सकती है। किन्तु आगे चलकर दीर्घकाल में कीमत को कुल लागत के बराबर होना पड़ेगा वरना उत्पादन-कार्य बन्द हो जायगा। दीर्घकाल में कोई भी खर्च बचा हुआ नहीं होता। उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए दीर्घकाल में पूरक और प्रमुख लागत में कोई भेद या अन्तर नहीं रह जाता। यह भेद तो अल्पकाल में ही बित्या जा सकता है। वही इस भेद का जर्ज और महत्व है।

### सीमान्त और औसत उत्पादन-व्यय

(Marginal and Average Cost of Production)

किसी वस्तु की एक और इकाई के उत्पादन करने से जो कुल लागत में वृद्धि होती है, उसको 'सीमान्त उत्पादन-व्यय' (marginal cost of production) कहते हैं। मान लो, जब किसी वस्तु की १० इकाइया तैयार की जाती हैं तो कुल लागत खर्च २०० रुपया है और ११ इकाइया तैयार करने से कुल खर्च २३१ रु० हो जाता है। इस उदाहरण के अनुसार सीमान्त उत्पादन-व्यय  $(२३१-२००) = ३१$  रु० है। एक और इकाई के उत्पादन से कुल लागत में ३१ रु० की वृद्धि हुई। इसलिए ३१ रु० उस वस्तु का सीमान्त उत्पादन-व्यय माना जायगा।

प्रति इकाई उत्पादन-व्यय को "औसत उत्पादन-व्यय" (average cost of production) कहते हैं। कुल लागत को उत्पाद की हुई इकाइयों की संख्या से भाग देने से औसत उत्पादन-व्यय मायूम किया जा सकता है। उपर्युक्त उदाहरण में जब १० इकाइयाँ उत्पन्न की जाती हैं, तो औसत उत्पादन-व्यय  $२००/१० = २०$  रु० है, और जब ११ इकाइयाँ तैयार की जाती हैं तो औसत उत्पादन-व्यय  $२२१/११ = २१$  रु० है।

उत्पादन की मात्रा बढ़ाने से औसत उत्पादन व्यय घट-बढ़ सकता है और बराबर भी रह सकता है। यदि उत्पादन की मात्रा बढ़ाने में औसत उत्पादन व्यय में कोई अन्तर नहीं पड़ता, तो सीमान्त उत्पादन व्यय औसत उत्पादन-व्यय के बराबर होगा। यदि उत्पादन में वृद्धि करने से औसत लागत घटती है, तो सीमान्त लागत औसत लागत से कम होगी और यदि औसत लागत बढ़ती है, तो सीमान्त लागत उससे अधिक होगी।

मूल्य-निर्धारण में सीमान्त लागत का विशेष महत्त्व है। माधारणतः किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन के सीमान्त खर्च के बराबर होने की प्रवृत्ति दिखाता है। जब किसी कारण से मुख्य सीमान्त लागत से कम या अधिक हो जाता है तो प्रतिपयोगितापूर्ण स्थिति में अनेक आर्थिक शक्तियाँ काम करने लगती हैं, जिनके प्रभाव से मूल्य फिर सीमान्त उत्पादन-व्यय के बराबर हो जाता है। पूर्ण प्रतिपयोगिता की परिस्थिति में मुख्य सीमान्त लागत और औसत लागत दोनों के बराबर होना है। एकाधिकार की परिस्थिति में मुख्य सीमान्त उत्पादन-व्यय से माधारणतः अधिक होता है।

### QUESTIONS

1. What is meant by 'supply'? How is it related to price?
2. What is the difference between the supply and stock of a commodity? Why does the supply of

a commodity ordinarily increase with a rise in price and decrease with a fall in price ?

- 3 Examine the main factors which influence elasticity of supply
- 4 Explain real and money costs of production
- 5 What are prime and supplementary costs ? Show why the price must cover prime costs in any case ?
- 6 What is meant by marginal and average cost of production ? Show the relationship between the two



## अध्याय ३१

### मूल्य-निर्धारण की समस्या

#### (Problem of Price Determination)

बाजार में नरह-नरह की वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता है। उन सब का मूल्य एक समान नहीं होता। कुछ वस्तुओं का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक होता है, और कुछ का कम। इतना ही नहीं, आज एक वस्तु का जो मूल्य है, वह भविष्य में उतना ही नहीं बना रहता। उसमें प्रायः उतार-चढ़ाव होता रहता है। इस सब में इस प्रकार के कई प्रश्नों का उत्तर देना स्वाभाविक है, जैसे, कैसे किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है? क्यों एक वस्तु का मूल्य अन्य वस्तुओं के मूल्य की अपेक्षा कम या अधिक होता है? क्यों मूल्य में अक्सर परिवर्तन होता रहता है? इस अध्याय में इन्हीं प्रश्नों पर विचार किया जायगा।

इसके पूर्व कि किसी वस्तु में कुछ मूल्य हो, यह आवश्यक है कि उसमें उपयोगिता और परिमितता के दोनों गुण विद्यमान हों। यदि किसी वस्तु में उपयोगिता नहीं है अथवा वह अपरिमित मात्रा में है, तो मूल्य देकर उसे खरीदने के लिए कोई भी तैयार न होगा। बहुत-सी वस्तुएँ ऐसी हैं, जिनमें उपयोगिता की तो कोई कमी नहीं होती जैसे हवा, सूर्य-किरण आदि, किन्तु साधारणतः इतना कुछ भी मूल्य नहीं होता, क्योंकि इनमें परिमितता का गुण नहीं होता। वस्तु में मूल्य होने के लिए यह आवश्यक है कि वह वस्तु बाजार में बिकने के लिए लाई जाय और लोग उसे खरीदने के लिए तैयार हों। बाजार में बिक्री के लिए कोई वस्तु तभी लाई जायेगी जबकि उसकी मांग परिमित होगी और

यह तभी खरीदी जायगी जबकि उसमें उपयोगिता होगी। अस्तु, मूल्य के लिए वस्तु में उपयोगिता और परिमितता दोनों ही विशेषताएँ होनी चाहिए। अब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि मूल्य कैसे निर्धारित होता है।

मूल रूप में वस्तु का मूल्य उसकी माग और पूर्ति पर निर्भर होता है। जिस बिन्दु पर माग और पूर्ति की समता होती है, वही पर मूल्य निर्धारित होता है। यह किस तरह होता है? कैसे माग और पूर्ति की समता द्वारा मूल्य निर्धारित होता है? इसे भली प्रणाली समझने के लिए संक्षेप में माग और पूर्ति सम्बन्धी कुछ बातों का विश्लेषण करना आवश्यक है।

### माग (सीमान्त उपयोगिता)

Demand (Marginal Utility)

माग की परिभाषा, माग के नियम तथा माग की लोच आदि बातों का विवेचन पहले किया जा चुका है। यहाँ पर केवल एक बात पर ही विचार करना पर्याप्त होगा। यह यह है कि क्यों किसी वस्तु की माग होती है? खरीदार उसके बदले में कथो एक विशेष भत्ता देने के लिए तैयार हो जाता है? इसका उत्तर आसानी से दिया जा सकता है। किसी वस्तु की माग इस कारण होती है कि उसमें उपयोगिता है। यदि किसी वस्तु में आवश्यकता-पूरक शक्ति अर्थात् उपयोगिता नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति उस वस्तु की चाह न करेगा और न उसके बदले में कुछ मूल्य देने के लिए तैयार होगा। जो कुछ मूल्य खरीदार किसी वस्तु के बदले में देने के लिए तैयार होता है, उसे माग-कीमत (demand price) कहते हैं। यह आवश्यकता की तेजी पर निर्भर होगी है। जितनी अधिक प्रबल आवश्यकता की तृप्ति कोई वस्तु करेगी, उतना ही अधिक मूल्य एक व्यक्ति उस वस्तु के लिए देने को तैयार होगा। दूसरे शब्दों में, उपयोगिता माग का आधार है। यह पहले कहा जा चुका है कि जैसे-जैसे कोई वस्तु अधिक मात्रा में खरीदी या उपयोग की जाती है, वैसे-वैसे उसकी सीमान्त उपयोगिता घटती जायेगी है। इस कारण आगे जाने वाली

इकादशों का माप-मूल्य भी घटता जायगा। अस्तु, जो मूल्य कोई खरीदार किसी वस्तु के लिए देने को तैयार होगा, वह उसकी सीमात उपयोगिता के बराबर होगा।

यदि मूल्य सीमान्त उपयोगिता में अधिक है, तो वह व्यक्ति उस वस्तु को न खरीदेगा। जैसे तो वह कम से कम मूल्य पर खरीदना चाहेगा, पर अधिक में अधिक मूल्य, जो वह देने के लिए तैयार हो सकता है, वह उस वस्तु की सीमात-उपयोगिता के बराबर होगा। संक्षेप में, माप की ओर से सीमात उपयोगिता बाजार-भाव की अधिकतम सीमा है। किसी वस्तु का मूल्य इस सीमा से अधिक नहीं हो सकता।

किन्तु इसका यह आशय नहीं कि केवल उपयोगिता द्वारा ही मूल्य निर्धारित होता है। किसी वस्तु की उपयोगिता भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिये पृथक् पृथक् होती है। अतः यदि केवल उपयोगिता पर ही मूल्य का निर्धारण निर्भर होता तो उस दशा में उसका मूल्य भी हर एक के लिए अलग-अलग होता। किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता। दूसरे यदि केवल उपयोगिता ही मूल्य का आधार है, तो जिन वस्तुओं में उपयोगिता अधिक है, उनका मूल्य अधिक होना चाहिए, और जिनमें उपयोगिता कम है, उनका मूल्य कम होना चाहिए। लाख-सामग्री, जल, हवा आदि की उपयोगिता मोटर, हीरे आदि से कहीं अधिक है। फिर भी मोटर व हीरे की कीमत इन सबसे बहुत ज्यादा है। इससे यह पता चलता है कि मूल्य उपयोगिता के अनिश्चित और किसी बात में भी प्रभावित होगा है। मूल्य के लिए केवल उपयोगिता का होना ही पर्याप्त नहीं है।

### पूर्ति (सीमात उत्पादन-व्यय)

Supply (Marginal Cost of Production)

पिछले अध्याय में पूर्ति-सम्बन्धी बातों का संक्षेप रूप से अध्ययन किया जा चुका है। वहाँ हम कह चुके हैं कि जब तक किसी वस्तु की मात्रा सीमित नहीं होगी, तब तक उसकी पूर्ति का कोई प्रश्न नहीं उठेगा।

यदि कोई वस्तु अपरिमित मात्रा में है तो बेचने के लिए उसे बाजार में ले जाने का कौन कष्ट उठायेगा ? अस्तु, बाजार में बिक्री के लिए उन्हीं वस्तुओं को ले जाया जाता है जिनकी मात्रा परिमित होती है। ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में कुछ न कुछ लागत अवश्य लगती है। इसीलिए विक्रेता इन वस्तुओं के बदले में कुछ मूल्य मांगते हैं। यदि मूल्य लागत-खर्च व उत्पादन-व्यय से कम है, तो विक्रेता उस वस्तु को न बेचेगा। कम से कम मूल्य, जो वे किसी वस्तु की एक इकाई के लिए स्वीकार करने को तैयार हो सकते हैं, वह उनके सीमांत उत्पादन-व्यय के बराबर होगा। यदि मूल्य सीमांत उत्पादन-व्यय से कम है, तो वे उस इकाई का उत्पादन करना बन्द कर देंगे। यह सम्भव है कि किसी दिन मूल्य उत्पादन-व्यय से कम हो जाय, पर यह कभी हमेशा के लिए बनी नहीं रह सकती। जिस मूल्य पर विक्रेता एक वस्तु को बेचने के लिए तैयार रहते हैं, उसे पूर्ति मूल्य (supply price) कहते हैं। यह उत्पादन-व्यय पर निर्भर होता है। मूल्य की यह न्यूनतम सीमा है। आमतौर से मूल्य इस सीमा के नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि उस दशा में विक्रेता को हानि होगी और वे बेचने के लिए तैयार न होंगे।

किन्तु इनका यह आशय नहीं कि मूल्य केवल उत्पादन-व्यय से ही निर्धारित होता है। चाहे जितना अधिक किसी वस्तु का उत्पादन-व्यय क्यों न हो, किन्तु जब तक उसमें उपयोगिता न होगी, तब तक उसका कुछ भी मूल्य न होगा। कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिनके उत्पादन-व्यय का उनके मूल्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता जैसे प्रसिद्ध पुराने चित्रकारों की तस्वीरें, कई वर्षों की तैयार की हुई जराब आदि। इसके अलावा मूल्य में अन्तर परिवर्तन होता रहता है, पर उत्पादन समाप्त हो जाने पर लागत-खर्च में कोई खास परिवर्तन नहीं होता, वह उतना ही रहता है। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल उत्पादन-व्यय से ही मूल्य निर्धारण की समस्या हल नहीं की जा सकती।

## माग और पूर्ति की समता

(Equilibrium of Demand and Supply)

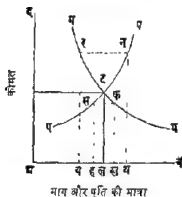
उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि माग और पूर्ति दोनों के द्वारा मूल्य निर्धारित होता है। प्रोफेसर मार्शल ने मूल्य के निर्धारित होने की उपमा कपड़े और कैंची से दी है। कपड़ा काटने के लिए कैंची के दोनों फलों की आवश्यकता होती है। केवल एक फल की सहायता से कपड़ा नहीं काटा जा सकता। माग और पूर्ति कैंची के दोनों फलों के समान हैं। जिस तरह कपड़ा काटने के लिए दोनों फलों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी तरह मूल्य-निर्धारण के लिए माग और पूर्ति दोनों आवश्यक हैं। यह ठीक है कि कैंची के दोनों फलों को खिंचाए सदा एक-सी नहीं होती। कभी एक में अधिक काम लिया जाता है, और कभी दूसरे में। उदाहरणार्थ आम तौर से एक साधारण व्यक्ति दोनों फलों को साथ-साथ चलाता है, खिंचा नीचे वाले फल को चलाती है और दबो नीचे के फल को मज पर जमाकर ऊपर वाले फल को चलाते हैं। यही बात माग और पूर्ति के साथ भी लागू है। कभी माग का प्रभाव अधिक होता है और कभी पूर्ति का, पर दोनों का होना आवश्यक है।

माग मूल्य की अधिकतम सीमा निश्चित करती है और पूर्ति मूल्य की न्यूनतम सीमा। इन्हीं दोनों सीमाओं के बीच मूल्य निर्धारित होता है। यदि माग का प्रभाव अधिक है, तो मूल्य न्यूनतम सीमा के निकट होगा; यदि पूर्ति का अधिक प्रभाव है, तो मूल्य अधिकतम सीमा के निकट होगा। अन्ततः किसी समय मूल्य उस स्थान पर निर्धारित होगा, जहाँ पर माग और पूर्ति दोनों बराबर हैं, अर्थात् दोनों में सामंजस्य होगा। विनिमय उसी भाव पर होता है जिस पर माग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं। उदाहरणार्थ नीचे भाव की माग और पूर्ति की सूची दी जाती है। इसकी सहायता से यह और स्पष्ट हो जायगा कि किस तरह माग और पूर्ति के साम्य-बिन्दु पर मूल्य निर्धारित होगा।

मूल्य प्रति पौंड	भाग की मात्रा	पूर्ति की मात्रा
६ ६०	१०० पौंड	११०० पौंड
५ "	२०० "	१००० "
४ "	४०० "	८०० "
३ "	६०० "	६०० "
२ "	९०० "	३०० "
१ "	१२०० "	५० "

\* इस सूची में ३ ६० प्रति पौंड की दर पर चाय की भाग और पूर्ति दोनों बराबर हैं। अतएव चाय का मूल्य इसी स्थान पर निर्धारित होगा। यह समझना कठिन नहीं कि चाय का मूल्य यहाँ ३ ६० प्रति पौंड होगा। उदाहरण के लिए मान लो कि चाय का प्रति पौंड मूल्य ४ ६० है। इस मूल्य पर भाग की मात्रा केवल ४०० पौंड है जबकि पूर्ति की मात्रा ८०० पौंड है। पूर्ति की मात्रा भाग की मात्रा से कहीं अधिक है। ऐसी दशा में बेचने वालों में प्रतिबोधिता होगी जिसके फलस्वरूप मूल्य गिरने लगगा। मन लो मूल्य गिरकर २ ६० हो जाता है। इस मूल्य पर भाग की मात्रा पूर्ति की मात्रा की अपेक्षा कहीं अधिक है। भाग अधिक होने के कारण मूल्य बढ़ेगा। इस तरह हम देखते हैं कि जब मूल्य ३ ६० से अधिक या कम है, तो कई आर्थिक शक्तियाँ काम करने लगती हैं जिससे मूल्य फिर ३ ६० हो जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि और किसी स्थान पर भाग और पूर्ति के बीच सामंजस्य नहीं है। इसलिए मूल्य ३ ६० ही होगा।

भाग और पूर्ति के परस्पर प्रभाव से किसी वस्तु की कीमत किस स्थान पर निश्चित होगी, यह रेखा चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है। इसने मूल्य निर्धारण के विषय को समझने में और भी आसानी होगी।



ऊपर दिए हुए चित्र में 'म' माग-रेखा है और 'प' पूर्ति की रेखा है। ये दोनों रेखाएँ एक दूसरे को 'ट' बिन्दु पर काटती हैं। ऐसी दशा में वस्तु की कीमत 'ट' होगी। इस कीमत पर माग की मात्रा 'अ' है और पूर्ति की मात्रा भी इतनी ही है। दोनों बराबर-बराबर हैं, जितनी की माग है, उतनी ही की पूर्ति है। अस्तु 'ट' सामान्य या साम्य-कीमत (equilibrium price) है। इसी कीमत पर वस्तु का वय-विक्रय होगा। अन्य किसी कीमत पर माग और पूर्ति बराबर नहीं है, इसलिए और किसी स्थान पर कीमत निश्चिन्त न होगी। थोड़ी देर के लिए मान लो कि कीमत 'र' है, जो साम्य-कीमत (ट) से अधिक है। इस कीमत पर माग कुल 'अ' है और पूर्ति 'अ'। इस स्थान पर पूर्ति की मात्रा माग की मात्रा से कहीं अधिक है। इसका परिणाम यह होगा कि बेचने वालों में परस्पर प्रतियोगिता होगी, जिसके फलस्वरूप कीमत नीचे गिरेगी। अर्थात् 'र' कीमत स्थिर न रह सकेगी। मान लो कीमत 'ट' से कम है, अर्थात् 'स' है। इस कीमत पर माग की मात्रा (अ) पूर्ति की मात्रा (अ) से कहीं अधिक है। ऐसा

होने पर खरीदने वालों में प्रतियोगिता होगी और फलस्वरूप कीमत ऊपर चढ़ने लगेगी। अस्तु, 'ट ल' कीमत ही साम्य कीमत है। यही माग और पूर्ति का साम्यस्थ है। इसलिए वस्तु की कीमत यही पर निर्धारित होगी।

अस्तु, अब यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी माग और पूर्ति पर निर्भर रहता है। यदि माग पूर्ति से अधिक है तो मूल्य बढ़ेगा और यदि माग कम है और पूर्ति अधिक है तो मूल्य गिरेगा। इसी नियम के अनुसार मशी में वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है।

ऊपर कहा जा चुका है कि माग और पूर्ति दोनों के द्वारा मूल्य निर्धारित होता है। दोनों का होना परमावश्यक है। पर यह सम्भव है कि किसी एक परिस्थिति में माग का प्रभाव अधिक हो और दूसरी परिस्थिति में पूर्ति का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक हो। यह बात समय या काल पर निर्भर होती है। अल्पकाल (short period) में माग का प्रभाव अधिक होता है। इसका एक कारण है। अल्पकाल में पूर्ति की मात्रा एक तरह से निश्चित ही रहती है। उसको घटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह तो तभी सम्भव हो सकता है, जबकि परिवर्तन करने के लिए उत्पादकों तथा बेचने वालों को बाकी समय मिले। अर्थात् अल्पकाल में पूर्ति की मात्रा में बहुत कम छोच होती है। लेकिन माग के परिमाण में घट-बढ़ हो सकती है। इस कारण अल्पकालीन समय पर माग का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि माग कम हो जाय तो दाम गिर जायगा, क्योंकि बेचने वालों की आपस में प्रतियोगिता होगी। वे पूर्ति में इच्छानुसार कामी नहीं ला सकते, इसलिए उन्हें कम ग्राहकों के बीच अपनी वस्तु को बेचना पड़ेगा। फलस्वरूप कीमत गिरेगी। सम्भव है उत्पादन-व्यय के नीचे भी कीमत चली जाय। ऐसा होना उन वस्तुओं के साथ विशेष रूप से सम्भव है जो सीधे नष्ट होने वाली है, क्योंकि बेचने वाले उनको जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। टिकाऊ वस्तुओं को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है।



इसलिए माग कम होने पर इन वस्तुओं की कीमतें बहुत न घिरेंगी। इसी प्रकार यदि अल्पकाल में माग बढ़ जाय तो कीमत भी ऊपर चढ़ जायगी। माग बढ़ जाने पर खरीदारी में आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ जायगी, क्योंकि पूर्ति की मात्रा अल्पकाल में निर्दिष्ट होती है, वह आसानी से बढ़ाई नहीं जा सकती। ऐसी दशा में माग चढ़ जाएगा। वस्तु, अल्पकाल में कीमत अधिकतर माग पर निर्भर होती है। पूर्ति का कीमत पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता।

किन्तु दीर्घकाल ( long period ) में पूर्ति की मात्रा घटाई-बढ़ाई जा सकती है। यदि माग स्थायी रूप से कम हो जाती है तो पूर्ति कम कर दी जायगी। उस वस्तु के उत्पादन में लगे हुए साधन अन्य व्यवसायों में धीरे-धीरे चले जायेंगे। और यदि माग बढ़ जाती है, तो उसके अनुसार पूर्ति भी बढ़ा दी जायगी। अन्य व्यवसायों में लगे हुए साधनों को निकाल कर अथवा खाली साधनों को उस वस्तु के उत्पादन में लगा दिया जायगा। फलस्वरूप उत्पत्ति और पूर्ति की मात्रा बढ़ जायगी। वस्तु, दीर्घकाल में माग के अनुसार ही पूर्ति होगी। ऐसी दशा में वस्तु का मुख्य उत्पादन-व्यय पर अधिक निर्भर होगा। यदि मुख्य उत्पादन-व्यय में कम होगा, तो उत्पन्न करने वालों को घाटा होगा और वे उत्पादन कम कर देंगे। माग पूर्ववत् रहने पर खरीदने वालों में आपस में प्रतियोगिता बढ़ेगी। इसके फलस्वरूप कीमत ऊपर चढ़ने लगेगी। दूसरी ओर, यदि कीमत उत्पादन-व्यय से अधिक होगी, तो उत्पादकों को अधिक लाभ होगा। इसका परिणाम यह होगा कि लोग अधिक परिमाण में उत्पत्ति करने लगेंगे। माग के पूर्ववत् रहने पर, उत्पादकों के बीच प्रतियोगिता बढ़ जायगी, जिसके प्रभाव से कीमत नीचे गिरने लगेगी। वस्तु, दीर्घकाल में कीमत उत्पादन-व्यय के बराबर होगी। मूल्य पर पूर्ति का प्रभाव दीर्घकाल में अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है।

इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि जितना ही कम समय होगा, उतना ही मूल्य पर माग का प्रभाव अधिक होगा और जितना ही समय

अधिक या कमवा होगा, मूल्य पर पूर्ति का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। फलस्वरूप कीमत अल्पकाल में उत्पादन-व्यय से कम या अधिक हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में उत्पादन-व्यय के बराबर होगी।

अल्प-कालीन मूल्य को बाजार-मूल्य कहा जाता है और दीर्घ-कालीन मूल्य को स्वाभाविक व सामान्य मूल्य कहा जाता है। अब हम इनका विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।

### बाजार तथा सामान्य मूल्य (Market and Normal Price)

बाजार-मूल्य से अभिप्राय यह है कि किसी वस्तु का किसी समय पर क्या मूल्य है। जिस मूल्य पर मंडी में किसी वस्तु का त्रय-विक्रय होता है, उसे उस वस्तु का 'बाजार-मूल्य' (market price) कहते हैं। यह माग और पूर्ति के प्रतिदिन के साम्य अथवा सामंजस्य का फल है। जब किसी कारण से साम्य टूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाता है, तो बाजार-मूल्य भी, जो साम्य पर निर्भर होता है, बदल जाता है। माग काफी अनिश्चित है। उसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। किन्तु पूर्ति में इसकी जल्दी परिवर्तन काना कठिन है। इस कारण माग और पूर्ति का साम्य-बिन्दु सदा एक स्थान पर नहीं रहता, वह बदलता रहता है। इसके फलस्वरूप बाजार-मूल्य में भी बराबर उतार-चढ़ाव होता रहता है। किसी वस्तु का बाजार-मूल्य आज कुछ है, तो कल कुछ—यहाँ तक कि कभी-कभी एक ही दिन में बाजार-मूल्य कई बार चढ़ता-निरता है। इसका मुख्य कारण माग की घटबढ़ है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है अल्पकाल में पूर्ति की मात्रा माग के अनुसार घटाई-वढ़ाई नहीं जा सकती। इसलिए यह कहा जा सकता है कि बाजार-भाव के निर्धारण में माग का प्रभाव पूर्ति के प्रभाव की अपेक्षा अधिक होता है।

बाजार-मूल्य में बराबर परिवर्तन होता रहता है किन्तु यह एक केन्द्रीय स्तर या सतह के चारों ओर ही होता है। यदि किसी तात्काल

या नदी में पत्थर फँका जाय, तो कुछ देर के लिए जल में हलचल मच जाती है। जल अपनी बमली सतह से हट जाता है, किन्तु हमेशा के लिए नहीं। हलचल का प्रभाव ज्यों ही दूर हो जाता है, जल अपनी वास्तविक सतह पर आ पहुँचता है। ठीक यही दशा बाजार-मूल्य की है। माग और पूर्ति में घटबढ़ होने के कारण बाजार-मूल्य अपनी वास्तविक सतह से हट जाता है। कभी उस सतह के ऊपर हो जाता है, तो कभी नीचे। पर और किसी स्थान पर वह निश्चित रूप से टिकता नहीं। बार-बार अपनी वास्तविक सतह पर लौट आने की उमंगे प्रवृत्ति होती है। वह मूल्य, जिसके चारों ओर बाजार-मूल्य घूमता रहता है, उसे 'स्वाभाविक' व सामान्य मूल्य (normal price) कहते हैं।

स्वाभाविक मूल्य उत्पादन-व्यय के बराबर होता है। यह सम्भव है कि अल्पकाल में बाजार-मूल्य उत्पादन-व्यय से कम हो या अधिक। किन्तु ऐसी परिस्थिति सदा नहीं बनी रह सकती। उदाहरणवत् मान लो कि किसी वस्तु का बाजार-मूल्य उत्पादन-व्यय से अधिक है। उस दशा में उत्पत्तिकर्ता को बहुत लाभ होगा। इसका परिणाम यह होगा कि और लोग भी उस वस्तु को तैयार करने लगेंगे। फलस्वरूप अन्ततः पूर्ति बढ़ जायगी और बाजार-मूल्य गिरने लगेगा। इसी प्रकार यदि बाजार-मूल्य उत्पादन-व्यय से कम हुआ तो नुकसान होने के कारण कुछ उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन बन्द कर देंगे और कुछ उत्पादन को मात्रा घटा देंगे जिससे पूर्ति घट जायगी। पूर्ति घट जाने के कारण मूल्य बढ़ जायगा। अतएव दीर्घ-कालीन दृष्टि से मूल्य उत्पादन-व्यय के बराबर होगा। स्वाभाविक व सामान्य मूल्य की दीर्घकालीन मूल्य भी कहते हैं। इस मूल्य के निर्धारित होने में उत्पादन-व्यय का प्रभाव माग के प्रभाव की अपेक्षा अधिक होता है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि बाजार-मूल्य और स्वाभाविक मूल्य के निर्धारण में कोई रैखान्तिक अन्तर है। दोनों माग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होते हैं। अन्तर केवल इतना ही

है कि बाजार-मूल्य माग से अधिक प्रभावित होता है और स्वाभाविक-मूल्य पूर्ण अथवा उत्पादन-व्यय से ।

### QUESTIONS

- 1 Show how the price of a commodity is determined  
Explain it with the help of a diagram
- 2 Construct imaginary demand and supply schedules for a commodity and explain how the price will be determined
- 3 "Price is determined by the equilibrium of supply and demand" Explain
- 4 What do you mean by 'market price' and 'normal price' of a commodity? How are they determined?

## प्रतियोगिता और मूल्य

(Competition and Price)

मूल्य-निर्धारण पर इस बात का विशेष प्रभाव पड़ता है कि मंडी में प्रतियोगिता की परिस्थिति है अथवा एकाधिकार की। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि प्रतियोगिता और एकाधिकार का क्या अर्थ है और दोनों का मूल्य पर क्या-कैसा प्रभाव पड़ता है। इस अध्याय में प्रतियोगिता-सम्बन्धी बातों का विवेचन किया जायगा और अगले अध्याय में एकाधिकार विषय का।

प्रतियोगिता का वास्तव्य उस परिस्थिति से है जिसमें मनुष्य बिना किसी बाहरी रोक-टोक के व्यापार, उत्पादन, उपभोग आदि अनेक आर्थिक क्षेत्रों में अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए स्वतन्त्र रूप से काम कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है कि वह जिस भी व्यवसाय या काम को लाभप्रद समझे बिना किसी बाहरी बाधा के कर सकता है। दूसरे शब्दों में, प्रतियोगितापूर्ण परिस्थिति में आर्थिक क्षेत्र के हर अंग में स्वतन्त्रता की पूरी-पूरी छाप होती है।

पूर्ण प्रतियोगिता (perfect competition) के दो मुख्य चिह्न माने जाते हैं। एक तो यह कि उत्पत्ति के साधनों के स्थान या व्यवसाय-परिवर्तन में कोई बाहरी रूकावट न हो। इसका परिणाम यह होगा कि एक तरफ़ के साधनों का पारिभ्रमिक एक समान ही होगा, क्योंकि यदि उसमें कोई असमानता है, तो वे साधन कम लाभप्रद वाले धन्यों को छोड़कर उन धन्यों में जाने लगेंगे जिनमें अपेक्षाकृत अधिक

लाभ दिखाई पड़ेगा। इस तरह का परिवर्तन या गमनागमन उस समय तक चालू रहेगा, जब तक कि भिन्न-भिन्न धंधों में एक तरह के गावन का पारिथमिक बराबर नहीं हो जायगा। ऐसा क्यों या कैसे होता है, इसकी समझना कठिन नहीं है। मान लो 'अ' और 'ब' दो धन्धे हैं। 'अ' में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी 'ब' धन्धे की अपेक्षा कहीं अधिक है। ऐसी दशा में अगर पूर्ण प्रतियोगिता है अर्थात् भिन्न-भिन्न उद्योग धंधों में आने-जाने की पूर्ण स्वतन्त्रता है, तो 'ब' के मजदूर वहाँ की गौकरी छोड़कर 'अ' धन्धे की ओर जाने लगेंगे क्योंकि इसमें उन्हें लाभ होगा। इसका परिणाम यह होगा कि 'ब' में मजदूरों की कमी होने के कारण, वहाँ पर मजदूरी बढ़ने लगेगी और दूसरी ओर 'अ' धन्धे में मजदूरों की संख्या घट जाने के कारण मजदूरी कम होन लगेगी। इस तरह मजदूरों का पारिथमिक 'अ' और 'ब' दोनों धन्धों में आगे चलकर एक समान हो जायगा। जब तक पारिथमिक व मजदूरी में समानता न आ जायगी, तब तक व्यवसाय-परिवर्तन या गमनागमन चलता ही रहेगा।

पूर्ण प्रतियोगिता की दूसरी विशेषता यह है कि किसी एक वस्तु के बेचने और खरीदने वाले बहुत अधिक मूल्य में हों। यदि ऐसा है तो किसी एक के थोड़ा अधिक व कम खरीदने अथवा बेचने का मूल्य पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मान लो कि किसी चीज के बनने वालों की संख्या १० लाख है और हर एक उस वस्तु की १० इकाई तैयार करता है, तो माल के उस वस्तु की कुल पूर्ति की मात्रा १०० लाख इकाईया होंगी। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई उत्पादक पहले से दुगुना माल तैयार करने लगे, या माल बनाना बिल्कुल बन्द कर दे, तो कुल माल की मात्रा में कोई विशेष अन्तर न पड़ेगा। इस कारण मूल्य में भी कोई परिवर्तन न होगा। इसी तरह यदि खरीदारों की संख्या अधिक है, तो किसी एक के कम या अधिक खरीदने से मूल्य में परिवर्तन न होगा। इसका यह तात्पर्य नहीं कि प्रतियोगितापूर्ण स्थिति में मूल्य माग

और पूर्ति द्वारा निर्धारित नहीं होता। यहाँ केवल यही कहा गया है कि बेचने और खरीदने वालों की अधिक मर्यादा होने के कारण व्यक्तिगत रूप से कोई मूल्य में परिवर्तन नहीं ला सकता। हाँ, यदि सभी उत्पादक कम या अधिक उत्पन्न करने लगे अथवा सभी ग्राहक कम या अधिक खरीदने लगे तो मूल्य में अवश्य परिवर्तन होगा।

उपर्युक्त बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतियोगिता की स्थिति में किसी एक खरीदार या बेचने वाले की नीति अथवा व्यवहार से मूल्य प्रभावित नहीं होता। मंडी में जो मूल्य, कुल माग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होगा, उसी पर खरीद और बिक्री होगी, चाहे कोई कम या अधिक खरीदे अथवा बेचे। ऐसी परिस्थिति में मूल्य एक ही होगा। कारण, अगर कोई बेचने वाला बाजार-भाव से अधिक मागता है, तो उसके पास कोई भी ग्राहक न जायगा और जब वह यह जानता है कि जितना भी चाहे वह बाजार-भाव पर बेच सकता है, तो उससे कम मूल्य पर वह भला क्यों बेचना चाहेगा। इसलिए समस्त मंडी में एक समय में किसी वस्तु का मूल्य एक ही होगा।

अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी स्थिति में कोई उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन किस सीमा तक करेगा? यह तो वह भलीभाँति जानता है कि व्यक्तिगत उत्पादन का प्रभाव मूल्य पर कुछ भी न होगा। चाहे वह पहले से कम या अधिक उत्पादन करने लगे, उस वस्तु के बाजार-भाव में कोई अन्तर न पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान लो कि किसी वस्तु का मूल्य १ रुपया है। जो कुछ माल उत्पादक तैयार करेगा, हर इकाई के बेचने में उसे १ रुपया मिलेगा। इस हान्तर में जब तक सीमात उत्पादन-व्यय १ रुपये से कम होगा, वह और अधिक उत्पादन करता जायगा क्योंकि ऐसा करने से उसे लाभ होगा। एक सीमा के बाद उत्पादन का परिमाण बढ़ाने से सीमात उत्पादन-व्यय मूल्य के बराबर पहुँच जायगा। यही उसके उत्पादन की सीमा होगी। यदि वह इससे अधिक माल तैयार करेगा, तो मूल्य तो उतना ही रहेगा पर सीमान्त

उत्पादन-व्यय में वृद्धि होती जायगी। इस कारण ऐसा करने से उसे हानि होगी। इससे बचने के लिए वह उत्पादन का परिमाण कम कर देगा। यह काम वह उस समय तक करता जायगा, जब तक कि सीमात उत्पादन-व्यय मूल्य के बराबर नहीं आ जायगा। जहाँ पर दोनों बराबर हो जायेंगे, वही उसके उत्पादन की सीमा होगी। अगर वह इस सीमा से कम उत्पादन करता है तो उत्पादन की मात्रा बढ़ाने में उसके लाभ में वृद्धि होगी और यदि वह उस सीमा से अधिक उत्पादन करता है, तो उत्पादन का परिमाण घटाने से उसे लाभ होगा। ऐसा करने से वह हानि को बचा सकता है। अस्तु, प्रतियोगिता के अन्तर्गत कोई उत्पादक उतना माल तैयार करेगा जितने से सीमात उत्पादन-व्यय मूल्य के बराबर हो जाय।

(संक्षेप में, प्रतियोगितापूर्ण स्थिति में मूल्य के सम्बन्ध में दो बातें उल्लेखनीय हैं—एक तो यह है कि किसी वस्तु का मूल्य समस्त मर्जी में एक समय में एक ही होगा, और दूसरे उस वस्तु का सीमात उत्पादन-व्यय और मूल्य दोनों बराबर होंगे।

### प्रतियोगिता से लाभ और हानियाँ

(Advantages and Disadvantages of Competition)

स्वतन्त्र प्रतियोगिता से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। ये लाभ केवल प्रतिद्वन्द्वियों तक ही सीमित नहीं होते, अपितु समाज के अन्य व्यक्तियों को भी प्राप्त होते हैं। उद्योग-धन्धों के चुनाव में पूर्ण स्वतन्त्रता होने से हर एक व्यक्ति उसी काम को अपनायेगा जिसमें वह अपनी अधिक-से-अधिक कुशलता और योग्यता दिखा सकता है। क्योंकि ऐसा न करने से वह दूसरों की प्रतियोगिता में ठहर न सकेगा। इससे मानव-शक्ति और समय का पूरा-पूरा उपयोग होता है। इससे धर्म-विभाजन में भी बहुत उत्प्रेरणा होती है जिसके लाभ से सभी अच्छी तरह परिचित हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिद्वन्द्वियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की बराबर होड़ मची रहती है। इसका परिणाम उत्पादन-क्षेत्र पर बहुत अच्छा पड़ता है।



इससे नये-नये आविष्कार होते हैं जिसके फलस्वरूप उत्पादन अच्छा और अधिक होने लगता है। साथ ही वस्तुओं की कीमत भी कम हो जाती है। इस प्रकार प्रतियोगिता ने हर एक को लाभ पहुँचाता है।

मक्षेप में, प्रतियोगिता के मुख्य लाभों को इस प्रकार रखा जा सकता है। प्रतियोगिता के प्रभाव से उत्पादन अधिकतम और उच्च कोटि का होता है, प्रत्येक फर्म सर्वाधिक अनुकूलतम रूप व आकार ग्रहण कर लेती है; उत्पादन-व्यय कम हो जाता है और साथ ही चीजों का बाजार-भाव भी, सबके लिए समान अवसर होने के कारण, घन-वितरण में व्यापकित समानता आ जाती है जो हर दृष्टि में आवश्यक और हितकर है। अस्तु, प्रतियोगिता में उत्पादन और वितरण के क्षेत्रों में बहुत लाभ होता है। व्यक्ति और समाज दोनों के विकास और उन्नति में इसमें बहुत सहायता मिल सकती है।

प्रतियोगिता के ये लाभ तभी प्राप्त हो सकते हैं जबकि प्रतियोगिता पूर्ण और स्वस्थ हो। वास्तविक जीवन में प्रायः प्रतियोगिता ऐसा भयकर रूप धारण कर लेती है कि हम इसकी अच्छाइयों से निराश हो होने पड़ता है। इतना ही नहीं, इसके कारण हम तरह-तरह की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक बुराइयों का सामना करना पड़ता है। अनियमित प्रतियोगिता से उत्पादन अत्यन्त ही अनिश्चित हो जाता है। उत्पादन की मात्रा कभी मांग में बहुत अधिक और कभी बहुत कम हो जाती है। इसमें व्यापार-व्यवसाय को बहुत धक्का लगता है। श्रमिकों को ठीक-ठीक स्थायी रूप से काम नहीं मिल पाता और अन्ततः सभी को इस कारण मुसीबत उठानी पड़ती है। प्रतियोगिता के कारण उत्पादन और वित्त के क्षेत्रों में किन्नल-खर्ची बहुत बढ़ जाती है। उत्पादन के नये-नये तरीकों और यंत्रों को मालूम करने के लिए उत्पादक अपने-अलग-अलग प्रयत्न करते हैं। इससे खर्च बढ़ जाता है और नये और पुराने तरीकों दोनों एक साथ चले रहते हैं। यह इसलिए कि जिन उत्पादकों को नये तरीके मालूम हो जाते

है, ये उसे अपने तक ही सीमित रखते हैं। अतः उस मुधार से सब लाभ नहीं उठा पाते। सामाजिक दृष्टि में यह खर्च बहुत-बहुत अशुभ तक व्यर्थ है। ठीक इस प्रकार मूल के विज्ञापन और यातायात पर बहुत अनावश्यक खर्च होता है। विज्ञापन का अपना गहत्व है, इसमें जानकारी बढ़ती है। लेकिन प्रायः प्रतियोगिता की स्थिति में विक्रेता ग्राहकों की जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें अपनी ओर खींचने के लिए तरह-तरह के खर्चीले विज्ञापनों का सहारा लेते हैं। इसमें उत्पादन-व्यय और फल-स्वरूप मूल्य बढ़ जाता है।

इसके अलावा यदि हम उत्पादन के गुण की ओर ध्यान दें तो हमें प्रतियोगिता में और भी निराशा होगी। प्रतियोगिता में ठहरने के लिए तथा अपने लाभ को बढ़ाने के लिए उत्पादक अच्छी, ठीकाऊ और लाभ-प्रद वस्तुओं के स्थान पर मम्मी, दिवालदी और हानिकारक चीजें तैयार करने लगते हैं। और जब इससे भी काम नहीं चल पाता तो वे चीजों में मिलावट करने लगते हैं। अगली चीजों की जगह पर नकली चीजें तैयार की जाने लगती हैं, क्योंकि इन पर खर्च कम पड़ता है, ये मम्मी होती हैं। इससे व्यापार का नैतिक आधार टूट जाता है और लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्रतिद्वन्द्वी एक दूसरे को हराणे के लिए बहुत बुरे और अनुचित तरीकों को काम में लाने लग जाते हैं जिसमें प्रतियोगिता “गला-काट” रूप धारण कर लेती है। इसका परिणाम सबके लिए बहुत हानिकारक होता है, लाभ तोर में जबकि प्रतिद्वन्द्वियों व स्वर्धको में समानता नहीं होती। यदि एक शक्तिशाली मिल-मालिक और एक शक्तिहीन मजदूर के बीच प्रतिस्पर्धा हो तो निश्चय ही मजदूर अपने हितों की रक्षा न कर सकेगा। उसे विवश होकर कम मजदूरी तथा अन्य प्रकार के अत्याचारों को सहन करना पड़ेगा। इसमें यह भी स्पष्ट है कि व्यापारिक विवरण के लिए पूर्णरूप में प्रति-योगिता पर निर्भर नहीं किया जा सकता।

अतः, अनिवारित प्रतिस्पर्धा में कोई स्थायी लाभ नहीं होता।

इससे उत्पत्ति अनिश्चित हो जाती है और वितरण की समस्या उत्पन्न होती है। सामाजिक कल्याण और प्रगति के लिये प्रतियोगिता को सीमित रखना, उस पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है। आधुनिक आर्थिक जगत आयोजित आर्थिक विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जहाँ प्रतियोगिता का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता।

### QUESTIONS

- 1 How is the price of a commodity determined under competitive conditions ?
- 2 What is meant by 'perfect competition' ? Describe its features
- 3 What are the advantages and disadvantages of competition ?

## एकाधिकार और मूल्य (Monopoly and Value)

एकाधिकार प्रतियोगिता का बिल्कुल उल्टा है। जब किसी वस्तु की उत्पत्ति, बिज्जी या खरीद का अधिकार किसी एक व्यक्ति या फर्म के हाथ में होता है जिसके द्वारा मूल्य पर प्रभाव डाला जा सकता है, तो उसे “एकाधिकार” (monopoly) कहते हैं। एकाधिकारी अपनी तरफ से मूल्य पर प्रभाव डाल सकता है। वह अपने लाभ को बढ़ाने के लिए बाजार-भाव में परिवर्तन ला सकता है, उसे घटा-बढ़ा सकता है। प्रतियोगिता की परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ से बाजार-भाव में हेर-फेर नहीं कर सकता। व्यक्तिगत रूप में मूल्य पर प्रभाव डालने की उसमें कोई शक्ति नहीं होती। एकाधिकारी के लिए यह संभव है क्योंकि जिस व्यवसाय या धन्य को वह करता है, उस पर उसका पूरा अधिकार होता है। परन्तु पूर्ण एकाधिकार बहुत कम देखने में आता है। अधिकांश एकाधिकारियों को किसी न किसी प्रकार की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। इसलिए बाजार पर उनका पूरा अधिकार नहीं हो पाता।

सब एकाधिकारी व्यवसाय न एक प्रकार के होते हैं और न ही उनका संगठन एक ढंग से होता है। इसलिए एकाधिकार के विभिन्न भेदों का स्पष्टीकरण आवश्यक है।

### एकाधिकार के भेद

(Kinds of Monopoly)

<sup>1</sup> स्वामित्व की दृष्टि से एकाधिकार का वर्गीकरण तीन भागों में

दिया जाता है। (क) जब किसी एकाधिकार का मालिक कोई एक व्यक्ति या व्यक्ति-समूह होता है तो उसे "व्यक्तिगत एकाधिकार" (private monopoly) कहते हैं। (ख) अब किसी एकाधिकार का मालिक सरकार, म्युनिसिपैलिटी या और कोई सार्वजनिक मस्वा होती है तो उसे "सार्वजनिक एकाधिकार" (public monopoly) कहते हैं। (ग) जब किसी एकाधिकार का मालिक तो कोई सरकार या सार्वजनिक संस्था हो किन्तु उसका प्रबन्धक कोई व्यक्ति या व्यक्ति-समूह हो, तो उसे "अर्ध-सार्वजनिक एकाधिकार" (quasi-public monopoly) कहते हैं।

एकाधिकार का दूसरा वर्गीकरण क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। (क) जब किसी एकाधिकार का क्षेत्र केवल एक विशेष नगर या स्थान तक ही सीमित होता है, तो उसे "स्थानीय एकाधिकार" (local monopoly) कहते हैं। (ख) जब किसी एकाधिकार का क्षेत्र सारे देश में फैला हुआ होता है तो उसे "राष्ट्रीय एकाधिकार" (national monopoly) कहते हैं। (ग) और यदि किसी एकाधिकार का क्षेत्र अनेक देशों तक विस्तृत हो तो उसे "अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार" (international monopoly) कहते हैं।

एकाधिकार का एक अर वर्गीकरण है जो उसके मूल कारण की दृष्टि से किया जाता है। (क) जब कोई प्राकृतिक पदार्थ परिमित मात्रा में किसी एक विशेष स्थान पर ही पाया जाता है और उस पर किसी का अधिकार हो जाता है, तो उसे "प्राकृतिक" अथवा "तैसृगिक एकाधिकार" (natural monopoly) कहते हैं, जैसे नमाल में पटखन व दक्षिण अफ्रीका में हीरे। (ख) सार्वजनिक उपयोगिता-सम्बन्धी पदार्थों में प्रतियोगिता होने में बहुत हानि होती है। बहुत-से सामान व्यर्थ ही नष्ट हो जाते हैं। और साथ ही अनुविभाज्य भी बहुत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी स्थान पर बिजली देने का काम कई प्रतियोगी कम्पनियों के हाथ में है तो इससे वहाँ के लोगों को बितनी

अमुविना होगी और ध्येय में लक्ष्य होगा, यह आसानी में सोचा जा सकता है। इनसे बचने के लिए जो एकाधिकार स्थापित किया जाता है, उसे "सार्वजनिक एकाधिकार" (social monopoly) कहते हैं, जैसे किसी एक स्थान पर जल, बिजली आदि का एकाधिकार। (ग) जो एकाधिकार किसी व्यक्ति को कानूनी प्राप्ति होता है उसे "कानूनी एकाधिकार" (legal monopoly) कहते हैं। नये आविष्कारों के पेटेंट और पुस्तकों के कॉपीराइट कानूनी एकाधिकार के उत्तम उदाहरण हैं। अनिकाय सार्वजनिक एकाधिकार धन्यो को कानूनी सुरक्षा मिली हुई होती है। (घ) जब कुछ प्रतिद्वन्द्वी व्यवसायी या व्यापारी आपस में मिलकर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं, तो उसे "स्वेच्छिक एकाधिकार" (voluntary monopoly) कहते हैं। प्रायः बड़े-बड़े व्यवसायी प्रतिस्पर्धिता के बुरे परिणामों से बचने तथा आबन्धनिक मिलन की अनेक वस्तुओं से लाभ उठाने के लिए आपस में मिलकर अपने काम को एक साथ करने की व्यवस्था कर लेते हैं। इससे उन्हें एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। आपुनिक अधिक जगत में इस प्रकार के एकाधिकारों का बड़ा जोर है। सभी देशों में इस तरह के एकाधिकारों व्यवसाय तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इन पर नियन्त्रण रखने के लिए अनेक देशों में कानून बनाये गये हैं।

### एकाधिकार-मूल्य

(Monopoly Value)

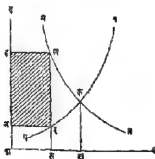
अब प्रश्न यह है कि एकाधिकार की परिस्थिति में मूल्य कैसे निर्धारित होता है? यह तो सभी को मालूम है कि एकाधिकारी उत्पादक का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ उठाना होता है। यही उद्देश्य प्रतिद्वन्द्वियों का भी होता है। किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि प्रतिस्पर्धिता की परिस्थिति में कोई उत्पादक व्यक्तिगत रूप से मूल्य में परिवर्तन नहीं ला सकता, और न मूल्य उत्पादन-मध्य से अधिक हो सकता है। एकाधिकारी के लिए ये बातें सम्भव हैं। वह उत्पादन-मात्रा में परिवर्तन लाकर मूल्य को घटा-बड़ा सकता है। उसके लिए यह सम्भव है कि

उत्पादन-व्यय से अधिक मूल्य निर्धारित करके विशेष लाभ उठा सके। इस तरह के लाभ को 'एकाधिकारी लाभ' कहा जा सकता है। यह प्रति-योगी उत्पादकों को उपलब्ध नहीं हो सकता।

एकाधिकारी को अधिक से अधिक लाभ पाने के लिए यह सुझाया जा सकता है कि वह ज्यादा से ज्यादा कीमत पर अधिक से अधिक माल बेचे। पर यह उसकी क्षमता के बाहर है। उसके लिए यह सम्भव नहीं कि बिना की मात्रा निर्धारित करने के साथ-साथ वह यह भी तय कर सके कि किस मूल्य पर माल को बेचा जाय। वह दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि पूर्ति पर उसका अधिकार तो अवश्य होता है, पर माग पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। (एक साथ कीमत पर वह बितना माल बेच सकेगा, वह माग पर निर्भर है) इसलिए वह दोनों में से केवल एक ही बात कर सकता है—चाहे तो वह मूल्य निर्धारित कर ले, या पूर्ति की मात्रा, जो वह बेचना चाहता है।

इससे यह पता चलता है कि मूल्य-निर्धारण के सम्बन्ध में एकाधिकारी इतना स्वतन्त्र नहीं है जितना कि साधारणतः सोचा जाता है। उसे भी माग और पूर्ति सम्बन्धी बातों पर पूरा-पूरा ध्यान देना पड़ता है। उसे यह देखना पड़ता है कि उसकी वस्तु की माग कितनी लोचदार है। यदि माग में अधिक लोच है, तो मूल्य कम रखने से उसे लाभ होगा क्योंकि ऐसा करने से माग में वृद्धि होगी। यदि माग कम लोचदार है तो मूल्य अधिक रक्खा जा सकता है क्योंकि खरीदार माग में विशेष कमी नहीं कर सकते। माग की लोच के साथ-साथ पूर्ति सम्बन्धी बातों पर भी उसे ध्यान देना पड़ता है। यदि वस्तु का उत्पादन भ्रमागत वृद्धि-नियम के अनुसार चल रहा है, तो उत्पत्ति-वृद्धि के साथ सीमान्त लागत में कमी होगी। ऐसी दशा में मूल्य कम रखने से बिना बढ़ेगी और एकाधिकारी को लाभ होगा। लेकिन अगर उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास-नियम लागू है, तो उत्पत्ति कम करने से प्रति इकाई खर्च में कमी होगी। ऐसी स्थिति में यदि माग कम लोचदार हुई, तो ऊँची कीमत रखने से उसे लाभ होगा।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एकाधिकारी वह मूल्य निर्धारित करने का प्रयत्न करेगा जिसमें उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। यह यह जानता है कि लाभ दो बातों पर निर्भर होता है—(१) प्रति इकाई मूल्य, और (२) बिक्री की मात्रा। दोनों में से यदि एक अधिक है तो यह आवश्यक नहीं कि कुल लाभ भी अधिक हो। यदि वह मूल्य बहुत अधिक रखता है, तो माग घट जाने के कारण बिक्री कम होगी। फलस्वरूप कुल लाभ अधिकतम न होगा। दूसरी ओर, यदि वह मूल्य बाल बेचता है, किन्तु प्रति इकाई मूल्य बहुत कम है तो भी कुल लाभ अधिकतम न होगा। अस्तु, एकाधिकारी को न तो बहुत ऊँची कीमत रखने से और न बहुत ज्यादा बेचने से ही अधिकतम लाभ मिलेगा। उन्ने मूल्य और बिक्री के बीच एक ऐसा मिलान खोज करना पड़ेगा जहाँ पर अधिकतम लाभ मिल सकता हो। नीचे दिए हुए रेखा-चित्र द्वारा यह सामान्यी में दिखाया जा सकता है कि किस स्थान पर मूल्य निर्धारित करने से एकाधिकारी को अधिकतम लाभ मिल सकता है।



ऊपर के चित्र में माग और पूति की रेखाएँ एक दूसरे को 'क' स्थान पर काटती हैं। प्रतिस्पर्धिता की परिस्थिति में मूल्य 'क' से बराबर होगा क्योंकि इस मूल्य पर माग और पूति की मात्राएँ बराबर



है। एकाधिकारी विशेष लाभ उठाने की दृष्टि में इससे अधिक मूल्य रखेगा। मान लो वह 'ल स' मूल्य निर्धारित करता है जो 'क स' मूल्य से अधिक है। इस मूल्य पर वह 'अ स' सख्या बेच सकेगा क्योंकि खरीदार इस मूल्य पर इतना ही खरीदने को तैयार है। 'अ स' सख्या का कुल उत्पादन व्यय 'अ स र न' आयत के बराबर है। इस सरपा के बेचने से उसे कुल कीमत 'अ स ल ह' आयत के बराबर मिलती है। इन दोनों के घटाने से एकाधिकारी-लाभ मालूम हो सकता है। इस बिन्दु में रंगा हुआ आयत एकाधिकारी-लाभ दर्शाता है। इस तरह 'क स' के ऊपर और बड़ी आयत बन सकते हैं। इनमें से एक का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। उरी स्थान पर एकाधिकारी अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारित करेगा।

ऊपर के विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि एकाधिकारी मूल्य निश्चित करते समय इस बात की सोच करेगा कि किम कीमत से उसे अधिकतम लाभ<sup>१</sup> होगा और अन्त में वह वही कीमत निश्चित करेगा। इस सम्बन्ध में उसे माग की ओर, आयत-क्षेत्र और उत्पत्ति के नियमों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा।

एकाधिकारी के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि अपनी वस्तु को वह एक ही कीमत पर बेचे। वह अपनी वस्तु को भिन्न-भिन्न स्थानों पर, भिन्न-भिन्न श्रेणी के लोगों के लिए अथवा भिन्न-भिन्न उपयोगों के लिए अलग-

१ एकाधिकारी का लाभ उस समय अधिकतम होगा जबकि उत्पादन की सीमान्त लागत सीमान्त आय के बराबर होगी। कुल आय में जो एक और इकाई के बेचने से वृद्धि होती है, उसे सीमान्त आय (marginal revenue) कहते हैं। जब तक सीमान्त लागत और सीमान्त आय बराबर न होंगे, एकाधिकारी को उत्पादन की मात्रा बढ़ाने या घटाने से लाभ होगा। जब दोनों बराबर हो जेंगे तो उसका लाभ अधिकतम हो लेगा।

अलग कीमत पर बेच सकता है। परन्तु दामो में इस प्रकार का भेद-भाव हमें सा सम्भव नहीं होता। इसके सम्भव होने के लिए दो बातें जरूरी हैं। एक तो यह कि वस्तु की वह मात्रा जो कम भाव वाले बाजार में बिकती है, ऊँचे भाव के बाजार में दुबारा बेच देयी जा सके। दूसरी बात यह है कि महुँगी मंडी के खरीदार रास्ती मंडी में जाकर अपनी मांग की पूर्ति न कर सकें। जब तब ये दोनों बातें मंजूर न होंगी, तब तक एकाधिकारी दामो में किसी भी प्रकार का भेद-भाव न कर सकेगा। और यदि वह ऐसा करने का प्रयत्न करेगा तो उसके लाभ में वृद्धि न होगी। वह बमफल रहेगा।

दामो में भेद-भाव करना उन एकाधिकारियों के लिए बहुत सरल होता है जो सेवा द्वारा प्रत्यक्ष रूप में दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जैसे डाक्टर, वकील आदि। प्रायः बड़े डाक्टर गरीबों से कम फीस लेते हैं और अमीरों से अधिक। ऐसा करने में वे गरीबों की भलाई ही नहीं करते बल्कि अपने लाभ को भी बढ़ाते हैं। यदि वे सभी के लिए एक-ही फीस रखें तो बहुत से मरीज गरीब होने के कारण उनके पास न आ सकेंगे। फलस्वरूप उनकी दवा या सेवा कम बिक सकेंगी। इसलिए वे विभिन्न ध्येनी वाले व्यक्तियों के लिए विभिन्न दाम या फीस रख सकते हैं। यहाँ यह सम्भव नहीं है कि गरीब आदमी को भेजकर, धनी आदमी अपने राग की दवा करवा सके अपना कोई व्यक्ति उस दवा को खरीद कर दुबारा दूसरों के हाथ बेच सके।

उपरोक्त बातों से एकाधिकार और प्रतियोगिता के अन्तर्गत मूल्य-निर्धारण में जो अन्तर है, वह स्पष्ट हो जाता है। प्रतियोगिता की परिस्थिति में किसी वस्तु की कीमत उसके सीमान्त उत्पादन-व्यय के बराबर होगी। कोई भी प्रतियोगी विवेका व्यक्तिगत रूप से मूल्य पर प्रभाव नहीं डाल सकता। बाजार-भाव से अधिक कीमत उसे नहीं मिल सकती। एकाधिकार की परिस्थिति में किसी वस्तु का मूल्य उसके सीमान्त उत्पादन-व्यय से साधारणतः अधिक होगा क्योंकि तभी एकाधिकारी-

हाम अधिकतम हो सकेगा। एकाधिकारी बाजार-भाव पर प्रभाव डाल सकता है। पूर्ति को घटा-बढ़ा कर वह बाजार-भाव में परिवर्तन ला सकता है। दूसरा अन्तर यह है कि एकाधिकारी दागो में भेद-भाव कर सकता है, वह विभिन्न खरीदारों से विभिन्न दाम ले सकता है। परन्तु प्रतियोगिता की परिस्थिति में ऐसा सम्भव नहीं है। उस समय किसी वस्तु का एक समय में एक ही मूल्य होगा। इन विभिन्नताओं के होते हुए भी यह नहीं समझ लेना चाहिए कि एकाधिकार और प्रतियोगिता की परिस्थितियों में मूल्य-निर्धारण में कोई सैद्धान्तिक भेद है। अन्ततः किसी वस्तु का मूल्य उसकी माग और पूर्ति द्वारा ही निर्धारित होगा, चाहे बाजार में एकाधिकार की परिस्थिति हो, अथवा प्रतियोगिता की।

**एकाधिकार-मूल्य—अधिक या कम ?**

(Monopoly Value—High or Low ?)

साधारणतः प्रतियोगिता की परिस्थिति में किसी वस्तु का मूल्य उसके सीमान्त उत्पादन-व्यय के बराबर होता है और एकाधिकार की परिस्थिति में मूल्य सीमान्त उत्पादन-व्यय में अधिक होता है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि एकाधिकार की परिस्थिति में मूल्य अपेक्षाकृत ऊँचा होता है। पर इसका यह आशय नहीं कि हमेशा और अवश्य ही कीमत ऊँची होगी। कई बातों के प्रभाव से एकाधिकार-मूल्य कम भी रह सकता है। एकाधिकार से अनेक प्रकार की सुविधाएँ मिलती हैं, इससे तरह-तरह की बचत होती है। एकाधिकारी अपने व्यवसाय को बहुत ऊँचे पैमाने पर कर सकता है जिससे विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। माल के विभाजन, विश्वादी आदि में भी उसे बहुत बचत होती है। इन सबके प्रभाव में लागत-व्यय कम बैठता है। फलस्वरूप सीमान्त उत्पादन-व्यय से अधिक होने पर भी एकाधिकार-मूल्य कम हो सकता है। फिर भी साधारणतः एकाधिकार-मूल्य अपेक्षाकृत ऊँचा होता है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि एकाधिकार-मूल्य मरदा बहुत ऊँचा होगा। कारण, ऊँचे दाम से हमेशा अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होता। ऊँचे दाम

से बिक्री कम हो जाने का डर रहता है । इसलिए एक सीमा के बाद एकाधिकारी दाम को और अधिक न बढ़ायेगा क्योंकि ऐसा करना उसके लिए लाभप्रद न होगा ।

### एकाधिकारी की शक्ति की सीमा

(Limits to the Power of Monopolist)

प्रायः यह कहा जाता है कि एकाधिकारी का बाजार पर पूर्ण अधिकार होता है । अपनी वस्तु के लिए जो मूल्य वह चाहे निश्चित कर सकता है, उस पर कोई बन्धन नहीं होता । लेकिन वास्तविक जीवन में एकाधिकारी की शक्ति असीमित नहीं होती । उसके सामने कुछ न कुछ बन्धन होते हैं जिनके कारण वह बहुत ऊँची कीमत नहीं ले सकता । सर्वप्रथम, उसे नये प्रतिस्पर्द्धियों से सतर्क रहना पड़ता है । उसे सदा यह भय लगा रहता है कि कहीं उस क्षेत्र में नये प्रतिस्पर्द्धी न आ जाय और उसका एकाधिकार छिन जाय । दूसरे, उसे इस बात का भी डर रहता है कि ऊँची कीमत के कारण उसकी वस्तु के बढ़ने में दूसरी वस्तुएँ उपयोग में न लाई जाने लगे । तीसरे, उसे यह भी खतरा रहता है कि नही जनता में असंतोष न फैल जाय और सरकार उस व्यवसाय पर नियन्त्रण लगा दे अथवा उसे अपने हाथ में ले ले । इन बातों के भय से एकाधिकारी बहुत ऊँची कीमत निर्धारित न करेगा ।

### एकाधिकार से लाभ तथा हानियाँ

(Advantages and Disadvantages of Monopoly)

एकाधिकार में होने वाले लाभों की सूची बहुत लम्बी है । यह पहले कहा जा चुका है कि 'गला-काट' प्रतिव्योमिता से तरह-तरह की अधिक, सामाजिक और नैतिक हानियाँ होती हैं । एकाधिकार इस तरह की प्रतिव्योमिता को दूर करके मगान को उन हानियों और कष्टों में बचाता है । माघारणत एकाधिकारी अपने पक्ष को एक प्रतिव्योमी को अपेक्षा कही अधिक बड़े पैमाने पर करता है । फलस्वरूप बड़े पैमाने की उत्पात्ति में जितने भी लाभ हैं, वे उसे प्राप्त होते हैं । प्रतिव्योमिता

जनित स्थिति में उत्पादन-क्षेत्र में बहुत उतार-चढ़ाव होता रहता है। इसमें माग और पूर्ति के बीच का सामाजिक बराबर टूटता रहता है जिससे लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एकाधिकार द्वारा यह भी दूर हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिद्वन्द्वियों को अपने माल के अलग-अलग विज्ञापन पर बहुत खर्च करना पड़ता है। हर एक अपने सामान को दूर और नजदीक की सभी मंडियों में बेचने का प्रयत्न करता है जिससे लागत-वर्धन बहुत बढ़ जाता है। खोज और अनुसंधान का भी अलग-अलग प्रवन्ध किया जाता है। जो कोई भी नई चीज का आविष्कार कर लेता है, उसे अपने तक ही सीमित रखता है, दूसरों को मालूम नहीं होने देता। इसका परिणाम यह होता है कि एक नई चीज मालूम हो जाने पर भी उसी चीज की खोज में दुबारा-तिबारा खर्च होता रहता है। इस तरह समाज का बहुत-सा समय, शक्ति और धन व्यर्थ नष्ट होता है। एकाधिकार की परिस्थिति में ये सब बातें दूर हो जाती हैं। एकाधिकारी संस्था की शाखाओं के बीच मंडी का यथोचित बंटवारा कर दिया जाता है। हर एक शाखा अपनी नियत मंडी में ही माल बेच सकती है, अन्य मंडियों में नहीं। इससे बहुत घर्षण होती है। विज्ञापन को उसका उचित स्थान दे दिया जाता है। खोज और अनुसंधान का कार्य एक कोटित स्थान पर होता है और प्रत्येक शाखा में सर्वोत्तम साधनों को प्रयोग में लाया जाता है। इन सब कारणों से उत्पादन में बहुत वृद्धि होती है और उत्पादन-व्यय घट जाता है।

पर इतना यह आश्चर्य नहीं कि एकाधिकार हानिरहित है। इसमें जो हानियाँ उत्पन्न होती हैं, उनमें कुछ तो बहुत ही भयंकर हैं। यह ठीक है कि एकाधिकार की परिस्थिति में माल तैयार करने और उसके बेचने में काफी बचत होती है। पर प्रश्न यह है कि क्या एकाधिकारी इन बचतों से लाभ उठाकर वस्तु का मूल्य कम कर देता है। साधारणतः यह देखा जाता है कि वह मूल्य कम नहीं करता। वह वस्तुएँ सस्ती तो अवश्य बनाता है, लेकिन लोगों को वह चीजें सस्ती नहीं बेचता। जो कुछ उत्पादन

और बेचने में बचत होती है, उसे वह अपनी जेब में रखता है। कभी-कभी तो यहाँ तक देखने में आता है कि एकाधिकारी मूल्य के गिरने के भय से तैयार की हुई वस्तु का कुछ भाग जान-बूझ कर नष्ट कर देता है। ब्रेजिल में काफी के साथ यह बात बक्सर देखने में आई है। उसके अतिरिक्त एकाधिकारी अपना अधिकार जमाये रखने के लिए तरह-तरह के अनुचित साधनों का प्रयोग करता है। यदि कोई उसके साथ प्रतियोगिता करने के लिए सिर उठाता है तो उसके कुचबने में वह कोई कसर नहीं छोड़ता। अनेक बाधाएँ उसके मार्ग में डालता है जिसमें वह पनप न सके, वह बाजार छोड़ कर भाग जाय। इस तरह प्रतियोगिता के भय से मुब्त होकर वह बड़े आराम से अपना कारोबार चलाता है।

संक्षेप में, एकाधिकार में निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। (१) अधिक से अधिक लाभ उठाने के उद्देश्य में एकाधिकारी उत्पादन को माया पट्टा देते हैं। इससे उपभोक्ता को कम मात्रा में वस्तुएँ मिलती हैं और उन्हें अधिक दाम भी देने पड़ने हैं। कम उत्पादन में उपभोक्ता की गुप्ति और मतोप में ही कमी नहीं होती, बल्कि उत्पत्ति के साधनों को भाग भी घट जाती है। इससे बेकारी फैलती है, और उत्पत्ति के साधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। (२) एकाधिकार से व्यवसाय में शिथिलता आ जाती है। प्रतियोगितारहित परिस्थिति में उत्साह न रहने के कारण उन्नति में बाधा पड़ती है। आविष्कार और वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य भी फाँका पड़ जाता है। (३) एकाधिकार होने पर उस क्षेत्र में नये लोग आसानी से नहीं आ पाते, जिससे समाज को उन लोगों की योग्यताओं और क्षक्तियों का पूरा-पूरा लाभ नहीं प्राप्त हो पाता। (४) यही नहीं, एकाधिकार के द्वारा घन-वितरण में बहुत विषमता आ जाती है, जिसके कारण अनेक आर्थिक, सामाजिक और नैतिक बुराईयाँ पैदा होती हैं। (५) एकाधिकार की परिस्थितियों में राजनीतिक घाबराहट का भी बहुत डर रहता है। एकाधिकारियों के पास बहुत अधिक सामन होने हैं। इनके द्वारा वे विभिन्न अनूचित तरीकों से राजनीतिक नेताओं, ससद् के

सदस्यों और व्यापारियों को अपने वश में लान का भरसक प्रयत्न करने हैं जिससे कानून उनके पक्ष में पास होत रहे और बाजार उनको मुट्ठी में बने रहे ।

इन हानियों को देखते हुए एकाधिकार पर सरकारी नियन्त्रण होना समाज की प्रगति और कल्याण के लिए बहुत जरूरी है । सभी दलों में सरकार इस ओर काफी ध्यान देती है ।

### QUESTIONS

- 1 What is monopoly ? Explain briefly the different kinds of monopoly
- 2 How is price determined under monopoly ? Explain it with the help of a diagram
- 3 Is monopoly price necessarily higher than competitive price ? Are there no checks on the power of a monopolist ?
- 4 What are the main advantages and defects of monopoly ?

## अध्याय ३४

### मुद्रा

#### (MONEY)

आजकल मसार के सभी सम्य देशों में मुद्रा का चलन है। वर्तमान समय में विनिमय, मूल्यमापन और लेन-देन का लघुभग सारा कार्य इसी के माध्यम द्वारा होता है। मुद्रा के रूप में ही लोगों को पारिश्रमिक दिया जाता है, वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता है, मूल्यों की माप और तुलना होती है, तथा इसी के आधार पर सब प्रकार का हिसाब-खाता रखा जाता है। निस्संदेह मुद्रा आधुनिक आर्थिक जगत की एक प्रमुख विशेषता है। अतः वर्तमान अर्थ-व्यवस्था को भली प्रकार समझने के लिए मुद्रा सम्बन्धी बातों को जानकारी अत्यन्त आवश्यक है। सर्वप्रथम मुद्रा कहते किसे है, इसी को ही ले लिया जाय।

### मुद्रा की परिभाषा

#### (Definition of Money)

बैसे तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा भिन्न-भिन्न प्रकार से की है और कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जिसे सभी स्वीकार करते हो, फिर भी मुद्रा की परिभाषा इन शब्दों में की जा सकती है—मुद्रा वह वस्तु है जो बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट के सर्वग्राह्य होती है, जो विनिमय-माध्यम का कार्य करती है तथा जिसके देने से हम पूर्णरूप से ऋणमुक्त हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, मुद्रा विनिमय के माध्यम तथा मूल्य-मापन का कार्य करने वाली सर्वग्राह्य वस्तु होती है। यदि किसी स्थान पर किसी वस्तु को सर्वमान्यता या सर्वग्राह्यता प्राप्त रहती है, यदि विनि-



मय, कर्ज व लेन-देन में लोग उसे बिना किसी मन्देह अथवा सकोच के स्वीकार करते हैं, तो वह मुद्रा है। जैसे हम भारत में रिजर्व बैंक के नोटों और रुपयों को सब प्रकार के विनिमय के लेन-देन में निस्सन्देह स्वीकार करते हैं। अतः ये सब मुद्रा हैं। इस परिभाषा के अनुसार पेश, हुण्डी आदि साख-पत्र मुद्रा नहीं हैं। कुछ अंश तक ये विनिमय के साधन का कार्य अवस्थ करने में सक्षम इनमें सर्वग्राह्यता का गुण नहीं है। लोग चेक आदि साख-पत्रों को बिना रीच-विचार व देगे वाले व्यक्ति की बिना जानकारी के कर्ज अथवा माल के भुगतान में स्वीकार नहीं करते। सर्वग्राह्यता का गुण न होने से इन्हें पूर्ण रूप में मुद्रा नहीं मान सकते। मुद्रा की प्रमुख विशेषता, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, यह है कि विनिमय और लेन-देन के कार्य में यह निस्सकोच सर्वग्राह्य हो।

ऊपर दी हुई परिभाषा में यह स्पष्ट है कि मुद्रा किसी एक वस्तु के नहीं कहते। मुद्रा के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह सोने-चादी अथवा अन्य किसी विशेष पदार्थ की बनी हुई हो। यदि हम मुद्रा के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि भिन्न-भिन्न समय और स्थान पर अनेक प्रकार की वस्तुएँ मुद्रा के तौर पर प्रयोग की जा चुकी हैं जैसे कौड़ियाँ, पन्ना, चमड़ा, अनाज आदि। आज सोने चादी के सिक्के और कागज के नोट मुद्रा के रूप में प्रचलित हैं। सभ्य है भविष्य में मुद्रा का कार्य किसी और वस्तु व वस्तुओं को सौंप दिया जाय। अस्तु, मुद्रा का आशय किसी सख वस्तु में नहीं है, कोई भी वस्तु मुद्रा बन सकती है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि वह मुद्रा का कार्य करे। वह विनिमय के माध्यम और मूल्यमापन का कार्य करे और निस्सकोच सर्वग्राह्य हो। यहाँ यह पूछा जा सकता है कि सर्वग्राह्यता के लिए क्या यह आवश्यक है कि मुद्रा में स्वतः मूल्य या उपयोगिता हो? शुरु-शुरु में तो यह अवश्य जरूरी था किन्तु अब ऐसी बात नहीं रही। लोग इतने आगे बढ़ गये हैं और मुद्रा के कार्य से इतने भलीभाँति परिचित हो चुके हैं कि उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं रहती कि मुद्रा किस वस्तु की बनी हुई है और उसमें वास्तविक

मूल्य है या नहीं। उदाहरण के लिए कागज के नोटों को ले लो। उनमें कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। फिर भी लोग इन्हें लेन-देन के कार्य में बिना किसी हिचक के स्वीकार करते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें यह विश्वास होता है कि दूसरे भी उन नोटों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे। मुद्रा का यही प्रधान कार्य है। यह विनिमय का माध्यम है। यह एक त्रय-शक्ति है, एक चिह्न, मोहर या टिकट है जिसके द्वारा इच्छित वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। इसका कार्य मनुष्य की आवश्यकताओं को सीधे तौर पर पूर्ति करना नहीं है। वस्तु, मुद्रा के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि उस वस्तु में उपयोगिता हो। चाहे वह वस्तु किसी भी प्रकार की हो, चाहे उसमें और कोई उपयोगिता हो या नहीं, यदि वह विनिमय के माध्यम और मूल्य-मापन का कार्य करती है तो वह मुद्रा है। हा, यह बात अवश्य है कि यदि उस वस्तु में मुद्रा के अलावा और कोई उपयोगिता व मूल्य है, तो वह आसानी से अधिक सर्वप्राप्त होगी।

### मुद्रा के कार्य

(Functions of Money)

मुद्रा की परिभाषा करने समय हम ऊपर कह चुके हैं कि मुद्रा का सम्बन्ध किसी विशेष प्रकार की वस्तु से नहीं बल्कि मुद्रा के कार्यों से है। वास्तव में मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। उन मुद्रा के प्रधान कार्यों को समझे बिना हमें मुद्रा के स्वरूप की पूर्ण कल्पना नहीं हो सकती। मुद्रा के अनेक कार्य हैं जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं —

#### (१) विनिमय-माध्यम (Medium of Exchange) —

मुद्रा का सबसे प्रमुख कार्य यह है कि यह विनिमय का माध्यम होती है। यह विनिमय का माध्यम है। वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय हमें के माध्यम द्वारा होता है। हम अपनी वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रा के बचने में बेचते हैं और फिर उस मुद्रा से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य वस्तुएं अथवा सेवाएं खरीदते हैं। मुद्रा के माध्यम द्वारा विनिमय-कार्य सरल हो जाता है और वस्तु-विनिमय अथवा प्रत्यक्ष विनिमय

(barter) की सबसे बड़ी कठिनाई,—आवश्यकताओं के दुहरे समूह में मेल का अभाव—, दूर हो जाती है।

(२) मूल्यमापन या मूल्यमान का साधन (Measure or Standard of Value)—मुद्रा का दूसरा प्रधान कार्य मूल्यमापन का कार्य है। जिस प्रकार दूरी नापने के लिए गज, बरत नापने के लिए मन, सेर, छटाक आदि हैं, इसी प्रकार अन्य वस्तुओं का मूल्य मुद्रा में नापा जाता है, अर्थात् मुद्रा में प्रकट किया जाता है। मुद्रा मूल्य मापने का साधन है। इसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का मूल्य मापा जाता है। मुद्रा के इस कार्य में वस्तुओं के परस्पर मूल्यों की तुलना करने तथा उनके मूल्य निश्चित करने में बड़ी सुविधा होती है। फलस्वरूप विनिमय का कार्य अधिक सुगम हो जाता है।

(३) मूल्य-संचय (Store of Value)—मुद्रा का तीसरा प्रमुख कार्य मूल्य-संचय है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुल आय को वर्तमान में ही खर्च न करके उसका कुछ भाग भविष्य के उपयोग के लिए बनाना चाहता है। यह कार्य वस्तुओं का संग्रह करके सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। कारण, वे अधिक समय तक संग्रह नहीं रखी जा सकती। यह भी समझ है कि भविष्य में उन वस्तुओं की आवश्यकता न रहे। मुद्रा इस कठिनाई को दूर कर देती है। मुद्रा एक जय-शक्ति है। इससे जब और जो वस्तु चाहे, हम आसानी से खरीद सकते हैं। इसके अलावा मुद्रा के मूल्य में अधिक स्थिरत्व (stability) भी रहता है। अतः मुद्रा मूल्य को संचय करने में बहुत सहायक होती है। भविष्य में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कुछ मुद्रा जोड़कर रखते हैं।

मुद्रा मूल्य-संचय का सुलभ साधन होने के कारण अथवा क्रय-शक्ति होने के कारण आमानी से एक व्यक्ति या स्थान से दूसरे व्यक्ति या स्थान को किसी भी समय भेजी जा सकती है। अतः मुद्रा मूल्य के हस्तांतरण

(transfer of value) का कार्य भी करती है ।

(४) **स्थगित देयमान (Standard for Deferred Payments)**—स्थगित अथवा भविष्यकालीन लेन-देनो के भुगतान का कार्य भी मुद्रा ही करती है । आधुनिक व्यापारिक लेन-देन में साख का अर्थात् ऋण व उधार का बहुत महत्व है । हम प्रत्येक वस्तु के बदले में उसी समय भुगतान नहीं करते बल्कि भविष्य के लिए स्थगित कर देते हैं, अर्थात् उसका भुगतान कुछ समय के बाद भविष्य में करते हैं । इस प्रकार के भुगतान को भविष्यकालीन अथवा स्थगित देय कहते हैं । इस कार्य के लिए भी मुद्रा उपयोग में लार्ई जाती है । मुद्रा एक ऋण-शक्ति है । इसमें अन्य वस्तुएं आसानी से खरीदी जा सकती हैं, उनका मूल्य भी मुद्रा में बदलाया जाता है । इसके अलावा मुद्रा के मूल्य में अधिक स्थायित्व भी रहता है । फलस्वरूप स्थगित देयमान का कार्य जितनी सुगमता और ठीक प्रकार से मुद्रा कर सकती है, उतनी सुगमता में यह कार्य अन्य वस्तुओं द्वारा नहीं हो सकता । इस कारण भावी लेन-देनो का भुगतान मुद्रा के माध्यम द्वारा होता है । इससे व्यापार में, भावी लेन-देन के कार्य में बहुत सुविधा होती है ।

मुद्रा के उपर्युक्त चार मुख्य कार्यों को अंग्रेजी की दो पंक्तियों के पद्य में बड़ी अच्छी तरह व्यक्त किया गया है । वे पंक्तियाँ ये हैं —

“Money is a matter of functions four,  
A medium, a measure, a standard, a store”

मुद्रा के कार्यों के विवेचन से मुद्रा का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट है । मुद्रा किसी विशेष वस्तु की नहीं कहते, अपितु जो वस्तु मुद्रा के उपर्युक्त कार्यों को करती है, वही मुद्रा है । इसमें यह भी स्पष्ट है कि मुद्रा हमारा साध्य नहीं है; यह तो एक साधन है । हम मुद्रा केवल इसलिए चाहते हैं कि इसमें कय-शक्ति है, इसके द्वारा हम इच्छित वस्तुओं पर अधिकार प्राप्त कर सकने हैं ।

### अच्छी मुद्रा-वस्तु की विशेषताएँ

(Qualities of Good Money-Material)

यदि हम मुद्रा के इतिहास का अध्ययन करें तो देखेंगे कि समय-समय पर तम्बाकू, पशु, भमड़ा, कौड़ी इत्यादि वस्तुओं का उपयोग मुद्रा के रूप में हुआ है और अन्त में सर्वमान्य मुद्रा-वस्तु के रूप में सोना तथा चादी का उपयोग होने लगा और आज भी होता है। यह पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों तम्बाकू, पशु, कौड़ी इत्यादि वस्तुओं के स्थान पर सोना और चादी को मुद्रा के लिए ग्रहण किया गया है? इसका उत्तर यह है कि मुद्रा के कार्यों को भली-भाँति और पूर्ण रूप में करने के लिए वस्तु में अनेक आवश्यक गुण व विशेषताएँ होनी चाहिए। ये गुण तम्बाकू, पशु, कौड़ी जैसी वस्तुओं में बहुत कम पाये जाते हैं। फलस्वरूप मुद्रा के रूप में इनका उपयोग धीरे-धीरे बन्द होता गया और अन्त में इनके स्थान पर सोना और चादी को ग्रहण किया गया क्योंकि अच्छी मुद्रा-वस्तु में जो गुण होने चाहिए, वे सब इन दोनों धातुओं में पाये जाते हैं।

अच्छी मुद्रा-वस्तु में निम्नलिखित गुण व विशेषताएँ होनी चाहिए—

(१) सर्वमान्यता (General Acceptability)—सर्वप्रथम अच्छी मुद्रा-वस्तु में सर्वमान्यता का गुण होता चाहिए। वह वस्तु ऐसी हो कि सभी उसे लेन-देन के कार्य में बिना किसी आच या शर्त के स्वीकार करने को तैयार हो। यदि किसी वस्तु में सर्वमान्यता अथवा सर्वग्राह्यता का गुण नहीं है, तो वह मुद्रा का कार्य नहीं कर सकती; अर्थात् मुद्रा के रूप में वह उपयोग में न आ सकेगी।

जैसे तो सरकारी कानून में मुद्रा-वस्तु में सर्वमान्यता की विशेषता आ जाती है, फिर भी यदि उसमें उपयोगिता और आन्तरिक मूल्य है तो वह अधिक आसानी से सर्वत्र सर्वग्राह्य होगी। अतः मुद्रा-वस्तु में, मुद्रा के अतिरिक्त, कुछ अपनी अलग उपयोगिता और मूल्य होना चाहिए जिससे उसे सभी निगमों स्वीकार करने को तैयार रहे।

(२) वहनीयता (Portability)—मुद्रा-वस्तु में वहनीयता का भी गुण होना चाहिए, अर्थात् मुद्रा-वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि उसे सुगमता से और कम खर्च में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके। इस गुण के बिना वह वस्तु मूल्य-हस्तांतरण का कार्य न कर सकेगी जो मुद्रा का एक प्रमुख कार्य है। इन गुण के होने के लिए यह जरूरी है कि वह वस्तु वजन में तो हल्की हो लेकिन मूल्य में भारी हो अर्थात् कम वजन में उसका मूल्य अधिक हो। सोना और चादी में यह गुण विशेष रूप से पाया जाता है।

(३) अविनाशिता (Durability)—अच्छी मुद्रा-वस्तु का तीसरा आवश्यक गुण अविनाशिता अथवा टिकाऊपन है। उसमें टिकाऊपन का गुण होना आवश्यक है जिसमें अधिक समय तक धातु में रहने से उसमें विमादत अधिक न हो। यदि वह वस्तु शीघ्र नष्ट होने वाली है तो वह मुद्रा का कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकेगी, विमेशरूप में मूल्य-नवाग, स्थगित देयमान और मूल्य हस्तांतरण का कार्य।

(४) एकरूपता (Homogeneity)—मुद्रा वस्तु में एकरूपता अथवा समरूपता भी होनी चाहिए। अर्थात् उसमें यह गुण होना चाहिए कि यदि समान वजन व आकार के उसके अनेक टुकड़े किसे जाय तो उनका मूल्य एक ही हो। उनमें छोटने और चुनने की जरूरत न हो और लोग यह न कह सकें कि हम अमुक टुकड़ा व मितका लेंगे और अमुक नहीं। यदि वस्तु में एकरूपता नहीं है तो उसके हर टुकड़े की अलग-अलग जांच करनी पड़ेगी और फलस्वरूप उसके चलन में रुकावट होगी और यह वस्तु मुद्रा का कार्य ठीक प्रकार से न कर सकेगी।

(५) विभाज्यता (Divisibility)—मुद्रा-वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि मूल्य अथवा उपयोगिता में किसी प्रकार की हानि के बिना उसका विभाजन हो सके जिससे थोड़ी रकम के लेन-देन के उपयोग में भी यह आ सके। यदि किसी वस्तु में विभाज्यता का गुण नहीं है अथवा

विभाजन करने से उसका मूल्य कम हो जाता है, तो विभिन्न रकमों के लेन-देन में उसका उपयोग सम्भव न हो सकेगा, फिर वह किस प्रकार विनिमय-माध्यम का कार्य ठीक प्रकार से कर सकेगी। उदाहरण के लिए पशुओं अथवा बहुत कीमती पत्थरों को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त करने से उनका मूल्य बहुत गिर जाता है। इसलिए इनके द्वारा मुद्रा का कार्य भली-भाँति नहीं हो सकता। मोना और चांदी में विभाज्यता का गुण है। मूल्य में कमी न होते हुए, इनके छोटे-बड़े टुकड़े आसानी से हो सकते हैं।

(६) मुज्ञेयता अथवा परिचयता (Cognizability)—मुद्रा-वस्तु ऐसे पदार्थ की बनी होनी चाहिए कि वह बिना किसी कठिनाई के शीघ्र पहिचानी जा सके। वह ऐसी हो कि देखने, छूने अथवा आवाज से वह जल्दी पहिचान में आ जाय और अन्य वस्तुओं से उसकी भिन्नता आसानी से जानी जा सके जिसमें धोखे की सम्भावना कम रहे।

(७) कुट्टयता (Malleability)—साथ ही मुद्रा-वस्तु ऐसे पदार्थ की होनी चाहिए कि उस पर कलापूर्ण चित्र, चिह्न, मोहर इत्यादि आसानी से छापे जा सकें। वह न तो इतनी मुलायम हो कि उस पर जो चिह्न इत्यादि बने वे शीघ्र ही मिट जाय और न इतनी सख्त हो कि निशान व मोहर आदि छापते समय वह टूट जाय।

(८) मूल्य-स्थिरता (Stability in Value)—उत्पत्तियों के अतिरिक्त, मुद्रा-वस्तु में मूल्य-स्थायित्व होना आवश्यक है। उसके मूल्य में स्थिरता होनी चाहिए जिससे वह मुद्रा के मूल्य-गणन तथा स्थगित व्ययमान के कार्यों को कर सके। यदि उसके मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता है, तो लोग उसे मूल्य-मापन के लिए इस्तेमाल न करेंगे क्योंकि हानि होने की सम्भावना रहेगी और न ही लोग भावी भूगतान के लिए उसका उपयोग करेंगे क्योंकि मूल्य के उतार-चढ़ाव के कारण देनदार अथवा लेनदार किसी न किसी को हानि होती ही है। अतः मुद्रा-वस्तु के मूल्य में स्थायी स्थिरता रहना आवश्यक है।

उपभूक्त लगभग सभी गुण एक साथ तोता और चादी में पाये जाते हैं। यही कारण है कि सभी देशों में मुद्रा-वस्तु के रूप में इनका उपयोग शुरू हुआ। धीरे-धीरे मुद्रा के रूप में सोने का चलन हटता जा रहा है और इसके स्थान पर सस्ती धातुओं और पत्र व कागजी मुद्रा का उपयोग बढ़ रहा है।

### धात्विक मुद्रा (Metallic Money)

धात्विक मुद्रा आज-कल सिक्कों के रूप में प्रयोग की जाती है। सिक्के अधिकतर गोल आकार के होते हैं। इनके दोनों तरफ सरकारी चिह्न और मोहर बने होते हैं जिनसे उनकी शुद्धता और मूल्य का बोध होता है। किन्तु पहले-पहल जब धात्विक मुद्रा का चलन शुरू हुआ था, तो उसका यह रूप न था। उस समय धातुएँ, विशेषकर मोना-चादी, छद्म या ईंटों के रूप में मुद्रा का कार्य करती थी। इससे व्यापार में बड़ी असुविधा होती थी क्योंकि भिन्न-भिन्न वजन और मूल्य होने के कारण हर बार उनकी जाँच और तौल करनी पड़ती थी। कुछ दिनों बाद बड़े-बड़े व्यापारी, जिनकी मण्डी में काफी शास होती थी, अपनी मोहरे उन पर छापने लगे जिससे उनके वजन और मूल्य का पता आसानी से चल सके। इससे विविध-क्षेत्र में कुछ असुविधा तो अवश्य दूर हुई, लेकिन धातु के टुकड़ों को घिसने, खुरचने आदि की बेदगानी चलती रही। इस तरह की ठगबाजी में व्यापारियों को अन्ततः बहुत घोसा होता था। इन बुराइयों को दूर करने के लिए धीरे-धीरे सभी देशों में सरकार द्वारा टंकण अथवा सिक्का डलाई का काम होने लगा। आजकल केवल सरकारी टंकनाला में ही सिक्के डाले जाते हैं। यह कार्य अब बहुत वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। सिक्के के किनारे बटे और कुछ उठे होते हैं जिनसे खोज-उड़ के लाभ होते हैं। एक ताँ याद कोई फिनारो को काटे या खुरच तो सीधे ही पता चल जाता है, और



दूसरे सिक्के पर्याप्त समय तक चलते रहते हैं और बहुत कम पिघले हैं। सिक्के के दोनों तरफ बारीक कलापूर्ण चित्र बने रहते हैं जिससे उनकी तकल न की जा सके। लेकिन इतनी उन्नति होने हुए भी वह नहीं कहा जा सकता कि जाली मुद्रा बनाने का काम सरम हो गया है। अब भी लोग प्रायः धोखा खा जाते हैं।

### मिक्का ढलाई अथवा टकण

(Coinage)

टकण अथवा मिक्का ढलाई स्वतन्त्र हो सकती है या परिमित। जब लोगों को यह अधिकार होता है कि वे धातु ले जाकर सरकारी टकसाल में किसी भी मात्रा में सिक्के बनवा सकते हैं, तो उसे "स्वतन्त्र टकण व मिक्का ढलाई" (Free Coinage) कहते हैं। इसके विपरीत जब सिक्का ढलाई का काम केवल सरकारी हाथों पर ही होता है और जनता सरकारी टकसाल से सिक्के नहीं बनवा सकती, तो उसे "प्रतिबन्धित टकण व मिक्का ढलाई" (Restricted coinage) कहते हैं।

यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि "स्वतन्त्र मिक्का ढलाई" का यह अर्थ नहीं है कि सरकार टकण का काम मुक्त करती है। जब सरकार सिक्का ढलाई के लिए लोगों से कुछ भी शुल्क (seignior charge) नहीं लेती तो उसे "मिशुल्क टकण" (gratuitous coinage) कहते हैं। जब यह शुल्क सिक्का बनाने में जो व्यय होता है उसी के बराबर होता है, तो उसे 'टकण-शुल्क' (brassage) कहते हैं। जब सरकार वास्तविक खर्च से अधिक शुल्क लेती है तो उसे टकण-नाश (seigniorage) कहते हैं।

### पत्र व कागजी मुद्रा

(Paper Money)

पत्र व कागजी मुद्रा का चलन काफी पहले से चला आ रहा है, किन्तु आजकल इसका चलन बहुत बढ गया है। आज हर सम्य देश में पत्र-

मुद्रा का उपयोग होता है। यहाँ तक कि अब इसका चलन सम्पत्ता का चिह्न माना जाता है। साधारणतया पत्र-मुद्रा को छापने का अधिकार देश के केन्द्रीय बैंक को होता है, परन्तु कुछ देशों में सरकार स्वयं पत्र-मुद्रा को छापती है। सन् १९३५ में भारतवर्ष में पत्र-मुद्रा के छापने का पूर्णाधिकार रिजर्व बैंक को है जो यहाँ का केन्द्रीय बैंक है। इसके पहले सरकार की ओर से नोट छापे जाते थे।

कागजी मुद्रा निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है —

(१) प्रतिनिधिक पत्र-मुद्रा (Representative Paper Money)—पत्र-मुद्रा का यह सबसे सरल रूप है। प्रतिनिधिक पत्र-मुद्रा जमा की हुई रकम, धातु या धातु-मुद्रा का एक प्रमाण-पत्र व सर्टिफिकेट होती है। नोटों का अंकित मूल्य खजाने में सुरक्षित धातु के बराबर होता है। अर्थात् जितना सोना-चादी या धातु-मुद्रा कोप व खजाने में जमा की जाती है, उतने ही मूल्य के नोट छापे जाते हैं। इस तरह की पत्र-मुद्रा को, जो खजाने में जमा किए हुए मूल्य के प्रमाण-पत्र होती है, प्रतिनिधिक पत्र-मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार की पत्र-मुद्रा के अच्छे उदाहरण अमरीकी स्वर्ण तथा रजत प्रमाण पत्र (American gold and silver Certificates) हैं जिनके बदले में उतनी ही रकम का सोना या चादी अमरीकी खजाने में रखा जाता था।

(२) परिवर्तनीय-पत्र मुद्रा (Convertible or Fiduciary Paper Money)—इसका आशय उस पत्र-मुद्रा से है जिसे किसी भी समय मांग करने पर प्रामाणिक मुद्रा या सोना-चादी में बदला जा सकता है। लोगों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि जब भी चाहें वे पत्र-मुद्रा को धातु-मुद्रा में बदलवा या भुना सकते हैं। लेकिन इस परिवर्तन के लिए यह जरूरी नहीं है कि जितने मूल्य के नोट चलन में हों, उसी के बराबर धात्विक मुद्रा खजाने में रखी जाय क्योंकि सभी लोग पत्र-मुद्रा को एक साथ भुनाने के लिए न लायेंगे। उसका एक

थोड़ा भाग ही एक समय में परिवर्तन के लिए लाया जायगा। इसलिए बैंक या सरकार, जितने मूल्य के नोट छापनी हैं, उसका केवल एक भाग या अंश ही धातु-मुद्रा या धातु के रूप में रखती हैं। फिर भी उनके परिवर्तन या मुदाने में कोई दिक्कत नहीं होती।

(३) अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा (Inconvertible or Fiat Paper Money) — इसका आशय उस प्रकार की पत्र-मुद्रा से है जो अपरिवर्तनीय होती है, जिनको धातु-मुद्रा या मोना-चादी में बदला या भुनाया नहीं जा सकता। इस प्रकार की पत्र-मुद्रा के बदले में सरकार धातु या धातु-मुद्रा देने के लिए कानूनन बाध्य नहीं होती। इस तरह की पत्र-मुद्रा अधिकतर आर्थिक संकट या युद्ध के समय में सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। यह मुद्रा सरकार के हुक्म से चलती हैं। इसका चलन और मूल्य सरकार की आज्ञा पर निर्भर रहता है। इसलिए इसे 'हुक्मी मुद्रा' (Fiat Money) भी कहा जाता है। लोग इसे इसलिए स्वीकार करने हैं कि सरकार पर उन्मत्त विश्वास होता है।

### पत्र-मुद्रा के लाभ और हानियाँ

#### (Advantages and Disadvantages of Paper Money)

पत्र-मुद्रा के उपयोग से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम इसमें बड़ी बचत होती है। इसके उपयोग से सिक्कों की पिसाई बच जाती है। साथ ही सिक्कों के बनाने में जो श्रम और पूँजी लगानी पड़ती है, उसमें भी काफी बचत होती है क्योंकि पत्र-मुद्रा के बनाने में बहुत थोड़ी लागत लगती है। इस प्रकार से बचे हुए श्रम, पूँजी और अन्य साधनों को दूसरे आवश्यक और लाभप्रद स्थानों में लगाया जा सकता है। इसके अलावा नोट बहुत हल्के होते हैं। इनको आसानी से और कम खर्च में दूर-दूर ले जाया जा सकता है। तीसरे, ये किसी भी मूल्य को बनाये जा सकते हैं। इसलिए इनके बिगने, रखने और ले जाने में बड़ी सुविधा होती है। बड़ी से बड़ी रकमों का भुगतान आमानी में पत्र-मुद्रा के द्वारा

किया जा सकता है। चौथे, पत्र-मुद्रा में बहुत अधिक लोच शक्ति होती है। मांग के अनुसार इसकी मात्रा आसानी से घटाई-बढ़ाई जा सकती है। धातु-मुद्रा के साथ ऐसी बात सम्भव नहीं है।

लेकिन पत्र-मुद्रा में कुछ असुविधाये भी होती हैं। खास तौर से जब इसकी लचिल दम से व्यवस्था नहीं की जाती। सबसे बड़ा भय इसके अत्यधिक प्रसारण (over issue) का है। इसके छापने में लागत बहुत कम लगती है। इससे बराबर खर्चा लगा रहता है कि कहीं सरकार इसे अधिक मात्रा में न छाप दे। मकड़ के समय सरकार के सामने मनचाही मात्रा में नोट चलाने का लालच रहता है। जब नोट अत्यधिक मात्रा में चलने लगते हैं, तो वे अपरिवर्तनीय हो जाते हैं। फलस्वरूप इनका मूल्य तंजी में गिरने लगता है। व्यापार में हलचल मच जाती है। चीजों की कीमतें निरन्तर बढ़ने लगती हैं जिसके कारण मजदूर वर्ग, उपभोक्ताओं और बची जाय पाने वाले व्यक्तियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मट्टेबाजी का बाजार गर्म हो जाता है। व्यवसाय का नैतिक आधार टूट जाता है और इस तरह अन्त में सभी को हानि पहुँचती है।

इसके अलावा पत्र-मुद्रा के प्रचलन का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। जिस देश की वह मुद्रा होती है, वही पर वह चलती है, उसके बाहर नहीं। दूसरे देश के लोगों के लिए इसका कोई मूल्य नहीं होता। वे इसे मुगलान में स्वीकार नहीं करते। इस कारण विदेशी व्ययमात्र में कठिनाई पड़ती है। मही नहीं, पत्र-मुद्रा का और कोई दूसरा उपयोग नहीं होता। यदि मुद्रा का रूप इससे छिन्न लिया जाय तो इसका मूल्य कुछ भी न रह जायगा। इसमें अविनाशिता का गुण नहीं है। तेल या पानी से भीग जाने पर नोट क्षीण खराब हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त धातु-मुद्रा की अपेक्षा पत्र-मुद्रा में मूल्य-स्थिरता भी कमी है। मुद्रा-प्रसार के कारण इसका मूल्य स्थायी नहीं रहता, अपितु बदलता रहता है।

## मुद्रा का वर्गीकरण

## (Classification of Money)

मुद्रा का कई दृष्टि से वर्गीकरण किया जा सकता है। यहाँ हम केवल दो-तीन भेदों पर ही विचार करेंगे।

(१) वास्तविक तथा हिसाब की मुद्रा (Actual Money and Money of Account)—वास्तविक मुद्रा उसे कहते हैं जो प्रचलन में है और जिसको देकर सब भुगतान चुकाये जाते हैं। इसी के द्वारा सब कबों और ठेके आदि का भुगतान होता है, और इसी के रूप में अर्थ-शक्ति (purchasing power) रखी जाती है। दूसरी ओर हिसाब की मुद्रा वह है जिसमें हिसाब-खाता रखा जाता है, जिसमें कर्ज, ठेका और कीमतों को अंकित या प्रकट किया जाता है। वास्तविक और हिसाब की मुद्रा का भेद इस प्रकार और स्पष्ट किया जा सकता है। हिसाब की मुद्रा एक वर्णन या नाभ है और वास्तविक मुद्रा स्वयं वह वस्तु है जिसका वर्णन किया जाता है। हिसाब की मुद्रा में सब कर्जों और कीमतों को प्रकट किया जाता है, लेकिन उनका भुगतान वास्तविक मुद्रा में चुकाया जाता है।

(२) कानून-प्राप्त और ऐच्छिक मुद्रा (Legal Tender Money and Optional Money)—जिस मुद्रा को स्वीकार करने के लिए लोग कानूनन बाध्य होते हैं, उसे कानून व विधि-प्राप्त मुद्रा (legal tender money) कहते हैं। कानून अथवा विधि-प्राप्तता सीमित हो सकती है और असीमित भी। जब कोई मुद्रा किसी भी मात्रा में कानूनन चुकाई जा सकती है और लेने वाले मना नहीं कर सकते, तो उसे असीमित कानून-प्राप्त मुद्रा कहते हैं। किन्तु यदि वह एक खास रकम तक ही कानून-प्राप्त है, उसके बाद नहीं, तो वह सीमित कानून-प्राप्त मुद्रा कहलायेगी। भारतवर्ष में रुपया असीमित कानून-प्राप्त मुद्रा है। जिस भी मात्रा में लोग चाहे, इसका द्वारा अपना हिसाब

चुका सकते हैं। देश में इसे स्वीकार करने से कोई भी गना नहीं कर सकता। इकट्ठी तथा दुबली केवल १० रुपये तक ही कानून-ग्राह्य है। इससे अधिक मात्रा में लोग लेने में इन्हें इन्कार कर सकते हैं।

ऐच्छिक मुद्रा ( optional money ) वह है जो विनिमय का माध्यम होती है, जो भुगतान चुकाने में साधारणतः काम आती है लेकिन कानून की दृष्टि से ग्राह्य नहीं होती। इसको स्वीकार करने के लिए किसी को कानून से बाध्य नहीं किया जा सकता। यह तो लोगों की इच्छा पर निर्भर है कि कर्ज आदि का भुगतान करते समय उसे ले मानें के। बैंक-नोट, चेक, आदि ऐच्छिक मुद्रा के उदाहरण हैं। वर्तमान समय में इस प्रकार की मुद्रा का काफी चलन है।

(३) प्रामाणिक और साकेतिक मुद्रा (Standard and Token Money)—प्रामाणिक मुद्रा देश की प्रधान मुद्रा होती है। यह मूल्य का मान होती है। सब कर्ज, ठके और वस्तुओं के मूल्य इसी में जकित और निश्चित किये जाते हैं। वास्तव में यह हिसाब की मुद्रा होती है। रुपया भारतवर्ष का प्रामाणिक मुद्रा है। साधारणतः यह सोना या चांदी का बना हुआ सिक्का होता है। यह असीमित कानून ग्राह्य होता है और इसका अंकित मूल्य इसके वास्तविक मूल्य के बराबर होता है।

इसके विपरीत साकेतिक मुद्रा वह होती है जिसका अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक होता है। इसके बनाने का अधिकार केवल सरकार को ही होता है। सरकार द्वारा इसका प्रचलन होता है और इसका मूल्य स्थिर रखने के लिए इसे सीमित मात्रा में चलाया जाता है। प्रायः यह सीमित कानून-ग्राह्य मुद्रा होती है।

इस दृष्टि से हमारे रुपये की दशा अजीब है। यह देश की प्रधान मुद्रा है। सब मूल्य इसी में अंकित और निश्चित किये जाते हैं। हिसाब पगार भी इसी में रखे जाते हैं। यह असीमित मात्रा में कानून ग्राह्य है। ये सब प्रामाणिक मुद्रा के लक्षण हैं। लेकिन साथ ही इसमें साकेतिक

मुद्रा के भी कुछ लक्षण मौजूद हैं। जैसे इसका अंकित मूल्य इसने वारस-विक मूल्य से कहीं अधिक है। इसमें केवल ५० फीसदी ही चादी है, बाकी मिलावट है। इसकी ढलाई स्वतन्त्र नहीं है। सरकार द्वारा ही इसका प्रचलन होता है। इन्हीं कारणों से रुपये को प्रामाणिक-आवैतिक सिक्का कहा जाता है।

### ग्रेशम का मुद्रा सम्बन्धी सिद्धान्त

(Gresham's Law of Money)

‘ग्रेशम के मुद्रा सम्बन्धी सिद्धान्त की, संक्षेप में, इन शब्दों में व्याख्या की जा सकती है “बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से भगा देती है।” सर टामस ग्रेशम इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के अर्थ-सलाहकार थे। कहा जाता है कि उन्होंने ही इस सिद्धान्त की स्थापना की थी। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। ग्रेशम के पहले और कई विद्वानों ने इस सिद्धान्त का उल्लेख किया था, खास तौर से निकोलस ओरमेस ने जो फ्रांस के थॉर्न पंचम बादशाह के मंत्री थे। किसी तरह इसका नाम “ग्रेशम का सिद्धान्त” पड़ गया। मुख्य रूप से मैक्लूड (MacLude) ने इसे ग्रेशम के सिद्धान्त के नाम से प्रचलित किया।

इस सिद्धान्त के अनुसार “जब किसी देश में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की मुद्राएँ एक साथ चलन में होती हैं और दोनों पूर्ण कानून ब्राह्म होती हैं, तब बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से भगा देती है, अर्थात् उसका चलन सत्पन्न कर देती है।” यहाँ यह ध्यान रहे कि बुरी मुद्रा का अर्थ जाली व छोटे सिक्कों से नहीं है। इसका आशय उन मुद्राओं व सिक्कों से है जिनका धातु-मूल्य हल्का, कम व सस्ता होता है। उदाहरण के लिए यदि चादी के सिक्के चलन में हैं तो नये व भारी भिक्कों को अच्छी मुद्रा कहेंगे और पुराने, पिसे हुए सिक्कों को बुरी मुद्रा। अब प्रश्न यह है कि बुरी मुद्रा किस तरह अच्छी मुद्रा को प्रचलन से भगा देती है? इसको समझना कठिन नहीं है। सर्वप्रथम, यदि पिसे हुए सिक्कों के देने में कोई

बढ़चन नहीं है, तो लोग अच्छे और नए सिक्के अपने पास रखने की कोशिश करेंगे और पुराने तथा धिसे हुए सिक्को को प्रचलन में रक्खेंगे। जिस किसी को मूल्य-संचय करने की इच्छा होगी, वह अवश्य ही नये और भारी सिक्को को ही चुनकर संग्रह करेगा। फलस्वरूप कुछ भारी सिक्के लोगों के संचय व जमा करने के कारण प्रचलन से हट जायेंगे। दूसरे, जब अच्छी और बुरी दोनों मुद्राएँ एक साथ चलन में होती हैं तब लोग अच्छी मुद्राओं को प्रायः पिघला डालते हैं और फलस्वरूप बुरी मुद्रा ही प्रचलन में रह जाती है और अच्छी मुद्रा पिघलाने के कारण खरब हो जाती है। यदि किसी को मुद्रा पिघला कर धातु की आवश्यकता है तो वह निश्चय ही नये और भारी सिक्को को ही पिघलायेगा क्योंकि उनमें पुराने सिक्को की अपेक्षा अधिक धातु-मूल्य होता है। पुराने सिक्को का वजन धिसने इत्यादि के कारण कुछ कम हो सकता है। तीसरे, भारी व नये सिक्के विदेशी व्यापार के भुगतान में उपयोग होकर प्रचलन से बाहर हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि एक देश की मुद्रा को विदेशी उसके लिखित मूल्य पर नहीं बल्कि उसके धातु-मूल्य के हिसाब से लेते हैं, अर्थात् वे तोलकर वजन के हिसाब से सिक्के लेते हैं। अच्छी और पुरानी मुद्रा का लिखित व विविधय मूल्य तो एक ही होता है, लेकिन उनके वास्तविक व धातु-मूल्य में थोड़ा अन्तर होता है। यदि विदेशी व्यापारियों को नये सिक्कों में भुगतान किया जाय तो भारी होने के कारण अपेक्षाकृत कुछ कम सिक्को में ही काम चल जायगा। इसलिए लोग पूरे वजन के नये सिक्के बाहर भेजेंगे। इस प्रकार अच्छी मुद्रा जमा करने, पिघलाने तथा विदेशी माल के भुगतान करने में लुप्त हो जाती है और प्रचलन में बुरी मुद्रा ही रह जाती है। इसी के आधार पर यह कहा जाता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से हटा देती है।

यह सिद्धान्त कुछ परिस्थितियों में लागू नही होता। एक तो उस समय जबकि अच्छी और बुरी मुद्रा की कुल पूर्ति मुद्रा की कुल माग से कम हो। यदि मुद्रा की कुल पूर्ति उसकी कुल माग से कम है अर्थात् जितनी मुद्रा की



समाज में आवश्यकता है उससे मुद्रा की मावा व पूर्ति कम है, तो अच्छी धीर बुरी दोनों प्रकार की मुद्राएँ एक साथ प्रचलन में बनी रहेंगी। प्रेषण का मिद्धान्त क्रियाशील न हो सकेगा। दूसरे, यदि सब लोग बुरी मुद्रा की स्वीकार करने से मना करने लगें तो ब्रज दशा में भी यह सिद्धान्त क्रियाशील न होगा। उन परिस्थिति में बुरी मुद्रा स्वयं प्रचलन से बाहर हो जायगी।

### मुद्रा का महत्त्व

(Importance of Money)

आधुनिक आर्थिक समाज में मुद्रा की महान् महत्त्व प्राप्त है। वर्तमान आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का ठाँवा बहुत-बहुत इसी पर आश्रित है। मुद्रा आज हमारे जीवन का इतना आवश्यक अंग बन गई है कि इसके बिना शायद कोई भी काम ठीक प्रकार से नहीं चल सकता। निरसादेह इसकी अनुपस्थिति में प्रगति धीमी पड़ जायगी और सम्म जीवन की अनेक अच्छाइयों और विशेषताओं से हमें हाथ धोना पड़ेगा।

उपभोग, विनिमय, वितरण आदि सभी क्षेत्रों में मुद्रा के उपयोग से बहुत गह्रायता मिलती है। इसके माध्यम द्वारा उपभोगता अपनी आवश्यकता की विभिन्न वस्तुएँ जब और जितनी मात्रा में चाहे खरीद सकता है और इस प्रकार वह अपनी आय से अधिकतम तृप्ति प्राप्त कर सकता है। अधिकाधिक तृप्ति प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सम-मीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त के अनुसार खरीद की जाय, अर्थात् खरीदी गई हुई वस्तुओं की मीमान्त उपयोगिताएँ एक समान हों। यह कार्य मुद्रा के द्वारा ही ठीक प्रकार से सम्भव हो सकता है। मुद्रा ने वस्तु-विनिमय की अनेक कठिनाइयों को दूर कर दिया है। वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय, उनके मूल्यों का निर्धारण और तुलना मुद्रा के माध्यम द्वारा बहुत सरल और सुविधाजनक हो गया है। इसके कारण मण्डियों का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। मुद्रा के उपयोग के कारण तथा विनिमय पद्धति में सुधार होने से ही बड़े-बड़े कारखाने तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन

सम्भव हो सका है और उद्योगों में श्रम-विभाजन का अधिकाधिक सहारा लिया जा सका है। आजकल अनेक व्यक्तियों को मिलकर, अनेक साधनों को जुटाकर उत्पादन-कार्य चलाया जाता है। व्यक्तियों अथवा साधनों का यह एकत्रीकरण मुद्रा के द्वारा ही सम्भव हुआ है। श्रम, पूँजी, आदि की सेवाओं का मूल्य मुद्रा के रूप में आसानी से दिया जा सकता है। इसके अलावा मुद्रा के द्वारा पूँजी के निर्माण में बहुत सहायता मिलती है और उसकी गतिशीलता भी बढ़ जाती है। पूँजी की वृद्धि और गतिशीलता देश की आर्थिक उन्नति और विकास के लिए कितनी आवश्यक है, यह सभी को मालूम है। इसके बिना उत्पादन कार्य ठीक तरह से नहीं चल सकता और न ही देश आर्थिक उन्नति के पथ पर तेजी से बढ़ सकता है।

मुद्रा से एक और लाभ है। इसके द्वारा लोगों की मात्रा का ठीक-ठीक अनुमान लगाया जा सकता है और उनके अनुसार यह निश्चित किया जा सकता है कि कौन-कौन सी वस्तुएँ, कब और कितनी मात्रा में तैयार की जायें। इस तरह माग और पूर्ति के बीच उचित तालमेल अथवा सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, मुद्रा के उपयोग से स्पर्धा तथा अनुबंध (Contract) ने हडियों को बहुत-कुछ हटा दिया है और फलस्वरूप मनुष्य की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि में स्वतन्त्र बना दिया है। अस्तु, मुद्रा का महत्त्व तथा इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले लाभ स्पष्ट हैं। इसे आर्थिक उन्नति और सम्यता का चिह्न माना जाने लगा है।

कहने का सारांश यह नहीं है कि मुद्रा में कोई दोष नहीं है। इतने सब लाभ होने हुए भी मुद्रा में कुछ दोष अवश्य हैं। आर्थिक कार्यों का आधार तथा मूल्य का मान होने के कारण, इसके मूल्य के छोटे-से भी उतार-चढ़ाव से समाज पर भयंकर परिणाम होता है। बाजार की तेजी-मंदी, दोषपूर्ण वितरण तथा व्यापारिक अतृप्तता आदि बातों में मुद्रा का

काफी हाथ होता है। फिर भी मुद्रा कोई दूरी वस्तु नहीं है। इसका दोषों को समुचित व्यवस्था द्वारा दूर किया जा सकता है।

### QUESTIONS

- 1 What is money ? Explain its main functions
- 2 What are the qualities of good money ? Why are gold and silver regarded as good money ?
- 3 What are the chief merits and demerits of paper money ?
- 4 State and explain Gresham's Law of money Under what conditions does it not hold good ?
- 5 Distinguish between standard and token money Examine in this respect the position of the Indian Rupee
- 6 Write short notes on —
  - (a) Actual money and money of account
  - (b) Legal tender money and optional money
- 7 Bring out the importance of money in the present day economic society

## मुद्रा का मूल्य (Value of Money)

किसी वस्तु के मूल्य का अर्थ यह होता है कि उसके बदले या विनिमय में दूसरी वस्तु कितनी मिल सकती है। जैसे यदि एक मेज के बदले में दो कुर्सियाँ मिलें तो हम कहेंगे कि मेज का मूल्य दो कुर्सियों के बराबर है। ठीक यही अर्थ मुद्रा के मूल्य का होता है। इसका आशय मुद्रा की क्रय-शक्ति (purchasing power) से है। जो कुछ चीजें मुद्रा के बदले में मिल सकती हैं या खरीदी जा सकती हैं, वही मुद्रा का मूल्य है। मुद्रा का मूल्य अथवा उसकी खरीदने की शक्ति मूल्य-स्तर (price level) पर निर्भर होती है। यदि मूल्य-स्तर उँचा है, तो मुद्रा की एक इकाई से कम चीजें खरीदी जा सकेंगी। फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य कम होगा। और यदि मूल्य-स्तर नीचा है, तो मुद्रा की एक इकाई से अधिक माना में चीजें मिल सकेंगी। इस कारण मुद्रा का मूल्य अधिक होगा। इसमें यह स्पष्ट है कि मुद्रा के मूल्य या क्रय-शक्ति और मूल्य-स्तर में विरोधी सम्बन्ध होता है। जब एक घटता है तब दूसरा बढ़ता है।

सचक-अंक

(Index Numbers)

मुद्रा मूल्य का मापक है। सब वस्तुओं का मूल्य इसी में निश्चित किया जाता है और मूल्यों की तुलना आदि भी इसी के द्वारा होती है। फिर भला मुद्रा के मूल्य को कैसे मापा जाय? प्रत्यक्ष रूप में यह सम्भव नहीं है क्योंकि मुद्रा स्वयं ही मूल्य का मापक है। कोई ऐसी एक वस्तु नहीं है जिसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप में मुद्रा के मूल्य की माप और तुलना की जा

सके। हा, परोक्ष रूप में मूल्य-स्तर अथवा कीमत को मात्तूम करके मुद्रा का मूल्य निश्चित किया जा सकता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है मूल्य-स्तर और मुद्रा के बीच उल्टा सम्बन्ध है। जब मूल्य-स्तर गिरता है, तो मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है और जब मूल्य-स्तर बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य गिरता है। अस्तु, मूल्य-स्तर के स्तर को देखकर मुद्रा के मूल्य का बोध हो सकता है। इस तरह से मुद्रा के मूल्य को मात्तूम करने के तरीके को अर्थशास्त्र में 'सूचक-अंक' अथवा 'मूल्य-निर्देशक' कहते हैं।

सूचक-अंक मूल्य-स्तरो की एक सूची होती है जिससे मूल्य-स्तर में जो समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं मात्तूम किए जा सकते हैं और फिर उनके द्वारा मुद्रा के मूल्य का पता चल सकता है। यह एक कोष्ठक के रूप में तैयार किया जाता है। तैयार करते समय एक आधार-काल (base period) ले लिया जाता है और कुछ चीज चुन ली जाती हैं। उन चीजों के मामले उनके मूल्य लिख लिए जाते हैं और उनका औसत निकाल लिया जाता है। फिर अन्य कालों के मूल्यों को उस आधार-काल के मूल्यों से तुलना करके मूल्य-स्तर अथवा मुद्रा के मूल्य के परिवर्तनों को मात्तूम किया जा सकता है। एक उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट हो जायगा।

वस्तुएँ	१९३५ (आधार काल)		१९५३	
	कीमत	सूचक अंक	कीमत	सूचक अंक
गेहूँ	४६० प्रतिमन	१००	१८६० प्रति मन	४५०
घी	४० " "	१००	२०० " " "	५००
दूध	५ " "	१००	३० " " "	६००
कपडा	८ आना प्रति गज	१००	२ " प्रति गज	४००
ईंधन	१२ " प्रति मन	१००	३ " प्रति मन	४००
चीनी	१०६० प्रति मन	१००	३५ " " "	३५०
औसत		६१० ÷ ६ = १००		२७०० ÷ ६ = ४५०

इस सूचक-अंक में सन् १९३५ और सन् १९५३ के कुछ वस्तुओं के मूल्यों की तुलना की गई है। सन् १९३५ में वस्तुओं का मूल्य १०० के बराबर था और सन् १९५३ में यह बढ़कर ४५० हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि मूल्य-स्तर में ३५० प्रतिशत की वृद्धि हुई, अर्थात् मुद्रा के मूल्य में ३५० प्रतिशत की घटी हुई। इस तरह विभिन्न कालों में मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को मालूम किया जा सकता है।

सूचक-अंक तैयार करने में अनेक कठिनाइयाँ सामने आती हैं। इस कारण इनको तैयार करते समय बहुत देखभाल और सावधानी की जरूरत होती है। सर्वप्रथम कठिनाई आधार-काल को चुनते समय उठती है। यह बहुत जरूरी है कि आधार काल पूर्ण रूप से साधारण और सामान्य हो। दूसरी कठिनाई वस्तुओं के चुनाव के सम्बन्ध में होती है। दिक्कत इस बात में होती है कि सूचक-अंक तैयार करने के लिए कौन-कौन और कितनी वस्तुएँ चुनी जाय। निःसंदेह वस्तुओं को चुनते समय हमें यह देखना होगा कि सूचक-अंक किस बात के लिए, किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किये जा रहे हैं। उसी के अनुसार वस्तुओं का चुनाव करना होगा। यह आवश्यक है कि जो वस्तुएँ चुनी जाय, वे उम्र वर्ग के लोगों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं का उचित रूप से प्रतिनिधित्व कर सकें। उन्हीं वस्तुओं को सूचक-अंक में शामिल करना चाहिए जिनकी उस वर्ग के लोगों में अधिकाधिक मांग हो। फिर कीमतों के सम्बन्ध में भी कठिनाई उत्पन्न होती है। वह यह है कि थोक मूल्यों को लिया जाय या फुटकर मूल्यों को? यहाँ भी हमें यही देखना होगा कि सूचक-अंक किस उद्देश्य से बनाये जा रहे हैं, यदि सूचक-अंक जीवन-स्तर का खर्च मापन के लिए बनाये जा रहे हैं तो फुटकर मूल्यों को लेना अच्छा होगा। कारण, साधारण उपभोक्ता वस्तुओं को फुटकर मूल्यों पर खरीदते हैं, थोक मूल्यों पर नहीं। इन कठिनाइयों के अतिरिक्त औसत निकालने की कठिनाई रहती है कि कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाय। औसत निकालने की भिन्न-भिन्न विधियाँ हैं और उनसे भिन्न-भिन्न परिणाम निकल सकते हैं।

मूल्य-निर्देशक अथवा सूचक-अंक के बनाने से विभिन्न प्रकार के लाग प्राप्त होते हैं। इनकी सहायता से मूल्य-स्तर अथवा क्रय-शक्ति में होने वाले परिवर्तन मालूम किये जा सकते हैं। इन परिवर्तनों की जानकारी बहुत उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है। इसके द्वारा भिन्न-भिन्न समय पर लोगों के जीवन-स्तर के परिवर्तनों को जाना जा सकता है। इसमें यह मालूम हो सकता है कि लोगों की आर्थिक दशा सुधर रही है या नहीं और उनके अनुसार आर्थिक नीति में मनुषित परिवर्तन लाया जा सकता है। श्रमता की आय तथा धमिकों के वेतन में क्रय-शक्ति के परिवर्तन से क्या-कितना अन्तर पड़ता है, इसकी जानकारी से मजदूरी एवं आय में आवश्यक समायोजन ( adjustment ) करना सम्भव हो जाता है। इसी प्रकार दीर्घकालीन ऋणों के न्यायपूर्ण भुगतान करने में भी सूचक-अंक सहायक हो सकते हैं क्योंकि इनके द्वारा क्रय-शक्ति की कमी या वृद्धि का माप मिलता है। कीमतों के परिवर्तन के कारण व्यापार और उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी सूचक-अंक से हो सकती है, और फिर इसके आधार पर मूल्य-स्तर स्थिर रखने तथा व्यापार में स्वायत्तत्व लाने के लिए उचित नीति अपनाई जा सकती है। अस्तु, हर दृष्टि से सूचक-अंक बहुत उपयोगी होते हैं। यही कारण है कि आज सभी सम्म देशों में विभिन्न प्रकार के सूचक-अंक तैयार किये जाते हैं।

### मुद्रा का मूल्य-निर्धारण

(Determination of Value of Money)

मूल्य-निर्धारण के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी माग और पूर्ति के आधार पर निर्दिष्ट होता है। ठीक इसी तरह मुद्रा का मूल्य भी निर्धारित होता है। अर्थात् मुद्रा का मूल्य उसकी माग और पूर्ति के आधार पर निर्दिष्ट होता है। लेकिन मुद्रा की माग और पूर्ति में कुछ खाम होते हैं जिनके कारण मुद्रा के मूल्य-निर्धारण सिद्धान्त को एक अलग दर्ज में रखता जाता है। मक्षेप में, हम

यह मुद्रा की माग और पूर्ति का अलग-अलग अध्ययन करेंगे।

**मुद्रा की माग**—मुद्रा विनिमय का माध्यम है। इससे अन्य वस्तुएँ खरीदी जा सकती हैं। इसलिए मुद्रा की माग विनिमय की आवश्यकता के कारण अथवा अन्य वस्तुओं की माग के कारण होती है। जितनी कम या अधिक विनिमय की आवश्यकता होगी या व्यापार का परिमाण होगा, मुद्रा की माग उतनी ही कम या अधिक होगी। व्यापार के परिमाण में वृद्धि होने से मुद्रा की माग बढ़ेगी और व्यापार के कम होने पर, मुद्रा की माग घटेगी। लेकिन जितनी वस्तुएँ उत्पन्न की जाती हैं, उन सभी का मुद्रा द्वारा विनिमय नहीं होता। कुछ तो उत्पादक स्वयं ही उपभोग कर लेते हैं और कुछ का प्रत्यक्ष रूप में विनिमय हो लेता है। इनसे मुद्रा की माग पैदा नहीं होती। उत्पादन के केवल उसी भाग में मुद्रा की माग निक्षिप्त होती है जिसका विनिमय मुद्रा में होता है। मुद्रा की माग के सम्बन्ध में एक बात विशेष रूप में ध्यान देने योग्य है। वह यह है कि मुद्रा की माग की लोच समानुपात (unitary) होती है। अन्य वस्तुओं की माग की लोच में इस विशेषता का होना आवश्यक नहीं है। इसका अर्थ, संक्षेप में, यह होता है कि मुद्रा की पूर्ति और उसकी न्य-क्षिप्त का गुणनफल एक समान रहता है। इसी के आधार पर मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त स्थापित है।

**मुद्रा की पूर्ति**—मुद्रा की कुल मात्रा को मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। इसमें नोट्स, नोट, और बैंकों के जमा भी शामिल हैं। साथ ही हमें मुद्रा के चलन के वेग (velocity of circulation) को भी ध्यान में रखना होगा। जितनी दूर मुद्रा की एक इकाई का एक निश्चित काल में विनिमय अथवा हस्तांतरण होता है, वह चलन का वेग कहलाता है। मुद्रा की मात्रा जो चलन में है, उसको चलन के वेग से गुणा करने पर जो गुणनफल निकलेगा, वही मुद्रा की वास्तविक पूर्ति होगी। जैसे यदि १०० करोड़ चलन में है, और प्रत्येक रुपया पाँच बार उपयोग



अथवा हस्तान्तरित होता है, तो मुद्रा की कुल पूर्ति  $100 \times 4 = 400$  रु० होगी।

### मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त

(Quantity Theory of Money)

मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त मुद्रा की पूर्ति और उसके मूल्य के बीच सम्बन्ध स्थापित करता है। यह बतलाता है कि अन्य बातों के समस्थिति रहने पर मुद्रा का मूल्य मुद्रा की पूर्ति के उल्टे अनुपात में घटता-बढ़ता है। मुद्रा की पूर्ति यदि २० प्रतिशत में बढ़ा दी जाय, तो अन्य बातों के पूर्ववत् रहने पर मुद्रा का मूल्य २० प्रतिशत से घट जाएगा और मूल्य-स्तर २० प्रतिशत से बढ़ जायगा। इसी प्रकार यदि मुद्रा की पूर्ति आधी कर दी जाय तो मुद्रा का मूल्य दुगुना हो जायगा और वस्तुओं की कीमतें आधी हो जायगी।

एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी। मान लो चलन में कुल १०० रु० हैं और बिस्त्रों के लिए लाई हुई वस्तुओं की संख्या भी १०० है। साथ ही यह भी मान लो कि प्रत्येक वस्तु का अर्ध-विवरण मुद्रा में होता है और हर रुपये केवल एक बार हस्तान्तरित होता है। ऐसी दशा में औसत कीमत एक रुपये होगी। मान लो कि अब रुपये की मात्रा दुगुनी हो जाती है और वस्तुओं की मात्रा या संख्या उतनी ही रहती है। ऐसा होने पर औसत कीमत २ रुपये हो जायगी और मुद्रा का मूल्य आधा रह जायगा। यदि रुपये की मात्रा घटाकर ५० कर दी जाय, तो मुद्रा का मूल्य दुगुना हो जायगा और औसत कीमत आधी रह जायगी। इससे यह स्पष्ट है कि मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होने से मुद्रा के मूल्य में उसी अनुपात में लेकिन विरोधी दिशा में और वस्तुओं की कीमतों में उसी अनुपात में सीधा परिवर्तन होता है। संक्षेप में, मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त यही बतलाता है।

साधारणतः इस सिद्धान्त को बीजगणितीय समीकरण के रूप में

स्पष्ट किया जाता है। पहले इसका रूप इस प्रकार था—

$$M V = P T, \text{ अथवा } P = \frac{M V}{T}$$

यहां  $M$  का अर्थ मुद्रा की मात्रा में,  $V$  का चलन के वेग से,  $P$  का मूल्य-स्तर से और  $T$  का व्यापार की मात्रा से है। इस समीकरण के दो पक्ष हैं (१) मुद्रा का पूर्ति-पक्ष ( $M V$ ) और वस्तुओं अथवा माप का पक्ष ( $P T$ )। ये दोनों पक्ष अपेक्ष्य ही बराबर होंगे। व्यापार की मात्रा को कीमतों से गुणा करने पर जो गुणगण्य आयेगा (अर्थात्  $P T$ ) वह निश्चय ही मुद्रा की कुल पूर्ति (अर्थात्  $M V$ ) के बराबर होगा। लेकिन धातु-मुद्रा के अलावा बैंक-मुद्रा भी विनिमय के वायों में उपयोग होती हैं। इसलिए बैंक-मुद्रा और उनके चलन के वेग को भी मुद्रा की कुल पूर्ति में शामिल करना आवश्यक है। यदि बैंक-मुद्रा  $M^1$  है और उसके चलन का वेग  $V^1$  है तो इस सिद्धान्त को इस रूप में रखा जा सकता है

$$M V + M^1 V^1 = P T$$

$$\text{अथवा } P = \frac{M V + M^1 V^1}{T}$$

इस समीकरण में  $P$  परिणाम है और बाकी सब अज्ञात कारण हैं। मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त यह बतलाता है कि एक निश्चित समय में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से  $T$ ,  $V$  और  $V^1$  में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वे स्थायी रहते हैं, बदलते नहीं। साथ ही  $M$  और  $M^1$  के बीच का अनुपात भी वैसा ही बना रहता है। इस कारण  $M$  जो परिवर्तन होगा, ठीक वही परिवर्तन  $P$  अर्थात् मूल्य-स्तर में होगा। और चूंकि मूल्य-स्तर और मुद्रा

$$M V = P T, \text{ Or } P = \frac{M V}{T}$$

$$\text{याद में रखता रूप } M V + M^1 V^1 = P T$$

$$\text{Or } P = \frac{M V + M^1 V^1}{T}$$

का मूल्य एक दूसरे के विपरीत घटते-बढ़ते हैं, इसलिए मूद्रा के मूल्य में उल्टे अनुपात में परिवर्तन होगा। ममझने के लिए एक उदाहरण लिया जा सकता है।

मान लो  $m = 200$ ,  $v = 3$ ,  $m^1 = 100$   $v^1 = 2$  और  $T = 400$  है। चूंकि  $m + m^1 + v^1 = T$ , इसलिए  $200 \times 3 + 100 \times 2 = 7 \times 400$  होगा। समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जायेंगे ही, फलस्वरूप  $p = 2$  होगा।  $p$  पर प्रभाव देखने के लिए  $m$  और  $m^1$  को दुगुना कर दो लेबिन अन्य बातों ( $v$ ,  $v^1$  और  $T$ ) में कोई परिवर्तन न हो।

$$400 \times 3 + 200 \times 2 = 7 \times 400$$

दोनों पक्षों को बराबर रखने के लिए  $p$  को अवश्य ही दुगुना होना पड़ेगा। अस्तु अन्य बातों के पूर्ववत् रहने पर, मूद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने में मूल्य-स्तर में सीधे उभी अनुपात में परिवर्तन होगा और मूद्रा का मूल्य उभी अनुपात में उट्टी दिशा में बढ़ेगा।

कई विद्वानों ने इस सिद्धान्त की बड़ी कड़ी आलोचना की है। अपने प्रधान आलोचना यह है कि इसमें यह मान लिया जाता है कि अन्य बातें एक-ही रहती हैं जो वास्तविक जीवन में एक-सी नहीं रह पाती।  $m$  में परिवर्तन होने में  $v$ ,  $v^1$  और  $T$  में भी परिवर्तन होता है।  $p$  के परिवर्तनों का प्रभाव  $T$  और  $v$  पर पड़ता है। वास्तव में समीकरण के विभिन्न अंश स्वतन्त्र नहीं हैं। वे एक-दूसरे में प्रभावित होते हैं। इसलिए यह मान लेना कि  $m$  का  $v$  या  $T$  पर प्रभाव न पड़ेगा ठीक नहीं है। उभी प्रकार  $m$  और  $m^1$  में हमेशा एक-सा सम्बन्ध नहीं रहता, लेकिन परिमाण निश्चय में यह मान लिया जाता है कि दोनों के बीच एक स्थायी सम्बन्ध होता है। और फिर परिमाण-सिद्धान्त में जो मूद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर में आनुपातिक सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, इन बातों के आधार पर साथ नहीं ठहरता। अर्थात् मूद्रा की मात्रा को दुगुना करने

से मूल्य-स्तर हमेशा दुगुना नहीं हो जाता। इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि यह सम्बन्ध दीर्घकाल में दिखाई देगा। लेकिन दीर्घकाल में तो हम सब मर भी सकते हैं।

इस सिद्धान्त में एक यह भी कमजोरी है कि हमने प्रति-पक्ष पर अल्प-धिक बल दिया गया है। साथ ही यह स्पष्ट नहीं होता कि मुद्रा की मात्रा का प्रभाव मूल्य-स्तर पर किस तरह में पड़ता है।

यह सब मानते हुए भी यह कहना ठीक न होगा कि यह सिद्धान्त बिल्कुल गलत या व्यर्थ है। इस सिद्धान्त से हमें यह मान्य पड़ता है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तनों का क्या-क्या प्रभाव होता है। इसके द्वारा मूल्य-स्तर को स्थिर रखने का एक रास्ता मान्य पड़ जाता है।

### मुद्रा के मूल्य-परिवर्तनों के परिणाम

(Effects of Changes in the Value of Money)

जैसा कि उपर कहा जा चुका है, मुद्रा मूल्य का मापक है, यह मूल्य-सत्य तथा म्यगित देयमान का भी माप करती है। अतः इसके मूल्य में होने वाले परिवर्तन में आर्थिक और सामाजिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। यह प्रभाव सब तरफ एक-सा न पड़ कर, भिन्न-भिन्न वर्ग के लोगों पर अलग-अलग पड़ता है। यहाँ तक कि एक ही व्यक्ति पर विभिन्न दिशाओं में मुद्रा के मूल्य-परिवर्तनों का परिणाम भिन्न-भिन्न होता

\*इस सम्बन्ध में मुद्रा-स्फीति (inflation) और मुद्रा-संकोच (deflation) के अर्थ को समझ लेना आवश्यक है। जब मुद्रा की मात्रा की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति अधिक होने के कारण वस्तुओं का मूल्य-स्तर बढ़ने लगता है और मुद्रा का मूल्य गिरने लगता है, तब उसे मुद्रा-स्फीति कहते हैं। इसके विपरीत जब मात्रा की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति कम होने से वस्तुओं का मूल्य-स्तर गिरने लगता है और मुद्रा का मूल्य बढ़ने लगता है—तब उसे मुद्रा-संकोच कहते हैं। अर्थात् मुद्रा-स्फीति की दशा में मूल्य-स्तर बढ़ने लगता है और मुद्रा-संकोच की दशा में मूल्य-स्तर घटने लगता है।

है। सामान्य रूप से मुद्रा के मूल्य के घटने-बढ़ने\* का अथवा कीमतों के उतार-चढ़ाव का परिणाम अन्ततः घरा ही होता है। इससे आर्थिक क्षेत्र में अतिरिच्यता आ जाती है, सावर्ष बढ़ता है, और विश्वास उठने लगता है। कुछ की आसानी निराशाओं में परिणित हो जाती है और कुछ दिना बीये ही काट पाते हैं। इन सब बातों से व्यापार और व्यवसाय को बहुत धक्का लगता है और आर्थिक उत्थान रुक जाती है। साथ ही अनेक सामाजिक समस्याएँ पैदा होती हैं जिनके शिक्षकों से बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। संक्षेप में, हम यहां यह देखेंगे कि मुद्रा के मूल्य-परिवर्तनों का ऋणी, ऋणदाता, उत्पादक, व्यापारी, श्रमिक आदि वर्गों पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है।

जिस समय मुद्रा का मूल्य गिरता है अर्थात् कीमत बढ़ती है, उन समय कर्जदार का लाभ होता है और कर्ज देन वाला का हानि। यह इसलिए नहीं कि कर्जदार कम रकम लौटाने है। रकम तो व पूरी लौटाते हैं,

\* यहाँ यह पूछा जा सकता है कि मुद्रा का मूल्य कम और कीमतें बढ़ती हैं। अन्य वस्तुओं के मूल्यों की तरह, मुद्रा का भी मूल्य मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण घटता-बढ़ता है। जब उत्पादन, व्यापार आदि में वृद्धि होने से मुद्रा की मांग बढ़ जाती है और मुद्रा का परिमाण उतना ही रहता है अथवा मुद्रा की मांग के उतने ही रहने पर मांग, पत्र-मुद्रा या धातु-मुद्रा के कम होने के कारण मुद्रा का कुछ परिमाण पहले से कम हो जाता है, तब मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और कीमतें गिरने लगती हैं। इसके विपरीत जब मांग, पत्र-मुद्रा व धातु-मुद्रा की मात्राएँ बढ़ाने से मुद्रा का कुल परिमाण बढ़ जाता है और उत्पादन, व्यापार आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता अर्थात् मुद्रा की मांग उतनी ही रहती है अथवा जब मुद्रा के परिमाण में कमी न होते हुए, उत्पादन आदि के घटने के कारण मुद्रा की मांग गिर जाती है, तब मुद्रा का मूल्य कम होने लगता है अथवा कीमतें बढ़ने लगती हैं।

लेकिन उसका वास्तविक मूल्य पहले की अपेक्षा कम होता है। जो कुछ साहूकार को मिलता है उसमें वह उतना नहीं खरीद सकता जितना वह कज देने समय वह खरीद सकता था। क्योंकि कीमतों के बढ़ने से मुद्रा की शक्ति गिर गई है। इससे विपरीत जब कीमत गिरती है तब कजदार को हानि होती है और साहूकार लाभ में रहता है। कजदार उतनी ही रकम लौटाता है पर वस्तुओं अथवा कम शक्ति का रूप में वह अधिक लौटाता है। मजदूर की शक्ति बढ़ जाने से साहूकार को लाभ होता है क्योंकि अब वह ठीका अधिक वस्तुएं खरीद सकता है।

जब कीमतों के समय व्यवसायी अथवा उत्पादक को लाभ होता है और गिरती हुई कीमतों के समय में वह हानि होती है। जब कीमत बढ़ती है तब उत्पादन को लाभ होता है क्योंकि उत्पादन व्यय नहीं इतनी तर्ज़ में और न कम मीमांसा बढ़ता है जितनी कि वस्तुओं का कीमत बढ़ती है। इससे अलावा अधिकतर वे उद्योग भी हैं जहाँ से काम करता है अर्थात् वे कजदार होते हैं और चूंकि कजदार एवं मजदूर में लाभ में रहता है इसलिए उनका लाभ और भी बढ़ जाता है। काम की मात्रा बढ़ जाने से वह उत्पादन का परिमाण बढ़ा देते हैं जिससे लोगों को अधिक काम मिलने लगता है। जब कीमत गिरती है तब इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। उनका लाभ कम हो जाता है। उन्हें हानि होने लगती है। फलस्वरूप उत्पादन घटा दिया जाता है जिससे दूसरी बार फलनी है।

मजदूर वर्ग की चालती हुई कीमतों के समय में वह कठिनाई होती है। इसका कारण यह है कि कीमतों के हिसाब से मजदूरों का काम धीरे धीरे बढ़ता है। अपनी मजदूरी में वह पहला जितना चीज नहीं खरीद पाएँ। लेकिन ऐसे समय में काम अधिक मिलता है लाभ में बढ़ि होने के कारण उत्पादन उत्पादों का मात्रा बढ़ा देते हैं जिससे मजदूर वर्ग को काम अधिक मिलता है। दूसरी ओर जब कीमत गिरती है तो मजदूरों की दर उतनी नहीं गिरती इसलिए मजदूर वर्ग का इस बात से लाभ

होता है। लेकिन ऐसे समय उत्पादक को हानि होती है और वे काम घटा देते हैं। फलस्वरूप मजदूरों को काम कम मिल पाता है और बेकारी बढ़ जाती है।

इसी प्रकार बची व निश्चित आय पाने वाले व्यक्तियों और उपभोक्ताओं को बढ़ती हुई कीमतों के काष्ठ में हानि होती है और बचती हुई कीमतों के समय में ये लोग लाभ में रहते हैं।

कीमतों की पटी-बढ़ी का प्रभाव उत्पादन पर भी बहुत पड़ता है। बढ़ती हुई कीमतों के समय में व्यवसायों का अनावश्यक उत्तेजना मिलती है। व्यवसायी का लाभ बढ़ जाता है और वह इस कारण उत्पादन में अधिक पूँजी और अन्य साधन लगाना शुरू करता है। अन्त में बाजार माल में लड़ जाता है और लाभ के स्थान पर हानि होने लगती है। कीमतें गिरने लगती हैं और बेकारी में वृद्धि होती है। व्यवसाय में अनिश्चितता छा जाती है, तथा जोखिम का अंश बहुत बढ़ जाता है और जब कीमतें गिरती हैं तब व्यवसाय के क्षेत्र में अनावश्यक मुदी का सामना करना पड़ता है। व्यवसाय का काम ढीला हो जाता है और बेकारी तेजी में फैलने लगती है।

मूल्य-परिवर्तनों का सामाजिक जीवन पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अस्थिर मूल्यों के समय समाज में एक तरह की तनावपूर्ण और अस्थिरता छा जाती है। श्रम और पूँजी का संबंध खटित रूप धारण कर लेता है। हड़ताल और सालाबन्दी से समाज का गला घटने लगता है। ऐसे समय में हर प्रकार की उन्नति का मार्ग बन्द हो जाता है।

अस्तु, हम कह सकते हैं कि मूल्य-परिवर्तनों का प्रभाव व्यक्ति और समाज पर अत्यंत बुरा ही होता है। इनके कारण अनेक आर्थिक, सामाजिक और नैतिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं जिनके प्रभाव से शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। इसलिए कोशिश इस प्रकार करनी चाहिए जिससे मुद्रा की अत्यधिक बढ़ा-तफ हो सके स्थिर रहे तथा उसमें तेजी से और अनावश्यक परिवर्तन न हो।

## QUESTIONS

- 1 What is meant by the value of money ? Can it be measured ?
- 2 What are index numbers ? How are they constructed ?
- 3 Explain the value of money and show how it is determined
- 4 State and explain briefly the quantity theory of money
- 5 Examine the effects of changes in the value of money
- 6 How and in what manner do rising and falling prices affect the following —
  - (a) Creditors and debtors,
  - (b) Producers and labourers



## अध्याय ३६ साख और बैंक

### (Credit and Banks)

आधुनिक युग में साख और बैंक का विशेष महत्व है। उद्योग, व्यापार आदि अनेक आर्थिक क्षेत्रों में इनकी विशेष आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में देश की औद्योगिक एवं व्यापारिक उन्नति बहुत-कुछ साख और बैंक की व्यवस्था पर निर्भर करती है। अतः इनकी जानकारी आवश्यक है।

सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि साख है क्या अथवा साख किसे कहते हैं? साख किसी भी व्यक्ति की उस शक्ति को कहते हैं जिसके बल पर वह दूसरों में कुछ समय के लिए आर्थिक वस्तुएं अथवा धन राशि उधार ले सकता है। अर्थात् किसी भी व्यक्ति की ऋण लेने वाली शक्ति, विशेषता या गुण को अर्थशास्त्र में 'साख' कहते हैं। साख का आधार विश्वास है। साधारणतः एक व्यक्ति किसी को ऋण देने के लिए तभी तैयार होता है, जब उसे यह विश्वास होता है कि उधार ली गई सम्पत्ति नियत समय पर लौटा दी जायगी। यह विश्वास कर्जदार की भुगतान करने की शक्ति और उसकी भ्रष्टाचार पर निर्भर है। कुछ लोगों में ऋण चुकाने की शक्ति तो बाफ़ी होती है लेकिन उनकी नियत अच्छी नहीं होती। मौका पड़ने पर वे पूरी रकम को हड़प करने से नहीं चूकते। ऐसे व्यक्तियों की साख, अथवा उधार देने की शक्ति बहुत कम होती है।

### साख-पत्र

#### (Credit Instruments)

साख के आधार पर जितने सौदे किये जाते हैं, उनके पूरा होने में

कुछ समय लगता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उनका पूरा ध्योरा लिख लिया जाय जिससे भविष्य में हिमाव व लेन-देन करते समय कोई भूल या आपत्ति न हो। जिन कागजों पर यह सब लिखा जाता है, उन्हें 'साख-पत्र' कहते हैं। साख-पत्रों के कई रूप होते हैं जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं—

**ट्रुण्डी (Bills of Exchange)**—यह एक शर्त रहित चिट्ठी है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है कि गगन पर एक निश्चित समय के पश्चात् उसमें लिखी हुई रकम लिखने वाले या किसी विशेष व्यक्ति को, या उसके लाने वाले को दे दे। ट्रुडिया केवल व्यापार और उद्योग-धन्धे सम्बन्धी कार्यों में लिए ही प्रयोग की जाती हैं। माल बेचने वाले ट्रुडी लिखकर खरीदार के पास भेजते हैं। खरीदार उसके अनुसार भुगतान करते हैं। ट्रुडिया दो प्रकार की होती है—(१) दर्शनी ट्रुडी (sight bills) और (२) भिती या मुदती ट्रुडी (time bills)। दर्शनी ट्रुडी वह है जिसका रुपया गगन पर जयवा ट्रुडी दिखलाते ही मिल जाता है। मुदती ट्रुडी उसे कहते हैं जिसका रुपया एक निश्चित समय के बाद ही मिल सकता है। अर्थात् समाप्त होने पर तीन दिन से लेकर पांच दिन का और समय दिया जाता है। इन ट्रुडियों पर मृत्यानुसार टिकट लगाये जाते हैं।

दर्शनी ट्रुडी चार प्रकार की होती है—(१) घनी जोग (२) शाह जोग, (३) फरमान जोग, और (४) देखाडनार जोग। घनी जोग ट्रुडी वह ट्रुडी है जिसका रुपया केवल उमी को मिल सकता है जिसके हक में वह लिखी गयी हो। शाह जोग ट्रुडी का रुपया केवल नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति या शाह को ही दिया जा सकता है। फरमान जोग ट्रुडी का रुपया रकम पाने वाले को, या उसकी आज्ञानुसार दिया जा सकता है। देखाडनार जोग ट्रुडी 'बेयरर चेक' के समान होती है। इस का रुपया ट्रुडी ले जाने वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है।

हुण्टिया के प्रयोग से व्यापार व्यवसाय में बहुत सुविधा होती है। वर्तमान आर्थिक जगत में इनका सहस्रद्वय स्थान है। व्यवसाय सम्बन्धी लेन देन का भगताग अधिकतर हुण्टी के द्वारा किया जाता है। हुण्टियों के उपयोग से धार्मिक गुद्रा के चलन में भी काफी बचत होती है।

**चेक (Cheque)**—चेक वक के नाम एक गत रहित-लिखित आना पत्र है जिसके द्वारा ब्राह्मक अपने वक को यह आदेश देता है कि मागन पर उसे जयवा उस व्यक्ति को जिसका नाम चेक पर लिखा है लिखित रुपया दे दिया जाय। मागन पर चेक का रुपया देन के लिए वक बाध्य होता है। चेक दो प्रकार के होते हैं—बयरर (bearer) तथा आर्डर (order)। बयरर चेक का रुपया जो भी व्यक्ति चाहे थक में ले जाकर रुपय ले सकता है। लेकिन आर्डर चेक का रुपया केवल उसी व्यक्ति को मिल सकता है जिसको देन के लिए वक को जाना हो गइ हो। जब चेक पर दो समानांतर रेखाएँ खींची जाती हैं तो उसे क्रॉस्ड चेक (crossed cheque) कहते हैं। ऐसा करने पर वक नगद रुपया न देकर ब्राह्मक के धात में जमा कर देता है। उसे भगया नहीं जा सकता।

चेक और हुण्टी में बहुत अंतर है। चेक वक के नाम पर ही किया जा सकता है किन्तु हुण्टी किसी के ऊपर की जा सकती है चाहे वह व्यक्ति हो या फर्म। चेक का रुपया मागन पर वक को तुरन्त देना पड़ता है परन्तु हुण्टियों के माय यह बात गलत रहती होगी। मुरती हुण्टी का रुपया एक निश्चित समय के गन्धान देना पड़ता है। इससे अतिरिक्त हुण्टी में मन्वन्तुमार टिकट लगाना पड़ता है किन्तु चेक में इसकी काद आवश्यकता नहीं पड़ती।

चेक के उपयोग से अनेक लाभ होते हैं। व्यापार क्षेत्र में इसका बड़ी महामता मिलती है। चेक द्वारा जो भुगतान किया जाता है उसका पूरा निमाव लिखा रहता है—जस कितना रुपया किस कारण वक और जिसको दिया गया है। यदि भविष्य में किसी बात पर गगदा उठे तो

समकी पुष्टि आसानी से की जा सकती है। इसका अतिरिक्त चेक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर द्रव्य भ्रमण में बड़ी सुविधा हाती है और सर्व भी कम लगता है। तीसरे, चेक के प्रयोग से धार्मिक मुद्रा की कम आवश्यकता पड़ती है। इस कारण धर्म और पूजा में काफी बचत होती है। इन सब हुए साधनों को अन्य आवश्यक और लाभप्रद धन में लगाकर धार्मिक उन्नति की जा सकती है। इन्हीं सब कारणों से आज सभी नग्य और उन्नतिशील देशों में चेक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।

**प्रामिषरी नोट (Promissory Note)**—यह एक अनरहित लिखित साख-पत्र है जिसका अनुसार एक निश्चय व्यक्ति को या जिसको यह कह या जो उसे ले जाय उसमें लिखी हुई एकमात्र वारण पर अथवा एक निश्चित समय पर चुकान की प्रतिज्ञा करता है। केवल यह अन्तर छोड़कर कि यह ऋणी द्वारा लिखा जाता है प्रामिषरी नोट की बाकी सब विशेषताएँ हुण्डी में मिलती हैं। यह किसी व्यक्ति मर्यादा या सरकार द्वारा लिखा जा सकता है। दृष्टिमा की तरह इसका भी विनिमय या हस्तान्तरकरण हो सकता है।

**बैंक ड्राफ्ट (Bank Draft)**—यह एक आज्ञा पत्र है जो एक बैंक द्वारा बैंक को अथवा अपनी शाखा को लिखता है कि एक निश्चित एकमात्र व्यक्ति को दे दे जिसका नाम उस पत्र में लिखा है। भ्रमण करने का यह एक बहुत सस्ता और सुरक्षित साधन है। अन्तर्राष्ट्रीय भ्रमण भी इसके द्वारा किया जाता है। कोई भी व्यक्ति वहां में अपना पैसा करके बैंक ड्राफ्ट लिखवा सकता है। इस काम के लिए बैंक को कुछ कमीशन या फीस देनी पड़ती है।

### साख का महत्त्व

(Importance of Credit)

साख आधुनिक व्यापार का प्राणस्वरूप है। वर्तमान उत्पत्ति प्रणाली इतनी जटिल हो गई है कि साख की सहायता बिना इस ढांचे को बनाए

रखना कठिन है। हर पक्ष पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। मही कारण है कि जिन व्यक्तियों की साख अच्छी मही होती, वे व्यापार-व्यवसाय में उन्नति नहीं कर पाते। मध्येप में, साख से निम्नलिखित लाभ होते हैं—

(१) इगरे धात्विक मुद्रा के चलन में बहुत बचत होती है। इसके अतिरिक्त आधुनिक व्यापार का क्षेत्र इतना बढ़ गया है कि उसकी आवश्यकताएँ केवल धात्विक मुद्रा में ही अच्छी तरह पूरी नहीं की जा सकती।

(२) इसकी सहायता से उत्पादन बड़े परिमाण पर किया जा सकता है और इस तरह बड़े परिमाण पर उत्पादन के ज़ियाने लाभ हैं, वे उपलब्ध हो सकते हैं।

(३) साख द्वारा पूँजी उन क्षेत्रों में सुगमता से भेजी जा सकती है जहाँ उसका उपयोग अधिक अच्छे ढंग में होना सम्भव है। इससे पूँजी की क्षमता या उत्पादन-शक्ति बहुत बढ़ जाती है।

(४) भुगतान करने का बड़ा एक बहुत ही गुविधायक साधन है। यही नहीं, इसकी सहायता से मनुष्य कुछ समय के लिए आर्थिक कष्टों से बच सकता है।

(५) साख की उचित व्यवस्था से कीमतों में उतार-चढ़ाव को, जिनके कारण अनेक आर्थिक और सामाजिक बुरादमा उत्पन्न होती हैं, बहुत-बहुत रोका जा सकता है।

लेकिन साख से कई दोषों व आपत्तियों के उत्पन्न होने का भी भय रहना है जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं—

(१) यदि साख पर बहुत आसानी से ढ़र मिलने लगता है, तो लोग अपनी शक्ति से बाहर ऋण लेने लगते हैं। उनमें तरई-तरह की पिचूल्जर्ची की आदत पड़ जाती है और अन्त तक वे इस रोग से मुक्त नहीं हो पाते। इससे फलस्वरूप बेईमानी, चालबाजी आदि अन्त बुरादमा पैदा होती है जिनके कारण व्यापार का नैतिक आधार टूट जाता है।

(२) साख द्वारा कुछ समय के लिए किमी धर्म या कारवाने की कमज़ोरियाँ आसानी से छिपाई जा सकती हैं। इस कारण जन-साधारण

को उसकी वास्तविक दशा का ज्ञान नहीं हो पाता । लेकिन इस प्रकार की धोखे की टट्टी बहुत दिन तक चल नहीं पाती । फर्म की कमजोरियाँ दिन प्रति दिन बढ़ती जाती हैं और जब उसका अन्तिम दिवाला पिटता है, तो जनता को पहले से कहीं अधिक हानि उठानी पड़ती है । इस तरह धोखा खाकर लोगों का विश्वास उठ जाता है जिससे अन्य औद्योगिक संस्थाओं को वित्त अथवा साख की प्राप्ति में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

(३) मजदूरी की आपत्ति का भय साख के अत्यधिक प्रसारण का है । इससे तरह-तरह की जटिल समस्याएँ उत्पन्न होती हैं । वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं । ब्रूवे और गट्टेबाजी का आधिपत्य सारे व्यावसायिक क्षेत्र में छा जाता है । संधर्ष और अस्थान्ति की लहर लहराने लगती है । फलस्वरूप लोगों का जीवन अनिश्चित और दुःखमय बन जाता है ।

अतः, साख में लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी उचित दम से व्यवस्था हो तथा उस पर सरकारों नियन्त्रण हो । यह काम आवश्यक केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है ।

### बैंक

(Bank)

बैंक उग व्यक्ति या संस्था को कहते हैं जिसका कार्य संचयन-साधन ले कर जमा करना और उधार देना होता है । यह साख का व्यवसाय करता है । अर्थात् साख, धन और मुद्रा का लेन-देन करने वाली संस्था को बैंक कहते हैं । बैंक आधुनिक युग की देन नहीं है । बहुत प्राचीन काल से बैंक का कारोबार चला आ रहा है । हा, यह बात अवश्य है कि समय के साथ-साथ इसमें अनेक परिवर्तन होते रहे हैं । यदि आज हम बैंक के पुराने और वर्तमान रूप, कार्य और व्यवस्था की तुलना करें, तो शायद ही कोई समानता बख्ताई देगी । आधुनिक बैंक का पूरा ढांचा ही बदल गया है । यही कारण है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बैंक

वा 'नम आधुनिक युग' में ही हुआ हो। बैंक काय अब बहुत नम और वनानिक ढंग में होता है। जैसे शत्रु की तरह बैंक-व्यवसाय में भी विनिमयीकरण का नियम और पकड़ रहा है। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अलग अलग बैंक होते हैं। जैसे कुछ कृषि की आवश्यकताएँ पूरी करते हैं कुछ व्यापार की देखभाल करते हैं कुछ उद्योग धंधों का काम सभालते हैं और कुछ विदेशी विनिमय का। भिन्न भिन्न काम करने वाले बैंकों को पक्ष-पक्षक नाम दिए गए हैं—जैसे 'वाणिज्यिक बैंक औद्योगिक बैंक सहकारी बैंक विदेशी विनिमय बैंक' इत्यादि।

### बैंक — काय

(Functions of Bank)

बैंक बैंक लाभप्रद काय करता है। बैंक का सबसे प्रमुख काय जनता के धन को इकट्ठा करना है। यह काम बैंक लोगों की जमा स्वीकार करके करता है। बैंक कई प्रकार के खाते आलता है जिनमें लोग अपनी धन जमा करते हैं। चालू खाते (current account) में जमा कराने में बैंक अपने ग्राहकों को यह अधिनार देता है कि जब वे चाहें जमा किया हुआ रुपया निकाल लें। इस खाते में जमा किये हुए रुपयों को बैंक स्वतन्त्र रूप से उपयोग में नहीं ला सकता क्योंकि पता नहीं प्राइक कने रुपया माय बैठे। यही कारण है कि चालू खाते की रकम पर बैंक सूद नहीं या बहुत कम देता है। मद्धती जमा खाते (fixed account) में रुपया एक निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है। उस समय में पहले उमम से रुपया नहीं निकाला जा सकता। बैंक उस समय तक जमा किए हुए रुपयों को लाभप्रद स्थातों में आसानी से लगा सकता है क्योंकि उसे पहले से ही इस बात का पूरा पता होता है कि ग्राहक जब उस रकम को निकाल सकने है। इस कारण बैंक इस खाते में जमा की हुई रकम पर पयोजित सूद देता है। सूद की दर मद्धी की स्थिति और किताने वाक के लिए रकम जमा की गई है उग पर निर्भर होती है।

बैंक का दूसरा मुख्य काय ऋण या उधार देना है। जन्मव दाय

यह बात सिद्ध है कि ग्राहक अर्थात् जमा करने वाले सब एक साथ सब से अपना रपया नहीं निकालते । इसलिए कुछ जमा का केवल थोड़ा ही भाग नकदी (cash) में रख कर बक अपन ग्राहकों का भाग पूरी कर सकता है । बाकी रकम उधार देने के लिए उपयोग का जा सकती है । चिन्ता भाग नकदी के रूप में निधि व ग्जिव में रखना चाहिए । इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता । प्रत्येक बक को अपनी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय करना पड़ता है कि जमा किये हुए धन का कितना प्रतिशत भाग रिजर्व में रखा जाय जिसमें ग्राहकों की मांग की पूर्ति करने में कोई अड़चन न हो । यदि बक आवश्यकता में अधिक भाग रिजर्व या निधि में रखता है तो ऋण देव के लिए बक के पास बहुत कम भाग बच रहेगा । इस कारण उसका लाभ घट जायगा । दूसरी ओर यदि बक बहुत कम रिजर्व रखता है तो ग्राहकों की मांग पूरी न हो सकेगी । ऐसी परिस्थिति में जनता का विश्वास उस पर से घट जायगा और साथ ही उसे अपना बागीदार बंद करना पड़ेगा । अतएव बैंक को एक ऐसा रिजर्व रखना पड़ता है जो न तो अधिक हो और न कम । जो बक ऐसा कर पाता है उस ही सफलता प्राप्त होता है ।

रिजर्व व निधि का परिमाण निश्चित करने के बाद बक शेष पूँजी से ऋण देने का कार्य चलाता है । पूँजी बक की अधिकतर पूँजी ग्राहकों द्वारा चालू की हुई होती है । इसलिए उसका प्रयोग करने में बक को बहुत सावधानी में काम करना पड़ता है । ऋण देने व गहल बक कई बातों को अच्छी तरह से जान-पड़ताऊ करता है । उसे यह देखना पड़ता है कि ऋण मांगने वाला कौन है कितना समय और किस काम के लिए ऋण चाहता है उसकी आर्थिक स्थिति कैसा है किस प्रकार की जमावत देने के लिए वह व्यक्ति तैयार है इत्यादि ? इन सब बातों का जांच करने के पश्चात् बक यह निश्चय करता है कि कब और किसे कितना उधार दिया जाय । जितने पूँजी सुरक्षित रहे और साथ ही साथ उसे लाभ



भी हो। अपनी ऋण-नीति से बैंक इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करने की कोशिश करता है।

उधार देने का काम बैंक कई प्रकार से करता है जैसे हण्डी भुनाना, माल और ऋण-पत्रों की जमानत पर कर्ज देना अथवा जमा की गई रकम से अधिक रकम देना जिसे “ओवर-ड्राफ्ट” (over draft) कहते हैं। कभी-कभी बैंक बिना किसी जमानत के भी कर्ज दे देते हैं। लेकिन यह तभी किया जाता है जब कि बैंक को उस व्यक्ति पर पूरा-पूरा भरोसा होता है, उसकी ईमानदारी और सामर्थ्य पर विश्वास होता है, अन्यथा नहीं।

अस्तु, बैंक एक पक्ष से जमा के रूप में कर्ज लेता है और दूसरे पक्ष को विभिन्न ढंग से उधार देता है। अर्थात् यह दलाल या मध्यस्थ का कार्य करता है। जमा की रकम पर बैंक थोड़ा मूद देता है और उधार माग्ने वालों से अधिक मूद लेता है। मूद के इन दोनों दरों में जो अन्तर होता है, वही बैंक की मुख्य कमाई होती है।

इन दोनों प्रधान कार्यों के अतिरिक्त बैंक और भी कई प्रकार के लाभदायक काम करता है। बैंक अपने ग्राहकों के लिये एजेंट का काम करता है। वह अपने ग्राहकों की तरफ से उनके बिज, चेक, टैक्स, मुनाफा, जम्मा, बीमा आदि की किश्तें लेता और देता है। इससे ग्राहकों को बड़ी सुविधा होती है। ग्राहकों के ट्रस्टों और वसोयतों का प्रबन्ध भी बैंक करता है। उनके बीमती माल को वह सुरक्षित रखता है और उनके हिस्सा-पत्रों (shares) की बेल-रेल करता है। कई प्रकार के उपबोगी साख-मन्त्र भी वह देता है जिससे ग्राहकों को बड़ा सुभीता होता है। इसके अलावा बैंक विनिमय के लिए सस्ते साधन प्रदान करता है जैसे चेक, नोट, आदि। इनकी सहायता से बड़ी-बड़ी रकमें दूर-दूर के स्थानों तक आसानी से और कम खर्च में भेजी जा सकती हैं। विदेशी व्यवसाय के लिए पूंजी व वित्त सम्बन्धी सहायता भी इससे मिलती है। बैंक अपने ग्राहकों की

विदेशी विनिमय की दुब्धियों को लेते और भुनाते हैं जिससे विदेशी व्यापार सम्बन्धी भुगतान करने में बड़ी सुविधा होती है।

## बैंक की महत्ता

(Importance of Bank)

बैंक के विभिन्न कार्यों का विवेचन ऊपर किया जा चुका है, जिससे पता चलता है कि वर्तमान आर्थिक संसार में बैंक का कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है। बैंक द्वारा लोगों में पूँजी संचय करने की आवृत्ति बढ़ जाती है। बैंकों में थोड़ी वृत्ति को भी जमा किया जा सकता है जिस पर बैंक यथोचित मूद देता है। इस तरह पूँजी जमा करने के कार्य में लोगों को बैंक द्वारा सुविधा ही नहीं बल्कि प्रोत्साहन भी मिलता है। और यह तो हमें भली भाँति मालूम ही है कि आधुनिक आर्थिक उत्पत्ति का आधार पूँजी है। इसलिए यह हम कह सकते हैं कि बैंक पूँजी की मात्रा में वृद्धि लाकर देश की आर्थिक उत्पत्ति में पर्याप्त सहायता पहुँचाता है। बैंक द्वारा पूँजी की गतिशीलता भी बढ़ जाती है। जिन स्थानों पर पूँजी की अधिक आवश्यकता होती है, वहाँ पर बैंक की महत्त्वपूर्णता से पूँजी आसानी से पहुँचाई जा सकती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास पूँजी की कमी तो नहीं होती, पर उनके उचित ढंग से प्रयोग करने की क्षमता और वृद्धि नहीं होती। दूसरी ओर, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उद्योग-धंधों के संचालन का काम खूब अच्छे ढंग से कर सकते हैं, किन्तु उनके पास आवश्यक पूँजी नहीं होती। इस कारण वे अपनी व्यावसायिक कुशलता तथा योग्यता का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा पाते। बैंक इन उद्दर की कमी को दूर करने की भरसक कोशिश करता है। जनता की वृत्ति को एकत्रित करके बैंक उन गुणोद्योग व्यक्तियों के पास पहुँचाता है जो उचित लाभप्रद ढंग से काम में लगा सकते हैं। इसके फलस्वरूप व्यक्ति और समाज की आर्थिक उत्पत्ति बहुत तीव्र गति में होती है।

बैंक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी बहुत सुविधा होती है। आज सब एक दूसरे देश का लेन-देन इसी के द्वारा किया जाता है। इसके

बलावा बैंक से चेक-मुद्रा का चलन बढ़ता है जिससे धात्विक मुद्रा के प्रयोग में काफी वृद्धि होती है। यही नहीं, चेक-मुद्रा में बहुत शक्ति होती है जिससे व्यापार सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति बिना किसी कठिनाई के हो सकती है।

अस्तु, वर्तमान आर्थिक जीवन में बैंक का बहुत ऊँचा स्थान है। राष्ट्र की आर्थिक उन्नति बहुत कुछ अंश तक इसी पर निर्भर करती है। भारतवर्ष आर्थिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। इसका एक कारण यह भी है कि यहाँ पर बैंकों की समस्या बहुत कम है और उनका संचालन भी ठीक ढंग से नहीं होता।

### QUESTIONS

- 1 Define credit. Bring out its significance
- 2 Explain briefly the main forms of credit instruments
- 3 What are the main differences between a cheque and a bill of exchange?
- 4 What is a 'bank'? What are its important functions?
- 5 In what ways can bank help in the economic development of a country?
- 6 Bring out the importance of banks in the present day economic society
7. Write short notes on the following :—
  - (a) Bills of Exchange
  - (b) Bank Drafts
  - (c) Promissory Notes
  - (d) Cheques.

वितरण

(Distribution)

## वितरण और उसकी समस्या (Distribution and its Problem)

उपभोग, उत्पत्ति और विनिमय सम्बन्धी बातों का विवेचन किया जा चुका है। अब केवल एक विभाग का अध्ययन शेष है, वह है धन का वितरण। इस विभाग में यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार धन का वितरण उन सब साधनों के बीच होता है जो उसके उत्पादन में सहायता देते हैं। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को उत्पादन का क्या भाग मिलता है, किम सिद्धान्त के अनुसार उनका पारिश्रमिक निर्धारित होता है, उनके पारिश्रमिकों के बीच आपस में क्या-कैसा सम्बन्ध होना है, इन सब प्रश्नों का विचार वितरण विभाग के अन्तर्गत किया जाता है।

प्राचीन काल में प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग की सभी वस्तुएँ स्वयं ही तैयार करता था। उत्पादन-कार्य में जिन साधनों की आवश्यकता पड़नी थी, वह अपने आप ही प्रदान करता था। अस्तु, उस समय में वितरण का कोई प्रश्न न था, क्योंकि जो कुछ भी एक व्यक्ति उत्पादन करता था उस पर केवल उसी का अधिकार होता था, किसी दूसरे का नहीं। जब तक व्यक्तिगत रूप से उत्पादन का कार्य चलता रहा, वितरण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। कुछ समय बाद उत्पत्ति का यह रूप न रह सका। कारण, मनुष्य की आवश्यकताएँ इतनी बढ़ गईं कि उत्पत्ति के इस सीधे और सरल रूप द्वारा उनकी तृप्ति करना असम्भव हो गया।

अतएव उत्पादन-क्षेत्र में समय के साथ-साथ अनेक परिवर्तन होने रहे, विशेषकर पिछले दो सौ वर्षों में। आज वर्तमान युग में उत्पादन-प्रणाली का पूरा ढाँचा ही बदल चुका है। उसने एक नया रूप धारण कर लिया है। अब उत्पत्ति व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि सानूहिक ढंग से की जाती है। उत्पादन का परिमाण इतना बढ़ गया है कि अब किमी के लिए यह साधारण रूप से सम्भव नहीं है कि वह सब आवश्यक साधनों को स्वयं ही प्रदान कर सके। उत्पादन के साधनों को जुटाने के लिए अब भिन्न-भिन्न वर्गों के लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। उनकी सहायता के बिना उत्पत्ति का कार्य एक पल भी नहीं चल सकता। जो कुछ उत्पन्न होता है, वह उन्हीं सब के सहयोग का फल होता है। इसलिए सहयोग देने वाले अनेक राशियों के बीच उत्पादित धन का वितरण करना आवश्यक हो गया है। बिना वितरण के उत्पत्ति निरर्थक है और उपभोग असम्भव। आजकल उपभोग सभी सम्भव हो सकता है जबकि उत्पादन का सहकारी साधनों के बीच वितरण हो। यही कारण है कि वर्तमान आर्थिक संसार में वितरण को एक विशेष स्थान प्राप्त है।

वितरण अर्थशास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। इसका अध्ययन बहुत आवश्यक और साथ ही साथ मनोरञ्जक भी है। हम सब किसी न किसी रूप में धनोत्पत्ति में हाथ बटाने हैं। इसलिए हम इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि कुल उत्पत्ति में हमारा हिस्सा कैसे निर्धारित होता है। इस बात की जानकारी वितरण के सिद्धान्त द्वारा होती है। इसमें आप के कारण और परिमाण का स्पष्टीकरण हो जाता है। वितरण-समस्या का अध्ययन रुचिकर तो अवश्य है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसमें विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उत्पादन-क्षेत्र में भिन्न-भिन्न माधनों को इस तरह मिलाकर काम लिया जाता है कि निश्चित रंग से यह कहना कि कुल उत्पत्ति का कितना भाग किस साधन के उद्योग का पल है, बहुत कठिन है। इस कारण साधनों का

पारिथमिक निर्धारित करते समय अनेक शराओं की बातों को तय करना पड़ता है। यदि किसी साधन को अधिक पारिथमिक दिया गया, तो अवश्य ही अन्य साधनों के लिए कम रह जायगा। फलस्वरूप वितरण-विभाग का अध्ययन तरह-तरह की जटिल समस्याओं से भरा हुआ है।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य है कि वितरण की व्यवस्था का समाज के आर्थिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। देश की आर्थिक उन्नति, सुख-समृद्धि काफ़ी अंश तक वितरण पर निर्भर है। जितना न्यायपूर्ण और उचित वितरण का आधार होगा, उतना ही अधिक वह समाज सुखी और उन्नतशील होगा। यदि वितरण गड़बड़ है, तो निस्संदेह उत्पादन उतना न होगा जितना कि सम्भव हो सकता है। उत्पादक उत्पत्ति में अपनी पूरी शक्ति लगाने के लिए उस दशा में तैयार न होवे। धीरे-धीरे उनकी कार्य क्षमता गिरती जायगी। व्यापार और उद्योग-धंधों में शिथिलता आ जायगी। उत्पादन कम हो जायगा। इसके फलस्वरूप समाज का आर्थिक ढांचा लड़खड़ाने लगेगा और तरह-तरह के आर्थिक और सामाजिक संकट उत्पन्न होने लगेंगे। ऐसी दशा में जनता का जीवन-स्तर नीचा ही बना रहेगा। इन सब बातों के कहने का सारांश यह है कि यदि वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो आर्थिक जीवन का कार्य सुचारुरूप से नहीं चल सकता। लेकिन अभाग्यवश आज बहुत-से देशों में धन-वितरण की व्यवस्था अत्यन्त ही दूषित है जिसके कारण लोगों को अनेक जटिल आर्थिक और सामाजिक संकटों से मुठभेड़ करना पड़ रहा है। वितरण की व्यवस्था के कारण वर्ग-संघर्ष की गति और तीव्रता दिन पर दिन तीव्र होती जा रही है। भारतवर्ष में भी धन का वितरण इसी प्रकार दूषित है। अनुमान लगाया जाता है कि राष्ट्रीय आय का एक तिहाई भाग से भी अधिक केवल दो प्रतिशत लोगों के पास चला जाता है। यही कारण है कि देश की राष्ट्रपति-मुष्टिमय लोगों में संचित हानि जा रही है। यहाँ के गिरे हुए जीवन-स्तर का यह एक मुख्य कारण है। देश की

आर्थिक दशा सुधारने के लिए वर्तमान वितरण पद्धति को बदल कर उसे एक नया रूप प्रदान करना नितान्त आवश्यक है। अस्तु, वितरण विषय का अध्ययन वैद्वान्तिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है।

## वितरण की समस्याएँ

### (Problem of Distribution)

वितरण सम्बन्धी समस्याएँ बहुत जटिल हैं और उनका क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। इसलिए उनको कई भागों में विभक्त करके उनका क्रम-क्रम विश्लेषण एवं अध्ययन करने में ही सुविधा होगी। सर्व-प्रथम प्रश्न यह है कि वितरण किस चीज का होता है? इसका उत्तर बहुत सरल है। वितरण राष्ट्रीय आय (national income) का होता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा कई ढंग में की गई है। प्रो० मार्शल ने जो परिभाषा दी है, वह इस प्रकार है—“राष्ट्रीय आय का वास्तविक उग समस्त वस्तुओं और सेवाओं में है, चाहे वे भौतिक हो या अभौतिक, जो किसी देश के धर्म, पूजा और प्राकृतिक साधनों की सहायता से एक वर्ष में उत्पन्न की जाती हैं।” शुद्ध व वास्तविक राष्ट्रीय आय (net national income) को मापने के लिए कुल आय में से टूट-फूट का खर्चा आदि निकाल देना चाहिए। दूसरी ओर प्रो० फिशर का कहना है कि जितनी वस्तुएँ एक वर्ष में पैदा की जाती हैं, उन सबको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। उत्पादित पदार्थों के केवल उनी भाग को इनके अनुसार राष्ट्रीय आय में शामिल करना चाहिए जिसका प्रत्यक्ष रूप में उस वर्ष में उपभोग किया गया हो। एक उदाहरण द्वारा इन दोनों परिभाषाओं में जो अन्तर है, वह आसानी से माफूम किया जा सकता है। मान लो गाल भर में एक मशीन तैयार की गई। मार्शल के अनुसार टूट-फूट का खर्चा काटकर उस मशीन की कुल कीमत राष्ट्रीय आय में शामिल कर ली जायगी। लेकिन फिशर की परिभाषा



के अनुसार मशीन की कुल कीमत का केवल वही भाग राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जायगा जिसका उरा वर्ष में वास्तव में उपभोग हुआ है। यह तो शायद मानना पड़ेगा कि वैज्ञानिक दृष्टि से प्रो० फिशर की परिभाषा अधिक ठीक है। लेकिन इस ढंग से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना बहुत कठिन है। यह हिसाब लगाना एक तरह से जमझम-सा है कि किस वस्तु का कीमती भाग एक वर्ष में उपभोग में लाया गया और उसका कितना मूल्य वाका जाना ठीक होगा। अस्तु, फिशर के ढंग से राष्ट्रीय आय के परिमाण को निश्चित करना बहुत कठिन है। सरलता और सुविधा इसी में होगी कि एक वर्ष के अन्दर जितनी वस्तुएं उत्पन्न हो, उनकी एक सूची तैयार कर ली जाय और इसके आधार पर राष्ट्रीय आय के परिमाण का अनुमान लगाया जाय। अस्तु, वैज्ञानिक अथवा शास्त्रीय दृष्टि में बहुत युक्ति-मगल न होतें हुए भी प्रो० मार्शल की परिभाषा अधिक उपयुक्त है।

राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के तीन मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि कुल उत्पत्ति का मूल्य जोड़ कर उसमें से टूट-फूट का खर्चा घटा दिया जाय। राष्ट्रीय आय के मापन का दूसरा तरीका यह है कि सब लोगों की आमदनी को जोड़ लिया जाय चाहे वे जाय-नार (income tax) देते हो या नही। अनुमान लगाने का तीसरा तरीका यह है कि देश में जितने धंधे हों, उनकी गणना कर ली जाय जिसमें जगमें काम करने वाली की कुल आमदनी को पेंता चल मके। इस तरह के जोड़ से जो नक्सा आयेगी, वह राष्ट्रीय आय व बराबर होगी।

राष्ट्रीय आय की माप करने समय इन बात का ध्यान रखना जरूरी है कि एक ही रकम अनेक बार न जोड़ ली जाय। साथ ही राष्ट्रीय आय में उन चीजों की कीमत को शामिल नहीं करना चाहिए जिनके पाने के लिए किसी प्रकार की सेवा नहीं की गई है—जैसे दान की बरतुए। इसी तरह वह रकम जो दुआबरा में पेंशन के रूप में मिलती है अथवा जो

धोखवाजी से पैदा की जाती है, राष्ट्रीय आय में समावेशित नहीं होती।

इस तरह हम देखते हैं कि एक ओर तो राष्ट्रीय आय उत्पत्ति के साधनों की सेवाओं का फल है और दूसरी ओर यह इन साधनों के पारिभाषिक देने का स्रोत व कोष भी है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि साल भर राष्ट्रीय आय को जमा किया जाता है और फिर उनके बाद उसका वितरण होता है। (राष्ट्रीय आय का उत्पादन और उसका वितरण साथ-साथ चलता रहता है)। राष्ट्रीय आय एक बहते हुए सागर के समान है जिसमें एक ओर से जल भरता रहता है और दूसरी ओर से खाली होता रहता है। अर्थात् राष्ट्रीय आय एक स्थायी-निधि नहीं है। यह एक धारा या प्रवाह है जो सदा चालू रहता है क्योंकि प्रत्येक समय वस्तुओं तथा सेवाओं की उत्पत्ति का नाश तथा रहता है।

अस्तु, पहले प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। वितरण राष्ट्रीय आय का होता है। अन्य बातों के समान रहने पर, यह निश्चय है कि राष्ट्रीय आय का परिमाण जितना अधिक होगा, उत्पत्ति के साधनों का हिस्सा उतना ही बड़ा होगा।

अब दूसरा प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय आय का वितरण किनके बीच होता है? इसका उत्तर और भी सरल है। यह हम पहले कह चुके हैं कि उत्पादन में मुख्यतः चार साधनों की आवश्यकता पड़ती है—भूमि, श्रम, पूँजी और सगठन या माहुर। जो कुछ उत्पादन होता है, उसमें इन सबका हाथ होता है। इसलिए कुल उत्पत्ति का वितरण इन्हीं चारों साधनों के बीच होता है। इन साधनों के प्रतिफल को भिन्न-भिन्न नाम दिये गये हैं। श्रम की सेवाओं के बदले में जो कुछ दिया जाता है उसे 'मजदूरी' या 'वेतन' (wages) कहते हैं। भूमि प्रदान करने वाले के हिस्से में जो आता है, उसे 'लगान' अथवा भाटक (rent) कहा जाता है। पूँजी के प्रतिफल स्वरूप जो प्राप्त होता है, वह 'सूद' या 'आव' (interest) कहलाता है। सगठन और जोखिम का भार उठाने

बाल को जो कुछ मिलता है, उसे 'लाभ' (profit) कहते हैं। जब तक आवश्यक साधनों की उनकी सेवाओं के बदले कुछ न कुछ पारिधमिक न दिया जायगा, तब तक ये वस्तु-उत्पत्ति में हाथ बढाने के लिए तैयार न होंगे। इन साधनों के पारिधमिक सम्बन्धी बातों का अगले अध्यायों में पूयक्-नृयक् अध्ययन किया जायगा। यहाँ पर केवल इतना ही विचार करना काफी होगा कि सामान्य रूप से इन साधनों का पारिधमिक कौन निर्धारित होता है।

यह तो स्पष्ट है कि जो कुछ उत्पत्ति के किसी साधन को मिलता है, वह एक तरह से उस साधन की सेवाओं के मूल्य के समान है। यदि यह ठीक है, तो प्रश्न यह उठता है कि बेचने और खरीदने वाले कौन हैं ? बेचने वाला तो साधन का स्वामी होता है और खरीदने वाला व्यवस्थापक, उपक्रमी या माहमी व्यवसायी। उत्पत्ति विभाग में यह बताया जा चुका है कि आवश्यक साधनों के जुटाने का काम व्यवस्थापक अथवा उपक्रमी करता है। व्यवसाय का पूरा उत्तरदायित्व व्यवस्थापक पर ही होता है। वही यह निर्णय करता है कि कौन-सा धन्धा शुरू किया जाय, किस ढंग से वह धन्धा चलाया जाय, कितनी मात्रा में और कहाँ पर वस्तुएँ तैयार की जाय ? इस तरह की अनेक बातों की जिम्मेदारी उसी पर होती है। वह उसी व्यवसाय या धन्धे की ओर झुकता है जिसमें उसे लाभ की आशा दिखाई देती है। उसका लाभ दो बातों पर निर्भर होता है—उत्पादन व्यय और मूल्य। यदि उत्पादन व्यय कम है और मूल्य अधिक है तो उसे काफी लाभ होगा। इसलिए उसे इन बातों पर विचार करना पड़ेगा कि जिस वस्तु को वह तैयार करना चाहता है, उसका उत्पादन-व्यय लगभग कितना होगा और भविष्य में उस वस्तु का कितना मूल्य होगा ? जिस धन्धे में उसे अधिक लाभ दिखाई देगा, उसे ही वह चुनेगा। उसके इस प्रकार के निर्णय करने से उत्पत्ति के साधनों की मांग पैदा होती है। यह आवश्यक साधनों के खरीदने अथवा जुटाने की कोशिश करेगा क्योंकि वह जानता है कि उनकी सहायता बिना वह अपने इच्छित काम को

चला न सकेगा। अस्तु, उत्पत्ति के साधनों की सेवाओं की खरीदारी व्यवस्थापक व उपभोक्ता करता है। व्यवस्थापक साधनों की सेवाओं को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं खरीदता। वह उनकी सेवाओं को इसलिए खरीदता है जिससे कि उन वस्तुओं का उत्पादन हो सके जिनकी समाज की ओर से मांग होती है। अस्तु, एक तरह से उत्पत्ति के साधनों की मांग समाज द्वारा ही होती है। व्यवस्थापक तो केवल सगाज की तरफ से एक एजेंट के तौर पर काम करता है। वह अन्य साधनों की सेवाओं को खरीदता है और उनका पारिस्थितिक मजदूरी, व्याज आदि के रूप में बाँटता है। सफल होने पर उसे लाभ प्राप्त होता है।

अब हमें यह देखना है कि व्यवस्थापक साधनों की खरीदते समय किम वात का ध्यान रखता है और अधिक से अधिक किसी साधन को पारिस्थितिक के रूप में कितना मूल्य देने को तैयार हो सकता है। यह तो सभी को भली भाँति मालूम है कि प्रायः खरीदार का यह ध्येय होता है कि वह अपनी खरीदारी इस तरह से करे जिससे उसे अधिक से अधिक तृप्ति प्राप्त हो। उपभोग सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करते समय यह कहा जा चुका है कि उपभोक्ता को उसी समय अधिकतम तृप्ति प्राप्त हो सकती है जब वह अपनी आय को भिन्न-भिन्न पदार्थों पर इस प्रकार खर्च करे कि खरीदी गई हुई सब वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिताएँ एक समान हो। भुगतान उपभोक्ता सम-सीमान्त-उपयोगिता नियम के अनुसार खरीदारी करने की कोशिश करता है। वह इस बात को ध्यान में रखता है कि अलग-अलग वस्तुओं पर जो रुपये की अन्तिम इकाई खर्च हो उसकी उपयोगिता सब स्थानों पर बराबर रहे क्योंकि और किसी दूसरे तरीके से अधिकतम तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतः, खरीदते समय उपभोक्ता का ध्यान वस्तु की सीमान्त उपयोगिता पर रहता है। वह किसी वस्तु के लिए अधिक से अधिक मूल्य उसकी सीमान्त उपयोगिता के बराबर दे सकता है। यही नहीं, वह एक वस्तु को खरीदते समय अन्य वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिताओं को भी ध्यान में रखता है। ठीक

इसी प्रकार का काम व्यवस्थापक करता है। उसका भी यही अधिक से अधिक लाभ उठाने का उद्देश्य होता है। उत्पत्ति के साधनों की सेवाओं को सरीसृप समय वह उनकी उत्पादन-शक्ति अथवा उत्पादितता (productivity) का अनुमान लगाता है और उसी के आधार पर उनकी कीमत तय करता है। चूँकि सब साधन एक साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए कुल उत्पत्ति में से यह मालूम करना कि कितना भाग किस साधन के कारण तैयार हुआ है, सम्भव नहीं है। फिर किस तरह किसी साधन की उत्पादितता का अनुमान लगाया जा सकता है? इसका एक हल है। यह कहना तो ठीक है कि हमारे लिए यह मालूम करना सम्भव नहीं है कि पूँजी के कारण कितनी उत्पत्ति हुई है और कितनी भूमि अथवा श्रम के कारण। लेकिन इन बातों का अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि किसी एक साधन की सीमान्त उत्पादितता (marginal productivity) कितनी है।

उदाहरण के लिए मान लो कि उत्पत्ति के साधनों को किसी विशेष अनुपात में मिलाया गया है जिसमें श्रम की संख्या १०० है और कुल उत्पत्ति ५०० इकाई के बराबर है। अन्य साधनों की मात्राएँ उसी ही रहते हुए, मान लो श्रम की संख्या १०० में बढ़ाकर १०१ कर दी जाती है और इस कारण कुल उत्पत्ति ५१० इकाई हो जाती है। कुल उत्पत्ति में इस तरह जो १० इकाई की वृद्धि हुई है, वही श्रम की सीमान्त उत्पादितता होगी। व्यवस्थापक श्रम को अधिक से अधिक १० इकाई के मूल्य के बराबर पारित्यक्तिक दे सकता है, इसमें अधिक नहीं। अगर मजदूरी सीमान्त उत्पत्ति के मूल्य से अधिक है तो व्यवस्थापक को हानि होगी। इस कारण वह मजदूरी को संख्या सब तक कम करता जायगा जब तक कि सीमान्त उत्पादितता मजदूरी के बराबर नहीं जा जायगी। अर्थात्, हम यह कह सकते हैं कि व्यवस्थापक की ओर से (अर्थात् धान की ओर से) किसी साधन की सेवा का मूल्य अधिक से अधिक उसकी सीमान्त उत्पादितता के बराबर हो सकता है।

उत्पत्ति के साधनों पर जितका स्वामित्व होता है, वे अपने साधनों के बदले में कुछ मूल्य चाहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उन साधनों की कमी है और उनमें उत्पादन-शक्ति भी है। मित्र-भिन्न व्यवसाय-धन्यों में उनकी माग होती है। इसलिए साधनों के मालिक बिना कुछ मूल्य पाये उन साधनों अथवा उनकी सेवाओं को बेचने के लिए तैयार नहीं होते। जिन स्थानों पर अधिक मूल्य पाने की सम्भावना होती है, वही पर वे अपने साधनों को लगाने की कोशिश करते हैं। उन साधनों को ठीक ढंग से बनाये रखने के लिए उन्हें कुछ खर्च करना पड़ता है। अर्थात् अन्य वस्तुओं की तरह इन साधनों का भी कुछ उत्पादन-व्यय होता है जो इनके मूल्य की न्यूनतम सीमा होती है। यदि किसी साधन का मूल्य उसके सीमान्त उत्पादन-व्यय से कम है तो साधारणतः उस साधन की मेनाएँ उत्पादन के लिए उपलब्ध न हो सकेंगी।

इस तरह विचार करने से पता चलता है कि वस्तुओं के मूल्य की तरह साधनों के मूल्य व पारिश्रमिक के सम्बन्ध में भी दो सीमाएँ होती हैं—एक तो अधिकतम सीमा जो माग की ओर से सीमान्त उत्पादित के आधार पर निर्धारित होती है और दूसरी न्यूनतम सीमा जो पूर्ति की तरफ से सीमान्त उत्पादन-व्यय द्वारा निर्दिष्ट होती है। इन्हीं दोनों सीमाओं के बीच, माग और पूर्ति की विशेष परिस्थितियों के अनुसार, किसी साधन का पारिश्रमिक निर्धारित होगा।

इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि विनिमय और वितरण के सिद्धान्तों में कोई अन्तर नहीं है। जिस प्रकार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है, उसी प्रकार साधनों का मूल्य भी निर्धारित होता है। यह निरावेह ठीक है। फिर भी साधनों के पारिश्रमिक व मूल्य-निर्धारण को अलग अध्ययन किया जाता है क्योंकि साधनों की पूर्ति और माग पूरी तरह से वस्तुओं की पूर्ति और माग के समान नहीं है। उदाहरणार्थ, भूमि की पूर्ति बिल्कुल निर्दिष्ट है, इसे मूल्य के अनुसार घटाय़ा-बढ़ाय़ा

नहीं जा सकता। अन्य साधनों की पूर्ति में कमी-बेशी लाई जा सकती है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस प्रकार किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। श्रम की पूर्ति अन्ततः जनसंख्या पर निर्भर करती है और इसमें जल्दी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा साधनों के उत्पादन-व्यय को आसानी से ठीक-ठीक मालूम नहीं किया जा सकता। अस्तु, यद्यपि वस्तुओं और साधनों के मूल्य-निर्धारण में कोई मौलिक व सैद्धान्तिक भेद नहीं है, दोनों का मूल्य अन्ततः माग और पूर्ति के सिद्धान्त द्वारा निर्धारित होता है, फिर भी साधनों के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें देखने में आती हैं। अतः इनका अलग अध्ययन करना ही अच्छा होगा। हम अगले अध्यायों में साधनों के पारिश्रमिक सम्बन्धी बातों पर अलग-अलग विचार करेंगे।

## QUESTIONS

- 1 How and when does the problem of distribution arise? Is the distribution of income of any social significance?
- 2 What is national dividend? How is it calculated?
- 3 How is the share of the factors of production determined? Explain briefly

## अध्याय ३८

### मजदूरी

(Wages)

श्रमिकों को उनके काम या सेवाओं के बदले में जो पारिश्रमिक दिया जाता है, उसे मजदूरी (wages) कहते हैं। “श्रम” शब्द के अन्तर्गत हम सब प्रकार के श्रमिकों को सम्मिलित करते हैं। इसलिए श्रमिक का कार्य चाहे कुशल हो या साधारण उसके पारिश्रमिक को मजदूरी ही कहेंगे।

वैसे तो काम लेने और मजदूरी देने के अनेक तरीके हैं लेकिन इनमें दो मुख्य हैं— एक तो समय के अनुसार मजदूरी या समय-मजदूरी (time wages) और दूसरे काम के गुण-परिमाण के अनुसार मजदूरी या अनुक्रम मजदूरी (piece wages)। पहले तरीके में एक खास समय के आधार पर मजदूरी दी जाती है जैसे ५०० रु० प्रति माह या ५ रु० प्रतिदिन। दूसरे तरीके में कार्य के गुण-परिमाण के विचार से मजदूरी निश्चित की जाती है। इसमें यह तय कर लिया जाता है कि इतने और इस तरह के काम के लिए इतनी मजदूरी दी जायगी। मजदूरी देने के इन दोनों तरीकों के अपने खास गुण और अवगुण हैं जिन पर मक्षेप में नीचे विचार किया जाता है।

### समयानुसार मजदूरी

(Time Wages)

वर्तमान समय में इस प्रणाली का अधिक प्रचार है। बहुत प्राचीन काल से यह प्रणाली चली आ रही है। मजदूरी देने का यह तरीका बहुत



शरत और सीधा है। इसके समझने में किसी को कठिनाई नहीं होती। और फिर कुछ कार्य ऐसे हैं जहाँ केवल इसी तरीके से मजदूरी देना सम्भव है, जैसे मैनजर, निरीक्षक आदि के कार्य। निरीक्षक का काम ऊपरी प्रबन्ध और देख-रेख होता है। इस काम को पूरी तरह से मापने के लिए कोई मापदण्ड नहीं है। इस कारण किये हुए काम के गुण और परिमाण के आधार पर निरीक्षक को मजदूरी देना सम्भव नहीं है। इसी तरह यह तरीका उन स्थानों पर विशेषतया सुविधाजनक है जहाँ कार्य की पूर्णता और सुचारुता अत्यन्त आवश्यक है अथवा जहाँ बड़ी कीमती मशीनों को प्रयोग में लाया जाता है। यह तरीका कार्य करने में जल्दबाजी को रोककर काम को सराब नहीं होने देता। मजदूरी भुगतान करने का यह ढंग धमिकों के दृष्टिकोण से भी काफी लाभप्रद है। उन्हें इस बात का पहले से ही ज्ञान होता है कि एक निश्चित समय में उन्हें कितनी मजदूरी मिलेगी। इसके आधार पर वे अपने व्यय की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही वे इस चिन्ता से भी बचे रहते हैं कि भगले दिन उन्हें कितनी मजदूरी मिल सकेगी।

इन सब अच्छाइयों के होने हुए भी इस प्रणाली में एक बड़ा अवनुगुण है। वह यह है कि मजदूरी को औरों से अधिक और अच्छा काम करने के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं मिलता। निपुण धमिक को अधिक काम करने के बदले में कोई विशेष पुरस्कार नहीं मिलता। फलस्वरूप वह भी साधारण मजदूरों के धरातल पर आ जाता है। इनके अतिरिक्त मजदूरी निश्चित होने के कारण धमिकों में शिथिलता आ जाती है, उनमें काम ढालने की आदत पड़ जाती है। इस कारण मालिक को मजदूरों पर देख-रेख करने के लिए कई निरीक्षकों को नियुक्त करना पड़ता है। इससे उत्पादन-व्यय बढ़ जाता है।

### कार्यानुसार मजदूरी

(Piece Wages)

आजकल अनुकर्म व कार्य-मजदूरी प्रणाली का अधिक प्रचार होता

जा रहा है। बहुत-कुछ अद्य तक मजदूर और मालिक दोनों के लिए यह प्रणाली लाभप्रद है। जितना अधिक और अच्छा काम कोई श्रमिक करेगा, उतनी ही अधिक उसे मजदूरी मिलेगी। अस्तु, यह प्रणाली योग्यता और परिश्रम से कार्य करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत अधिक योग्यता व कार्यक्षमता प्रदर्शित करके कुशल और अनुभवी श्रमिक को अधिक मजदूरी प्राप्त करने का पूरा अवसर मिल जाता है। इससे श्रमिकों को ही नहीं बल्कि मालिक को भी लाभ होता है। जो कुछ मजदूरी वह अपने मजदूरों को देता है, उसे उसका पूरा फल मिल जाता है और साथ-साथ देख-रेख का खर्च भी बहुत कम पड़ता है। किन्तु कार्यानुसार मजदूरी प्रणाली में भी कई हानियाँ व दोष हैं। सबसे बड़ा दोष यह है कि श्रमिक ज्यादा से ज्यादा मजदूरी कमाने के लिए काम में जल्दबाजी करने लग जाते हैं जिससे काम खराब और घटिया बित्तम का होता है। अधिक और जल्दी से काम करने में केवल काम ही खराब नहीं होता बल्कि श्रमिकों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ज्यादा काम करने के कारण उनकी कार्य-शक्ति गिर जाती है और जीवन अपवि भी घटने लगती है। इसके अनिश्चित इस प्रणाली के फलस्वरूप समजीवियों में परस्पर होड़ और ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण मजदूर-सब कमजोर पड़ जाता है और इस प्रकार मजदूरों के हितों की पूरी रक्षा नहीं हो पाती।

मजदूरी देने के सतोषजनक तरीके के लिए उपयुक्त दोनों प्रणालियों का मिश्रण आवश्यक है जिससे दोनों की अच्छाइयों से लाभ उठाया जा सके। उस दशा में निश्चितता भी होगी और योग्य अगतीवियों को अपनी विशेष योग्यता का लाभ लठाने का अवसर भी मिल सकेगा।

### नकदी तथा वास्तविक मजदूरी

(Money and Real Wages)

साधारणतः वर्तमान समय में मुद्रा के रूप में ही मजदूरी दी जाती है। जो कुछ मजदूरी किसी श्रमिक को रुपये-पैसे या मुद्रा के रूप में

मिलती है, उसे मौद्रिक, नकदी या नाममात्र की मजदूरी (money or nominal wages) कहते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि मुद्रा द्वारा आवश्यकताओं को सीधे तौर से पूर्ण नहीं किया जा सकता। मुद्रा तो केवल विनिमय का एक साधन है। इसमें अन्य वस्तुएँ खरीदी जा सकती हैं। अस्तु, श्रमिकों के लिए जो महत्वपूर्ण बात है, वह यह नहीं कि उन्हें कितनी नकदी मजदूरी मिलती है, बल्कि यह कि नकदी मजदूरी के बदले में उन्हें कितनी अन्य वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त हो सकती हैं। दूसरे शब्दों में, श्रमिक के लिए नकदी मजदूरी का स्वतः कोई महत्व नहीं होता। नकदी मजदूरी तो वह इसलिए स्वीकार करना है ताकि उसके बदले में वह आसानी से अपनी इच्छानुसार वस्तुएँ खरीद सके। इसमें यह स्पष्ट है कि मजदूरी की वचार्थ आर्थिक स्थिति नकदी मजदूरी पर नहीं, बल्कि वास्तविक मजदूरी पर निर्भर होती है। “वास्तविक मजदूरी”-(real wages) से अभिप्राय उन तमाम वस्तुओं और सेवाओं से है जो किसी श्रमिक को उसके काम के बदले में प्राप्त होती हैं। भिन्न-भिन्न कार्यों में से किसी एक को चुनते समय श्रमिक मुख्यतः वास्तविक मजदूरी को ही देखता है। अतः उन बातों पर विचार करना आवश्यक है जिनमें वास्तविक मजदूरी निर्धारित होती है। मुख्यरूप से वास्तविक मजदूरी निम्नलिखित बातों द्वारा निश्चित होती है —

(१) मूल्य-स्तर—वस्तुओं का मूल्य सब स्थान और समय पर एक समान नहीं होता। कुछ स्थानों पर वस्तुओं का मूल्य कम होता है, और कुछ स्थानों पर अधिक। इसका प्रभाव वास्तविक मजदूरी पर बहुत पड़ता है। यदि किसी स्थान पर वस्तुएँ सस्ती हैं, तो वहाँ के श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी, महंगे स्थानों के श्रमजीवियों की मजदूरी की अपेक्षा, अधिक होगी। उदाहरण के लिए दो मजदूरों को ले लो जिनकी नकदी मजदूरी बराबर है। मान लो इनमें से एक मेरठ में रहता है और दूसरा दिल्ली में। छोटा शहर होने के कारण मेरठ में दिल्ली की अपेक्षा रहन-सहन का खर्चा कम है। वहाँ चीजें सस्ती हैं। इस कारण बराबर नकदी-

मजदूरी होते हुए भी, गैरठ बाते मजदूर की वास्तविक मजदूरी अधिक होगी ।

(२) **भुगतान का द्रव्य व रूप**—यद्यपि साधारणतया मजदूरी को नकदी मजदूरी ही जाती है, फिर भी प्रायः उनमें से कुछ को उसके अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ, सुविधाएँ आदि भी मिलती हैं, जैसे सेतिहर मजदूरी को प्रायः बिना मूल्य अथवा सस्ते भाव पर अनाज, दूध, घी, आदि वस्तुएँ मिल जाती हैं । इसी प्रकार खानों में काम करने वालों को सस्ता बोयला और मछेरो को मछलियाँ मिल जाती हैं । कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ अवधि समाप्त होने पर पेन्शन मिलनी है । वास्तविक मजदूरी का अनुमान लगाते समय हमें इस प्रकार के सब लाभों की गणना करनी होगी । ऐसी दशा में नकदी मजदूरी के कम रहने पर भी वास्तविक मजदूरी बहुत अधिक हो सकती है ।

(३) **कार्य का रूप**—कार्य का रूप भी विरोध महत्व रखता है । कुछ काम बहुत ही कठिन और खतरनाक होते हैं जिनके करने में शरीर और मस्तिष्क पर बहुत जोर पड़ता है, मृत्यु या चोट लग जाने का डर रहता है और उनमें तरह-तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ता है । इन कारणों से वहाँ के श्रमिकों की कार्य करने की अवधि घट जाती है । फिर कुछ काम ऐसे भी हैं जो बहुत गन्दे और अशुभ होते हैं, जो उन्नति और सम्मान में बाधक होते हैं । ऐसे धंधों में नकदी मजदूरी अधिक होने पर भी वास्तविक मजदूरी कम ही ठहरती है । इसके विपरीत जिन कार्यों में सम्मान प्राप्त होता है, जो रचिकर और स्वास्थ्यकर होते हैं, उनमें वास्तविक मजदूरी अपेक्षाकृत अधिक बैठती है ।

(४) **कार्य का स्थायीपन और नियमितता**—वास्तविक मजदूरी का हिमाय लगाते समय काम की नियमितता और स्थायीपन पर ध्यान देना आवश्यक है । कुछ देशों में लगातार काम नहीं मिलता,—जैसे खेती, गृह-निर्माण अथवा गुड फेरने का काम । मछलीगारों और जहाजी

व्यवसाय में जो काम मिलता है, वह भी निश्चित नहीं होता। इस प्रकार के धन्यो में श्रमजीवियों को कभी काम मिल जाता है और कभी उन्हें बेकार बैठना पड़ता है। काम निश्चित तथा लगातार न होने के कारण इन धन्यो में वास्तविक मजदूरी अपेक्षाकृत कम होती है।

(५) पुरक आय के अवसर—इस सम्बन्ध में पुरक आय के अवसरों का महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ काम इस ढंग के होते हैं जहां श्रमिकों को काफी अवकाश मिलता है जिसका उचित उपयोग करके वे अपनी आय अन्य माधनों द्वारा बढ़ा सकते हैं। उदाहरणतः एक अध्यापक शांति समय में पुस्तकें लिख कर अथवा विद्यार्थियों को अलग पड़ा कर अपनी आय बढ़ा सकता है। इस प्रकार के अवसरों से कम तकदी मजदूरी होने पर भी वास्तविक मजदूरी बढ़ सकती है। किन्तु हर एक काम में ऐसे अवसर प्राप्त नहीं होते।

(६) सफलता और उन्नति की आशा—मजिदिय में उन्नति और अधिक मजदूरी मिलने की संभावना से धर्मिक दुरु में अन्य स्थानों से कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि दीर्घकालीन दृष्टिकोण में इस तरह के काम में वास्तविक मजदूरी अधिक होती है। जिन धन्यो में उन्नति के अवसर कम अथवा बिल्कुल नहीं होते उनमें वास्तविक मजदूरी कम होती है।

(७) काम सीखने का समय और खर्चा—कुछ पेशों जैसे डाक्टरों, इंजीनियरों आदि में बहुत लम्बी और महंगी शिक्षा तथा ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, खोदने का काम, दूध डोने का काम आदि ऐसे धन्यो हैं जिनमें किसी विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। धर्मिक छोटी उम्र में ही इन कामों को करने लग जाते हैं। लेकिन डाक्टर, वकील आदि के लिए यह सम्भव नहीं है। वास्तविक मजदूरी का अनुमान लगाने समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है।

(८) व्यापार सम्बन्धी व्यय—कुछ पेशों में दूसरों की अपेक्षा व्यापार-सम्बन्धी व्यय अधिक होते हैं। वकीलों को पूरा दफ्तर रखना

पड़ता है, पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं और कचहरी में एक विशेष धेस-भूषा मूल्यस्थित होना पड़ता है अर्थात् उन्हें एक खास प्रकार की मजबूत और साज-सामान की जरूरत पड़ती है। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को इन सब की कोई आवश्यकता नहीं होती। वास्तविक मजदूरी मान्य करते समय नकदी मजदूरी में से इस प्रकार के खर्च घटा देने चाहिए। नकदी आय अधिक होने पर भी यदि व्यावसायिक-व्यय भी अधिक करना पड़ा तो वास्तविक आय अपेक्षाकृत कम ही होगी।

(९) काम करने का काल—वास्तविक मजदूरी का अनुमान लगाने समय प्रतिदिन कार्य करने के घण्टे और छुट्टियों की गिनती का भी ध्यान रखना आवश्यक है। जब हम प्रातः ९ बजे से रात्रि तक कार्य करने वाले बैंक के कर्मचारी की तुलना दो अथवा तीन घण्टे निरपेक्ष पढ़ाने वाले और बहुत अधिक छुट्टियां पाने वाले कालेज के प्रोफेसर से करते हैं, तब यह अन्तर स्पष्ट हो जाता है। नकदी आय थोड़ी कम होने पर भी प्रोफेसर की वास्तविक आय इस कारण अधिक ही ठहरेगी।

गिन्नत-भित्त रचना तथा उद्योग-धन्धों में काम करने वाले मजदूरों की आर्थिक स्थिति की तुलना करते समय नकदी और वास्तविक मजदूरी का अन्तर ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि किसी मजदूर को ५०० रुपये मासिक वेतन मिलता हो और दूसरे को केवल ४५० रुपये मासिक, तो यह कोई आवश्यक नहीं कि ५०० रु० पाने वाले मजदूर की आर्थिक स्थिति दूसरे की अपेक्षा अधिक अच्छी ही हो। किसी मजदूर की आर्थिक स्थिति का निर्णय उसकी वास्तविक मजदूरी से हो किया जा सकता है, न कि उसकी नकदी मजदूरी द्वारा। नकदी मजदूरी कम होने पर भी वास्तविक मजदूरी अधिक हो सकती है और नकदी मजदूरी अधिक होने पर भी वास्तविक मजदूरी अपेक्षाकृत कम हो सकती है।

### मजदूरी-निर्धारण

(Wage-Determination)

मजदूरी सम्बन्धित समस्याओं में से हम यहाँ केवल दो पर ही विचार

करेंगे। प्रथम यह कि मजदूरी की दर कैसे निर्धारित होती है और दूसरे विभिन्न धर्मिकों की मजदूरी की दरों में इतना अंतर क्यों होता है ? पहले मजदूरी-निर्धारण को ही ले लिया जाय।

अर्थशास्त्रियों ने निम्न-भिन्न समय पर मजदूरी निर्धारित करने के भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। इनमें से मुख्य ये हैं जीवन्त-निर्वाह-मजदूरी-सिद्धान्त, मजदूरी-कोष-सिद्धान्त, अवशिष्ट अधिकार सिद्धान्त और सीमान्त उत्पादित-सिद्धान्त-। इनके असतोपजनक गिद्ध होने के कारण अब इनका स्थान आधुनिक सिद्धान्त ने ले लिया है जिसे मजदूरी की माग और पूर्ति सिद्धान्त कहते हैं। मजदूरी के निर्धारण का यह सिद्धान्त सर्वथा वैसा ही है जैसा कि मूल्य-निर्धारण का सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के अनुसार वस्तुओं के मूल्य की भाँति मजदूरी भी धर्म की माग और उसकी पूर्ति के परस्पर प्रभाव के फलस्वरूप निर्धारित होती है। मजदूरी की दर उस स्थान पर निर्धारित होती है जहाँ पर धर्म की माग और पूर्ति बराबर होती है। यदि धर्म की माग पूर्ति से अधिक है तो मजदूरी की दर ऊँची होगी, और यदि धर्म की पूर्ति माग से अधिक है तो मजदूरी की दर कम ब नीची होगी। अब हम यहाँ पर धर्म की माग और पूर्ति का अलग-अलग अध्ययन करके यह देखेंगे कि दोनों के पारस्परिक प्रभाव से किस प्रकार मजदूरी की दर निर्धारित होती है।

### धर्म की माग

(Demand for Labour)

हम किसी वस्तु की माग इसलिए करते हैं कि उसमें उपयोगिता होती है और यही कारण है कि हम उस वस्तु के बदले में कुछ मूल्य देने के लिए तैयार होते हैं। अधिक में अधिक मूल्य जो हम किसी वस्तु के लिए देने को तैयार हो सकते हैं, वह उसकी सीमान्त उपयोगिता के बराबर होगा। इसमें अधिक मूल्य देने में हमें हानि होगी। अतएव हम उस वस्तु को न खरीदेंगे। ठीक यही बात धर्म की माग के लिए लागू है। धर्म की माग व्यवसायी करता है क्योंकि उत्पादन कार्य में धर्म की आवश्यकता

पहती है। दूसरे शब्दों में, धर्म की मांग उससे उत्पादन-शक्ति के कारण होती है। अब प्रश्न यह है कि एक व्यवसायी कहा तक मजदूरों को काम पर लगाता जायगा और कितनी मजदूरी देने को तैयार हो सकेगा। इसका उत्तर देना सरल है। व्यवसायी उस समय तक धर्म को काम पर लगाता जायगा जब तक कि उसे ऐसा करने में लाभ होगा। यह लाभ धर्म की उत्पादिता और उसकी मजदूरी पर निर्भर है। यदि उत्पादिता मजदूरी से अधिक है, तो व्यवसायी को मजदूरों की संख्या बढ़ाने से लाभ होगा। किन्तु यह दशा बराबर बनी नहीं रह सकती, क्योंकि यह अनुभव सिद्ध बात है कि यदि उत्पत्ति के अन्य साधन वैसे ही रखे जाय और किसी विशेष साधन की मांग लगातार बढ़ाई जाय, तो एक अवस्था के बाद उत्पत्ति-धाम-नियम लागू होने लगता है, अर्थात् उस साधन की सीमान्त उत्पादिता कमश घटने लगती है। इसलिए अगर व्यवसायी मजदूरों की संख्या बढ़ाता जायगा, तो उसे भी इस बात का अनुभव करना पड़ेगा। धर्म की सीमान्त उत्पादिता कुछ समय के बाद घटने लगेगी। आगे चलकर एक ऐसी अवस्था भी आ पहुँचेगी जबकि सीमान्त उत्पत्ति कमश घटने-घटते मजदूरों के बराबर हो जायगी। यदि व्यवसायी को हर बात का पूरा-पूरा ज्ञान है, तो वह इस सीमा के बाद और मजदूरों को काम पर न लगायेगा क्योंकि ऐसा करने से सीमान्त उत्पत्ति मजदूरी से कम हो जायगी जिनसे उसे हानि होगी। जिस श्रमिक को काम पर लगाने से सीमान्त उत्पादन अथवा उसका मूल्य मजदूरी के बराबर हो जाता है, उसे "सीमान्त श्रमिक" कह सकते हैं। इस श्रमिक को अधिक से अधिक सीमान्त उत्पादन के गृह्य के बराबर मजदूरी दी जा सकती है। जब हम श्रमिकों के किसी एक समूह के बारे में विचार कर रहे हैं, तो उस समूह के सीमान्त और अन्य श्रमिकों की उत्पादन शक्ति को एक ममान मान सकते हैं। फलस्वरूप उस समूह के प्रत्येक श्रमिक की मजदूरी बराबर होगी। यह मजदूरी वह होगी जो व्यवसायी सीमान्त श्रमिक को देने के लिए तैयार हो सकता है। अस्तु, जहां तक धर्म की मांग



के पक्ष का प्रश्न है, मजदूरी सीमान्त उत्पादिता पर निर्भर करती है। व्यवसायी श्रम के बदले में अधिकसे अधिक इसी को बराबर मूल्य व मजदूरी दे सकता है।

### श्रम की पूर्ति (Supply of Labour)

एक विशेष मूल्य पर काम के लिए प्रस्तुत की गयी श्रम-शक्ति को श्रम की पूर्ति कहते हैं। श्रम की पूर्ति के अन्तर्गत हम उन सब श्रमिकों की गणना करते हैं जो मजदूरी पर काम करने को तैयार हैं। इसके अर्थ इसके अन्तर्गत उन घण्टों की जितनी देर प्रत्येक श्रमिक कार्य करने को तैयार है और उसके काम करने की तेजी की भी गणना की जाती है। जिस प्रकार उत्पादन की लागत वह सीमा निश्चित करती है जिसमें नीचे साधारणतः वस्तु का मूल्य नहीं जा सकता, उसी प्रकार मजदूरी का जीवन-स्तर वह सीमा है जिसके नीचे आम तौर से मजदूरी की दर नहीं गिर सकती। श्रमिक के जीवन-स्तर के अन्तर्गत हम उन सब आवश्यक, आराम तथा विलास की वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं जिनके उपभोग का वह आदी हो गया है। साधारण तौर पर कोई भी श्रमिक ऐसी मजदूरी स्वीकार करने को तैयार न होगा जिससे उसका जीवन-स्तर बना नहीं रह सकता। अतः श्रम की पूर्ति-पक्ष में एक न्यूनतम सीमा है जिसमें नीचे साधारणतः मजदूरी नहीं जा सकती। यह सीमा श्रमिक के जीवन-स्तर द्वारा निर्धारित होती है।

यद्यपि बहुत-सी बातों में श्रम अन्य वस्तुओं के समान है, फिर भी श्रम की पूर्ति में कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिनमें इसमें और अन्य वस्तुओं की पूर्ति में काफी अन्तर होता है। श्रम के परिच्छेद में हम इन विशेषताओं की चर्चा कर चुके हैं। मजदूरी के बारे में माग और पूर्ति सिद्धान्त का प्रयोग करते समय इन विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।

### माँग और पूर्ति का परस्पर प्रभाव (Interaction of Demand and Supply)

हम ऊपर देख चुके हैं कि माँग के पक्ष से सीमान्त उत्पादिता मजदूरी की उच्चतम सीमा निर्धारित करती है और पूर्ति के पक्ष से जीवन-स्तर न्यूनतम सीमा का निर्धारक है। मजदूर और मालिक के पारस्परिक सौदा करने की शक्ति के अनुसार इन्हीं दोनों सीमाओं के बीच में मजदूरी की दर निश्चित होती है। यदि मालिक या व्यवसायी को सौदा करने की शक्ति अधिक है तो मजदूरी न्यूनतम सीमा की ओर झुकेगी और यदि श्रमिकों की सौदा करने की शक्ति, मजदूर-सम अथवा अन्य किसी कारण से अधिक है तो मजदूरी उच्चतम सीमा के निकट होगी। किन्तु साधारणतः मालिक की अपेक्षा मजदूरों की सौदा करने की शक्ति कमजोर होती है। इसलिए मजदूरी अधिकतर जीवन-स्तर द्वारा निर्धारित निम्नतम सीमा के निकट ही निश्चित होती है। पूरा प्रतियोगिता की स्थिति में मजदूरी श्रम की सीमान्त उत्पादन के मूल्य के बराबर होगी।

### मजदूरी में अन्तर (Differences in Wages)

अभी तक हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे थे कि मजदूरी की दर कैसे निर्धारित होती है। अब हमारे सामने एक और प्रश्न है जिस पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक है। वह है मजदूरी की दरों में अन्तर। हम देखते हैं कि अलग-अलग धन्यों में काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी की दरें भिन्न-भिन्न होती हैं। यही नहीं, एक ही व्यवसाय अथवा धन्य में श्रमिकों की मजदूरी की दरों में काफी अन्तर होता है। मजदूरी की दरों में इस भिन्नता के क्या कारण हैं? किसी एक व्यवसाय में मजदूरों अन्य व्यवसायों की अपेक्षा कम या अधिक क्यों होती है? मजदूरों की दरों की विभिन्नता के कुछ महत्वपूर्ण कारणों का विश्लेषण नीचे किया जाता है।

(१) उत्पादित का मजदूरी पर विशेष प्रभाव पड़ता है । नियम के तौर पर श्रमिक की जितनी अधिक उत्पादन-शक्ति होगी, उतनी ही अधिक उनकी मजदूरी होगी । सब मजदूरी की उत्पादन-शक्ति बराबर नहीं होती । उदाहरणार्थ निपुण श्रमिक की उत्पादन-शक्ति साधारण मजदूर से कहीं अधिक होती है । इसलिए दोनों की मजदूरी की दरों में काफी अन्तर होता है ।

(२) भिन्न-भिन्न प्रकार के धम के लिए माग की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है । कुछ प्रकार के धम के लिए माग अधिक होती है, और कुछ के लिए कम । माग में अन्तर होने के कारण मजदूरी की दरों में भी अन्तर हो जाता है । यही नहीं, धम की माग मदा एक समान बनी नहीं रहती । फैशन, उत्पादन प्रणाली, लोगों की आय आदि में परिवर्तन होने से कुछ प्रकार के श्रमिकों की माग अधिक हो जाती है और कुछ की कम । माग में इस प्रकार की भिन्नता आ जाने से उनकी मजदूरी की दरों में भी भिन्नता आ जाती है ।

(३) विभिन्न व्यवसायों व धन्यों में धम की पूर्ति भिन्न-भिन्न होती है । कुछ धन्यों में धम की पूर्ति की मात्रा बहुत कम होती है, और कुछ में अधिक । अतः पहले धन्यों में दूसरों की अपेक्षा मजदूरी की दर अधिक होगी । भिन्न-भिन्न धन्यों में धम की मात्रा की कमी अथवा अधिकता मपो होती है, इतको मालूम करना कठिन नहीं है । कुछ धन्यों में ऐसे विशेष गुण रखने वाले मजदूरों की आवश्यकता होती है जो मरणा से बहुत कम होते हैं । इस कारण अधिक मजदूरी वाले धन्यों में काम करने की योग्यता न रखने के कारण बहुत-से मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है । किन्तु सबसे बड़ी बात है काम रखने का खर्चा । कुछ धन्यों के सीखने में इतना अधिक खर्च पड़ता है कि बहुत ही बड़े मजदूर उन्हें सीख पाते हैं । स्वाभाविक योग्यता होने पर भी यहूदा निर्धनता के कारण बहुत-से मजदूरों के लिए अधिक मजदूरी वाले देशों में काम करने के लिए आवश्यक शिक्षा पाना अमम्भव हो जाता है ।

सुगमता और सस्ते में सीखे जाने वाले धन्वों की अपेक्षा इन महंगे पेशों में धन की पूर्ति की माशा बहुत कम होती है। इस कारण भिन्न-भिन्न व्यवसायों में मजदूरी की कमी या अधिकता होने से मजदूरी भिन्न-भिन्न होती है।

(४) किसी पेशे के रुचिकर अथवा अरुचिकर होने से भी मजदूरी की दरों में भिन्नता आ जाती है। जब काम एक बराबर रुचिकर नहीं होते। कुछ काम तो बहुत ही अरुचिकर, खतरनाक और अनिश्चित होते हैं। अधिक छुट्टियों वाले, मानप्रब, सुरक्षित और निश्चित पेशों की अपेक्षा ऐसे अरुचिकर पेशों में मजदूरी की दरें अधिक होगी। यदि ऐसा न हो तो मजदूर उन बेखिम और अरुचिकर धन्वों में जाना पयो वसन्द करेंगे। लेकिन प्रायः यह देखा जाता है कि गन्दे पेशों में मजदूरी बहुत कम होती है जैसे भारतवर्ष में भगी का धन्वा। इसका कारण यह है कि इस काम को करने के लिए किसी विशेष योग्यता या शिक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती और काम करने वालों की मरुया बहुत होती है, क्योंकि भारतीय समाज के रीति-रिवाज ऐसे हैं कि अन्य धन्वों में जाने के लिए भगी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनकी मजदूरी कम है।

(५) इसके अतिरिक्त कुछ धन्वों में दूसरे धन्वों से अधिक संगठित होने के कारण मजदूरी को अधिक मजदूरी मिलती है। संगठन द्वारा मजदूरी की शक्ति बढ़ जाती है और प्रायः वे मजदूरी बढ़ाने की माग को पूरा कराने में सफल होते हैं। जिन पेशों में मजदूरी में इस तरह की शक्ति नहीं होती, वहाँ मजदूरी की दरें बहुत कम होती हैं। मजदूरी की दरों की भिन्नता में कुछ हद तक रीति-रिवाज और परम्परा का भी हाथ होता है।

उपर्युक्त बातों से पता चलता है कि विभिन्न व्यवसायों या धन्वों में मजदूरी की दरें भिन्न-भिन्न क्यों होती हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि जब मजदूर एक समान योग्य, कुशल, गढ़ और शिक्षित नहीं होते और न ही उनमें आपस में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। भिन्न-भिन्न व्यवसायों में प्रवेश

करने की पूर्ण स्वतन्त्रता श्रमिकों को नहीं होती और न उनमें पूर्ण गति-शीलता ही होती है। फलस्वरूप कुछ धन्यो में बहुत ऊँची मजदूरी होती है और कुछ में बहुत कम। पूर्ण प्रतियोगिता और गतिशीलता के अभाव के कारण मजदूरी की दरों में भिन्नता बनी रहती है। पर इसका यह ज़ात नहीं कि पूर्ण प्रतियोगिता और गतिशीलता के होने पर मजदूरी की दरों की भिन्नता दूर हो जायगी। थोड़ी देर के लिए यदि यह मान भी लिया जाय कि सब मजदूर एक समान योग्य और कुशल हैं और प्रत्येक मजदूर को अपनी रुचि के अनुसार किसी व्यवसाय में प्रवेश करने की पूर्ण स्वतन्त्रता और सुविधा है, तो भी मजदूरी की दरें एक समान नहीं होंगी। इसका कारण यह है कि सब धन्ये एक जैसे नहीं होते। कुछ धन्ये श्रमिक रहते हैं, कुछ अवशिकर। किसी धन्ये में उन्नति और सफलता की बड़ी गुंजा-यश होती है किसी में कम। कुछ धन्ये ऐसे हैं जिनके सीखने में बहुत समय लगता है और खर्च भी बहुत होता है और इससे विपरीत कुछ धन्यो को बहुत शीघ्र और कम खर्च में आसानी से सीखा जा सकता है। इसके अति-रिक्त कुछ धन्यो में काम बराबर मिलता रहता है, काम करने वाले पर भरोसा किया जाता है, और उन कार्यों से समाज में सम्मान प्राप्त होता है। पर दूसरी ओर कुछ धन्ये घृणा की दृष्टि में देखे जाते हैं या उनमें लगा-तार काम नहीं मिलता। इन सब कारणों से विभिन्न व्यवसायों और धन्यो में मजदूरी की दरें भिन्न-भिन्न होती हैं। यदि ऐसा न हो तो अवशि-कृत, जोखिम, नीरस और भारी धन्यो में जाने के लिए कोई भी तैयार न होगा।

### स्त्रियों की मजदूरी

(Women's Wages)

सामान्य रूप से स्त्रियों की मजदूरी से कम मजदूरी मिलती है। इसके कई कारण हैं। एक तो यह है कि साधारणतः उनकी शारीरिक-शक्ति और योग्यता पुरुषों से कम होती है। उन धन्यो में जहाँ शारीरिक शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है, स्त्रियों की उत्पादितता पुरुषों से कम

होती है। इस कारण उनको कम मजदूरी मिलती है। यह ठीक है कि कुछ ऐसे काम हैं, जैसे शिशुपालन आदि, जिनमें पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक योग्य और कुशल होती हैं, किन्तु ऐसे कामों की संख्या बहुत कम है। इसलिए सामूहिक रूप से स्त्रियों की मजदूरी अपेक्षाकृत कम होती है। दूसरे, स्त्रियों को बहुत छोटे कामों में से ही चुनाव करना पड़ता है। रीति-रिवाज, परम्परा, कानूनी व्यवस्था अन्य प्रतिबंधों के कारण स्त्रियों के लिए बहुत कम व्यवसाय या पेशे खुले होते हैं। फलस्वरूप स्त्रियों को छोटे में घघों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस सीमित कार्य-क्षेत्र में स्त्रियों में परस्पर अधिक होड़ होने के कारण मजदूरी कम हो जाती है। तीसरे, अधिकतर स्त्रियाँ स्थायी रूप से काम नहीं करती। वे केवल छोटे समय तक के लिए ही काम करती हैं और विवाह आदि हो जाने पर काम छोड़ देती हैं। इस कारण वे अधिक मजदूरी वाले धंधों के लिए तम्बी अवधि तक शिक्षा लेने को तैयार नहीं होती। और न मालिक ही उन्हें इस तरह के काम देने के लिए तैयार होने हैं क्योंकि वे जामते हैं कि स्त्रियाँ स्थायी रूप से काम न करेंगी। अतएव उन्हें इस प्रकार के काम सीधे जामते हैं जो आसानी से सीखे और किये जा सकते हैं और जिनके फल में सारे काम को कोई विशेष धक्का नहीं लगता। फलस्वरूप उनको कम मजदूरी मिलती है। चौथे, प्रायः स्त्रियों के उत्तरदायित्व पुरुषों में कम होते हैं। जबकि उन्हें केवल अपना ही पालन करना होता है और कभी-कभी वे इस उत्तरदायित्व में भी मुक्त होती हैं। इसलिए वे कम मजदूरी भी स्वीकार न कर लेती हैं। पांचवें, मजदूर-श्रम के रूप में सुसंगठित न होने के कारण स्त्रियों की सौदा करने की शक्ति पुरुषों से कम होती है। अतएव उन्हें प्रायः कम मजदूरी स्वीकार करनी पड़ती है।

### मजदूरी और कार्य-कुशलता

(Wages and Efficiency)

ऊपरी तौर से यह माहूम पड़ता है कि यदि व्यवसायी श्रमिकों को कम से कम मजदूरी दे और ज्यादा से ज्यादा समय तक उनमें काम लें

तो उन्हें अधिक लाभ होगा। किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। व्यवसायियों का अनुभव भी इस बात की पुष्टि करता है। यदि मजदूरी बहुत कम दी जाती है, तो दैनिक अपना और अपने कुटुम्ब का पालन ठीक ढंग से न कर सकेंगे। उनका जीवन-स्तर नीचे गिरने लगेगा और इस कारण उनकी कार्यक्षमता में भी कमी आ जायगी। इसका प्रभाव उत्पादन पर अवश्य ही बुरा पड़ेगा। फलस्वरूप व्यवसायी के लिए कम मजदूरी देना लाभप्रद न होगा क्योंकि इससे उत्पादन कम और बुरा होगा। ठीक यही बात काम करने के घंटों के लिये लागू है। यदि कोई व्यवसायी अपने मजदूरों से धुब देर तक काम लेता है जिससे उत्पादन में वृद्धि होने में उसे लाभ हो तो सम्भव है कुछ दिनों तक ऐसा होता रहे। किन्तु अधिक समय तक यह बात नहीं चल सकती। लगातार कई घण्टा तक काम करने से मजदूरों की कार्य-शक्ति गिर जाती है। काम करते समय उन्हें आलसपन और नींद घेर रहेगी। इस कारण उत्पादन में बार-बार नुटिया होगी और साथ ही साथ काम करने की रफ्तार भी एक सीमा के बाद कम होती जायगी। इन सब बातों का प्रभाव व्यवसायी के लिए अहितकर होगा। अतएव यह योजना कि कम मजदूरी देना या अधिक समय तक काम लेना सस्ता पड़ता है, भूल है। वास्तव में सस्ते मजदूर अन्त में महंगे पड़ते हैं। एक सीमा तक मजदूरी बढ़ाने में दैनिक की उत्पादन-शक्ति में उस अनुपात से कहीं अधिक वृद्धि होगी। कार्य-शक्ति में वृद्धि होने से उत्पादन की मात्रा भी तेजी से बढ़ेगी। इस कारण ऊँची मजदूरी देने पर भी मजदूर महंगे नहीं पड़ते क्योंकि काम साफ और अधिक होने लगता है। उदाहरणतः अमेरिका के मिल-मजदूरों को हिन्दुस्तानी मजदूरों की अपेक्षा चौगुनी मजदूरी दी जाती है। फिर भी वे महंगे नहीं हैं। जहाँ पर कीमती मशीनें प्रयोग की जाती हैं अथवा काम की सफाई अधिक आवश्यक है, वहाँ पर ऊँची मजदूरी देना विशेष रूप से लाभप्रद होता है।

## QUESTIONS

- 1 What are the relative merits and demerits of time and piece wages system ?
- 2 Distinguish between nominal and real wages  
Explain the factors that determine real wages
- 3 How is the wage rate determined ?
- 4 How are wages related to (a) supply of labour and (b) efficiency of labour ?
- 5 Account for the wide differences in wages
- 6 Discuss the causes of inequality of wages  
Why are the wages of women lower than those of men ?
- 7 Is high paid labour dear labour ? Explain fully



## अध्याय ३९

### व्याज

.... Interest

जैसा कि पहले कहा जा चुका है आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में पूँजी का स्थान बहुत ऊँचा और महत्वपूर्ण है। कृषि, उद्योग, व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में पूँजी की विशेष आवश्यकता पड़ती है। इसके उपयोग से धन की उत्पादन-शक्ति बहुत बढ़ जाती है और उत्पादन विभिन्न प्रकार का तथा बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। एक सीमा तक जिस उत्पादन में जितनी ही अधिक पूँजी लगाई जा सकती है, वह उतना ही अधिक, अच्छा और सस्ता होगा। लोगों को उतना ही अधिक काम और सस्ते भाव पर तरह-तरह की चीजें मिल सकेंगी। पूँजी के अभाव में उत्पादन, व्यापार आदि किन्हीं भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ऐसी परिस्थिति में लोगों को काम मिलना मुश्किल हो जायगा और फलस्वरूप देश में बेकारी, गरीबी आदि जटिल समस्याएँ फैलने लगेंगी। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि व्यवसाय की तेजी-मंदी, व्यक्ति और समाज की समृद्धि-दरिद्रता, उन्नति-अवनति बहुत अंशों में पूँजी के उपयोग पर निर्भर है। पूँजी का उपयोग मुख्यतः व्याज के आधार पर निर्धारित होता है। यदि व्याज की दर नीची है, तो साधारण रूप से नये उद्योगों के खोलने तथा पुराने व्यवसायों को फैलाने में पूँजी अतिरिक्त मात्रा में उपयोग की जायगी। फलस्वरूप उत्पादन का परिमाण बढ़ेगा। इसके विपरीत यदि व्याज की दर ऊँची है, तो पूँजी कम मात्रा में लगाई जायगी और फलस्वरूप उत्पादन का कुल परिमाण कम होगा। व्याज की दर के कम या

अधिक होने का प्रभाव केवल उत्पादन पर ही नहीं पड़ता बल्कि वितरण और सामाजिक क्षेत्रों पर भी पड़ता है। वास्तव में व्याज का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, राजकीय अर्थ-व्यवस्था, व्यवसाय-वन, आर्थिक आयोजन आदि अनेक गहत्वपूर्ण विषयों के साथ जुड़ा हुआ है। अतः व्याज का विश्लेषण और अध्ययन हर दृष्टि में बहुत आवश्यक है।

### शुद्ध और कुल व्याज

(Net and Gross Interest)

धनोत्पादन का वह भाग जो पूँजी प्रदान करने वालों को उनकी पूँजी की सेवाओं के बदले में दिया जाता है "व्याज" या "मृद" (Interest) कहलाता है। अर्थात् व्याज उस धन को कहते हैं जो पूँजी के उपयोग के लिए दिया जाता है। इस सम्बन्ध में शुद्ध और कुल व्याज के बीच जो अन्तर है, उसे समझ लेना बहुत जरूरी है। "शुद्ध व्याज" (Net Interest) का आशय उस धन से है जो केवल पूँजी के उपयोग के लिए ही दिया जाता है। यदि पूँजी के उधार देने में कोई जोखिम न हो और न ही उसमें कोई असुविधा, अतिरिक्त अर्थ अथवा किसी प्रकार के कार्य की आवश्यकता हो, तो जो व्याज उस दशा में मिलेगा वह केवल पूँजी के उपयोग के लिए ही होगा। इस तरह के व्याज को, जिसमें पूँजी के उपयोग के अलावा अन्य किसी बात के लिये भुगतान की रकम शामिल नहीं रहती, अर्थशास्त्र में शुद्ध अथवा वास्तविक व्याज कहते हैं। शुद्ध व्याज का उदाहरण देना तो कठिन है क्योंकि सभी प्रकार के ऋणों में कुछ न कुछ जोखिम व असुविधा तो होती ही है। फिर भी इसका अन्दाजा उस व्याज से हो सकता है जो सरकार अपने कर्जों पर देती है। साधारणतः जो कर्ज सरकार को दिया जाता है, उसमें जोखिम और असुविधा नहीं के बराबर होती है। अतः जो व्याज सरकार द्वारा मिलता है, वह लगभग शुद्ध व्याज के समान होता है।

"कुल" अथवा "संकुल व्याज" (Gross Interest) उस सारी रकम व धन को कहते हैं जो उधार लेने वाला माहूकार

अथवा ऋणदाता को लौटाता है । इसमें मूल-व्याज के अलावा अन्य भुगतानों की रकमें भी शामिल रहती हैं जैसे जोखिम के लिए बीमा की रकम, कष्ट और अमुविधाओं के लिए मुआवजे की रकम इत्यादि । यदि हम कुल व मूल व्याज का विश्लेषण करें तो देखेंगे कि हममें मुख्यतः निम्नलिखित भुगतानों की रकमें शामिल रहती हैं —

(१) मूल व्याज (Net Interest)—यह वह रकम है जो क्रेयट पूंजी के उपयोग के बदले में दी जाती है ।

(२) जोखिम के लिए बीमा की रकम—(Insurance against Risk)—माधारणतः उधार देने समय ऋणदाता को कुछ जोखिम उठानी पड़ती है । अतः वह मूल व्याज के अलावा जोखिम का भार अपने ऊपर लेने के लिए बीमे के रूप में कुछ रकम लेता है । किसी ऋण के देने में जितनी अधिक या कम जोखिम होगी, मूल व्याज को उतनी ही अधिक या कम होगी । यह जोखिम दो प्रकार की होती है—

(१) वैयक्तिक जोखिम (personal risks) और (२) व्यापारिक जोखिम (trade risks) । (जब कोई कर्जदार बेईमानी के विचार से या ऋण चुका सकने में असमर्थ होने के कारण ऋण नहीं चुकाना, तब जिस जोखिम का भार ऋणदाता को उठाना पड़ता है वह वैयक्तिक जोखिम कहलाता है) । अर्थात् वैयक्तिक जोखिम का सम्बन्ध उधार देने वाले व्यक्ति के साथ होता है । यह इस कारण पैदा होती है कि कर्जदार बेईमान व निकम्मा निकल सकता है । ऋण देते समय माहूकार को डर लगा रहता है कि कहीं कर्जदार बेईमानी न कर बैठे अथवा निकम्मा न निकल जाय और इस कारण उसकी पूंजी लौट न सके । इस तरह के जोखिम को वैयक्तिक जोखिम कहते हैं । इसके विपरीत व्यापारिक जोखिम का सम्बन्ध उद्योग-धन्ये व व्यापार में उतार-चढ़ाव के साथ होता है । व्यापारिक जोखिम इस कारण पैदा होगी है कि उत्पादन के समय अथवा उसके बाद भाग बदल जाती है, कच्चे माल की कीमतें गिर जाती हैं अथवा नये गुधारों व आबिष्कारों के कारण उत्पादन

व्यय कम हो जाता है और इनके परिणामस्वरूप उत्पन्न वस्तु के दाम कम हो जाते हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों के कारण उत्पन्न की हुई पूँजी के मिलन में जो अड़भन व बाधाएँ पड़ती हैं, वे सब व्यापारिक जोखिम के अन्तर्गत आ जाती हैं। सम्भव है कर्जदार सच्चा और ईमानदार हो लेकिन जिस व्यापार अथवा व्यवसाय में उसने उत्पन्न की हुई पूँजी लगा रखी हो वह अनिश्चित हो उसमें उतार चढ़ाव होता हो और फलस्वरूप साहूकार की पूँजी खतरे में पड़ जाय और वह वापिस न हो सके। इन सब खतरों व जोखिमों को अपने मिर पर लाने के लिए साहूकार कुछ व्यापक अन्दाजा अतिरिक्त वन कर्जदार से लेता है जो कुल व्यापार में शामिल रहता है।

(३) असुविधाओं के लिए भुगतान (Payment for Inconvenience)—जोखिम व अन्दाजा कर्जदारों को कर्ण देने में कुछ असुविधाएँ भी होती हैं जिनके मुआवज़ के लिए वह कुछ रकम देता है। उदाहरणार्थ जितन समय के लिए वह ऋण देता है उतने समय के लिए अपनी पूँजी के उपयोग करने का उसका अधिकार जाता रहता है। सम्भव है उस बीच में उसे और अपितु लाभप्रद इस से पूँजी लगान का अवसर मिल जायवा कर्जदार ऐसे समय वज्र अंदा करे जो साहूकार के लिए बहुत असुविधापूर्ण हो अर्थात् उस समय जबकि पूँजी को फिर से किसी लाभ के कार्य में लगाना कठिन या असम्भव हो। इन सब असुविधाओं के लिए भी साहूकार कर्जदार से कुछ रकम लेता है जो कुल व्यापार में शामिल रहता है। साहूकार को कुछ दिन में असुविधाएँ जितनी अधिक होंगी, कुछ व्यापार भी उतना ही अधिक होगा।

(४) कार्य और प्रबन्ध के लिए पारिश्रमिक (Payment for Work and Management)—प्रत्येक वज्र के सम्बन्ध में साहूकार को कुछ कार्य और प्रबन्ध करना पड़ता है। उसे हिमायत रखना पड़ता है व्यापार की जो छोटी छोटी क्लिष्ट आती है उन्हें निवृत्त

पड़ता है, तत्कार्य भेजने पड़ते हैं और कभी कभी मुकादमेबाजी भी करनी पड़ती है। इन सब कार्यों के लिए भी साहूकार कुछ पारिश्रमिक चाहता है। कुल व्याज में ऋण सम्बन्धी कार्य और प्रबन्ध के लिए जो रकम ली जाती है शामिल रहती है।

उपपुंक्त बातों में कुल और शुद्ध व्याज का अन्तर स्पष्ट है। शुद्ध व्याज कुल व्याज का केवल एक अंश है। कुल व्याज में, शुद्ध व्याज के अतिरिक्त, अन्य अनेक प्रकार के भुगतानों की रकमें शामिल रहती हैं। इसलिए यह सम्भव है कि शुद्ध व्याज के कम होना पर भी कुल व्याज अधिक हो। इसके अलावा प्रतियोगिता के कारण एक खास समय और स्थान में शुद्ध व्याज की दर के एक ही होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किन्तु अन्य भुगतानों की रकमों ने भिन्न होने के कारण, एक ही समय और एक ही देश के विभिन्न भागों में कुल व्याज की दर भिन्न-भिन्न पाई जाती है। अर्थात् कुल व्याज की दरों में एक ही होने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती।

### व्याज की आवश्यकता और औचित्य

(Necessity and Justification of Interest)

व्याज लेना उचित है या नहीं, यह मुख्यतः एक नैतिक प्रश्न है। फिर भी इसका एक आर्थिक पहलू है, इसलिए अर्थशास्त्र के अन्तर्गत इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। प्राचीन काल में प्रायः सभी देशों और घरों में व्याज लेना अनुचित और निन्दनीय ठहराया जाता था। इसके अनेक कारण थे। एक तो उस समय के लोग पूँजी के विभिन्न लाभप्रद उपयोगों अथवा सेवाओं से परिचित नहीं थे। वे यह सोचते थे कि ऋण देने में न तो साहूकार किसी प्रकार का त्याग करता है और न कर्जदार को उसमें कोई लाभ पहुँचता है। इसके अलावा प्राचीन काल में उत्पादन का ढंग बहुत सीधा और सरल था। व्यापार और उद्योग-मन्थों का क्षेत्र बहुत सीमित था। अतः उस समय पूँजी से लाभ उठाने के माँके बहुत कम थे। अधिकतर लोग व्यापार-व्यवसाय के द्वारा लाभ उठाने के लिए

नहीं बल्कि जीवन-रक्षा के लिए ऋण लेते थे। अर्थात् अधिकतर ऋणों का सम्बन्ध उत्पादन से नहीं, बल्कि उपभोग से होता था। साधारणतः ऋण देन वाला धनी व्यक्ति होता था और कर्जदार गरीब। इन सब बातों के कारण प्राचीन काल में व्याज लेना निन्दनीय मन्सा आता था।

किन्तु अब पुरानी बात और परिस्थितियाँ बिन्दुबिन्दु बदल गई हैं। वैज्ञानिक उन्नति के प्रभाव से उत्पादन प्रणाली का मारा टाँचा बदल गया है। कृषि व्यापार व्यवसाय मातापिता आदि सभी आर्थिक क्षेत्रों में महान् परिवर्तन हुए हैं। अब उत्पादन अधिकतर बड़े परिमाण पर बड़े-बड़े कारखानों में होता है जहाँ विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी मशीन उपयोग में लाई जाती हैं। उद्योग धंधों की संख्या में वरतार वृद्धि होती रही है। व्यापार न स्थानीय रूप छोड़ कर अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है। इन सब परिवर्तनों के कारण आधुनिक आर्थिक जगत में पूँजी का स्थान बहुत ऊँचा हो गया है। इसके लाभप्रद उपयोग का क्षेत्र आधुनिक संसार में बहुत बड़ा हुआ है। कृषि उद्योग व्यापार व्यवसाय आदि सभी क्षेत्रों में पूँजी के उपयोग के लाभप्रद अवसरों में बड़ी तीव्र गति से वृद्धि हुई है। अब पूँजी अधिकतर उत्पादन कार्य में लगाने के लिए ली जाती है। इसकी सहायता से उत्पादन में बहुत वृद्धि होती है और कर्जदार का लाभ पहुँचता है। इस वृद्धि का एक भाग पूँजी देन वाले को व्याज के रूप में दिया जाना उचित हो नहीं बल्कि आवश्यक है। पूँजी के संचय और निर्माण में एक साधारण व्यक्ति को अपने वर्तमान मुल्य का मतोप और तृप्ति का कुछ अंश तक त्याग करना पड़ता है। अतः यह उचित ही है कि उसकी पूँजी के उपयोग के बदले जिसके लिए उसे स्वार्थ त्याग और कुछ समय के लिए प्रत्याक्षा करनी पड़ती है और जिसके उपयोग से उत्पादन यन्त्रों का अर्थ बढ़े वृद्धि होती है कुछ धन व्याज के रूप में दिया जाय। यही नहीं यदि व्याज न दिया जाय तो पूँजी संचय करने की इच्छा की तभी काफी कम हो जायगी। फलस्वरूप पूँजी की मात्रा घट जायगी। पूँजी की इस कमी के कारण उत्पादन व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में थड़कन

पड़ेगी और आर्थिक उन्नति रुक जायेगी। अस्तु, यदि हम चाहते हैं कि लोग अधिक मात्रा में पूँजी संचय करें और बहु उत्पादन कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकें, तो व्याज के रूप में लोगों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। आधुनिक मूल व्याज लेने के विह्वल नहीं हैं और न वह काम अब घृणा अबवा निन्दा की दृष्टि में देखा हो जाता है।

व्याज क्यों माँगा और दिया जाता है ?

(Why is Interest Demanded and Given?)

हम ऊपर कह चुके हैं कि पूँजी के उपयोग के बदले में जो रकम पूँजी-पति को मिलती है व्याज कहल जाती है। अब प्रश्न यह है कि पूर्वापत्ति व ऋणदाता व्याज क्यों मांगते हैं और कर्जदार व्याज देने के लिए किन कारण से तैयार हो जाते हैं ? ऋणदाता को यह भली भाँति मालूम रहता है कि पूँजी के उपयोग में अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। पूँजी में उपयोगिता है, इसमें उत्पादन-शक्ति है। इसकी सहायता से उत्पादन और लाभ बढ़ जाता है और कुछ समय के लिए आर्थिक मकदो का सामना किया जा सकता है। यदि इन अतिरिक्त उत्पादन व लाभ का कुछ भाग ऋणदाता को न मिलेगा तो वह अपनी पूँजी उधार देने के लिए तैयार न होगा। वह स्वयं इसे प्रत्यक्ष रूप में उपयोग में लाकर लाभ उठाने का प्रयत्न करेगा। यही कारण है कि जब वह दूसरों को पूँजी ऋण के रूप में देता है तो व्याज मांगता है। ऋण देने पर पूँजी से स्वयं लाभ उठाने का अधिकार कुछ समय के लिए जाता रहता है। दूसरे, ऋणदाता को पूँजी-नसब करने और उधार देने में कुछ कष्ट होता है, मतोष और तृप्ति का त्याग करना पड़ता है, वर्तमान उपयोग की भविष्य के लिए स्थगित करना पड़ता है, अर्थात् कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इन सबके बदले में वह व्याज के रूप में कुछ पारिधमिक व पुरस्कार मांगता है। कर्जदार भी इसी बातों की ध्यान में रखते हुए पूँजी के उपयोग के लिए व्याज देने को तैयार रहते हैं। वे जानते हैं कि पूँजी में उपयोगिता और उत्पादन-शक्ति है और उसके उपयोग से लाभ होना है, मतोष और तृप्ति प्राप्त होती

है। इस बात का भी उन्हें ज्ञान होता है कि पूँजी के संचय करने और उधार देने में कुछ अमुविधाएँ होती हैं। अतः जब तक ऋणदाता को कुछ पुरस्कार व प्रतिफल न दिया जायगा, तब तक पूँजी के संचय करने तथा उसके उधार देने में जो अमुविधाएँ होती हैं, उनको सहने के लिए वे साधारणतः तैयार न होंगे। अस्तु, व्याज मागने और दिये जाने के कारण स्पष्ट है।

### व्याज-दर का निर्धारण

(Determination of the Rate of Interest)

व्याज-दर के निर्धारण के सम्बन्ध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने समय-समय पर अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। इनमें से बहुत से सिद्धान्त व्याज-दर के निर्धारण की समस्या को भली प्रकार हल नहीं कर पाते। ये केवल इस समस्या के कुछ पहलुओं पर ही प्रकाश डालते हैं, सब पर एक साथ नहीं। ये एकांगी हैं और फलस्वरूप अपूर्ण। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार माग और पूर्ति का सिद्धान्त सब से ठीक है। इसमें अनेक सिद्धान्तों का समन्वय हो जाता है। इन सिद्धान्तों के अनुसार व्याज पूँजी के उपयोग व सेवा का मूल्य है और अन्य मूल्यों की तरह पूँजी का मूल्य भी अर्थात् व्याज, माग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। जिस स्थान पर पूँजी की माग और पूर्ति का साम्य होगा, वही पर व्याज की दर निर्धारित होगी। संक्षेप में, अब हम पूँजी की माग और पूर्ति तथा इनके साम्य द्वारा किस प्रकार व्याज की दर निश्चित होती है, इन पर विचार करेंगे।

**पूँजी की माग (Demand for Capital)**—पूँजी की माग उसकी उपयोगिता अथवा उत्पादन-शक्ति के कारण होती है। व्यवसायी, व्यापारी आदि अन्य व्यक्ति या व्यक्ति-समूह पूँजी की माग करते हैं क्योंकि इसके उपयोग से उन्हें लाभ होता है, उन्हें सतोष और शक्ति प्राप्त होती है और यही कारण है कि वे पूँजी के उपयोग के लिए व्याज के रूप में कुछ धन देने को तैयार होते हैं। कोई व्यक्ति पूँजी की विद्वती माग को माग करेगा अथवा उपयोग में लायेगा, यह पूँजी की सीमान्त उत्पादित



और व्याज की दर पर निर्भर करता है। यदि सीमान्त उत्पादिता व्याज में अधिक है, तो वह और अधिक धन में पूँजी को माग करेगा अर्थात् पूँजी का उपयोग करेगा क्योंकि ऐसा करने से उसे लाभ होगा। लेकिन अन्य वस्तुओं की तरह पूँजी के साथ भी घटती सीमान्त उपयोगिता व उत्पात्ति का नियम लागू होता है। यदि अन्य सब बाने पूर्ववत् रहें, तो एक सीमा के बाद पूँजी की मात्रा बढ़ाने में उसकी सीमान्त उपयोगिता व उत्पादिता कम-कम होती जायगी। अस्तु, वह व्यक्ति तभी तक पूँजी को अधिक मात्रा में उपयोग करना जायगा जब तक कि उसकी सीमान्त उत्पादिता उस रकम में अधिक है जो उसे पूँजी के बदले में देनी पड़ती है अर्थात् व्याज से। जहाँ पूँजी की सीमान्त उत्पादिता व्याज के बराबर हो जायगी, वहीं वह व्यक्ति रुक जायगा। उसमें अधिक मात्रा में वह पूँजी की माग न करेगा क्योंकि उसके बापे और अधिक पूँजी उपयोग में लाने में उसे पूँजी से कम सीमान्त उत्पादिता मिलेगी लेकिन उसके बदले में उसे अधिक व्याज देना पड़ेगा। इस कारण उसे हानि होगी। अतः वह व्यक्ति पूँजी को उस सीमा के बाद उपयोग में न लायेगा जहाँ पर उसकी सीमान्त उत्पादिता व्याज के बराबर हो जाती है। साम्य की स्थिति में पूँजी की सीमान्त उत्पादिता व्याज के बराबर होती है। अधिक से अधिक जो कुछ कोई व्यक्ति पूँजी के उपयोग के बदले में दे सकता है, वह पूँजी की सीमान्त उत्पादिता के बराबर होगा। अस्तु, मक्षेप में हम कह सकते हैं कि पूँजी की माग उसकी सीमान्त उपयोगिता व उत्पादिता पर निर्भर होती है और माग की तरफ से व्याज अधिक में अधिक पूँजी की सीमान्त उत्पादिता के बराबर हो सकता है। इससे अधिक व्याज होने पर कोई भी व्यक्ति पूँजी की सेवाओं की खरीदने के लिए तैयार न होगा।

**पूँजी की पूर्ति (Supply of Capital)**—पूँजी की मात्रा (जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन पूँजी के अध्याय में किया जा चुका है) मुख्यतः संचय करने की शक्ति और इच्छा पर निर्भर करती है। संचय-शक्ति वस्तु की आय और उसके व्यय पर निर्भर रहती है और संचय

करने की इच्छा मनुष्य की दूरदृष्टिता, कुटुम्ब-श्रेम आदि अनेक आन्तरिक और बाहरी बातों पर निर्भर करती है। कारण कुछ भी हो, यह तो स्पष्ट है कि पूजा वचन द्वारा सचय की जाती है और वचन करते समय मनुष्य को वर्तमान उपभोग भविष्य के लिए टालना पड़ता है। अस्तु, जब कोई व्यक्ति वचन द्वारा मर्चि पूजा को दूसरों को उधार देता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह वर्तमान वस्तु या तृप्ति को भावी वस्तु या तृप्ति के साथ विनिमय कर रहा है। किन्तु साधारणतः मनुष्य भविष्य के लिए रुकना, ठहरना व प्रतीक्षा करना पसन्द नहीं करना। वह भविष्य की तुलना में वर्तमान को अधिक गहस्ब देता है। भविष्य की चीजें उसे छोटी दिवाई देती हैं। भविष्य में प्राप्त होने वाला मतोप, वर्तमान की अपेक्षा उसे कम आकर्षक जान पड़ता है। "नौ नकद न तेरह उबार" की कहावत इस बात की और पुष्टि करती है। अतएव पूजा देने समय मनुष्य को वर्तमान तृप्ति को भविष्य के लिए त्याग करना पड़ता है। साधारणतः कोई भी व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त गुरस्कार व प्रतिफल की आशा के इस तरह का त्याग करने को तैयार न होगा। पूजा के सचय और उसके उधार देने में जो त्याग करना पड़ता है, जो प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसे पूजा का उत्पादन-व्यय कह सकते हैं। यदि पूजा के उपयोग के बदले में ऋणदाता को उसके उत्पादन-व्यय में कम प्रतिफल व व्याज मिलता है, तो वे अपनी पूजा को दूसरों को देने के लिए तैयार न होंगे क्योंकि उन्हें लाभ के बजाय हानि होगी। वे पूजा सचय करना कम कर देंगे व छोड़ देंगे और धन को अपने वर्तमान उपयोग में लाने लगेंगे क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अधिक तृप्ति मिलेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि कुछ भी व्याज न मिले तो भी कुछ लोग कुछ न कुछ वचन तो करेंगे ही। लेकिन इस तरह जो पूजा की मात्रा प्राप्त हो सगी, वह बहुत कम होगी। उसमें पूजा की कुल माग का बहुत बड़ा भाग पूरा हो सकेगा। यदि माग के अनुसार पूजा की पूर्ति होनी है अर्थात् यदि पूजा की पूर्ति इतनी होनी है कि पूजा की माग पूरी हो सके, तो व्याज की दर को

पूजी के सीमान्त उत्पादन-व्यय के बराबर होनी पड़ेगी। यदि व्याज पूजी के सीमान्त उत्पादन-व्यय से कम है, तो पूजी की पूर्ति घटती जायगी जब तक कि दोनों बराबर न हो जायेंगे। पूजी के सीमान्त उत्पादन-व्यय का आशय उस स्वाग व उत्पादन-व्यय में है जो पूजी की सीमान्त इकाई के कारण होता है। अस्तु, जहाँ तक पूजी की पूर्ति का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि पूजी की पूर्ति सीमान्त उत्पादन-व्यय द्वारा निश्चित होती है। साधारणतः कोई भी कृषिदाता पूजी के उपयोग के बदले में सीमान्त व्यय से कम लेने के लिए तैयार न होगा। यह पूजी के मूल्य को अर्थात् व्याज की न्यूनतम सीमा है।

**माग और पूर्ति का साम्य (Equilibrium of Demand and Supply)**—हम ऊपर पूजी की माग और पूर्ति पर विचार कर चुके हैं। इससे पता चलता है कि पूजी की माग उसकी सीमान्त उपयोगिता से और पूजी की पूर्ति उसकी सीमान्त लागत से निश्चित होती है। इन दोनों शक्तियों अर्थात् पूजी की माग और पूर्ति के परस्पर प्रभाव, घात-प्रतिघात में व्याज की दर निर्धारित होती है। यह वह दर होती है जिस पर पूजी की माग और पूर्ति बराबर होती है, जिस पर पूजी की सीमान्त उपयोगिता और सीमान्त लागत खर्च बराबर होती है। यदि दोनों में कुछ अन्तर होगा तो माग और पूर्ति में अन्तर पड़ेगा और फलस्वरूप व्याज की दर में उतार-चढ़ाव होगा। उदाहरण के लिए यदि सीमान्त उत्पादन-व्यय अधिक है, तो पूजी संचय करने वालों को हानि होती है। इस कारण पूजी की माग कम हो जायगी। पूजी की माग कम होने में पूजी की सीमान्त उत्पादित बट जायगी और फलस्वरूप व्याज की दर भी। और अन्त में फिर दोनों में बराबरी आ जायगी। इसके विपरीत यदि सीमान्त उपयोगिता अथवा उत्पादित अधिक हुई, तो पूजी की अधिक प्रतिकूल मिलेगी, अर्थात् व्याज की दर बढ़ जायगी। इसके प्रभाव में पूजी का संचय अधिक होगा और पूजी की माग बढ़ जायगी। ऐसा होने में पूजी की सीमान्त उत्पादित कम हो जायगी, माग घटने लगेगी और फलस्वरूप व्याज

की दर घट जायगी। यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूजा की माग और पूर्ति में, सीमान्त उत्पादिता और सीमान्त उत्पादन-व्यय में साम्य स्थापित न हो लेगा, अर्थात् समानता न आ जायगी।

अस्तु अन्य वस्तुओं की तरह ही पूजा की माग और पूर्ति के घात-प्रतिघात द्वारा व्याज की दर निश्चित होती है। पूजा की माग और पूर्ति में परिवर्तन होने से व्याज की दर में भी परिवर्तन होता रहेगा और अन्त में व्याज की दर वहाँ निश्चित होगी जहाँ माग और पूर्ति का साम्य होगा।

### व्याज की दरों में विभिन्नता

(Differences in the Rates of Interest)

व्याज की दरों में काफी विभिन्नता पाई जाती है। भिन्न-भिन्न देशों में व्याज की दरें भिन्न-भिन्न होती हैं। यही नहीं, एक ही देश में, एक समय में, अल्प-अल्प व्याज की दरों पर ऋण मिलता है और उन दरों में काफी अन्तर रहता है। जैसे हमारे देश में सरकार को २ या ३ प्रतिशत व्याज पर ही ऋण मिल जाता है, शहर के व्यापारियों और उद्योगपतियों को साधारणतः ६ प्रतिशत में कम व्याज की दर पर ऋण नहीं मिल पाता और गांव के किसानों को तो १५ प्रतिशत में भी अधिक और कभी-कभी १०० प्रतिशत तक व्याज देना पड़ता है। व्याज की दरों में यह अन्तर क्यों होता है ?

शुद्ध व्याज की दर, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, पूजा की माग और पूर्ति द्वारा निश्चित होती है। यदि प्रतियोगिता की परिस्थितियाँ हैं और विभिन्न स्थानों और उपयोगों के बीच पूजा पूर्णरूप से गतिशील है, तो एक समय में शुद्ध व्याज की दर एक ही होगी, उसमें अन्तर नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि यदि एक स्थान या व्यवसाय में शुद्ध व्याज की दर अधिक होगी और दूसरे में कम, तो जिस व्यवसाय या स्थान पर व्याज की दर कम होगी वहाँ से लाभ पूजा निकाल कर उस स्थान या व्यवसाय में लगाने लगेंगे जिसमें व्याज की दर अधिक होगी।

इसका परिणाम यह होगा कि जिस व्यवसाय में दर कम होती, उनमें पूजी की मात्रा कम होने लगेगी और जिसमें व्याज की दर ऊँची होगी, उसमें पूजी की मात्रा बढ़ने लगेगी। अन्य बातों के पूर्ववत् रहने पर, जिस व्यवसाय व स्थान से पूजी निकलने लगेगी, वहाँ व्याज की दर बढ़ने लगेगी और जिस व्यवसाय में पूजी अधिक लगने लगेगी उसमें दर गिरेगी। एक व्यवसाय व स्थान से पूजी निकाल कर दूसरे व्यवसाय व स्थान पर पूजी लगाने का यह काम तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों स्थानों अथवा व्यवसायों में व्याज की दरें बराबर न हो जायें। अस्तु प्रतियोगिता के प्रभाव से शुद्ध व्याज की दर एक समय में एक ही होगी। लेकिन यह अभी सम्भव होगा जबकि पूर्ण प्रतियोगिता हो, जबकि विभिन्न स्थानों और व्यवसायों के बीच पूजी पूर्ण रूप से गतिशील हो, अर्थात् उसके निकालने व लगाने में किसी भी प्रकार की रकाबट व अड़चन न हो। वास्तव में प्रतियोगिता अपूर्ण होती है, पूजी स्वतन्त्र रूप से एक स्थान व व्यवसाय से दूसरे स्थान व व्यवसाय में आ-जा नहीं सकती। फलस्वरूप भिन्न-भिन्न स्थानों और व्यवसायों में, वहाँ की विशेष मात्रा और पुंति के अनुसार, व्याज की दरें भिन्न-भिन्न होती हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर पूजी की मात्रा और पूंति अलग-अलग होती है। इस कारण उनके प्रभाव में जो व्याज की दर निश्चित होती हैं, उनमें काफी विभिन्नता रहती है। प्रतियोगिता अपूर्ण होने के कारण, इन दरों में समानता नहीं स्थापित हो पाती। अस्तु, व्याज की दरों में विविधता का एक प्रमुख कारण अपूर्ण प्रतियोगिता का होना है।

व्याज-दर में इस कारण भी अन्तर पड़ जाता है कि ऋण अलग-अलग सगम के लिए लिये जाते हैं। जितने अधिक लम्बे समय के लिए ऋण लिया जायगा, व्याज की दर उतनी ही अधिक ऊँची होगी क्योंकि साहूकार को अपनी पूजी का काफी दिनों के लिए त्याग करना पड़ेगा। थोड़े समय के लिए दिये गये ऋण पर व्याज की दर अपेक्षाकृत कम होगी है।

व्याज की दरों में जो अंतर दिखाई पड़ता है वह मुख्यतः कुल व्याज की दरों में होता है शुद्ध व्याज की दर में नहीं। इसका कारण यह है कि कुल व्याज में जिन जिन चीजों को शामिल किया जाता है वे सब अलग-अलग एक समान नहीं रहती। किसी अवस्था में अधिक जोखिम होती है और किसी में कम। इसी प्रकार विभिन्न ऋणों के सम्बन्ध में अमुविधाओं तथा प्रबंध काय में भिन्नता होती है। किसी में अमुविधाएं अधिक होती हैं और अधिक प्रबंध काय करना पड़ता है और किसी में कम। इन सब बातों में अंतर होने से कुल व्याज की दर भिन्न भिन्न होती है। जिस अवस्था में अधिक जोखिम होगी उसमें ऋण के लिए कुल व्याज की दर अधिक होगी। इसी प्रकार जिस ऋण में अधिक अमुविधाएं होंगी अथवा जिसमें अधिक प्रबंध काय करना पड़ेगा उसमें कुल व्याज की दर अधिक होगी। इसके विपरीत जिन ऋणों के देन में कम जोखिम होती है अथवा जिनके लिए कम अमुविधाएं उठानी पड़ती हैं कम प्रबंध काय करना पड़ता है उनमें कुल व्याज की दर अपेक्षाकृत कम होगी। उदाहरणार्थ सरकार को जो ऋण दिया जाता है वह बहुत सुरक्षित होता है उसमें बहुत कम अमुविधा होती है और प्रबंध काय नहीं के बराबर करना पड़ता है। इसलिए साहूकार सरकार को बहुत कम व्याज पर ऋण देने को तैयार हो जाते हैं। व्यापारियों को ऋण देने में साहूकार को थोड़ी बहुत जोखिम उठानी पड़ती है और बही खाता आदि पर भी कुछ खर्च करना पड़ता है। फलस्वरूप व्यापारियों को सरकार की अपेक्षा अधिक व्याज देना पड़ता है। चाय के किसानों को तो इनमें भी कहीं अधिक व्याज देना पड़ता है। इसका कारण यह है कि हमारे किसान बहुत गरीब हैं। उनकी आय बहुत थोड़ी और अनिश्चित है और न वे अच्छी जमानत दे सकेंगे। इससे अतिरिक्त उनका धंधा अर्थात् कृषि अत्यंत अनिश्चित है। यदि वर्षा कम या अधिक हुई तो खेती चौपट हो जाती है। एसी दशा में पूंजी लीट आन की जो कुछ थोड़ी बहुत आशा रहती है वह भी टूट जाती है। इस जोखिम के अलावा साहूकार को गरीब और भूमिहीन किसानों

को श्रृण देने में बहुत असुविधा भी होती है और प्रसन्न-भाव भी बहुत करना पड़ता है। इन विभिन्न बातों के कारण साहूकार किसानों को अपेक्षाकृत बहुत ऊँची व्याज की दर पर श्रृण देता है।

### उन्नति का व्याज पर प्रभाव

(Effect of Progress on Interest)

उन्नति का प्रभाव पूँजी की माँग और माग पर पड़ता है और फलस्वरूप इसमें व्याज की दर भी प्रभावित होती है। उन्नति के साथ-साथ मनुष्य की आवश्यकताएँ भी तेजी से बढ़ती जाती हैं। उनकी पूर्ति के लिए नये-नये उद्योग-धन्यों की स्थापना करनी पड़ती है। व्यापार का क्षेत्र और बढ़ जाता है। इन सब कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता पड़ेगी। पूँजी की माग में इस तरह से वृद्धि होने से व्याज की दर में बढ़ने की ओर प्रवृत्ति होगी। साथ ही व्यापार, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में उन्नति होने से देश में धनोत्पादन बढ़ेगा। इस कारण लोगों में बचत करने की शक्ति अधिक होगी। बचत करने की इच्छा भी प्रबल हो जायेगी क्योंकि उन्नति की अवस्था में मनुष्य में उत्तरदायित्व, दूरदर्शिता आदि के गुण आ जायेंगे। फलस्वरूप पूँजी की माँग बढ़ेगी। इसके प्रभाव से व्याज की दर में कम होने की प्रवृत्ति होगी। अतः, व्याज पर उन्नति का प्रभाव मालूम करने के लिए हमें यह देखना होगा कि पूँजी की पूर्ति और माग में किस दर से वृद्धि होती है। यदि माग में बढ़ने की दर अपेक्षाकृत अधिक है, तो व्याज ऊँचा होगा और यदि पूर्ति में बढ़ने की दर अपेक्षाकृत अधिक है, तो व्याज कम होगा।

बहुत-से अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि माग की अपेक्षा पूर्ति में अधिक वृद्धि होती है। इसलिए उन्नति की अवस्था में व्याज की दर में घटने की प्रवृत्ति होगी। पर क्या चिरने-चिरते व्याज की दर अभिप्राय में शून्य के बराबर हो जायेगी? यह तभी सम्भव है जब कि लोग बिना किसी प्रतिफल की आशा से दान करने जगें अर्थात् पूँजी-सकम में कोई लाभ

न हो और पूँजी के लाभप्रद प्रयोग करने का कोई स्थान न रह जाय। यह अवस्था तभी आ सकती है जबकि पूँजी को सीमान्त उत्पादिता शून्य हो जाय। अर्थात् पूँजी के और अधिक उपयोग द्वारा उत्पादन में अब और अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती। इसका अर्थ यह होगा कि हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति और तृप्ति पूर्ण रूप में हो चुकी है। ऐसी अवस्था की कल्पना तो की जा सकती है लेकिन वास्तविक जीवन में इस अवस्था तक पहुँचना असम्भव सा ही है। मनुष्य की आवश्यकताओं का कोई अन्त नहीं है। उसे सदा नई-नई आवश्यकताएँ घरे रहती हैं और पुरानी आवश्यकताओं की तृप्ति भी शायद ही कभी पूरी तरह से होती हो। इस कारण पूँजी के लाभप्रद उपयोगों का भी कोई अन्त नहीं है। उसके उपयोग के अनकानक अवसर निकलते ही रहेंगे जिसके कारण उसकी सीमान्त उत्पादिता कभी शून्य न होगी। फलस्वरूप मूल की दर भी शून्य तक न गिर सकती, वह हमेशा उसके ऊपर ही होगी।

### QUESTIONS

- 1 What is interest? On what grounds was it condemned in the past?
- 2 Why is interest demanded and paid? How do you justify the payment of interest?
- 3 Analyse fully gross interest. Show why does it differ from place to place and person to person?
- 4 How is the rate of interest determined? Show how it is related to the (a) growth of capital and (b) productivity of capital.
- 5 Explain fully the causes of differences in the rates of interest.
- 6 Show how under the influence of competition there will prevail only one rate of interest.
- 7 How is interest affected by progress? Will it sink down to zero?



## अध्याय ४०

### लगान

(Rent)

भूमि के उपयोग के लिए जो रकम दी जाती है, उसे अर्थशास्त्र में लगान (Rent) कहते हैं। साधारण बोलचाल में लगान का अर्थ उस रकम से होता है जो कोई किसान खेत के मालिक को देता है अथवा कोई किरायेदार किसी मकान-मालिक को देता है। इसमें अनेक प्रकार की भूगतियों की रकम शामिल रहती है जैसे प्रकृतिदत्त भूमि के उपयोग के लिए दी जाने वाली रकम अर्थात् लगान, भूमि के सुधार आदि में लगाई गई पूँजी के लिए ब्याज, उसकी देख-रेख, प्रबन्ध आदि के लिए भू-स्वामी अथवा उसके प्रतिनिधियों के श्रम के लिए वेतन या मजदूरी तथा भूमि की उन्नति के लिए जोखिम उठाने के बदले में भू-स्वामी को कुछ लाभ की रकम। अतः साधारणतः जिसे लगान कहा जाता है, उसमें लगान की रकम के अलावा अन्य और कई प्रकार की रकम शामिल रहती है। इसलिए इसे शुद्ध व आर्थिक लगान (net or economic rent) न कहकर "कुल लगान" कहना अधिक उपयुक्त होगा। शुद्ध व आर्थिक लगान का आशय उस रकम से होता है जो केवल भूमि के उपयोग के बदले में मिलती है। अर्थात् भूमि की मूल और अविनाशी प्रकृतिदत्त उत्पादक-शक्तियों के उपयोग से प्राप्त होने वाली रकम व आय को अर्थशास्त्र में लगान कहते हैं। भूमि में लगी हुई पूँजी, किये गये श्रम तथा उस सम्बन्ध में जोखिम उठाने से जो आय प्राप्त होती है अथवा जो रकम मिलती है, उसे आर्थिक दृष्टि से लगान नहीं कह सकते क्योंकि वह भूमि के उपयोग से नहीं बल्कि अन्य बातों के कारण प्राप्त होती है। लगान तो केवल

उसी रकम को कह सकते हैं जो भूमि के उपयोग के बदले में प्राप्त होती है ।

### लगान के वास्तविक अर्थ का स्पष्टीकरण

(Explanation of Real Meaning of Rent)

यदि हम ऊपर दी हुई लगान की परिभाषा का ठीक प्रकार से अध्ययन और विश्लेषण करें तो देखेंगे कि इसका वास्तविक अर्थ वचन, अतिरेक व आधिक्य (surplus) में है और अर्थशास्त्र में वचन व आधिक्य के भाव में ही इसका प्रयोग होता है । यह अर्थ लगान के साधारण अर्थ से इतना भिन्न है कि लगान सम्बन्धी विषय को भली भाँति समझने के लिए लगान के साधारण अर्थ को क्लिष्ट मूल जाना ही अच्छा होगा, अन्यथा मग्न में पड़ने की संभावना बनी रहेगी । ऊपर दी हुई परिभाषा में कहा गया है कि भूमि के उपयोग के बदले में जो कुछ प्राप्त होता है वही लगान है । अर्थशास्त्र में, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रकृति-दत्त वस्तुओं को भूमि कहते हैं । भूमि प्रकृति की देन है । इसके उत्पादन में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता । यह तो प्रकृति की ओर से मानव समाज को बिना किसी लागत के मुक्त प्राप्त होती है । समाज की दृष्टि से इसके उत्पादन में कोई लागत नहीं लगती । इसका उत्पादन-व्यय शून्य है । अतः जो कुछ भूमि के उपयोग के बदले में मिलता है, वह एक वचन व आधिक्य है । और चूँकि भूमि के उपयोग के लिए मिलने वाली रकम को लगान कहते हैं, इसलिए लगान वचन स्वल्प है, यह एक वचन अथवा अतिरेक है । इस ध्यान के आधार पर हम लगान के अर्थ व भाव को इन शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं : लगान वह रकम है जो उत्पादन-व्यय के ऊपर प्राप्त होती है । अर्थात् उत्पादन-व्यय के ऊपर प्राप्त होने वाली वचन व अतिरेक को लगान कहते हैं ।

लगान के इस विशिष्ट अर्थ को भूमि के अलावा अन्य सामनों के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है । यह दिखाया जा सकता है कि केवल भूमि के सम्बन्ध में ही लगान अर्थात् वचन की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि

कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य साधनों को भी लगान प्राप्त हो सकता है, अर्थात् अन्य साधनों की आय में लगान का अंश हो सकता है। हम ऊपर कह चुके हैं कि लागत के ऊपर जो बचत होती है, वह लगान है। लागत का आशय किसी साधन की न्यूनतम पूर्ति-कीमत (minimum supply price) से होता है। यह वह कीमत है जिसका मिलना उस साधन को वर्तमान कार्य में लगाये रखने के लिए जरूरी है। इसके न मिलने पर वह उस कार्य में न करेगा, वह उसे छोड़ देगा। यदि किसी साधन की उसकी न्यूनतम पूर्ति-कीमत से अधिक मिलता है, तो वह ऊपर वाली रकम बचत होगी और इस कारण उसे लगान कह सकते हैं क्योंकि लगान बचत को कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कोई मजदूर ४ रुपये पर काम करने को तैयार है, अर्थात् उसकी न्यूनतम पूर्ति-कीमत ४ रुपये है। इसमें कम मजदूरी पर वह काम न करेगा। दूसरे शब्दों में यह उसकी लागत है। यदि बाजार में अम की मांग इतनी है कि उन मजदूरों की भी जरूरत पड़ती है जिनकी पूर्ति-कीमत ६ रुपये है, तो ऐसी परिस्थिति में बाजार में मजदूरी की दर ६ रुपये होगी और पहले वाले मजदूर को भी यही मिलेगा। अतः उस मजदूर को (६६० - ४६०) = २ रुपये की बचत होगी। यह उसके लिए लगान स्वरूप है। इस तरह अन्य साधनों की आय में भी लगान का अंश हो सकता है। जैसे मान लो कोई कृषिदाता २ प्रतिशत व्याज-दर पर आण देने को तैयार है, अर्थात् उसकी न्यूनतम पूर्ति-कीमत २ प्रतिशत है। यदि बाजार में व्याज की दर ५ प्रतिशत है तो उसे भी ५ प्रतिशत की दर से व्याज मिलेगा। ३ प्रतिशत की यह बचत उसके लिए लगान के स्वरूप है। उसकी दृष्टि में २ प्रतिशत व्याज है और शेष ३ प्रतिशत लगान। देने वाले की दृष्टि में सबका-सब व्याज है। अस्तु केवल भूमि-के-सम्बन्ध में ही लगान की प्राप्ति नहीं होती बल्कि हर साधन की आय में लगान का अंश हो सकता है। किसी साधन को लगान या बचत की प्राप्ति तभी हो सकती है जबकि उसकी पूर्ति पूर्णतः लोचदार न हो और साथ ही उसकी मांग इतनी हो

कि ऊँची पूर्ति-कीमत वाली इकाइयों की जरूरत पड़े। भूमि में यह विशेषता पूर्णरूप से है। यही कारण है कि लगान का विचार मात्रागत भूमि के साथ ही जुड़ा होता है।

### लगान-निर्धारण और रिकार्डों का सिद्धान्त

(Determination of Rent and Ricardian Theory)

अब हमें यह देखना है कि भूमि के सम्बन्ध में लगान कब और क्यों प्रारम्भ होता है और कैसे इसकी मात्रा निश्चित व निर्धारित होती है। रिकार्डों का सिद्धान्त इन सब बातों पर यथोचित प्रकाश डालता है। यद्यपि इस सिद्धान्त पर अनेक प्रकार के आक्षेप लगाये गये हैं और कहीं-कहीं पर इसमें थोड़ा-बहुत संशोधन भी किया गया है, फिर भी इसका बहुत महत्त्व है। लगान सम्बन्धी आधुनिक विचारों का यह आधारस्वरूप है। इसकी महायत्ना से इस विषय की आसानी में समझा जा सकता है। अब इस सिद्धान्त के आधार पर हम इस विषय का अध्ययन करेंगे।

रिकार्डों की विचारधारा का अनुसरण करते हुए हम एक उदाहरण लेकर यह स्पष्ट करेंगे कि लगान कब प्रारम्भ होता है तथा इसकी मात्रा कैसे निर्धारित होती है। मान लो कुछ लोग एक नये देश व स्थान में जाकर बसते हैं और वहाँ खेती आरम्भ करते हैं। शुरू में वे सबसे उत्तम व उपजाऊ भूमि पर खेती करेंगे। जब तक इस तरह की भूमि अर्थात् सबसे उपजाऊ भूमि प्रचुर मात्रा में होगी और जो चाहे उसे आसानी से पा सकता है, तब तक भूमि के उपयोग के लिए कोई कुछ न देगा। ऐसी स्थिति में लगान का कोई प्रश्न नहीं उठ सकता, किसानों को भूमि के लिए लगान के रूप में कुछ नहीं देना पड़ेगा क्योंकि उत्तम भूमि प्रचुरता से सबको मिल सकती है। जिस वस्तु की पूर्ति मांग के हिसाब से सीमित नहीं होती, उसमें लिए कोई कुछ नहीं देता। धीरे-धीरे आबादी में वृद्धि होती है तो सबसे उपजाऊ भूमि के बाकी हिस्सों में भी खेती होने लगती है। मान लो उस स्थान की जनसंख्या और बड़ा जा रहा है अथवा बाहर से बड़ा और लोग आ जाते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि वहाँ पर अब की आवश्यकता

व भाग बढ़ जायगी । इसकी पूर्ति के लिए अब दूसरे दर्जे की जमीन पर खेतों की जाने लगेगी क्योंकि पहले दर्जे की जमीन अब खाली नहीं है । उपजाऊपन में अन्तर होने के कारण दूसरे दर्जे के खेतों में पहले दर्जे के खेतों की अपेक्षा उपज कम होगी । उतने ही वर्षों में दूसरे दर्जे की भूमि में कर्म पैदावार होगी क्योंकि पहले दर्जे की भूमि की तुलना में यह कम उपजाऊ है । उदाहरण के लिए मान लो कि एक विशेष रकम खर्च करने से प्रथम श्रेणी की भूमि में ३५ मन गेहूँ पैदा होता है और उतने ही वर्षों से दूसरे दर्जे की भूमि में केवल ३० मन ही गेहूँ पैदा होता है । मशी में गेहूँ का मूल्य तो एक ही होगा चाहे वह किसी भी श्रेणी की भूमि में पैदा किया गया हो । गेहूँ के इस मूल्य को इतना होना पड़ेगा जिससे दूसरे दर्जे की भूमि का लागत खर्च निकल आये । यदि ऐसा न होगा तो शेष दूसरे दर्जे के खेतों को नहीं जोतेंगे । ऐसी स्थिति में प्रथम श्रेणी की भूमि पर ५ मन गेहूँ की वचत होगी क्योंकि दोनों श्रेणी के खेतों पर उत्पादन खर्च एक बराबर लगता है । यह ५ मन गेहूँ की वचत प्रथम श्रेणी की भूमि का लगान है, चाहे वह किसान के पास रहे या भूमि के मालिक के पास । दूसरे दर्जे की भूमि पर कोई वचत नहीं होगी । इस भूमि पर जो उपज होती है, उसमें से उत्पादन-व्यय घटाने से कुछ शेष नहीं रहता, कुछ वचत नहीं होती । इसलिए इस भूमि पर कोई आर्थिक लगान नहीं होगा । ऐसी भूमि को सीमान्त भूमि (marginal land) या बे-लगान भूमि (no-rent land) कहते हैं । यह लगान आकने का आधार है । दसकी उपज से जितनी अधिक जिस भूमि की उपज होगी, उतना ही अधिक उग पर लगान होगा । इस उदाहरण में दोनों उपजों का अन्तर ५ मन है । अतः यह प्रथम श्रेणी की भूमि का लगान हुआ । अब मान लो जन-संख्या और बढ़ जाती है । ऐसा होने से अन्न की आवश्यकता में वृद्धि होगी जिसकी पूर्ति के लिए तीसरे दर्जे के खेत जोतने पड़ेंगे । इनकी उपज दूसरे दर्जे के खेतों में भी कम होगी । अब मूल्य को तीसरे दर्जे की भूमि के उत्पादन-व्यय के बराबर होना पड़ेगा, नहीं तो उग भूमि पर संती व

की जायगी। अतः यह भूमि अब सीमान्त भूमि होगी और इस पर कोई लगान न बचत न होगी। दूसरे दर्जे की भूमि की उपज इसमें अधिक होने के कारण, इस पर अब लगान शुरू होगा और पहले दर्जे की भूमि का लगान और बढ़ जायगा। इस तरह जैसे-जैसे नीचे दर्जे की भूमि पर खेती की जाने लगेगी, उसमें भूमि पर उपज का अन्तर अर्थात् लगान का परिमाण वैसे ही वैसे बढ़ता जायगा।

एक उदाहरण लेकर इस बात को और स्पष्ट किया जा सकता है। मान लो 'अ', 'ब', 'स' तीन तरह की जमीनें हैं। 'अ' भूमि सबसे उपजाऊ है, 'ब' उसमें कम और 'स' सबसे कम उपजाऊ है। सर्वप्रथम 'अ' भूमि पर खेती होगी क्योंकि वह सबसे अधिक उपजाऊ है। समय बीतने पर जनसंख्या में वृद्धि होने से क्रमशः 'ब' और 'स' भूमि पर भी कृषि होने लगेगी। इन तीनों जमीनों की उत्पादकता में अन्तर होने के कारण एक विशेष रकम खर्च करने पर तीनों की उपज बराबर न होगी। मान लो तीनों के अलग-अलग खतने-बोने में ६० रुपये खर्च किया जाता है जिसमें 'अ' भूमि पर २० मन अनाज पैदा होता है, 'ब' पर १५ मन और 'स' पर १० मन अनाज मिलता है। यदि कुल माग की पूर्ति के लिए 'स' भूमि की उपज की आवश्यकता है, तो मूल्य को ६ रुपये मन होना पड़ेगा, नहीं तो 'स' भूमि पर खेती न की जायगी। 'अ' और 'ब' भूमि की उपज भी इसी मूल्य पर बिकेगी। अस्तु, 'अ' भूमि के खेतने वाले की उपज की बिक्री से १२० रुपये मिलेगा, 'ब' भूमि वाले को ९० रु० और 'स' भूमि वाले को कुल ६० रु० ही मिलेगा। हम पहले मान चुके हैं कि प्रत्येक भूमि पर ६० रु० खर्च किया जा रहा है। इस कारण 'स' भूमि पर कुछ भी बचत न होगी। यह सीमान्त भूमि है। 'अ' पर ६० रु० की वसत होगी और 'ब' पर ३० रु० बचेगा। इस 'बचत' को अर्थशास्त्र में लगान कहते हैं। इसे उपज के रूप में आका जाता है। यहाँ केवल मुविधा के लिए बचत अथवा लगान को रुपये में दिखाया गया है।

ऊपर यह बताया गया है कि लगान क्या है, क्यों और कैसे उत्पन्न होता है और कैसे इसकी मात्रा निर्दिष्ट होती है। इस सम्बन्ध में यह कहा गया है कि उत्पादन-व्यय को ऊपर जो वचन होती है, वही लगान कहलाता है। लगान आरम्भ होने का यह कारण बताया गया है कि भिन्न-भिन्न भू-भागों की उत्पादन-शक्ति पृथक्-पृथक् होती है। जब तक सबसे अच्छी भूमि प्रचुरता से सब तरह के काम के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आसानी में मिल सकती है, तब तक लगान का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन जब जन-संख्या में वृद्धि होने के कारण अच्छी भूमि खत्म हो जाती है और दूसरे दर्जे की भूमि पर खेती की जाने लगती है, तो पहले दर्जे की भूमि पर वचन होने लगती है। यही लगान कहलाता है। इसी प्रकार जैसे-जैसे जन-संख्या बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे क्रमशः नीचे दर्जे की जमीन काम में लाई जाने लगती है। खेती की उपज की सीमा घटती जाती है और लगान उत्तरोत्तर क्रमशः बढ़ता जाता है।

किन्तु इसका यह आशय नहीं कि लगान केवल भूमि की उत्पादन-शक्ति की विभिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। यदि सब भू-भाग एक समान उपजाऊ हो, उनके गुण में कोई अन्तर न हो, तो भी एक सीमा के बाद लगान प्रारम्भ होगा। जन-संख्या में वृद्धि होने के कारण एक सीमा के पश्चात् भूमि की कमी पड़ जायेगी और अधिक भूमि न मिल पाने के कारण गहरी खेती का सहारा लेना पड़ेगा। बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए उन्हीं खेतों में श्रम और पूँजी की और मात्राएँ लगाकर उपज बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा करने से एक सीमा के पश्चात् क्रमागत उत्पत्ति-ह्रास नियम लागू होने लगेगा। जैसे-जैसे किमी खेत में और अधिक श्रम और पूँजी की इकाइयाँ लगाई जायेंगी, वैसे ही वैसे सीमान्त उत्पत्ति क्रमशः कम होती जायेगी। यदि श्रम और पूँजी की पहली इकाई से २० मन गेहूँ पैदा हुआ था, तो दूसरी इकाई के कारण उससे कम पैदा होगा। तीसरी इकाई से इससे भी कम मात्रा में उपज होगी। सीमान्त उपज के

क्रमशः घटने के कारण उत्पादन-व्यय बढ़ेगा। मूल्य की भी इस कारणा-  
वदना पड़ेगा जिससे बढ़ता हुआ सीमान्त उत्पादन-व्यय निकल सके।  
यदि मूल्य श्रम और पूँजी की सीमान्त इकाई से जो उपज होती है उसके  
बराबर न होगा, तो उस इकाई को लेती में न लगाया जायगा। अस्तु,  
सीमान्त इकाई की उपज और मूल्य दोनों बराबर होंगे। सीमान्त इकाई  
पर कुछ न बचेगा। लेकिन प्रारम्भ की इकाइयों से अधिक उपज होती है।  
इस कारण उन पर बचत होगी और बचत को ही अधिक लगान कहते  
हैं। अस्तु, लगान ने प्रारम्भ होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि  
भित्त-भित्त भू-भागों की उत्पादन-शक्ति भित्त-भित्त हों। लगान प्रारम्भ  
होने के दो मौलिक कारण हैं (१) भूमि की परिमितता, उसकी बेढोच-  
वार पुँति और (२) क्रमागत उत्पत्ति-ह्रास नियम। यदि भूमि परिमित न  
हो, उसकी पुँति लोच रहित न हो या क्रमागत उत्पत्ति-ह्रास नियम  
लागू न हो, तो लगान न होगा। यदि भूमि की मात्रा प्राण के हिसाब से  
सीमित नहीं है तो लगान का मसाला न उठेगा। इसी प्रकार यदि क्रमागत  
उत्पत्ति-ह्रास नियम लागू न हो, तो भी भूमि पर लगान न होगा क्योंकि  
फिर तो सबसे उत्तम भूमि के एक भाग से ही जितनी जरूरत होगी उपज  
कर ली जायगी।

### लगान और मूल्य

(Rent and Price)

अब यह देखना है कि लगान और मूल्य में क्या-कैसा सम्बन्ध है ?  
साधारण तौर पर यह कहा जाता है कि मूल्य-उत्पादन द्वारा प्रभावित होता  
है। लगान के बढ़ने से मूल्य बढ़ता है और कम होने से मूल्य घटता है।  
प्रायः हम किसानों को यह कहते हुए सुनते हैं कि गन्नाज की कीमत इस  
कारण ऊँची है कि उन्हें बहुत ज्यादा लगान देना पड़ता है। दूसरे सन्दर्भों में,  
साधारणतः लगान मूल्य के कम या अधिक होने का एक कारण माना  
जाता है। पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है। लगान मूल्य को निर्धारित  
नहीं करता, बल्कि स्वयं ही मूल्य द्वारा निर्धारित होता है। यह मूल्य का



धारण नहीं, बल्कि उसका फल है। इस बात के लिए जो हलील दी जा सकती है, उसे इस प्रकार रखा जा सकता है।

प्रतिभोगिता की परिस्थिति में अनाज का मूल्य एक समय में एक ही होगा। यह मूल्य सीमान्त भूमि के उत्पादन-व्यय के बराबर होगा, क्योंकि यदि मूल्य इतना नहीं है कि सीमान्त भूमि की लागत खर्च निकाल सके तो कोई भी उस भूमि को नहीं जोतेगा। अतएव यदि सीमान्त भूमि की उपज की आवश्यकता है, तो मूल्य को उसके उत्पादन-व्यय के बराबर होना पड़ेगा। सीमान्त भूमि की चर्चा करते समय हम यह कह चुके हैं कि इस पर कोई बचत नहीं होती। इस कारण इस पर लगान नहीं होता क्योंकि बचत को ही लगान कहते हैं। चूंकि मूल्य सीमान्त भूमि के उत्पादन-व्यय के बराबर होता है और लगान इस उत्पादन-व्यय में शामिल नहीं होता है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि लगान भूम्य में शामिल नहीं होता। लगान सीमान्त उत्पादन-व्यय व मूल्य का अंश नहीं है। फलस्वरूप लगान में घट-बढ़ होने के कारण मूल्य में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मान लो कि लगान कम कर दिया गया है या बिलकुल छोड़ दिया गया है। फिर भी मूल्य पर इसका कोई प्रभाव न पड़ेगा। कारण यह है कि मूल्य सीमान्त भूमि के उत्पादन-व्यय द्वारा निर्दिष्ट होता है। लेकिन लगान कम करने अथवा हटा देने से इसके उत्पादन-व्यय पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। यह वैसा ही रहेगा क्योंकि इस पर लगान का कोई अंश नहीं होता। जब तक सीमान्त भूमि की लागत खर्च में अन्तर न पड़ेगा तब तक मूल्य में भी कोई अन्तर न होगा। चूंकि लगान में परिवर्तन लाने में सीमान्त लागत खर्च में कोई अन्तर नहीं पड़ता, इसलिए मूल्य में भी इसके कारण कोई घट-बढ़ न होगी।

यही नहीं कि लगान कीमत निर्दिष्ट नहीं करता बल्कि यह कीमत का परिणाम है। कीमत द्वारा लगान की मात्रा निर्धारित होती है। कीमत में उतार-चढ़ाव होने से लगान में घट-बढ़ होता है। उत्पादन के तौर पर

मान लो कि मूल्य बढ़ जाता है। ऐसा होने पर लोगो को और कम उपजाऊ भूमि को, जिस पर अभी तक खेती नहीं होती थी, कृषि-कार्य में लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उत्तम भू-भागों पर और गहरी खेती की जाने लगेगी। इसका फल यह होगा कि कृषि की सीमा और आगे बढ़ जायेगी। जो पहले सीमान्त भूमि थी, उस पर अब वचत होने लगेगी और इससे अच्छी जमीनों पर की वचत और बढ़ जायेगी। इस कारण लगान में वृद्धि होगी। इसके विपरीत यदि मूल्य गिर जाता है, तो उसका प्रभाव उल्टा होगा। मूल्य घट जाने के कारण जो पहले सीमान्त भूमि थी, उस पर खेती न की जायेगी क्योंकि उसका उत्पादन-व्यय मूल्य से अधिक हो जायेगा। जो जमीन इसमें अच्छी थी और जिस पर पहले कुछ लगान या वचत होती थी, अब वह सीमान्त भूमि बन जायेगी। अधिक उपजाऊ जमीनों पर वचत की मात्रा घट जायेगी और इस कारण उन पर लगान की मात्रा भी। इस प्रकार मूल्य में परिवर्तन होने से लगान में घट-बढ़ होता है। मूल्य में कम होने से लगान कम हो जाता है और मूल्य में बढ़ने पर लगान बढ़ जाता है। अस्तु यह कहना सही नहीं है कि लगान अधिक होने के कारण अनाज महंगा है अथवा कीमत ऊँची है। बल्कि कहने का सही तरीका यह है कि अनाज का भाव ऊँचा है, इसलिए लगान उन्हाय अधिक है।

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि लगान से मूल्य निर्धारित नहीं होता, बल्कि मूल्य से लगान निर्धारित होता है। लगान उत्पादन-व्यय के ऊपर की वचत है। यह उत्पादन-व्यय का अंश नहीं है, यह उसमें शामिल नहीं होता। मजदूरी, ध्यान और लाभ आवश्यक प्रतिकार्य है। यदि ध्यान न दिया जाय तो पूँजी की पूर्ति बहुत घट जायेगी। यही बात मजदूरी के साथ कही जा सकती है। मजदूरों को काम पर लगाने के लिए उन्हें मजदूरी देना आवश्यक है, वरना उनकी सेवाएँ प्राप्त न हो सकेंगी। इसी तरह यदि व्यवस्थापक को लाभ न मिले तो वह जोखिम का भार उठाने के लिए तैयार न होगा। किन्तु भूमि के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा

सकती। चाहे जितना कम या अधिक लगान हो, भूमि की पूर्ति उतनी ही रहेगी। यदि लगान शून्य भी हो जाय, तो भी भूमि कही चली नहीं जायगी। वह तो प्रकृति की देन है। उसी सेवाएँ बिना कुछ मूल्य दिये ही मिलती रहेंगी। अर्थात् इस पर कुछ लागत नहीं होती। इसलिए भूमि के प्रतिफल को "बचत" कहते हैं और बचत होने के नाते यह उत्पादन-व्यय में शामिल नहीं हो सकता।

इस सम्बन्ध में कुछ लोग यह कहते हैं कि सामाजिक दृष्टि से तो लगान बचत है और उत्पादन-व्यय में शामिल नहीं होता, लेकिन व्यक्तिगत दृष्टि से यह उत्पादन-व्यय का एक भाग है और इस कारण मूल्य पर प्रभाव डालता है। इसके लिए वे यह दलील देते हैं कि भूमि समाज के लिए मुफ्त है, लेकिन व्यक्ति के लिए नहीं। भूमि को पाने के लिए व्यक्ति को कीमत चुकानी पड़ती है। जो कुछ भूमि के लिए उसे देना पड़ता है, वह उसके उत्पादन-व्यय में अवश्य शामिल होगा। जिस प्रकार वह मजदूरी, व्याज आदि को लागत-खर्च में डालता है, उसी तरह लगान को भी वह उत्पादन-व्यय में शामिल करता है। उसके लिए इनके बीच कोई अन्तर नहीं होता। वे सब भुगतान उसके लिए आवश्यक हैं, और आवश्यक भुगतान उत्पादन-व्यय में शामिल होते हैं।

ऊपरी तौर से यह दलील बिल्कुल ठीक लगती है। भूमि समाज के लिए मुफ्त हो सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए नहीं। व्यक्ति को भूमि मुफ्त नहीं मिलती, उसके लिए उसे दाम चुकाने पड़ते हैं। बिना दाम दिये उसे भूमि की सेवाएँ नहीं मिल सकती। इसलिए कहा जाता है कि लगान समाज की दृष्टि से तो बचत है लेकिन व्यक्ति की दृष्टि से उत्पादन-व्यय का एक भाग है, व्यावहारिक दृष्टि से चाहे यह मुझे ही ठीक हो, लेकिन सैद्धान्तिक दृष्टि से यह ठीक नहीं है। जब हम लगान को बचत व आधिक्य के अर्थ में प्रयोग करते हैं, तो फिर वैसे इसे उत्पादन व्यय में शामिल कर सकते हैं। वास्तव में जो रकम एक व्यक्ति लगान के रूप में देता है, वह लगान नहीं होता, वह और कुछ होता है। सब तो यह है कि

लगान दिया नहीं जाता, यह मिलता है। अर्थात् देने वाले की दृष्टि में नही बल्कि लेने वाले की दृष्टि से यह निश्चित होता है कि अनुकूलक लगान है कि नहीं। देने वाले की दृष्टि में वह बचत नहीं है, इसलिए उसे लगान गही कह सकते। फिर उसे उत्पादन-व्यय में शामिल करने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता।

### लगान पर कुछ बातों का प्रभाव

(Influence of Certain Things on Rent)

ऊपर कहा जा चुका है कि अर्थशास्त्र में "लगान" शब्द दो वस्तु व आधिन्य के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अस्तु, जिस बात या कारण से वस्तु की मात्रा में वृद्धि या घटी होगी, उसमें लगान में भी वृद्धि या घटी होगी। वस्तु की मात्रा मूल्य और उत्पादन-व्यय पर निर्भर करती है। यदि उत्पादन-व्यय उतना ही रहता है, तो मूल्य के बढ़ने से वस्तु में वृद्धि होगी और मूल्य के घटने में वस्तु में कमी होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मूल्य के बढ़ने के साथ लगान बढ़ता है और मूल्य के गिरने के साथ लगान गिरता है। अस्तु, यदि लगान पर किसी बात का प्रभाव देखना है तो हमें यह मान्य करना होगा कि मूल्य और उत्पादन-व्यय पर उसका क्या-क्या प्रभाव पड़ता है। यदि उसके कारण दोनों के बीच का अन्तर बढ़ता है, तो लगान में वृद्धि होगी और यदि अन्तर कम हो जाता है तो लगान में घटी होगी। उदाहरण के लिए लगान पर कुछ विशेष बातों के प्रभाव का विमर्श नीचे किया जाता है।

(१) जन-संख्या और लगान—जनसंख्या में वृद्धि होने में लगान में भी वृद्धि होगी। जनसंख्या के बढ़ने पर भूमि से उत्पन्न होने वाले पदार्थों की माग बढ़ेगी और साथ ही उनकी कीमतें भी। इस प्रकार बढ़ी हुई माग की पूर्ति के लिए और निम्न श्रेणी की भूमि उपयोग में लाई जायेगी। साथ ही उत्तम भूमि पर और अधिक गहरी खेती-कृषि-कार्यवाही दोनों ही परिस्थितियों में क्षति की सीमा गिरेगी और फलस्वरूप लगान में वृद्धि होगी। इसी बात को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि जन-संख्या

के बढ़ने से भूमि की कमी बढेगी और इसलिए लगान में वृद्धि होगी ।

(२) कृषि-सुधार और लगान—कृषि-सुधार के कारण भूमि की उत्पादन-शक्ति बढ जायगी । इससे कुस उपज की मात्रा में वृद्धि होगी । ऐसी दशा में यदि उपज की माग न बढी, तो मूल्य गिर जायगा और मूल्य के गिरने में लगान कम हो जायगा । मूल्य के घटने से जो पहले सीमान्त भूमि थी, वह कृषि में निकल जायगी क्योंकि उसकी उपज से लाभत-खर्च न निकल सकेगा । इसके ऊपर बाली भूमि, जिस पर पहले वसत होती थी, अब सीमान्त भूमि बन जायगी । फलस्वरूप लगान कम हो जायगा ।

(३) लगान और यातायात के साधनों में वृद्धि—यातायात के साधनों में वृद्धि होने से माल को ले आने-ले जाने में सुविधा होगी और दुलाई का खर्चा भी कम हो जायगा । इसका परिणाम यह होगा कि दूर-दूर के स्थानों से उपज मंडी में आने लगेगी । इस कारण मण्डी के पास वाले भू-भागों का महत्त्व कम हो जायगा, उनकी माग घट जायगी । पहले इन भू-भागों पर खेती की जाती थी क्योंकि दूर के स्थानों से माल नहीं लाया जा सकता था अथवा वही कठिनाई और अधिक खर्च करके लाया जा सकता था । यातायात के साधनों में सुधार और वृद्धि होने में यह कमी दूर हो जायगी । माल आसानी से और कम खर्च में आने लगेगा । इसके प्रभाव में मंडी के निकटवर्ती भू-भागों का लगान गिर जायगा और दूर के स्थानों का जहाँ से माल आने लगेगा, लगान बढ जायगा ।

## QUESTIONS

1. What is meant by economic rent ? How does it arise and how is it measured ?

- 2 Explain fully the concept of rent Can it be enjoyed by factors other than land ?
- 3 Define economic rent How will it be affected by (i) increase of population (ii) improvement in transport and (iii) improved methods of agricultural production ?
- 4 Examine the relationship between rent and price
- 5 Is rent a part of cost of production ? Does it affect price ? Explain fully

## अध्याय ४१

### लाभ (Profit)

लाभ के विषय में अनेक धारणाएँ प्रचलित हैं। इस सम्बन्ध में अनेक अर्थशास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। कुछ अर्थशास्त्री लाभ को अतिमिचितता और जोखिम उद्योगों का प्रतिफल ठहराने हैं, कुछ इसे योग्यता का समान मानते हैं, कुछ इसे बचन या अवशिष्ट आय मानने हैं, कुछ इसे केवल मजदूरी का एक रूप बताते हैं और कुछ लाभ को लूट-खसोट कहते हैं। इन विभिन्न धारणाओं के होते हुए भी, इसमें कोई मन्देह नहीं कि लाभ का सम्बन्ध साहसी, उपक्रमी या व्यवस्थापक की आय के साथ होता है। अर्थात् व्यवस्थापक के प्रतिफल को लाभ कहते हैं। उत्पादन का वह भाग जो व्यवस्थापक को उसकी सेवाओं के बदले में मिलता है, लाभ कहलाता है। अस्तु, लाभ की प्रकृति को अच्छी तरह से समझने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि व्यवस्थापक क्या काम करता है, और जिस सेवा व कार्य के बदले में उसे लाभ मिलता है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है व्यवस्थापक अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। उत्पादन की मारी बाण्डोर उसके हाथ में होती है। वही यह निश्चय करता है कि कौन-सी वस्तु, वस्त्र, कपड़ा और जिनकी मात्रा में तैयार की जाय। उत्पादन के आवश्यक माधनों को जुटाना और उनके बीच काम का उचित बंटवारा करना भी उसी का काम होता है। व्यवसाय का मारा प्रबन्ध, मंचालन, देख-रेख, नीति-निर्धारण आदि सबका बोझ उसी पर होता है। इनसे अनिश्चित वह एक और आवश्यक कार्य करता

है जिसका महत्व इन सबसे अधिक है वह है साहस अथवा जोखिम उठान का काम । व्यवस्थापक उत्पत्ति के अन्य माधनों को भिन्न भिन्न मात्रा में मिलाता है और वस्तु के उत्पन्न होने के पहले ही स मजदूर को मजदूरी पूँजीपतियों को व्याज और प्रबन्धक को वेतन देन लगता है । लेकिन सम्भव है कि जब उत्पन्न की हुई वस्तु बिनी के लिए मही में ले जाई जाय तो उसकी मांग अनुमान से कम हो या अधिक और वह विक्रय न हो । यदि वह खप न सके तो हानि होगी । इस जोखिम का भार व्यवस्थापक को उठाना पड़ता है । हर उत्पादन-काम में जोखिम उठान की आवश्यकता पड़ती है । इसके बिना किसी भी प्रकार के व्यवसाय का चलना अशुभव है ।

अस्तु संक्षेप में व्यवस्थापक दो प्रकार से कार्य करता है—एक तो प्रबन्ध का कार्य और दूसरे जोखिम उठान का काम । इन दोनों तरह के कार्यों को काफी हद तक अलग अलग किया जा सकता है । व्यवस्थापक के लिए सम्भव है कि वह निश्चित बातों पर मजदूरों या प्रबन्धकों को नियुक्त करके प्रबन्ध और निरीक्षण का काम उन्हे सौंप दे । पर साहस अथवा जोखिम उठान का काम किसी दूसरे पर नहीं सौंपा जा सकता । इसकी जिम्मेदारी तो व्यवस्थापक पर ही होती है । जोखिम उठान का काम उस ही करना होगा । वास्तव में उसका प्रधान काम यही होता है । इस बात को लेकर बहुत से अर्थशास्त्रियों का यह कहना है और यह ठीक भी है कि लाभ व्यवस्थापक के साहस या जोखिम उठान का प्रतिफल या पुरस्कार है । जो जोखिम उठाता है वही व्यवस्थापक या मालिक है या यूँ कह लीजिए कि जो मालिक है वही जोखिम उठाता है और इस काम के बदले उस जो मिलाता है उस अर्थशास्त्र में लाभ कहते हैं ।

### कुल लाभ का विश्लेषण

(Analysis of Gross Profit)

आम तौर से जो रकम कुल बिनी में से कुल उत्पादन व्यय के घटाने से व्यवस्थापक के पास बच रहती है वह उसका लाभ माना जाता है ।



लेकिन यह उसका वास्तविक लाभ (net profit) नहीं है। इसे कुल या सफ़ल लाभ (gross profit) कहना अधिक उपयुक्त होगा। कुल लाभ में अनेक प्रकार के भुगतानों को रकम शामिल रहती है और उनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें लाभ कहना उचित नहीं है। वास्तव में लाभ सम्बन्धी विषय में जो अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, उनका यह मुख्य कारण है। वास्तविक व आर्थिक लाभ को अच्छी तरह से समझने के लिए कुल लाभ के विभिन्न अंशों पर विचार करना आवश्यक है। कुल लाभ में निम्नलिखित चीजें शामिल रहती हैं —

(१) व्यवस्थापक के निजी साधनों का प्रतिफल—व्यवसाय में प्रायः व्यवस्थापक की अपनी निजी पूँजी और भूमि लगी हुई होती है। इन साधनों के उपयोग के बदले में जो रकम मिलती है, उसे लाभ नहीं कह सकते क्योंकि अगर वह अपने इन साधनों को किसी अन्य स्थान पर लगाता, तो अवश्य ही उसे उनके बदले में मूँद और लभान मिलता। इसलिए कुल लाभ में से व्यवस्थापक के निजी साधनों का प्रतिफल निकाल देना चाहिए। तभी वास्तविक लाभ मालूम हो सकता है।

(२) प्रबन्ध का पारिश्रमिक—कुल लाभ में प्रबन्ध का पारिश्रमिक भी सम्मिलित रहता है। बहुधा व्यवस्थापक स्वयं ही प्रबन्ध, संचालन, देख-रेख आदि का काम करता है। इस सेवा के बदले जो कुल उसे मिलना चाहिए उसे प्रबन्ध का पारिश्रमिक कह सकते हैं। अगर वह किसी दूसरे व्यवसाय में मैनेजर के तौर पर यह काम करता, तो उसे एक निश्चित एकाग्र वेतन के रूप में मिलती। कुल लाभ में से इस वेतन का बराबर का भाग निकाल देना चाहिए क्योंकि यह तो उसे प्रबन्धक के रूप में मिलता ही।

(३) जोखिम उठाने का प्रतिफल—यह पहले कहा जा चुका है कि प्रत्येक धन में कुछ न कुछ जोखिम अवश्य होते हैं। वर्तमान उत्पत्ति प्रणाली के कारण व्यवसाय में जोखिम का अंश बहुत बढ़ गया है। अब उत्पादन बड़े परिमाण पर दूर-दूर की मण्डियों में बिखरने के लिए बिगा

जाना है। मशी में किस वस्तु की भविष्य में कितनी माग होगी, इस अनुमान के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन होता है। लेकिन माग बहुत अनिश्चित होती है। कारण यह है कि माग पर फैशन, आय, औसत, जल-मर्यादा आदि कई बातों का प्रभाव पड़ता है और इनमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। इसलिए यह सम्भव है कि अब उत्पन्न पदार्थ मशी में ले जाया जाय, तो माग में परिवर्तन होने के कारण वह न बिक सके। इसी तरह उत्पादन के तरीकों में भी परिवर्तन होने से अनिश्चितता आ जाती है। इस अनिश्चितता के कारण व्यवसाय में हानि और लाभ का प्रश्न बराबर उपस्थित रहता है। जब तक कोई इस जोखिम का भार अपने ऊपर न लेगा, उत्पादन का काम नहीं चल सकेगा। लेकिन इस तरह का साहस करने के लिए अनेक अनुविधाओं में मुठभेड़ करनी पड़ेगी, तरह-तरह की समस्याओं को हल करना होगा। अनिश्चितता और जोखिम की जिम्मेदारी गुप्तद और सरल नहीं होती। इसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। वस्तु बिना किसी प्रतिफल की आशा के कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के कठिन कार्य में हाथ न लगायेगा। इसलिए व्यवस्थापक को जोखिम उठाने का प्रतिफल मिलना अत्यन्त आवश्यक है। कुल लाभ में जोखिम का प्रतिफल भी शामिल रहता है। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है इसी प्रतिफल को अर्थात् जोखिम उठाने के लिए जो रकम मिलती है वही वास्तव में लाभ कहलाता है।

व्यवस्था और जोखिम उठाने के प्रतिफल को "साधारण या सामान्य लाभ" (normal profit) कहते हैं। साधारण लाभ को औसत उत्पादन-व्यय में शामिल किया जाता है। यदि दीर्घकाल में व्यवस्थापक को उत्पादन से उपायन्त दोनों बातों के लिए प्रतिफल नहीं मिलेगा, तो वह उत्पादन-कार्य बन्द कर देगा।

(४) बचत व अतिरिक्त आय—कुल लाभ का शेष भाग बचत या अतिरिक्त आय कहलाता है। इसे कुछ अर्थशास्त्री शुद्ध लाभ (pure profit) कहते हैं। यह बचत अथवा अतिरिक्त लाभ कई

कारणों से हो सकता है। सम्भव है वह व्यवस्थापक एकाधिकारी भी हो। उदाहरण के लिये खरीदने वालों से अधिक मूल्य लेकर बिक्री या बर्तितरत लाभ प्राप्त कर सकता है। कभी-कभी ऐसी अनहोनी और असाधारण परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिससे व्यवस्थापक का लाभ बहुत अधिक बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए यदि माँग एक दम बढ़ गई तो कीमत भी आमयान पर बढ़ जायगी। इसके फलस्वरूप व्यवसायी को विशेष लाभ होगा जिसका उसे स्वप्न भी न था। इसी तरह अकस्मात् मुद्रा छिड़ जाने से या ऐंगो और घटनाओं के कारण व्यवस्थापकों के लाभ में विशेष वृद्धि हो जाती है। मटेरिअल के फलस्वरूप भी कभी-कभी काफी बचत हो जाती है। इस तरह के लाभ के पीछे कोई लागत नहीं होती; यह अनावश्यक है। इसे भीसत लागत में शामिल नहीं किया जाता।

ऊपर के विश्लेषण से यह पता चलता है कि कुल लाभ के अन्तर्गत वितनी तरह के प्रतिक्रिया का समावेश रहता है। इनमें से कुछ तो आवश्यक हैं, और कुछ नहीं। विभिन्न अर्थशास्त्री 'कुल लाभ' के भिन्न-भिन्न अंशों पर जोर देते हैं। कई लाभ का आशय बचत से लेते हैं, कई लाभ को जोखिम उठाने के प्रतिकूल के रूप में ग्रहण करते हैं, और कई अर्थशास्त्री तो लाभ को केवल एक तरह की मजदूरी ही मानते हैं। इस कारण लाभ का विषय बहुत ही विवादग्रस्त और समात्मक बन गया है। किन्तु अधिकांश अर्थशास्त्री जोखिम उठाने के प्रतिकूल या पुरस्कार को ही लाभ मानते हैं। प्रत्येक उत्पादन-कार्य में जोखिम उठाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना कोई भी उत्पादन-कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सकता। क्योंकि लाभ जोखिम उठाने का पुरस्कार माना जाता है, इसलिए लाभ एक आवश्यक प्रतिकूल है। व्याज, मजदूरी आदि की तरह यह उत्पादन-व्यय का एक अंश है।

## लाभ का निर्धारण

(Determination of Profit)

हम ऊपर कह चुके हैं कि लाभ जोखिम उठाने का प्रतिपाद व मूल्य है। अतः अन्य वस्तुओं के मूल्य की तरह जोखिम का भी मूल्य अर्थात् लाभ जोखिम की माग और पूर्ति के द्वारा निर्दिष्ट होता है। लाभ कम या अधिक होगा, यह जोखिम की माग और पूर्ति पर निर्भर करता है। यदि जोखिम की माग अधिक है, तो लाभ की दर ऊँची होगी और यदि जोखिम की पूर्ति अधिक है तो लाभ की दर कम होगी।

जोखिम की पूर्ति उन व्यक्तियों द्वारा होती है जो जोखिम उठाने के लिए तैयार होने हैं। जिस प्रकार किंगी वस्तु की पूर्ति उसके उत्पादन-व्यय पर निर्भर करती है, वैसे प्रकार जोखिम की भी पूर्ति जोखिम उठाने में जो लागत लगती है उस पर निर्भर होती है। जोखिम उठाने में मनुष्य को कुछ कष्ट होता है, कुछ त्याग करना पड़ता है। यही जोखिम उठाने की लागत है। जितनी अधिक जोखिम की लागत होगी, लाभ की उतना ही उँचा होना पड़ेगा, नहीं तो लोग उस मात्रा में जोखिम उठाने के लिए तैयार न होंगे।

जोखिम की माग उन लाभों द्वारा होती है जो उत्पादन-कार्य के सम्बन्ध में जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होते जैसे धूम, पूँजी आदि। ये साधन जोखिम की माग करते हैं क्योंकि जोखिम उठाने के बिना उत्पादन-कार्य नहीं चल सकता और वे स्वयं जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होते। जोखिम के लिए कुछ पारिश्रमिक देना पड़ता है क्योंकि यह उत्पादन के लिए अनिवार्य है और साथ ही इसकी कुछ लागत होती है। जोखिम के सहयोग से उत्पादन में वृद्धि होती है। इसकी माग उस सीमा तक होगी जब तक कि इसकी सीमान्त उत्पादिता जोखिम के मूल्य अर्थात् लाभ से बराबर न हो जाएगी। जोखिम के लिए उसकी सीमान्त उत्पादिता से अधिक मूल्य नहीं दिया जा सकता। अतः, जोखिम की माग सीमान्त उत्पादिता द्वारा निर्दिष्ट होती है और साम्य की स्थिति में

सीमान्त उत्पादिता और लाभ दोनों बराबर होंगे ।

अन्ततः जोखिम की मात्रा और पूर्ति के परस्पर बात-प्रतिपात से लाभ की वह दर निर्दिष्ट होगी जिस पर माग और पूर्ति का साम्य होगा, जिस पर जोखिम की सीमान्त उत्पादिता और सीमान्त लागत बराबर होगी । यदि दोनों में कोई अन्तर होगा तो माग और पूर्ति में परिवर्तन होने से लाभ की दर साम्य की स्थिति पर पहुँच आएगी ।

लाभ के निर्धारण के विषय में यहाँ जो कुछ कहा गया है, वह केवल सामान्य लाभ (normal profit) में ही सम्बन्ध रखता है । सामान्य लाभ सदैव धनात्मक (positive) होता है । यह औसत लागत में शामिल रहता है । शुद्ध लाभ की दर का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह आवश्यक नहीं है और यह ऋणात्मक (negative) और धनात्मक दोनों ही हो सकता है । व्यवस्थापक को सामान्य लाभ की प्राप्ति आवश्यक है लेकिन शुद्ध लाभ जरूरी नहीं है । यह तो केवल आकस्मिक है ।

### लाभ तथा उत्पादन-व्यय

#### (Profit and Cost of Production)

उत्पादन-व्यय में लाभ शामिल होता है या नहीं, इस पर कोई एक मत नहीं है । कुछ अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि लाभ अवशिष्ट बचत या शेष धन है और यह उत्पादन-व्यय में शामिल नहीं होता । कुल प्राप्तियों में से लागत खर्च निकालने के बाद जो कुछ शेष रह जाता है, वही लाभ कहलाता है । इस दृष्टिकोण से लाभ को उत्पादन-व्यय के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं कर सकते और इस कारण लाभ मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता । यह भी लगान की तरह मूल्य पर निर्भर रहता है । मूल्य में वृद्धि होने से लाभ बढ़ता है और मूल्य के गिरने से लाभ घटता है ।

अहाँ तक कुल लाभ के उस भाग का सम्बन्ध है, जितने व्यय में अतिरिक्त व शुद्ध लाभ कहते हैं, यह विचार थोड़ा ठीक है । लेकिन लाभ के अन्य अंशों के विषय में यह कहना ठीक न होगा । व्यवस्था और जोखिम उठाने के

प्रतिफल आवश्यक प्रतिफल है और आवश्यक प्रतिफल को-उत्पादन-व्यय में शामिल करना पड़ता है। यदि दीर्घकाल में मूल्य इतना नहीं होगा कि इन आवश्यक सेवाओं का प्रतिफल निकल सके, तो निश्चय ही व्यवसायी अपना धन्धा बन्द कर देगा। हो सकता है कि कुछ समय तक इन सेवाओं के बदले में प्रतिफल न मिलने पर भी व्यवसायी काम करता रहे क्योंकि भविष्य में उसे अधिक लाभ मिलने की आशा हो सकती है। किन्तु यदि यह परिस्थिति सदैव ऐसी ही बनी रहे, तो अवश्य ही निराश होकर उसे अपना वह काम छोड़ना पड़ेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनिश्चितता वातावरण में बुरी लगती है। इसलिए बिना किसी लोभ के कोई अनिश्चित बातों के लिए काम करने को तैयार न होगा। ठीक वही बात व्यवस्थापक के प्रसन्न में भी कही जा सकती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है जोखिम उठाने का कार्य अत्यन्त ही आवश्यक है। इसके बिना कोई भी काम नहीं चल सकता। लेकिन यह काम उतना ही अनिश्चित है। सम्भव है भविष्य में हानि उठानी पड़े या लाभ हो। इस तरह की अनिश्चितताय के लिए काम करने को कोई व्यवस्थापक या व्यक्ति तभी तैयार होगा, जब कि उसे कोई लोभ दिखाया जायेगा। यह लोभ है उम्र व्यनसाय का लाभ। अस्तु, लाभ एक आवश्यक प्रतिफल है। इसके बिना व्यवसायी जोखिम उठाने का भार अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहोये। आवश्यक होने के नाते, यह उत्पादन-व्यय में शामिल होगा। अतएव इस प्रश्न का उत्तर कि लाभ लागत खर्च में शामिल होता है या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि "लाभ" को किस अर्थ में प्रयोग किया गया है। यदि लाभ का अर्थ वचन से लिया गया है, तो यह उत्पादन-व्यय का अंश नहीं माना जा सकता और यदि लाभ को प्रबन्ध तथा जोखिम के प्रतिफल के अर्थ में प्रयोग किया गया है तो निश्चय ही उसको लागत खर्च में शामिल किया जायेगा। अर्थात् सामान्य लाभ उत्पादन-व्यय में शामिल होता है लेकिन अतिरिक्त या शुद्ध लाभ उत्पादन व्यय का अंश नहीं है।

## लाभ तथा मजदूरी

(Profit and Wages)

प्रो० टास्मिन्, लेबनपार्टे आदि ऐसे कई अर्थशास्त्री लाभ को मजदूरी का केवल एक रूप या प्रकार मानते हैं। वे कहते हैं कि यह निस्संदेह सत्य है कि व्यवस्थापक का लाभ अम्पाई और अनिश्चित है, लेकिन यह सोचना कि लाभ परिस्थितियों अथवा मौके के कारण होता है, ठीक नहीं। सहायी व्यवसायी अथवा व्यवस्थापक की सफलता मौके की बात नहीं है। सफलता के लिए उसमें कई गुणों का होना आवश्यक है, जैसे दूर-दृष्टिता, तीव्र बुद्धि तथा संगठन और निर्णय शक्ति, कुशल श्रमिकों के पहिचानने का गुण, दूसरों में विश्वास उत्पन्न करने की शक्ति आदि। इन्हीं गुणों के बल पर व्यवसायी को सफलता प्राप्त होती है। लाभ इन्हीं गुणों का प्रतिफल है। अर्थात् व्यवस्थापक भी श्रमिकों की तरह काम करता है, जिसके प्रतिफल स्वरूप उसे लाभ मिलता है। इस कारण कुछ लोग लाभ को एक प्रकार की मजदूरी मानते हैं।

यद्यपि कुछ अंश तक लाभ और मजदूरी में कोई विशेष अन्तर नहीं पाया जाता, फिर भी दोनों को एक प्रकार का प्रतिफल ठहराना भूल है। दोनों में काफी भेद है। मजदूरी एक निश्चित प्रतिफल है, लेकिन लाभ सर्वथा अनिश्चित है। साधारण तौर पर मजदूरी एक विशेष सीमा के नीचे नहीं जा सकती। परन्तु लाभ की कोई सीमा नहीं। वह बहुत अधिक भी हो सकता है, और बहुत कम भी। यहाँ तक कि कभी वह हानि का रूप धारण कर सकता है। व्यवस्थापक का मुख्य कार्य जोखिम उठाना, लाभ-हानि की जिम्मेदारी लेना है, लेकिन श्रमिकों को इससे कुछ मतलब नहीं। श्रमिकों को आय समीप पर निर्भर नहीं होती। वह ठहराव के अनुसार निश्चित होती है। यह ठीक है कि श्रमिकों को भी कुछ जोखिम उठाना पड़ता है, जैसे कि जिस धन्य को उन्होंने मीखा है, उसमें काम कम होने पर उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। फिर भी व्यवस्थापक को जितने और जिस प्रकार के जोखिम उठाने

पड़ते हैं, वे श्रमिकों के जोखिम से कहीं अधिक हैं। इसके अलावा प्रति-योगिता में रुकावट आने से लाभ बढ़ जाता है, पर इसके प्रभाव से मजदूरी कम होने लगती है। साथ ही कीमत के उतार-चढ़ाव का प्रभाव जितना अधिक और जितनी सीधता से लाभ पर पड़ता है, उतना मजदूरी पर नहीं पड़ता। कीमत के धोड़ा बढ़ने-घटने से लाभ की रकम बहुत बढ़-घट जाती है। किन्तु मजदूरी पर उसका वैसा प्रभाव नहीं पड़ता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लाभ और मजदूरी को अलग-अलग रखना आवश्यक है। दोनों में बहुत अन्तर है। लाभ को मजदूरी का एक रूप मानना ठीक न होगा।

### QUESTIONS

1. What is profit? Is it a necessary payment?
2. Analyse gross profits and show what is normal profit.
3. Examine the nature of profit. Differentiate between wages and profit.
4. What are the constituent elements of profits? Does profit enter into cost of production?



**DELHI  
HIGHER SECONDARY EXAMINATION  
PAPERS**

(Three Year Course)

1950

**I What are Economic Laws ?**

Compare and contrast the laws of economics with the laws of physical sciences

**II What do you understand by 'elasticity of demand' ? Distinguish extension of demand from increase of demand.**

Illustrate your answer with the help of curves

**III Define 'land' and discuss its importance as a factor of production.**

What are the factors that affect the productivity of land ?

**IV State and explain the Law of Diminishing Returns Why do Diminishing Returns occur ?**

**V What do you understand by Division of Labour ? What are its various forms ?**

Discuss its advantages

**VI What is a 'market' ? What are the factors that determine the size of a market ?**

Give illustrations

**VII Explain the meaning of 'distribution', bringing out clearly the various problems involved in it**

Discuss its significance in modern economic life

**VIII Distinguish between Gross and Net interest**

Is there any justification for the payment of interest ?

IX. Write notes on any two of the following —

- (a) Capitalistic System
- (b) Industrial Revolution
- (c) Monopoly
- (d) Co-operative Associations
- (e) Saving and Spending

X. Show how 'profits' are determined

Is it correct to say that profits do not affect prices ?

XI. What are the various kinds of credit instruments ? Discuss the advantages and disadvantages of paper money

XII. What do you understand by the 'value of money' ? How is the value of money determined ?

### 1951

I. What are the essential characteristics of wealth ? In the light of your answer explain whether the following can be considered wealth —

- (a) Opium. (b) Music (c) Nature's gifts like coal and mica (d) Taj Mahal (e) Business ability

II. Explain the law of demand. Show clearly the effects of changes in demand

III. What is the distinction between wealth and capital ? Explain the nature of capital and indicate the conditions which govern the growth of capital in a country. Illustrate your answer with Indian examples

IV. What are the economies due to machinery and mass production ? Explain why small scale industries like hand loom production exist side by side

with large scale production

V What is a market ? Explain how market price is determined

VI Discuss how the value of money is determined Has the value of money in India changed during the last one year ? If so indicate the nature of the change

VII Explain the functions and advantages of banks

VIII Explain the origin and nature of rent showing its connection with the operation of diminishing returns

IX Distinguish between real wages and nominal wages What are the causes of differences in wages ?

X Discuss the salient characteristics of the Capitalistic System of Production

XI Define monopoly and show how monopoly value is determined

XII Write short notes on any four of the following —

- (a) Marginal utility (b) Elasticity of demand
- (c) Token coins (d) Legal tender (e) Seigniorage
- (f) Bill of Exchange (g) Circulating capital (h) Economic laws

## 1952

I What is the subject matter of Economics as a science ? Briefly point out the importance of the study of Economics

II State the essential features of the capitalistic system of production What are the defects of capitalism ?

III Explain the law of diminishing utility and point out how this law is related to the law of demand

IV. Discuss the factors which govern the growth of population

V What do you understand by a Co operative Association ? Account for the slow progress of co-operation in the sphere of production

VI How is the market price of a commodity determined under competitive condition ?

VII What is meant by bank money ? Show how bank money is created

VIII Explain how the rate of interest is determined

IX Give the meaning of economic rent Briefly point out the relation between economic and rent price

X What are, in your judgment, the most important causes of poverty in India ? Has India become poorer, say, in the last twenty years ?

XI Write brief notes on any two of the following —

- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| (a) Engel's law                      | (b) Inelastic demand  |
| (c) Velocity of circulation of money |                       |
| (d) Increasing return                | (e) Marginal product. |

1953

1 (a) What do you understand by economic activities of man ?

(b) Bring out clearly the meaning in which the following terms are used by an economist —

- (i) economics (ii) economy (iii) economic (iv) economical

II Write a short account of the evolution of economic life

III Explain the concept of elasticity of demand Show how elasticity of demand is related to the law of demand

IV How would you distinguish land from capital ?

V What is meant by a 'market' in economics ? Enumerate the factors which govern the size of a 'market'

VI Explain and illustrate the law of diminishing returns What are the fundamental causes of diminishing returns ?

VII Why has money any value at all ? State the circumstances in which the value of money would tend to fall

VII The function of a banker is that of a middle-man Discuss

IX What is the difference between real wages and nominal wages ? A labourer is said to be interested in his real wages Why ?

X Explain the nature of business profits and point out whether such profits form a part of costs of production

XI Explain, adding comments wherever necessary, any two of the following statements —

(a) A free good has no price, for its marginal utility is zero,

(b) Extension of demand must not be confused with increase of demand,

(c) A co-operative association aims at minimising the evils of competition,

(d) To an individual entrepreneur rent is as much a cost as wages are

## 1954

I Discuss clearly using appropriate illustrations the nature of economic problem

II Examine the characteristics of wealth Are the following wealth —

(a) Dexterity of a mechanic (b) Gold at the bottom of the sea (c) Intoxicating liquors

III Explain the law of diminishing utility and point out how this law is related to the law of demand

IV Why is the present economic order called the capitalistic system? What are its basic defects?

V Define capital

Distinguish between (a) capital and wealth, (b) fixed and circulating capital

Which is fixed and which is circulating capital in the following cases? —

(a) Pen and ink (b) Bulb, battery and flashlight case (c) Bow and arrow

Can you give a difficult borderline case between the two categories?

VI Carefully consider the factors that affect the supply of labour in a country

VII What are the effects of the introduction and use of machinery?

VIII What do you mean by market price? What is the relation between market price and cost of production?

IX Explain clearly the concept of economic rent To an individual entrepreneur rent is as much a cost as wages are Explain

X What do you mean by 'value of money' ? State the circumstances in which the value of money would tend to fall

XI Discuss any two of the following ~

(a) Wages tend to be equal to the value of the marginal product of labour (b) In certain industries monopoly is an economic necessity (c) Ice cubes would not make a good unit of money (d) If labour is held constant, and land is increased in amount, would the producer experience diminishing returns ? (e) Barter puts people to serious difficulties